राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 15

गुरूवार

22 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

211. श्री केसर देव बाबर: क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कब से कार्यरत हैं एवं उनमें किस-किस विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीकर जिले में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थपित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ कस्बे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) जिला सीकर में वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य सरकार निजी क्षेत्र में आई.टी.आई. की स्थापना हेतु नि:शुल्क जमीन देने जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के अंतर्गत ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है वहां निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि उपलब्ध

(श्री वासुदेव देवनानी)

करायेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ हेतु प्रस्ताव का चयन कर आशय पत्र जारी किया जा चुका है तथा भूमि आबंटित की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब ना में दिया है, परसों तो आप आई.आई.टी. मांग रहे थे शेखावाटी क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: आई आई टी नहीं, आई टी आई।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कहने जा रहा हूं (व्यवधान) मैं आई.टी.आई. मांग रहा हूं और आप दो दिन पहले शेखावाटी क्षेत्र के लिए आईआईटी मांग रहे थे, इसलिए मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्षजी को मांगने की जरूरत नहीं है, अध्यक्षजी को हुकुम देना पड़ता है (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय ने हुकुम दे दिया अब पूरा करो (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि..

श्री अमराराम (धोद): जमीन तो तैयार है आप तो लागू करो।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): क्या यह सही है कि प्रत्येक तहसील में कम से कम एक आई.टी.आई. खोलने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी, यदि हां, तो सीकर जिले में शेष तहसीलों में कब तक खोलने का विचार रखती है? क्या यह सही है कि सरकार रोजगारोन्मुख शिक्षा पर जोर देना चाहती है? यदि हां, तो आई.टी.आई. खोलने के लिए वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति पर कम से कम एक आई.टी.आई. हो, उसके अंतर्गत राजस्थान में 237 उपखण्ड हैं, 124 उपखण्डों पर गत वर्ष तक आई.टी.आई. थे..

श्री अध्यक्ष: 237 उपखण्ड हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 113 ऐसी पंचायत समितियां

(श्री वासुदेव देवनानी)

थीं जहां पर आई.टी.आई. नहीं थी, उनमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत 104 पंचायत समितियों पर आई.टी.आई. के प्रस्ताव आ चुके हैं और उनको हमने आशय पत्र जारी कर दिये हैं। अब केवल 9 उपखण्ड ऐसे बचे हैं जिनको भी हमने दुबारा विज्ञापित किये हैं। इसके आधार पर हम जो राष्ट्रीय औसत पर एक लाख जनसंख्या पर 70 सीटें हैं, राजस्थान में केवल 40 सीटें थीं, इस प्रस्ताव के आधार पर हम राष्ट्रीय स्तर को भी क्रॉस कर जाएंगे। राजस्थान में हमने 498 आशय पत्र जारी कर दिये हैं। मैं समझता हूं उसके बाद जो अभी 22 हजार सीटे हैं उसमें 48 हजार की वृद्धि होकर के 70 हजार सीटें आई.टी.आई. की राजस्थान में हो जाएंगी जो भूतो न: भविष्यति, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां तक इनके सीकर जिले की बात है उसमें मैं बता दूं कि चार इनके पंचायत समितियों पर जिनमें से तीन में राजकीय और एक में प्राइवेट आई.टी.आई. था, बाकी चारों के लिए भी आशय पत्र जारी हो गये हैं, जिनमें इनका भी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र आता है।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): मंत्री महोदय, कोटा जिले में पंचायत समिति इटावा में क्या प्रस्ताव आये हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है ...

श्री अध्यक्ष: आपके तो खुल गया न, अब कह दिया है उन्होंने, अब क्या पूछोगे?

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आजकल आधुनिक युग है, सन् 1965 में जो विषय खोले गये थे सीकर में वो के वो विषय ही आज चल रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा, जी हां, आई टी आई चालू है सीकर में वहां मोबाइल, कम्प्यूटर, डीजल मैकेनिक आदि के विषय चालू करने में कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहेगी और ये वित्तीय व्यवस्था कब तक उपलब्ध हो जाएंगे। एक, दो आपने खण्ड-3 के उत्तर में भूमि आबंटन करने की बात कही है, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कितनी भूमि आबंटित की गई है और किस फर्म को यह भूमि आबंटित की गई है और कब तक शुरू हो जाएगा?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह विचार था कि पहले हम आई.टी.आई. शिक्षा का विस्तार करें और साथ-साथ धीरे-धीरे उसका सुदृढ़ीकरण भी करें। हमने पिछली बार टोटल 81 ऐसे यूनिट थी जो एस.सी.वी.टी. में थी उसमें से हमने 51 यूनिट को एन.सी.वी.टी. में कन्वर्ट करके इनको क्रमोन्नत किया है और उसमें पाँच करोड़ रुपए राज्य सरकार ने व्यय किए हैं। जिसके कारण से आधुनिकतम सारे उपकरण भी उसमें खरीदे गये हैं, 30 केवल एस.सी.वी.टी. के बाकी कोर्सेज यूनिट्स जिनको भी धीरे-धीरे सभी एन.सी.वी.टी. में बदलने का सरकार का विचार है। जहां तक इन्होंने पूछा प्रत्येक आई.टी.आई. जो पी.पी.पी. मोड में खोल रहे हैं उसमें पाँच बीघा जमीन राज्य सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। उसमें हमने एक कमेटी बना रखी है प्रिंसिपल सैक्रेटरी, टेक्नीकल एजुकेशन की अध्यक्षता में उसमें डायरेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन है, एकाउंट्स ऑफिसर है, ओएसडी है, जितने भी प्रस्ताव आते हैं उसमें प्रायोरिटी के आधार पर हमारे माप-दण्ड तय हैं, जिसको इण्डस्ट्रीज चलाने का अनुभव है, उसका भी एजुकेशन बैकग्राउण्ड है और उनकी क्षमता है, फाइनेंसियल साउंडनेस है, ऐसे मुद्दों को देखते हुए हमने इतने सारे आई.टी.आईज. को जमीन उपलब्ध करा के आई.टी.आई. आशय पत्र जारी कर दिये हैं।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात जो मूल थी वह रह गई। मोबाइल, कम्प्यूटर, डीजल मैकेनिक आदि विषय चालू करने पर सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा और यह कब तक चालू हो जाएंगे? सीकर में जो आई.टी.आई. स्थित है उसके बारे में पूछ रहा हूं और दूसरा यह कि जो जमीन आवंटित की गई है, कौन से फर्म या किस फर्म को की गई है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ में एक पारिवाला वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है लक्ष्मणगढ़ का, उसे पी.पी.पी. मोड़ में जमीन अलॉट की गई है। जहां तक इनके सीकर के जो आई.टी.आई. का प्रश्न है वहां पर छह आई.टी.आई. चल रहे हैं, वहां जिन नये हमने आई.टी.आई. को दिया है, उसमें सब आधुनिकतम व्यवसाय है। सरकार के इस आई.टी.आई. के अंदर नये अभी हमने विस्तार किया है धीरे-धीरे यह विचाराधीन है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इनमें नये कोर्स भी शुरू होंगे लेकिन जितने भी नये आई.टी.आई.ज. खोल रहे हैं उन सब में इस प्रकार के मोबाइल और बाकी जो प्रकार के कोर्सेज आधुनिकतम हैं उन्हीं को ही हम प्रायोरिटी से दे रहे हैं और वहीं खोले जा रहे हैं।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया, एक तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे इन विषयों को चालू करने में कितना खर्चा आ सकता है, एक जो लक्ष्मणगढ़ में...

श्री अध्यक्ष: खर्चे के बारे में पूछा ही नहीं आपने?

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): पूछा है अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि मोबाइल, कम्प्यूटर और डीजल मैकेनिक इन तीन विषयों को खोलने में सरकार पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न है मेरा यह।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हर ट्रेड के लिए अलग-अलग है, मोबाईल के लिए पाँच से दस लाख के बीच में आधुनिकतम उपकरणों की आवश्यकता होती है, हर ट्रेड का अलग-अलग है, कोई इलेक्ट्रिशियन का है, कोई कम्प्यूटर का है, कम्प्यूटर में सबसे कम होता है तो हमने कई जगह कम्प्यूटर सेंटर भी खोले हैं और सबसे पहले सरकार के पास प्रायोरिटी है कि यह आई.टी.आई. की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो जाए और साथ में जितने एस.सी.वी.टी. कोर्सेज है ये एन.सी.वी.टी. में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम धीरे-धीरे नये कोर्सेज बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने तीन मिनट ले लिया (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, पहले इनको बोलने दीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सरकारी आई.टी.आई. जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में है वो रिजर्व सीट है, वहां पर एससी, एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं। इसलिए सरकारी आई.टी.आई. खुलेगी तभी वहां रोजगार बच्चों को मिलेगा। यह जो तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय है (व्यवधान) आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा आश्वासन दे दें कि यह जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें सरकारी आई.टी.आई. खोली जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल लीजिएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आई.टी.आई. नहीं खोले थे हमारी सरकार ने 20 नये आई.टी.आई. सरकार क्षेत्र में गत वर्ष खोले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। श्री सी.पी.जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है... (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम सी.पी.जोशी का पुकार लिया। आप स्थान ग्रहण करें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सत्र 2006-07 के बजट भाषण में सरकार ने पीपीपी मोड में आई.टी.आई. लगाने की बात की थी? आपने खाली आशय पत्र जारी किये हैं । आप यह बतायें कि 2006-07 में कितने एक्चुअल आई.टी.आई. लगे।– नंबर-1. नंबर-2 भारत सरकार आपको कितना पैसा दे रही है जो आज दिन तक नहीं मिला उसकी राशि कितनी है? वो बता दें आप।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आ जाने दो इसका।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): मैं कब से हाथ खड़ा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बाद में। पहले जवाब आने दीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): सबका एक साथ ही आ जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप उसको उलझाना क्यों चाहते हैं? आप उसको उलझाना चाहते हैं ...(व्यवधान) आप इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में कोई आई.टी.आई. खोलने की योजना है क्या?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार ने केवल मात्र पी.पी. मोड में केवल मात्र आशाय पत्र दिये हैं एक्चुअल में पी.पी. मोड में राजस्थान में सरकार की घोषणा करने के बाद में नहीं लगी संस्थान । - नंबर-1 नंबर-2 भारत सरकार आपको स्ट्रेन्थन करने के लिए जितना पैसा दे रही है उतने पैसे का भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि रेलमगरा तहसील में जिला राजसमंद में कब तक आई.टी.आई. खोल देंगे? राजसमंद जिले में रेलमगरा में आज तक आई.टी.आई. नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मावली से आने वाले माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है। आपका प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पी.पी. मोड में 2006-07 के अन्दर 11 आई.टी.आई. प्रारंभ हो चुके हैं और बाकी आई.टी.आई. जुलाई से शुरू हो जाएंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि हम सब जगह खोल रहे हैं तो रेलमगरा में कब तक खोलेंगे?

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 149 की आपने आशय पत्र दिये हैं 149 के आपने जवाब दिया है। 149 के आपने आशय पत्र दिये हैं और उन 149 के अगेंस्ट में केवल 11 लगे हैं और उन 11 में भी अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एक रैकेट है इसको समझने की आवश्यकता है जो लोग पी.पी. मोड में सरकार से जमीन को लेकर बुक कर रहे हैं और जमीन बुक करने के बाद जमीन की कोस्ट बढ़ जाएगी और दूसरे को जाकर सरेण्डर करेंगे । क्या सरकार यह एश्योर करेगी कि जिनको पी.पी.पी. मोड़ में आईटीआई के लिए आप आशय पत्र दे रहे हैं यदि वो एक साल में या 6 महीने में नहीं लगायें तो उनको कैंसिल करेंगे? यह आपने फैसला किया क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): निश्चित रूप से सरकार ने जहां पर आई.टी.आई. के लिए जमीन दी है उसका उपयोग आई.टी.आई. के लिए होगा यदि कोई नहीं खोलेगा तो सरकार उससे जमीन जो है लेगी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कितने साल में? आप कितने समय में, 149 के आप आशय पत्र दे चुके हैं आपके इस साल तक 11 खुले हैं बाकी जगहों पर जमीन बुक करवा दी लोगों ने और इसके करने के बाद एक भी जगह आई.टी.आई. नहीं खुली है इसके लिए सरकार को नियम नहीं बनाना चाहिए क्या कि 6 महीने, 8 महीने में आप ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं आई.टी.आई. के आशय पत्र जारी होने के पश्चात् आई.टी.आई. के सारे प्रस्तावों पर एक कमेटी जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है उसका निरीक्षण करती है निरीक्षण करने के बाद उसकी अनुमति के बाद ही आई.टी.आई. खुलता है वह प्रोसेस चालू है। निश्चित रूप से इस जमीन का दुरुपयोग नहीं होगा यह मैं आपसे कहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, एक साल से कह रहे हो एक साल से बजट भाषण में घोषणा की है कि पी.पी. मोड में हम लगायेंगे। भारत सरकार अभी तो एक साल से ...(व्यवधान) आपके नहीं आया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने नीति की घोषणा की थी उस समय आशय पत्र कहां आये हुए हैं आशय पत्र उसके बाद जारी हुए हैं वो प्रोसेस है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इसका मतलब सरकार जो घोषणा करती है और प्रैक्टिकल करने में दो साल लगते हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): दो साल नहीं हुए। एक साल भी पूरा नहीं हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): राजस्थान की जनता को, पिछले बजट में घोषणा की अध्यक्ष महोदय, कि पी.पी.पी. मोड में हायर एजुकेशन में जाएंगे, पी.पी.पी. मोड़ में कॉलेज में जाएंगे, पी.पी.पी. मोड़ में मेडिकल में जाएंगे, पी.पी.पी. मोड़ में आईआईटी में जाएंगे और राजस्थान सरकार की ये स्थिति है कि पिछले साल दस प्रतिशत जगह भी आपने न तो हायर एजुकेशन में, न टैक्निकल एजुकेशन में, न मेडिकल फील्ड में पी.पी.पी. मोड में आप इंस्टिट्यूट खड़े कर सके, केवल मात्र लोगों ने जमीन अलॉटमेंट कराकर लाखों करोड़ों रुपये की जमीन को बुक कर लिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कोई समय तो तय होना चाहिए ...(व्यवधान) ये तो होना चाहिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमसंद जिले में रेलमगरा तहसील है और पंचायत हैडक्वार्टर भी है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आशय पत्र जारी होने की तिथि के एक साल के अन्दर उसको खोलना है ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, वो बोल रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): पंचायत हैडक्वार्टर भी है वहां आप कब तक खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप खड़े हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जिस तारीख को आशय पत्र जारी होगा ...(व्यवधान) जिस तारीख को संस्था का आशय पत्र जारी होगा उसके एक साल के अन्दर वो खुलेगा।

श्री अमराराम (धोद): नहीं खुलेगा तो वो निरस्त हो जाएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं खुलेगा तो फिर उस पर हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार क्या है ...(व्यवधान) आप यह कहिये कि एक साल में नहीं खुलेगा तो जमीन का आबंटन निरस्त करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ...(व्यवधान) यह एक अहम मुद्दा है, आप रेलमगरा में कब तक खोल देंगे?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): (व्यवधान) जयपुर में आईआईटी खोली जाए उसके लिए जमीन चिह्नित की जाए और इसके साथ साथ चूंकि ये अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं है । जयपुर में आईआईटी खोलने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये आईआईटी का मुद्दा नहीं है आई.टी.आई. का है, आईआईटी का कंफ्यूजन कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) उनको तो आईआईटी दे दो आप जयपुर में।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनके सवाल का राजस्थान का इन्होंने जवाब दिया है मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं ...।

श्री अध्यक्ष: मैंने जिसका नाम नहीं पुकारा उसका अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): XXX

श्री अध्यक्ष: आपका नाम किसने पुकारा?

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): XXX

श्री अध्यक्ष: मैंने नहीं पुकारा। डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): XXX

श्री अध्यक्ष: अब आप दूसरा प्रश्न करके जानना ये। डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): XXX

श्री अध्यक्ष: एजुकेशन की आज डिमाण्ड है यदि आप उससे अधिक कोई बात प्लीज, आज एजुकेशन की डिमाण्ड है शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा भी उसमें है आपको यदि कोई और बात कहनी है तो उस वक्त कहियेगा आप। लेकिन इस एक प्रश्न के ऊपर बाकी प्रश्नों को आने नहीं दें यह कहां का तरीका है?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: जो अनुशासन नहीं मानेगा उसको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: जो अनुशासन में रहेगा उसी को अवसर दिया जाएगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

पंजाब राज्य से सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी

212. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) वर्ष 2004 से अब तक इंदिरा गांधी नहर परियोजनान्तर्गत पंजाब से राज्य को कितना पानी उपलब्ध कराया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक उक्त परियोजनान्तर्गत फेज प्रथम तथा फेज-द्वितीय को सिंचाई हेतु कितना पानी उपलब्ध कराया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसी पेयजल योजना हेतु कितना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2007 तथा 2008 में कौन-कौनसी नवीन सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं हेतु कितना पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इंदिरा गांधी नहर मंत्री (श्री सांवर लाल) : अध्यक्ष महोदय, (1) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 (माह फरवरी तक) इंदिरा गांधी नहर परियोजनान्तर्गत राज्य को उपलब्ध कराये गये पानी का माहवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त अवधि में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में बहाव क्षेत्र को 5.23 क्यूसेक्स/1000 एकड़ एवं जलोत्थान क्षेत्र को 3.90 क्यूसेक्स/1000 एकड़ जलांक के अनुसार पानी दिया जा रहा है तथा द्वितीय चरण के बहाव क्षेत्र में 3.00 क्यूसेक्स/1000एकड़ एवं जलोत्थान क्षेत्र में 2.00 क्यूसेक्स/1000 एकड़ जलांक से दिया जा रहा है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 (माह फरवरी) तक दिये गये पानी का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत पेयजल योजनाओं को उपलब्ध कराये गये पानी का माहवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) उक्त परियोजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 48000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु खोलना प्रस्तावित है। इसी परियोजना से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वर्ष 2007-08 में 139 नवीन पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 87 क्यूसेक पानी और उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इसमें है पंजाब से 2004-05 में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पानी मिला 4.31 एमएएफ, 2005-06 में मिला 6.21 एमएएफ, 2006-07 में मिला 4.67 एमएएफ अभी तक। जब आपको पानी पंजाब से प्राप्त होना चाहिए यह आपको मालूम है पोंग डेम के लेवल के आधार पर आपको पानी की मात्रा तय की जाती है, पहला मेरा सप्लीमैंट्री क्वेश्चन यह है कि पोंग डेम के लेवल के आधार पर 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के अंदर कितने पानी की मात्रा राजस्थान को दिये जाने के लिए निर्धारण किया गया और उसके अगेंस्ट में आपको कितना पानी मिला? यदि पानी आपको कम मिला तो उसके लिए आपने पंजाब सरकार को कब-कब, क्या-क्या पत्र लिखे या क्या-क्या प्रयास किये?

सप्लीमैंट्री क्वेश्चन नं-2 है कि आपने किसानों के साथ 11 दिसम्बर, 2004 को समझौता किया, उस समझौते के आधार पर आपने फेज-1 और फेज -2 को पानी का प्रतिशत वितरित किया वो उस समझौते के पहले कितना था और समझौते के बाद में कितना था? क्वेश्चन नं. 3 कि आपने पेयजल योजनाओं के लिए 2005-06 के अंदर ...।

श्री अध्यक्ष: आप एक-एक करके पूछें एक साथ करेंगे तो...

श्री सांवर लाल: पूछो एक बार में। और पूछने दो। पूछो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पेयजल योजनाओं के लिए जो आपने परिशिष्ट 'ब' के 1 खण्ड में जो आपने लिखा है कि 28076 क्यूसेक डेज और वो ही पानी 2006 के अन्दर 25202 क्यूसेक डेज कर दिया तो ये पेयजल योजनाओं में पानी की कटौती आपने क्यों की?

श्री सांवर लाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पोंग डेम के लेवल एक्सपेक्टेड इनफ्लोज के आधार पर राजस्थान का जो हिस्सा है उसकी मांग हम करते हैं। 4 ग्रुप में से दो चल सकते हैं तो उसके आधार पर फर्स्ट फेज और सेकण्ड फेज के लिए पानी लेते हैं। अगर पानी का हिस्सा उससे कम हमारे को लगता है तो तीन में से एक ग्रुप चलाकर उस हिसाब से पानी लेते हैं मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कुछ समय का फ्लेक्चुअलेशन आया हो, फ्लेक्चुअलेशन में कभी हमको ज्यादा पानी भी मिलता है कभी थोडा बहुत कम भी हो जाता है बाकी जितना पानी हमने मांगा है उसी हिसाब से यह पानी मिला है । दो पीरियड होते हैं एक तो फिलिंग पीरियड और एक होता है डिप्लेशन पीरियड । डिप्लेशन पीरियड में भी

(श्री सांवर लाल)

हमारी मांग के हिसाब से होता है और बांध में जितना पानी आने की संभावना है और जितना भर जाता है उन दोनों को देखते हुए फिर डिप्लीट करने के लिये 20 मई तक जो पानी लिया जाता है वह फैसलों के हिसाब से लिया जाता है । खरीफ में 21 मई से लगाकर 20 सितम्बर तक जो पानी है वह फर्स्ट स्टेज और सैकण्ड स्टेज में जितनी मांग करते हैं उसके आधार पर पानी देते हैं । उसी आधार पर पानी लिया गया और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितना पानी हमने हमारे हिसाब से अनुमानित किया हमारे हिस्से का पूरा पानी हमको मिला है । इसके अलावा दूसरी बात आपने कही है कि 11 दिसम्बर को जेल में समझौता हुआ उसके पहले का वाटर अलाउंस प्रति हजार एकड का फर्स्ट स्टेज का 5.23 था, सैकण्ड स्टेज का 3 एकड़ प्रति है और लिफ्ट योजना है कंवर सेन का 3.9 है और बाकी दूसरी का 2 प्रति हजार एकड़ के हिसाब से पानी उपलब्ध करवा रहे हैं । इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूं जो स्टेज है इसमें 5.43 लाख हैक्टेयर के लगभग एरिया है जिसमें पानी दिया जा रहा है । इसकी इंटेनसिटी भी 119 प्रतिशत है । सैकण्ड स्टेज का जो एरिया है उसमें लगभग 3 लाख 40 हजार हैक्टेयर पानी मिल रहा है और 3 क्यूसेक्स के हिसाब से हम पानी ले रहे हैं । इसमें जो अनुपात है वह जो मिल रहा था उसी हिसाब से मिल रहा है । आप अगर चाहे तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष: जितना पूछा है उतनी ही जानकारी दो आप ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 1999-2000 में फर्स्ट स्टेज को मिला टोटल 7 लाख 12396 और द्वितीय चरण को मिला 2 लाख 4500, लगभग 9 लाख । इसी प्रकार 2001-02 से भी हमारे पास डिटेल है । मैं यह कह सकता हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकंड स्टेज को जो औसत एरिया फीड हुआ 1 लाख 78248 हैक्टेयर और हमारे टाइम में हुआ 2 लाख 64849 हैक्टेयर । यह एरिया भी बढा है और इस वर्ष कंवर सेन लिफ्ट में लगभग 15 हजार एरिया को हमने पानी उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ किया है । इसके अलावा पेयजल के लिये भी कहीं फ्लेक्चुअलेशन की बात अलग है बाकी ड्रिंकिंग वाटर कहीं सफर नहीं कर रहा है मैं आपको कह सकता हूं जिस-जिस का हिस्सा है उसके हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है । आपकी जानकारी के लिये बता दूं रावतसर में लगभग 56 क्यूसेक्स हम देते हैं । इसी प्रकार कंवर सेन लिफ्ट को हम ढाई सौ देते हैं । उसमें भी कई बार हमको

(श्री सांवर लाल)

थोड़ा ज्यादा पानी देना पड़ता है। इसी प्रकार सावा लिफ्ट है उसमें 30 क्यूसेक्स दिया जाता है । जौधपुर लिफ्ट के लिये लगभग 155 क्यूसेक्स दिया जा रहा है और जैसलमेर के लिये 30 क्यूसेक्स पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिये 70 क्यूसेक है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो ग्रामीण और शहरी एरिया है उसको भी पानी उपलब्ध कराया जाता है ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैंने पहला सप्लीमैंट्री क्वेश्चन यह पूछा था जैसे पहले साल आपको 2004 में मिला 4.31 । आपने यह कहा कि जितना मांगा उतना पानी मिल गया । जब आपको अलाटेड 8 एमएएफ है तो आपका निर्धारण कितना किया गया था और आपको मिला कितना ? दूसरे साल में आपको मिला 6.21, तीसरे साल मिला 4.67 तो आपने कम पानी की मांग क्यों कि जब कि आपका हक 8 एमएएफ पानी पर है । पोंग डेम का लेवल पिछले दो साल से ठीक चल रहा था तो आपने कम पानी की मांग क्यों की? दूसरा] जब समझौता आपने किया तो उस समझौते में आपने यह लिखा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में प्रतिवर्ष मिलने वाले कुल पानी 14100 क्यूसेक क्षमता वाली नहरों का वितरण प्रथम व द्वितीय चरण में 8200 और 5900 के हिसाब से किया जायेगा । समझौते के पहले जो आप पानी दे रहे थे फेज वन और फेज टू को, फेज वन को दे रहे थे 67.5, फेज टू को दे रहे थे 32.5 । इस प्रतिशत में पिछले तीन साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना फेज वन को मिल रहा था उतना ही फेज वन को मिल रहा है, जितना फेज टू को मिल रहा था उतना ही फेज टू को मिल रहा है और एक सब से महत्वपूर्ण चीज एक तरफ आप बार-बार यह कह रहे हैं कि सतही जल का प्रयोग पेयजल योजनाओं के लिये किया जायेगा लेकिन आपने पेयजल योजनाओं के लिये यदि आप प्रतिशत निकाले तो टोटल प्रतिशत पेयजल योजनाओं में आप व्यय करते हैं उसमें पहले साल आपने दिया 3 प्रतिशत पानी । जितना टोटल पानी आपको मिला उसका 3 प्रतिशत आपने पेयजल में दिया ।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): दूसरे साल इन्होंने दिया 2.6 प्रतिशत। तो यह कटौती क्यों की गई जब कि पेयजल में आपको पानी ज्यादा आबंटित करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: हां, यह कहो कि कटौती क्यों की?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष: विद्वान तो आप भी कम नहीं हो ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने जो यह पढ़ा है 12100 क्यूसेक को दो भागों में बांटने का जो पढ़ा है इतना पानी नहीं चलाया जायेगा । हमने यह लिखा है कि उपलब्ध पानी को इतनी क्षमता की नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जो शेयर डिसाइडेड होता है, पोंग में अवेलिबिलिटी प्लस इनफ्लोज के आधार पर जो आपके टाइम में यह समझौता हुआ 1981 का, टोटल अवेलिबिलिटी 17.17 एमएएफ मानते हुए ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वह ठीक है साहब, मेरे को तो यह बता दो कि कितने पानी की मांग की और कितना पानी आपको मिला ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको ही बता रहा हूं और किस को बता रहा हूं पूरी जानकारी ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जब 8 एमएएफ पानी मिलना चाहिये तो 4.31, 6.21, 4.67 यह कम क्यों मिला आपको, उसके लिये आपने क्या किया ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कम नहीं मिला और आप कहोगे तो पाँच साल के आंकड़े भी बता दूंगा । मैं यह कह रहा हूं पानी की उपलब्धता जो भी पोंग डेम प्लस इनफ्लोज आयेगा फिलिंग पीरियड में 20 मई तक उसका हिसाब लगाकर फिर इसको भी हम मार्च में रिव्यु करेंगे । अगर हमने ड्राई पेटर्न पर अनुमानित किया उससे ज्यादा आयेगा तो फिर पानी की और मांग कर लेंगे । राजस्थान के हिस्से का पानी कम मांगे यह कभी संभव नहीं है । हर महीने हम हमारा डिमांड चार्ट देते हैं । 17.17 को अधिकतम पानी की संभावना मानी गई है । अवेलिबिलिटी पोंग डेम, रणजीत सागर प्लस आपका इनफ्लोज Share of Punjab 4.22, share of Haryana 3.5, share of Rajasthan 8.6, Delhi water supply .2 M.A.F., share of Jammu and Kashmir .65 M.A.F. यह समझौता होने के बाद Until such time as Rajasthan is in a position to utilize it full share, Punjab shall be free to utilize the water surplus to Rajasthan requirement. As Rajasthan will soon be able to utilize its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its own land by the time

(श्री सांवर लाल)

Rajasthan is in a position to utilize the full share… और पंजाब का शेयर होगा 4.82 उसके बाद हम मांग कर रहे हैं यह तो हमको नहीं मिला बाकी आपका यह कहना कि इस साल इतना कम क्यों मिला, इस साल ज्यादा क्यों मिला, माननीय सदस्य, मैंने बताया कि अवेलिबिलिटी आफ वाटर होगी उसी को इस अनुपात में बांट कर लिया जा रहा है । उसमें राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लिया जा रहा है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक क्यूसेक पानी भी कम नहीं ले रहे हैं और यह इंडिकेट करता है टेल एण्ड तक हमने पानी पहुंचाया है और इर्रिगेटेड एरिया का जो आंकड़ा हमने दिया वह भी लगातार बढ़ रहा है । इसलिए यह कहना बिलकुल उचित नहीं है कि पानी का पूरा हिस्सा हम नहीं ले रहे हैं ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं आपकी थोड़ी सी मदद चाहता हूं । मैंने मोटे रूप में यह पूछा कि वर्ष 2004-05 व 2005-06 में राजस्थान ने कितने पानी की मांग की है और उसकी एवज में आपको कितना पानी मिला और दूसरा आपने पेयजल योजनाओं में पानी की कटौती क्यों की? क्योंकि जो चार्ट आपने दिया है उसमें आपने परिशिष्ट 'ब' के पहले पृष्ट पर आप देखें टोटल पानी का आबंटन पेयजल योजनाओं के लिये किया है 28076 क्यूसेक और उसके अगले साल 2006 में किया है 25202 क्यूसेक। यह कटौती आपने क्यों की?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ड्रिंकिंग वाटर की जहां-जहां जितनी जरूरत है पानी दिया गया । डिसाइडेड शेयर आपको बता दिया है । इसमें कई बार कंवर सेन लिफ्ट में ज्यादा देना पड़ सकता है उसकी वजह से वह ज्यादा दिया होगा इसलिए कभी आंकड़ा ज्यादा हो गया बाकी कहीं पर भी कोई कटौती नहीं की है । आर.एल.जी.सी. जौधपुर को पहले हम 110 देते थे अभी इन्होंने डिमांड की तो हमने 155 देना शुरू कर दिया । अगर ऐसा कहीं संकट आता है तो माननीय सदस्य उस एरिया के लोग-बाग़ ड्रिंकिंग वाटर के लिये इस नहर पर निर्भर हैं तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है यह मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 50 प्रतिशत एरिया राजस्थान का डार्क जोन में आ गया और पेयजल योजनाओं के लिये जो सतही जल उपलब्ध है उसमें आप कटौती कर दें और आप कह रहे हैं कि कटौती नहीं की । आप

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

स्वयं ही देख लें आपने परिशिष्ट 'स' (2) में जो चार्ट दिया है उसका टोटल लगाकर मैं बता रहा हूं, 28 हजार से कम करके आपने 25 हजार क्यूसेक कर दिया । मतलब 3 हजार क्यूसेक कम कर दिया । जब कि आपको पेयजल योजनाओं के लिये पानी बढाना चाहिये और अभी मेरे पहले प्रश्न का जवाब भी नहीं मिला कि आपने मांग कितने की की थी और मांग की एवज में आपको कितना मिला ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं जब आपको बार-बार यह कह रहा हूं जितना मांग किया हर महीने उसी हिसाब से पानी चलता है, तो पानी मिला आपको वह बता दिया, वही मांग है। आप और क्या पूछना चाह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष: अमराराम जी।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपके कहने का मतलब यह है कि टोटल पानी जो निर्धारित किया गया था वह 4.31 ही था क्या, टोटल 2004-5 में 4.31 ही निर्धारित किया था, 2005-6 में 6.21 ही निर्धारित किया गया था, आपने इतनी मांग की और आपको इतना ही मिल गया, यह तीनों फीगर एक ही हैं क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): डाक्टर साहब, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर महीने यह निर्धारण होता है, हर महीने इनफ्लोज का हम स्टडी करते हैं उसके आधार पर अगर शेयर बढ़ जाता है तो उसी हिसाब से हम बढ़ाकर मांग करते हैं। अब आप पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पूरे साल की, पूरे की बात कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप बिराजिए, मैं एक मिनिट... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पूरे साल का जो टोटल है उसकी बात कर रहा हूं। पूरे साल का टोटल 4.31 ही था क्या आपका 2004-5 में, और 2005-6 में 6.21 ही था क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप बिराजिए, मैं बता रहा हूं आपको। 2004-5 में हमने मांगा 21 लाख 75 हजार 352 और वह मिला। फिर उसके बाद में मांगा 31 लाख 32 हजार 647 और वह मिल गया। फिर मांगा 23

(श्री सांवर लाल)

लाख 56 हजार 108 जो अभी वर्ष चल रहा है। मई तक और डिमांड करेंगे, मार्च में रिव्यू करेंगे, अगर हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा इनफ्लोज की वजह से तो और बढ़ाकर मांग लेगे। अब आप क्या चाह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या यह मान रहे हो क्या कि पहले साल का पानी...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उसमें आपने लिखा है, अब आप बता रहे हो क्यूसेक के हिसाब से आप यह बता दो जितना एम.ए.एफ. मांगा उतना मिल गया क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह क्यूसेक को हमने एमएएफ में बदल दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): क्यूसेक को हमने एम.ए.एफ. में इसलिए बदला, हमारे..(व्यवधान) 8 आया, 8 के बावजूद जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हमारा हिस्सा 4.31 बना है वह हमको मिला, यह 6.3 बढ़ा वह हमको मिला और 4.67 अभी तक फरवरी तक का हमने दिया है उसके बाद और बढ़ेगा और जोड़ देंगे इसमें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमरारामजी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी आंकड़ों के हिसाब से यह बताया कि....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है अमराराम।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है अमराराम।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री अध्यक्ष: भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं हो रहा। नहीं करना अंकित।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने अजमेर जेल में जो समझौता किया उसमें इस परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के रेगुलाइज को अलग करने के लिए प्रथम चरण का रेगुलेशन चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ के पास रहेगा और द्वितीय चरण का रेगुलेशन चीफ इंजीनियर, जैसलमेर के साथ रहेगा यह आपने उस समझौते में किया और वह इसलिए किया कि दोनों चरणों में फसल की किस्म अलग-अलग है, बुवाई का समय अलग-अलग है और इसलिए उस पानी का सदुपयोग हो सके इसलिए वहां के किसानों की संघर्ष समिति और व्यापारी संघर्ष समिति के साथ आपने दोनों चरणों का रेगुलेशन अलग-अलग करने का समझौता किया था। क्या आपने इनका रेगुलेशन आज तक भी अलग नहीं किया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों खड़े हो? मंत्रीजी, आप क्यों खड़े हो गए बीच में।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न है कि आपने समझौते में रेगुलेशन अलग-अलग करने का समझौता किया था एवं आज की तारीख तक भी आपने उस समझौते को लागू नहीं किया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने 48 हजार हैक्टेयर जमीन इस साल और प्रस्तावित है सिंचाई के लिए खोलने का, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस 48 हजार हैक्टेयर भूमि इस साल सिंचाई के लिए खोलेंगे, इसके लिए अतिरिक्त पानी की कोई व्यवस्था की है या इन्हीं किसानों की, जहां पानी के लिए मारामारी हो रही है उसी पानी में से काटकर इनके लिए सिंचाई की सुविधा करेंगे। यह जो आपने दिया है मैं समझता हूं 2005-6 में इस डेम की फुल केपेसिटी इनफ्लो भी थी और आपने 6.21 एम.ए.एफ. पानी लिया है जब कि राजस्थान का हिस्सा 8.6 एमएएफ है, उसकी बजाए आपने केवल 6.21 एम.ए.एफ. ही लिया है। यह राजस्थान के हिस्से में, जबकि इसमें वह पानी भी है जो आखिरी पिलाई के लिए आपने पंजाब से दो... (व्यवधान) लिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण न दें, प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल..

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें। मिस्टर भाटी, जवाब आने दें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी का बंटवारा जमीन के आधार पर होना चाहिये। जितना रकबा जमीन फर्स्ट फेज में है तो उस हिसाब से पानी का बंटवारा आना चाहिये। सैकण्ड फेज में जितना बीघे, जितना एकड जमीन है जमीन के हिसाब से पानी मिलना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बढ़िया। मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): धोद से आने वाले सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, नोर्थ चीफ इंजीनियर और जैसलमेर चीफ इंजीनियर दोनों जगह यह रेगुलेशन, माननीय सदस्य सारे उसके मैम्बर हैं वहां पर जाकर होता है, वह ही उसका नियंत्रण करते हैं। समझौता है हमने उसकी पालना कर दी है उसकी प्रति अगर आपको नहीं मिली, हालांकि हमने अख़बार में भी... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पानी का रेगूलेशन अलग-अलग करने की बात है। रेगुलेशन अभी भी आज की तारीख में एक ही है महत्वपूर्ण बात है कि अलग-अलग सिंचाई है..

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मेरी बात तो सुनिये, आप अपनी ही अपनी..

श्री अमराराम (धोद): अलग-अलग कर दिया क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप अपनी तो कह चुके हो।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सदस्य विधान सभा के सदस्य है, प्रधान है, प्रमुख है मैं इस बात पर नहीं जा रहा, आपने उनकी कमेटी की मीटिंग भी ली, मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं इस बात को पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): आपने रेगुलेशन अलग-अलग करने के लिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह है कि यहां कपास की बुवाई और वहां ग्वार की बुवाई होती है, वह अप्रैल में होती है, यह जुलाई में होती है और जो रेगुलेशन अलग-अलग चलते हैं, जब ग्वार की बिजाई नहीं होती जब कि द्वितीय चरण में जो आप पानी देते हैं..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): जैसलमेर में कपास नरमा होता है किसने कह दिया ग्वार होता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री सांगसिंह भाटी)

यह कहना चाहता हूं (व्यवधान) सैकण्ड फेज और फर्स्ट फेज यह कब बने, सैकण्ड फैज चालू नहीं हुआ, सैकण्ड फेज में नहरों में पानी नहीं चला, सैकण्ड फेज में अलाटमैंट नहीं हुआ, नहरें नहीं बनी, पहले था सैकण्ड और फर्स्ट। अब तो पूरी नहरें कम्प्लीट हो चुकी हैं, माइनर बन चुके। अब सैकण्ड फेज की लड़ाई यह राजस्थान में क्यों डाल रहे हैं?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें और भी निवेदन है, जब नहर का पानी लिमिटेड हो चुका है तो हम तो यह कहेंगे कि पानी पूरा नहीं हो रहा, तो नई-नई नहरें भी नहीं निकाली जानी चाहिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बिराजे तो सही। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने स्पष्ट कहा है, लिखित में भी बांटा हुआ है और लिखित में हमारे पास है, आदेश निकाला है, नोर्थ चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ वहां का रेगुलेशन जारी करता है और वह सारी चीजे, माननीय सदस्य उसके मैम्बर हैं वह उसके रेगुलेशन को देखते हैं, जैसलमेर वाला जारी करता है वह देखता है। मैं बार-बार कहूंगा तो भी आपको तो जो बात कहनी है वह तो कहेंगे ही। मेरी बात को भी समझने की कोशिश करे। सरकारें कोई समझौते करती हैं, अगर कोई लागू नहीं होता, यह पंजाब का और हमारा नहीं चल रहा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस हुआ। अगर आपको कहीं लगता है तो पधारो न, कोई मना थोड़े ही कर रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने समझौते को लागू कर दिया। दूसरा, यह कि पानी तो फिक्स है 8.6, अब आप सभी माननीय सदस्यों की भावना भी यही है, हमने सर्वसम्मति से यहां संकल्प भी पास किया, हमारे हिस्से का पाइंट सिक्स एमएएफ जो नहीं दिया जा रहा वह दिया जाए, इसके लिए आप सब का मैं सहयोग चाहूंगा। बार-बार हम लिखा-पढ़ी करेंगे, दबाव बनाएंगे, निश्चित रूप से 8.6 के आधार पर हमारा जो हिस्सा है वह रेस्टोर हो जाएगा, यह हमको प्रयास करना चाहिये, ज्यादा पानी मिलेगा।

दूसरा, यह तो स्पष्ट है कि जो पानी मिलना है वाटर अलाउंस जमीन के आधार पर तय है तो जैसे-जैसे एरिया डवलप होते जाएंगे उसी हिसाब से वह पानी आपको उपलब्ध होता जाएगा। अभी सैकण्ड स्टेज के एरिया में बहुत कम खाले और दूसरे सिस्टम डवलप होने हैं, तो यह काम लगातार चल रहा है, जैसे ही डवलप हो जाएगा पानी जो पोंग डेम में भराव और उसके बाद इनफ्लोज पर आएगा हिस्सा उसके आधार पर दे देंगे। यह 48 हजार हैक्टेयर

(श्री सांवर लाल)

जो भी है उसको भी पानी दिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, जो पानी उपलब्ध है उसमें से ही दिया जाएगा पानी तो, कोई नया बाँध तो आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अमराराम (धोद): इसमें काटकर देंगे, यह तो कह रहे हैं कि जो हिस्सा है...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): प्रश्न संख्या 213

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): किसी का हिस्सा नहीं कटेगा जब वाटर अलाउंस तय है तो, सबको अपना-अपना एरिया खुलता जाएगा उसके आधार पर पानी उपलब्ध होगा वह मिलेगा

श्री अमराराम (धोद): कहां से आएगा, काटकर देंगे?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): प्रश्न संख्या 213

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बाँध में से आएगा बता दिया न, घर में से थोड़े ही आएगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार यह बताए कि 8.6 एम.ए.एफ. केपेसिटी खड़ी कर दी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने केपेसिटी खड़ी कर दी, हम आरोप लगाते हैं (व्यवधान) दो चीजें हैं, नम्बर एक, क्या राजस्थान सरकार ने अभी तक 8.6 एम.ए.एफ. पानी यूटिलाइज करने की केपेसिटी पैदा कर दी ? नम्बर दो, आप जो पंजाब से पानी ले रहे है हम पानी ले रहे हैं वह 8 एम.ए.एफ. के आधार पर ले रहे हैं या 8.6 एम.ए.एफ. के आधार पर मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, आप बैठो तो सही, मैं देता हूं जवाब।

श्री अध्यक्ष: काहे को बोल रहे हैं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य ने

(श्री सांवर लाल)

यह सवाल उठाया है। यह पानी लेने के लिये हम सक्षम हैं। यह आपकी सरकार के टाइम भी लिखा है और हम भी ले सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वही तो हम कह रहे हैं न।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आज अगर पानी मिल जाता है तो हम पानी का उपयोग कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दूसरा यह है कि पानी जो मिल रहा है, वह 8 एम.ए.एफ. के हिसाब से मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): प्रश्न संख्या 213 ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही तो कह रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक राजस्थान को पानी 8 एम.ए.एफ. के आधार पर मिल रहा है, 8.6 एम.ए.एफ. के आधार पर नहीं मिल रहा है। हमारी मांग यह होनी चाहिए कि 8.6 के आधार पर पानी मिले तब 40 हजार हैक्टेयर की बात करें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसके लिये मैंने आप सब का सहयोग मांगा है कि आप सब सहयोग करें। भारत सरकार पर दबाव हम बनाएंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो यह तो आप मांग ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेन मुद्दा यह है कि राजस्थान सरकार को 8 एम.ए.एफ. के आधार पर ही पानी मिल रहा है जब कि हमारी पानी की मांग 8.6 एम.ए.एफ. के आधार पर करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप जैसे विचार आपके नेताओं के नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कैसे नहीं हैं? (व्यवधान) आपके 3 साल हो गये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे नेताओं के नहीं हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, सरकार को फिर निवेदन करना चाहते हैं, हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। फिर निवेदन करना चाहता हूं, आज भी सरकार का स्टेण्ड यह होना चाहिए कि हमें 8.6 एम.ए.एफ. के आधार पर हमें पानी मिलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम सहमत हैं। हम स्वागत करते हैं आपकी बात का। करो न संघर्ष। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): कांग्रेस के राज में किसानों को बिलकुल पानी नहीं मिला। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 3 साल से बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कांग्रेस के राज में पानी बिलकुल नहीं मिलता था पहले तो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पंजाब सरकार पानी लेकर बैठी हुई है, ये बोलते नहीं कुछ भी। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कांग्रेस के राज में किसानों को पानी बिलकुल नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम स्वागत करते हैं जोशी साहब, आपकी बात का। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण अब 8.6 एम.ए.एफ....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): XXX

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): XXX

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक मिनट, 3 साल से क्या किया, यह भी मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं। यह मामला 3 साल का नहीं है। माननीय सदस्य, 1981 में जो समझौता हुआ उसके बाद में हिस्सा डिसाइड होने के बाद सरेण्डर हुआ। मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उसके बाद में बराबर दबाव बना रहे हैं। चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब आप किस तरीके से चाहते हो? (व्यवधान) सरकार सरकार होती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): XXX

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): XXX

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, यह जो मोटी किताब आपको दिखा रहा हूं, यह पंजाब और राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। यह भारत सरकार के स्तर पर बैठक हुई है, वहीं पर यह निर्णय हुआ है। (व्यवधान) आप सुनिये, आप सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): भारत सरकार को लिखा जाए कि भारत सरकार इंटरविन करे और राजस्थान को हिस्सा दिलाये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सरकार कांग्रेस की थी। (व्यवधान) राजस्थान के हिस्से के लिये भारत सरकार को इंटरविन करना पड़ेगा। भारत सरकार का निर्णय था। तत्कालीन मंत्रीजी के लेवल पर यह निर्णय हुआ था, सरेण्डर करने का, इसलिये भारत सरकार हस्तक्षेप करे और राजस्थान का 0.6 एम.ए.एफ. का हिस्सा दिया जाए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): XXX

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीजी, (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, टोडरायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण करें। क्वेश्चन-आवर, प्रश्नकाल इंफार्मेशन सीक करने के लिये होता है। आरोप-प्रत्यारोप करने के लिये बहुत समय है। आपको आगे भी मिलेगा, जब आप आरोप-प्रत्यारोप एक-दूसरे पर लगाते हैं। यह प्रश्नकाल जो है केवल इंफार्मेशन सीक करने के लिये होता है। इसलिये जो इंफार्मेशन इनके पास थी, वह उन्होंने दे दी। आरोप-प्रत्यारोप इस समय नहीं होना चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): XXX

श्री अध्यक्ष: No, no, next question. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): XXX

श्री अध्यक्ष: Please sit down.

कोटपूतली की क्षतिग्रस्त/शोल्डर रहित सड़कें

213. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां से, कब से व कितनी क्षतिग्रस्त हैं या उनके दोनों ओर के किनारे टूट चुके हैं? मय चेनेज प्रत्येक सड़क की लम्बाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राज्य में नई सड़कों के निर्माण के समय डामरीकृत सीमा के अलावा सड़कों के दोनों ओर शोल्डर निर्माण की नीति बनाई गई है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पाँच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितनी नई सड़कों का निर्माण हुआ और उनके शोल्डर नहीं बांधे गये, जिस कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गईं? ग्रामवार किलोमीटर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पूर्व में बनी सड़कों के शोल्डर नहीं बांधे गये थे, जिस कारण सड़कों के दोनों ओर काफी गहरे गढ्ढे हो गये और आये दिन दुर्घटना घटने का अंदेशा बना रहता है? क्या सरकार उन सभी सड़कों के शोल्डर बांधकर यातायात सुगम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि पिछले पाँच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सड़कों के पुनर्निर्माण में ठेकेदार को ठेका देते समय सी.सी. या डामरीकृत क्षेत्र के अलावा सड़कों के दोनों ओर शोल्डर बांधे जाने की शर्तें भी शामिल की गई थीं। यदि हां, तो उक्त वर्षों में कितनी सड़कों का, कहां-कहां पर, कितनी दूरी तक पुर्ननिर्माण हुआ तथा किन-किन सड़कों के शोल्डर नहीं बांधे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार संबंधित ठेकेदार जिसने पुनर्निर्मित सड़कों के शोल्डर नहीं बांधे, जिसके कारण सड़कें पुन: क्षतिग्रस्त हो गई, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

(7) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क, कटे हुए किनारों को सही कराने व पुन: सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बाई, क्षतिग्रस्त भाग, टूटे किनारों की स्थिति मय चेनेज व कब से क्षतिग्रस्त है, इसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) नई सड़कों के निर्माण के समय डामरीकृत क्षेत्र के अलावा सड़कों के दोनों ओर शोल्डर निर्माण किया जाना आवश्यक है। शोल्डर निर्माण की कोई अलग से नीति नहीं है। यह शोल्डर निर्माण सड़क का एक आवश्यक भाग है।

(3) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ऐसी कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है जिसमें शोल्डर नहीं बनाये गये हों। गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 38 नई सड़कों (32 सड़कें सा.नि.वि. द्वारा व 6 सड़कें राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा) का निर्माण किया गया है। इन सभी सड़कों पर शोल्डर का निर्माण किया गया है।

(4) जी, नहीं। पूर्व में पुरानी निर्मित सभी सड़कों के निर्माण के समय मिट्टी के शोल्डर बांधे गये थे। यातायात के दबाव एवं कई वर्षों की बरसात के कारण कुछ सड़कों के शोल्डर डामर सड़क से नीचे हो गये हैं जिनमें ग्रेवल के शोल्डर निर्माण कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हैं।

(5) जी, हां। पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की 26 (सा.नि. विभाग द्वारा 13 सड़कें व रा.रा. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 13 सड़कें) सड़कों के पुनर्निर्माण (नवीनीकरण) का कार्य मय शोल्डर बांधे जाने सहित किया गया। इन सड़कों के नाम, नवीनीकरण, लम्बाई मय चेनेज परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है। गत 5 वर्षों में ऐसी कोई सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया जिसमें शोल्डर नहीं बांधे गये हों।

(6) जी, नहीं। ठेकेदार द्वारा सभी पुनर्निर्माण सड़कों के साथ शोल्डर का कार्य भी किया गया है।

(7) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विवरण परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है जिसमें क्रम संख्या 1 से 4 तक के कार्य आर.एम.यू.पी. फेज तृतीय में स्वीकृत हैं तथा कार्य प्रगति पर हैं क्रम संख्या 5 व 6 के कार्य नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ.-XII में स्वीकृत हैं। जिसकी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। क्रम संख्या 7 पर पावटा-नारेडा सड़क पर कि.मी. 0/0 से 7/0 तक सुदृढीकरण व नवीनीकरण कार्य आर.आई.डी.एफ.-XII में स्वीकृत हैं तथा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। सभी स्वीकृत/प्रगतिरत कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण होना सम्भावित है। शेष सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क, कटे हुए किनारों को सही करने व पुन: सड़कों का डामरीकरण कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सड़कों के दोनों तरफ बांधे जाने वाले शोल्डर केवल मिट्टी के बांधे जाते हैं या ग्रेवल के बांधे जाते हैं या ईंटों से बाँध कर उनको किया जाता है?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आपने जवाब में परिशिष्ट 'ब' में लिखा कि ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जिसके शोल्डर नहीं बांधे गये। मैं यह बताना चाहता हूं कि फेज- 2003-04, 2004-05, 2005-06 में जितनी भी सड़कें बनीं और जितनी भी पुनर्निर्मित सड़कें हुई उनके किसी के शोल्डर नहीं बांधे गये। आपने जो जानकारी दी है, यह जानकारी बिलकुल गलत है और निश्चित रूप से आप मौके पर अब देखेंगे इसकी स्थिति तो वास्तव में आपको यह पता लगेगा कि एक भी सड़क शोल्डर बांधी हुई नहीं है तो आप कृपया, यह बताने की कृपा करें कि क्या इन सड़कों की स्थिति जो खराब है। इन सड़कों की जो स्थिति खराब है उस खराब स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है और सड़कों के दोनों तरफ जो शोल्डर बांधने की स्थिति है वह ग्रेवल या मिट्टी की है? यह बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में पहले ही कहा है और माननीय सदस्य को जो परिशिष्ट 'ब' उपलब्ध कराया है उसमें जिन सड़कों का जिक्र आपने किया है, जो नवीनीकरण और उन्नयन का कार्य जिनमें 2002-03 से जो शुरू हुआ है, उसमें भी लिखा है कि मिट्टी की पटरी बनायी गयी है। यह शोल्डर माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के भी बनाये जाते हैं और ग्रेवल के भी बनाये जाते हैं। जिन सड़कों का जिक्र आपने किया है, जिनका रिन्यूवल किया गया है उनमें सड़कें, सड़क पर मिट्टी के शोल्डर बनाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन सड़कों का आपने जिक्र किया, वहां इन दिनों के अन्दर कुछ ऐसे प्लांट लग गये और कुछ ईंट के भट्टे लग गये कोटपूतली क्षेत्र में पावटा से नारेड़ा, दूद्वावास इन सब पर हरियाणा बोर्डर तक माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 बजरी के प्लांट लग गये और 9 स्टोन क्रेशर लग गये इनके कारण से यातायात का दबाव बढ़ा और यातायात के दबाव के बढ़ने के कारण से यह जो मिट्टी के शोल्डर, जो हमने यह पटरियां बांधी थीं इनके अन्दर निश्चित तौर पर नुकसान होना स्वाभाविक है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी हैं, उन सड़कों का आप कहो तो मैं एक-एक सड़क का जिक्र कर दूं, अधिकांश सड़कों को हमने रिन्यूवल में भी ले लिया है और जहां शोल्डर जिनके खराब हैं, उनके भी निश्चित तौर पर हमारे संसाधन को देखेंगे, चूंकि मिट्टी की पटरी है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ग्रेवल बनायी नहीं गयी थी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उस पाँच साल में तो जो बनी है सड़कें, उनके तो आपने शोल्डर बनाये हैं। उसके डामरीकरण का काम हुआ तो ... (व्यवधान) वे तो पाँच ही साल की पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ग्रेवल के। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002-03 में ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): यही मैं कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पिछले तीन साल में या पाँच साल में जो सड़कें निर्मित हुई हैं उनमें ग्रेवल के शोल्डर बनाये जाने चाहिए थे जो नहीं बनाये गये और हालत यह हो गये कि वहां पर डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट के गड्ढे सड़क के दोनों तरफ हैं। चौकी गोरधनपुरा से राजनोता सड़क जो जा रही है, एक परावपुरा से पाछुड़ाला सड़क जा रही है, पावटा से नारेड़ा सड़क जा रही है, इन सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है और उसमें ग्रेवल के शोल्डर नहीं बनाये गये हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि आप मिट्टी ही मिट्टी के शोल्डर की बात कह रहे हैं इसमें ग्रेवल के शोल्डर बनाये जाने चाहिए थे जो नहीं बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: जानकारी कर लीजिए। जानकारी कर लीजिए, क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह सड़कें बनीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नयी सड़कें बनती हैं। माननीय सदस्य जिन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं इन सड़कों का नवीनीकरण किया गया था 2002-03 में भी किया गया, 2003-04 में भी किया गया और अब भी किया गया। जो नवीनीकरण जिन सड़कों का किया उनका पहले जिनके शोल्डर बन गये थे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर आप तो जवाब में दूसरी बात कह रहे हो। इन्होंने प्रश्न भी नई सड़कों का पूछा है और आपने जवाब भी नई सड़कों का दिया है, माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, दिया है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पाँच वर्ष की सड़कों का जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष: हां, तो पाँच वर्ष में आपका भी योगदान है। आपका भी था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो पाँच वर्ष में दो केटेगरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पाँच वर्षों के अन्दर जो 26 नई सड़कें बनी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके तो शोल्डर ग्रेवल के बने हैं और इन्हीं पाँच वर्षों में जो पुरानी सड़कें थीं, जिनका नवीनीकरण हमने किया है उन सड़कों के शोल्डर पूर्व में मिट्‌टी से बने हुए थे और उनमें कोई क्षतिग्रस्त हो गये हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी न किसी योजना में लेकर उन शोल्डर को हम ठीक करवा देंगे और प्राथमिकता भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या?

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या पूछना चाहते हो? शोल्डर की बात कह दी मंत्रीजी ने। नो-नो।

श्री सुरेश मीणा (करौली): बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): मेरे एरिया में जो सड़कें बन रही है उनमें भयंकर घोटाला हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि हमारे एरिया में जितनी भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो इनका कहा हुआ। मैंने नेक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। नो-नो, नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुरेश मीणा (करौली): XXX

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। करौली से आने वाले माननीय सदस्य, करौली का सवाल नहीं है यह। करौली का सवाल नहीं है, आप विराज जाएं। करौली का सवाल नहीं है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुरेश मीणा (करौली): XXX

श्री अध्यक्ष: ... (व्यवधान) फिर मतलब क्या हुआ इसका? क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: आप कृपया, स्थान ग्रहण कर लें। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। आप एक बार स्थान ग्रहण कर लें। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

करौली का सवाल नहीं है, माननीय सदस्य। यह तो कोटपूतली का

(श्री अध्यक्ष)

सवाल है। उन्होंने कह दिया। वे संतुष्ट हो गये। प्रश्न काल सूचना प्राप्त करने के लिए होता है, उन्होंने कर ली और अब आप स्थान ग्रहण कर लें, प्लीज।

प्रश्न संख्या-214

श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

ब्यावर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण

215. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड रिक्त है? यदि हां, तो कितने व किस माप के और कहां-कहां?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक?

(3) क्या यह सही है कि प्रस्तावित रीको क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इसे हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) रीको औद्योगिक क्षेत्र ब्यावर द्वितीय चरण में एक भूखण्ड एवं तृतीय चरण में 6 भूखण्ड रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, हां। ग्राम नरबदखेड़ा में आबंटित राजकीय भूमि का कब्जा रीको को प्राप्त होने के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना सम्भव होगा।

(3) जी, हां। अतिक्रमण वाली भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि का कब्जा दिलाने एवं अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन को निगम ने निवेदन किया है।

(4) जी, हां। रुपये 128.41 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। रुपये 48.91 लाख के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं और इन्हें दिनांक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

30.06.2007 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। शेष कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाकर दिनांक 31.07.2007 तक सम्पूर्ण सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो रीको को आबंटित भूमि है उस पर यह अतिक्रमण कब से है और यह अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए अब तक कितने प्रयास हुए और इस अतिक्रमण के हटने में कोई सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? यदि यह हटेगा तो कितना समय और लगेगा, इसके बारे में मंत्री महोदय थोड़ा बता दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम नरबदखेड़ा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 727 की 62 बीघा 17 बिस्वा, 10 बिस्वा का आबंटन राज्य सरकार ने दिनांक 23.04.1996 में किया। इस भूमि की प्रिमियम राशि भी जमा दिनांक 23.09.1996 को करा दी। उसके बाद भूमि का अतिक्रमण नहीं हटने के कारण आज तक भूमि का कब्जा रीको को नहीं दिया गया है। 1996 से लेकर इस वर्ष के अन्त तक बीसों पत्र लिखे हैं, बीसों बार अधिकारी भी वहां पर गये हैं। अभी 14 तारीख को भी गये थे लेकिन प्रशासन वहां पर क्योंकि भीड़ अधिक एकत्रित हो गयी थी और वे अतिक्रमी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसलिए भीड़ आस-पास से एकत्रित कर लेते हैं। छितरे हुए मकान हैं। छितरे हुए हैं एक अगर लाट में हो, एक साथ हो तो हम उसको अलग अलाट करके भी दे दें। प्रशासन को, हमने यह भी कोशिश की है कि इतना एरिया छोड़कर बाकी शेष जमीन दे दें तो उसमें कम से कम विकास कार्य हम आरम्भ कर दें। बार-बार इनकम टैक्स डिपार्टमैंट को भी कमिटेड लायबिलिटी या प्रस्तावित खर्च के आधार पर दिया जाना, यह भी परेशानी का सबब है। इसमें यदि अगर आप लोग भी मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं इसको जल्दी से जल्दी इस अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में विकास कार्य करके समर्पित कर दूंगा।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 1996 से यह आबंटित भूमि है।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि केवल 6 भूखण्ड ब्यावर में रीको के अंदर रिक्त हैं और ब्यावर के अंदर कम से कम 50 यूनिट वूल की आने को तैयार हैं और कोई क्षेत्र है नहीं तो जब तक यह कब्जा नहीं हटेगा तब तक सरकार कोई नया रीको क्षेत्र डवलप करने का विचार नहीं रखती है, यह कब्जा 1996 से चल रहा है। यह कब्जा जब हट भी जायेगा और माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो कब्जा है उस जमीन को छोड़कर, यदि वह कब्जा 20-25 बीघा में कब्जा है और यदि वह 20-25 बीघा कब्जा छोड़ दिया तो बाकी शेष बचेगा क्या ? उसमें रीको का क्या डवलप हो जायेगा ? इसलिए माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि कोई नया रीको डवलप करने के बारे में कोई कार्य योजना है या नहीं ?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कई जगह डिफिकल्टीज आती हैं और लैण्ड कोस्ट बढ़ने के कारण वास्तव में डिफिकल्टीज हैं । रीको को और इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, नई जमीन के प्रस्ताव हम जिलाधीश को भेजकर इस पर अतिशीघ्र कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से मंत्रिमण्डल के सदस्य द्वारा संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के संबंध में।

   उपरोक्त प्रस्ताव अनुमान पर आधारित है। प्रस्ताव में पीड़ितों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का भी उल्लेख है। नियमों के तहत स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से ऋषभदेव पुलिस फायरिंग में मरे आदिवासी को दी गयी सहायता राशि में भेदभाव के संबंध में।

   प्रस्ताव में उल्लेखित विषय पर इसी सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2007

(श्री अध्यक्ष)

को पर्ची के माध्यम से विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, अतः मैं इस पर पुनः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, अब आपने रूलिंग दे दी अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: सुनिये, जब तब आसन पांवों पर है, तब तक कृपया बैठें। उसके बाद यदि आपको कुछ कहना है तो आसन पांवों पर न रहे, तब आपको कहने का अधिकार है। कृपया करके बीच में न खड़े हुआ करें।

3. श्री अमराराम धोद, एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से रावला एवं अनूपगढ़ पुलिस द्वारा किसान आन्दोलन के नेताओं के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट की कार्यवाही के संबंध में।

घटना कब की है, इसका प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि यह बहुत पुरानी घटना है रिसेंट, प्लीज डोंट स्टेंड। यह घटना बहुत पहले की है।

श्री अमराराम (धोद): ना-ना, घटना पहले की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नियमों के तहत ... (व्यवधान) फिर, नो-नो, बीच में नहीं बोलेंगे आप। बीच में नहीं बोलेंगे। ...(व्यवधान) नो-नो । आप बैठ जायें। उसके अलावा स्थगन प्रस्ताव की परिधि में भी नहीं आता है, लेकिन कल आपको पूरा मौका मिला था पुलिस की डिमाण्ड पर इन सब बातों को उठाने का, तब आप क्यों नहीं बोले? अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत सूरजगढ़ में चल रहे अकाल राहत कार्यों के भुगतान में सरपंच द्वारा अनियमितता करने के संबंध में।

सदन में 3 अप्रैल को इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी और माननीय सदस्य को उस समय बोलने का निश्चित तौर पर मौका दिया जायेगा। अतः अनुमति देने में अमसर्थ हूं।

5. श्री बी. डी. कल्ला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल के ग्राम जालनियासर में एक बी.पी.एल. परिवार दम्पत्ति की भूख से मौत के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजा जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर अग्रेत्तर इस पर विचार किया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री भरत सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्यों में अवैध शिकार, खनन व सुरक्षा के अभाव में वन्यजीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा तो नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री भरत सिंह को दो मिनट बोलने का मौका दिया जायेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम की सीमा बढ़ाने के संबंध में ।
2. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील फागी में बिजली का 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के संबंध में।
3. डा0 चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से तहसील तारानगर में 'आपणी योजना' में बड़े गांवों को घर-घर पानी कनेक्शन देने के संबंध में।
4. श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से तहसील सूरतगढ़ के गांव संगीता एवं पांच एस डी आई में आई सेम से निजात दिलवाने के संबंध में। गांव का नाम संगीता है क्या, कमाल है।
5. श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के सेशनल मार्क की व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में।
6. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से नगरपालिका निवाई द्वारा भूखण्ड आबंटन हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को भूखण्ड देने के संबंध में।
7. श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से खान विभाग के निदेशक द्वारा मैसर्स बृजेन्द्र मिनरल्स के खिलाफ रायल्टी चोरी की डिमाण्ड को खत्म कर देने के संबंध में।
8. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन करने के संबंध में।
9. श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल का संकट होने के संबंध में।

10. श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से कोटपूतली को जिला बनाने के संबंध में।

11. श्री लालचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से गंगनहर में बुर्जी संख्या 31 से 205 को पक्का करने के संबंध में।

12. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से परबतसर में नया पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देकर सदन इन्हें पढ़ा हुआ मान लेगा, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है। श्री भरत सिंह।

(विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

रावला एवं अनूपगढ़ पुलिस द्वारा किसान आन्दोलन के नेताओं के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह पुरानी घटना नहीं है। यह सोमवार को घटना हुई है। सोमवार को एक पंचायत समिति का मैम्बर, मैंने लिखकर दिया है राजू जाट, यह सोमवार को हुई है। मुझे मंगलवार के बाद बुधवार को कल मुझे यह सूचना मिली है तो मैं कल गृह मंत्रालय की मांग पर मंगलवार को कहां से बोल लेता ? यह घटना सोमवार की है। मुझे बुधवार को पता लगा है । अध्यक्ष महोदय, मंगलवार को तो गृह मंत्रालय की मांग थी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है । आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन मुझे बुधवार को ही सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष: आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मेरी व्यवस्था यह है। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति का मैम्बर है जिसको जुडिशल करने के बाद ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने अकाल राहत के बारे में मुझे बताया ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं यह कहना चाहता हूं अकाल राहत के बारे में नहीं बोलना चाहता, फर्जी मस्टरोल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) आपने जो लिखकर दिया है ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हो सकता है घटना की तारीख...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने कहीं नहीं लिखा है कि घटना रिसेंट अकरेंस की है। यह कहीं नहीं लिखा। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): तारीख नहीं लिखी होगी, लेकिन घटना सोमवार की है। मुझे बुधवार को पता लगा है। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : प्रतिपक्ष के भी हैं, सत्ता पक्ष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको यह विशेषाधिकार किसने दिया कि जब चाहे आप खड़े हो जायें, आपको यह विशेषाधिकार किसने दिया ?

श्री सी. डी. देवल : नहीं सत्ता पक्ष का है ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्या आसन के खड़े होने पर हमारे पर ही प्रतिबन्ध है? सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं कह रही हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे कह रही हूं आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सी. डी. देवल : आप हमें तो कह रहे हैं उनके लिये भी कोई व्यवस्था करिये। आसन की बात तो निष्पक्ष होनी चाहिये। प्रतिपक्ष को तो कह देते, आसन पैरों पर है और सत्ता पक्ष कैसे घूम रहा है? ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था । मैं अकाल के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अकाल राहत में गड़बड़ी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है। ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री अध्यक्ष: पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, क्या तकलीफ है ? क्यों खड़े हैं आप ? आसन बैठे तब आप बोलियेगा ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, क्या आपसे अपने जिले का आदमी भी नहीं सम्भलता?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आपने यह कहीं नहीं लिखा है और आपने यह लिखा है...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री अध्यक्ष: क्या फर्माया?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री अध्यक्ष: कई सदस्य पहली बार आये हैं, इन माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए गलती कर जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी कभी नहीं करते हैं यह गलती।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं भी नहीं करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो कभी-कभी कर जाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: आसन की व्यवस्था सब के लिए है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: सब के लिए है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: ऐसा है खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है इसलिए जब आप रोज यह काम करते हो तो कभी-कभी यह भी कर लेते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री अध्यक्ष: सुनिये। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। आपने यह लिखा है ...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): XXX

श्री अध्यक्ष: नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, आपने यह लिखा है कि मैंने इसकी सूचना ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, सुनिये। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री अध्यक्ष: आपने लिखा कि मैंने इसकी सूचना गृह मंत्रीजी को दे दी तो गृह मंत्रीजी अपने आप इस पर कोई न कोई कार्यवाही करेंगें।

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री अध्यक्ष: क्यों लिख रहे हो? ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री अध्यक्ष: आज तो आसन व्यवस्था दे चुका है और कल आप लाइयेगा, वापस ले आइयेगा, कल आपको दो मिनट बोलने की अनुमति दे दूंगी। ऐसे आसन व्यवस्था नहीं बदलता है। नो, नो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए, वहां ले जाकर के थाने के अन्दर पिटाई करे, ऐसा आज तक बहुत कम देखने को मिला है और आपके गृह मंत्री होते हुए इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, यह तो बहुत अशोभनीय बात है।

श्री अध्यक्ष: और आपके नेता प्रतिपक्ष होते हुए हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको जानकारी करके और उसको खुलासा करना चाहिए। निर्वाचित जन प्रतिनिधि, पंचायत समिति का सदस्य है जिसके गोली लगी हुई है आन्दोलन में, उसको पकड़ कर ले गये और थाने में पीटा, डीवाई.एस.पी. की मौजूदगी में पिटाई हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, आप तो इस विषय को शायद आज दे पाये, मेरे को 17 तारीख को इसकी जानकारी जब मिली कि एक जुडिशियल कस्टडी में जेल से पेशी पर ले गये और रास्ते में ले जाकर उसको पीटा और फिर जेल में भर्ती कराया, इसके बाद उसका मेडिकल हुआ, उसके दस चोटें लगीं। मैंने तुरन्त क्राइम ब्रांच के एडिशनल एस.पी. जोधपुर को, उस एरिया में भी नहीं जांच रखी है, उसको जांच दी है।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं घटना प्रत्यक्ष जो कुछ भी देखा है और समझा है, उसने बहुत बड़ी भूल की है लेकिन मैं केवल इन्तजार कर रहा हूं, उनको मैंने सात दिन का समय दिया आप जांच देओ और उसमें जो भी सख्त से सख्त सज़ा, वास्तव में उसने नियमों की भारी अवहेलना की, जुडीशियल कस्टडी में जो व्यक्ति है और पेशी पर लाया और वापस भेजने के बीच में उसने उसके साथ जो पिटाई की है वो वास्तव में अपराध किया है, मैं कठोर से कठोर जो सज़ा, सारी जांच आने के बाद दूंगा। मैंने मेरा काम पहले ही कर लिया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव पर ...

श्री अध्यक्ष: अब आप काहे को?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान का गृह मंत्री कन्विस्ड है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, आप कठोर से कठोर सज़ा क्या देंगे, आप बरखास्त तो कर नहीं सकते, आपकी कलम में तो सस्पैण्ड करना है।

जब आप, राजस्थान का गृह मंत्री सैटिस्फाइड है और कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो आप समझते हैं ज्यादती हुई है, उसके बाद में उस पर एक्शन नहीं होगा? यह तो बड़े दुःख की बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष: तो जांच रिपोर्ट तो आने दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): रिपोर्ट आ जायेगी, पता है न उनको।

श्री अमराराम (धोद): एक नहीं यह डीवाई.एस.पी., माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा गृह मंत्रीजी को लेकिन जिस तरह से यह डीवाई.एस.पी. एक नहीं कर रहा है इसने रावला थाने में इससे पहले पिटाई, जो मैंने आपको कहा इनको नहीं, मेरे को साढ़े तीन घंटे तक इसी डीवाई.एस.पी. ने थाने में ले जाकर, राज्यासर थाने में साढ़े तीन घंटे तक, जिसका भी उत्तर गृह मंत्रीजी के माध्यम से आपके पास भेजा, बिलकुल असत्य है। इससे ज्यादा नाकारा डीवाई.एस.पी. नहीं हो सकता जो एक माननीय सदस्य के साथ कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको बुलाया, इसीलिए मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि जवाब यह आया है इसलिए आप मुझ से आकर मिलें, आप मिले तो नहीं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, मिला हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में। आपने चिट्ठी पढ़ी, मैंने बिलकुल आपके सामने यह बात रखी। साढ़े तीन घंटे तक माननीय सदस्य को नाजायज रूप से, कोई केस नहीं होने के बाद यही डीवाई.एस.पी. थानेदार ले जाकर के थाने में बैठाता है। आपको मैंने शिकायत की, आपने चिट्ठी दी, में आपके चैम्बर मैं आया। यही डीवाई.एस.पी. है निर्मल सिंह जो सरकार से और मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी से ऊपर हो गया, इस सदन से ऊपर हो गया। इस सदन के माननीय सदस्य को, कोई भी ऐसा केस हो तो मेरे को जेल में डाल दें, साढ़े तीन घंटे राज्यासर के थाने में, चार बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक, न-केवल मेरे को बल्कि मेरे को लाने के लिए दो व्यक्तियों को, जो ड्राइवर थे उनको नंगा करके तीन घंटे तक पीटा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है और वो डीवाई.एस.पी. आज भी वहीं बैठा है। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्य के साथ इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है?

श्री अमराराम (धोद): अब गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, गृह मंत्रीजी के कहने के बाद एस.पी. को मेरे सामने निर्देश दिये उसके बाद। जंगलराज हो रहा

(श्री अमराराम)

है। मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो यह कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने जो चिट्ठी लिखी थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, नहीं, आप एक बार बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): जब गृह मंत्रीजी अपने आप में सैटिस्फाइड हैं तो फिर जांच की जरूरत कहां है?

श्री अध्यक्ष: आपने जो चिट्ठी लिखी, मैंने गृह मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी और मैंने लिखा कि बहुत गलत बात है इस तरीके से। इनकी चिट्ठी मेरे पास वापस, पुन: आयी और इन्होंने लिखा कि वो अपनी मर्जी से बैठे थे। ...(व्यवधान)

सुनिये तो सही, अब आप कह रहे हैं यह बात लेकिन जो आयी कि वो अपनी मर्जी से बैठे थे। गृह मंत्रीजी की तरफ से यह चिट्ठी आए तो मैं तो यही मान कर चलूंगी कि आप अपनी मर्जी से बैठे थे। इन्होंने कहा कि हमने उनको डिटेन नहीं किया, वो अपनी मर्जी से बैठे थे, हमने उन्हें वहां चाय पिलायी है और वो अपने थाने में बैठे रहे दो-तीन घंटे। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आपसे मिलना चाहिए अगर इनको एतराज था तो। आपने जब इतना प्रयास किया तो आपसे आकर मिलते यह। आकर कुछ कहते।

श्री अध्यक्ष: नहीं, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी थी। ...(व्यवधान) यह मैंने गृह मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हर चीज का राजनीतिक मुद्दा बनाना, क्या वास्तव में यह अपनी मर्जी से बैठे थे कि नहीं बैठे थे, यह तो इनको पता है। अगर इनको एतराज था तो आपको आकर कहते कि मैंने आपको प्रार्थना पत्र दिया।

श्री अमराराम (धोद): मिला हूं मैं चैम्बर में आकर, कह कर गया हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चिट्ठी लिखी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जांच अधिकारी रहा है उनको पूछो न जाकर के कि आप वहां से मन से बैठे हो कि कैसे बैठे हो। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): चैम्बर में आकर पूरी चिट्ठी को पढ़ करके इनको पूरी स्थिति बता कर गया हूं उसके बाद कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव को निरस्त किया और उसके बाद भी सहृदयता से गृह मंत्रीजी ने उठ कर सारी बात कह दी। इनको धन्यवाद देना चाहिए गृह मंत्रीजी को।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, धन्यवाद, गृह मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन राजस्थान की मुख्य मंत्री अपनी मर्जी चला रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): क्या जांच करने वाले व्यक्ति ने इनको पूछा कि यह स्वेच्छा से गये थे या इनको जबरदस्ती बैठाया? ...(व्यवधान) इनको पूछा क्या जाकर के? ...(व्यवधान) इनको पूछा क्या, आप कन्फर्म करिये उनको।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से मिल कर गये थे और वहां पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका थाना, जो आपके भूतपूर्व डी.जी. ने मन्दिर बताया था, वो मन्दिर क्या वहां बैठने के लिए है? क्या लोगों की चौपाल बना रखी है जो कोई भी वहां आकर बैठ जाए? आप कह रहे हो अपनी मर्जी से बैठे, थाने में जाकर मर्जी से बैठे?

श्री अध्यक्ष: आप इनसे मिलने गये क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किससे मिलने गया?

श्री अध्यक्ष: मिलने गये क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): दूसरे लोग, जो अरेस्ट थे उनके पास मिलने गये, उनके पास बैठे।

श्री अध्यक्ष: मिलने गये थे इनसे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलने जाने वालों को भी थाने से बाहर बैठाते हैं।

श्री अध्यक्ष: मिलने गये थे? एम.एल.ए. को, आप और वो जाएं तो थाने के बाहर नहीं बैठा सकते आपको, अन्दर ही जाने देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मिलने वालों को भी थाने के बाहर बैठाते हैं, जेल में मिलने वालों से भी जेल के बाहर बैठाते हैं।

श्री अध्यक्ष: जेल थोड़ी थी तो वो, वो तो थाना था। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, थाने मेरे आने के बाद नये गठित होकर के व्यवस्था लागू हमने नहीं की, जब से देश आजाद हुआ तब से थाने हैं। मन्दिर है या क्या है, आपने भी 42 साल तक उनको देखा है और मैं भी देख रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किस को?

श्री अध्यक्ष: थानों को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस पर अधिक विवरण करने से कोई लाभ नहीं है। थाने मन्दिर हैं या नहीं हैं, आप भी जानते हैं पर आप में से अभी मेरे पास 150 चौकियों की केवल बजट में स्वीकृति मिली। और शायद मेरे पास चार सौ की तो आवश्यकता आ गयी कि मेरे यहां खोलो। अगर यह मंदिर नहीं हैं तो फिर इनको खुलवाने की जरुरत काहे को महसूस करते हैं? कोई न कोई कारण होना चाहिए। पुलिस की उपस्थिति से थोड़ा बहुत उनको संतोष होता है इसलिए मांगते हैं। इसलिए थानों को मंदिर कहकर के हमने कोई पाप नहीं किया। यह मंदिर देश की आजादी के साथ ही बने हुए हैं और वहां बाहर लिखा हुआ बोर्ड है, हमारे योग्य कोई सेवा हो, वह मेरे टाइम पर नहीं लगा जब से है तब से है। क्या स्थिति है क्या नहीं है यह आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, उसका विश्लेषण करने की जरुरत नहीं है। यह 17 तारीख की घटना है, यह आज इस विषय को उठा रहे हैं। मेरे ध्यान में जिस समय आया मैंने उसी दिन इसके खिलाफ कार्यवाही की है और मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि जो घटना हुई क्योंकि जेल से ले जाकर पेशी पर लाना और पेशी पर वापस जाकर जेल में उसको जमा करा देना या उसको सुपुर्द कर देना यही काम है पुलिस का। इसके बीच में से अगर ले जाकर थाने पर पिटाई हुई यह बिलकुल तथ्यों से प्रमाणित हो रही है।

फिर भी मैं यह चाहता हूं क्योंकि डीवाईएसपी स्तर का व्यक्ति भी उसमें है, बाकी है तो सही रिपोर्ट आने के बाद, मैंने आपको पहले से एडवांस में कह दिया कि इस प्रकार के अपराध को न मैं क्षमा कर सकता हूं, न सदन क्षमा कर सकता है, न मेरा पुलिस डिपार्टमैंट इसको कोई अच्छा मानता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गलती हुई है मैं सोचता हूं कि मैंने एडवांस में आपके बिना कहे जांच पहले से ही एडिशनल एसपी जोधपुर को (क्राइम ब्रांच) को दे दी है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह उसके खिलाफ होगी। कहीं बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको कैसे पता चला कि उसके साथ ज्यादती हुई है, यह घटना हुई है, आपको कैसे पता चला ? राजस्थान के होम मिनिस्टर को यह कैसे पता चला कि उसको पीटा गया है? आपसे बड़ी एविडेंस और क्या होगी? आप विधान सभा के अन्दर एडमिट कर रहे हैं कि मैं कन्विन्स्ड हूं, उसको पीटा गया है फिर आप जांच करवा रहे हो? जांच करवाने से पहले सस्पैण्ड करो, उसके बाद जांच करवाओ ...(व्यवधान) हटाइये वहां से, उसको वहां रखकर के आप जांच करेंगे तो कौन एविडेंस देगा उसके खिलाफ, उसके खिलाफ बयान कौन देगा ...(व्यवधान) डीवाईएसपी के खिलाफ कोई बयान देगा ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको यह लगता है कि उसको वहां से हटाकर जांच की जाए तो आज ही वहां से हटाकर के जांच करा देंगे। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव के मजमून की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुन तो लीजिए अध्यक्ष महोदय। आपने व्यवस्था दी मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: क्यों सुन लूं? जब इस पर चर्चा हो चुकी है और नियम है कि जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा इश्यू दूसरा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: उस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरा इश्यू दूसरा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने जिन स्थगन प्रस्ताव को निरस्त फर्मा दिया उन पर भी माननीय सदस्य अगर बोलते चले जाएं तो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैं अध्यक्ष महोदय की जानकारी में ला रहा हूं उससे भी आप रोकोगे क्या? उससे भी आप रोकोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: क्या ला रहे हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: क्या सुनूंगी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद अगर आप निर्देश देंगे कि मैं नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी आदत पड़ गई है कि जिस विषय को, स्थगन प्रस्ताव को यहां पर अनुमति नहीं दें उस पर भी एक आपकी आदत पड़ गई है दुराग्रह करते हैं आप ...(व्यवधान) जो कुछ भी हो आपको बोलना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे एक महीने, एक तो अध्यक्ष महोदय ...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पढ़ लिया आपने।

श्री अध्यक्ष: आपका पढ़ लिया तो आपको मौका तीन तारीख को मिलेगा न।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): तीन तारीख को मिलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा घोटाला है आप देख लो, आप खुद ही कह देंगे।

श्री अध्यक्ष: तीन तारीख को मिलेगा तो मौका ...(व्यवधान) अकाल पर चर्चा उसी दिन है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अकाल राहत में गड़बड़ी है क्या? (व्यवधान) फर्जीवाड़े का काम किया है, फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूं मैं। मैं अकाल राहत की बात कर रहा हूं क्या? आप खुद ही देख लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपकी जानकारी में यह बात लाई है कि यह उस आदिवासी को जो पुलिस की गोली से मरा है ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीज रिकार्ड पर जा रही है। जिस विषय वस्तु पर स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया और आसन ने विचार करके उसको निरस्त कर दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब उसी पर अगर आप इनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं, मैं समझता हूं ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सारी चीज रिकार्ड पर जा रही है। आपने अनुमति निरस्त कर दी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपकी जानकारी में अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह ला रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: 8.3.2007 की जो कार्यवाही है ....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा पाइंट तो सुन लीजिए आप उसके बाद आप जो व्यवस्था देंगी मैं मान लूंगा। मेरा इश्यू तो सुन लीजिए आप। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आदिवासी को मुआवजा ...(व्यवधान) वही बात आपकी है ...(व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): जो मामला ठंडा हो गया है, ऋषभदेव में कोई विवाद नहीं है, फालतू काम की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सहायता राशि में भेदभाव की बात कर रहे हैं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): बिलकुल शांत हो गया, वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुश्किल से वह मामला ठंडा हुआ, उसको क्यों ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): XXX

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): XXX

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर आपने व्यवस्था दी है कि यह मामला पहले चिट के द्वारा उठाया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष: जी हां।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और सदन के अन्दर आ गया, इस पर दुबारा चर्चा नहीं कराई जाती है। यह बात सही है लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुबारा स्थगन प्रस्ताव आया तो आपको आपके आफिस से ही रिजेक्ट करके उनको सूचना दे देनी चाहिए थी। आपने यहां व्यवस्था दी।

श्री अध्यक्ष: दे दी ना और क्या दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, यहां आपको घोषणा नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: क्या नहीं घोषणा करनी चाहिए ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसको वहीं आप दफ्तर में ही, यहां तो वही बात आनी चाहिए जिसके बारे में हमें भी बोलने का अधिकार हो जाएगा क्योंकि आपने काग्नीजैंस ले लिया।

श्री अध्यक्ष: यह क्या नई व्यवस्था दे रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप नया सुझाव दे रहे हैं। आज दिन तक जो स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया जाता है और उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है। आज दिन तक यही परम्परा चली आ रही है और यही नियम है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब आप मानती हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है पर्ची द्वारा उसके बाद में आपको स्थगन प्रस्ताव नहीं मानना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था में यही तो लिखा है इसके अन्दर ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके आफिस को स्थगन प्रस्ताव नहीं मानना चाहिए था, आप अपने पास रिजर्व कर लेतीं।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा है जब ही तो पढ़कर सुनाया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): रिजर्व करने की महाराज परम्परा रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): XXX

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): XXX

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): XXX

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): XXX

श्री अध्यक्ष: कोई खास बात है कि आप खड़े रहेंगे? ...(व्यवधान) पहले मुझे सुनिये, पहले मुझे सुनिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): XXX

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है आपकी बात सुन ली।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): XXX

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): XXX

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सुन ली।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): XXX

श्री अध्यक्ष: मिस्टर जीतमल खांट, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण कर लें। पहले आप स्थान ग्रहण करिये। आसन से जो व्यवस्था दी जाती है उसके बाद उस पर किसी तरह की टिप्पणी और किसी तरह की चर्चा नहीं होती लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है आप मेरे वेश्म में आकर मुझसे बात करें। फिर कोई रास्ता उसका निकालने की कोशिश करते हैं बाकी इस तरीके से अध्यक्षीय व्यवस्था के ऊपर चर्चा करना और चर्चा के जरिये किसी प्रकार का आक्षेप लगाना उचित नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण को मैं एक बात कह रही हूं जो अनुशासन में नहीं रहेंगे और इस प्रकार से मर्जी आए जब खड़े होंगे मैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दूंगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री जयराम जाटव (खैरथल): XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री मदन लाल मेघवाल (जायल): XXX

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आपके माननीय सदस्य खड़े हैं पीछे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सब बैठ गये। हमारी पार्टी के अध्यक्ष, इस सदन के प्रतिपक्ष के भूतपूर्व नेता और इस सदन के अब माननीय सदस्य उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि जायल के अन्दर एक बीपीएल दम्पत्ती पति और पत्नी भूख से मर गये। वह स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने उसको राज्य सरकार के पास भेज दिया। मान्यवर, उसको इतना हल्का मत लो, लाइटली मत लो। यह हमारे लिये प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष के पास यह जानकारी आयी। कैसे भी आयी ... (व्यवधान)

श्री मदन लाल मेघवाल (जायल): XXX

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम यह मान कर चलते हैं कि वह सही है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): XXX

श्री जयराम जाटव (खैरथल): XXX

श्री अध्यक्ष: आप आसन का काम क्यों करते हो ? क्यों करने लग जाते हो ? प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष के पास अदरवाइज कोई इनफोर्मेशन है तो वह रख सकते हैं। अभी रख दो हम सुन लेंगे। अगर

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं है तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने, इस सदन के प्रतिपक्ष के पूर्व नेता ने यह बात रखी है उस पर वज़न दिया जाना चाहिये। सत्ता किसी की हमेशा दासी नहीं रही है। यह दासी आती जाती रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि डेढ साल बाद में आप सत्ता पक्ष में हो और यह इधर बैठने वाले इधर ही बैठे रहें। यह कोई सम्भावना नहीं है। कुछ भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रतिपक्ष के नेता 'सदा काहू की ना रही, चढ़ी इकरंग, कभी उजाला होत है, कभी होत बदरंग'

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी बात ठीक है अध्यक्ष महोदय। आपकी कही हुई बात तो कहीं प्रतिवाद का सवाल ही नहीं है। शिरोधार्य है लेकिन हमारे पक्ष को भी सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये तो कहा मैं। आपकी बात तो रखी उनको। नहीं तो है नहीं क्या आपको ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी पार्टी के अध्यक्ष और यहां माननीय सदस्य ने जिम्मेदारी के साथ में आपको प्रस्ताव दिया है कि भूख से मौत हुई है। अदरवाइज सत्ता पक्ष के पास सूचना है तो अध्यक्ष महोदय, पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष: सुनिये ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर नहीं है तो ....

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इसीलिये मैंने कहा राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार इसके बारे में कल कह देगी। पूरी सूचना तो एकत्रित कर लें ना। ऐसे ही एटरेंडम तो नहीं बोल सकते वह ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो रुटीन है।

श्री अध्यक्ष: आपने दिया है तो मैंने यही तो कहा है कि राज्य सरकार को भेजा है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में अगर आसन से आज्ञा भी हुई तो हमने उसी वक्त, राज्य सरकार ने उत्तर दिया है। आपने चूंकि इस पूरे प्रकरण की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार के पास नोटिस भेजा है। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मसले होते हैं जो पूरे राजस्थान को कलंकित करने वाले होते हैं। उनमें सत्यता हो मामला उठाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं पर इसी चीज में राजनीति करने का काम करें हम, अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति नहीं दी इसलिये मैं उसके तथ्यों की तरफ तो नहीं जाऊंगा पर मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके मुख से निकली हुई एक-एक चीज को राजस्थान के लोग विश्वास के साथ सुनते हैं, देखते हैं। अगर सत्यता नहीं निकली तो इस चीज की भी व्यवस्था होनी चाहिये कम से कम इस तरह के मामले के अन्दर कोई मामला उठे तो तथ्यों के साथ उठे। अध्यक्ष महोदय, तथ्य जो कह रहे हैं मैं जब आपके चैम्बर में जाकर कहूंगा, बताऊंगा तो आप स्वयं कहेंगे और अच्छा रहे सदन में इस चीज के आने से पहले आप चैम्बर में इनको भी बुला लें। हमें बुला लें। हम सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे। माननीय सदस्य जो वहां से निर्वाचित हैं वह अपनी बात रखेंगे उसके बाद अगर आप सदन में लाएं तो लाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। चैम्बर में आकर बात करें। आप भी आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मतलब राजस्थान को कलंकित करने की कोशिश करें हम राजनीति करने के लिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): XXX

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): XXX

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज सिट डाउन। यह सदन नियमों से चलता है। अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया चैम्बर में आइये। मैं सरकार को भी बुलाऊंगी, आप भी आइये। यह ऐसे गम्भीर यदि मामले हैं तो इनको इस तरीके से अब इस शोरगुल के अन्दर चर्चा करके क्या करना चाहते हैं ? इसका कुछ परिणाम आना चाहिये। बात की सत्यता पता लगनी चाहिये उसके बाद इसका इंतजाम होना चाहिये इसलिये मैं

(श्री अध्यक्ष)

आपसे पुन: निवेदन करूंगी नेता प्रतिपक्ष मैं आपके अब हाथ जोड़ रही हूं। अब आप आगे चलें। भरत सिंहजी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आप बहुत पुरानी इस सदन की माननीय सदस्य हैं। आपसे सीनियर यहां कोई नहीं है। आप 1952 में जब विधान सभा थी और 1952 में जो राजस्थान था आज वैसा नहीं है ...

श्री अध्यक्ष: नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज इनफोर्मेशन टैक्नोलाजी में जो तरक्की की है, विकास किया है। राजीव गांधी ने जो नया सिस्टम कायम किया देश के अन्दर वह ऐसा है कि हर चीज इंटरनेट से ले सकते हैं, फैक्स से ले सकते हैं। टेलीफोन से ले सकते हैं, वायरलैस से ले सकते हैं, होम मिनिस्टर के पास साधन नहीं हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: इसलिए तो वैश्म में बात कर रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके वैश्म में बुलाइये आप ...(व्यवधान) आप हमें भी बुलाइये।

श्री अध्यक्ष: यही तो कह रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): होम मिनिस्टर साहब को भी बुलाइये।

श्री अध्यक्ष: आपको तो जरूर बुलायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राहत मंत्री को भी बुलाइये और आपके चैम्बर में बैठकर के इस पर फैसला होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, बिलकुल। ठीक है, मान ली बात आपकी। आप बीच में न बोलें। श्री भरत सिंह।

राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में अवैध शिकार, खनन एवं सुरक्षा के अभाव में वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा

श्री भरत सिंह (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, जो 2 वर्ष पूर्व रणथम्भौर और सरिस्का में टाइगर्स की पोचिंग का प्रकरण उजागर हुआ था और राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित की थी। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट

(श्री भरत सिंह)

27.08.2005 को गवर्नमैंट को दी थी और मुझे भी सौभाग्य मिला था कि मैं इस टास्क फोर्स का एक सदस्य था। टास्क फोर्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे और एक उम्मीद बनी थी कि हमारे यहां के टाइगर्स की पोचिंग के बाद जब यह प्रकरण उजागर हो गया तो हमारा वन विभाग सतर्क होगा और इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि भविष्य में इस प्रकार के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनमें शिकारी की घटनाएं नहीं घटेंगी।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से इस रिपोर्ट को आये डेढ़ साल हो चुका है और जैसा कि इसके प्रथम पृष्ठ पर इसके चेयरमैन ने यह आशंका प्रकट की थी कि यह रिपोर्ट वन विभाग के कार्यालय या दफ्तरों में धूल खाती हैं। उसके अलावा इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह आशंका चेयरमैन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में प्रकट की थी और जैसी उनकी आशका थी वैसी की वैसी हकीकत में आज हो रही है। हमारे राजस्थान में जो सबसे अच्छे अभयारण्य थे उनके बारे में हाल ही में आडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है उसके 18 पेज, सिर्फ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों पर जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें जो कमियां हैं इनको समर्पित हैं। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। मुझे पता नहीं है कि वन मंत्रीजी ने इसका अवलोकन किया है कि नहीं किया। मगर 18 पृष्ठ की इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ वन्य जीवों की दुर्दशा पर आशंका है और यह हमारे वह नेशनल पार्क हैं जिसकी रिपोर्ट में प्राथमिकता है। अगर यह हालत नेशनल पार्क की है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जो 25 अभयारण्य हैं उनकी क्या दशा होगी। हमारे कुल फोरेस्ट एरिये का दस हजार स्कवायर किलोमीटर से कम एरिया फोरेस्ट का वन्य जीव संरक्षण विभाग के पास है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी के रूप में। अगर हम इस दस हजार स्कवायर किलोमीटर एरिये को भी यदि हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं, जो रिकमंडेशन गवर्नमैंट ने दी हैं उसके ऊपर बुनियादी अमल नहीं हो, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक जिसके बारे में रिकमंडेशन की है कि साल में दो बैठकें उसकी होना अनिवार्य है। शेर मर गये, टाइगर मारे गये। उसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रिक्रूटमेंट के संबंध में, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि बजट में उल्लेख किया है कि हम एक हजार रिटायर्ड

(श्री भरत सिंह)

फौजियों को जो फौज से थके हुए हैं वह आकर के हमारे वन्य जीवों की अभयारण्य में सुरक्षा करेंगे। फौजियों का उपयोग कोई बैंक के सामने बंदूक लेकर उसकी सुरक्षा के लिए तो किया जा सकता है मगर जहां वन विभाग में समस्या यह है कि जहां अवरेज फोरेस्ट गार्ड की एज 45 साल है और वह अपनी बीट में घूमने में सक्षम नहीं है। उसकी संख्या वहां कम है उसमें आप सिर्फ एक लाइन मेंशन कर दूं कि हम एक हजार रिटायर्ड फौजियों को सुरक्षा के लिए एम्प्लाई करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि वह आपके पास आयेंगे। जो आदमी फौज से थका हुआ है वह आपके यहां जंगल में घूमने के लिए क्यों आयेगा? बैंक में गार्ड के लिए तो चल सकता है और इसमें रिपोर्ट की जो रिकमंडेशन है वह यह है कि इन अभयारण्य के पास जो ट्राइबल लोग रहते हैं, इनके इर्द-गिर्द जो लोग-बाग़ रहते हैं उनमें से लोगों को फोरेस्ट में सर्विस में लिया जाये ताकि उनका इनवाल्व हो, उससे जो प्रताड़ित होते हैं, वन्य जीव जो बाहर निकलते हैं उनसे जो दुर्दशा होती है वह लोग सुरक्षा कर पायें।

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बतायें कि खनन तो कहां हो रहा है, आप यह बतायें कि अवैद्य शिकार में आपके बाघों की और दूसरों की कितना संख्या कम हो गयी है। यह है आपका विषय।

श्री भरत सिंह (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोटा सम्भाग से आता हूं। यह तीन दिन से दरा अभयारण्य के बारे में जिसको इन्होंने नेशनल पार्क घोषित किया है। उसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था, इन्होंने कहा कि यह मुकुन्दरा हिल नेशनल पार्क होगा। अगर गधे को शेर कह दें तो उससे वह शेर नहीं बन जायेगा। नेशनल पार्क का ग्रेडिएशन उसका कर दिया। मगर हो क्या रहा है उसके अंदर, उसके अंदर शिकार होकर के गोश्त पक रहा है। यह इसके प्रकरण दर्ज हैं। जो घड़ियाल सेंक्चुरी है उसमें एक घड़ियाल नहीं है। उसमें घडियाल का अस्तित्व खतम हो चुका है। अवैद्य खनन हो रहा है। पिछली बार जब वन विभाग पर चर्चा थी मैंने गिना है 70 माननीय सदस्यों ने अवैद्य खनन को उजागर किया था। वन मंत्रीजी आंख मीच लें और कहें कि वहां खनन नहीं हो रहा है। 500 करोड़ का इनका राजस्व 3-4 साल में बढ़ने का यह दावा कर रहे हैं। वह राजस्व कहां से बढ़ रहा है। वह पूरा वन क्षेत्र से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: उनका नाम लेते कि यह-यह हैं। जो कर रहे हैं वहां खनन।

श्री भरत सिंह (दीगोद): एक का बता दूं मैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बताओ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): वह जो भैंसरोडगढ़ में सेंक्चुरी के अंदर एक यहां सदस्य हैं जिनका उल्लेख अखबारों में आ रहा है, यहां के एक सदस्य हैं। उन्होंने उस सेंक्चुरी का एरिया दबा रखा है। एक का उल्लेख है उसी पर कार्यवाही कर लें, एक ही माननीय सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ करो वन मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, अगली पीढ़ी को अगर हमें जानवर दिखाने होंगे तो टेलीविजन पर ही देखेंगे। अगर इस प्रकार की दुर्दशा होगी। मैंने शुरू में ही आशंका प्रकट की थी कि एक वन मंत्री उसी का खनिज मंत्री बना देंगे तो यह बिलाऊ के सामने छोटी-सी चुहियां को रखने जैसा है। उसको चबा ही जायेगा यह और वह चबा गया, पूरे जंगल को साफ कर गया। पूरा जंगल इनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। इन्होंने कभी किसी जंगल को जाकर के देखा क्या? कभी कोटा गये? अभयारण्य की घोषणा कर दी। मैंने खुद ने कहा इस सदन के अंदर कि बहुत अच्छी बात करी कि आपने दरा अभयारण्य को बनाया है। कभी आकर के इन्होंने अभयारण्य को देखा है। उस अभयारण्य में पर्यटकों को ठगना है। दरा अभयारण्य की मैंने विधान सभा से रिपोर्ट ली है उसमें दस हजार तो गायें हैं और तीन हजार वन्य जीव बतायें हैं उसमें से दो हजार बंदर और पांच सौ मोर और उसके बाद पांच सौ दूसरे जानवर हैं। वह क्या देखने आयेगा। दस हजार गायें देखने आयेगा? इस प्रकार की स्थिति उसकी हो रही है और वन खनन पूरे राजस्थान में, धौलपुर में रियासत के जमाने का वन विहार था, यह वन मंत्रीजी, वन विहार में जहां क्रोकोडाइल फार्म है उसके बगल में ही स्टोन पार्क है। रहीम दासजी कह गये हैं कि कैसे निभेगा कैर, बैर का संग, यह तो कैर भी यहां है और बैर भी यहां है। इसमें से एक ही डाल तो काटें आप। मुझे कहना है कि वन मंत्रीजी को इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि या तो यह अपना इस्तीफा दें और या वनों को नष्ट होने से बचायें। मुझे आपने इजाजत दी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वन एवं जंगली जीवों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, सेंक्चुरी के बारे में और विभाग में हो रहे अतिक्रमण के बारे में बहुत ही

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

गम्भीर चिंता प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल पार्क सरिस्का में 1988 में सेंक्सेस की रिपोर्ट के आधार पर 45 बाघ थे। 1989 में जब सेंक्सेस हुआ 19 बाघ बताये गये। 1989 में जब 19 बाघ बताये गये, न तो एक अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच कमेटी बैठायी गयी ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई, ना कमेटी का गठन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि शिकार हुए हैं और यह शिकार की घटनाएं मात्र इन तीन सालों के कार्यकाल में नहीं, मात्र राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की घटनाएं हर नेशनल पार्क और सेंक्चुरी में हुई हैं जो दु:खदायी हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा और चिंता प्रकट की है कि इस प्रकार से वन्य जीव-जंतुओं की हत्या करके उनकी खाल वगैरह को विदेशों में और तिब्बत का उदाहरण दिया कि तिब्बत में इस प्रकार के मार्केट लगते हैं। वहां पर टाइगर, पैंथर तथा अन्य जंगली जीवों की खालों का मार्केट लगता है। लोग उनकी खालों को पहनते हैं तो प्रधानमंत्रीजी ने काग्निजेंस लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अहिंसा के पुजारी दलाई लामा को जिन्होंने तिब्बत में अपने शिष्यों को पत्र लिखा और उनको आव्हान किया, उनको ओथ दिलायी कि इनका उपयोग कोई नहीं करें और इनकी कोई खरीद-फरोख्त नहीं करें। इस प्रकार का वातावरण बना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरिस्का में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो हमने 2005 और 2006 में 425 रेट्स लगाये, सरिस्का के अंदर अगस्त, 2005 में 342 और 250 लगाये और हमने कमेटी का गठन किया और उसकी सिफारिशें राजस्थान सरकार को की गयी। उसके आधार पर 250 होमगार्ड को वहां पर लगाया गया। इसी तरह से 100 पी.ए.सी. के जवानों को लगाया गया और राजस्थान में वनों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 175 एडीसी कमेटी का फाउंडेशन किया।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में कमेटियों का गठन वन्य जीव सुरक्षा समितियों का गठन, 4661 वन सुरक्षा समितियों का गठन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान में 32 एफडीए, वन विकास अधिकरणों का गठन किया गया है ताकि राजस्थान के लोगों में एक प्रकार की जब तक सहभागिता नहीं होगी, लोगों में एक प्रकार की जागृति नहीं होगी, वन विभाग अपना कार्य कर रहा है, हमारे अधिकारी अपना काम

कर रहे हैं, हमारे जितने सीमित साधन हैं उनका उपयोग कर रहे हैं लेकिन जनता के अंदर इस प्रकार का वातावरण जब तक नहीं बनेगा वनों के प्रति, आज वास्तव में चिंता का विषय है, मात्र यह चिंता का विषय राजस्थान का ही नहीं है, यह भारत ही नहीं विश्व की चिंता का विषय भी है। चिंता के विषय दो हैं, एक बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। राजस्थान सरकार चाहती है कि समग्र विकास के साथ संतुलित विकास हो, ईश्वर ने प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे का पूरक बनाया है और उसने जब कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो प्रकृति ने मनुष्य का साथ देना बंद कर दिया, निर्णय हमारे सामने है, चेतावनी हमें मिल रही है, सुनामी लहरों का आना, ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में छेद होना, वनों की कटाई और कुओं का जल स्तर गिरना एक प्रकार से मानव मात्र के लिए जो हमारा जीवन आधार है वन जिससे हमें आक्सीजन मिलती है, अगर यह अवेयरनेस पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में अगर नहीं आई और लोगों ने इसके प्रति जागृति नहीं रखी तो आने वाले समय में जिस तरह से बिसलेरी की बोतल दस और बारह रुपए लीटर में मिलती है, हमें आक्सीजन की बोतल साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस प्रकार का वातावरण बना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने ई डी सी का फोर्मेशन किया है। हमने इन कमेटीज की रिकमण्डेशन के आधार पर सूचना तंत्र को विकसित करने का कार्य किया है, सैंक्चुरी की दस किलोमीटर की परिधि में वहां पर जो लोग रहते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां जिनकी हैं, जिन पर डाउट होता है उनको लाइसेंस के लिए, वन विभाग के द्वारा लाइसेंस लेने के लिए हमने इस प्रकार का प्रावधान रखा है।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी, मेरी भी सुन लो थोड़ा। आपकी यह बात बिलकुल ठीक है कि इकोलाजिकल बेलेंस के लिए, यह तो उन्होंने फरमाया कि खनन आपके चल रहा है अभयारण्यों में और उन्होंने यह कहा कि वन्य जीवों की वहां संख्या कम हो रही है और आप इन दोनों बातों का जवाब दे दें कि कोई खनन नहीं चल रहा है, आप बता दो, नाम लिया है एक का कि वहां हो रहा है, यह बताओ आप, आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस भैंसरोडगढ का नाम लिया है, तथ्यों से बिलकुल झूठ और असत्य बात है। अगर माननीय सदस्य भैंसरोडगढ़ स्थान

पर खनन की बात साबित कर दें तो आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। आपके पास पूरी सूचना नहीं है, आरोप लगाना चाहते हैं, आरोप लगाने के लिए आपके पास कोई तथ्य नहीं है। ...(व्यवधान) बेसलेस तथ्यों के आधार पर बात करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वन्य जीव प्रदूषण से खतम हुए हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: वह तो बंदर और मोर हैं और कोई है नहीं, बता रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह कह रहे हैं कि पर्यावरण खराब हो गया, पर्यावरण तो खराब हो गया सबको पता है, प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन वन्य जीव तो प्रदूषण से खतम नहीं हुए न, वन्य जीव तो इसलिए कम हो गए कि आपकी सरकार की देखभाल ठीक नहीं है। आप मंत्री किस चीज के हो, आपने कभी जाकर किसी वन को देखा है क्या? आपका काम वनों की रक्षा करने का है, आपने एक भी अभयारण्य में जाकर नहीं देखा, एक भी आदमी को आपने सज़ा नहीं करवाई। बैठे हुए हैं यहां पर और हमें भाषण दे रहे हैं कि जागरूक हों।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कह नहीं पाए अपनी बात लेकिन यह बात सही है कि आपके चम्बल के किनारे मृत मगरमच्छ मिला, लकड़ियों से भरी दो नावें जब्त हुई, दर्रा अभयारण्य में शिकार, शिकार के बाद मांस पकाया, 6 जने गिरफ्तार, सोरसन से लापता हो गए गोडावण तो यह बात तो वह कह नहीं पाए, कहनी तो उनको यह बात चाहिए थी, आप जवाब दें इनका।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात की है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरिस्का के अंदर पहली बार राज्य सरकार ने और हमने यह इच्छा प्रकट की है कि सेंसस रिपोर्ट जो आई उसको जनता के अंदर, सार्वजनिक करके सच्चाई जनता के सामने प्रस्तुत की। 1988 में 45 टाइगर और 1989 में 19 बताए, न तो आपने जांच कमेटी बनाई और न किसी अधिकारी और कर्मचारी की लाइबिलिटी फिक्स की, हमें जब यह जानकारी मालूम हुई तो हमने आरएन मलहोत्रा को डाइरेक्शन दिए और जांच करवाई और जांच में उदयराम, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हनुमंत शर्मा, वनपाल, श्यामलाल, वनपाल, कल्याण सहाय, वृक्षपालक, राजाराम, वृक्षपालक और बदनसिंह, बेलदार, इनको हमने निलम्बित

किया। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में हमारे एडीशनल पीसीसीएफ जिसकी लापरवाही साबित हुई, उनको भी हमने निलम्बित किया। साथ में 20.7.2005 को...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसको जाकर कहें हम, जो हैं उनको तो कहा नहीं।

श्री अध्यक्ष: वह नहीं सुनेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम, हम की कहानी बना रखी है।

श्री अध्यक्ष: 'हम' ही कहेंगे और क्या कहेंगे? आपका नाम कैसे लेंगे वह? वह तो यही कहेंगे कि हमने ऐसा किया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या किया?

श्री अध्यक्ष: जो कुछ किया वह बता रहे हैं न, सुनो तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इन्होंने खाया और +++ किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: क्या किया?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ किया, +++ किया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ को कम आंकने का काम किया है। +++ का कितना महत्व है, गाय हमारी संस्कृति में माता है, उससे निकला हुआ +++, +++ तो हमारे लिए मैं समझता हूं कितना काम आता है, खाद के लिए, किसान के लिए तो +++ अमृत है। आपने कैसे कह दिया कि +++ किया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह तो दर्रा की बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का कहीं नाम नहीं लिया। सरकार अकेले, हम नहीं हैं क्या? सरकार राजस्थान की है, 'हम-हम-हम' लगा रखा है, क्या 'हम-हम' करते हो?

श्री अध्यक्ष: 'हम' ही कहेंगे और क्या कहेंगे, 'मैं' कहूं तो आप फिर कहेंगे कि 'मैं' कह दिया हमारी सरकार ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार का नाम लो।

श्री अध्यक्ष: लेकिन आपने जो गलत शब्द का प्रयोग किया कृपया उसे वापस लो। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं आपसे कि मान्यवर, 'हम-हम-हम', क्या 'हम' है? सरकार ही तो है यह, सरकार का नाम क्यों नहीं लेते कि हमारी सरकार ...(व्यवधान) राजस्थान की सरकार नहीं है क्या? यह राजस्थान की सरकार नहीं है क्या? तो हम नहीं हैं क्या राजस्थान में, हम राजस्थान से बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमारी सरकार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 'मैं' भी नहीं कहें और 'हम' भी नहीं कहें तो आप बता दो साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इसका फैसला आप कर दीजिए। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम जो जीत कर आए हैं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य उनकी सब की सरकार है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पिछले तीन सालों की गाथा मत गाओ आप, जो काम की बात है उसका उत्तर दो और काम की बात है उसको सुनो और आप आस्तीनें मत चढ़ाओ।

श्री अध्यक्ष: आप भी तो चढ़ा लेते हैं कई बार।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम गर्व से कहेंगे कि हमारी सरकार है। इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं, हमारी सरकार है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 'हम' क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं बैठती, 'हम-हम-हम', कहो कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष: देखिए, ऐसा है कि आप कोई शब्द तो उनके मुंह में डाल नहीं सकते।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का गरिमामय पद है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता ने जो +++ शब्द का प्रयोग किया है उसको कार्यवाही से निकाल देना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता अपनी भाषा शैली पर कण्ट्रोल करें। हर माननीय सदस्य इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता जो चाहे वैसा कहने के लिए, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनको क्षमा मांगनी चाहिए, इस प्रकार की

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बात करते हैं। +++ तो आपने किया है और इस बुढ़ापे में +++ कर रहे हो, शर्म आने की बात है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, यह तो दर्रा अभयारण्य की बात कर रहे हैं। आप सरिस्का में समय खराब मत करो, वह दर्रा अभयारण्य की बात कर रहे हैं और आप पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप दर्रा अभयारण्य की कहो।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह की यह स्थिति असम के काजीरंगा अभयारण्य के अंदर पैदा हुई थी। वहां के वन अधिकारियों ने यह कहा असम के लोगों को कि अगर वन और जीव रक्षा करनी है तो उनको विश्नोई बनना होगा।

श्री अध्यक्ष: क्या करना होगा?

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): विश्नोई बनना होगा।

श्री अध्यक्ष: हम सब बन जाते हैं विश्नोई, बिलकुल रक्षा करेंगे वनों की।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): अगर वनों और अभयारण्यों की रक्षा करनी है, जीवों की तो विश्नोई बनना होगा यहां के लोगों को। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी, कि जो 250 गार्ड आपने लगाए हैं, उन 250 गार्डों की जगह 200 गार्ड भी वहां विश्नोई कम्यूनिटी के लगा दो और एक भी शिकार हो जाए तो हमें आप कह देना।

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): सदन की भावना है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भारत की संस्कृति में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। उस ब्राह्मण की पूजा होती आई है और आज भी पूजा होती है, आज भी गांव में ब्राह्मण ने जो कह दिया वह शिरोधार्य है। मैं जाति-पांति की बात नहीं करता, स्वयं में विशुद्ध ब्राह्मण दवे साहब जो हमारे फोरेस्ट मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से पण्डत ही हैं और पण्डत हैं और पण्डत होकर वहां आपने जो पढ़ा...

श्री अध्यक्ष: मांस खाया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, वह पढ़ा, वह इनकी मौजूदगी में हुआ तो इनको तो हट जाना चाहिए इस बात पर।

श्री अध्यक्ष: और ही मौजूद थे, यह थोड़े मौजूद थे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो कुछ पढ़ा है न यह इनको पढ़ा कर सुना देते तो इनका कोई धर्म नहीं है मंत्री रहने का और कोई मंत्री रहने का धर्म है? विश्नोई साहब ने कहा कि सब विश्नोई बनो।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनका ध्यान दो बातों की ओर दिलाया था। एक तो जो सैंक्चुरी है, आपकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वहां स्टाफ अवेलेबल नहीं है और वहां स्टाफ 508 ही है और वन विभाग के नोर्म्स के अनुसार 1434 होने चाहिए, मैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात कर रहा हूं। 1434 के अगेंस्ट 508 इनके पास स्टाफ है और इस कम स्टाफ में और वह भी 45 साल की एवरेज उम्र है, स्टाफ की भर्ती के बारे में इन्होंने क्या किया? क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। अभी शिक्षा विभाग में 50 हजार अध्यापक ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुन लो आप। आपकी सुनी थी, अब आप उनकी सुनो।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ये जवाब मुझे पर्यावरण का दे रहे हैं, वे पूरे खतरे को बता रहे हैं मैं तो वन्य जीव खतरे की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पर्यावरण खनन से होता है, पोचिंग से होता है, वही तो बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं?

श्री भरत सिंह (दीगोद): यहां पर वाइल्ड-लाइफ बोर्ड गठित है।

श्री अध्यक्ष: वाइल्ड-लाइफ के लिए कहना चाहते हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में वाइल्ड-लाइफ बोर्ड है जिसकी साल में दो बार उसकी बैठक होनी चाहिए। यह प्रकरण उजागर होने के बाद इसकी गम्भीरता से इन्होंने कमेटी का नाम तो ले लिया कि हमने इतनी वन कमेटियां बनायीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें उलझना भी नहीं चाहता, मैं तो वाइल्ड-लाइफ बोर्ड की बैठक, जब इस प्रकार की घटना हो गई और आप लोगों को इन्वाल्व करना चाहते हैं तो स्टेट वाइल्ड-लाइफ की बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं उसके बारे में प्रकाश डालें और जो भर्ती आप कर रहे हैं उसमें रिकमंडेशन है कि आप सैंक्चुरी के आसपास के लोगों को भर्ती करना, चाहे वो विश्नोई करें, पर नई करें, वे थके हुए फौजी उसको कैसे रोकेंगे?

श्री अध्यक्ष: विश्नोई बन जाओ यह कहा इन्होंने। विश्नोई बनो। आपको वनों की रक्षा करनी है तो विश्नोई बनो। विश्नोई तो रिलीजन कोई भी एडोप्ट कर सकता है, 20 और 9 जो 29 नियमों का पालन करे वो विश्नोई। कोई भी कास्ट बन सकता है विश्नोई इसमें क्या बात है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आसन की तरफ से आश्वासन मान लें कि विश्नोई की भर्ती करेंगे।

श्री अध्यक्ष: 29 नियमों को जो मानेगा वही तो विश्नोई होगा। उनमें एक नियम पेड़ की रक्षा करना भी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): वह जंभाजी के नियम हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जाट तो उसमें आने चाहिए क्योंकि विश्नोई तो जाटों से ही बने हैं।

श्री अध्यक्ष: विश्नोई राजपूत भी हैं, विश्नोई ब्राह्मण भी है, विश्नोई बनिया भी है, कोई भी कास्ट बन सकती है। यह तो रिलीजन है, जो 29 नियमों का पालन करे वो विश्नोई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 नियम में एक इस्लाम का भी लिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: होगा।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना राजपुरोहितों के राज नहीं चलता है और जहां राजपुरोहित नहीं होगा वहां पर अशुद्धता होती है। इसलिए राजपुरोहित को सर्वमान्य कहा गया है। पुराने समय से ऐसी धारणा है, ब्राह्मणों में भी रही है।

श्री अध्यक्ष: इनसे भी श्रेष्ठ हैं। दवे से भी श्रेष्ठ होता है राजपुरोहित? क्या बात कर रहे हो आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यही तो उपाध्यक्षजी कह रहे हैं कि सारा सदन मान ले अपन विश्नोई बन जाएं, वन्य जीवों की रक्षा करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं शंकर सिंहजी राजपुरोहित को इस राज का राजपुरोहित बना दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: देखो, आप मजाक में न लें। इस गम्भीर विषय को आप इस तरह से मखौल न बनाएं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में वन्य जीव-जंतुओं के अन्तरराष्ट्रीय मुलजिम थे, चाहे तो रानी गेहरा हो, चाहे आकाश गेहरा हो..

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): रानी गेहरा कौन है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में रानी गेहरा का जो कार्ड मिला है वो दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति (कांग्रेस) मोर्चे की महामंत्री बतायी है। संसारचंद्र को गिरफ्तार किया, नीमा अन्तरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया, हीरा खटीक ... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): क्यों इसको घुमा रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूं बोर्ड की मीटिंग कब होगी उसके बारे में बताएं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जितने मुलजिम थे वन्य जीव-जंतुओं के अन्तरराष्ट्रीय हत्यारे थे दो वर्षों में हमने एक्शन लेकर इनको सींखचों में भेजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार का वातावरण बना है, हम यह चाहते हैं सरिस्का के अंदर, सरिस्का के रिइंट्रोडक्शन के लिए राज्य सरकार ने योजना बनायी है और सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जो दिशा-निर्देश दिया है उसमें जो गांव हैं उनको शिफ्ट करने का है। दो गांव हैं कांकनबाड़ी और एक गांव है, उनको शिफ्ट करने की कार्यवाही चल रही है, हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि पहले तीन फिमेल टाइगर्स और उसके बाद में दो टाइगर्स को सरिस्का में रिइंट्रोडक्शन करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाए। एक प्रकार का वातावरण बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में वन्य जीव-जंतुओं के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, पहले 15 हजार रुपये उस परिवार को मिलते थे, हमने एक लाख की व्यवस्था की है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं खेत की बात कर रहा हूं आप खलिहान का जवाब दे रहे हैं। वाइल्ड-लाइफ बोर्ड की बैठक के बारे में क्या कर रहे हैं आप? खेत की बात करो, खलिहान का जवाब मत दो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप विराजो तो सही।

श्री भरत सिंह (दीगोद): आप विराजो, आप बात को घुमाकर पता नहीं कौन से जंगल में ले जा रहे हो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है वास्तव में वन विभाग में कमी है और राज्य सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार रिटायर्ड सैनिकों को लेने की घोषणा की है। हम पूरे वन विभाग की तरफ से, मैंने भी मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की है, मामला मुख्य मंत्रीजी के विचाराधीन है और निश्चित रूप से नई भर्ती के बाद में नौजवान आएंगे तो वन की सुरक्षा में और भी इजाफा होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं।

इसके साथ में वी.पी. सिंहजी की कमेटी के द्वारा जो रिकमंडेशन की है हमने अधिकांश रिकमंडेशन को मान लिया है और राजस्थान के अंदर पिछले दो साल के बाद में एक प्रकार की अवेयरनेस आई है, वन्य जीव-जंतुओं की हत्याओं पर जिस प्रकार से राज्य सरकार ने शिकंजा कसा है और फोरेस्ट के अंदर इल्लीगल माइनिंग के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं इन तीन साल के कार्यकाल में फोरेस्ट में इल्लीगल माइनिंग पर जो कठोरता से कार्यवाही की, चाहे लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत हो, चाहे वन अधिनियम के तहत हो, हमने कार्यवाही करके इल्लीगल माइनिंग करने वालों में एक प्रकार का भय का वातावरण पैदा हुआ है, वातावरण बन रहा है।

मुकंदरा हिल की बात की है, निश्चित रूप से मुकंदरा हिल्स वहां के एक पर्यावरण प्रेमी थे वहां के ठाकुर थे, उनके नाम का एक बंगला बना हुआ था, आसपास में वे पर्यावरण प्रेमी थे इसलिए इसका नाम मुकंदरा हिल रखा था। आसपास में पहा़डियां भी थीं, अच्छा वातावरण है इसलिए इसका नाम मुकंदरा हिल रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज सदन में विश्वास दिलाता हूं वन्य जीव-जंतुओं के हत्यारों पर शिकंजा कसा है और लगातार हम अपनी तरफ से मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और फोरेस्ट के अंदर जहां कहीं भी इल्लीगल माइनिंग है और जहां कहीं भी फोरेस्ट में एनक्रोचमेंट है उसको सख्ती से निपटने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): वाइल्ड-लाइफ बोर्ड।

श्री अध्यक्षः हो गया, काफी जवाब दे दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड-लाइफ बोर्ड की जो बात की है यह प्रक्रियाधीन है और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी वाइल्ड-लाइफ बोर्ड का गठन होकर इसकी मीटिंग भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कब्रिस्तानों में अतिक्रमण

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का, माननीय गृह मंत्रीजी का और माननीय राजस्व मंत्रीजी जो वक्फ के प्रभारी मंत्री हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 50-60 साल पहले कब्रिस्तान हो या श्मशान हो या ग्रेवयार्ड हो, ये आबादी से दूर बाहर बनाये जाते थे, लेकिन आबादी के बढ़ने से कस्बों और शहरों के विकास के कारण आज ये कब्रिस्तान, श्मशान शहर की घनी आबादी के बीच आ गये हैं। जमीनों के भाव बढ़े और स्थिति यह हो गई कि वक्फ एक्ट, 1995 पार्लियामेंट ने अमेण्डमैंट करके पास किया है उसमें प्रावधान यह है कि कब्रिस्तान में केवल वो ही लोग निवास करेंगे जो मुर्दे दफनाने, गाड़ने और कब्र खोदने का काम करते हैं और वो भी टेम्प्रेरी, यानी कच्चे मकान बनाकर निवास करेंगे। लेकिन आज पूरे राजस्थान के कब्रिस्तानों की स्थिति यह हो गई कि एक-एक कब्रिस्तान में 200-200 मकान बन रहे हैं। आज घाटगेट, टांसपोर्ट नगर का कब्रिस्तान है वहां पर 25 हजार रुपये गज का भाव है तो जो लोग वहां कब्रिस्तान में रहते थे उन्होंने आगरा तक के दूर के अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और वे आलीशान पक्के मकान बनाकर वहां रह रहे हैं। शास्त्री नगर कब्रिस्तान है उसमें भी 137 पक्के मकान बन गये। मुर्दों के रहने की जगह पर अगर जिंदा लोग रहने लग जाएंगे तो कब्रिस्तान तो रिहायशगाह बन जाएगा और आगे मुर्दे दफनाने के लिए जगह नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी इश्यू को लेकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः रजिस्टर्ड कब्रिस्तान है, यह तो वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वक्फ बोर्ड की भी है, वक्फ मंत्रीजी भी तो यहां बैठे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं आप सुनिए तो सही। 15 जुलाई, 2006 को, काफी दिनों से यह समस्या चल रही थी। जब शास्त्री नगर में लोगों ने कब्रिस्तान बचाओ, अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया, फायरिंग हुई, उसमें 6 लोग मरे, 19 लोग घायल हुए। इस समस्या को लेकर वक्फ बोर्ड ने कई बार रेवेन्यू आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को

एप्रोच की कि आप हमको फोर्स उपलब्ध कराएं ताकि हम इन अतिक्रमणों से कब्रिस्तान को मुक्त करने का काम करें। यह इश्यू चल रहा था। 15 जुलाई, 2006 को ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी जयपुर आई। लाल जान बादशाह, टी.डी.पी. के आंध्रप्रदेश के एम.पी. हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी आई। इस कमेटी ने इन कब्रिस्तानों का मौका भी देखा, वक्फ बोर्ड में राजस्थान विधान सभा का प्रतिनिधि होने के नाते और दुर्रु मियां साहब भी उनके साथ थे, उस ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी ने सचिवालय में मीटिंग की। चीफ सैक्रेटरी और प्रिंसिपल रेवेन्यू सैक्रेटरी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पांच का समय है, आप 5 मिनट में समाप्त कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी तो एक मिनट हुआ है, इतना गम्भीर विषय है, आप सुनिए तो सही, बीच में आप टोकने लग जाते हैं, बैठ जाऊं या तो मैं फिर? पांच मिनट हो गये क्या ? दो मिनट तो हुए नहीं। आधे-आधे घंटे लोग बोल लेते हैं तब कुछ नहीं होता। मैं एक ज्वलंत समस्या की तरफ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज एजुकेशन की डिमाण्ड है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): होगी, एजुकेशन की डिमाण्ड है तो। यह हमारे लिए ज्यादा जरूरी है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 12 फरवरी, 2007 को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में चीफ सैक्रेटरी को, प्रिंसिपल सैक्रेटरी रेवेन्यू को दिल्ली बुलाया और जब जयपुर के सचिवालय में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट, होम डिपार्टमैंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ डिपार्टमैंट मिलकर के ज्वाइंट अभियान चलाएंगे और एक समयबद्ध सीमा के अन्दर इन कब्रिस्तानों से इन अतिक्रमणों को मुक्त कराने का काम करेंगे लेकिन फिर यह मीटिंग हुई 15 जुलाई को और 15 जुलाई को निर्णय हो गया, चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता जो राजस्थान के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई और लगातार मकान बनते चले जा रहे हैं। इसको लेकर के 7 मार्च से शास्त्री नगर में पुन: कब्रिस्तान बचाओ कमेटी के लोग धरने पर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई तो 17 मार्च से ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह आप गलत कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए फिर आप कहिए मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं उनसे मिल कर आया हूं और आज ही हास्पिटल में ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सरकार हो क्या? ग़लतफ़हमी है क्या आपको? मैं कह रहा हूं आप सरकार हो क्या? आप अभी भी अपने आप को मेयर समझते हो क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं वहां जाकर आया हूं और उन लोगों से मिल कर आया हूं, आपके जिस व्यक्ति ने अनशन कर रखा है उससे तो मैं हास्पिटल में मिल कर आया हूं। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने इनको बोलने की इजाजत दी है और ये इनको बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। पांच मिनट तो यही खा जाते हैं और आपने अनुमति दी है इनको बोलने की और ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्री आपको बनाया नहीं और आप इस तरह से ...(व्यवधान) आप मंत्री होते और जवाब देते तो समझ में आता। ...(व्यवधान) आप जबरदस्ती इस तरह से करते हो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करिए, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको क्या मतलब है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि····

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। किसी एक स्थान की बात नहीं कह रहे हैं पूरे राजस्थान की ही यही स्थिति हो रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घाटगेट कब्रिस्तान के अन्दर आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं मृत उनको दफना देते हैं, कुत्ते उनको निकालकर के ले जाते हैं, लोगों में रोष हुआ, 4-5 हजार आदमियों ने जुलूस निकाला, नगर निगम गये, नगर निगम के मेयर ने एक लाख रुपये देकर उसका गेट लगवाने का काम किया, वक्फ बोर्ड ने भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज 17 मार्च से जो लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, कल उनकी हालत एकदम बिगड़ गई, मरणासन्न स्थिति में हो गये उनको अस्पताल में ले गये, खुद किशनपोल से आने वाले सदस्य जाकर उनसे मिल कर आये इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है लेकिन आज भी उसकी स्थिति यह है कि वह मुंह से कुछ लेने के लिए खाने के लिए तैयार नहीं है और उसकी स्थिति मरणासन्न हो रही है, उसका रि-एक्शन होगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि माननीय गृह मंत्रीजी और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब दोनों यहां बैठे हैं, आप दोनों मीटिंग करके और एक समयबद्ध सीमा तय करके राजस्थान में वक़्फ़ बोर्ड के जरिए एक अभियान चलाएं और खुदा के लिए यह कब्रिस्तान जो मुर्दों के रहने की जगह है इनमें जो जिंदा लोग रह रहे हैं, मुसलमान ही रह रहे हैं, सारे लोग मुर्दों के रहने की जगह पर जिंदा लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाने का काम करें। केवल उनका रजिस्ट्रेशन जो कब्रों में खोदने और मुर्दे दफनाने का काम करते हैं, वह कच्चे मकानों में रहें बाकी के जिंदा लोग हैं उनको वहां से हटाने का काम करें, नहीं, पूरे कब्रिस्तान भर जाएंगे और नई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाएगी इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे श्मशान हो या कब्रिस्तान हो उन पर जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनको सख्ती से निपट करके हटाने का काम दीजिए, आप राजस्थान की जनता को इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करें कि शीघ्र ही इसके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे ताकि विस्फोटक स्थिति नहीं बन जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा एक दिन और यह मैटर उठा था। गृह मंत्रीजी ने यह कहा था कि मुझसे भी यह शास्त्री नगर, जयपुर कब्रिस्तान वाले मिले थे, मैं एक दो दिन में जानकारी लेकर सदन को बताऊं। ये माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारी बात इन्होंने विस्तार से कह दी है। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई मंत्री आश्वासन दे दे और उसकी पालना नहीं हो। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि मैं तथ्य इकट्ठे करके सदन को अवगत कराऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्री नगर में कब्रिस्तान जो है वहां पर कब्रिस्तान बचाओ कमेटी के लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से मेरा निरंतर सम्पर्क है और वहां पर कब्रिस्तान के बाहर जो खम्भे लगे हुए हैं, उसके बाहर कुछ लोग बसे हुए हैं, करीब पांच सौ की संख्या है, पांच सौ परिवार वहां रहते हैं। उनके भी रहने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और उनसे वार्ता चल रही है। दोनों के बीच कार्डिनेशन बिठा कर और एक वार्ता चल रही है। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता चल रही है कि उनको भी वहां मकान मिल जाएं, वह भी एग्री हैं इस बात के लिए कि एक बाउण्ड्री जो खम्भे लगे हुए हैं उसके बाहर उनको मकान बनाकर दे दिए जाएं और अन्दर पूरे कब्रिस्तान को खाली करा कर अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाए। इस बात की वार्ता चल रही है लेकिन इस विषय को ...(व्यवधान) राजनीतिक विषय न बनाते हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, गलत बात है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): साहब, ये बीच में बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब आ जाता, इनका जवाब क्या मायने रखता है? ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह तो मेरे स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये सही बात कह रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने अनौपचारिक प्रयास किये हैं और यदि दोनों पक्ष वहां पर पहले गोली चल चुकी है। ...(व्यवधान) मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार का तनाव हो, आपस में लड़ें, झगड़ें इसलिए समन्वय की दृष्टि से मैं कहता हूं कि वहां के रहने वाले लोगों को जगह मिल जाए और कब्रिस्तान को भी अतिक्रमणों से मुक्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इस समन्वयकारी नीति से हम निश्चित रूप से सरकार के पास में, आज भी कलक्टर के यहां मीटिंग है।

श्री अध्यक्ष: किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, ठीक है आपकी बात, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह अनशनकारियों का अनशन तुड़वाएं और आज ही शायद अनशन तोड़ देगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। (व्यवधान) ... माननीय जो संबंधित विधायक हैं, किशनपोल से उन्होंने अपनी बात कही और वह अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) स्थान ग्रहण कर लें। उन्होंने तो ठीक बात कही कि वे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि उस भूखण्ड को खाली करवाया जाए, कब्रिस्तान वाली जमीन को खाली करा कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो लोग वहां बस गये हैं उनकी करें, ठीक है लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है, मैं पूछना चाहती हूं कि आप क्या कर रहे हैं ? जब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो आपका भी कर्तव्य था कि आप उनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए कोई न कोई इस संबंध में कार्यवाही करते। आपने क्या किया ? बताएं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह किशनपोल की ही नहीं, पूरे राजस्थान की ही यह समस्या है, आप उसका कोई समाधान निकालें। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर आमरण अनशन की बात है। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आमरण अनशन वाली बात तो, इससे संबंधित मेरा मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्यों नहीं है ? आपका डिपार्टमेंट है, वक़्फ़ की जमीन के ऊपर यदि कोई बसता है ...(व्यवधान) मेरी सुनिए, अतिक्रमण करता है तो वक़्फ़ की जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनका संरक्षण करने की। ...(व्यवधान) उसके आधार पर कोई आमरण अनशन पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नुमाइंदे के रूप में अनशनकारियों से सुबह बात करने गया था, उनसे हास्पिटल में जाकर के मिला हूं और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही मिला हूं इसलिए सरकार का कोई दोष नहीं है। यह सब कुल मिला कर हम जन समस्या का समाधान करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको मैं हाथ जोड़ती हूं, आप बीच-बीच में चाहे जब खड़े हो जाते हैं, क्या करें? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो आपके माहिर आजाद साहब ने जो चिंता व्यक्त की और उस वक़्फ़ बोर्ड के ···

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बताओ वक़्फ़ की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? ...(व्यवधान) यह बताओ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं जो बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह कब्रिस्तान जो नाहरी का नाका और शास्त्री नगर, जयपुर के अन्दर है और इस पर 108 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और 108 अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाने का जब हमने वक़्फ़ बोर्ड की धारा 1995 की धारा 54 के अन्दर उनको नोटिस दिये, उनमें से 16 व्यक्तियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। ...(व्यवधान) मेरे पास जितनी इन्फार्मेशन है, ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता और मंगा लेंगे यदि सूचना सही होगी तो उस आधार पर मंगा लेंगे और फिर बाद के अन्दर एक आदेश पारित किया 1995, धारा 55 के तहत जो वक़्फ़ बोर्ड की अलग से धारा है, जैसे अपने 91 की धारा है, वह वक़्फ़ बोर्ड में अलग से है तो उसके तहत हमने वक़्फ़ बोर्ड ने एस.डी.एम. के पास हटाने के लिए इनको जो 108 में जो 16 बचे हैं, 92 अतिक्रमियों को हटाने के लिए एस.डी.ओ. को कहा, हमने एप्लाई किया एस.डी.ओ. को कि आप इन अतिक्रमियों को हटाएं और उनके लिए सुरक्षा वगैरह जो कि जाब्ता फौजदारी, इमदाद वगैरह वह एस.डी.एम. मांगे। तो उनको दिया और उनको देने के बाद में यह सारी बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, अभी तक वो अतिक्रमण हटे नहीं हैं। इस दरमियान अतिक्रमण हटाने के लिए संघर्ष समिति...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ. को एप्लाई करोगे या एस.डी.ओ. को निर्देश दोगे? एस.डी.ओ. को तो निर्देश देना चाहिए हटाने का, आप एप्लाई कर रहे हो एस.डी.ओ. के पास।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वक्फ बोर्ड ने एस.डी.ओ. के पास एप्लाई किया है। रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड अलग-अलग हैं। कानून व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही है वह एस.डी.एम. करेगा और एस.डी.एम. जाब्ता वगैरह जो है वह होम डिपार्टमैंट से मांगेगा और इस प्रकार से कार्यवाही अभी चल रही है। इस दरमियान इन्होंने संघर्ष समिति बनाकर के एक व्यक्ति अनशन पर बैठ गया और अनशन वाली जो बात है, अभी मैं नहीं कहना चाहूंगा इसलिए कि माहिर आजाद साहब और...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने ही बिठा दिया क्या?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ...दोनों ही आप उसके मैम्बर हैं और मैम्बर होने के नाते इनकी भी पूरी कमेटी बैठती है समय-समय पर, पूरे राजस्थान के अन्दर कहां-कहां किस प्रकार से वक्फ पर अतिक्रमण हो रहा है, बाकायदा इनकी चर्चा होती है और उसी के आधार पर डिपार्टमैंट को भेजा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जितनी जानकारी आई है इस आधार पर कि 108 में से 16 का तो स्टे है, 92 को हटाने की कार्यवाही चल रही है। उस दरमियान इस प्रकार कब्रिस्तान...

श्री अध्यक्ष: और बातें तो ठीक हैं, सब ठीक है, आप तो उस आमरण अनशन को तुड़वाने वाली बात करो क्योंकि वही पर्ची का विषय है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उसमें वार्ता चल रही है। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों और उनके बीच में चल रही है।

श्री अध्यक्ष: आप आश्वासन दोगे तब ही तो होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पर्ची पढ़ लें। राजस्थान के कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाना, यह मेरा उसमें है, इसी में यह आता है। मैं तो जैसा इन्होंने जिक्र किया इसलिए मैं यह कर सकता हूं कि वक्फ बोर्ड के जरिये हम यह सर्वे करवा लें कि कौन व्यक्ति जरूरी है, उसमें मुर्दे दफनाने का काम करने वाले जो हैं वो तो जायज है वहां रहने वाले और बाकी कौन अतिक्रमी हैं उनकी लिस्ट रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को अवेलेबल करवा दें। आपसे तो निवेदन यह है कि आप समयबद्ध सीमा तय करके एक फोर्स बनाकर के एक अभियान चलाकर के इन अतिक्रमणों को हटाने का काम करें चाहे आपको सख्त कदम उठाने पड़े। मेरा तो यह निवेदन है कि वो आप कब तक कर देंगे? वो घोषणा कर दें आप तो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी

(श्री रामनारायण डूडी)

आइडेंटिफाई हुए हैं और उनकी पूरी जितनी भी वक्फ की प्रोपर्टी है, कब्रिस्तान है या दूसरी भी है...

श्री अध्यक्ष: वक्फ बोर्ड हटाये न।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वो वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है, वक्फ बोर्ड अपने नियमों के अनुसार उन पर कार्यवाही करता है और उन पर कार्यवाही के लिए आगे कोर्ट में तो पार्टी जाती है मगर उनकी पैरवी वगैरह वक्फ बोर्ड करता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वक्फ बोर्ड के पास फोर्स थोड़े ही है। वक्फ बोर्ड तो आपको सूचना अवेलेबल करायेगा बाकी तो गवर्नमैंट का एडमिनिस्ट्रेशन ही तो उसको हटायेगा या वक्फ बोर्ड का कर्मचारी, वक्फ बोर्ड का मैम्बर जाकर के हटायेगा?

श्री अध्यक्ष: वक्फ बोर्ड का आपने लिखा है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, लिखा है और जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजा है और प्रिंसिपल रेवेन्यू सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही करेगी। तारीख बताइये हमें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास जो अभी इन्फार्मेशन आई है वह मैं आपको पढ़कर के सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सुन तो लो उनको पहले। अब आप क्यों बीच में खड़े हो गये? सुन तो लो पहले।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं। मैं बता दूं आपको, पूरी फाइनल रिपोर्ट बता दूं आपको। एक साल 6 महीने में ये खुद ही हट जाएंगे वह अतिक्रमण नहीं हटेगा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप तो बैठिये न। आप भी हटते आये हैं, हम भी हटते आये हैं, कभी इधर आये हैं कभी उधर आये हैं, क्या फर्क पड़ता है। काम कौन करता है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विषय को डायल्यूट मत करो, हमारा जवाब आने दो, हमारी समस्या का समाधान होने दो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर के 108 अतिक्रमी थे जिनमें से 16 अतिक्रमियों ने...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो बता चुके आप। आप इसी को रिपीट कर रहे हो, तीन बार बता चुके।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। बोर्ड द्वारा शेष 92 अतिक्रमियों, बोर्ड मतलब...

श्री अध्यक्ष: Mr. Meena, please don't disturb.

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जो अभी गठित बोर्ड है, 92 आदमियों को अतिक्रमण हटाने हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड द्वारा प्रकरणों की सुनवाई कर अतिक्रमियों के खिलाफ आदेश पारित कर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 55 के तहत अतिक्रमियों को बेदखल कर वक्फ सम्पत्ति का कब्जा वक्फ बोर्ड अथवा वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि को दिलाने हेतु 92 प्रकरण उप खण्ड अधिकारी, जयपुर के यहां प्रेषित किये जा चुके हैं। एक अतिक्रमी का दौराने सुनवाई देहांत हो गया। उक्त प्रकरण में अतिक्रमियों को वक्फ सम्पत्ति से बेदखल करने की कार्यवाही उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने तो एस.डी.ओ. को कौनसी तारीख को लिखा? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी, कब तक करेंगे? समय सीमा निर्धारित करिये कि कब तक करेंगे आप उसे? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सरकार बहुत चिंतित है। राजस्थान के अन्दर वक्फ प्रोपर्टी को बचाने के लिए, कब्रिस्तान को मुक्त कराने के लिए जो भी अतिक्रमी हैं, अध्यक्ष महोदय, अब दुकानें बना लीं। (व्यवधान) जो अभी रजिस्टर्ड की आप बात कर रहे हैं, सारे आइडेंटिफाई करायेंगे तो 108 में से कितने लोग वो निकलेंगे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सब तो कर दिया, आप अनशन भी तुड़वा दो। कोई मर जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, उसका अनशन तुड़वायें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह तो चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अभी वार्ता चल रही है। अध्यक्ष महोदय, उस वार्ता के अनुसार अनशन वाली बात भी कर रहे हैं और जैसा कि हमारे एम.एल.ए. साहब इस क्षेत्र से आ रहे हैं इनका प्रयास चल रहा है और वह सारी

बात को गम्भीरता से देख रहे हैं। इस दरमियान जो अतिक्रमी हैं उनको हटाने के लिए एकदम तो, उनका सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सारा हटाने के लिए...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने खुद ने अपने जवाब में पढ़ा है कि वक्फ बोर्ड ने मीटिंग करके नोटिस देकर अतिक्रमियों को चिह्नित करके और जो 16 को स्टे है उसके अलावा 92 की लिस्ट एस.डी.एम., जयपुर को दे दी। आज दिये हुए 16 महीने हो गये कि आप इन अतिक्रमणों को हटायें। सारा काम हो चुका, जांच हो चुकी और आप कह रहे हैं कि हम अभी भी चिन्हित करेंगे। आपने खुद ने ही जवाब पढ़ा है, आप देख लो। एस.डी.एम. को आपने अतिक्रमियों के नाम की लिस्ट दे दी या नहीं दी? क्यों आप गलत जवाब दे रहे हो? सिर्फ 16 लोगों को है, 92 लोगों को नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील मामला है। 1997 के अन्दर सक्सैना कमेटी बनी और उसके अन्दर जब अतिक्रमणों को हटाया तो वहां उस वक्त गोली चल गई थी। बहुत गम्भीरता के साथ इस बात को हम ले रहे हैं। आप यह नहीं समझें कि सरकार...

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है। माननीय रामनारायण मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप जस्टिस सक्सैना कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो न। जस्टिस सक्सैना आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो...

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से आपने एक प्रश्न उठाया और उसका जवाब मंत्रीजी ने दे दिया। अब मैं दूसरी पर्ची वाले का नाम पुकारती हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी, आपने सदन में कहा है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): गृह मंत्रीजी, मैं एक मिनट बोल दूं उसके बाद बोल देना आप। एक मिनट। मंत्रीजी, आप जवाब दे देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): शायद मेरी बात पहले आ जाए तो...

श्री अध्यक्ष: आपको कोई गलतफहमी हो तो बाद में पूछ लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस विवाद के कारण से पहले भी एक बहुत ही बड़ा हादसा यहां हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। उसमें सक्सैना कमेटी की रिपोर्ट 2001 में आई, उसकी कार्यवाही उन्होंने शुरू की। जो मुद्दा मेरे सामने आया था, इस कमेटी के अध्यक्ष और कुछ लोग जो धरना दे रहे थे पिछली 5 तारीख को वो मेरे से मिले थे और उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए यह धरना हमने लगाया हुआ है, आप इसमें कुछ करके किसी तरह से हमको राहत दिलायें। मैंने उसी दिन जिला कलक्टर से व्यक्तिगत टेलीफोन भी किया और पत्र लिखकर के भी दिया कि आप इसकी कार्यवाही करें, कार्यवाही नहीं हुई। 13 तारीख को उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू किया। 17 तारीख को उनके अध्यक्ष ने आमरण अनशन शुरू किया। कल 21 तारीख को उनकी तबीयत काफी खराब हुई, पुलिस ने उनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराकर के बचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वे प्रयास हम कर रहे हैं। विषय जहां तक है, मैंने कलक्टर से बात करके मेरे एस. पी. से बात की और आज उनकी नगर निगम, जे.डी.ए., कलक्टर, स्वयं हमारा एस.पी., इन सब की मिलकर के मीटिंग चल रही है और वो निर्णय करेंगे कि हम किस तरह से इसको हटा सकते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि कल ही इसकी कोई क्रियान्विति हो जाएगी लेकिन सरकार जब, आपने यहां सदन में भी इस विषय को उठाया था और मैंने कहा था कि मैं स्वयं इसके बारे में और कलक्टर इसकी चिंता करे, हमसे जो मदद मांगेंगे वह मदद पूरी तरह से देंगे। और हम चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की तरफ से और वहां के एस.डी.एम. के द्वारा जो भी हमसे सहायता मांगी जायेगी, हम देंगे और निश्चित रूप से सिद्धान्ततः सारी बातचीत में यह आया कि अतिक्रमी हैं, अतिक्रमी को हटाया जाना चाहिए। कब और कैसे हटाया जाये, इसकी प्लानिंग करने की दृष्टि से मैं सोचता हूं, ये सारे लोग बैठे हैं, आज कोई न कोई उनकी बातचीत में से कोई परिणाम निकलेगा और इस बात का भी प्रयास करेंगे कि उनको वहां से हटाने के बाद वहां का जो उपाध्यक्ष है उस कमेटी का, वह उसके बाद आमरण अनशन पर बैठा हुआ है इस समय। विषय गम्भीर है तो विषय सुलझना भी इतना आसान नहीं है, यहां भाषण देंगे और कल वहां समस्या सुलझ जायेगी, ऐसा नहीं है। ठीक तरह से और सही रचना करके, संतुष्ट करके, समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि आज की इस मीटिंग में कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी दो शब्द कह दो। यह तो शास्त्री नगर का हो गया।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। श्री रामनारायण मीणा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, मेरा काम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मेरे से मदद मांगेंगे, मेरी पुलिस वह मदद करेगी।

श्री अध्यक्ष: 20 मिनट पूरे हो गये हैं। एक बजकर सात मिनट पर शुरू किया था और एक बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया था। दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो रहमत खां जी का इंतकाल हुआ था तो मैं स्वयं शास्त्री नगर में उनके जनाजे में गया था। मैंने देखा कि बिलकुल कब्रों के पास में लोगों ने मकान बना लिये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राजेन्द्र सक्सैना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आप उन कब्रिस्तानों को कब तक खाली करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: वह बात तो हो गई सारी। अब बाकी क्या रह गया? सारी बात तो आ गई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय ने भी समय-समय पर निर्देश दिये हैं कि कब्रिस्तानों को वेकेट किया जाये?

श्री अध्यक्ष: आपकी बात माहिर आजाद ने कह दी। अब और क्या बात रह गई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, कोर्ट का मामला नहीं आया था, कोर्ट का मामला नहीं आया था। कोर्ट का निर्देश है, इसकी पालना भी सरकार नहीं कर रही है। क्या आपने भूख हड़तालियों ने कोई वार्ता की और वार्ता की तो उसमें क्या परिणाम आये? अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच दिन तक भूख हड़ताल हो और राज्य सरकार वार्ता नहीं करे, यह बहुत गलत बात है, उनसे बात करके इसका समाधान निकाला जाये और राजस्थान में जितने भी कब्जे हैं श्मशानों में, उनको खाली कराया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपको तो अपनी बात बोलनी है। श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी जिले के करवर में गौशाला हेतु भू-आबंटन व सरसों खरीद केन्द्र की स्थापना

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी, तीनों से एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सहकारिता मंत्रीजी तो हैं नहीं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): करवर में गौण मण्डी यार्ड में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, कृषि मंत्रीजी बैठे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कृषि मंत्रीजी के पास ही सहकारिता विभाग है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह मदन दिलावरजी से छीन कर, एस.सी. के आदमी से छीन कर इनको दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: हां हां, बोलिये बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, करवर में खसरा संख्या 2030 करवर, तहसील नैनवां जिला बून्दी में है, उसमें रकबा है 12 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन हाट बाजार, 12 बीघा 10 बिस्वा जमीन है अध्यक्ष महोदय, हाट बाजार की है और हाट बाजार को संचालित करना, वहां रेगुलराइज मण्डी करने की जिम्मेदारी कृषि उपज मण्डी समिति की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत करवर ने भी अपना प्रस्ताव 19.1.2007 को लेकर, प्रस्ताव संख्या 26, उसमें यह निर्णय लिया है कि खसरा संख्या 2030 की जमीन है, 12 बीघा 10 बिस्वा जमीन है, करवर में है, यह मुख्य सड़क पर मौजूद है। करवर से आंतड़ता जाने वाली और बिलकुल रोड से लगवां है। वहां आवागमन के संसाधन हैं, ट्रेक्टर-ट्रोली खड़े हो सकते हैं, सरसों का क्रय केन्द्र वहां चालू किया जाये, वहां हाट बाजार के प्लेटफार्म बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं और इतनी अच्छी जगह है करवर में कि आसपास के गांवों में नहीं है।

(समय : 13.33 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां चूंकि गाय एक धार्मिक भावना का पशु है। गांव के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने

(श्री रामनारायण मीणा)

मिलकर एक गौशाला बनाई। मैंने विधायक की हैसियत से वहां दीवार बनाई, ट्यूबवैल दिया। वहां खेल बनी हुई है। मवेशी पानी पीते हैं, चारे-पानी का इंतजाम है और कोई भी श्रद्धालु आदमी एक ट्रक-ट्रोली भूसा डालता है। उस स्थिति में उसको यदि डिस्टर्ब किया गया तो वहां हालात खराब हो सकते हैं। धार्मिक भावना का मामला है। सरकार की बदनामी हो सकती है। कम से कम जो गौशाला चलती हुई है, 12 बीघा 10 बिस्वा जमीन है। बहुत छोटी जगह है। वहां ट्रेक्टर-ट्रोली खड़ी नहीं हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया कि इनके पास बहुत फण्ड्स हैं। यदि वहां फेंसिंग हो जाये तो आप कर लें। एम.एल.ए. फण्ड है, एम.पी. फण्ड है, नगरपालिका का फण्ड है। मेरा आपसे निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जिला प्रशासन के कुछ लोगों ने दखलन्दाजी करके, एक दबाव डाला जा रहा है कि इस गौशाला को खतम किया जाये। रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात सहायक रजिस्ट्रार के यहां पड़े हुए हैं। सारे लोग एकमत हैं, पूरा गांव एकमत है, गांव वालों की मीटिंग हो गई कि गौशाला को यथावत रखा जाये। यदि वहां से गायों को निकाला गया, उनकी दशा खराब होगी, तरह-तरह की भ्रांतियां पैदा होंगी और सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें होंगी। वहां के लोगों ने, वहां के निवासियों ने एक पत्र दिया उपखण्ड अधिकारी, नैनवां को। उन्होंने साफ लिखा है कि हमारे यहां मकर संक्रांति के दिन गौशाला समिति का गठन हमने किया है गांव वालों ने मिलकर, उसका हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यह जो जगह है, वह विधायक ने बाउण्ड्री वाल बनवाई। वह गौशाला के लिए बनाई है। वहां पीने का पानी है। इसलिए वहां जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको पाबन्द किया जाये, उनको वहां डिस्टर्ब करने से रोका जाये और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा निवेदन है कि गौशाला, गाय जो निरीह पशु है, को वहां से निकालने की कार्यवाही जो जबरदस्ती से प्रशासन कुछ लोगों के लिए, प्रभावशाली लोगों के लिए कर रहा है, उनको रोका जाये। 12.50 बीघा जमीन है वहां, मैन रोड पर है। मैंने मंत्रीजी से अर्ज किया और मंत्रीजी भी इसमें उत्सुक हैं गायों के बारे में। वहां आसपास में कोई गौशाला नहीं है, चार-पांच जो वहां कस्बे पड़ते हैं। न करवर में है, न इन्द्रगढ़ में है, न वहां जरखोदा में है इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाये। धार्मिक भावना से जुडा हुआ, गौ से संबंधित मामला है, छोटी-सी जगह है।

(श्री रामनारायण मीणा)

अब वहां कांटा लगेगा, कृषि उपज मण्डी समिति का कांटा लगेगा। वहां सरसों तौल केन्द्र होना चाहिए, यह सही है। वह 12.50 बीघा जमीन में है। मैं उसमें क्या सहयोग कर सकता हूं, मैं भी करूंगा। मंत्रीजी से भी निवेदन है, मंत्रीजी इंट्रेस्टेड भी हैं क्योंकि मण्डी यार्ड को डवलप किया जाये। वहां कृषि उपज मण्डी समिति में टैक्स की चोरियां हो रही हैं मंत्रीजी। वह डवलप होते ही वहां तुलेगा, दूसरे साधन भी तुलेंगे। वहां व्यापारी भी हैं, सारा का सारा सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं सहयोग करने को तैयार हूं। प्रशासन के ऊपर नाजायज दबाव है। प्रशासन को रोका जाये और मंत्रीजी, कृषि उपज मण्डी समिति के सैक्रेटरी से भी मेरी बात हुई है, आप भी इसमें मदद कर रहे हैं पर प्रशासन अपनी हरकत ठीक करे ताकि बदनामी नहीं हो और गौशाला में दस तरह की बातें होंगी, सरकार के ऊपर भी लांछन आयेगा। हमें भी एक तरह से कहा जायेगा कि आप अटकाने वाले हो इसलिए यह गौशाला हट रही है। हम पूरा सहयोग करेंगे। 2030 जो खसरा संख्या की जमीन है, हाट बाजार है और खाते में लिखा हुआ है, 978 में जमाबन्दी है, खसरा नम्बर है, गैर मुमकिन हाट बाजार है वहां। वहां सरसों तुलाई केन्द्र प्रारम्भ करने का आदेश सरकार करेगी, हमारी समस्या का स्वत: समाधान हो जायेगा। नई जमीन की जरूरत नहीं है। फर्श लदा हुआ है। वह बना हुआ है। पास में पीएचईडी का है। पीने का पानी है, सब कुछ ठीक है। यहां गायों के लिए छाया का इंतजाम है, सारा सब कुछ है जो दूसरी जगह है इसलिए गायों को डिस्टर्ब नहीं किया जाये। मण्डी में सरसों क्रय केन्द्र चालू किया जाये, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से चिंता जाहिर की है, इसमें तीन विभागों के अलग-अलग काम आपने बताये हैं। पहला, आपका यह कहना है कि अतिक्रमण है जिसको जिला प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। दूसरा, आपका यह कहना कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति के द्वारा जो वहां पर सरसों क्रय केन्द्र खोलने की बात कही है। अभी हाल ही में जिला कलक्टर, बून्दी से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे यह बताया है वहां पर सरसों क्रय केन्द्र में काम प्रारम्भ कर दिया गया है और गत वर्ष जहां सरसों क्रय केन्द्र स्थापित किया गया है, उसी जगह वहां प्रारम्भ कर दिया गया है।

जहां तक गौशाला का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कलक्टर से जो वार्ता हुई है, उन्होंने यह बताया कि यदि भूमि आबंटन का कोई प्रकरण हमारे समझ आयेगा तो निश्चित रूप से गौशाला के लिए भूमि का आबंटन किया जायेगा और उन्होंने यह भी बताया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे पशुपालन विभाग के माध्यम से मैंने जानकारी ली है, आज की तारीख में गौशाला करवर में कोई पंजीकृत नहीं है। ज्योंही वह पंजीकृत होगी, निश्चित रूप से उनको कोई भी सिवाय चक भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी और जो समस्या अभी सरसों क्रय केन्द्र की थी, वह चालू कर दिया गया है। यह सूचना अभी प्राप्त हुई है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि गाय को चारा डालना गुनाह है मंत्रीजी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कौन कहता है गुनाह है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। मैं विधान सभा में इस मामले को नहीं लाता, यदि जिला प्रशासन हठधर्मितापूर्वक, अन्यायपूर्वक तरीके से यह मामला नहीं रखता। आपकी सारी 12.50 बीघा जमीन है मंत्रीजी और वहां क्यों नहीं चालू करना चाहते? क्या आप जिला प्रशासन से डिक्टेट हो रहे हैं? जिला प्रशासन आपको मिस-लीड कर रहा है, मिस-गाइड कर रहा है? और आपके पास में 12.50 बीघा जमीन है, वहां चालू नहीं करना चाहते। जिला प्रशासन यह कह दे कि हम तो यह करेंगे, वह करेंगे, जिला प्रशासन से इतनी कमजोर कैसे हो गई सरकार? मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्रीजी, जिला प्रशासन में जो बैठे हैं अफसर, उनकी चलेगी कि सरकार की चलेगी कि जन प्रतिनिधि की भावना की बात होगी। वहां का बहुमत, आसपास के गांवों के लोग, मेरा मत स्पष्ट है कि सरकार अपनी क्षमता को समझे, अफसर जो कहे, हठधर्मिता बरते वह ठीक नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए आप कृपा करके जिला प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करिये, मैं लगाम लगाने की बात नहीं कहता, लेकिन आप उससे इस तरह से डिक्टेट होकर के जवाब दे रहे हैं, यह आपकी आदत ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। आप बताइये कि वहां साढ़े बारह बीघा जमीन का क्या कर रहे हैं आप। कोई अतिक्रमण नहीं है साढ़े बारह बीघा जमीन में।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा: हम करेंगे, आप दो बिस्वा में कैसे सरसों क्रय केन्द्र खोलने की बात करते हैं, आप कृपा करके...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। नहीं, यह कोई बहस का, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।

श्री रामनारायण मीणा: मंत्रीजी, आप जाकर मौका देख लें। आप जाकर मौका देख लें। आप निर्णय करें, जिला प्रशासन का नाम नहीं लें। व्यक्तिगत निर्णय हो रहा है वह।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, करेंगे, करेंगे। डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

श्री रामनारायण मीणा: वह जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, इस बारे में आपको, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारा सब यार्ड करवर में बना हुआ है उसके बारे में मंडी समिति से भी मैंने चर्चा की है और उसमें जिस प्रकार उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसी कोई आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं, सरसों एकत्रित नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में शीघ्र केन्द्र को चालू कराया जाना भी आवश्यक है, यदि हम उसको ठीक भी करा देंगे तो उसमें बहुत अधिक टाइम लगने की एक सम्भावना बन जायेगी, इसलिए मैं सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, ज्यों ही यह सरसों केन्द्र का काम अभी चल ही रहा है उसके बाद जो हमारे सब यार्ड को ठीक करने का काम है, उसके प्रस्ताव बना कर जो भी स्थिति होगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी मरम्मत का या सुधार का, यह हमारे विभाग के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण मीणा: मेरा तो आपसे अर्ज करना है माननीय मंत्रीजी, आप इतने अक्षम कैसे हो गये?

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा: वहां पर हाट बाजार बना हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां हाट बाजार बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। अब बार-बार इसका जवाब नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण मीणा: हाट बाजार बना हुआ है। यदि नहीं बना हुआ है तो बता दें कि हाट बाजार है या नहीं है। वहां फर्श बना हुआ है, वहां क्वार्टर बने हुए हैं, वहां पीने के पानी का इंतजाम है और आपसे जिला प्रशासन ने कह दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: वह उचित है। सरकार उसको उचित स्थान समझेगी उसी जगह तो करेगी।

श्री रामनारायण मीणा: यह कल को वहां बात खराब होगी तब हमसे कहोगे कि आप जाकर के, मैं वहां जाऊंगा कल। वहां हालत खराब होगी और मंत्रीजी, आप चलिये मेरे साथ। आप एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए गायों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। गायों के लिए बहुत चिंता है।

श्री रामनारायण मीणा: वहां बजरंग दल वाले आयेंगे, कल आर.एस.एस. के आदमी आयेंगे। कल को कांग्रेस के लोग आयेंगे। आप कृपा करके मेरे साथ चलिये। आप क्या चाहते हैं, रात भर में कोई वहां पत्थर भी पड़ा हुआ है तो हम हटा देंगे। जब वहां फर्श बना हुआ है वहां क्वार्टर बने हुए हैं..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी भावना...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा: नहीं तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या आफत आ रही है उनको।

श्री रामनारायण मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिये, यह गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप मंत्री महोदय, कृपा करके आप चलिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा: विधान सभा में मामला आने के बाद आप जवाब नहीं दे पा रहे, कल को दूसरे लोग उस बात को रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे दिया, माननीय सदस्य, आप क्या जवाब, आपके कहने के अनुसार थोड़े ही जवाब देंगे।

श्री रामनारायण मीणा: नहीं, मेरे कहने से नहीं। मैं जन प्रतिनिधि हूं, हम इनको राय देंगे, राय के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, मेरा तो यह अर्ज करना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। दे दिया निर्णय। कह दिया न। गौशाला की कोई जगह वहां पर है नहीं। किसी की की हुई, अलाटमैंट नहीं हुआ हुआ है।

श्री रामनारायण मीणा: हमें राय देने का अधिकार है। सरकारी

(श्री रामनारायण मीणा)

कर्मचारियों की बात मानें और हमारी बात नहीं मानें, यह तो बड़ी शर्मनाक बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप संतुष्ट नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपने कह दिया।

श्री रामनारायण मीणाः मैं बिलकुल बैठ जाऊंगा। आप मंत्रीजी से कहलायें, कल को वहां झगड़ा होगा।

श्री उपाध्यक्षः कह दिया मंत्रीजी ने जो बात थी।

श्री रामनारायण मीणाः मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कल को लड़ाई-झगड़ा होगा, फिर गृह मंत्रीजी क्या कहेंगे उनसे।

श्री उपाध्यक्षः मंत्रीजी ने जो आवश्यक थी वह बात कह दी।

श्री रामनारायण मीणाः कल को वहां लड़ाई-झगड़ा होगा, मैं जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि धार्मिक भावना है। सारे लोग हमारे हैं, बीजेपी हमारी है, कांग्रेस हमारी है, बजरंग दल हमारा है, गाय के मामले में सब एक है वहां। वहां कोई अंतर नहीं है और वहां जिला प्रशासन कल को कोई बात होगी....

श्री उपाध्यक्षः यह बहस का विषय नहीं है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणाः यह विषय है।

श्री उपाध्यक्षः नहीं है अभी।

श्री रामनारायण मीणाः एक जन प्रतिनिधि आपसे अर्ज कर रहा है, मंत्रीजी, आप मेरे साथ चलिये वहां।

श्री उपाध्यक्षः आपने अपनी भावना प्रकट कर दी, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया और आप कोई उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो मंत्रीजी से बात कर लेना।

श्री रामनारायण मीणाः प्रकट कर दी। कल को सदन में मेरे से क्वेश्चन किया जायेगा, कल को सदन में मेरे से पूछा जायेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या बात है, आप चलिये न मेरे साथ, शनिवार को चलिये, इतवार को चलिये, क्या बात है माननीय, आप जब तक वहां खुलवाइये, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं, मेरे पास भी विधायक कोष है।

श्री उपाध्यक्षः अभी कोई निर्णय इसमें, आप इस वक्त कोई निर्णय कराना चाहते हैं क्या इनसे? यह अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्शन लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा: मेरा तो एक निवेदन है कि कर्मचारियों से डिक्टेट नहीं हों, जनता की भावनाओं को समझें, एक-दो आदमियों से डिक्टेट नहीं हों और कृपा करके आप कोशिश करिये, मेरा तो यही अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती।

आक्सीटोसिन इंजेक्शन का दुरुपयोग

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक बहुत ही क्रूअल क्राइम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में हमने प्रकृति को पूजा है, पशु को पूजा है, पत्थर को पूजा है और अभी पूरा विश्व मानने लग गया है कि ईको बैलेंस के लिए जितनी आवश्यकता इंसान की है उससे ज्यादा आवश्यकता पशुधन की है और प्रकृति की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज में कुछ लोग अपने लालच के लिए जिस प्रकार से दवाओं का दुरुपयोग करते हैं और उनका दुरुपयोग करके धन कमाना चाहते हैं वह सोसाइटी के लिए बहुत चिंता की बात है। मैं आपका ध्यान आक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो उपयोग हो रहा है पशुधन में और वनस्पतियों में, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व अपने राजस्थान में बीस जगह छापे पड़े और करीब सात लाख इंजेक्शन आक्सीटोसिन के मिले जो कि बेन किया हुआ ड्रग है और उस इंजेक्शन को पशुपालक गाय का दूध निकालने में उपयोग करते हैं, सब्जी को जल्दी बड़ा करने के लिए हाई ब्रिड करने के लिए सब्जी बोने वाले किसान उसको सब्जी में इंजेक्ट करते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि ऐसा दूध जो आक्सीटोसिन से दुहा गया है या ऐसी सब्जी जो उससे पैदा हुई है उस सब्जी को काम में लेने से इंसान को भी कैंसर और इंपोटेंसी जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए क्रूअल है कि जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय का दूध दुहने के लिए जब आप यह इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी जो तड़पन होती है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी भयंकर तड़पन उस गाय को होती है दूध देते वक्त कि जिसकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता है। और तो और, इसके लिए हमने एजुकेट भी नहीं किया कि जो गाय दस साल दूध देती है, वह गाय आक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बाद तीन से चार साल तक से ज्यादा दूध नहीं दे सकती। वह भी कोई फायदेमंद नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी अज्ञानता, हमारी नालेज नहीं होना और हमारा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

लालच, और सरकार ने अपने काम की इतिश्री इसमें मान ली कि केन्द्र सरकार के सामाजिक अधिकारिता विभाग ने 2001 में एक इनको पत्र भेजा, उस पत्र की इतिश्री चाहे कोई भी सरकार तब रही हो या आज है, सरकार ने केवल एक निकाला सर्कुलर कलक्टर के नाम पर और एनीमल हसबेंड्री के नाम पर और पत्र निकाल करके चुप हो गये, आज भी उस पर कोई प्रभावी रोक नहीं है। जो ड्रग एच शिड्यूल में बेन है वह ड्रग आराम से मिल रही है और सात लाख की संख्या तो पकड़ी गई है छापे के अंदर, न जाने कितने लाख इंजेक्शन यह काम आते होंगे, जो आपके पशुधन को बरबाद कर रहे हैं और पशुधन को बरबाद करने के साथ-साथ जो जनरेशन वह दूध पी रही है उस पशु का, उसके अंदर अनाहूत रूप से ऐसे रोग पैदा कर रही है जिसकी कल्पना वह व्यक्ति आज नहीं कर रहे हैं। यही की यही स्थिति सब्जियों में है। सब्जियों में यह ड्रग का इंजेक्शन लगाकर के सब्जी पैदा करने वाले किसान यह सोचते हैं कि वह सब्जी ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वह सब्जी बड़ी हो रही है, दाम बड़े मिलेंगे। क्योंकि आज जब समाज के अंदर आर्थिक दौड़ मची हुई है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि सरकार ने जागरूक रहकर के इस इंजेक्शन पर बेन नहीं लगाया और बेन ही नहीं, चाहे कोई आपको नया कानून बनाना पड़े, ऐसे क्रूअल क्राइम को रोकने के लिए सरकार को अपने कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हम पशुधन को भी बचा सकें और साथ-साथ हम उन मनुष्यों को बचा सकें जो मनुष्य उस आक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बाद का दूध और सब्जी काम में ले रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आज सदन में इसलिए लेकर आया, यह कोई राजनीति की बात नहीं है, फिर भी मैं इसको लेकर आया, इसलिए लेकर आया कि यदि सोसाइटी के अंदर सदन में चर्चा नहीं होगी और सदन इस पर गम्भीरता से विचार करके कोई ठोस कदम नहीं उठायेगा तो हमें आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी क्योंकि जो दूध और जो सब्जी हम इंसान को पिलाना चाहते हैं या देना चाहते हैं वह उसके लिए नुकसानदायक है। उसके लिए नुकसानदायक है और साथ ही साथ पशुधन के लिए हार्मफुल है। तो मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं इस चर्चा के माध्यम से कि सरकार इस बात को बहुत गम्भीरता से ले और आक्सीटोसिन इंजेक्शन के राजस्थान में आने पर बेन लगाये और जिन लोगों को छापों में पकड़ा गया है उन लोगों के साथ ऐसी कार्यवाही करें, ऐसी कार्यवाही करें कि आइंदा कोई व्यक्ति यह हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सके कि गौ माता को

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

कष्ट देने के लिए इसका उपयोग किया जाये। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान दिया है आज आपसे और सदन से चाहूंगा कि हम सब का ध्यान एस.ओ.जी. के उस प्रयत्न के बाद हुआ। हमने लगातार एस.ओ.जी. टीम को लगाकर के इन लोगों को ढूंढने के लिए एक लम्बे समय से प्रयास करती है...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और आपने देखा होगा कि हमारी इस टीम ने राजस्थान के 17 ज़िलों में 60 स्थानों पर एक साथ रेड की और हमने तीन लाख इंजेक्शन उन लोगों से जो इसके अधिकृत विक्रेता नहीं थे उनसे हमने बरामद किये हैं। 24 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इस सारे के सारे रैकेट को जो बिहार से और बाकी जगह से जुड़ा हुआ है उसका हमने पता किया है और आगे भी हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। जो अधिकृत विक्रेता है वह ही इसका उपयोग करता है और वह केवल महिला को जिस समय प्रसव होता है उसमें किसी प्रकार का उसको कोई पेन न हो उसके लिए उसका उपयोग होता है लेकिन लोगों ने अपना धन कमाने के लिए उपयोग किया है तो आज सदन को इस घटना को आपके और अख़बार के सामने लाने का जो प्रयास एस.ओ.जी. की टीम ने किया है, सदन उसे धन्यवाद देना चाहता है कि उसके सतत प्रयास से हमने इतनी बड़ी गम्भीर समस्या को हमने पकड़ा है और उसके अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए हमारी टीम गई हुई है और भी जहां किसी भी इस प्रकार की इन दवाइयों का चाहे दुधारू गायों के लिए हो रहा हो या चाहे सब्जी या और किसी के लिए हो रहा है, निश्चित रूप से कठोरतम कार्यवाही करेंगे। 24 लोग पकड़े हैं और भी इसमें गिरफ्तारी होगी इतना मैं विश्वास दिलाता हूं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): एस.ओ.जी. को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गत सत्र में भी मैंने आक्सीटोसीन की बात उठाई थी और मैं धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह डिबेट की बात है क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप अगला नाम पुकारो। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपके प्रयास ने और आपका जो एस.ओ.जी. का प्रयास है वह वास्तव में तो तारीफ के काबिल है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गृह मंत्रीजी को कोई धन्यवाद दे तो भी आपको तकलीफ है क्या? (व्यवधान) वों धन्यवाद दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी को और उनके विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद, पर आपका ध्यान साथ में यह भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मेडिकल जो दवाइयां हैं उसका दुरुपयोग नशे में हो रहा है, यह भी आवश्यक है कि यंग जनरेशन को बचाने के लिए जिस तरह से आपने इसमें प्रयास किये यह भी प्रयत्न करें कि इस तरह की गोलियां, उस तरह की दवाइयां जो नशे में बच्चे यूज में ले रहे हैं उसके भी रैकेट को तोड़ें जिससे यह मैसेज जाए, आपके विभाग को बहुत-बहुत साधुवाद। आशा करते हैं इस संबंध में आप कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सदन का भी आभारी हूं क्योंकि एस.ओ.जी. के अभी हमारे पास एक टीम है अब के बजट में हमने दो टीम और ली हैं। इस प्रकार के और भी रैकेट हैं जो कबूतरबाजी में हैं या और किसी प्रकार में, इन सबको कसने के लिए ही इन टीमों को बनाया और वह सेपरेट इसी काम को करेगी, जो इस प्रकार की गलत गतिविधियों में शरीक हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देने के साथ ही इस बात पर ध्यान दिलाऊंगा कि डायकोफ्लोनिक जो दवाई है दर्द निरोधक पशुओं में यूज होती है और उसके कारण जो मृत पशु है उनको गिद्धों के खाने की वजह से गिद्ध पक्षी मृत प्राय: हो रहे हैं तो आप इस दिशा में भी इसके बारे में क्योंकि बैन तो लग गया है प्रदेश में मगर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ है और पांच करोड़ अपने आप में ये पशु हैं जो खुले में सड़ रहे हैं तो अगर ये पक्षी लुप्त हो जाएगा तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इसके ऊपर भी आप जांच करायें और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी इस प्रदेश की जो है सर्वे करेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कृषि विभाग

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री 24 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित 24 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-प.6(6)कृषि/ग्रुप-2/99 दिनांक 21.6.2006 जिसके द्वारा मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर हेतु भूमि अवाप्त की गई है ।
2. अधिसूचना संख्या-प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/III दिनांक 21.6.2006 जिसके द्वारा खैरथल मण्डी के लिए बाइपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई है ।
3. अधिसूचना संख्या-प.10(8)कृषि/ग्रुप-2/86/II दिनांक 22.6.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अंतर्गत गौण मण्डी यार्ड प्याज की सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।
4. अधिसूचना संख्या-प..6(2)कृषि/ग्रुप-2/99 दिनांक 27.6.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर को कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) उदयपुर से नामित किया गया है ।
5. अधिसूचना संख्या-प.6(13)कृषि/ग्रुप-2/96 दिनांक 28.6.2006 जिसके द्वारा गौण मण्डी यार्ड, झालरापाटन की सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।
6. अधिसूचना संख्या-प.6(3)कृषि/ग्रुप-2/98/III दिनांक 29.6.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के अंतर्गत नवीन गौण मण्डी यार्ड, शाहपुरा की सीमाओं को अधिसूचित किया गया है ।
7. अधिसूचना संख्या-प.6(3)कृषि/ग्रुप-2/98/III दिनांक 30.6.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के अंतर्गत नवीन गौण मण्डी यार्ड, बस्सी की सीमाओं को अधिसूचित किया गया है ।
8. अधिसूचना संख्या-प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/III दिनांक 1.7.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के नवीन यार्ड निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई है ।
9. अधिसूचना संख्या-प.6(7)कृषि/ग्रुप-2/96/III पार्ट दिनांक 28.7.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर द्वारा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

टर्मिनल मार्केट के निर्माण हेतु ग्राम केश्यावाला की भूमि अवाप्त की गई है ।

10. अधिसूचना संख्या-प.10(5)कृषि/ग्रुप-2/88 दिनांक 6.8.2006 जिसके द्वारा नई कृषि उपज मण्डी समिति, देई की स्थापना की गई है ।

11. अधिसूचना संख्या-प.10(7)कृषि/ग्रुप-2/78/II दिनांक 15.9.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट के अंतर्गत नये फल सब्जी मण्डी यार्ड हेतु भूमि अवाप्त की गई है।

12. अधिसूचना संख्या-प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 15.9.2006 जिसके द्वारा ईमारती लकड़ी पर से मण्डी शुल्क हटाया गया है ।

13. अधिसूचना संख्या-प.10(7)कृषि/ग्रुप-2/78-II दिनांक 9.10.2006 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.9.2006 में संशोधन किया गया है ।

14. अधिसूचना संख्या-प.17(69)कृषि/ग्रुप-2/89 दिनांक 13.10.2006 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों के जी.पी.एफ. नियमों में संशोधन किया गया है ।

15. अधिसूचना संख्या-प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 13.10.2006 जिसके द्वारा सूखा मेवे पर मण्डी शुल्क हटाया गया है ।

16. अधिसूचना संख्या-प.6(7)कृषि/ग्रुप-2/96 दिनांक 18.10.2006 जिसके द्वारा जयपुर फल सब्जी मण्डी क्षेत्र निर्धारित किया गया है ।

17. अधिसूचना संख्या-प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 19.10.2006 जिसके द्वारा ज्वार, बाजरा, मक्का पर मण्डी शुल्क की दर 100 रुपये पर 1.60 रुपये के स्थान पर 0.50 रुपये विनिर्दिष्ट की गई है ।

18. अधिसूचना संख्या-प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 19.10.2006 जिसके द्वारा मक्का, ज्वार व बाजरा पर 'क' वर्ग दलाल को संदेय कमीशन 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत किया गया है ।

19. अधिसूचना संख्या-प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 दिनांक 23.10.2006 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

20. अधिसूचना संख्या-प.6(14)कृषि/ग्रुप-2/2004 दिनांक 23.11.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमण्डी हेतु भूमि अवाप्त की गई है ।

21. अधिसूचना संख्या-प..6 (24)कृषि/ग्रुप-2/2003 दिनांक 1.2.2007 जिसके द्वारा गौण मण्डी यार्ड जावाल की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

22. अधिसूचना संख्या-प.10(64)कृषि/ग्रुप-2/79/II दिनांक 17.2.2007 जिसके द्वारा गौण मण्डी यार्ड गुढाचन्द्रजी व नारौली को मण्डी समिति, हिण्डौन के अंतर्गत घोषित किया गया हैं।

23. अधिसूचना संख्या-प.10(42)कृषि/ग्रुप-2/79/III दिनांक 1.3.2007 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) उदयपुर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

24. अधिसूचना संख्या-प..10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/III दिनांक 5.3.2007 जिसके द्वारा गौण मण्डी यार्ड किशनगढ़बास की सीमाएं निर्धारित की गई है ।

प्रतिवेदन

राजस्थान वित्त निगम के लेखों वर्ष 2005-06 पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरपतसिंह राजवी, उद्योग मंत्री वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37 (7) के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों का समय पर वितरण

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

ऑफ ऑर्डर। आज सदन में शिक्षा की डिमाण्ड है और वह दुर्भाग्य है उपाध्यक्ष महोदय बार-बार सदन में यह कहने के बाद कि प्रतिवेदन समय पर आयेंगे, ये संस्कृत शिक्षा का प्रतिवेदन संस्कृत शिक्षा विभाग यहां आज इस टेबिल पर रखा गया है और माननीय शिक्षा मंत्रीजी जितने काम्पीटेंट मंत्रीजी इस विभाग के मंत्री हो और उसकी चर्चा हो और उसको आज सदन प्रारम्भ होने के बाद में टेबिल पर रखा हो, मैं समझता हूं कि इस संबंध में एग्जम्पलरी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, you have to set an example. एग्जम्पलरी आप पनिसमेंट नहीं देंगे तो यह मैसेज नीचे नहीं जाएगा कि सदन में चर्चा करने से पहले प्रतिवेदन हमारे पास आना चाहिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आशा करता हूं कि मंत्रीजी जो हैं या तो ऑन करें खुद या यदि उनकी गलती नहीं हुई है तो विभाग के जिन कर्मचारियों ने उन विभाग को बदनाम करने की कोशिश की, आपके काम्पीटेंस को इन-काम्पीटेंस बताने में कोशिश की, मंत्रीजी खड़े होकर बतायें कि क्या आप इतने इन-कम्पीटेंट हैं कि आपके विभाग का प्रतिवेदन आज हमको सदन में मिले और आप उस पर कुछ नहीं बोले, मैं समझता हूं कि आपको इस बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रयत्न हो रहा है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संस्कृत शिक्षा और वह भी संस्कृत शिक्षा के ऊपर इस सरकार का रवैया जाहिर होता है कि संस्कृत के प्रति कितने संवेदनशील हैं?

श्री उपाध्यक्ष: देरी से आये हैं तो उसके ऊपर निश्चित कार्यवाही होगी (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना, ना, let the minister make a comment. मंत्रीजी खड़े होकर के बतायें कि कोई टेक्नीकल गलती है, कोई आपका ऐसा अनअवाइडेबल कोई बात हो तो मान लेंगे लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि यह मसला गम्भीर है तो आपसे कम से कम आप तो खुद ही विधि मंत्री हैं अब यह कानून की पालना भी आप नहीं कर पाये, शिक्षा मंत्रीजी भी आप हैं, सबसे पोपुलर शिक्षा मंत्री आप हैं, रोज आपकी वाहवाही होती है, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हो, स्कूले खोल रहे हो और इतने में ही आपका

(डा. सी. पी. जोशी)

ध्यान नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि आपकी कैप में जो फेदर में जो कैप लगे हुए हैं उसमें यह दाग क्यों लग रहा है आपको? आप खड़े होकर मंत्रीजी इस बारे में गम्भीरता से सदन को अवगत करायें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री की शह से अधिकारी और कर्मचारी आपको बदनाम तो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: इतना बहम मत करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी सारी व्यवस्था में सदन को यह अधिकार है कि जब डिमाण्ड पर चर्चा होती है, उसके 48 घंटे या 24 घंटे पहले कम से कम विभाग का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के पास पहुंचना चाहिए जिसको देखकर वो बोल सके, यह बहुत जरूरी है। हमारे चार-पांच प्रतिवेदन थे बाकी सारे प्रतिवेदन पहले पहुंच गये। आज सुबह जब यह प्रतिवेदन यहां रखा गया मैं भी यहीं बैठा था, यहां आने के बाद ही यह प्रतिवेदन आया, मुझे स्वयं को दु:ख हुआ इस बात का कि प्रतिवेदन इस समय वितरित क्यों किया जा रहा है? अंदर जाकर उसके तुरन्त बाद मैंने जानकारी प्राप्त की कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है, वैसे तो विभाग की जो भी गलती है वह मेरी ही गलती है लेकिन मैंने पता किया कि 15 दिन पहले यह मेरे यहां से प्रमाणित होकर चला गया। उसके बाद इसको लिखना चाहिए था, टाइम पर देना चाहिए था, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिया लेकिन जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है वह पर्याप्त नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती अधिकारियों के द्वारा हुई है और मुख्य रूप से इसलिए मैंने हमारे सुधीर भार्गव जो प्रमुख शासन सचिव हैं, उनको कहा है कि जो डायरेक्टर है उसको तुरंत आप ए.पी.ओ. कर दीजिए और सात दिन में मुझे जांच करके बताइए कि किसकी गलती है? डायरेक्टर संस्कृत एजुकेशन की मैं गलती मानता हूं, इस गलती के लिए ए.पी.ओ. करके सेक्रेटेरिएट में करते हैं और सात दिन में प्रमुख शासन सचिव से मैं कह रहा हूं कि वो निश्चित रूप से जांच करके रिपोर्ट दे, यद्यपि उन्होंने कहा है कि हमने इसको छपाने की पूरी कोशिश की है, उन्होंने कहा कि हमको कागज नहीं मिला, हमको प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिली, ये अपर्याप्त कारण थे। मैंने स्वयं ने जांच की है और मैं समझता हूं कि सदन सर्वोपरि है और सदन में परम्पराओं का निश्चित रूप से पालन किया जा रहा है। सरकार निश्चित रूप से पालन करेगी।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (सं. 3 व 4)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2006-2007 समिति के दो प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2006-2007 के निम्नांकित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

1. गृह विभाग की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण (अवशेष) के कार्य-कलापों से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन, एवं

2. अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग में पृथक-पृथक संवर्गों के चल रहे आरक्षण अवशेष (बैकलॉग) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का चतुर्थ परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सं. 2)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2006-2007 वित्त, अल्प बचत, आयोजना, राज्य बीमा, आर्थिक एवं सांख्यिकी व प्रशासनिक सुधार विभागों के वर्ष 2001 के लंबित आश्वासनों से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2006-2007 वित्त, अल्प बचत, आयोजना, राज्य बीमा, आर्थिक एवं सांख्यिकी व प्रशासनिक सुधार विभागों के वर्ष 2001 के लंबित आश्वासनों से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा, सदस्य विधान सभा दो याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

ब्यावर को जिला बनाने बाबत्

1 ब्यावर को जिला बनाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, एवं

ब्यावर में स्टेडियम का निर्माण

2 ब्यावर में स्टेडियम का निर्माण करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

कुचील एवं भांभोलाव (किशनगढ़) में पशु चिकित्सालय की मांग

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ (अजमेर) की ग्राम पंचायत कुचील एवं भांभोलाव में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

खोड़ा ग्राम (अजमेर) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने बाबत

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम खोड़ा (ग्राम पंचायत-बुबानी) जिला अजमेर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओ.पी. महेन्द्रा, सरकारी उप मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. ''इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 की क्लाज-1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2007-08 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 की क्लॉज-1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2007-08 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 की क्लॉज-1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2007-08 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233 ख की क्लाज-1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2007-08 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का पारण किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री ओ.पी. महेन्द्रा, सरकारी उप मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 की क्लॉज-1, 231 सहपठित नियम 232 की क्लाज-1, 232 ख की क्लॉज-1 द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति 'क', प्राक्कलन समिति 'ख' व राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है। सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 की क्लाज-1, 231 सहपठित नियम 232 की क्लाज-1, 233 ख की क्लॉज-1 को निलंबित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में जो प्रस्ताव रखा महेन्द्राजी साहब सरकारी उप मुख्य सचेतक ने उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ये व्यवस्था की जाए कि राजनीतिक दलों के जो नेता अपने सदस्यों के नाम दें उसमें हेराफेरी नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं करता है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बिलकुल सही बात है। पक्षपात हुआ है पहले। मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन कम से कम आप यह व्यवस्था करें। यह प्रस्ताव तो ठीक है प्रस्ताव का मुझे विरोध नहीं है लेकिन राजनीतिक दल के नेता जिन सदस्यों के नाम भेजें उसके अन्दर हेराफेरी नहीं होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती यह सर्वमान्य सिद्धांत है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को यह बात कहनी चाहिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर सदन में प्रस्ताव आया है कोई एक प्रस्ताव आया है ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नहीं कहना चाहिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रस्ताव आया है सदन में उस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव पर विरोध प्रकट कर सकता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामैंट्री मिनिस्टर साहब, उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप प्रतिपक्ष के

(डा. सी. पी. जोशी)

नेता के साथ मिल कर चर्चा करने के बाद प्रस्ताव लाते हैं तो आपने वो प्रक्रिया की है तो हम सहमत हैं । आप यदि हमारे प्रतिपक्ष के नेता को नहीं पूछ कर ये प्रस्ताव लाये हैं तो हमारे माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं बात ही नहीं की आपने। ये परंपरा नहीं है I am very sorry. मैं पार्लियामैंट्री मिनिस्टर महोदय, फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में पहले प्रतिपक्ष से चर्चा होने के बाद क्योंकि नियम ...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष से चर्चा होने के बाद उनके हस्ताक्षर हो गये, सारी बात होने के बाद हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, I am on a point of order. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में सरकार की तरफ से कोई माननीय मंत्री कोई बात कह दें तो उसका एक अर्थ होता है और ये जो कलेक्ट्रेट में जो प्रकरण होली के समय में हुआ था नृत्य-नाच हुआ, पत्रकारों की पिटाई हुई और माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य के अंत में यह कहा था कि मेरी दृष्टि में कलक्टर साहब पाँच बजे से पहले वहां मौजूद थे उनका उत्तरदायित्व है और उनको ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और यह कहा था कि मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करके सदन को अवगत कराऊंगा तो मैं जानना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी

(श्री जुबेर खान)

आज सात दिन से ज्यादा हो गये आप कब सदन को बतायेंगे कि आपके और मुख्य मंत्री के बीच क्या चर्चा हुई?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और क्या कार्यवाही उस कलक्टर साहब के खिलाफ करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ ऑर्डर का क्या प्रश्न है इसमें?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसको दूसरे तरीके से उठाइये आप। पाइंट आफ आर्डर क्या है इसमें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी शायद भावना नहीं समझ पाया और आपके कहने का अर्थ नहीं समझा। एक सेकिंड आप विराजें। बहुत ज्यादा जोर से भी बोलने से कोई चीज का हल नहीं निकल सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कहा जो मेरे वर्डिंग निकाल लो। टेप में वर्डिंग निकाल लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कहा था कि दो दिन में करेंगे तीन दिन में करेंगे मैंने ऐसा समय बताया? मैंने कोई यह नहीं कहा था कि मैं पांच दिन में करूंगा ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो कहा है उसको आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निकाल लें और पढ़ लें। मैंने बहुत संयमित शब्दों में कहा है जिसको अभी भी निकाल कर दुबारा पढ़ लें आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पाइंट आफ आर्डर को मैं डिस्अलाऊ करता हूं। कोई डिस्कसन नहीं इसके बारे में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आज की तारीख दी थी क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बार प्रोसीडिंग पढ़ लेना आप फिर उसके बाद बात करना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अब इस विषय पर नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: कहां धमका रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: यह डरते थोडे ही हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल ।

याचिकाओं का उपस्थापन

काशीपुरा से रूपाहेडी (बस्सी) तक सड़क निर्माण बाबत

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री सड़क योजना में तहसील बस्सी में काशीपुरा से रूपाहेडी तक सड़क का निर्माण करने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

वन विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य विधान सभा वन विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 131 के तहत वन अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वन विभाग में वन रक्षक और रेंजर फर्स्ट स्तर के अधिकारी और कार्मिकों की पदोन्नति में 20-22 वर्ष तक लग जाते हैं । साथ में मुझे इस तथ्य को स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है कि सरकार में विभिन्न पदों पर कैडर प्रबन्धन ठीक नहीं होने के कारण बहुत से विभागों में अनेक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में कार्मिकों के मनोबल को बनाये रखने के लिये बढ़ती उम्र के साथ बढ़ने वाली पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिये कार्मिकों को उच्च स्तर के पद सृजित नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने और उच्च स्तर के वेतनमान देने के लिये वर्ष 1992 में राज्य सरकार ने ऐसे कार्मिकों के लिये चयनित वेतनमान देने का प्रावधान किया था और उस

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्रावधान का लाभ अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह ही वन विभाग के इन कार्मिकों को मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, वनों पर बढ़ते जैविक दवाब, उनकी सुरक्षा और जिलों में बढते वन विकास के कार्य, वन्य जीव सुरक्षा की चुनौतियां आदि से वन कर्मियों के काम का दायित्व बढ़ गया है तथा देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक परिस्थितियां बदल रही हैं । अत: बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को वनों के विकास व सुरक्षा हेतु अधिक प्रभावी बनाने के लिये सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है और यह प्रक्रिया मात्र राजस्थान में है । हिन्दुस्तान में इस प्रकार के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का प्रस्ताव आज तक पेश नहीं किया गया । यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव के बाद निश्चित रूप से वन कर्मियों के कार्य वन अधिनियम व तदनंतर नियमों में उल्लिखित के अनुसार वन विभाग द्वारा यह जो पदोन्नति की व्यवस्था है और प्रशासनिक ढांचे में जो परिवर्तन की बात है निश्चित रूप से की जायेगी ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय ने हमारी इस बात को माना है कि इनकी पदोन्नति आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष: अब और क्या क्लियरीफिकेशन चाह रहे हैं आप ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा हूं वह मेरी बात से सहमत हैं लेकिन इनके अधिकारियों ने जो जवाब दिया है जो मैंने पूछा नहीं वह जवाब दे दिया । अभी वन मंत्रीजी ने भी इसमें बताया कि इन अधिकारियों को 9-18-27 का वेतनमान का लाभ मिल रहा है । मैंने मंत्री महोदय वेतनमान के लाभ की बात नहीं की । मैंने उनके कार्य में दक्षता लाने के लिये उनके प्रमोशन की बात की है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने अपने विभाग में परसों ही घोषणा की है कि मैंने शत प्रतिशत प्रमोशन करवा दिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल धन्यवाद के काबिल हैं और ईमानदार हैं, नेक हैं, कार्य में इनकी दक्षता है। मंत्री महोदय मैं आपसे यह चाहूंगा कि उनको लाभ देने की बात नहीं है, बात आती है प्रमोशन की । अभी कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया था आज हजारों एकड़ आपकी वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह इतनी ज्यादा बहस का विषय नहीं है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात पूरी तरह नहीं रख पाया और आप कहते हो बैठ जाओ । उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मैं इसकी मूल समस्या आपको नहीं बताऊंगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है और मूल समस्या यह है कि जो भी चर्चा चल रही है अभी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो बातें आप खुद देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उसकी मूल समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है । मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी आपने जो बात कही है जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इसमें सारे मामले पर डिस्कस नहीं हो सकता ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आज स्टाफ की कमी है, उनका प्रमोशन नहीं होने के कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन है । उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह बात कह रहा है ...

श्री उपाध्यक्ष: आपके कहने पर वक्तव्य दिलवाया है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूं । नेशनल फोरेस्ट कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रख रहा हूं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं करूं आप कहें तो बैठ जाता हूं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ... (व्यवधान) इनके क्षेत्र में तो कोई जंगल है नहीं तो इनको फोरेस्ट का क्या ज्ञान है । इनको फोरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात तो रखूं, यह तो कोई बात नहीं हुई । जब तक आप आधे घंटे की चर्चा नहीं करायेंगे..

श्री उपाध्यक्ष: इसमें यह स्कोप नहीं है । आप दूसरे नियमों में आइए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है जब तक मैं मेरी बात पूरी नहीं रखूंगा तब तक कोई मतलब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गई है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर के मुझे समय दें । सभी सदस्य इसकी सिफारिश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: नियमों में इतना ही हो सकता है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं फिर कहां अड़चन आ रही है? मैं मेरी बात नहीं रखूंगा तो क्या रखूंगा? उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत तथ्य पेश किये हैं मैं आपको बता रहा हूं । इन्होंने यह कहा कि श्री एस.एन. गुप्ता, अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.05 को बैठक आयोजित हुई थी । शासन सचिव वन, कार्मिक एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । समिति द्वारा बैठक में उक्त 64 पदों को क्रमोन्नत करने की सहमति व्यक्त की गई । एक तरफ यह लिख रहे हैं, ''की गई'', दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव वित्त ने उक्त अपग्रेडेशन की अनुशंसा कर पत्रावली तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय के पास भिजवाई थी। तब से उक्त पत्रावली अपग्रेडेशन की स्वीकृति के आदेश लंबित है यह मैंने कहा था और इन्होंने कहा यह सही नहीं है। अगर मैं असत्य हूं, यह सही नहीं है तो आप फाइल नम्बर, 12/9/2003 की, जिसमें उस वक्त के वित्त सचिव की आप फाइल मंगवा ले और उनका नोट देख लें। उन्होंने इसमें सिफारिश की थी इस प्रमोशन के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं स्टेट फाइनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट है, वह आपको बता रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी मुश्किल से स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया और उस गठन के बाद लगभग एक वर्ष के बाद, एक वर्ष की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में भी इन्होंने माना है कि जब तक.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, जब तक

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उनको प्रमोशन नहीं देंगे उनमें प्रस्ट्रेशन रहेगा और कार्य में दक्षता नहीं आयेगी और तब तक यह आई.एफ.एस. है, मैं आपको बताना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो इसमें बहस करने लगे। नहीं ऐसा नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात प्रस्तुत करूंगा। इन्होंने आई.एफ.एस. की जो लिस्ट है, आपके प्रगति प्रतिवेदन में, उसमें प्रशासनिक सेवाओं के 112 पद माने हैं जिसमें इन्होंने 94 पद ही बताए। 12 पद बताए राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति और 4 पद बताए केन्द्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं उसके बावजूद इन आई.एफ.एस. ने 5 पद रिक्त बता दिये। जब आपने 112 माने आई.एफ.एस. के, 112 पूरे हो रहे हैं, 96 पद भरे हुए हैं और 4 और 12 यह 16 हो रहे हैं 112 तो फिर 5 पद रिक्त क्यों बताए?

जब मैंने जानकारी हासिल की माननीय मंत्री महोदय से, तब यह बताया गया कि वो ए.सी.एफ. है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए.सी.एफ., आई.एफ.एस. है इस वजह से इन्होंने कैडर भी रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह आई.एफ.एस. वन को खा रहे हैं, जंगली जानवर को खतम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों का प्रमोशन नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): और एक्स कैडर क्या होता है (व्यवधान) जितने ए.सी.एफ. के पद, जो रिटायर हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। आपने भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उन ए.सी.एफ. का पद निरस्त करके आर.एफ.एस. में आई.एफ.एस. में पदोन्नति कर दी, बढ़ोतरी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, वह एक्स

कैडर इन्होंने अलग से सृजित कर दिया। जब गार्ड कल रिटायर होगा, फोरेस्टर रिटायर होगा तब उस फोरेस्टर और गार्ड का भी एक्स कैडर करके उसकी जगह आई.एफ.एस. लगा दे, वह क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्स कैडर के नाम से आई.एफ.एस अपनी पदोन्नति ले रहा है, अपने जीवन काल में वह 25 साल की सर्विस में 6 पदोन्नति लेता है, अधीनस्थ अधिकारी को 25 साल में एक भी पदोन्नति नहीं मिली। उनको लाभ पूरा मिल रहा है, वन विभाग के ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं आ रहा।

श्री उपाध्यक्ष: यह जनरल (व्यवधान) अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो दे देंगे, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो भाषण शुरू कर दिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा, आप समय बरबाद नहीं करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा यह।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव के महत्व को कमजोर कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव इस तरह से...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: यह भाषण देने की परमिशन किसने दी है आपको।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात को स्वीकार किया है कि काडर प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण यह समस्या मात्र वन विभाग में ही नहीं है, यह समस्या अनेक विभागों में है जिनमें कार्मिकों की पदोन्नति का मामला है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान महामहिम उप राष्ट्रपति ने 1992 में चयनित वेतनमान की व्यवस्था की, 9-18-27 और उसका लाभ वन कर्मचारियों को भी मिल रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने सदन को अवगत कराया कि वास्तव में वनों के जैविक दबाव, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा, अदालतों में पैरवी के लिए और अनेक वन विभाग की समस्याओं को देखते हुए प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए हमने एक प्रारूप तैयार किया है, वह राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। उसमें काडर प्रबंधन की पूरी व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर बीच में, आप जवाब नहीं सुनना चाहते वह अलग बात है पर बीच में मत बोलिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उसमें पदोन्नति, प्रमोशन, अपग्रेडेशन की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार के पास यह व्यवस्था विचाराधीन है। 73 ए.सी.एफ. जिनके अपग्रेडेशन के लिए हमने प्रस्ताव किया है, राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं आपको, सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर यह प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का, इसमें राज्य सरकार ने विचार किया तो एक राजस्थान मॉडल और एक उदाहरण पेश होगा। वास्तव में राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में वन्य जीव जंतुओं की हत्याओं पर प्रतिबंध लगा है। कठोरता से हमने काम किया है। आपने रणथम्भौर की बात की। मैं मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि रणथम्भौर में 14 कब्स और टाइगर सुरक्षित हैं, पूरी देखभाल की जा रही है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिये हमने वित्त विभाग से, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फाइनेंस, हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फोरेस्ट, चीफ सैक्रेटरी के बीच में चर्चा हुई है, इस पर विचार चल रहा है और अगर इस प्रशासनिक ढांचे को मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन आयेगा। मुख्य मंत्रीजी भी इस बारे में चिन्तित हैं। एक हजार गार्ड जो सेवानिवृत्त हैं उनको, घोषणा की है और नये गार्डों की भर्ती के लिये...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बीच में टोकें नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच-बीच में टोका-टाकी नहीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि कर रहे हैं। (व्यवधान) बहुत सीधी सी बात है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय सदस्यों ने जो आई.एफ.एस. की बात की और उन्होंने रिक्त पदों की भी बात की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, बीच में नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आई.एफ.एस. के बारे में इन्होंने चर्चा की, मैं आपको जानकारी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

देना चाहूंगा, सेण्ट्रल डेपुटेशन रिजर्व में 13, स्टेट डेपुटेशन रिजर्व में 17 और ट्रेनिंग रिजर्वेशन में 2, ऐसे कुल 101 और लीव रिजर्व जूनियर पोस्ट रिजर्व के लिये 11, यह 101 प्लस 11 टोटल 112 हो गये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह क्लीयर किया न मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, यह प्रश्न-जवाब के बारे में नहीं है। आपने स्पष्टीकरण दे दिया कि हम कर रहे हैं कार्यवाही, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग भी नये पदों के सृजन के लिये चिन्तित है। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बारे में चिन्तित हैं। निश्चित रूप से यह मामला मुख्य मंत्रीजी और वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और इस पर विचार कर मुख्य मंत्रीजी कोई न कोई निश्चित रूप से निर्णय लेंगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): XXX

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आवश्यक कार्यवाही हो रही है। अब यह फालतू... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह प्रमोशन के पदों के लिये ए.सी.एफ. बनाने के लिये यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। प्रक्रिया के अधीन मामला चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया चल रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं अपनी तरफ से आप लोगों की भावनाओं और वन विभाग की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पुन: आग्रह कर, इस मामले में कोई न कोई निर्णय होगा, निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: घनश्यामजी तिवाड़ी। अनुदान की मांग।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बता दिया, आप पूछ लेना। आप मिलते रहते हैं, आप इनसे यह पूछ लेना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी राय ही नहीं, पूरे फोरेस्ट विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग में भेजा हुआ है और हमारी राय है, जब हमने प्रस्ताव भेजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांग संख्या 24, विचार एवं मतदान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,26,39,15,000/- (अक्षरे रुपये पचास अरब छब्बीस करोड़ उन्तालीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों क लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट भाषण पढ़ा था, उन्होंने कला एवं संस्कृति विभाग का नाम कला, संस्कृति और साहित्य रख दिया। तो क्या साहित्य इसमें सम्मिलित है या नहीं है, इसको आप स्पष्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मांग एक ही है सब की, मांग संख्या-24 है। अब नाम मुख्य मंत्रीजी ने घोषित कर दिया, इसके बाद प्रश्न ही कहां पैदा होता है। अभी तक विभाग का नाम शिक्षा, कला एवं संस्कृति है। जब विभाग का नाम शिक्षा अलग रहेगा, कला एवं संस्कृति के साथ साहित्य और जुड़ जाएगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): व्यवस्था का प्रश्न तो है। अब देखिये, पहले कला और संस्कृति था। अब कला, संस्कृति और साहित्य होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह अलग से, यह शिक्षा, कला एवं संस्कृति फिर शिक्षा, कला एवं साहित्य एवं संस्कृति भी हो जाएगा तो डिमाण्ड संख्या-24 ही रहेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, तो फिर उनको साहित्य जोड़ना नहीं चाहिए था? नहीं, तो साहित्य उनको अलग नहीं करना चाहिए था?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अभी तो वही है। अभी डिमाण्ड यही है, हैड यही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह ठीक है लेकिन उस हैड को करेक्ट करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): संशोधन करा देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि गत 3 वर्षों में राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, वह अभूतपूर्व काम किया है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने स्वस्थ, हरित, शिक्षित और विकसित राजस्थान की कल्पना की है।

(समय : 14.38 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति पदासीन)

राजस्थान के सभी निवासी स्वस्थ हों, राजस्थान में हरित क्रान्ति हो, राजस्थान में सभी बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले और इसी के साथ-साथ राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आये, इस बात की कल्पना उन्होंने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को जो कि विद्वान हैं, उन्होंने हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच को अमली जामा पहनाया। उसमें उनका उद्देश्य यह रहा कि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ें, सभी बच्चे स्कूल में ठहरें, सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो। इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति उन्होंने की है। बच्चे पढ़ें, बच्चे ठहरें और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करके अच्छे संस्कार प्राप्त करें।

'ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान' की भावना से बच्चे शिक्षा प्राप्त करके देश के अच्छे नागरिक बनें। उसके लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया कि हर ढाणी में विद्यालय हो। शिक्षा मंत्रीजी ने तय किया। अमलीजामा पहनाने के लिए तय किया। हर ढाणी में विद्यालय हो, हर विद्यालय में भवन हो, हर विद्यालय भवन में शिक्षक हो और हर शिक्षक के पास में शिक्षण सामग्री हो।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

यह लक्ष्य तय किया क्योंकि यदि ढाणी में विद्यालय नहीं होगा तो हम सर्व शिक्षा अभियान को पूरा नहीं कर सकेंगे। विद्यालय का भवन नहीं होगा तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? विद्यालय का भवन भी आवश्यक है और फिर शिक्षक भी आवश्यक है और शिक्षकों के पास में शिक्षण सामग्री भी आवश्यक है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तिवाड़ीजी ने कदम आगे बढ़ाये और जो अधिकतर शिक्षा मंत्री करते हैं ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ज्यादा ध्यान रहता है। इनका ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, राजस्थान का प्रत्येक छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसकी ओर गया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के बारे में कल्पना की, वह कल्पना इन्होंने भी की। स्वामी विवेकानन्द ने 'असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय' के साथ-साथ यह भी कहा कि हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिनके चेहरों पर आभा, बुद्धि में पांडित्य, शरीर में बल, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, जीवन में स्वावलम्बन, हृदय में शिवा, प्रताप, ध्रुव और प्रहलाद की जीवन गाथाएं अंकित हो और जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियां आज झंकृत हो उठे। इस प्रकार के छात्र तैयार करने हैं और उस प्रकार के छात्र तैयार करनें की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानन्द के सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान आगे बढ़ रहा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं, एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां, एक साथ 39 हजार से अधिक विद्यालयों की शुरूआत एवं क्रमोन्नयन, कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत राजस्थान, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की स्थापना, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित संस्थाओं से एम.ओ.यू. कर विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के व्यापक प्रसार और उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा राजस्थान का स्थान दिलाना, यह एक बहुत बड़ी पहल हुई है।

मैं हर उपलब्धि पर विस्तृत जाने से पूर्व जो नये काम, जो नये नवाचार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में किये गये हैं उनका मैं वर्णन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, एक अनूठी योजना चलायी- 'आपणी धरती, आपणा लोग', इतिहास संकलन की एक बहुत अच्छी योजना चलायी है और इस योजना के माध्यम से गांव-गांव में इतिहास के संकलन में लोग लग गये। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, उस पर हमें गर्व है। यह अंग्रेजों का इतिहास, यह मुग़लों का इतिहास, यह हमारा इतिहास नहीं है। इससे पूर्व जो हमारी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

संस्कृति जब गांवों में बसती थी, रचती थी वह हमारे छात्र पढ़ें, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें, अपनी ख्याति को आगे बढ़ायें, इस दृष्टि से जो प्रयास किया है वह बहुत ही अच्छा प्रयास है।

इन्होंने शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन को ले जाने पर रोक लगायी। पेप्सी और कोला जैसे शीतल पेय पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको स्कूलों में ले जाने में पाबंदी लगायी और योग शिक्षा को शुरूआत करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश, यह हमारा बन रहा है। योग शिक्षा स्वामी रामदेवजी के तत्वावधान में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया गया और उसी के साथ योग शिक्षक खड़े करके योग की शिक्षा प्रारम्भ की गयी।

माननीय सभापति महोदय, पारदर्शी तरीके से एक लाख लोगों को रोजगार दिया गया। एक लाख लोगों को और एक लाख लोग भी वह जिनको पूर्णतया वेतन मिलेगा, पूरे सरकारी कर्मचारी का। यह कोई ऐसे टेम्प्रेरी शिक्षक खड़े नहीं किये हैं। योग्य शिक्षक, शिक्षा के लिए आवश्यक है कि पढ़ाने वाला व्यक्ति योग्य हो। विद्वान हो। चरित्रवान हो। गांव में ऐसे किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि तू दसवीं पास है तो पढ़ा। तू बी.ए. पास है तो पढ़ा। तू नौवीं पास है तो पढ़ा। इस प्रकार की यह टेम्प्रेरी व्यवस्था हमारे राजस्थान में लागू थी। यह हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने योग्य शिक्षकों की भर्ती का बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और एक लाख शिक्षक आज गांव-गांव में हमारी वसुन्धराजी राजे सरकार को यह कह रहे हैं कि वास्तव में वसुन्धराजी ने जो कहा वह करके दिखाया और हमें रोजगार दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के टाइम पर भी शिक्षा मंत्री थे वे भी विद्वान थे। हमारे शिक्षा मंत्री भी विद्वान हैं। वह भी अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे शिक्षा मंत्रीजी भी अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं।

श्री सभापतिः आप तो मुद्दे पर आ जाओ, साहब।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वे भी शिक्षा मंत्री थे और यह भी शिक्षा मंत्री हैं लेकिन हमारे पंडित विद्वान साथी भाई घनश्यामजी उनसे बहुत ही आगे निकल गये शिक्षा के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक लाख लोगों को रोजगार दिया। विधवाओं को रोजगार दिया। प्रत्येक एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय खोला। एक किलोमीटर की परिधि में और दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा का प्रावधान किया और जनजाति क्षेत्र की 12255 बालिकाओं को नि:शुल्क साइकलों का वितरण किया। 39 हजार से अधिक विद्यालय खोले और क्रमोन्नत किये। यह इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बच्चों को साइकल देना, गांव-गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए, उनके ठहराव के लिए, जाग्रत करना उनको पूरी सुख-सुविधाएं देना, मिड-डे-मील की व्यवस्था करना और अभी तो हमारे बजट में जहां-जहां पर मिड-डे-मील केन्द्र सरकार नहीं दे रही है वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की है कि हमारी सरकार मिड-डे-मील देगी और इसके लिए चालीस करोड़ से ज्यादा का प्रावधान भी किया गया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, अतिरिक्त कक्षा कक्षों की व्यवस्था और प्रदेश में एक भी विद्यालय भवनविहीन नहीं है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी वहां पर कोई पता ही नहीं था कि विद्यालय कहां चल रहा है? पेड़ के नीचे विद्यालय चल रहा है। खाली आसमान में विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। टाट-पट्टी की व्यवस्था नहीं है। चॉक की व्यवस्था नहीं है। बिजली कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से हमारे यह विद्यालय चल रहे हैं लेकिन तीन साल में जिस प्रकार से भौतिक उपलब्धियां की हैं वह अभूतपूर्व है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने 1 अरब 68 लाख रुपये की नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की हैं। 1 अरब 68 लाख रुपये की फ्री, नि:शुल्क। 1 अरब 68 लाख रुपया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 अरब से ज्यादा की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना, यह वही इस बात का द्योतक करता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। सभी छात्र पढ़ें और उनका अधिकतम ठहराव हो। ठहराव की दृष्टि से मिड-डे-मील देना, पुस्तकें देना, साइकिलें देना और जयपुर शहर में और विभिन्न शहरों में यह व्यवस्था की कि उनको नि:शुल्क बसों के पास भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब चारों ओर शिक्षा का इस प्रकार का वातावरण बन गया कि प्रत्येक मां-बाप अपने बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षा देना चाहता ही चाहता है। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं किसी कारण या कोई काम-धन्धा कर रहे हैं और नियमित रूप से विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, उनके

लिये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, स्टेट ओपन स्कूल की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं ओपन स्कूल के माध्यम से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 50 हजार है। 50 हजार विद्यार्थी आज ओपन स्टेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार से यह काम कर रहे हैं उससे हमारी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का ठहराव बढ़ रहा है, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है ।

माननीय सभापति महोदय, विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से "विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना" विद्यार्थियों के लिये लागू की गयी है और हमारे विद्यार्थी इन्टरनेशनल स्टेण्डर्ड के बनें, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की भी निश्चित रूप से प्रारम्भिक शिक्षा अच्छी हो, सुदृढ़ हो, उसके लिये पहली कक्षा से ही अंग्रेजी के पढ़ाने की व्यवस्था की है।

वनवासी क्षेत्र में निजी स्कूलों की मान्यता के लिये आधा शुल्क लिया गया है। सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की कम्प्यूटर फीस पचास प्रतिशत कर दी गयी है। संस्कृत शिक्षा के लिये पृथक से बजट का प्रावधान किया गया है। मैं इसमें माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत बधाई देना चाहता हूं । संस्कृत शिक्षा, जो हमारी मातृ भाषा की शिक्षा है, उसके लिये आपने सोचा, उसके लिये क्रियान्वित किया और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से पूरी सरकारी सहायता उनको प्रदान कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जहां राष्ट्रीय औसत उच्च शिक्षा में 8 प्रतिशत है, राजस्थान में उसका औसत 11 प्रतिशत है। जहां 2003-04 में एक लाख साठ हजार विद्यार्थी पढ़ रहे थे, आज करीब चार लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं। यह शिक्षा के वातावरण से ही हुआ है। जब प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो उच्च प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी होगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो ध्यान रखो पहले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री सुरेश चौधरी : इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं कि बड़े मगन होकर सुन रहे हैं, वह सो थोड़ी रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी तो

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

उच्च शिक्षा भी हमारी बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यह बेस तैयार किया, राजस्थान में पढ़ाई का वातावरण तैयार किया है, उस आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और मैं समझता हूं कि जहां चार लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण आज बन रहा है, निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा में, विभिन्न शिक्षा के आयामों में हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमारा राजस्थान आगे होकर देश का नाम रोशन करेगा। इस बात के लिये मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय खुले, इस बात की हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। 41 नये विधि महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। महाविद्यालय में 308 नये रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के आधार पर हमें इस बात के लिये गर्व है कि आज राजस्थान की उच्च शिक्षा की दृष्टि से कैम्प्स इंटरव्यू प्रारम्भ हो गये। बड़े-बड़े जो लोग हैं वह बड़ी-बड़ी कम्पनियां कैम्प्स इंटरव्यू के लिये आ रही हैं और हमारे राजस्थान के छात्रों को नौकरियां मिल रही हैं, अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। महाविद्यालय में ई-नेटवर्क कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है और टैक्नीकल एजुकेशन की दृष्टि से जिस प्रकार से हमने काम किया है, वह बहुत ही अभूतपूर्व है। कोटा में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की है। सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स की स्थापना की है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 15 हजार से अधिक सीटों की रिकार्ड वृद्धि हुई है। एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश की पहल हुई है। एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश इन तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हुआ है और माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में आर.एन.डी. एण्ड साइंस टैक्निशियन की अन्य देशों के मुकाबले संख्या कम है। पर थाउजेंड पापुलेशन जापान में 7.1 प्रतिशत है, जर्मनी में 4 है, इजरायल में 5.9 है, यू.एस.ए. में 4 है, कोरिया में 2.9 है, ब्राजील में 0.2 है, चाइना में 0.6 है, लेकिन भारत वर्ष में वैज्ञानिक और तकनीशियनों की एक हजार पर उपलब्धता केवल 0.3 है। पूरे विश्व भर में हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे डाक्टरों की, हमारे इंजीनियर्स की, हमारे एम.बी.ए. करने वाले लड़कों की, हमारे कम्प्यूटर इंजीनियर्स की बहुत बड़ी डिमाण्ड है। इस डिमाण्ड को पूरा करने के लिये तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा में निवेश निश्चित रूप से आवश्यक है और इस दृष्टि से जो प्रयास हमारी राजस्थान सरकार ने किया है, वास्तव में बधाई की पात्र है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्टरनेशनल

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

लेवल पर जो एजुकेशन हो रही है और जिस प्रकार से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यूज. किये हैं, वह एम.ओ.यूज.कम नहीं हैं। वह एम.ओ.यूज. जो किये हैं वह विभिन्न संस्थाओं के साथ किये हैं जिसमें नन्दी फाउंडेशन, जिसमें अमेरिका की बहुत सारी कम्पनियां, कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, अजीम प्रेमजी फाउडेंशन के सहयोग से संचालित है। माइक्रोसोफ्ट, यह बहुत बड़ी कम्पनी है। इससे भी हमने एम.ओ.यू. किया है । अमेरिकन इण्डियन फाउंडेंशन से हमने एम.ओ.यूज. किया है। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबल इस संस्था से भी हमने एम.ओ.यूज. किया है। सिसको हॉल इन द वॉल, बच्चों के स्वयं के हाथों में सीखने के लिये भी यह किया है। इन्टेल 3600 सैकण्डरी विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। बोध शिक्षा समिति, जो जयपुर शहर में असुविधा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। इससे भी एम.ओ.यूज. किया है। लर्निंग गारंटी प्रोग्राम, प्रेमजी फाउंडेशन, अब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन छोटी-मोटी संस्था नहीं है, नन्दी फाउंडेशन कोई छोटी-मोटी संस्था नहीं है। सी.आई.आई., यह कोई छोटी-मोटी संस्था नहीं है। सी.आई.आई. अडाप्ट थ्री स्कूल्स। यह प्रोग्राम सी.आई.ए. मिड डे मील प्रोग्राम, फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पीरामल फाउंडेशन, इतने बड़े-बड़े नाम हैं।

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के विख्यात नाम, अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में राजस्थान को चमकाने वाले नाम, अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में राजस्थान के बच्चों को आगे बढ़ाने वाले नाम, आई.सी.आई.सी.आई., इन सब संस्थानों से और हमने एम.ओ.यू. करके बालकों के सर्वांगीण विकास के प्रयास किये हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से एम.ओ.यू. किया और देश ही नहीं विदेश की शिक्षा भी उनको प्राप्त हो सके, आधुनिकतम शिक्षा प्राप्त हो सके इस बात के लिए प्रयत्न किया।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं प्रथम वक्ता हूं, सभापति महोदय, आप बैठा देंगे तो मैं तो अभी बहुत तैयारी करके आया हूं।

श्री सभापति: प्रथम वक्ता हैं तो समय की भी सीमा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने गांव-गांव गोद लेकर के उनके तकनीकी संस्थानों को भागीदार बनाया और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने काम किये हैं, मैं समझता हूं कि इसकी एक रोजगार की राह भी बढ़ी है।

राजस्थान देश का एक पहला राज्य है जहां पर शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश हुआ है। सर्वाधिक निवेश, इसके आंकड़े देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह निवेश किस प्रकार से हुआ है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 1413 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, स्कूल शिक्षा में 1222 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 3500 करोड़ का निवेश हुआ है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के इस शिक्षा क्षेत्र में 7135 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो एक दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, बधाई के पात्र हैं, 7135 करोड़ रुपये करीब-करीब और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से तीन वर्षों में 8135 करोड़ रुपये का निवेश हो गया जो कि राज्य की वार्षिक योजना के बराबर है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां साक्षरता की दर में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है, 23 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है और राजस्थान में महिला साक्षरता की दृष्टि से जो पहले 20 परसेंट थी अब 43 परसेंट हो गयी। महिला साक्षरता 43 परसेंट। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से महिलाओं को चांस मिल रहे हैं, महिला शिक्षा की ओर जब हमारा ध्यान जा रहा है, आज राजस्थान के तीन बड़े पदों पर महिलाएं हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी महिला हैं, विधान सभा अध्यक्ष महिला हैं, राज्यपाल महिला हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, महिला शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो एक सिफारिश मेरी भी कर देना माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि अभी पूरी हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में एक भी सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी में विज्ञान का विषय नहीं है। आप जिन इंजीनियरों की बात कर रहे हो न, तो वो वहां पैदा ही नहीं हो रहे इसलिए आप मेरी सिफारिश कर देना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपके राज में तो बेसिक शिक्षा ही आप नहीं दे रहे थे। अभी मैंने आंकड़े बताये हैं, एक लाख 60 हजार विद्यार्थी आपके समय जब हमने चार्ज लिया था उच्च शिक्षा में पढ़ रहे थे, आज चार लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरी विधान सभा का तो एक ही नहीं है। विज्ञान का विषय ही नहीं है पूरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी स्कूल में, रिकार्ड है राजस्थान का।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आपकी विधान सभा के आंकड़े माननीय शिक्षा मंत्रीजी देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आये जब बोल लेना आप।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): कृपया बीच में बोल कर नये विद्यार्थियों की भ्रूण हत्या न करें। आपके हाथ जोड़ते हैं हम।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और हरिमोहनजी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपके क्षेत्र में भी जो किया है वो बता देंगे लेकिन पूरे राजस्थान का आंकड़ा मैंने दिया और मैं समझता हूं जब तक कि बेसिक शिक्षा का आंकड़ा पूरा नहीं होगा, बेसिक शिक्षा पूरी नहीं होगी उच्च शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त होगी।

राजस्थान का रैबारी समुदाय जो कि बकरियां चरा करके अपना जीवन यापन करता है उसको पढ़ने-लिखने की फुर्सत ही नहीं थी, उसको पढ़ाई-लिखाई के लिए विशेष व्यवस्था की गयी, 'झोली और झोली में किताबें'। एक अनूठी योजना है यह। कहां-कहां से आप आइडिया लाते हैं, यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन गरीब से गरीब विद्यार्थियों को भी, दूर-दराज के विद्यार्थियों को भी, जो लोग स्कूल तक नहीं पहुंच सकते उनको भी, जो स्कूल तक पहुंच कर छूट जाते हैं उनको भी स्टेट ओपन विद्यालयों के माध्यम से आपने जो पढ़ाई करने की योजना बनायी है उसका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): स्टेट ओपन स्कूलों में किताबें भेजीं आपने आठ महीने बाद। आठ महीने बाद भेजी हैं किताबें, यह माना है आपने और यह स्टेट ओपन स्कूल की बात कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): खुले तो हैं न यह?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): भेजी तो हैं, आपने तो वो भी नहीं भेजी थीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें, बाइंडअप करें। तीस मिनट हो गये आपके।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, हमारे सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके, उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए बहुत आगे कदम उठाये हैं लेकिन एक शिक्षा और है जिसके मंत्री भी हैं माननीय घनश्यामजी और वह है चिकित्सा शिक्षा। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा शिक्षा का विभाग अलग किया, उसके परिणाम सार्थक आये हैं और उस शिक्षा में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, जयपुर में मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया, उसके लिए विधेयक पास किया, नयी कैथ लैब सेवाएं जयपुर, अजमेर में करीं, एस.एम.एस. अस्पताल की कायाकल्प कर दी और वहां आज आप देखिये कि किस प्रकार से एस.एम.एस. अस्पताल में लोगों की सेवा की जाती है और एस.एम.एस. अस्पताल एक तरह से पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश भर का एक अच्छा और आदर्श और मॉडल अस्पताल बन गया। वहां पर सेवा भाव से हमारे चिकित्सक काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि चिकित्सकों की भर्ती, सीनियर रेजिडेंट्स के पद सृजित करना और 119 करोड़ रुपये की लागत से एस.एम.एस. से सम्बद्ध चिकित्सालयों की कायाकल्प की योजना माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बनायी है। इसी के साथ-साथ 40 करोड़ रुपये की लागत से मानसरोवर, जयपुर में एक बड़ा विद्यालय, चिकित्सालय प्रारम्भ कर रहे हैं 'आरोग्य सदन'। मैं समझता हूं कि जयपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, जयपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा आयाम है और सभी विद्यालय और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टैली मेडिसिन से जुड़े हैं, उसके लिए प्रयत्न किये हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले शिक्षा विभाग की योजना करीब 400 करोड़ की हुआ करती थी आज वो 1400 करोड़ की हो गयी और आज 1400 करोड़ की होने के साथ-साथ हमारे शिक्षा मंत्रीजी देश की सर्वोच्च कैब कमेटी के अध्यक्ष रहे और कैब कमेटी ने सिफारिश की है, अभी ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार इस योजना में फिफ्टी-फिफ्टी करना चाहती है कि जो सर्व

शिक्षा अभियान है उसको माध्यमिक स्तर तक ले जाया जाए और उसमें राज्य का प्रतिशत 25 परसेंट ही रखा जाए। 50 परसेंट अगर रहेगा तो राज्य में चूंकि पहले ही पैसा कम है इसलिए इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार उस पुरानी योजना को लागू करे और 75 परसेंट और 25 परसेंट की उस नीति को लागू करके और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान को एक और बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है और वह उपलब्धि प्राप्त हुई है कि राजस्थान को यूनेस्को पुरस्कार दिया है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। यूनेस्को का पुरस्कार प्राप्त करना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

पाकिस्तान को भी मिला है, बंग्लादेश को भी मिला है और अन्य देशों को भी मिला है लेकिन भारतवर्ष में सिर्फ राजस्थान को इस प्रकार से यह पुरस्कार मिला है, यूनेस्को पुरस्कार। दूर-दूर तक शिक्षा को पहुंचाना, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शिक्षा को पहुंचाना ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): पाकिस्तान से तुलना कर दी आपने।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तुलना नहीं की है। जो है वह फैक्ट है एक राजस्थान में कई पाकिस्तान, कई बांग्लादेश आ सकते हैं ...(व्यवधान) मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इतना बड़ा राजस्थान दूरदराज के क्षेत्र हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी......

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप गुस्सा मत करो, विद्वान नहीं हैं हम लोग, हमें पता नहीं है इस कहानी का, आंकड़ों का इसलिए आप क्षमा करें पर तुलना आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान से की तो हमारी तो सोच के हिसाब से कह दिया। आप तो पढ़कर बता रहे हो, पढ़ना हमें तो आता नहीं ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और स्टेट्स में जिस प्रकार से काम किया उसमें राजस्थान अग्रणी रहा है। वह राजस्थान एक प्रदेश है ..

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपको यही टिप्पणी करनी चाहिए कि राजस्थान प्रदेश है जो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिना आसन की अनुमति के बीच-बीच में खड़े न हों।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप पूरी बात सुनिये और मैंने पहले भी कहा है कि पूरे देश भर में हमारे छह राज्यों में राजस्थान को यूनेस्को का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बाइंड अप करें, समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, श्रीमती अनिता भदेल।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं दो मिनट का समय और लेना चाहता हूं। जयपुर से मैं विधायक हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर में आई. आई. टी. की स्थापना की जाय।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर एक अन्तरराष्ट्रीय शहर बन गया है और एशिया के दस शहरों में यह आ रहा है और जब केन्द्र सरकार यहां सब्सिड़ी दे रही है, केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है राजस्थान में ....

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: माननीय कोटपूतली से आने वाले सदस्य.....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयपुर शिक्षा का केन्द्र बन रहा है तो इसलिए आई.आई.टी. जयपुर शहर में खोली जाए। इस बात की मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसी के साथ-साथ माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने भौतिक सुख सुविधाओं का और भर्तियों का जाल बिछा दिया लेकिन जयपुर शहर में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर भी आप कण्ट्रोल कीजिए। जितने प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर जिस प्रकार से फीस ली जा रही है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों के और उनके अभिभावकों के इंटरव्यू लिये जा रहे हैं वहां पर, बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कि बड़े-बड़े लोगों के बच्चे वहां भर्ती हों, मां-बाप को परेशान किया जाए और भर्ती के नाम पर लूट की जाए। इस प्रकार से पारदर्शी नीति माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आप बनाएं ताकि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा प्रदान करा सकें, सुलभ शिक्षा हो सके।

अभी दिल्ली में एक कानून बना है, हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि दो किलोमीटर की परिधि में आने वाले जो बच्चे हैं ......

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उन्हीं का एडमिशन वहां होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस जयपुर शहर में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जहां-जहां भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की नीति एक बनाएं, उनके एगजामिनेशन की नीति बनाएं और नीति बनाकर के आम विद्यार्थी वहां पर पढ़ सके इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं जब सुझाव दे रहा हूं ....

श्री सभापति: ऐसा कोई सुझाव नहीं है। अब आप ऐसा है आपको चालीस मिनट से ज्यादा हो गये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे को करीबन तीस मिनट हुए हैं ...(व्यवधान) आप देख लीजिए दो-तीन सुझाव हैं मेरे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह पहले वक्ता हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका आशीर्वाद चाहता हूं मैं, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं, कुछ सुझाव देने हैं मेरे को।

श्री सभापति: बिल्कुल महत्वपूर्ण सुझाव दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि सरकारी विद्यालयों में खेल की सुविधा के लिए वहां पर जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान दें। वहां पर नैतिक शिक्षा, आपने योग्य शिक्षा तो दे दी लेकिन नैतिक शिक्षायुक्त हमारे विद्यार्थी हों, इस बात के लिए भी आप प्रयत्न करें, पाठ्यक्रम में नैतिक सामग्री को आप शामिल करें। अभी कल ही केन्द्र सरकार ने एक अच्छा काम किया है, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा उन्होंने एक कानून बनाया है वृद्धजनों की सेवा के लिए, लड़के-लड़कियों को पाबंद करने का एक कानून बनाया है वृद्धजनों की सेवा के

लिए एक बहुत अच्छा कानून बनाया है। तो मैं समझता हूं वह कानून जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से यहां भी बच्चों में नैतिकता हो, अपने मां बाप के प्रति, गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो और शिक्षा यही कहती है, हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि उनमें शिक्षा का भाव पैदा हो, इस प्रकार की नैतिक शिक्षा आप प्रदान कराएं, उसका पाठ्यक्रम शामिल करें।

खेल की सुविधा के साथ-साथ पीने का पानी, जल और टंकियां, पानी की टंकियों को आप दिखवाएं, पानी की टंकियां जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको शुद्ध जल भी प्राप्त होता है कि नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है कि उन टंकियों में निश्चित रूप से पानी ठीक नहीं होता है, कीड़े होते हैं । इसलिए कृपा करके बहुत छोटे-छोटे काम हैं। अगर छोटे-छोटे काम हमने ठीक कर दिये, वहां शौचालय बना दिये, वहां पानी की टंकी ठीक कर दी, वहां फर्नीचर की व्यवस्था कर दी और आपने जिस प्रकार से विद्यालयों की समिति बनाई है छात्रों के साथ उन विद्यालयों की समितियों को खर्च करने के पावर देकर के विद्यालयों में सफाई हो, खेल का मैदान अच्छा हो, विद्यालय हरा भरा हो और मैं समझता हूं कि ...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर में एक महिला महाविद्यालय निश्चित रूप से आप खोलें और एक मिडिल स्कूल, आज हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ...

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय सभापतिजी, नये सदस्यों में कई ऐसे बैठे हैं जिनको कई दिन से किसी भी विषय की डिबेट में नहीं बोलने दिया गया। आज आपसे निवेदन है कि अगर किसी सदस्य को बुलाएं तो बराबर का समय लेंगे। इस तरह की व्यवस्था आपके माध्यम से हम करवाना चाहते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): दस मिनट से ज्यादा का समय किसी भी सदस्य को नहीं दिया जाए, यह अध्यक्षजी की व्यवस्था है । माननीय सभापतिजी, दस मिनट से ज्यादा .....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से राजस्थान को आगे ले जाएं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): सभापतिजी, हमारा क्या होगा, हम भी तो बोलना चाहेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से वह बहुत ही ... (व्यवधान) भगवान को मानने वाले, निश्चित रूप से सेवा करने वाला 'ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान' करने वाला विद्यार्थी बने। इस बात की व्यवस्था करें। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति के विषय में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने, विद्वान शिक्षा मंत्रीजी ने पिछले तीन वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किये हैं वह अनगिनत हैं और प्रशंसनीय हैं, चाहे वह बालिका शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा ही क्यों न हो। हमारे इतिहास और परम्पराओं के अनुसार यदि हम बात करें तो बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व समाज का होना चाहिए क्योंकि जन्म से जब मानव पशुवत पैदा होता है तो शिक्षा के माध्यम से ही उसको संस्कारित कर समाज के अनुरूप बनाया जाता है और जब वह शिक्षित होता है तो समाज का अभिन्न घटक कहलाता है। जो काम समाज के स्वयं के हित में हो रहा होता है यह समाज उसी काम के लिए पैसे की डिमांड करे, शुल्क यदि हम रोपित करें तो यह सर्वथा गलत बात होगी क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है, स्कूल से जब बालक शिक्षित होकर के बाहर समाज में काम करने के लिए आता है तो वह समाज के लिए काम करता है और जो बालक समाज के लिए काम करता है तो फिर उससे शुल्क की किस प्रकार से हम मांग कर सकते हैं। एक यह बिंदु विचारणीय है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं और उनमें यह क्षमता है क्योंकि जो व्यक्ति देता है, करता है समाज के लोगों की अपेक्षाएं उसी से बढ़ती हैं तो उनमें यह क्षमता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करती है । जब व्यक्ति स्कूल से निकलता है तो हम चाहते हैं कि वह समाज के लिए काम करे लेकिन समाज के लिए काम न करके वह व्यक्ति के लिए काम करता है तो इस विचारधारा को यदि हमें बदलना है तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेज़ों के माध्यम से हम पर थोपी गयी है जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि क्लर्कों का निर्माण करना ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उन्होंने तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली पर हमारे समाज को बरबाद कर दिया। हमारी युवा पीढ़ी को बरबाद कर दिया इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करें जो हमारे समाज के अनुरूप हो, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो ताकि हमारे समाज में जो अव्यवस्था हुई है उसको हम सुधार सकें और पुनः संगठित समाज की परिकल्पना कर सकें और यह गुण मैं निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री महोदय में देखती हूं। वह चरणबद्ध रूप से इस शिक्षा पद्धति को संवार कर भारतीय परम्पराओं के अनुसार एक नयी शिक्षा पद्धति का निर्माण करेंगे ऐसी मुझे उनसे आशा है।

मैंने जैसा पहले भी कहा कि इन तीन वर्षों में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, सार्वजनिक शिक्षा हो। प्राथमिक शिक्षा को हम सार्वजनिक शिक्षा बना सकें, सार्वभौमिक शिक्षा बना सकें इसके लिये हमारी सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिये और उन नीतिगत निर्णयों का परिणाम था कि हमारी जो साक्षरता का प्रतिशत है वह 61.03 कुल साक्षरता का प्रतिशत हुआ बढ़कर जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 76.46 प्रतिशत और महिला साक्षरता 44.34 प्रतिशत हुई।

इसके अलावा साक्षरता ही नहीं बढ़ी बल्कि शिक्षा की गुणात्मकता भी बढ़ी। शिक्षा किस प्रकार से हमारे लिये उपयोगी साबित हो, अच्छी शिक्षा दे सकें तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भवनों का निर्माण करना। बालकों का नामांकन अधिक कैसे बढ़े इसके लिये मिड-डे-मील की व्यवस्था करना। बालक विद्यालय में रुकें, एक बार प्रवेश ले करके वापस न चले जाएं इसके लिये यह व्यवस्था करना और शिक्षा का वातावरण, जो शिक्षा भवन हैं उनको उन बालकों के अनुरूप बनाना। हमारे बालक का जो अधिगम स्तर है उस स्तर तक जा करके शिक्षक कैसे शिक्षा प्रदान करें उसके लिये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। उन शिक्षकों को वह सामग्री उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से हम बालक में अभिवृद्धि कर सकें। बालक के शैक्षिक स्तर को उठा सकें और उसके अधिगम स्तर तक जाकर उसके पढ़ने की व्यवस्था हम कर सकें यह सारे प्रयास हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने किये हैं। निश्चित रूप से इन प्रयासों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग के ही परिणाम है कि आज प्रत्येक गांव में एक अच्छा विद्यालय उपस्थित हुआ है जो शिक्षा का काम करते हैं। हम विद्यालय के बाहर लिखते हैं

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि 'ज्ञानार्थ और सेवार्थ प्रस्थान'। इसका अर्थ यही है कि ज्ञान के लिये आप आइये और समाज की सेवा इन विद्यालयों से जाइये तो।

मैं यह कहना चाहूंगी आपने शिक्षा के लिये बहुत सारे प्रयास किये हैं और शिक्षा की गुणवत्ता के लिये, शिक्षा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिये जो आपने प्रयास किये हैं उनका कुछ उल्लेख मैं करना चाहूंगी। जैसे शैक्षिक सत्र 2004-2005 के कक्षा एक से अंग्रेजी विषय का शिक्षण कराना। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं हेतु माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को घर से स्कूल की यात्रा नि:शुल्क बस की सेवा उपलब्ध कराना। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2005-2006 से कम्प्यूटर शिक्षा के लिये 50 प्रतिशत शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय तथा 2006-2007 से बालिकाओं को कम्प्यूटर फीस में पूर्ण छूट प्रदान करना। राज्य में प्रथम चरण में 130 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के लिये आई.सी.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय लेकर उसको लागू करना। और भी अन्य बहुत सारे उपाय हमारे मंत्रीजी ने किये, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकने की स्थति में हैं कि आज राजस्थान में शैक्षिक स्थिति संतोषजनक है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में काम हुए हैं उसी प्रकार से तकनीकी शिक्षा में भी काम हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो आज आवश्यकता है ऐसे कामगार युवाओं का निर्माण करने की जिनके हाथ में कौशल हो और वह उस कौशल के माध्यम से अपनी जीविका उपार्जन का साधन उस कौशल को बना सकें, अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। एक अरब की जनसंख्या वाले इस देश में जो संसाधन हमें बहुत सुगम तरीके से उपलब्ध हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि जिसे उपयोगी बनाना बहुत आवश्यक है वह है मानव संसाधन। यदि इस मानव संसाधन को हमने शिक्षित कर लिया, श्रमशील बना दिया तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है उस प्रश्न का समाधान हम कर पायेंगे। उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ पायेंगे और इसके लिये हमारी सरकार ने जो तकनीकी शिक्षा में प्रयास किये हैं उनकी कुछ बानगी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

113 ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधा नहीं थी वहां निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर, उन्हें आमंत्रित करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु चुनाव किया गया और 77 पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को आशय पत्र जारी किये गये। बाकी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और वह कार्यवाही में चल रहे हैं। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के लिये भी कुछ नार्म्स तय किये हैं, कुछ नीतिगत निर्णय लिये हैं। जैसे कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। सेण्टर फार ई-गवर्नेंस की पहल की गयी। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 15,000 से अधिक सीटों में हुई रिकार्ड वृद्धि। हमने उनकी सीटों को बढ़ाया ताकि बालक आएं और प्रवेश लें ऐसा न हो कि सीट के अभाव में योग्य बालक भी उसमें प्रवेश ना पा सकें। सभी जिलों में पॉलीटैक्निक और प्रत्येक पंचायत समिति में आई.टी.आई. की स्थापना। एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश की पहल हुई। 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 राज्य पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों की स्थापना इसके अन्तर्गत हमने की। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र उत्कृष्टता केन्द्र में क्रमोन्नत किये गये। निश्चित रूप से कई बार हम यह कहते हैं बालक ने आई.टी.आई. तो किया है, पॉलीटैक्निक तो किया है लेकिन आई.टी.आई. करने के बाद भी उसके पास में वह कौशल प्राप्त नहीं हुआ जिसके आधार पर वह व्यवसाय का सके। तो इस कमी को देखते हुए उनको उन्नत बनाया गया। 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों का कैम्प्स प्लेसमैंट हुआ। यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। यह परिणाम यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगी कि 70 प्रतिशत बालकों का कैम्प्स सलेक्शन हुआ। यह हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा की योजनाओं का परिणाम है कि बालक का वहां से यदि प्लेसमैंट होता है तो दूसरे बालक भी उत्साहित होकर के प्रवेश लेते हैं और इस प्रकार एक बालक को यदि रोजगार मिलता है तब उसका सम्पूर्ण परिवार समृद्ध बनता है। जब परिवार समृद्ध बनता है तो मैंने कई बार कहा कि वह कड़ी लगातार जुडती रहती है और वह राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको तय करते हैं। बजट को दुगुना किया गया। गांव गोद लेकर तकनीकी संस्थान बनेंगे और गांवों में उनकी भागीदारी तय की गयी। यह सब काम तकनीकी शिक्षा में हुए हैं निश्चित रूप से मैं इसके लिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं परन्तु इसके साथ एक सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे आई.टी.आई. में

(श्रीमती अनिता भदेल)

एन.सी.वी.टी, एस.सी.वी.टी.दो. प्रकार से कोर्सेज संचालित हैं। एन.सी.वी.टी. कोर्स से उत्तीर्ण छात्र राष्ट्रीय स्तर पर यदि वह आई.टी.आई. में लैक्चरर बनना चाहे तो एप्लाई कर सकता है। यदि रेलवे में कोई आई.टी.आई. होल्डर पद की वैकेंसी है तो उसमें वह एप्लाई कर सकता है लेकिन एस सी वी टी कोर्स के माध्यम से जो छात्र निकलता है वह दोनों ही जगह एप्लाई नहीं कर सकता तो इस प्रकार हम उस बालक के साथ छलावा कर रहे हैं। इस कोर्स को करा करके हम उसका समय भी बरबाद कर रहे हैं, उसका पैसा भी बरबाद कर रहे हैं। या तो हमें यह कोर्स बंद करना चाहिये, नहीं तो फिर इन कोर्सेज को एन.सी.वी.टी. में क्रमोन्नत करना चाहिये ताकि उन छात्रों को लाभ मिल सके। उन आई.टी.आई. होल्डर्स को लाभ मिल सके जो अपने रोजगार की तलाश में यह कोर्स करने के लिये प्रवेश लेते हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार जैसा मैंने पहले भी कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिये गये और इसके आधार पर ही हम जहां महाविद्यालय नहीं थे, चाहे वह महिला महाविद्यालय हों या को एजुकेशन वाले महाविद्यालय हों, कई जिला मुख्यालय उनसे वंचित थे, कई पंचायत समिति मुख्यालयों पर इस प्रकार के महाविद्यालय नहीं थे। लेकिन हमारी सरकार की सोच और पहल के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने निजी निवेशकों को आमंत्रित किया और यह कहा कि जो इस प्रकार की शिक्षा में सुविधाएं उपलब्ध करनी थी कि वह हमारे पास आयें, हम उनको भवन भी देंगे, हम उनको भूमि भी देंगे और आप अपना महाविद्यालय वहां संचालित करें। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम था और विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते थे। इस प्रकार की सुविधाएं भी उन क्षेत्रों के लिए प्रदान की हैं तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, मैं बालिका शिक्षा के विषय में विशेषकर बोलना चाहूंगी। मैं एक योजना का उल्लेख करते हुए कुछ बात अपनी कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने 'आपणी धरती आपणां लोग', नाम से इतिहास संकलन के लिए एक योजना बनाई और नाम दिया आपणी धरती आपणां लोग', इसका अर्थ जो मैं अपनी बुद्धि से निकालती हूं, वह यह हुआ कि हम हमारे इतिहास में जो लोग हुए हैं जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किये हैं, जो हमारे

प्रेरक बने हैं, जिन्होंने जीवन में मूल्य तय किये हैं हम उनका इतिहास रचें। कोई व्यक्ति जब प्रेरणा लेता है तो हम उसको यह नहीं कह सकते हैं कि अब्राहम लिंकन ने ऐसा किया इसलिए तुमको भी ऐसा करना है। लेकिन यदि हम उसको यह कहेंगे कि हाड़ी रानी ने ऐसा किया है इसलिए तुमको करना है तो वह इस बात को स्वीकार करेगा क्योंकि वह उसकी भूमि से पैदा हुई है। उसके जीवन मूल्यों में रची-बसी है। उसके समाज से निकली हुई है इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि यह जो योजना आपने शुरू की है निश्चित रूप से मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए आपको याद रखेगी कि आपने हमें एक ऐसा इतिहास दिया जिसके माध्यम से हम हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, सदन में इतनी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है और आधे-आधे मंत्री बैठे हुए हैं। एक-आध पूरे मंत्री को बुलवायें। इतने केबिनेट मंत्री हैं, सरकार में इतने केबिनेट मंत्री हैं, एक-आध को तो बैठा कर रखें यहां पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो बिराजें...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आधे और पूरे क्या होते हैं।

एक माननीय सदस्य: आपके सुनने वाले भी तो आधे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बीच-बीच में बात नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): देवनानीजी कुछ बोलेंगे वह हो जायेगा क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सदस्य, आप प्लीज मुझे बोल लेने दीजिये फिर आप जितना चाहें उतना बोल लेना। मुझे अपना विषय खतम कर लेने दीजिये फिर आप बोल लेना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): देवनानीजी कुछ बोलेंगे वह हो जायेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): देवनानीजी तो वही बोलेंगे, कागज पर लिखकर के पकड़ा देंगे और क्या करेंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको बहनों से एलर्जी तो नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कृपया महिला शक्ति को डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सभापति महोदय, इन्हें बैठायें प्लीज ...(व्यवधान) इनको शांति से बैठाइये माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): अच्छा बोल रही हैं शांति से सुनें...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सबसे ज्यादा कद्र महिलाओं की मैं ही करता हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): तभी बार-बार बीच में उठ जाते हो ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप ही करते हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आप मुझे बोलने दीजिये, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, केबिनेट मंत्री को तो हाजिर करो आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): हां, हां, वह मेरी बात सुन रहे हैं। आप चिंता मत करें, मुझे बोलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं? आपका ही नम्बर आ रहा है।

एक माननीय सदस्य: व्यवधान विधायकजी, कृपया शांत बैठें।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, मैं बालिका शिक्षा के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा की क्या महत्ता है। भारतीय समाज और भारतीय जीवन पद्धति, परिवार और जीवन के मूल्य सम्पूर्ण विश्व में श्रेष्ठतम माने जाते हैं और यही

(श्रीमती अनिता भदेल)

कारण है कि विश्व के अनेक देश हमारे भारतीय परिवार कैसे हैं, भारतीय समाज की संरचना कैसी है इसको जानने के लिए और इसका अनुसरण करने के लिए भारत आते हैं। भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास के, आदर्श के अनेक पृष्ठ भरपूर हैं। हमारे पास वह इतिहास है जिसमें मातृत्व की साक्षात् प्रतिमा के रूप में जीजा बाई, नेतृत्व में लक्ष्मी बाई, प्रदत्त में देवी अहिल्या और हाड़ी रानी को कोई नहीं भुला सकता है। यह उदाहरण हमको बताते हैं कि भारतीय इतिहास में, भारतीय धर्म, परंपरा में, भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत उच्च स्थान था और उसके कारण से हमारा समाज समृद्ध था। समाज समृद्ध होने के कारण से ही हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाता था। यदि हम राष्ट्र को पुन: सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें शिक्षा में उन सभी बातों पर विचार करना चाहिए जिसके माध्यम से हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): मैं समाप्त कर रही हूं। यह विषय खत्म करके मैं समाप्त करूंगी। अंग्रेजों के पूर्व जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी और एक बात मैं कहना चाहूंगी शिक्षक होने से भी कि शिक्षा मनुष्य के नैसर्गिक गुणों का विकास करती है। हम सिर्फ साक्षर हो जायें उसी से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। हमारे अंदर जो गुण हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया उनके विकास का माध्यम शिक्षा होती है। शिक्षा के माध्यम से हम उन गुणों का विकास करते हैं और यह भी कहना चाहूंगी कि स्त्री शब्द को हम लिंग वाचक रूप में पहचानते हैं। लेकिन मैं अपनी अवधारणा के अनुसार यह कहूंगी कि यह शब्द लिंग वाचक शब्द नहीं है। यह शब्द गुण वाचक शब्द है। जहां दया, करूणा, ममता, श्रम और कष्ट सहने की देह है, जिसमें यह सारे गुण हों, जिस देह में यह सारे गुण हों वह 'स्त्री' कहलाती है। यह गुण वाचक शब्द हैं और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि इस नैसर्गिक गुणों का वह विकास करें। उस पराकाष्ठा तक उन गुणों को लेकर के जायें। जब तक स्त्री के इन गुणों का विकास नहीं होगा तब तक हम यह कह सकते हैं कि वह शिक्षित नहीं होगी। मैं तो यह कहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि स्त्री में शारीरिक सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन मैं यह कहूंगी कि उसकी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि यदि उसका

(श्रीमती अनिता भदेल)

उचित मंच पर, उचित जगह उपयोग किया जाये तो वह समाज में और परिवार की दिशा को मोड़ देती है।

सभापति महोदय, एक घटना, सिर्फ एक घटना मैं सुनाना चाहूंगी, माननीय मोहनलालजी गुप्ता ने विवेकानंदजी की बात का उदाहरण दिया था। विवेकानन्दजी की शिक्षा के बारे में कहा लेकिन विवेकानन्दजी को किसने शिक्षित किया। यह मैं आपको बताना चाहूंगी। एक घटना उनके जीवन की सुनाऊंगी। जब विवेकानन्दजी छोटे थे और उनका नाम नरेन्द्र था, कई बार पुराने घरों में यह प्रचलित होता था कि बच्चे आपस में मिलकर के खेल खेलते थे और तय करते थे कि मैं डाक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं यह बनूंगा। सारे बच्चे पूरी कालोनी के आकर के उसके घर में खेल रहे थे और खेलते हुए आपस में तय कर रहे थे कि किसको क्या बनना है। अचानक जब नरेन्द्र की बारी आयी तो नरेन्द्र से दूसरे बच्चे ने पूछा कि तुम क्या बनोगे नरेन्द्र। नरेन्द्र का अनायास ही जवाब था, क्योंकि बच्चा जैसे देखता है वैसे ही वह सोचता है। उसके आसपास में अंग्रेज घोड़ा बग्घी से बहुत निकला करते थे। उस समय अंग्रेज घोड़ा बग्घी में बैठकर के आने-जाने का काम करते थे तो उसने जैसा देखा वैसा ही कहा, उसने कहा कि मैं तो जो घोड़ा बग्धी चलाता है कोचवान वह बनूंगा। मां पीछे खड़ी हुई यह सारी घटना सुन रही थी। मां ने सोचा कि सभी बच्चे तो कोई डाक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है और मेरा बच्चा घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचवान बनेगा क्या। लेकिन उसका दिमाग देखिये और उसके विचार देखिये और जो उसने बोला वह सुनिये। उसने अपने बच्चे का हाथ थामा और अपने ड्राइंग रूम में लेकर के गयीं, वहां एक चित्र लगा था उसको देखकर वह बताती है, वह चित्र था कृष्ण का और अर्जुन का, कृष्ण अर्जुन का रथ खींच रहे थे, उसने उस ओर इशारा करते हुए कहा कि देख बेटा, तुझे कोचवान बनना है ना तो तुझे निश्चित रूप से कोचवान बनना है, डाक्टर, इंजीनियर नहीं बनेगा। कोचवान ही बनेगा पर तुझे कोचवान बनना है तो कृष्ण के जैसा कोचवान बनना। यह भाव, यह विचार उस बालक के हृदय में इस प्रकार से अंकित हुए कि बड़ा होकर के वह विश्व में धर्म गुरु के नाम से प्रसिद्व हुआ और उन्होंने राष्ट्र को एक दिशा प्रदान करके, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास किया जिसका परिणाम आज हम देखते हैं।

सभापति महोदय, यह मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को शिक्षित

(श्रीमती अनिता भदेल)

करने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि उनको साक्षर करना है या पुरूष के बराबर लाकर के खड़ा कर देना है। महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य है कि राष्ट्र को उत्तम स्थान की ओर ले जायें और मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हाड़ी रानी के नाम से एक फोर्स के गठन की बात कही है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान की महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। और हमारे राजस्थान की महिलाएं, हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त करेंगी और ऐसी बालिकाओं का निर्माण हम हमारे इन विद्यालयों से करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मुझे जो बोलना था वह तो बोल दिया, पर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र और कुछ सुझावों की ओर आना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

श्री सभापति: अब क्या सुझाव रह गए?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): प्लीज। मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगी। (व्यवधान)

हमारी सरकार ने मुझे ध्यान है कांग्रेस के टाइम में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए बहुत बवाल मचा था। पता नहीं उन्होंने कौनसा करप्शन किया था, उसके लिए सब व्यक्तियों के मुख पर वह बात थी।

श्री सभापति: अब एक मिनट में अपने सुझाव दीजिए, एक मिनट में।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, हां, वह यही सुझाव हैं। मैं यह कहूंगी कि कम्प्यूटर शिक्षा सत्र 2001-2002 में प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 एजेंसियों, जिनमें सबसे प्रमुख काम्प्यूकॉम था, उससे विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए पाँच वर्ष का अनुबंध किया गया, बाद में जिसको एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया तो वह 2007 तक उन्होंने कम्प्यूटर शिक्षा को कंटीन्यू रखा लेकिन चूंकि अब 2007 समाप्त होने वाला है तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगी कि वह जब अपना वक्तव्य दें तो यह बताने की कृपा करें कि आगामी समय में कम्प्यूटर की क्या व्यवस्था होगी, इनकी व्यवस्था कौन देखेगा, क्या नियम होंगे उस व्यवस्था के लिए और वर्तमान में

जो कम्प्यूटर जिस कम्पनी ने छोड़े हैं विद्यालयों में वह किस स्थिति में है, विद्यालयों को कैसे उनको मेनटेन करना है।

दूसरी, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों वाली बात है। हमने कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की। पिछले सत्र की 50 प्रतिशत पुरानी पुस्तकें वापस जमा कर और चालू सत्र की 50 प्रतिशत नई पुस्तकें मिलाकर वितरित की जाती हैं, यह व्यवस्था है हमारी। लेकिन छात्रों द्वारा जो पुरानी पुस्तकें लौटाई जाती हैं वह काफी फट जाती हैं तथा सभी छात्र नवीन पाठ्य पुस्तकें लेना चाहते हैं। अत: वितरण में भेदभाव की संभावना रहती है क्योंकि पुरानी पुस्तकें सभी छात्रों से प्राप्त कर जमा की जाती हैं इससे 50 प्रतिशत पुस्तकें प्रत्येक कक्षा की जमा होने पर विद्यालयों में पुस्तकों का ढेर लग जाता है। उनके उचित संधारण में, श्रम शक्ति व्यय न हो, स्थान न घिरे और कम कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों में जहां पहले से ही कक्षा कक्ष कम हैं तो इस प्रकार की पुस्तकें जो इकट्ठी हो जाती हैं उनको रखने की अलग व्यवस्था करते हैं, यह एक तरह से कैश है, चूंकि करोड़ों रुपये हम इस पर खर्च करते हैं तो किसी न किसी दिन इस पर ऑडिट आब्जेक्शन भी होगा तो विभाग के सारे अधिकारी परेशान होंगे इसलिए अभी नियम बना दें कि इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और यह तय कर दें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): यह सारे सुझाव ही हैं। मैं खतम कर रही हूं अपनी बात को इसलिए मैं कह रही हूं..

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। आप विराजें, अब नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): बस खतम कर रही हूं। एक सैकण्ड, संयमजी, मैं खतम कर रही हूं।

मैं मिड-डे-मील के लिए कहना चाहूंगी कि इसके लिए जो केन्द्रीयकृत व्यवस्था की बात हम करते हैं तो हमारे विधायक फण्ड से पैसा देने के लिए तैयार हैं। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें तो जरूर इस विधायक फण्ड से इस मद में पैसा देंगे।

कर्मचारियों की बात मैं कहूंगी कि कई बार हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मेडिकल बिल हमारे पास आते हैं तो करोड़ों रुपयों के और बजट होता है हमारा बहुत न्यूनतम तो कई बार यह परेशानी हो जाती है कि किसको

(श्रीमती अनिता भदेल)

दें और किसको नहीं दें, किसी को दें तो कितना दें। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से भैरोंसिंहजी की सरकार ने एक बार जीरो बजट आबंटित किया था और उसके साथ जितने भी हमारे मेडिकल बिल थे वह समाप्त हो गए थे तो इस प्रकार से बजट आबंटित किया जाए।

हमारी पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक माडल विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का बनाया जाए। जिस प्रकार से आपने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बनाए हैं और वहां अनुशासित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जिससे वह विद्यालय पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालयों की मोनिटरिंग करे और हमारा काम सुगम हो जाए, हम प्रस्तुत कर सकें आदर्श कि हमारा यह एक मॉडल विद्यालय है।

हमारे जो नवीन विद्यालय हैं उनमें अभी तक भी कई जगहें खाली पड़ी हैं, यदि इन खाली जगहों को नहीं भरेंगे तो हमारे विद्यालयों की रनिंग ठीक ढंग से हो पाएगी क्योंकि जिस प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्तर पर अभी बजट में घोषणा हुई है माध्यमिक स्तर तक हम शायद इसको लेकर जाएंगे यदि यह योजना वास्तव में इम्प्लीमेंट होती है तो निश्चित रूप से हमारे माध्यमिक विद्यालयों को इसका फायदा मिलेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे जो पद रिक्त हैं, यदि उन रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा क्योंकि उन्हें 9-18-27 का चयनित वेतनमान मिल रहा है, हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, उन पदों को प्रमोशन दिया जाए तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की हमारी इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है वह भर्ती हम कर सकते हैं और उनको हम क्रमोन्नत करके उन खाली पदों को भरेंगे तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे।

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं, शहरी क्षेत्रों में तो बहुत सारे अध्यापक बैठे हुए हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कमी है यदि हम इनका समानीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कई विद्यालयों में हम नियुक्ति कर पाएंगे और नए शिक्षक जो अतिरिक्त बैठे हैं उनके बोझ से भी हम बच पाएंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा कला एवं संस्कृति के मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं और यह आशा करता हूं कि जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ताओं के ऊपर आपका दिल उदार बना रहा, मेरे प्रति भी आपकी यह सहृदयता रहेगी।

श्री सभापति: आप 20-25 मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपनी पार्टी का टाइम ले रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हमारा भी ध्यान रखा जाए।

श्री सभापति: सब का ध्यान रख रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी की जो आज की स्थिति है उसका मौजूं अपने विद्यालय जीवन में सुना हुआ एक शेर मुझे याद आता है।

वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किस सफाई के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी के पर काटे हैं...

श्री सभापति: आप मुद्दे की बात कहो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पढ़ा गया बजट भाषण उसका परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजस्थान की तमाम अकादमियां चाहे वह साहित्य अकादमी हो, चाहे दूसरी अकादमियां हो, वह माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी से लेकर कला संस्कृति महकमे में डाल दी गई। क्या अंदाज है, कितनी खूबसूरती से, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज इस मांग पर अपने विचार रखते हुए यूनेस्को के पुरस्कार का जिक्र किया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, मोरक्को इन देशों का भी जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह इसलिए प्रदान किया जाता है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अगर आपने उस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था की है तो उसके आधार पर चयन करके यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिस यूनेस्को पुरस्कार की वजह से आप गौरवान्वित हो रहे हैं, आप अपना साक्षात्कार पर साक्षात्कार दिए जा रहे हैं, जरा राजस्थान की जनता को यह

(श्री संयम लोढ़ा)

बताएं कि राजीव गांधी पाठशालाओं को कंवर्ट करने के अलावा कितने नए प्राथमिक विद्यालय आपने खोले हैं? इस यूनेस्को पुरस्कार का श्रेय अगर किसी को जाता है, जिसको जाता है तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को जाता है जिन्होंने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में विषम परिस्थितियां होने के बावजूद, अकाल की भयावह मार होने के बावजूद राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में कैसे आए उसके लिए जीवटता के साथ प्रयास किया और 2006 का यह यूनेस्को पुरस्कार तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रयासों का परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, इस सरकार ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, क्या नहीं कहा?

अशोक गहलोत कटोरा लेकर भीख मांगते हुए घूमते थे और हमने राजस्थान में इतना बेहतरीन वित्तीय प्रबंध किया, आज हमारा खजाना भरा हुआ है। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, 8500 करोड़ रुपये की पिछले साल की योजना 11638 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी कि 35 फीसदी योजना का आकार बढ़ने के बाद राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री की निगाह में और उनके ध्यान में मानव संसाधन कौन से नम्बर पर है? माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं योजना का आकार इतना बढ़ने के बाद भी यह कौनसा कारण है कि राजस्थान सरकार के इस साल की जो वार्षिक योजना प्रस्तुत है उसमें प्लान का पैसा आपने घटाया है। जब 35 फीसदी योजना का आकार बढ़ा है तो यह प्रारंभिक शिक्षा पर जो प्रावधान आपने किया उसके अनुरूप वह नहीं बढ़ना चाहिए था?

माननीय सभापति महोदय, 2006-07 के बजट एस्टीमेट में 41293 लाख रुपये का प्रावधान था और प्रारंभिक शिक्षा के प्लान में इस वर्ष के बजट एस्टीमेट में 34454 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में 16 परसेंट कम है। किस बात का गुणगान कर रहे हो, किस बात के लिए अपनी पीठ ठोक रहे हो? राजस्थान का शैक्षिक जगत इस सरकार के लिए क्या मायने रखता है यह प्लान का आपका प्रोविजन जाहिर करता है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माध्यमिक शिक्षा के अंदर 2006-07 के बजट एस्टीमेट थे 3196.82 लाख रुपये और इस वर्ष उसको भी घटाकर 2427.88 लाख रुपये इन्होंने कर

(श्री संयम लोढ़ा)

दिया। इसमें भी 24.1 परसेंट की कटौती प्लान हैड के अंदर इस सरकार के द्वारा की गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो सामान्य शिक्षा का महायोग है उसका भी 2007 का प्लान का एस्टीमेट है 47343.15 लाख रुपये। वह भी घटकर 2007-08 में 39541.57 लाख रुपये हो गया है। इस तरह से सामान्य शिक्षा के महायोग में प्लान में जो कटौती है वह कुल मिलाकर 16.5 प्रतिशत है। मैं चाहूंगा कि जब शिक्षा मंत्रीजी जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें कि आयोजना के मद में यह कटौती क्यों हुई है या आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं भारत सरकार का कोई जलजला आये और आप रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट करके बाद में उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें, लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को भली-भांति समझेगी कि अपनी गांठ से राजस्थान की मुख्य मंत्री क्या देना चाहती है और भारत सरकार क्या दे रही है। जो आपका सपना है, जो आप क्रेडिट लेना चाहते हो 1500 सैकण्डरी स्कूल खोलने की, 600 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की यह राजस्थान की जनता भली-भांति समझ जाएगी कि यह किसके द्वारा हो रहा है, किस बात में हो रहा है और आपने इसमें क्या प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत महिमामण्डन हुआ इस सदन में और हमारे एक मित्र जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज की चर्चा की शुरूआत की उन्होंने जब तकनीकी शिक्षा की बात की तो अमरीका, मोरक्को, पता नहीं किस-किस देश के उदाहरण लाकर इस सदन में अपनी बात रखने का प्रयास किया। मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ भारत की तरफ ही दृष्टि डालना चाहता हूं और भारत सरकार की वेबसाइट पर 'सर्व शिक्षा अभियान' के बारे में जो स्थिति है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि राजस्थान देश के दूसरे राज्यों की तुलना में किस मुकाम पर खड़ा है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2006 तक 'सर्व शिक्षा अभियान' में राजस्थान को 86516 शिक्षकों की भर्ती करनी थी, लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान की यह अकर्मण्य, शिथिल और उदासीन सरकार मात्र 31896 शिक्षकों की भर्ती कर पायी। इसके विपरीत आप देश के दूसरे प्रांतों का उदाहरण लें आंध्र प्रदेश ने 95 फीसदी शिक्षकों की भर्ती कर दी, 36300 की उनको भर्ती करनी थी, 34676 की उन्होंने भर्ती कर दी। छत्तीसगढ़ का लीजिए

(श्री संयम लोढ़ा)

50 हजार की भर्ती करनी थी, 80 परसेंट से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कर दी।

(समय : 15.55 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मध्य प्रदेश जहां पर इनकी पार्टी की सरकार है 90 हजार शिक्षकों की भर्ती करनी थी उन्होंने 80 हजार शिक्षकों की भर्ती कर दी। उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, जिनको 64 हजार शिक्षकों की भर्ती करनी थी और उन्होंने 55 हजार शिक्षकों की भर्ती कर दी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए जहां 2,33,583 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उन्होंने 2,15,950 शिक्षकों की भर्ती कर दी। आपका क्या हाल है? राजस्थान के उस बेरोजगार ..(व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): आपने अपने कार्यकाल में क्या किया?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने अपने कार्यकाल में क्या किया उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। मेरे से बड़ा शुभचिन्तक आपको नहीं मिलेगा जो आपको समय से पहले आगाह कर रहा है कि अपने निकम्मेपन से उबर जाओ और भारत सरकार जो पैसा दे रही है उसका फायदा राजस्थान के उस गरीब बेरोजगार नवयुवक को दो जिसके परिवार वालों ने आपके वायदे पर भरोसा करके राजस्थान में पहली बार आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा Opening of Schools, इसका जो देश के अंदर टार्गेट दिया गया है राजस्थान सरकार को 37118 स्कूलें पिछले साल तक ओपन करनी थी उसकी तुलना में ये 28 हजार स्कूलें ओपन कर पाये। जब कि इनके मुकाबले दूसरे प्रदेशों ने, उत्तर प्रदेश ने 28 हजार के टार्गेट के विपरीत 27 हजार स्कूलें खोल दीं। झारखण्ड ने 16 हजार के टार्गेट के विपरीत 20 हजार स्कूलें खोल दीं। जम्मू-कश्मीर ने 6156 के टार्गेट के विपरीत 6154 स्कूलें खोल दीं और आंध्र प्रदेश ने 7011 के टार्गेट के विपरीत 7961 स्कूलें खोल दीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंदाजा लगाइए इस सरकार ने राजस्थान को किस मुकाम पर लाकर पटक दिया। देश के दूसरे राज्य 'सर्व शिक्षा अभियान' में भारत सरकार द्वारा दिये हुए पैसे का पूरी प्रतिबद्धता के साथ उपयोग कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं।

एडिशनल क्लास रूम, टार्गेट के मुताबिक राजस्थान को 40 हजार का निर्माण करना था, लेकिन 12200 बनाये। इसके विपरीत अगर दूसरे राज्यों का आकलन करें तो देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान बहुत पीछे है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो फण्ड यूटिलाइजेशन का काम है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसके अंदर भी राजस्थान बहुत पीछे है। राजस्थान की तुलना में मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार जैसे छोटे राज्य भी आगे खड़े हुए हैं। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान इस मुकाम पर खड़ा हुआ है।

शिक्षकों की भर्ती का परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में टार्गेट के विपरीत सिर्फ 37 प्रतिशत शिक्षकों की भर्ती हुई है। जब कि देश के दूसरे राज्यों में अंडमान निकोबार 73 परसेंट, आंध्र प्रदेश 96 परसेंट, अरुणाचल प्रदेश 74 परसेंट, असम 72 परसेंट, छत्तीसगढ़ 80 परसेंट, दमन एण्ड दीव 95 परसेंट, गुजरात 90 परसेंट, हरियाणा 79 परसेंट, हिमाचल 81 परसेंट, जम्मू-कश्मीर 92 परसेंट। यह आपकी उपलब्धि है देश के दूसरे राज्यों की तुलना में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार ने जो प्रगति प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराया है कहां तो आपका यह वादा था कि हर साल एक लाख नवयुवकों को सरकारी नौकरियां देंगे और यह आपके द्वारा उपलब्ध कराया हुआ प्रगति प्रतिवेदन हमको यह जानकारी देता है कि आज राजस्थान के अंदर 83713 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।

प्रथम वेतन श्रृंखला में 30, द्वितीय वेतन श्रृंखला में 11560 और कुल अध्यापक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज में 72123 और जब भर्ती का काम आपने किया है तीन सालों का आपने फिगर दिया हुआ है वह बहुत कम है। जितनी इसकी तुलना के अन्दर आपने लगातार स्कूलें खोलीं उसके अनुरूप आपने यह व्यवस्था नहीं की भारत सरकार का चाहे 2003-04 का हो, 2004-05 का हो, 2005-06 का हो और 2006-07 का हो, हर साल में जितना पैसा आपको दिया गया, आप उस पैसे को लेकर बैठे रहे और राजस्थान के उस आम आदमी के बच्चे को पढ़ाने की जो बेहतर व्यवस्था हो सकती थी वह करने का काम आपने नहीं किया। राजस्थान के बेरोजगार युवकों को जो पढ़ने के बाद एक सपना लेता है कि सरकारी नौकरी में आकर उसको राजस्थान की

(श्री संयम लोढ़ा)

जनता की सेवा का मौका मिलेगा, वह सेवा का मौका भी आपने नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इनकी जो विभागीय कार्य प्रणाली है, आपकी उसकी क्या हालत है ? ये विभागीय जांच के भी आपने इसमें आंकड़े दिये हुए हैं, कितने प्रकरण निस्तारित किये, आपने प्राथमिक जांच के 481 में से सिर्फ 26 सी.सी.ए. 17 के, 203 में से सिर्फ 16, सी.सी.ए. 16 के 309 के सिर्फ 16 और निलम्बन के 60 में से सिर्फ 5, माननीय अध्यक्ष महोदय, महीने महीनों हो जाते हैं चार्जशीट देने का काम नहीं करते, कोई सस्पेंड हो जाए तो सस्पेंड 10-10 महीने बैठा रहता है, कोई ए.पी.ओ. बैठा है तो बैठा रहता है, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं और उसी का नतीजा है कि राजस्थान के शैक्षणिक जगत के अन्दर एक अराजकता का माहौल बना हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री ने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि यह स्त्री शिक्षा को समर्पित है और इस बार तो उन्होंने और मुखर होकर के कहा कि यह महिलाओं को समर्पित है लेकिन बजट को कागजों में समर्पित करने से कुछ नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाहता हूं जो आपने हमको इसी महीने में उपलब्ध कराई है। मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सम्बलता पुरस्कार क्या लिखा है वर्ष 2006-07 में 97 बालिकाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पूरा साल खतम हो रहा है, अभी प्रक्रिया ही चल रही है आपकी ? इस तरीके से आप सम्बल देना चाहते हो उन नेत्रहीनों और मूक बधिर बच्चियों को? यह आपका कमिटमैंट है उस दीनहीन और कमजोर और ईश्वर के द्वारा मैं समझता हूं अन्याय का शिकार हुई बच्चियों के प्रति ? आपकी बेटी योजना, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके द्वारा भेजा हुआ यह विवरण कह रहा है, सत्र 2006-07 की दिनांक 7 फरवरी, 2006 तक कुल 10836 बालिकाओं के प्रस्ताव प्राप्त हैं जिनको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह जानकारी है, यह आपकी उपलब्धि है, आप चाहें अपनी पीठ थपथपाइए, हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन यह कागजों में इस तरीके से या तो आपकी चलती नहीं मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को इशारा किया हुआ होगा, मानना मत इनकी और निचले स्तर तक यह ठप करने का वातावरण चल रहा है और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं वह बच्चे और बच्चियां

(श्री संयम लोढ़ा)

जो इस उम्मीद में अपने प्रस्ताव देते हैं, अपने फार्म भरते हैं कि यह सरकार तत्परता से कार्यवाही करके उनको फायदा पहुंचाएगी और अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी में लाना चाहता हूं 'नन्हीं कली योजना', उक्त योजना में कुल व्यय लगभग एक करोड़ 80 लाख रुपये होगा और अभी तक मात्र 36 लाख रुपये की किश्त एक प्राइवेट फाउण्डेशन ने उपलब्ध कराई है यह तो आपकी बच्चियों के प्रति जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हुई हैं, एक के बाद एक उनका हाल किस कदर बेहाल हो रहा है ? यह आपका अपना प्रगति विवरण कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, जब आप अपना उत्तर दें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इसको स्पष्ट जरूर करना, यह जो नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण योजना में जो वित्तीय एवं भौतिक प्रगति है, इसमें 2006-07 में आपने जो विवरण दिया है, 2005-06 में जहां 512·32 लाख पुस्तकों का वितरण किया गया है और 2006-07 के अन्दर आपने 358·63 का आंकड़ा दिया है, अब इसमें क्या रहस्य है, वह आप बेहतर बता सकते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो भी वास्तविकता है वह आप बताने का कष्ट करें। अब मैं आता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि आप आसन पर पधार गई हैं क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने मातृ शक्ति को यह बजट समर्पित किया है, विशेष महिला शिक्षण शिविर, क्या हालत है इनकी ? आपके बाड़मेर में आपको 125 लगाने थे, आप कितने लगा पाये ? मात्र सौ, सिरोही में आपको 325 लगाने थे, आप 30 ही नहीं लगा पाये और पाली की हालत तो और भी बुरी है कि जहां आपको 250 शिविर लगाने थे और आप मात्र 161 शिविर लगा पाये।

श्री अध्यक्ष: तो आपको मदद करनी थी सिरोही में कम से कम।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये इतने भी लगे हैं यह मेरी वजह से लगे हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रयासों से लगे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अगर ये नहीं होते तो 300 ही लग जाते, इनकी वजह से ही 30 लगे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और टोंक की स्थिति देखिए 150 शिविर आपको लगाने थे, 87 ही लगा पाये और बड़े हिमायती आप आदिवासी बच्चियों को स्कूटी देकर वाहवाही लेना चाहते हो, सस्ती लोकप्रियता लेना

चाहते हो ? क्या हालत है डूंगरपुर की, 50 शिविर आप नहीं लगा पाये वहां पर।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 हजार की स्कूटी दी है, सस्ती कहां दी है ? सस्ती लोकप्रियता क्यों है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्कूटी के लिए नहीं कहा है, सस्ती तो लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वह लोकप्रियता 25 हजार रुपये की है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लोकप्रियता पैसों से नहीं आंकी जाती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बांसवाड़ा के अन्दर 83 शिविर यह सरकार नहीं लगा पाई और माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर जो कि राजस्थान का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसके अन्दर 50 शिविर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार नहीं लगा पाई।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है, ये मेरे जालौर को बदनाम कर रहे हैं, जालौर सबसे बैकवर्ड जिला अब नहीं रहा, आपके जमाने में था, अब आगे बढ़ गया जालौर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जालौर का तो पता नहीं, आप जरूर बहुत आगे बढ़ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह फैसला किया था कि हर पंचायत समिति में दो-दो व्यावसायिक उन्नयन शिविर लगाएंगे और क्या स्थिति है, इसका कोई ध्यान भी देता है क्या ? घोषणा करने के बाद उन कागजों को कोई पढ़ता भी है क्या ? अलवर में 28 शिविर आबंटित किये थे, 14 पंचायत समितियों को लगाये कितने, 3 बधाई दूं आपको ? भरतपुर का उदाहरण लीजिए, 18 शिविर लगाने थे, लगाये कितने मात्र 3, जोधपुर लगाने कितने थे 18 और लगाये कितने 2, पाली लगाने कितने थे 20 और लगाये कितने 5, यह माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक के बाद एक रिकार्ड तोड़ उपलब्धियां हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह डी.पी.ई.पी. का सैकण्ड फेज इसमें उसको पैसा देना था वार्षिक योजना 2006-07 में 89 करोड़ का प्रावधान था, खर्चा कितना किया ? मात्र 43 करोड़ रुपये और जो स्टेट शेयर जारी करना था वह आपने स्टेट शेयर पूरा जारी नहीं किया। आपने मात्र 4 करोड़ 31 लाख रुपये उसके

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर जारी करके आपने छुट्‌टी की और उसी का नतीजा है 13 करोड़ 48 लाख रुपये राज्यांश था और आपने जारी किये 4 करोड़ 31 लाख रुपये। अगर यह सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति गंभीर है तो आपको अपना शेयर उसके अन्दर क्यों जारी नहीं किया ? यही अपने आप में यह जाहिर करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक विद्यालय जो भवन रहित, अब यह मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षा मंत्रीजी, यह आपके द्वारा अनुमोदित आपका प्रगति विवरण कह रहा है जो कल, परसों में ही आपने हमको पहुंचाया है, इसमें विद्यालय भवन रहित में आपने बहुत मजबूत दावे के साथ लक्ष्य रखा था, 714 का, यह साल पूरा हो रहा है, कितने बना लिये आपने ? मात्र 57 भवन आपने पूरे किये, यह आपकी प्रोग्रेस है ? अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आपने क्या लक्ष्य रखा था 29039, पूरे कितने किये 4464 ?

और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भवन रहित हैं, आपको 103 बनाने थे। आपने कितने बना दिये? मात्र 8 बनाये। शौचालय आपको 2005 बनाने थे और मात्र 662 आप बना पाये। प्रधानाध्यापक कक्ष आपको 403 बनाने थे और मात्र 5 बना पाये। एन.पी.जी.एल. योजना में आपको जो एडिशनल क्लास रूम बनाने थे वो 186 बनाने थे और आप मात्र 4 बना पाये। यह आपकी सारी उपलब्धियां हैं। एन.पी.जी.एल. कार्यक्रम में प्रोग्रेस, 1806.28 लाख रुपया आपके पास उपलब्ध था और आप मात्र 321 लाख रुपया खर्च कर पाये। मतलब 20 प्रतिशत से भी कम यह आपकी उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'सर्व शिक्षा अभियान' में भी जो मैं महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इस सरकार को जो पैसा रिलीज करना था 264 करोड़ रुपये और उसकी जगह मात्र इन्होंने 140 करोड़ रुपये रिलीज किये और जनवरी में आपने 100 करोड़ रुपया रिलीज किया। अगर आप इसके प्रति गंभीर होते तो आप समय पर पूरा पैसा रिलीज करते जिससे भारत सरकार भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कर पाती और आप 'सर्व शिक्षा अभियान' के काम को लक्ष्य के अनुरूप आगे ले जा पाते लेकिन आपका यह मंतव्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हल्का सा आपका ध्यान मैं 'नामांकन' और 'मिड-डे मील' की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसमें मैं पूरे स्टेट के फीगर नहीं देना चाहता हालांकि एक एन.जी.ओ. ने 'राइट-टू-इन्फार्मेशन' में आपसे सूचना

(श्री संयम लोढ़ा)

लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर 'मिड-डे मील' में क्या हो रहा है उसका पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है और मैं चाहूं तो उसको भी पढ़कर के आपको सुना सकता हूं कि लगातार आपके नामांकन तो बढ़ गये पर प्रति बच्चे जो आप वितरण कर रहे हो वह लगातार घट रहा है। खासतौर पर मैं सिरोही जिले का आपको फिगर देना चाहता हूं कि 2002-03 में नामांकन 1,54,090 था, 2003 04 में 1,57,548 हुआ, 2004-05 में फिर कम हो गया और 1,35,000 हो गया, 2005-06 में 1,22,000 हो गया और अब 2006-07 में 1,06,000 हो गया। यह आपका ऑफिशियल फिगर है यह मुझे आपने दिया है। कौन से कारण है कि सिरोही जिला यों पिछड़ रहा है? क्या आपका विभाग कर रहा है? यह लगातार गिरावट क्यों आ रही है? जब आप एक तरफ एक करोड़ का आंकड़ा लेकर के जा रहे हो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप कोशिश करो बढ़ाने की।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप राजनीतिक आधार पर सारे फैसले करते हो, भेदभाव करते हो। प्राइमरी स्कूल खोलना होता है उसमें आपको तीन रंग का झंडा और दो रंग का झंडा अलग अलग दिखते हैं। मिडिल स्कूल खोलना होता है वहां आपको राजनीति दिखती है, सैकण्डरी स्कूल खोलनी होती है वहां आपको राजनीति दिखती है, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलनी होती है वहां आपको पालिटिक्स दिखती है। शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका दामन साफ है, आपकी सरकार का दामन साफ है, इस मामले में आप भेदभाव अगर नहीं कर रहे हैं तो आप विधान सभा क्षेत्रवार इस सरकार के आने के बाद में कितने-कितने स्कूल किस -किस विधान सभा क्षेत्र में खुले हैं, आप इसका आंकड़ा इस सदन की टेबल पर प्रस्तुत कर दें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक-एक फैसला राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया, राजस्थान के उस गरीब आदमी के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए नहीं लिया, आपने अपने हर फैसले में दिमाग में राजनीति रखी और राजनीति के आधार पर फैसला करने का काम किया। इस वजह से आज राजस्थान के उस दलित आदिवासी बहुल जिले को भुगतना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ रहा होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संयमजी, समरजीत सिंहजी से पूछ लें कि कितने स्कूल खोले हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): ....खुद ने खोले नहीं और दूसरे करे तो...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है तो सत्ता पक्ष वाले आपको उठने का अधिकार नहीं है। आपके मंत्री बैठे हुए हैं, ये जवाब देंगे। आप क्यों उछल रहे हो?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, गलत बोल रहे हैं। आपकी सरकार के समय जालौर का हमारा एक एम.एल.ए. था और पांच साल में एक भी स्कूल नहीं दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बाद में आप स्पष्टीकरण दे देना न। इनको बीच में मत टोको। मंत्रीजी, आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो बाकायदा फिगर्स दे रहे हैं हमारे वक्ता, वो गलत दे रहे हैं तो शिक्षा मंत्रीजी प्रतिवाद कर देंगे, वो गलत दे रहे हैं तो ये प्रतिवाद कर देंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री नोट ही नहीं कर रहे हैं कोई। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक-एक अक्षर लिखा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कुछ नहीं लिखा है आपने।

श्री अध्यक्ष: अटेंटिव बैठे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अटेंटिव बैठे हैं लेकिन नोट कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी याददाश्त थोड़े ही रह जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब में जवाब देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मर्जी है आपकी। हमें तो एक एक पाइंट का उत्तर चाहियेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं दे तो बात कहियेगा। वो उनकी बात का जवाब नहीं दे तब आप कहियेगा यह बात।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक-एक बात का जवाब चाहियेगा साहब।

श्री अध्यक्ष: लिखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हमारी बात हो गई, उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म निभाने के लिए अपना काम कर रहा हूं आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो। वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): निभा देंगे, धर्म में कोई कमी नहीं आने देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह टोका-टाकी के चैम्पियन तो स्वयं सिरोही से आने वाले विधायक हैं सबसे ज्यादा। ये ही टोकते हैं लोगों को।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): जोगेश्वरजी, अर्जुन सिंहजी अभी कह रहे थे कि पिछले पांच साल में एक विधायक था तो अब कांग्रेस का एक विधायक है, आपने तीन साल में एक भी नहीं खोली भीनमाल में। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): खूब खोल दीं। गुमराह कर रहे हैं आप सदन को। खूब खोल दीं, मेरे से ज्यादा आपके खुली हैं। जालौर से ज्यादा भीनमाल में खुली। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): सीनियर सैकण्डरी एक भी नहीं खोली आपने। आप रिकार्ड देख लें। आप दिखवा लें सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल पिछले तीन साल के अन्दर एक भी खोली हो। सीनियर सैकण्डरी एक भी खोली हो तो आप रिकार्ड देख लें। आप दिखवा लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हमने खोली हैं। जालौर से ज्यादा भीनमाल में खोली हैं। चैलेंज करता हूं मैं आपको। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में भीनमाल में सबसे अधिक स्कूलें खुली हैं। यह प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आंकड़े देखकर के बता सकते हैं। अपन ये आंकड़े देखकर के बता सकते हैं। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी एक भी नहीं खुली है, बिल्कुल नहीं खुली। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): .... छोटी-मोटी नहीं, पूरे जालौर जिले के अन्दर हम चुनौती देकर के बात करते हैं कि भीनमाल में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई पक्षपात नहीं हुआ है। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): खोली कहां सीनियर सैकण्डरी? अध्यक्ष महोदय, यह गलत है, सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी एक भी नहीं खुली। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): .... लेकिन वास्तव में आवश्यकता थी, भीनमाल में 50 साल में कांग्रेस ने सामने नहीं देखा इसलिए स्कूल ज्यादा खोली भीनमाल में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): इसलिए भीनमाल में 50 साल से ज्यादा जीतती आई है कांग्रेस। इसलिए जीतती आई है? क्या बात करते हो।

श्री अध्यक्ष: यह कांग्रेस के हारने-जीतने की बात नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): इतनी स्कूल नहीं खोली, आपने जनता के साथ आघात किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या शिक्षा दे रहे हो इन्हें?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं इनकी ताईद करता हूं कि अनपढ़ रखकर के, प्यासे रखकर के, झांसे दे-देकर के वोट लिये थे उसका यह परिणाम है। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): पिछले पांच साल में हमने सीनियर सैकण्डरी की 7-8 स्कूलें खोली हैं, ये फालतू की बातें छोड़ो आप। (व्यवधान) आपको पड़ेंगे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो आप बता रहे हो इसलिए वो जीत रहे थे। अब आपको लाले पड़ेंगे, अब आपको जीतने के लाले पड़ेंगे। (व्यवधान) यह तो चवन्नी आपने चला ली है वह आपकी अब नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं डालें, उन्हें बोलने दें। जवाब मंत्रीजी देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कृपा करें अध्यक्ष महोदय, कि जो मेरा 10 मिनट का समय खराब किया वह आपके ध्यान में रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट का तो नहीं किया आपका लेकिन आप भी कोई ऐसी बात कहोगे तो किसी को उत्तेजना होगी वो भी बोल देंगे। आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक बात प्रमाणिक रूप से इस सरकार के द्वारा दिये गये दस्तावेजों के आधार पर कह रहा हूं और मैंने.... (व्यवधान) हम तो सिर से पैर तक संयम ही संयम हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। यह आप बोल रहे हैं। आप बोलिये। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, प्रारम्भिक शिक्षा में जो बालिकाओं की स्थिति का आपको निवेदन किया, यही स्थिति माध्यमिक शिक्षा में भी आपकी सरकार में बन रही है। शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सम्बलता पुरस्कार, सत्र 2006-07 में दिनांक 7 फरवरी, 2006 तक कुल 435 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यहां भी फूटी कौड़ी नहीं। मूक, बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सम्बलता पुरस्कार 97 प्रस्ताव प्राप्त हुए और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 'नन्ही कली योजना', वो की वो स्थिति है। यह माध्यमिक का मैं पढ़ रहा हूं। यह पूरी स्थिति बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तिवाड़ी साहब, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, कोई खास इम्पोर्टेंट बात है, यह जो आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के छात्र-छात्राओं को जो मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना चलती है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जिन विद्यालयों को प्रवेश दिया जा रहा है यह प्रदेश के सिर्फ 13 जिलों में है, बाकी राज्य के जितने भी जिले हैं, पिछले लम्बे समय से इसको रिव्यू नहीं किया गया और जिन विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश मिल रहा है उनके पैसे का वास्तव में उपयोग हो रहा है या यों ही गुमनाम प्रवेश दिखाये जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों पर कितना खर्चा हो रहा है, क्या जिन स्कूलों की सूची बनी हुई उसको रिव्यू किया जाना चाहिए?

क्या राज्य के हर जिले के स्कूल को इसमें शामिल किया जाना चाहिए तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के बच्चे-बच्चियों को व्यापक रूप से, किस रूप से इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। आप इस दिशा में प्रयास करें और इसका पूरे तरीके से रिव्यू करें। इसके आडिट का अरेंजमेंट करें। जो पैसा इन स्कूलों को दिया जा रहा है, चाहे आपके निदेशक, कोष एवं लेखा के माध्यम से इसकी आडिट हो, चाहे आपके विभाग के लोग इसमें करें लेकिन इसमें जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको आप रोकने की चेष्टा करें और अन्य जिलों की स्कूलों को सम्मिलित करने की आप चेष्टा करें क्योंकि दूसरे जिलों के बच्चों को दूसरे जिले में जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना

(श्री संयम लोढ़ा)

पड़ता है तो आप सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर इस दिशा में कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उच्च शिक्षा के बारे में मैं एक बिन्दु आपके नोटिस में लाना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी। आपने यह जो फिगर दिये हैं कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के 2,34,789, आपने कालेजों की सूची और यह सारी संख्या में बढ़ोतरी और सब कुछ दिया है पर इसमें माइनोरिटी का पर्सेन्टेज क्या है विद्यार्थियों का? 2.36 प्रतिशत। मैं चाहूंगा आपसे कि आप इस सम्बन्ध में विचार करें और कोई ऐसे इन्सेंटिव की व्यवस्था करें जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति यह दो फीसदी पर अटकी हुई है, जब कि राजस्थान में उनकी आबादी सात से आठ फीसदी है। आप प्रयास करके उसको इस स्थिति में लाने की कोशिश करें जिससे राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय को भी लाभान्वित किया जा सके।

अब यह कालेज व्याख्याताओं की भर्ती की बात है, यह आपकी 2006-2007 की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या लिखा है आपने? 656 व्याख्याताओं की भर्ती प्रारम्भ की गई, यह आपकी उपलब्धि है? और 2007-2008 में आप क्या लिख रहे हैं, शेष 457 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। दोनों साल निकाल दिये। पिछला साल भी निकाल दिया, यह भी निकाल दिया और आपने कभी इस बात को रिव्यू करने की शिक्षा मंत्रीजी, कोशिश नहीं की कि राजस्थान में कितने कालेज ऐसे हैं जिसमें एक भी सब्जैक्ट टीचर नहीं है। विषय दिया हुआ है और उस विषय का टीचर नहीं है और उसका क्या परिणाम हो रहा है। आज मैं शिवगंज के कालेज का जिक्र करना चाहता हूं। वहां इंग्लिश का लेक्चरर नहीं, ए.बी.एस.टी. का लेक्चरर नहीं। फाइनल ईयर के बच्चों को कम्पार्टमैंट, सैकण्ड ईयर के बच्चों को कम्पार्टमैंट, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कम्पार्टमैंट। आपके विभाग के नोटिस में लाओ, कोई असर नहीं। गुनाह कर रहे हैं आपके कालेज में पढ़कर? आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि आपके कालेज में सब्जैक्ट का एक टीचर नहीं है और दूसरे कालेज में दो टीचर हैं, तीन लेक्चरर हैं तो आप कम से कम इन बातों की तो कोशिश कर सकते हैं कि वहां पढ़ाई की व्यवस्था उनको उपलब्ध हो सके। ए.बी.एस.टी. जैसे सब्जैक्ट के अन्दर क्या बच्चे खुद पढ़ सकते हैं लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं है। आप बहुत से दूसरे कामों में बिजी हैं। भारत सरकार ने आपको माध्यमिक शिक्षा समिति का चेयरमैन बना दिया और

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान की इस सरकार को हिचकोले देने में आपका पूरा योगदान रहता है तो इस सम्बन्ध में आपको समय कहां मिलता है? लेकिन मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके, राजनीति के चक्कर में, अपनी व्यस्तता के चलते राजस्थान के उन नौजवानों का भविष्य खराब नहीं करें और इस बात पर पूरा नोटिस लें।

अब जयपुर, यहां का राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्या पैसे दे रहे हो आप उनको? 2001-2002 में वेतन-भत्तों एवं कन्टीन्जेंसी में 41.30 करोड़ रुपये उनको मिलते थे, आज पांच साल बाद में, छह साल बाद में कितना खर्चा किस रूप में बढ़ा है लेकिन आप क्या दे रहे हो उनको? 41.30 करोड़ रुपये से भी घटाकर राजस्थान विश्वविद्यालय को आप 40 करोड़ रुपये दे रहे हैं। क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? यह प्रदेश की राजस्थान की यूनिवर्सिटी है। इसको किस रूप में आगे बढ़ाया जाये और यूनिवर्सिटी को दूसरे सोर्सेज से पैसा जुटाना पड़ रहा है। आपके आज की तारीख में 3059.22 लाख रुपये अपने सोर्स से जुटाकर इसमें खर्च करना पड़ रहा है। तो आपने किस खुशी में पहले से मिल रहा यह पैसा कम किया है? वह जरा रोशनी डालेंगे आप तो ठीक रहेगा।

मैं एक ध्यान कला, संस्कृति मंत्रालय की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहित्य अकादमी ने यह जो पुरस्कार दिया है, मीरा और देवराज उपाध्याय पुरस्कार, यह पहली बार है जब इसके लिए यह शर्त लगाई कि 200 पेज की पुस्तक होनी चाहिए। उससे कम पेज की पुस्तक उस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को निर्देश प्रदान करें, सरकार को निर्देश प्रदान करें कि अच्छी रचना कागजों पर निर्भर नहीं करती है। 150 पेज में भी अच्छी रचना हो सकती है, 125 पेज में अच्छी रचना हो सकती है। यह आपके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का कौनसा फलसफा है कि 200 पेज से ज्यादा की पुस्तक होगी, वही इसके लिए पात्र होगी? मैं चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप जब अपना उद्बोधन दें तो इस बात की घोषणा करें कि हम इस फैसले को चेंज करके और जो पहले से प्रक्रिया चल रही है, उसके अनुरूप करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान में पढ़ाई जा रही पुस्तकों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षा में जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, मैं इसको लाया हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने जब यह भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में गये तो उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और एन.सी.ई.आर.टी. का जो पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ाने से इन्कार कर दिया लेकिन यह जो पुस्तकें आप पढ़ा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसके आधार पर इसमें, जो सरकार यह पढ़ा रही है, अगर आप पूछें बच्चे से स्कूल के एग्जाम में कि महात्मा गांधी कौन थे? तो इस पुस्तक को पढ़कर वह जवाब देगा कि वह अंग्रेजों के सहयोगी थे। क्योंकि इस पुस्तक में ये पढ़ा रहे हैं "गांधीजी प्रारम्भ से सन् 1918 तक ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने प्रथम महायुद्ध में सहयोग के कारण उन्हें 'केसर-ए-हिन्द' की उपाधि से सम्मानित किया है।" यह आप पढ़ा रहे हैं। आप दिल्ली में जाकर बैठक का बहिष्कार करके आते हैं और यहां आप क्या पढ़ा रहे हैं, यह आप देखना नहीं चाहते और पूरा चैप्टर इसमें जो महात्मा गांधी पर दिया है। आपने कहीं यह नहीं लिखा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? आज इस बच्चे को पूछ लिया जाये कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? इस पुस्तक को पढ़कर जो एग्जाम देने जा रहा है, वह नहीं बता सकता कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई। यह आपके अन्दर डर है, यह आपके अन्दर छिपा हुआ चोर है जिसकी वजह से आप उसके हत्यारे का नाम इस पुस्तक के अन्दर देना नहीं चाहते क्योंकि उसके तार कहीं न कहीं उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस संगठन से जुड़े हुए हैं जिसकी हिमायत में राजस्थान की सरकार लगी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इसी पुस्तक में आगे लिखा है एनी बीसेंट के नाम से। एनी बीसेंट ने यह कहा कि "आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। हिन्दुत्व के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। हिन्दुत्व वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष की जड़ें गड़ी हुई हैं। यदि यह मिट्टी हटा दी गई तो भारत रूपी वृक्ष सूख जायेगा। भारत में प्रश्रय पाने वाले अनेक धर्म हैं, अनेक प्रजातियां हैं किन्तु उनमें से किसी की शिराएं भारत के अतीत तक नहीं पहुंचती। इसमें से भारत से वह विलीन हो जाये तो फिर भी भारत भारत ही रहेगा, किन्तु यदि हिन्दुत्व लुप्त हो गया तो क्या शेष रहेगा?" (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह सही है, एकदम सही है। इसमें गलत क्या है। एकदम सत्य है, शाश्वत सत्य है। यह शाश्वत सत्य है बन्धु, मानो।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन कर रहा था, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस मुल्क की सरकार को मुसलमान भी टैक्स देते हैं, ईसाई भी टैक्स देते हैं, बौद्ध भी टैक्स देते हैं, फारसी भी टैक्स देते हैं, क्रिश्चियन भी टैक्स देते हैं। उस सरकार को वह क्यों टैक्स देगा, जो उसके धर्म के प्रति वैमनस्य फैलाती हो, उसके धर्म के प्रति घृणा फैलाती हो? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह की पुस्तक को पढ़ाकर भारत के संविधान के अन्दर निहित इस देश की महान आत्मा है, महान संस्कृति है, उसको नष्ट करने का काम नहीं करें। आपने शिक्षा मंत्रीजी के रूप में तीन ही काम किये हैं, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का साम्प्रदायीकरण। यह तीन काम को करने का काम आपने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी स्कूल की पुस्तक में आगे क्या लिखा है सातवें अध्याय में, "क्रांतिकारी प्रजातंत्र एवं किसान आन्दोलन" वाले अध्याय में, राजस्थान में क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन करते हुए पेज 99 पर लिखा गया है कि क्रांतिकारियों के अदम्य साहस, ब्रिटिश सत्ता विरोधी प्रबल स्वर, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित भाव, काल कोठरी और काले पानी की असीम नारकीय यातनाएं भोगना इस तथ्य का प्रमाण है कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य नमस्ते सदावत्सल्ये एवं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे या न रहे। यह नमस्ते सदावत्सल्ये, यह आर.एस.एस. की प्रार्थना है। जब आर.एस.एस. की शाखा लगती है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस ध्वज के आगे (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह इसमें गलत क्या है। "नमस्ते सदावत्सल्ये मातृभूमि" हे मातृभूमि, तुझे नमन है। इसमें क्या गलत है। और इसका विरोध करते रहे तो +++ मातृभूमि की वन्दना करना....

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और मुझे यह बहुत संतोष है कि आप जैसी शख्सियत के आसन पर विराजमान होते वक्त मैं अपनी बात कह रहा हूं जिसके परिवार का इस राजस्थान के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान, स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह सरकार, मैं निवेदन करना चाहता हूं वीर सावरकर के आर्टिकल के बारे में क्या लिख रही है। वीर सावरकर न केवल प्रख्यात क्रांतिकारी थे अपितु सामाजिक, राजनैतिक विचारक एवं सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। वे प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कभी भी क्षमा याचना नहीं की। अब यह लिखने की कहां जरूरत है?

श्री बंशीलाल खटीक: सही है।

श्री संयम लोढ़ा: क्षमा याचना नहीं की तो यह लिखने की कहां जरूरत है? यह आपके अंदर का चोर है इसलिए आप लिख रहे हो।

श्री बंशीलाल खटीक: यह सत्य लिखा है।

श्री अध्यक्ष: क्या लिखा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: और माननीय अध्यक्ष महोदय, किस रूप में राज्य की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का काम इन किताबों में पढ़ाया जा रहा है, आप सुनेंगी तो आपको ताज्जुब होगा। दूसरे धर्म तो बस धर्म हैं, हिंदुत्व धर्म से ऊपर जीवन शैली है वैसे ही जैसे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया है। क्या समझना कठिन है? और आगे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, विविधता में एकता के आधार को ग्यारहवीं कक्षा की समाज शास्त्र की पुस्तक में इस रूप में लिखा है, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप टोके नहीं बीच में। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट: अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, बैठ जायें। बैठ जायें आप, मैं कहती हूं। आप बैठ जायें।

श्री बद्रीलाल जाट: बनाये, अपने क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायें।

श्री संयम लोढ़ा: आप सुनिये अध्यक्ष महोदय। संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, आध्यत्मवाद, स्वर्ग, नरक, ईश्वर या अलौलिक शक्ति में विश्वास भारतवासियों के मन-प्राण में रचे-बसे हैं। जातिवाद बसा है? वर्णवाद बसा है? यह कौन सी विचारधारा की तरफ आप हिंदुस्तान के समाज को वापिस ले जाना चाहते हैं। वह वर्णाश्रम जिसने हजारों-लाखों दलित, आदिवासियों का सालों-साल तक शोषण किया है, आप यह पढ़ाना चाहते हैं राजस्थान के बच्चों को और इस रूप में आप आने वाले राजस्थान का निर्माण करना चाहते हो और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगले पेज में क्या लिखा है, गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत राजनैतिक दृष्टि से एक नहीं रहा। मुगल काल से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर उनको प्रताड़ित करने का जो दौर प्रारम्भ हुआ, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इस काल में भी जारी रहा। ऐसे में भारतीय समाज में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से डाक्टर केशवराय बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की।

एक माननीय सदस्य: इसीलिए हम हैं।

श्री बंशीलाल खटीक: आपके मुख से कम से कम यह शुभ बात तो निकली...

श्री संयम लोढ़ा: कि एक ऐसा संगठन...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: माननीय सदस्य, आप भाषण खत्म करोगे इतनी तालियां नहीं बजेंगी जितनी अब बजी हैं।

श्री मदन राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की?

श्री बंशीलाल खटीक: कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज, 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी।

श्री मदन राठौड़: आप क्यों बोलते हो? आप क्यों बोलते हो?

श्री बंशीलाल खटीक: एक अंग्रेज था उस अंग्रेज ने 1885 में स्थापना की। आपकी स्थापना ही विदेशियों ने की है।

श्री मदन राठौड़: आप कृपया यह बतायें कि कांग्रेस की स्थापना किसने की?

श्री हरिमोहन शर्मा: आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यप्रणाली रही वह +++ तरीके की रही है। आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया।

श्री बंशीलाल खटीक: देश को आजाद कराने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आगे रहा। (व्यवधान) देश को आजाद कराने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आगे रहा...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आजादी की लड़ाई में भागीदार नहीं रहा और मुखबिरी करने की सजाएं हुईं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: और क्रांतिकारी दल रहा, हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्रांतिकारी दल रहा और देश को आजाद कराने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का लेना-देना नहीं। आजादी की लड़ाई में एक आदमी ने कुर्बानी नहीं दी, आजादी की लड़ाई में एक आदमी ने भाग नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: और आप कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ देकर देश के साथ में +++ की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वीर सावरकर कौन था, भगत सिंह कौन थे, यह सब स्वयंसेवक थे।

श्री बंशीलाल खटीक: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश को आजाद कराने में आहूतियां दीं।

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, यह हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो कहा है वह एक्सपंज किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बिलकुल। हम इसकी निंदा करते हैं। (व्यवधान) निकाला जाय यह। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप हिंदुस्तान के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: यह हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य की +++ का स्वरूप है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: यह बिलकुल गलत कहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आजादी की लड़ाई लड़ी हो तो एक जगह मुझे बता दो, एक जगह इतिहास में बता दो आप। इतिहास में इतना सा भी लिखा हुआ नहीं है बल्कि यह है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की वफादारी की।

श्री मदन राठौड़: नहीं, आप क्या समझते हैं इस बात में। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है। यह किसी की...

श्री बंशीलाल खटीक: अंग्रेजों का साथ तो तुम कांग्रेस ने दिया था।

श्री मदन राठौड़: इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, यह इनकी +++ का प्रतीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा: विकृत मानसिकता नहीं है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो और जेल गया हो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता: माननीय सदस्य ने आर.एस.एस. के बारे में शब्द कहा है उसको बाहर निकाला जाय।

श्री मदन राठौड़: वह संगठन राष्ट्रीय चरित्रयुक्त व्यक्तित्व का निर्माण करता है उस संगठन के प्रति इन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, यह इनकी हीन भावना का प्रतीक है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, एक ही परिवार से चुनने का मतलब यह नहीं है कि मर्जी आये जो कहने लग जायें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डाक्टर हेडगेवार ने जेल यात्राएं सही थीं पाँच-पाँच साल तक की। कौन कहता है कि जेल में नहीं रहे।

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वह आप मेरे दांये-बांये तरफ जो प्रचार कर रहे हैं इस तरह से वोट देने वाली नहीं है जनता। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: और इसके लिए हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को ताड़ना दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: इस तरह से वोट के टोकरे नहीं भरे जायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा: यह वोट का सवाल नहीं है, वोट की राजनीति नहीं है। यह देश के इतिहास का सवाल है। वास्तविकता का सवाल है जो आपकी पृष्ठभूमि रही है उस बात...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: इस पृष्ठभूमि की बात अलग है पर मेरे दांयी और बांयी तरफ जो हो रहा है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ से जुडे हुए नेता ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ गवाही दी, उसको फांसी लगी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुडे हुए नेता को फांसी लगी और फांसी इसलिए लगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए नेता ने गवाही दी, अंग्रेजों की मुखबिरी की। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, जो संगठन इस देश में...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, आपस में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप राजस्थान में ही बता दो कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता स्वतंत्रता सेनानी रहा? (व्यवधान) स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बताओ आप, लिस्ट बताओ आप स्वतंत्रता सेनानियों की। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शब्द प्रयोग किये हैं वह एक्सपंज किये जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो शब्द प्रयोग किया है वह एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। आप इतने असहिष्णु क्यों बन जाते हो, थोड़ा सहिष्णु बनो। इन्होंने जो कुछ कहा है...

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो गलत शब्द प्रयोग किया...

श्री बंशीलाल खटीक: यह गलत शब्द शब्द कहे इन्होंने।

श्री अध्यक्ष: यह देखने का काम आसन का है कि क्या संसदीय है, क्या नहीं है। यह काम आसन का है, आसन देखेगा इसे।

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, जो संगठन राष्ट्रीय चरित्र निर्माण

(श्री मदन राठौड़)

में लगा है उसके लिए इन्होंने घटिया शब्द प्रयोग किया है वह एक्सपंज किया जाना चाहिए। वह एक्सपंज करायें अध्यक्ष महोदय, और वास्तव में इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। यह ठीक बात नहीं है...

श्री शांतिलाल चपलोत: इन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, ऐसा हिण्डौली से आने वाले सदस्य ने कहा, इन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। बदतमीजी की पराकाष्ठा है यह। हम बहुत सहन कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे खिलाफ चालू कर दें यह लोग...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: अच्छी-खासी बात चल रही थी और उसमें विघ्न डालने का काम इन्होंने किया है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को यहां की परम्पराओं का ध्यान नहीं है, उनको यह भान नहीं है, वह शायद भूल जाते हैं, उनको क्या पता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: संयमजी, एक गिलास पानी और पी आओ। एक गिलास और पी आओ आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने वाला संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ....

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: आपको पानी पीना था इसलिए ऐसा विवाद छेड़ दिया आपने।

श्री मदन राठौड़: राष्ट्रीय चरित्रयुक्त व्यक्तित्व निर्माण करता है, यह इनको क्या मालूम है, यह अपनी विकृत मानसिकता को शुद्ध करने का प्रयास करें, थोड़ा ठीक करें और यदि नहीं समझते तो एक बार जाकर के देखें कि वह किस प्रकार का संगठन है। थोड़ा अंदर जाओगे आपको पता चल जायेगा कि वह एक ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्र के लिए समर्पण करने की भावना सिखाई है दुनिया में। आप नहीं समझ पाओगे...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आपने कोई इतिहास बनाया है क्या। आजादी में कोई लेना-देना नहीं है (व्यवधान) इतिहास की जानकारी नहीं....

श्री मदन राठौड़: आपने केवल इस प्रकार के संगठन के लिए...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: हमें क्या इतिहास बताते हो...

श्री मदन राठौड़: आप आग लगाने का काम करते हो, आप कभी भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश को आजाद कराया है।

श्री मदन राठौड़: एक्सपंज करायें इन्होंने जो शब्द, हिण्डौली के माननीय सदस्य ने जो शब्द प्रयोग किया, वह एक्सपंज किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: हालात यही रहे तो अगली बार सरकार निर्दलियों की बनेगी।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री नरपत सिंह राजवी: अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही थी चर्चा...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी: उसके बाद में ऐसे तथ्य जो वास्तव में ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, यह अगर विषय ऐसे ओपन रहेगा, जो भी कहा है माननीय सदस्य ने, वह आप देख लें और एक्सपंजेबल है, एक्सपंज करवा दें ताकि कम से कम आगे चलें।

श्री अध्यक्ष: यह तो कह चुकी मैं कि यह काम आसन का है, क्या कहा?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): ठीक है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिए चलिए आप बिराजिए (व्यवधान) चलिए चलिए आप बैठिए (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गलत कह रहे हैं मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही जो प्रमाणित नहीं हो (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वो आपने ले लिया (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब दूसरे मैम्बर्स कहते हैं तो, मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते उसके लिए (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इतना ध्यान कर लेना कि जितना कह रहे हो उतनी ही क्षमता से जवाब सुन लेना बस आप। बात कर रहे हो?

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मुझे अलग से एक घंटे का टाइम दिया जाए, मैं कांग्रेस की बखिया उखेड़ (व्यवधान) आ जाओ सामने (व्यवधान) खोल दूंगा तुम्हारी बखिया (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आप लोगों की देन है (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री को इतना ही निवेदन करना है कि चाहे पाँच साल जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और चाहे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है, सुन लेंगे जवाब।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ये माननीय सदस्य जवाब सुनने तक यहां रहें और जवाब सुनकर के जाएं, आप कृपया इसके लिए सदन आश्वस्त करें कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी का जवाब सुनने तक रहें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यही अर्ज कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा मंत्रीजी का क्या, वन मंत्रीजी का जवाब सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम शिक्षा मंत्रीजी के भाषण के एक-एक शब्द सुनेंगे और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके के हमने आंकड़े दिए हैं वैसे के वैसे ही आंकड़े इसके विपरीत में आप देंगे। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैं दूंगा, एक घंटे तक (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठिए, आप क्या दोगे?

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): हां, मैं दूंगा आपको एक घंटे तक आंकड़े और आपको सुनना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपने घर जाइए ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आपको सुनना पड़ेगा मैं बोलूंगा क्या होता है साम्यवाद, क्या होता है ईसाईवाद, क्या होता है मुस्लिमवाद, क्या होता है (व्यवधान) मैं बोलूंगा आपके सामने (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): क्या होता है कांग्रेसवाद यह बताएंगे आपको (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा कंट्रोल करें कुछ सदस्यों को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना है कि उनकी रिप्लाई सुनने के लिए मैं इसलिए उपस्थित नहीं रहूंगा कि उन्होंने मुझे कहा है, मैं इसलिए भी उपस्थित रहूंगा कि मुझे मालूम है कि वे एक बेहतरीन वक्ता है, मैं उनको सुनने का लोभ-संवरण नहीं कर सकता। इसलिए उनको सुनने का मेरा पहले से ही इरादा है और मैंने हर बार, हर साल उनकी रिप्लाई को हमेशा सुना है। इसलिए मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आपके मंत्रीजी बहुत सक्षम हैं अगर कोई कमी रही होगी हमारी तो ये अपने आप उसका निस्तारण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: बीच में कोई नहीं बोलेगा, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: फिर वहीं बात आप कर रहे हैं, क्या बात हुई है अभी?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसलिए खड़ा हुआ हूं कि दस मिनट का समय था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस का समय है बोलेगा अगला, अपने को क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिस समरसता का नाम लेकर बोला, उस समय में राजस्थान में गुरु गोलवलर के नाम पर, जन्म-शति के नाम पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता आपकी पार्टी का टाइम कन्ज्यूम कर रहे हो न आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): (व्यवधान) नाम दिया है हमारे लोगों का कौन बोलेगा? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप समरसता के प्रचार की बात कर रहे हैं और राजस्थान के विद्यार्थियों को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सीधी सी बात है आप बिराजें। स्थान ग्रहण करें आप। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक बार आप भी स्थान ग्रहण करें। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से पूछ रही हूं कि पार्टी का टाइम कन्ज्यूम कर रहे हो या मैं जिस हिसाब से मुझे कंट्रोल

करना है कि कितना समय किसको दूं, उस हिसाब से करूं तो फिर आपकी पार्टी के लोगों की आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर बोलने का मौका नहीं दूंगी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप एक घंटे के बाद तो यह बात कह रही हो, एक घंटे के बाद यह बात कह रही हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे किसने पूछा है? प्लीज सिट डाउन। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप बताइए।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): एक घंटे के बाद आप कह रहे हैं यह बात तो आप हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, हमेशा आपका काम यही होता है हम जब खड़े होते हैं (व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने कहा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वो आप जैसा रेगुलेट करेंगी हम आपके साथ होंगे लेकिन मान्यवर, अनगिनत आदमी सत्तापक्ष की तरफ से एक साथ खड़े होकर के हाका मचाते हैं (व्यवधान) तो इसका ख्याल रखो।

श्री अध्यक्ष: हां, उनका हाका कंट्रोल करूंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, कंट्रोल करो।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल ही की बात है दस मिनट, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे यह सुझाव कांग्रेस की तरफ से ही आया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या चाहते हो? मैं बैठ जाऊं क्या? आप मंत्रीजी क्या चाहते हो? बैठ जाऊं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप अपनी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लीजिए, आप अपनी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लीजिए अगर प्रतिपक्ष के नेता देते हैं तो।

श्री अध्यक्ष: आसन भी नहीं चाहता, सत्तापक्ष भी नहीं चाहता, आपकी ही पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नहीं-नहीं, कोई नहीं चाहता है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, वो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं न।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हमारा तात्पर्य यह है कि आप एक घंटे के

(श्री श्रवणकुमार)

बाद ही आप रिप्लाई दे रही हो, पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए था, +++ कभी इधर से बोलते हैं, कभी उधर से, आप एक घंटे के बाद भी बैठे सुन रहे थे, एक घंटे तक +++ (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आसन पर आप इस तरह से आरोप नहीं लगाओ माननीय सदस्य यह आसन की अवहेलना है (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): क्या आरोप लगाया है मैंने?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आसन पर इस तरह का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है आपको, सदन सर्वोच्च है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं माननीय अध्यक्षजी यह बहुत गलत बात है (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष के बारे में इन लोगों ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाए अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्षीय व्यवस्था सर्वमान्य है जितना समय आप लेने वाले हैं उसका डबल समय हमारा है, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है जो निर्णय दे दिया वह सर्वमान्य है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं और आपके सदस्य खड़े हो जाते हैं क्या व्यवस्था है? (व्यवधान) इन्होंने क्या आसन पर आरोप लगाया है? आप बताइए, कैसी बात कर रहे हो?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): एक घंटे से बंशीलाल बोल रहे हैं। (व्यवधान) खड़ा नहीं होता है, हाउस कंट्रोल में नहीं है (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान) यह बोल रहे हैं एक घंटे से उनको आप रोक नहीं सकते (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस प्रकार आसन को चेलेंज करना क्या आसन सहन करता रहेगा?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो जाते हैं, इनको आप बोल नहीं सकते।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस प्रकार आसन को चेलेंज करना, क्या आसन अपनी व्यवस्था नहीं देगा?

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था देंगे लेकिन आप (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस प्रकार आसन के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कुछ आक्षेप नहीं लगाया, आप असत्य +++ बोल रहे हो (व्यवधान) आसन का ध्यान आकर्षित किया है आपकी गलत गतिविधियों के बारे में ...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपके दो सदस्य बोल रहे थे, हमने कुछ बोला क्या?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप लोग किस तरह से आसन की अवहेलना कर रहे हो वह बताइए (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अभी क्या कर रहे हो? किसकी अनुमति से खड़े हो रहे हो? अभी किसकी अनुमति से खड़े हो? (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): क्या तरीका है यह आपके दो सदस्य बोले, हमने बोला भी नहीं, आपके दो सदस्य बोले एक घंटे तक हमने कहा नहीं, बोला नहीं, हमारा सदस्य बोलने खड़ा होता है, आप खड़े हो जाते हैं, यह कोई हाउस कंट्रोल की बात है क्या? इस तरह हाउस चलता है क्या? यह कोई तरीका है क्या? क्या बात करते हो? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सदस्य आपने अध्यक्ष महोदय के खिलाफ आरोप लगाया है, आपने सदन की अध्यक्ष महोदया के ऊपर आरोप लगाया है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ऐसी बात नहीं कहो, जो सदन में सही नहीं हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यही कहना चाहूंगा कि पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने (व्यवधान) आसन को जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, उनको हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप बार-बार बीच में बोल रहे हो? जवाब शिक्षा मंत्रीजी को देना है आपको तो वसुंधराजी ने कुछ बनाया नहीं है। आप उनकी बात को कह देने दीजिए यह बात सुनेंगे और जवाब दे देंगे, आप बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिलानी से

आने वाले माननीय सदस्य का व्यक्तिगत रोल हो सकता है लेकिन उस पर अभिव्यक्ति इस हाउस के अंदर इस प्रकार से नहीं की जा सकती, अगर आसन के प्रति जो भी शब्द कहे जो टॉलरेबल नहीं है, आपत्तिजनक है उनको एक्सपंज किया जाए और काम आगे आगे चलाया जाए (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कौन से आपत्तिजनक हैं, आसन के प्रति कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहे, किसको एक्सपंज करें? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आसन के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं, आप क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कोई नहीं कहा है उन्होंने यह कहा है (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): क्या कह दिया आसन को, आसन को कुछ नहीं कहा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इन्होंने कहा है आप कंट्रोल करो, यह हकीकत है इन्होंने क्या गलत बात कही है? आप बीच में आकर बोल रहे हो तो कंट्रोल तो आसन ही करेगा, हम करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने गैर सम्मानजनक बात कही है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मोहन लालजी मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं आप चाहे जब खड़े हो जाते हैं। बंशीलाल चाहे जब खड़ा हो जाता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आज आपकी बात कह रहा हूं आपने आसन का अपमान किया है, आपने अध्यक्ष महोदय का अपमान किया है, आपके शब्दों को निश्चित रूप से निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): क्या कह दिया, क्या कहा है मैंने यह कहा है कि हाउस कंट्रोल नहीं हो रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगी तो निकाल देंगी आपको क्या तकलीफ है? यह अध्यक्ष महोदय स्वयं ही फैसला कर देंगी। आप हर बार बीच में खड़े होते हो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, इनके जो अपमानजनक शब्द हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): राजस्थान के छंटे हुए 200 यहां बैठे हैं हाउस को आर्डर में करना आसान है क्या? (व्यवधान) छंटे हुए 200, आसान है क्या साढे पाँच करोड़ में 200 यहां जो एकदम छंटे हुए हैं (व्यवधान) वह आप अंदाजा लगा लें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल से समरसता के, समाज में समरसता की स्थापना के नाम पर गुरु गोलवलकर की जन्मशति को लेकर के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: He is consuming his party's time. I can't do anything.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लगातार अभियान चलाया गया, हमारी पार्टी ने मुझे इजाजत दे दी है मंत्रीजी, मैं सिर्फ पाँच मिनट और बोल रहा हूं। (व्यवधान) आपके पेट में दर्द बहुत होता है मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनका बंटवारा तो अध्यक्ष महोदय आसन करेगा, पूरा बुला दो फिर अभी तक फिर इधर से बोलेंगे, हमारी तरफ से भी (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका वक्ता (व्यवधान) जब एक घंटा बोला था जब आप कहां गये थे? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आधा घंटा बोले हैं पहले वक्ता हमारे आधा घंटे बोले हैं माननीय अध्यक्षजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं आधा घंटा बोला हूं। मुझे सभापति महोदय ने टोक दिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डराते क्यों हो आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर हमको भी आता है खड़ा होना ... (व्यवधान) आपके लोग बार-बार विरोध कर रहे हैं आप इनको रोकते नहीं हो। उनको कंट्रोल करो न फिर।

डा. सुरेश चौधरी: संसदीय कार्य मंत्रीजी के पास गायनॉकॉलोजिस्ट बैठे हैं और आपको पता चल रहा है यहां से इतनी दूर से कि उनके पेट में दर्द हो रहा है गायनॉकॉलोजिस्ट तो उनके पास है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पिछले एक साल से गुरु गोलवलकर जन्म-शती के नाम पर सामाजिक समरसता की स्थापना को लेकर पूरे राजस्थान में कार्यक्रम चलाया गया । उस दलित आदिवासी भाई के घर से रोटी मांग करके लायी गयी। उसको यह संदेश देने की कोशिश की गई कि तेरे सबसे बड़े हिमायती हम हैं और इसी विचारधारा के लोग सरकार चलाते हुए क्या पढ़ा रहे हैं, जाति व्यवस्था में विभिन्न लोगों को एक दूसरे के साथ संतुष्टिपूर्वक रहने का अवसर प्रदान किया जिसमें उनमें स्थाई एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें। एक तरफ तो समरसता की बात करते हो और दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को यह पढ़ाते हो कि जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जाति व्यवस्था श्रेष्ठ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। आपको स्पीकर ने अलाऊ नहीं किया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ये क्या तरीका है Who is he to say to me 'sit down'? Who is he to say to me 'sit down'? मुझे भी अधिकार है बोलने का आप किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं वो पूरा संदर्भ दीजिये तब पता चलेगा उसका मीनिंग ऐसे कहां से बोल रहे हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये काम आप लोग कर लेना, हमको अपना काम करने दो।

श्री अध्यक्ष: लेकिन आप बीच-बीच में क्यों उठते हो? यह कोई तरीका नहीं है आपका।

श्री मदन राठौड़: ...(व्यवधान) नहीं ये केवल अपने पास से लिखा हुआ बोल रहे हैं यदि वास्तव में इस प्रकार का है तो टेबल करो न अब क्या है आपके पास।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, आपका टाइम आये तब बोल देना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं टेबल कर दूंगा किताबें अगर एक शब्द भी, मेरा कहा हुआ रिकार्ड है मेरा अगर एक शब्द गलत हो जाए तो विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री मदन राठौड़: नहीं तो किस संदर्भ में है? कृपया अध्यक्ष महोदय, आप जो बोल रहे हैं वो संदर्भ पूरा बोलें । पूरा संदर्भ नहीं बोल रहे हैं उसमें से एक इश्यू निकाल करके बोल रहे हैं यह क्या मतलब है?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) आने वाले समय में जनता ...(व्यवधान) लेगी।

श्री बद्री लाल जाट : ...(व्यवधान) कितनी बार दिया इस्तीफा?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) इन्हें कंट्रोल कराइये और इस डिबेट को आगे बढ़ाइये।

श्री मदन राठौड़: नहीं, लेकिन ये गलत है न एक लाइन निकाल कर बोल दो। बोलो तो पूरा संदर्भ बोलो तो समझ में भी आता है।

श्री बद्रीलाल जाट: ये इस्तीफा कितनी बार आप दे चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: केवल एक लाइन निकाल कर बोल दी, आप पूरा संदर्भ बताइये तब समझ में आएगा कि किस संदर्भ में बात कही थी।

श्री अध्यक्ष: मैं देख रही हूं कि चार-पाँच सदस्य ऐसे हैं जो न तो बोलने देते हैं किसी को और जिनका काम है केवल व्यवधान डालना और मैं सब को देख रही हूं कौन-कौन ऐसा कर रहे हैं।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिये। ऐसे लोगों को आप चिन्हित कीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब आप फिर बीच में बोलने लगे। यस कंटीन्यू।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मैंने जाति व्यवस्था के प्रति, यह सरकार राजस्थान में नयी पीढ़ी के लोगों को क्या पढ़ाना चाहती है और बारहवीं कक्षा की अर्थशास्त्र की पुस्तक के बीसवें अध्याय में इन्होंने क्या लिखा है, सब स्मृतिकारों ने, मनु का व्यक्तित्व महान है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारतीय साहित्य में मनु को मानव जाति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में मनु को मानवता का पिता कहा गया है वे ब्रह्मा के मानस पुत्र की परम्परा में आते हैं। आपके लिए यह सही हो सकता है पर उन लाखों करोड़ों दलित आदिवासियों के लिए यह बिलकुल ठीक है उनके शोषण को, मनु की विचारधारा के आधार पर पाँच हजार साल तक उन लाखों दलित आदिवासियों का शोषण हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दसवीं कक्षा की सामाजिक ज्ञान प्रथम के आठवें अध्याय में मुसलमानों के प्रति क्या लिखा गया है। राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की तरफ पाकिस्तान को स्पर्श करती है।

सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी अत्यंत गरीब, अशिक्षित, धार्मिक श्रद्धा के कारण अंधविश्वासी भी हैं। समुदाय विशेष का तुष्टिकरण, सामाजिक भेदभाव, धर्मांतरण, अलगाववाद, घुसपैठ एक विकट समस्या बन चुकी है उनके साथ में लिंक करके ...(व्यवधान)... उनसे लिंक करके एक समुदाय के लोगों की निष्ठा पर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के लिए अशफाक उल्लाह जैसे लोग भी शहीद हुए हैं । एक संविधान निर्माण के तहत निर्मित सरकार को इस तरह का एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाने का पाठ पढ़ाना नयी पीढ़ी को माननीय अध्यक्ष महोदय, किस रूप में ठीक है? यह राजस्थान के शिक्षा मंत्री विचार करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: किताब है कहां, कौनसी किताब है?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

डा. जालमसिंह रावलोत : अध्यक्ष महोदय, यह आम मुसलमान के लिए नहीं है जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अगुवा हैं और इनकी पार्टी ने राष्ट्रद्रोही गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को विधायक बनाया है, जिला प्रमुख बनाया है, सांसद तक बनाया है इसलिए जो पुस्तक में लिखा गया है, मैं पिछले दस साल से सीमा जनकल्याण समिति के कार्यकर्ता के नाते 17 तहसीलों में घूमा हूं जो पुस्तक में लिखा गया है वो बिलकुल सही है। मुसलमानों के प्रति हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की और हमारी संस्थाओं की कोई गलत धारणा नहीं है राष्ट्रद्रोहियों के प्रति जो लिखा है वो बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये आप उद्धृत कौन सी पुस्तक से कर रहे हैं? मैं जहां तक देख रही हूं इस किताब को यह बार्क ने शायद आपको दी है और कोई ऑथेंटिक आप किसी पुस्तक में यह लिखा हुआ है जो कोर्स की किताब हो उसमें लिखा हुआ हो उस पुस्तक को पढ़कर सुनायें, बार्क के आधार पर नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुस्तकें मेरे पास मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष: बार्क ...(व्यवधान) सेन्टर के नाम पर एक सेन्टर चलता है और वो सेन्टर यह बात ठीक है कि बजट के बारे में आपको कुछ सूचनाएं देते हैं लेकिन किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मैं नहीं समझती कि यह कोई ऑथेंटिक बात है आपकी क्योंकि उन्होंने कोई यह किताबें थोड़ी पढ़ी हैं जिस आधार पर वो लिख रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो भी बात कह रहा हूं एक-एक अध्याय का जिक्र कर रहा हूं मैं पुस्तक का, क्लास का जिक्र कर रहा हूं और ये कोई बार्क से इसका कोई लेना-देना नहीं है इस किताब का।

श्री अध्यक्ष: वो किताब दिखायें। कोई बार्क के आधार पर नहीं, किताब दिखायें आप हमें। बार्क के आधार पर नहीं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह इस किताब से बार्क का कोई लेना-देना नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बार्क को पढ़कर बार-बार बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बार्क से कोई लेना-देना नहीं है इस पुस्तक का । ये राजस्थान के स्कूली पुस्तकों के संबंध में मैं सारी पांचों किताबें लेकर आया हूं और एक-एक अध्याय का मैं जिक्र कर रहा हूं और आपको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ा लेने दो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: कितने बजे तक के लिए?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 6 बजे तक के लिए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मांगें पास होने तक बढ़ाया जाए । शिक्षा की मांग है ऐसे नहीं होगा। 12 बजे तक चलेगी।

श्री भवानी जोशी: आप तो हमेशा 8 बजे बाद चले जाते हो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): पूछ लो मंत्रीजी से।

श्री भवानी जोशी: नहीं, कल भी नहीं थे आप, परसों भी नहीं थे और आप 12 बजे की कह रहे हैं। हमको बैठे रहना पड़ता है 12 बजे तक।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार एक घंटे के लिए बढ़ायें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): जोशी साहब, आपका काम बैठना ही है कोई फाइल तो निकालते नहीं हैं। कोई काम ही नहीं है आपके पास । आपके पास क्या काम है? हमारे पास पचास काम हैं मैटर इकट्ठा करना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है। आपको क्या काम है? सरकार पर भार हो आप। जनता के ऊपर भार हो सिवाय घूमने के ...(व्यवधान) मंत्रीजी, फाइल निकालते हो, कोई घोषणा करने को कंपीटेंट हो? फिर क्यों बात कर रहे हो? हम तो काम कर रहे हैं जाकर के।

श्री रामप्रताप कासनिया: इनके पास काम बहुत हैं। काम इनके पास है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनके पास काम है तो ये मंत्रीजी का रिप्लाई सुनना भी एक काम है। यह भी एक काम है।

श्री अध्यक्ष: समय तो बढ़ा लेने दीजिये 4.59 हो रहे हैं। क्या सदन की अनुमति है?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने घनश्यामजी तिवाड़ी का पूरा भाषण सुना है रात 11.45 बजे गया हूं यहां से और कह रहे हैं। मालूम नहीं है तो पूछें घनश्यामजी तिवाड़ी ने भाषण दिया, मैं सुनाऊं क्या भाषण आपको?

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप जरा आसन की ओर देखें। क्या सदन की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: हां किस बात पर ? मैं कोई आगे बोली ही नहीं। क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घंटों के लिए और बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

दो घंटों के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): इन्होंने इन एंटीसिपेशन बोला है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आशंका व्यक्त की है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: अब आप थोड़ा कंक्लूड कर लें। प्लीज कंक्लूड करें क्योंकि और भी बहुत बोलने वाले हैं। You have taken more than an hour and a half.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... कि कल माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का रिप्लाई जब नीरस और बोझिल होने लग गया तब मैं सदन से चला गया था।

श्री अध्यक्ष: आपका भी बहुत बोझिल हो रहा है। अब आपका भी बोझिल हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को पौन बजे तक इन सारी किताबों को चाटने का काम मैंने किया है। यह टैग लगाये हुए हैं, एक-एक किताब पर टैग है और आप चाहेंगे तो मैं जो मैंने बोला है एक एक शब्द इन किताबों में आपको पढा दूंगा अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष: तो आपने पढने का काम किया या चाटने का किया ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी किताब के सामाजिक जागरूकता के अध्याय में क्या लिखा है । जम्मू-कश्मीर .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में ना बोलें माननीय सदस्या ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जम्मू-कश्मीर की सरकार आतंकवादियों के दबाव में काम करती है । कुछ नेता उनसे सांठ-गांठ रखते हैं जिनके कारण पुनर्वास विधेयक पारित करवाया गया । धारा 370 संविधान में अस्थाई प्रावधान रखा गया जिससे तुष्टीकरण एवं दबाव निरन्तर बनाये रखा जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, संविधान के उस अनुच्छेद के खिलाफ संविधान के तहत सरकार के द्वारा कैसे पढाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हर स्तर पर संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। चाहे प्रभारी मंत्रियों की बात हो, चाहे मंत्रीमंडल की बैठकों की बात हो, चाहे सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो, चाहे मुख्य मंत्री के साथ टीम भावना से काम करने की बात हो, उन पर

(श्री संयम लोढ़ा)

भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात हो । अध्यक्ष महोदय, यह लगातार संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर रही है ।

श्री अध्यक्ष: इससे क्या ताल्लुक है शिक्षा की मांग का ? आज की मांग से इसका ताल्लुक बताओ ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, जगमोहन के हवाले से जो जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं ।

श्री अध्यक्ष: जम्मू-कश्मीर का आज की शिक्षा की मांग से क्या ताल्लुक है? अब आपका भाषण भी बहुत बोझिल हो रहा है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इससे अच्छा तो यह लिखवाते कि महाराणा सांगा ने खांडवा में जो बाबर के खिलाफ लड़ाई लडी थी उसमें किन लोगों ने महाराणा सांगा को धोखा दिया था और कौन लोग उनके साथ लड़े थे यह भी लिखवा देते ।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हो आप समझ में नहीं आ रही बात ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह भी लिखा है कि मेव उनके साथ लडे थे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): धोखा किसने दिया था यह भी बता दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह भी आपका कोई भाई था ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं 11वीं कक्षा की समाज शास्त्र द्वितीय की जो पुस्तक है उसमें बहु विवाह की पैरवी की गई है और यह कहा गया है कि बहु विवाह की वजह से संतानें उत्तम होती हैं। नस्लवाद की पैरवी की गई है और यह कहा गया है कि आरक्षण से कुशलता में कमी आती है, विद्वेष और वैमनस्य फैलता है । यह सारी बातें राजस्थान की यह सरकार हमारी नई पीढ़ी के लोगों को पढाना चाह रही है ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपके दिमाग में जहर भरा हुआ है न एक समुदाय के लोगों के प्रति और जिस विचारधारा का पोषण आप पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान में कर रहे हैं आपकी आँख खोलने के लिये मैं आपकी सरकार के द्वारा यह जो संस्कृत शिक्षा विभाग है इसमें जो आपने टेबल किया है, मुझे कम समय दिया आपने फिर भी मैंने इसमें कुछ ढूंढ कर आपको रोशनी देने के लिये कोई आंकड़ा जुटाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

(श्री संयम लोढ़ा)

करना चाहता हूं कि यह जो संस्कृत शिक्षा के राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों की जो संख्या है वह टोटल तो 1 लाख 10 हजार है लेकिन उसमें 2494 लड़के और लड़कियां हैं। वह संस्कृत पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक समुदाय और राजस्थान और हिन्दुस्तान का हर समुदाय पूरी निष्ठा के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है । इस देश को और इस प्रदेश को तरक्की के लिहाज से शिखर पर पहुंचाने के काम में लगा हुआ है और यह संस्कृत का ठेका सिर्फ आपकी विचारधारा के लोगों ने नहीं लिया है । भाषा, भाषा है हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्युशन करना चाहता है । हालांकि आपने संस्कृत के संदर्भ में उन पुस्तकों में जो लिखा है वह किताबें मेरे पास मौजूद हैं अगर मैं उन टिप्पणियों को भी पढ़ाऊंगा तो वह भी बहुत वैमनस्य से भरी हैं और धार्मिक विद्वेष से भरी हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने लोगों के क़शीदे सुन कर मस्त मत हो जाना । राजस्थान को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीदें हैं । बहुत भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने पहली बार बहुमत दिया था और यह जो घोषणाएं आप करते हैं यह घोषणाएं लगातार सिर्फ घोषणाएं बन कर रह रही हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार खुले दिल के साथ चाहे 'सर्व शिक्षा अभियान' हो, चाहे निचले स्तर पर माध्यमिक शिक्षा ग्राम स्तर पर लोगों को सुलभ कराने की बात हो (व्यवधान) जिस उदार दिल के साथ भारत सरकार आपको सहयोग कर रही है और भारत सरकार आपको पैसा दे रही है उस पैसे का राजस्थान की जनता के हक में सदुपयोग करें और मेहरबानी करके यह जो गंदी बातें, घृणा से भरी हुई बातें, वैमनस्य से भरी हुई बातें हमारी राजस्थान की नई पीढ़ी को आप लोग इन पुस्तकों के माध्यम से पढाने की कोशिश कर रहे हो और उसका कारण भी हम जानते हैं क्योंकि आज कल पूरे राजस्थान में आर.एस.एस. की शाखाओं में तो बच्चे आते नहीं, बच्चे आना बंद हो गये और बच्चे आना बंद हो गये तो इन किताबों के ज़रिये वह विष और वह जहर जो उन आर.एस.एस. की शाखाओं में आप नई पीढ़ी के दिमाग में डालते हो, इन किताबों के ज़रिये उन बच्चों के दिमाग में आप वह जहर पैदा करने का काम कर रहे हो, वह विष फैलाने का काम कर रहे हो

(श्री संयम लोढ़ा)

लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके इस मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देगी और राजस्थान के हर नौजवान को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से जोड़ कर एक स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिये उसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगी, पूरा उपयोग करेगी, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के पक्ष में अपना विषय रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके के आक्षेप, जिस तरीके के कटु भाव हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा पर रखे मैं उसकी कडी आलोचना करता हूं । अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले की बात है जब जोधपुर यूनिवर्सिटी में यह एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ता के नाते और मैं ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ता के नाते काम करते थे । हमारा शुरू से आपस में वाद - विवाद का विषय चलता रहा है । यह संघ के स्वयं सेवक रहे हैं । इनको ए.बी.वी.पी. में टिकट नहीं मिला, इनके पिताजी, इनके भाई, इनके परिवार के सब लोग संघ के स्वयं सेवक हैं । इनको ए.बी.वी.पी. का टिकट नहीं मिला इसलिए एन.एस.यू.आई. में चले गये । वह भड़ास यहां निकाल रहे हैं और कोई काम नहीं है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, I am on a point of explanation. इन्होंने यह कहा है कि मैंने ए.बी.वी.पी का टिकट मांगा था और मैं संघ से जुडा हुआ रहा हूं यह पूरी तरह गलत है। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हां, जुडे हुए थे संघ से ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): I am on a point of explanation. I am on a point of explanation.

श्री अध्यक्ष: आप इनके बोलने के बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे देना ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में जिस तरीके का चित्रण किया है मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो बातें बताई हैं वह फालतू की बातें है, जो लिखी गई हैं वह बिलकुल सही बातें लिखी गई हैं। पहले जब महामहिम भैरोंसिंहजी के

नेतृत्व में शासन चल रहा था उस समय नवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में गद्य पद्य संग्रह में पाठ था- 'स्वदेशी का भाव'। जोग से सत्ता परिवर्तन हुआ और जो पाठ्यक्रम में पाठ था स्वदेशी जिसके माध्यम से कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन चला कर देश द्रोहियों को, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला था उसी स्वदेशी के भाव के पाठ को इन्होंने पाठ्यक्रम से निकाला । मैं आपके माध्यम से इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के संस्थापक ए. ओ. ह्यूम जो खुद विदेशी थे और अभी इनकी नेता भी विदेशी हैं । इनका विदेशी का भाव है इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम से स्वदेशी को निकाला । इनके मन में स्वदेशी नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा पर बोल रहे हैं क्या, किस पर बोल रहे हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, इनको बोलिए यह शिक्षा पर बोलें, यह विदेशी भाव कौनसा है ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ... (व्यवधान) सोनिया गांधी ... (व्यवधान) की नागरिक है (व्यवधान) सोनिया गांधी विदेशी नागरिक है वह विदेशी नागरिक होते हुए भारत की नागरिक है । संविधान में प्रावधान है मैंने इसकी अच्छी तरह से स्टेडी कर रखी है ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम कोई पाकिस्तान से थोडे ही आये हैं हम भी हिन्दुस्तान में रहते हैं ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं है, समय की मर्यादा है ।

आपका संरक्षण चाहता हूं। इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में, इनके राज के समय जो पाठ्यक्रम चलते थे उसमें लिखा है कि शिवाजी, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप, राजा सूरजमल जाट को पाठ्यक्रम में डकैत, पहाड़ी चूहा बताया। देश के करोड़ों-अरबों लोगों की भावना को आघात किया है। जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी, जय सरदारजी की, जय सूरजमल जाटजी की। इन सबको यह डकैत, पहाड़ी चूहा बताते हैं और फिर पुन: राजस्थान में राज आने का सपना देख रहे हैं। इनको राजस्थान की सरकार कभी नहीं मिलने वाली, ऐसा मेरा दावा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मूल विषय पर आना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह माननीय सदस्य जो, असत्य है, आप तो स्वयं पढ़ी हैं। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अभी पंजाब में, ग्वालियर में, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में हम पुन: (व्यवधान) सत्ता में आने वाले हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस तरह की बात किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी भी सरकार के द्वारा कभी नहीं कही गई। आप स्वयं जानती हैं। जिस तरह की बातें इन्होंने कही हैं कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी सरकार ने इस तरह की बातें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं असत्य है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): स्वदेशी का भाव (व्यवधान) मेरा लिखा हुआ हटाया गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जब कैब की मीटिंग में विरोध किया था वह यही विरोध किया था कि वहां जाटों को लुटेरा और हत्यारा लिखा गया था1 शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा गया था। महावीर भगवान को एक भिखारी के रूप में चित्रित किया गया था। मुझे खुशी है कि मेरी इस बात का फिर हुड़ा साहब ने भी समर्थन किया। 50 साल तक, जिन जाटों को आप लुटेरा कहते थे उनको देशभक्ति की श्रेणी में हमने खड़ा किया, यह मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वह किताब एन.डी.ए. सरकार के टाइम में छपी होगी। (व्यवधान) एन.डी.ए. सरकार के समय तो छपनी ही थी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनके काले करतूतों का खुलासा किया है (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जो जिक्र कर रहे हैं अंग्रजों के जमाने की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मानव संसाधन मंत्री अर्जुनसिंहजी के जमाने में लिखी गई, कांग्रेस के जमाने में लिखी गई(व्यवधान) मुरली मनोहर जोशी ने इनको हटा दिया था और आप इनको वापस लगाना चाहते थे, उनको हमने नहीं लगाने दिया। यह मेरी जीत है सबसे बड़ी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ना, 61.3 प्रतिशत होना, पुरुषों में 76 प्रतिशत, महिलाओं में 44 प्रतिशत होना क्या इस बात का प्रतीक नहीं कि राजस्थान में पिछले तीन सालों में शिक्षा का सर्वांगीण विकास हुआ है? कोई पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर का किसी

सरकार को मिलता है तो इनके जमाने में क्यों नहीं मिला। अंतरराष्ट्रीय सरकार सर्वाधिक दृष्टि से यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड, 2006 राजस्थान को मिला है। राजस्थान की मुख्य मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी की कार्यकुशलता के कारण मिला है। मैं इस हेतु राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं। सत्यमेव मैत्रेय पुरस्कार भी इनके जमाने में राजस्थान को क्यों नहीं मिला क्योंकि इन्होंने क्या किया, पाँच साल में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं करना, पाँच साल का पीरियड, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लंबे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पैसा इसलिए नहीं मिला, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। आपकी सरकार थी उन्होंने पैसा नहीं दिया।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बैठिये, बैठिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसलिए कहां से नियुक्ति करते। अब हमारी सरकार खुले हाथ से दे रही है इसलिए नियुक्ति कर रहे हो। यह बता दीजिए मिडिल स्कूल तक (व्यवधान) सर्व शिक्षा के अभियान के लिए पैसे कितने दिये हैं?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी सरकार भी पैसे देती तो हमारी सरकार भी नियुक्ति कर देती। आप अपनी उपलब्धियां बताइये, आपने यह नहीं किया, आपने यह नहीं किया, रोज सुबह-शाम यही काम करते हो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने पाँच साल में एक भी नौकरी नहीं दी, जिन लोगों ने पाँच साल में एक भी विद्यालय नहीं खोला, जिन लोगों ने एक कमरा नहीं बनाया वह बड़ी-बड़ी बातें करते थकते नहीं जा रहे हैं। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने सब जगह प्रगति की है। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना कि राजस्थान को न केवल विकसित राज्य बनाना, विकसित राज्यों में भी क्रंमाक एक का विकसित राज्य बनाना उसको पूरा करने के लिए हमारे मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आगे बढ़ रहे हैं तो बिजली मंत्री बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान को नई दिशा दे रहे हैं तो सिंचाई और पानी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षा

के मामले में हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कमाल ही कर दिया। क्या कारण था अखिल भारतीय स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा को सार्वजनिकरण करने के लिए यानी दसवीं तक और बारहवीं तक सर्व शिक्षा अभियान लागू हो उसके लिए जो कमेटी बनी तो यह साम्प्रदायिक कहे जाने वाले कथाकथित मंत्री, तो इनको उस कमेटी का चेयरमैन कैसे बनाया, आप इसका उत्तर दीजिए। कुछ इनमें गुण था, कुछ इनमें योग्यता थी तब उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया। न केवल कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसके बारे में इन्होंने जो मेहनत करके उस कमेटी की जो रिपोर्ट दी माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए यानि हर पंचायत मुख्यालय पर दसवीं स्कूल होना चाहिये और बिल्डिंग का निर्माण और सारी सुविधाएं जो आठवीं स्कूलों तक होती हैं, वह दसवीं स्कूलों तक होनी चाहिये, उसके बारे में जो शानदार सुझाव हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने दिये, उसका परिणाम है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया उसमें माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विषय को उन्होंने प्राथमिकता से लिया। दसवीं, माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक का जो बजट था उसको दुगना किया गया। दो हजार करोड़ से बढ़ाकर चार हजार करोड़ रुपये किया गया। वह अगर किसी की देन है तो राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्रीजी की देन है, जो राजस्थान के मुख्य मंत्री के मार्गदर्शन में बहुत शानदार काम कर रहे हैं।

विद्यालय खोलने का मामला है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इनके समय जो स्कूलें खुली, राजीव गांधी स्कूलें इन्होंने खोली । राजीव गांधी स्कूलें, क्या हालत रही और किस तरीके से खोली, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता के ढाणियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में खोली गई। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे उनके यहां राजीव गांधी स्कूल नहीं खोली। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आंकड़े जो बता रहा हूं बिल्कुल आपके सामने हैं ।

इन राजीव गांधी स्कूलों को आपने प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्यों नहीं बदला ? आपके राजीव गांधी स्कूलों की हालत क्या थी, 800 रुपये का टीचर आपने लगाया उसकी जगह हमने आपकी सारी राजीव गांधी स्कूलों को प्राथमिक शिक्षा के रूप में बदला। आपने एक भी स्कूल को नहीं बदला, हमने 21812 राजीव गांधी स्कूलों को प्राथमिक स्कूलों में बदला।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया कनक्लूड कीजिए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरूआत है। मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं। मेरे से पहले वाले सब एक-एक घंटे बोल कर गये हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है जो अनपढ़ है वह बोल नहीं सकते।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मुझे तो मौका ही नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी की तरफ से सुझाव आया है कि हर माननीय सदस्य को दस-दस मिनट बोलने का मौका दिया जाए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह पहले लागू करना चाहिये था, फिर भी मैं जल्दी कर दूंगा1

श्री अध्यक्ष: आपने 5.6 पर बोलना शुरू किया था और 5.17 हो रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बीच में कांग्रेस के लोगों ने टोकाटोकी की उससे लेट हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य ऐसी बात करेंगे जिस पर लोगों को एतराज हो तो करेंगे भई। यह बोलेंगे तो आप करोगे, आप बोलोगे तो यह करेंगे। इसलिए आप ऐसी बात कहो ही नहीं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का चित्रण, सिरोही से आने वाले सदस्य, बार्डर के जिलों के बारे में लिखा गया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं कि हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की, हमारी विचारधारा की मुसलमान बंधुओं के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। जो टीका टिप्पणी की है (व्यवधान) वह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए लोग, कांग्रेस ने जिनको बढ़ावा दिया है उनके बारे में की है, इन्होंने बड़े-बड़े पदों तक पहुंचाया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।

मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं प्राथमिक स्कूल 2001 से 2003 इन्होंने एक भी नहीं खोली हमने 4162 खोली। कुल मिलाकर इन्होंने स्कूलें खोलीं या क्रमोन्नत की उनकी संख्या 4 हजार और हमारी 39 हजार। अभी सैकण्डरी स्कूलें 1500, सीनियर 600 और नई प्राथमिक और नई मिडिल कितनी होने वाली हैं उसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): रोजगार के क्षेत्र में (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मेरा संरक्षण करिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय आप एक अच्छे अधिकारी है, मंत्री है, मेरा आपसे एक निवेदन है कि कम से कम माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने में आप निष्पक्ष आचरण करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, यह बीच में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बोल रहे हैं (व्यवधान) क्या बोल रहे हैं आप बीच में?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक लाख अध्यापकों की नियुक्ति की...

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): विद्यालय, बजीरपुर में 9 साल पुराना है। 9 हजार व्यक्ति उस गांव में रहते हैं। 9 साल पहले वह स्कूल माध्यमिक हुआ था और आज तक वह क्रमोन्नत नहीं हुआ, मैंने आपसे निवेदन किया.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो इनका।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक लाख अध्यापकों की नियुक्ति होना इस बात का सबूत है कि हमने चिंता की है। मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महाभियान हमारी शानदार उपलब्धि है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): XXX

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इसमें हमारी उपलब्धि (व्यवधान) कम आयु के बच्चों का नामांकन 94 प्रतिशत होना, महिलाओं, बच्चों का नामांकन 93 प्रतिशत होना, हैल्थ चैक-अप 93, हैल्थ कार्ड वितरण 98, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण 99, टी.एस.पी. बालिकाओं को साइकिल वितरण 94 ...

श्री अध्यक्ष: आपको बोलना है तो बोलिये। कागज पढ़ने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) कागज पढ़ने की जरूरत नहीं है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके का हमारे यहां काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में उसकी भूरि-भूरि प्रंशसा करना चाहता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सैकण्ड्री स्कूल पूरे क्षेत्रों में और पूरे राजस्थान में हर पंचायत मुख्यालय पर हो। इसके लिये पूरे प्रयत्न होने चाहिए, आप प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे यहां जो गये सत्र में शुरूआत जुलाई में होती थी, वह...(व्यवधान) के दिन करके बहुत ही पवित्र काम किया है। पहली कक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता, नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण, पहली से 12 तक, यह तो शानदार उपलब्धियां हैं। हमारे क्षेत्र में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, एक ऐसे शानदार विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में चल रहे हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह आवासीय विद्यालय चूंकि बालिकाओं से जुड़े हुए हैं, यह ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहां पुलिस स्टेशन हों या पुलिस चौकी हो, सुरक्षा के पाइण्ट से यह बहुत ज़रूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है लेकिन अभी प्राथमिक शालाओं की हमारे जिलों में, बाड़मेर व जैसलमेर में, बहुत ज्यादा जरूरत है। एक किलोमीटर की जो मुख्य मंत्रीजी की और शिक्षा मंत्रीजी की सोच है उस सोच के तहत बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय और होने चाहिए जिससे हर गरीब पढ़-लिख पायेगा। संस्कृत शिक्षा के बारे में हमारी सरकार ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है। संस्कृत विश्वविद्यालय खोला है, वेद विद्यालय प्रत्येक जिले में 2-2 खोले हैं। लेकिन आज संस्कृत का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस हेतु हमारे यहां विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत से सम्बन्धित जो जुड़े हुए विषय हैं, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, इनके बारे में विशेषज्ञ कोर्सों की जरूरत है। इस हेतु शोध की जरूरत है। इस नाते मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय में यह कोर्स खोले जाएं और इसमें रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(समय : 17.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति पदासीन)

अभी विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिनके यहां संस्कृत की ओर संस्कृत से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, जो पण्डित हैं, उनकी जरूरत थी 2200 पण्डितों की लेकिन हम केवल 400 पण्डित दे पाये। यह जो 2200 पण्डितों

की मांग की थी, नीदरलैण्ड ने, पैराग्वे ने, फिनलैण्ड ने, स्विटजरलैण्ड ने, बोस्निया ने, नार्वे ने, डेनमार्क ने, आयरलैण्ड ने ..(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सभापति महोदय, आप पूर्व में जानते हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को और बाकी को खूब समय मिला। (व्यवधान) मैं संक्षेप में अपनी बात पूरी कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे यहां इतने सारे स्कूल हो गये हैं, इतने सारे स्कूलों के अन्तर्गत व्यवस्थाएं हो गयी हैं, इसकी मोनिटरिंग के लिये, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, एस.टी.आई., जिला शिक्षा अधिकारी, इनके बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं उनको भरने के लिये हमारी यशस्वी सरकार पूरी प्रयत्न कर रही है। इनको तुरन्त भरा जाए ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और एक शिक्षित राज्य के रूप में राजस्थान का नाम, जो कल्पना हमारी सरकार की है, वह बढ़े। मैं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिये हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल स्कूल खोले, न केवल उन भवनों का निर्माण किया बल्कि हमारे यहां जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी गुणवत्ता के परीक्षण का जो काम चालू किया है वह जोरदार काम है। वह पिछले सत्र में चौथी कक्षा और सातवीं कक्षा के छात्रों की गुणवत्ता की जांच हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि गुणवत्ता की जांच सभी कक्षाओं में होनी चाहिए ताकि हमारे यहां के विद्यार्थी आगे चलकर भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस बात के लिये आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी जो कल्पना है वह कांग्रेसी कल्पना से हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। इन्होंने तो राजीव गांधी स्कूलें खोलकर हमारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश किया।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं दो मिनट में कर रहा हूं।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं, आप एक मिनट में समाप्त करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हमारी मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी की जो सोच है, यह हमारे जैसलमेर और बाड़मेर की ढाणी के स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी अमरीका की लाइब्रेरी में, अमरीका के शानदार विश्वविद्यालय की किसी लाइब्रेरी में किस पुस्तक में क्या लिखा है, वह ढाणी में बैठा हुआ विद्यार्थी कम्प्यूटर और इण्टरनेट के माध्यम से वह प्राप्त कर सके, पढ़ सके। उसकी फोटो कापी ले सके, ऐसा सोचा है। न केवल सोचा बल्कि इसके लिये मुख्य मंत्रीजी ने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दावोस यात्रा हो या अन्य यात्रा हो, उसमें जो प्रयत्न किया है, वह आगे बढ़ाने के लिये जो काम किया है, जिसके माध्यम से जो काम चालू हुआ है कम्प्यूटर कई विद्यालयों में चालू हो गया है, इण्टरनेट की सुविधा हो गयी है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान के शैक्षिक जगत में सुन्दर विकास होने वाला है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जहां तहसील स्तर तक स्टेडियम निर्माण के बारे में और पंचायत स्तर तक खेल-मैदान के बारे में जो सोच है वह शानदार है। लेकिन हमारे, खासकर पश्चिमी राजस्थान में सभापति महोदय, आपने तो मेरे सामने उस समय मुख्य मंत्रीजी से मिलकर जैतारण में कॉलेज की मांग की, बजट में घोषणा करवा दी। पहले तो नहीं थी, लेकिन बाद में निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें एक भी कॉलेज नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप खण्ड मुख्यालय हैं, शिव उप खण्ड मुख्यालय है और फतेहगढ़ उप खण्ड मुख्यालय है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब लोग हैं। पिछली बार हमने प्राइवेट कॉलेज चालू किया था लेकिन चल नहीं पाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उप खण्ड मुख्यालय जहां भी है, वहां तो कम से कम सरकारी महाविद्यालय हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि सरकार ने तहसील स्तर तक कॉलेज खोलने के बारे में जो नीति की है, कॉलेज खोलना, उसके लिये बिल्डिंग बनाकर देना, वह बहुत शानदार काम है लेकिन मेरे इन दोनों क्षेत्रों में कॉलेज की बहुत जरुरत है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो मांगें हैं सरकार की शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में, मांग संख्या-24, उसके बारे में हमारी सरकार के काम के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, इस शिक्षा में सभी क्षेत्रों में...

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ब्लाक का, गांव का, सार्वजनिक शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, मेडिकल शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, सबसे

ज्यादा ध्यान रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यालय खोले जाएं उनमें कम से कम 10 प्रतिशत संस्कृत विद्यालय होने चाहिए।

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिये, प्लीज।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ताकि जो पूरी दुनिया में संस्कृत की मांग है, संस्कृत विश्वविद्यालय खोला है, उसके लिये भी मैटीरियल मिलना चाहिए, उसके लिये भी विद्यार्थी मिलने चाहिए। संस्कृत शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। मुझसे पहले जो-जो वक्ता बोले हैं, आज वह लगभग सब बहुत पढ़े-लिखे विद्वान वक्ता थे। मैं तो बहुत कम पढ़ा-लिखा हूं।

श्री सभापति: अब आप 10 मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हां, अनपढ़ व्यक्ति को 10 मिनट भी बहुत होते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं और इसलिये आंकड़ों का खेल मैं नहीं समझता हूं। आंकड़े इस सदन के पटल पर बहुत आ चुके पिछले 2 घण्टे में। इसलिये आंकड़ों की चर्चा मैं नहीं करता। मैं चर्चा करना चाहता हूं उस बात की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने किसी भाषण के दौरान इस सदन के सामने एक शेर के रूप में कही, दुष्यन्त का शेर है।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए।

बजट में प्रावधान बहुत कर दिया होगा, उन प्रावधानों का यूटिलाइजेशन भी हो गया होगा, खर्चा भी हो गया होगा। वह सब होने के बाद भी यदि ग्रास-रुट लेवल पर माहौल नहीं बदलता है तो सब कुछ बेकार है। मैं चाहूंगा कि मेरे को जो 10 मिनट आपने दिये, उन 10 मिनटों में मैं उस माहौल की चर्चा करुं जो 3 साल पहले था और 3 साल बाद है। 3 साल पहले क्या माहौल था। किसी भी स्कूल में जाएं, जहां गांव में बच्चे हैं वास्तव में पढ़ने को, वहां विद्यालय नहीं, विद्यालय है शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, भवन है तो बच्चे नहीं। इस प्रकार की एक विसंगति पूरे राजस्थान की धरती पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वह छाई हुई थी। उसके कारण ग्रामीण

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्षेत्र के लोग शिक्षा से वंचित थे। इस 12वीं विधान सभा के गठन के तुरन्त बाद एक प्रश्न हुआ था और उस प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रीजी की तरफ से बताया गया था कि बीकानेर शहर, जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं माननीय बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री थे, बीकानेर शहर में छात्र और शिक्षकों का रेशो क्या था, 9 छात्रों पर एक शिक्षक। बाकी राजस्थान के लिये क्राइटेरिया क्या लागू किया, पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के कार्यकाल में, क्राइटेरिया बदला गया, पहले था 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अशोक गहलोतजी की केबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, 60 पर एक होगा तो चलेगा। गांव में 60 पर एक होगा तो चलेगा लेकिन बीकानेर में 9 पर एक चाहिए। यह था माहौल। यह था आपका कार्यकाल। और उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग वंचित रह गये और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक वंचित रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। सभापति महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं, कल मुझे बहुत पीड़ा हुई। और मेरे जैसे और कई लोगों को पीड़ा हुई होगी। जिनको हम बहुत संजीदा नेता मानते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता मानते हैं, कभी उनके मान-सम्मान में हम कमी नहीं रखते, ऐसे माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कल एक टिप्पणी की। इस राजस्थान की धरती के 30 प्रतिशत लोगों को गाली दी। उन्होंने 2 मंत्रियों की तुलना की और सिर्फ जातिगत आधार पर तुलना की। सिर्फ इसलिए तुलना कर दी कि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सब क्यों हुआ है? मेवाड़ से तीन-तीन, चार-चार मुख्य मंत्री बन सकते हैं लेकिन 50 साल में आप एक आई.ए.एस. नहीं दे पाते, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोगों ने राज किया है। पहला आई.ए.एस. तीन साल पहले वहां से मुश्किल से निकला है। अब तो दो हो गये हैं। पूरे मेवाड़ से आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला आई.ए.एस. यदि बना तो हमारे शासन काल में बना। आप नहीं दे पाये। और उदाहरण देता हूं मैं। गत वर्ष के बोर्ड के रिजल्ट को उठाइये आप। 12वीं की कला का परिणाम, दो बच्चों ने टॉप किया उसको। एक साथ बराबर के नम्बर आये दोनों के। मुझे कहते हुए गर्व है और मैं उन प्रतिपक्ष के नेता महोदय की टिप्पणी के जवाब में सदन को यह सूचना दे रहा हूं, दोनों बच्चों में से एक बच्चा अनुसूचित जाति का था और दूसरा बच्चा अनुसूचित जनजाति का था। एक जाटव था और एक मीणा था। बोर्ड को टॉप किया, पूरे राजस्थान को और दूसरी गर्व की बात यह है कि वह दोनों

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बच्चे किसी पब्लिक स्कूल के नहीं थे। वे दोनों सरकारी विद्यालयों के थे। जिन सरकारी विद्यालयों की आपने हालत खराब करके रखी थी, जिन सरकारी विद्यालयों से गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को निकाल कर सुखी-दु:खी होकर भी जैसे-तैसे करके पब्लिक स्कूलों में भेज रहा था बच्चों को, उन सरकारी विद्यालयों का माहौल इतना बदला तीन साल के अन्दर कि उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बालक राजस्थान को टॉप करता है। परिस्थितियां बदल गयी हैं। स्थितियां बदल गयी हैं और अब इसलिए, आज जो स्कूटी वाला कल फोटो देखा हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक बच्ची के साथ, 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक मिले इसलिए उसको स्कूटी मिली है। अब 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों की बपौती नहीं रह गयी। अब एस.सी. और एस.टी. के हजारों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 75 प्रतिशत से ऊपर मार्किंग ला रहे हैं। नम्बर ला रहे हैं। 90 प्रतिशत तक जा रहे हैं। 95 प्रतिशत तक जा रहे हैं और मैं चाहूंगा इस पवित्र सदन के माध्यम से कि हमारी योग्यता के आधार पर हमारा मूल्यांकन करिये। हमारी जाति के आधार पर हमारा मूल्यांकन मत करिये। जाति के आधार पर इस तरह की फब्तियां कसना, अपमानित करने वाली टिप्पणियां करना बंद करिये। हमारी योग्यता को परखिये। यह जो माहौल बदला है, इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी है। यह जो समानीकरण करना पडा, 9 पर 1 शिक्षक, उनको हटा कर जहां आवश्यकता थी वहां भेजना पड़ा। नये शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ी। बहुत सारे शिक्षक भर्ती किये हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी भर्ती कम है। ठीक बात है और करेंगे। पर आपने तो पूरे पांच साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं किया। एक भी नहीं। जो भर्ती किये 1200 रुपये वाले राजीव गांधी पाठशाला के पैराटीचर्स, 1200 रुपये केवल मात्र उनको मिलेगा। इस जमाने में 1200 रुपये और उन 1200 रुपये के आगे उनकी कभी बढ़ोतरी होने की कोई उम्मीद नहीं थी हमको। उनको सपनों में भी उम्मीद नहीं थी कि हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। आपसे उन्होंने उम्मीद करी। आपने पूरी नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने उनको धैर्य से सुना और उनके मानदेय में बढ़ोतरी करी। उनको नियमित करने के लिए प्रयास किये लेकिन कोर्ट के निर्णय के आड़े आ गये। नहीं कर पाये उनको नियमित लेकिन एक को भी घर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नहीं भेजा। एक को भी हटाया नहीं, उनका मानदेय बढ़ाया। जीवन-यापन वे सम्मानपूर्वक कर सकें। सुविधापूर्वक कर सकें, ऐसी उनकी स्थिति बनायी। ऐसा ही एक वर्ग है। बीस तरह के उस समय शिक्षक चलते होंगे। उन सारी केटेगरीज को धीरे-धीरे समेटते-समेटते सबको समायोजित करते-करते केवल एक केटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी और हमारी सरकार, वह है शिक्षक। कोई पैरा टीचर, कोई शिक्षा-कर्मी, कोई ऐसा कर्मी, कोई वैसा कर्मी, सारा क्राइटेरिया खतम करते-करते सब को एक सम्मानजनक, एक शब्द देने का प्रयास, एक पद देने का प्रयास माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने किया है, उसके लिए निश्चित रूप से उनका जितना सम्मान और जितनी तारीफ की जाए, उतना कम है।

मैं चर्चा कर रहा था शिक्षा-कर्मियों की। शिक्षा-कर्मी योजना 1984 में लागू हुई। 1947 से लेकर 59 साल हो रहे हैं देश को आजाद हुए। इन 59 सालों में 59 तरह की योजनाएं लागू हुई होंगी देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए। अब मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मैंने पहले ही यह कह दिया लेकिन जितना भी मैं जानता हूं, इस शिक्षा जगत के बारे में और 17 साल से मैं राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हूं। जितना कुछ मैंने समझा है, मेरी नजर में शिक्षा-कर्मी योजना देश की पहली योजना थी जो वास्तव में सफल हुई और ठेठ धरती तक जाकर उसने शिक्षा का माहौल बदला। गांव का बालक 8वीं पास है, चाहे 10वीं पास है, चाहे 12वीं पास है, गांव के लड़के को ही गांव का स्कूल चलाने के लिए लगा दिया। अलग तरह से उसका प्रशिक्षण, अलग तरह का उसका माहौल दिया गया। अलग तरह की एक संस्कृति डवलप की गयी। उन शिक्षा-कर्मियों ने उस गांव का माहौल बदल कर रख दिया। वहां शिक्षक टिकता नहीं था वह जमकर रहे और जमकर रहकर वहां का माहौल बदला और वह एम.ए., बी.एड., बी.ए., बी.एड., उच्च योग्यताधारी जो लोग स्कूलें चलाते थे इनके मुकाबले में उनसे बेहतर स्कूल चलाकर उन्हें बताया। इन शिक्षा-कर्मियों का जो प्रोजेक्ट था, विदेशी सहायता से प्रोजेक्ट था, पांच साल चला, दस साल चला, जैसे-तैसे करके पांच साल और चलाया, आखिर में वह प्रोजेक्ट पूरा करने की नौबत आयी। 30 जून, 2005 को वह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, यह तय हो गया। कोई विदेशी सहयोग उसके लिए नहीं मिलेगी इसलिए उस प्रोजेक्ट को बंद करना ही पड़ेगा। यह स्थिति आयी। शिक्षा-कर्मी बोर्ड भंग होगा और उनकी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नौकरियों का क्या होगा, कोई आशाजनक स्थिति नहीं थी। उस परिस्थिति में वह आठ हजार शिक्षक माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिले, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम सब विधायकों ने उनको समर्थन दिया। हम सब विधायक मिलकर मुख्य मंत्रीजी से मिले। शिक्षा मंत्रीजी से मिले। परिणाम निकला, संवेदनशील सरकार का नमूना यह होता है, परिणाम यह निकला कि शिक्षा-कर्मी बोर्ड वह तो भंग हो गया, 30 जून, 2005 को शिक्षा-कर्मी बोर्ड भंग होता है और 01 जुलाई, 2005 को दूसरा शिक्षा-कर्मी बोर्ड गठित होता है। केवल इसलिए कि वह 15-15 साल, जिन लोगों ने काम कर लिया, अब उनकी 40 और 45 की उम्र उन नौजवानों की हो गयी। अब वह नया रोजगार कहां ढूंढने जाएंगे? क्या रोजगार का साधन ढूंढेंगे वह? उनको, उनकी सेवाओं को बरकरार रखने के लिए और उनकी योग्यता का सदुपयोग राज्य हित में, जनता के हित में करते रहने के लिए नया शिक्षा-कर्मी बोर्ड गठित किया गया। उसके माध्यम से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया।

मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि आप लोगों ने उनके प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया और उनको कंटिन्यू किया लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उनको कंटिन्यू तो कर लिया, उनकी नौकरी तो नहीं जाने दी, केवल इतना ही नहीं उनको एक और बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया। 2004 और 2005 में, 1984 से जो परियोजना शुरू हुई थी, 2003 तक उस परियोजना में से केवल 143 व्यक्तियों को वरिष्ठता प्रदान की गयी थी। नियम थे लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। 2004 में जाकर पहली बार हमने 545 लोगों को वरिष्ठता प्रदान की और 2005 में लगभग 4000 और शिक्षा-कर्मियों को वरिष्ठता प्रदान की। उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर। क्राइटेरिया सिर्फ इतना था कि यदि 8वीं पास व्यक्ति है तो 10 साल की सर्विस पर उसको वरिष्ठ माना जाए और 10वीं पास या ऊपर का है तो 8 साल की सर्विस पर उसको, 8 साल के अनुभव के आधार पर उसको वरिष्ठ मान लिया जाए। उस क्राइटेरिया को पिछली सरकारों ने लागू नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में कनक्लूड कर दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने पहल की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिए बजट प्रोविजन किया और ऐसे लगभग 4500 लोगों को हमने वरिष्ठता प्रदान की। केवल 1700 लोग ऐसे बच गये जो उस क्राइटेरिया में उस समय तक नहीं आ रहे थे इसलिए वरिष्ठ नहीं हो पाये।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे आसन के माध्यम से और सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत उदारता दिखाई है। अब वह 1700 लोग बचे हैं, वह भी उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। दस साल की सर्विस सब की हो गयी। दस साल का अनुभव सब को हो गया। शिक्षाकर्मी के हिसाब से जो उनका प्रशिक्षण होना चाहिये, वह सारा हो गया। अब उनको वरिष्ठता देने की बारी है। आप उनको वरिष्ठता देने के बारे में निश्चित रूप से सोच रहे हैं, मुझे पता है लेकिन उसमें एक अड़ंगा लग रहा है। अधिकारी उसमें आपको एक सुझाव दे रहे हैं, मुझे भनक लगी है कि जो एस.टी.सी., बी.एड. किये हुए हैं, उनको वरिष्ठता दे दो। जिन साढ़े चार हजार लोगों को वरिष्ठता दे दी, उन पर एस.टी.सी., बी.एड. का प्रतिबन्ध नहीं था। एस.टी.सी., बी.एड. की शर्त नहीं थी, उन पर शर्त थी दस साल का अनुभव आठवीं पास है तो और दसवीं पास है तो आठ साल का अनुभव। जैसा इन साढ़े चार हजार लोगों के साथ किया है, कृपया इन 1700 के साथ वही व्यवहार किया जावे। 30 जून, 2005 को जो नियम इन लोगों के लिये लागू थे, उन्हीं नियमों को वापस बहाल किया जाये। डेढ़-पौने दो साल से वह नियम लम्बित पड़े हैं। इनको जो-जो भी सुविधाएं मिल रही थीं, वह सब हमने निलम्बित कर दीं और उन सब को वापस बहाल करने की आवश्यकता है। उनको मंहगाई भत्ता मिलता था। सरकारी कर्मचारियों और अन्य शिक्षकों के साथ-साथ उनका मंहगाई भत्ता अपने आप बढ़ता था, वह बंद हो गया, उनको जो चिकित्सा अवकाश मिलते थे, वह बंद हो गये, उनको जो आकस्मिक अवकाश मिलते थे, वह बंद हो गये, उनको चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण मिलता था, वह बंद हो गया, उनकी परीक्षा फीस यदि वह आगे की परीक्षा देना चाहे कोई तो परीक्षा फीस का उनको रिअम्बर्समैंट होता था, वह बंद हो गया और परीक्षा के लिये उनको जो पाठ्य-पुस्तकें चाहिये, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिये, उन पुस्तकों के मूल्य का भी पुनर्भरण होता था, वह बंद हो गया। इस तरह की जो सुविधाएं उनको 30 जून, 2005 तक दे रखी थीं, 01 जुलाई, 2005 को आपने शिक्षाकर्मी बोर्ड तो बना लिया, उनकी नौकरी तो बचा ली आपने, बहुत बड़ा अहसान कर दिया। लेकिन वो जो सुविधाएं थीं, वह सारी चीज उनके साथ समाप्त हो गयीं। 01

जुलाई, 2005 को वह नये बोर्ड में एज इट इज लागू नहीं रहीं। मेरा आपसे निवेदन है उन गरीबों की तरफ ध्यान दें आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही एक अनूठा प्रोजेक्ट मेरे जालौर में चल रहा है वह है 'महिला शिक्षण विहार' । 'महिला शिक्षण विहार' एक जालौर में है, एक झालावाड़ में है और तीसरा पिछले बजट में चूरू में खोलने की घोषणा हुई थी राजेन्द्रजी राठौड़ साहब के क्षेत्र में, उसको मैंने देखा नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वह चालू हुआ कि नहीं, पता नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बीच वालों का भी ध्यान रखना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): लेकिन जालौर का जो महिला शिक्षण विहार है।

श्री सभापति: अब समय की सीमा है। माननीय सदस्यों ने तय किया है दस मिनट का, आपको पन्द्रह मिनट से ज्यादा हो गये हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, कि आप बिराजें प्लीज।

एक माननीय सदस्य: मान जाओ सभापति महोदय की बात।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जैसे आप बहुत मानते हैं।

श्री सभापति: अब आप बैठें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): दो-चार मिनट और।

श्री सभापति: दो-चार मिनट नहीं, अगर आपको कनक्लूड करना है तो एक मिनट में कर दीजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उस महिला शिक्षण विहार को लोक जुम्बिश परियोजना के तहत शुरू किया गया था। वह परियोजना समाप्त हो गयी। परियोजना समाप्त होने के साथ उस विभाग को साक्षरता विभाग को सौंप दिया गया उस संस्थान को। उस परियोजना की जो स्प्रिट थी, परियोजना की जो भावना थी, परियोजना की जो कार्यशैली थी, वह कार्यशैली इतनी उततम थी कि उस महिला शिक्षण विहार के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं का जीवन सुधर गया, उनका जीवन संवर गया। लेकिन अब पिछले डेढ़ साल से जो मैं देख रहा हूं, वह परियोजना वाली स्प्रिट, परियोजना वाली स्पीड,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

परियोजना वाली फीलिंग, परियोजना वाला सेंसेशन अब नहीं रह गया है, वह भावना तिरोहित हो रही है । उसी भावना से उनको चलाने की आवश्यकता है और इसलिए में मेरा एक सुझाव है, जैसे आपने नवोदय विद्यालय चला रखे हैं, भारत सरकार की योजना है, नवोदय विद्यालय के संचालन के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आपने कमेटियां बना रखी हैं और वह कमेटियां उसके बारे में पूरी स्वायत्तता से निर्णय करती है, उसकी देखभाल करती है, केवल बजट सरकार देती है। ठीक उसी स्टाइल में इन महिला शिक्षण विहारों की यदि व्यवस्था की जाये कलक्टर की अध्यक्षता में या जिस डिवीजन में वह है ...

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक कमेटी का गठन किया जाये। उसमें जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये और उसकी व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मेरा अंत में एक निवेदन है। आपने वेद विद्यालय खोलकर बहुत अहसान किया है राजस्थान की जनता पर। वेद विद्या को प्रोत्साहन देने का आपका जो प्रयास है, उसका स्वागत है। मेरा निवेदन है कि जालौर शहर में एक वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय आप खोलें और जालौर कालेज में एक हिन्दी का विषय खोलने की आवश्यकता है। लैक्चरर उपलब्ध हैं, कमरे उपलब्ध हैं, विद्यार्थी उपलब्ध हैं, कोई नया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया बजट देने की आवश्यकता नहीं है। तुरन्त अगले सत्र से शुरू हो सकता है। उसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से, कि यह आलोचनाएं होती रहेंगी पर तीन साल में आपने काम का जो रिकार्ड बनाया है, जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किये हैं, उस रास्ते पर आप चलते रहिये, उससे डिगने की आवश्यकता नहीं है। मैं शेर के रूप में अर्ज कर रहा हूं-

मोमजामा पहन कर निकला न कर, मोम के कपड़े, नाजुक,
मोमजामा पहन कर निकला न कर,
धूप हो या चांदनी, पिघला न कर,

आंधियां, तूफान हो या बिजलियां
डर के मारे रास्ते बदला न कर।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामप्रताप कासनिया, आप दस मिनट में पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा चल रही थी दाईं साइड से कि पहला वक्ता है तो बीच में से मैं भी पहला वक्ता हूं। थोड़ा मेरे पर भी रहम करना। सभापति महोदय, मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला और संस्कृति, आप मेरे गुरु मत बनो, एक बार चेले ही रहो।

श्री सभापतिः आप मुद्दे की बात पर आ जाओ। आप फालतू की बातों में मत फंसो।

श्री रामप्रताप कासनिया : फालतू की बात कर ही नहीं रहा । सभापति महोदय, सही बात यह है कि शिक्षा के मामले में जितना काम माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इन तीन वर्षों में किये हैं, इसकी तारीफ किन शब्दों में करूं, वह शब्द नहीं हैं और सभापति महोदय, सरकार में मंत्री भी बहुत हैं, पर यह मंत्री अपने आप में दक्ष हैं। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हर विषय पर इनकी पकड़ है और इसका प्रमाण केन्द्र सरकार ने स्वयं दे दिया। इससे ज्यादा और तारीफ करने की कोई बात नहीं हो सकती। जमीन से जुडी हुई हर बात को समझते हैं। सभापति महोदय, इससे पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कई गांव के लोगों ने आन्दोलन करके मुफ्त में पुस्तकें मांगने का कोई काम नहीं किया, कोई मांग गांवों में नहीं आयी। यह भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ थी कि गांवों में बैठा गरीब का बच्चा पुस्तकों के अभाव में अनपढ़ नहीं रह जाये और अब तो कमाल ही कर दिया । मेरे से पूर्व वक्ता ने स्कूटी, साइकिल की बात की, मैं सारी बात रिपीट करूंगा तो उचित नहीं होगा। मोटे रूप में अगर कमी है तो उस कमी के बारे में मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अध्यापकों की भर्ती भी आपने खूब की है। फिर भी मेरी दाईं साइड में बैठे लोग आलोचना करते हैं कि आपने भर्ती कम की है। सभापति महोदय, छाजला तो बोले जो बोले छलनी भी बोले जिसने एक भी भर्ती नहीं की। आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेहबान में झांककर देखना

(श्री रामप्रताप कासनिया)

चाहिये। शीशे के अंदर अपना चेहरा देखकर आरोप लगाना चाहिये। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदय से मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने वाकई में शिक्षा में सुधार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी की है तो मोनिटरिंग की । मोटे रूप में आप नियमों में कोई ऐसा प्रावधान कीजिये जिससे गांव का सरपंच हो सरपंच तो बहुत नीचा है पर कम से कम एम.पी. और एम.एल.ए. को यह छूट होनी चाहिए कि स्कूल के अन्दर जो अध्यापक गैरहाजिर हो उसकी गैरहाजिरी लगाने का या कोई नोट करने का रजिस्टर में, कोई पावर हो तो अध्यापकों के मन में भय रहेगा। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जन प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी.जे.पी. का हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी जन प्रतिनिधि शिक्षा के मामले में भेदभाव नहीं करेगा और अपने क्षेत्र के प्रति वो जागरूक रहेगा और विद्यालयों की सार-सम्भाल भी करेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो विद्यालय हैं उनमें बिजली के कनेक्शन नहीं हैं तो अगर जिन विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, अब पैसा तो खूब है, यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है और आप व्यवस्था कर भी सकते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उनमें बिजली के कनेक्शन कराने का काम करें। शौचालय आपने बना दिये, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी। सब-कुछ ठीक कर दिया।

दूसरा, सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो विडम्बना है वो यह है कि मानीटरिंग नहीं होने के कारण से जैसे एक स्कूल के अन्दर पांच अध्यापक हैं वो आपस में समझौता कर लेते हैं और कोई एक अध्यापक दस दिन के लिए अपने गांव या जहां कहीं भी जाना चाहता है, जाते वक्त एक प्रार्थना पत्र छुट्टी का लिख कर चला जाता है और अगर पीछे से कोई जांच करने वाला आ गया तब तो वह प्रार्थना पत्र यूज कर लिया जायेगा, जो व्यक्ति उस चारदीवारी के अन्दर स्कूल में घुसेगा उससे पहले ही उसकी छुट्टी दर्ज कर दी जायेगी और अगर कोई पीछे से नहीं आया तो, सभापति महोदय, बिलकुल प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आंखों देखी हुई बात बता रहा हूं, उसको ऐसे फाड़ कर के और एप्लीकेशन को डाल देते हैं और हाजिरी लगा लेते हैं। तो यह जो त्रुटि है इसमें सुधार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न लगाया था, विशेषकर के रिक्त पदों के बारे में

तो सबसे ज्यादा रिक्त पद हैं तो वो सूरतगढ़ पंचायत समिति में, यानी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं और माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन भी दिया था कि यह जो रिक्त पद हैं वो जल्दी भर दिये जायेंगे। सभापति महोदय, अभी तक वो पद नहीं भरे गये।

सभापति महोदय, इसके अलावा 6–7 स्कूल ऐसे हैं जो जिला और पंचायत समिति गलत अंकित होने के कारण पूरा वित्तीय वर्ष निकल गया है, अब तो निकलने वाला है, कोई थोड़े ही दिन शेष बचे हैं।

एक माननीय सदस्य: साल, डेढ़ साल और है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अभी डेढ़ साल किस के हैं, किस के नहीं हैं वो तो ऊपर वाला ही जाने, मेरे को तो इस बात का पता नहीं है।

श्री सभापति: अब आप प्लीज समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं बड़े पते की मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: तो आप एक मिनट में कनक्लूड कीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): एक मिनट में, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, मेरे कहने का भावार्थ है कि 6-7 स्कूल तो चले गये शिक्षाकर्मी में वो नहीं हुए और 7-8 स्कूल सिर्फ पंचायत समिति और जिला गलत अंकित होने के कारण से, यह स्टॉफ की गलती है कोई मंत्री महोदय की दुर्भावना नहीं है, इस बात को भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इन्होंने स्कूल जरूर खोले पर मेरे क्षेत्र के अन्दर 14-15 विद्यालयों का मुझे लोस हुआ है क्रमोन्नत होने में, उसकी पूर्ति की जाए और यह बड़े-बड़े गांव अभी मिडल स्कूल से वंचित हैं।

सभापति महोदय, यहां पर यह भी बात कही कि दो विद्यालय के बीच में एक मिडल स्कूल होगा तो यह भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र जो है उसमें भिन्नता है। दो प्राथमिक पाठशालाओं के बीच में एक मिडल स्कूल कई जगह अभी तक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं पुन: मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का सुधार करने के लिए एक तो हर बार यह समानीकरण वाली जो बात चलती है यह बड़ी बेइमानी की बात है। चाहे सरकार यह रही है चाहे वह रही है, समानीकरण नहीं हुआ है। आज तक किसी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

भी शिक्षा मंत्री ने हिम्मत नहीं की कि जो तीस-तीस वर्षों से एक ही शहर में बैठे हैं, मेरे से पूर्व वक्ता उदाहरण दे रहे थे कल्लाजी का, कल्लाजी का क्यों नाम लूं, पूरे राजस्थान में यही हालत है। शहरों के अन्दर बच्चे 9 हैं टीचर पांच हैं और गांव में बच्चे 200 हैं।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें। माननीय श्री रामचन्द्रजी सराधना।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): और यह जो समानीकरण वाली बात है इसको समाप्त करें। पुन: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान में जो रिक्त पद हैं, आपने विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये, वो रिक्त पद शीघ्र, अतिशीघ्र भरे जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षा के अन्दर उपलब्धि हासिल कर सकें।

सभापति महोदय, यहां बात चल रही थी कि भवन रहित कोई विद्यालय नहीं है, नहीं है, मेरे को भी पता है पर मेरे क्षेत्र में बड़ोपळ गांव है जहां सीनियर माध्यमिक विद्यालय है और भवन था, सेम के कारण से भवन पूर्णत: नष्ट हो गया। मैंने पर्ची के माध्यम से यह विषय उठाया और सरकार की तरफ से उस दिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी नहीं थे, गुलाबचन्दजी कटारिया, माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि आपका कथन बिलकुल सही है, बड़ोपळ गांव के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. का जो एस्टीमेट आया है वो तो बहुत बड़ा है, डेढ़ करोड़ रुपये का, इतना पैसा तो सरकार नहीं दे सकती पर काम चलाऊ भवन चालू वित्तीय वर्ष में बना दिया जायेगा।

सभापति महोदय, अनपढ़ हूं, नियमों का ज्ञान नहीं होगा पर इतना ज्ञान है कि इस साइड में बैठने वाला सरकार का कोई भी मंत्री अपने श्रीमुख से जो बात कहे वो बात पूरी होती है पर मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि पर्ची के माध्यम से जो मुझे उत्तर मिला उसकी पूर्ति नहीं हुई पर मैंने भी कोई कंजूसी नहीं की है, मैंने मेरे कोटे से पांच लाख रुपये तो उस गांव में दिये हैं भवन बनाने के लिए, शेष मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकार सीनियर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर भवन बनाने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 लाख रुपये तो उपलब्ध करवाओ ताकि पेड़ों के नीचे बैठे हैं।...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं अभी और सुझाव देना चाहूंगा कि अभी इसी चालू वित्तीय वर्ष में आपने मिडल स्कूल खोले, उन मिडल स्कूलों में

मैं बहुत खुश हुआ पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र में शिक्षाकर्मी स्कूल ज्यादा हैं। शिक्षाकर्मी स्कूल होने के कारण से आपने जो क्रमोन्नत किये विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों को मिडल में वो क्रमोन्नत नहीं हो पाये और इसके साथ-साथ मैं एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 1995 के अन्दर शिक्षाकर्मी योजना के अन्दर राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है और उसमें रत्तासर गांव, गांव कई हैं, मैं सारे गांवों की लिस्ट तो नहीं बताऊंगा पर कक्षा 6 से 8 तक की अलग कक्षाएं, 1995 में राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है। सभापति महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने राज्य सरकार की लिस्ट देख कर के और कह दिया कि आपके गांव में मिडल स्कूल क्रमोन्नत हो गये और आज हालत यह है कि उन गांवों में हम जाकर के कुछ बोलने लायक नहीं हैं। तो आपकी तो कलम में बहुत ताकत है, सभापति महोदय, वो 1995 का आदेश या जो भी व्यवस्था करनी है, नियम बनाना सरकार का काम है, जहां कोई अड़चन आ रही है वहां चीरा लगाओ और इसमें कोई प्रावधान करो, अगर कोई रोक लगी है तो 1995 के बाद लगी है, पहले नहीं थी।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, मान्य हो नहीं हो अलग बात है, यह पौध और पन्जीरी जिस तरह बढ़ रही है इसकी आप चाहे कितनी ही व्यवस्था कर लो, कुछ भी कर लो इस पर रोक लगाने का जैसे पंचायतों में दो बच्चों से ज्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, आप गरीब के बच्चे को जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है उसको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाओ। तब तक उसका पूरा आने जाने का और सारा खर्चा सरकार वहन करे। तो लोग आकर्षित होंगे, गरीब लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। नहीं तो सभापति महोदय, एक-एक झौंपड़ी में ग्यारह-ग्यारह नग निकलते हैं मेरे जैसे तो आप इसका इंतजाम कर नहीं पाओगे मेरा यह निवेदन है सरकार से।

श्री सभापति: माननीय रामचन्द्र सराधना।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर एक तो सभापति महोदय, गड़बड़ हो गयी, यह पहले वक्ता डेढ़-डेढ़ घण्टे, दो-दो घण्टे बोल गये, हम भी बीच में से पहले वक्ता हैं ...(व्यवधान) भविष्य में आसन से यह उम्मीद नहीं रहेगी।

श्री सभापति: आसन से आप अच्छी उम्मीद किया करो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरा सारा समय रामप्रतापजी कासनियां साहब को दे दिया जाए।

एक माननीय सदस्य: अब क्या फायदा?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा, कला और संस्कृति के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और राष्ट्र को, प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है। लेकिन अब शिक्षित किसको समझा जाए, अभी तो हम साक्षरता के बराबर आने में संघर्ष कर रहे हैं। साक्षरता का हमारा रेश्यो बढ़ रहा है और 2001 में 60.41 प्रतिशत हमारा साक्षरता का ग्राफ गया है। इसलिए साक्षरता के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षाकर्मी और साक्षरता के बारे में राजस्थान प्रदेश को कन्फ्यूशियस अवार्ड मिला है, यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड मिला है। हमें खुशी हुई इस बात की कि राजस्थान प्रदेश को मिला है और यह भी एक चांस है कि माननीय घनश्यामजी शिक्षा मंत्री हैं और उनको ग्रहण करने का अवसर मिला।

लेकिन यह जो स्तर बना यह कोई एक दिन में नहीं बन गया। यह कोई दो महीने या दो वर्ष या तीन वर्ष में नहीं बना। राजस्थान प्रदेश में शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ा है उसी के आसार हैं कि हमें यह अवार्ड मिला। माननीय सभापतिजी, इस साक्षरता के ग्राफ को बढ़ाने में यह कोई विवाद का विषय नहीं है इससे पहले अशोकजी गहलोत की सरकार थी और उस सरकार से पहले सतत शिक्षा, शिक्षाकर्मी, अनौपचारिक शिक्षा बहुत सारी योजनाएं चल रही थीं और सब का एक ही उद्देश्य था कि साक्षरता बढ़े, शिक्षित लोग ज्यादा बढ़ें। लेकिन उन सब को रोककर के अशोकजी गहलोत की सरकार में राजीव गांधी पाठशाला के नाम से एक कंसेप्ट आया। बहुत सारे साथियों को नहीं जंचता है, केवल उसका एक ही कारण है कि उसके साथ राजीव गांधीजी का नाम था, उससे लोगों को एलर्जी है अन्यथा वह कंसेप्ट इतना बढ़िया था, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा बिल्डिंग पहले बनी हो स्कूल बाद में खुला हो। पहले स्कूलें चलती थीं कहीं तिबारे में, कहीं झौंपड़ी में, कहीं और किसी के मकान में। तीन-चार वर्ष बाद में जाकर के विद्यालय भवन बनते थे। लेकिन पहले वह एक विचार बना कि पहले स्कूल की बिल्डिंग और राजीव गांधी पाठशाला चालू

हो। बहुत सारी कमियां थीं, बारह सौ रुपये मानदेय में उस सरकार ने शिक्षा सहयोगी रखे थे, उस समय की परिस्थितियां थीं लेकिन उन्होंने शिक्षा की साक्षरता बढ़ाने में राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप रेस्पेक्टेड गुरु रहे हुए हो, कोई सुझाव हो तो वह दें, रिपीटेशन करने से तो कोई मतलब नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यापक मेरे समान थे इसमें बहुत सुधार कर दिया यह राजीव गांधी पाठशाला में तो मेरे जैसे अध्यापक थे।

श्री सभापतिः इस शिक्षा में क्या परिवर्तन किया जाए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापतिजी, मैं धीरे-धीरे आना चाहता हूं।

श्री सभापतिः नहीं, धीरे-धीरे नहीं। दस मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको मैं कह देता हूं आपको जो सुझाव देने हैं सुझाव दीजिए आप।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): नहीं, आपका समय बच रहा हो और कोई बहुत बड़े काम में उपलब्धि मिल रही हो तो मैं तो बैठ जाऊंगा। नहीं, ऐसे मत करो पहले ही मैं तो आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री सभापतिः पूरा संरक्षण है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपके आसन पर विराजने के बाद मैंने सोचा अब तो मेरा बीस मिनट चल जाएगा, और ही काम बहुत हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था शिक्षा मंत्रीजी की बहुत बड़ी इच्छा है, कोई भी सरकार जब आती है तो यह नहीं चाहती कि मैं बुरा काम करूं। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके भी छटपटाहट है। उनके फेस की रिंकल्स को देखकर मैं महसूस करता हूं कि वह कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है, हो सकता है वित्त मंत्रालय उनका साथ नहीं दे रहा हो। उन्होंने परिवर्तन तो किये हैं राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में बदला, राजीव गांधी शिक्षा संकुल को राधाकृष्णनजी के नाम पर बदला, महात्मा गांधी आदर्श गांव को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बदला और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया, इनकी भावना दृढ़ थी। पांच हजार प्राथमिक विद्यालयों को अपर प्राइमरी में लिया, बहुत सारे सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनाये।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

लेकिन सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने तीन वर्ष में सैंतीस हजार स्कूलों को क्रमोन्नत किया या नई स्कूलें खोलीं और इन तीन वर्षो में अध्यापक लगाये मात्र छत्तीस हजार चौंसठ अध्यापक लगाये और उनकी भी स्थिति यह है कि प्राइमरी एजूकेशन की बात करना चाहता हूं। कुल स्वीकृत पद थे 2,53,415 और कार्यरत रहे 1,69,702, खाली पड़े रह गये 83713 पद, 83713 पद में 66789 पद रहे सर्व शिक्षा अभियान के इन्होंने किये पूरे उसमें, अभी आप कर रहे हैं कि 29028 पद आर.पी.एस.सी. को दिये। वह भी केवल मात्र 'सर्व शिक्षा अभियान' के हैं लेकिन इनको निकालने के बाद बचते हैं 51,460 खाली पद। वह प्लान और नोन प्लान के हैं। योजना, योजना भिन्न के हैं और उनके बारे में शिक्षा मंत्रीजी या राजस्थान की सरकार यह नहीं विचार करना चाहती और यह नहीं बताना चाहती अपने बजट में कि वह आयोजना भिन्न के और आयोजना मद के टीचर्स के जो खाली पद हैं उनको कौन भरेगा और कब भरेंगे।

मान्यवर, 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत प्राथमिक शिक्षा के साथ अन्याय किया गया, उनके नाम से टीचर्स की भर्ती की गयी और जो हायर एजूकेशन वाले टीचर्स थे उनको सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में पढ़ाने के लिए भेज दिया। यह क्या इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ? नींव को कमजोर रखने के लिए एक सोची समझी चाल थी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सोची समझी चाल के तहत इसलिए रखा गया कि उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर लगाये गये थे वह सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी में भरे गये क्योंकि इनके पास सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी के लिए टीचर्स नहीं थे। अपना बजट काम में नहीं ले सकते थे। केवल मात्र खजाना भरा दिखाना चाहते थे। जब खजाना भरा हुआ था तो आपने नियुक्ति क्यों नहीं की?

माननीय सभापतिजी, अब मिड डे मील की बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि मिड डे मील तो शिक्षा में है ही नहीं लेकिन इससे प्रभावित होती है शिक्षा। आज गांव में जाकर के देखेंगे बहुत बुरी दुर्गति है। माननीय सभापतिजी, आप भी जाते हैं, हमारे माननीय सदस्य सब अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, प्राइमरी एजूकेशन का यदि किसी ने सत्यानाश किया तो मिड डे मील ने किया और मिड डे मील की क्रियान्विति ने किया। मिड डे मील एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, बहुत बड़ा विचार था कि न्यूट्रीशन देने के

लिए जो गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं उनको कुछ न कुछ खाने का पोषण अच्छा मिलेगा लेकिन इसकी क्रियान्विति देखिये, घूघरी देकर के चला दिया करते थे लेकिन हमारे यहां मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा विचार दिया इनको लापसी खिलाओ, इनको चावल-चपाती खिलाओ, दाल-बाटी खिलाओ, जाने क्या-क्या खिलाओ। आप सुबह जाकर एक स्कूल को देखोगे तो उस स्कूल में मालूम पड़ेगा कि जैसे यहां कोई गोठ हो रही है या कोई पिकनिक में आये हुए हैं। बच्चे सुबह से देखने लग जाते हैं जब उसमें धुंआ उठने लग जाती है कि आज दाल बाटी चूरमा है, मास्टरजी भी कहते हैं कि देखो पकी कि नहीं, जल तो नहीं जाएगी। हालत बहुत खराब है। यह कटोरा जो बच्चों के हाथ में दिया है आज नहीं तो बाद में हम याद करेंगे इन बातों को कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ हमने क्या अन्याय किया है। उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा है और घर वाले भी अनपढ़ हैं, समझ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को करेक्ट कर दूं ...(व्यवधान) कि वहां न तो कोई मिड डे मील बनाता है वहां मिड डे मील बनाने के लिए अलग से व्यवस्था है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): घूघरी खिलाना गरीब बच्चों के लिए अभिशाप था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):...(व्यवधान) जो महिलाएं हैं वह मिड डे मील बनाती हैं और मिड डे मील के किचन अलग बना दिये सभी स्कूलों में और आप कह रहे हो धुंआ उठ रहा है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप लोगों ने जो घूघरी खिलाई और वह भी कच्ची घूघरी खिलाई और उनके दस्त लग गये और उनके पेट खराब कर दिये आपने।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): जी नहीं, आपको ध्यान हो तो हमारी जो संस्कृति थी ...(व्यवधान) पूरी तरह से वैज्ञानिक थी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बच्चों को दस्त लग गयी ...(व्यवधान) सरकार को लग गयी ।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): और घूघरी शादियों के बाद भी बंटा करती थी और पौष्टिक हुआ करती थी, यह जो खाना हम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पोष्टिक है घूघरी देना। हमने भी खाई हुई है ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): रोज-रोज खाने से पेट दुखता है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्या, वह तो कभी-कभी शादियों में ही खाई जाती है घूघरी। आज दिन तक कोई घूघरी डेली नहीं खाते हैं और आपने तो बच्चों को लगातार घूघरी खिलाकर के बीमार किया और आप कैसी बात कर रहे हो?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): रोज-रोज घूघरी नहीं खाते हैं।

श्री सभापति: आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं ? आप बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह क्या आप अपने राज्य सरकार के फण्ड से खिला रहे हो ? केन्द्र का पैसा आया है। केन्द्र का पैसा है इसमें काहे को आप इतने उल्लासित हो रहे हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, तो राज्य सरकार का भी फण्ड है। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं ना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पैसा केन्द्र का और आपने कहा घूघरी के बजाय हमने दूसरी बना दी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह आपका ही है लेकिन इसमें परिवर्तन किया है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): घूघरी से बच्चों की आंत बंद हो गयी थी। कई बच्चों के आपरेशन कराने पड़े थे घूघरी से।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे विचारों से सभी सहमत हों ऐसा नहीं है। अब मैं अपने विचार रख रहा हूं और न मैं आपको यह प्रेरित कर रहा हूं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, कि आप मेरी बात का प्रतिकार करें। आप मेहरबानी करके बैठे रहें। आप राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आपके विचारों की जरूरत नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं करेक्ट कर रहा हूं। आपका प्रतिकार नहीं कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं निवेदन यह करना चाहता था कि इसकी जगह यदि आप कोई पैकिंग में देना चाहे उसमें नमकीन बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, भीगा हुआ चना, भीगा हुआ मूंग आप पैकेट के रूप में दें तो न तो आपको रसोई की जरूरत है, न आपको धुंआ उठाने की जरूरत है और बच्चों को जाते वक्त उसके हाथ में देकर दस मिनट बैठाकर खाना खिला दें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा। कभी मौका लगे आपको। सौभाग्य से कभी जाकर देखना इंटरवेल के बाद में बच्चे नहीं मिलेंगे आपको जो खाना खाने के नाम से केवल आते हैं और चले जाते हैं। अपने कटोरे में दो बाटी और डाल जाते हैं। घर वाले भी खुश हो जाते हैं। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। यह कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं हो रही है। यह प्राइमरी स्कूलों का जो सत्यानाश हो रहा है इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे एक बात और कह रहा था अभी केन्द्रीय सरकार ने कहा कि अब इसको अपर प्राइमरी पर हम लेकर जायेंगे। मिड डे मील को वहां तक भी देना चाहेंगे लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गयी और गड़बड़ की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इशारा किया कि हम इस पक्षपात को सहन नहीं करेंगे और पक्षपात यह था कि उन्होंने यह कहा कि जहां पर शैक्षणिक गतिविधियां कमजोर हैं, जहां शैक्षणिक स्तर कम है उन ब्लाक में हम शुरूआत करेंगे। यह उन्होंने कहा था लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने उसको सहन नहीं किया और यह पक्षपात दूर करने के लिये उन्होंने घोषणा कर दी कि बाकी बचे हुए ब्लाक्स हैं हम राजस्थान सरकार उसको देगी। क्योंकि पक्षपात आप सहन करते ही नहीं। मुझे मालूम है इस बात का तो क्योंकि पक्षपात को इसलिये सहन नहीं करते..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: 12-13 मिनट हो गये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप बजाते हो मैं तो उकचूक हो जाता हूं। मान्यवर, एक-एक घण्टा बोलकर गये हैं। आप मेहरबानी करें। मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): राजस्थान की सरकार ने एस.टी. की बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिये तीन सौ रुपये में साईकिल दी। बढ़िया किया। हम खुश हैं। देना चाहिये था। आपको बधाई देते हैं लेकिन एस.सी. की लड़कियों ने क्या अन्याय कर दिया था। एस.सी. की लड़कियों को

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भी दे देते। ओ.बी.सी. की लड़कियों को भी दे देते। कहां फर्क पड़ रहा था ? खजाना तो भरा हुआ ही था। इतना अन्याय क्यों कर दिया ?

केन्द्रीय सरकार ने एक और गड़बड़ करी। 12 जिलों में उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत काम शुरू किया है। अब बाकी बचे हुए हैं तो आप कर दो। क्योंकि पक्षपात आप सहन करते ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह तो जयपुर जिले में क्या मालूम कब मेरा नम्बर काट देंगे।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जयपुर जिले में एलीमेंटरी एजुकेशन के लिये एक डी ओ है। एक डी ओ और कितने स्कूल ? दो डी.ई.ओ. नहीं कर सकते। एक डी.ई.ओ., दो डी.ई.ओ. बना देंगे तो भी मैं समझता हूं दो डी.ई.ओ. के आफिस में भी वह लोग एक-एक स्कूल को नहीं देख पायेंगे। आप यह ताकीद करें उन लोगों को इस बात के लिये पाबन्द करें कि एक स्कूल में एक बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर जाकर उसका निरीक्षण करे। होता ही नहीं है। निरीक्षण की बात खतम हो गयी। कोई देखता ही नहीं। जांच करने जाता ही नहीं है। केवल मात्र आपकी मीटिंग में आ जाएं, या आपके सैक्रेटेरिएट में आ गये या कलेक्ट्रेट में चले गये। मीटिंग में आने के बाद डी.ई.ओ. का काम पूरा हो गया। ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर का तो कोई नाम ही नहीं देखते। इसके कारण हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता था दूसरी बात डी.पी.ई.पी. की। डी.पी.ई.पी. का बहुत बड़ा काम हो रहा है। भले ही पैसा केन्द्र सरकार का आ रहा हो। इससे कोई मतलब नहीं है। केन्द्र सरकार कोई बाहर की सरकार नहीं है और हम कोई विदेश के नहीं है। राजस्थान और केन्द्र सरकार एक ही बात है। हमारा उन पर हक है और उनका हमारे पर हक है पर यह कहां से आया विचार कि टीचर्स से इसका कंस्ट्रक्शन करवायेंगे ? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, टीचर रोड़ी और बजरी का भाव पूछता फिर रहा है। मजदूर सस्ते कहां मिलेंगे जिनको मजदूरी नहीं मिलेगी। गांव वाले कपड़े फाड़ते फिर रहे हैं। मास्टर भागा भागा फिर रहा है। स्कूलों में आना बंद हो गया। यह क्या हो रहा है ? क्या करना चाहते हैं ऐसे ? जब पंचायती राज को इतना बड़ा अधिकार देना चाहते हैं तो उसमें आपके कानून में आप यह कहेंगे केन्द्र सरकार ने नोर्म्स बनाकर

दिये हैं। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। आपको तो वहां सदस्य बनाया गया है। सोच समझकर बनाया है। आपका सुझाव मानेंगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने प्रयोग करके देख लिया। तीन बार लिख भी दिया। व्यक्तिगत मिल भी आया। उन्होंने कहा कि 13 आदमियों की जो कमेटी है इसी के माध्यम से करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): अब इसमें आप कोई संशोधन कर सकें तो मेरा तो सुझाव है। क्योंकि इसके कारण जो एक स्कूल में एक टीचर है या दो टीचर है उनका बहुत बुरा हाल है। वहां पढ़ाने की उनको फुरसत नहीं है। माननीय, आपने एक और बात करी है कि छात्रों को खेल में सर्वांगीण विकास के लिये खेल बहुत जरूरी है। खेल में आपने बहुत बड़ा काम बताया है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी की हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गये हैं लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता की उपलब्धि क्या रही? एक तो हमें मिला रजत पदक और आठ मिले हमें कांस्य पदक। सारे राजस्थान में एक रजत पदक और आठ कांस्य पदक। माननीय मंत्रीजी, यह भी कोई केवल मात्र आपके शिक्षा विभाग के कारण नहीं मिला है। यह इन छात्रों के स्वयं के प्रयत्न थे जिनके कारण हुए हैं अन्यथा आज प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाला और साथ खेलने वाला कोई मिलता ही नहीं। सब साढ़े चार बजे का इंतजार करते हैं इतनी देर हो गयी। एक भी छात्र को कोई तैयार करने वाला नहीं है। खिलाने वाला नहीं मिल रहा है। इन बात पर आप छोटी-छोटी बातों पर गौर करेंगे तो मैं समझता हूं हमें फायदा होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा।

सैकेण्डरी एजुकेशन के लिये तो आप खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरना ही चाहते हैं और अब पैसा किस काम आयेगा ? डेढ़ वर्ष के बाद यह पैसा किसी काम का नहीं है आपके इसलिये इसको जल्दी से जल्दी सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में स्टाफ लगाइये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारे स्कूल जन सहयोग से बने हैं या और किसी स्कीम से बने हुए हैं लेकिन वह बिल्डिंग का इन्द्राज पी.डब्ल्यू.डी. में नहीं है। जब तक सरकारी रिकार्ड में या पी.डब्ल्यू.डी में वह बिल्डिंग नहीं जायेंगी तब तक उनकी मेंटीनेंस का काम पी.डब्ल्यू.डी. नहीं कर पायेगी। मैं आपको निवेदन करना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

चाहता हूं कि सारे राजस्थान में एक परिपत्र भेजकर सभी हैड मास्टर को, प्रिंसीपल को पाबन्द करें और ताकीद करें कि पी.डब्ल्यू.डी. उसमें ले ताकि उसका काम चले...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं दो छोटी-सी बात और कहना चाहूंगा। संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं। राजस्थान में केवल मात्र 18 जिले ऐसे हैं जिनमें संस्कृत महाविद्यालय नहीं हैं और 1200 स्कूलों में से 2000 टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। संस्कृत शिक्षा में आपने जिस तरह से बजट में उल्लेख किया है, सामान्य शिक्षा के स्कूलों का आप कह देंगे हम उनमें ही निकाल देंगे। कितना अच्छा होता संस्कृत शिक्षा के लिये भी आप क्रमोन्नत के लिये प्रवेशिका, उपाध्याय और शास्त्री कालेज का इसमें हवाला देते। बजट में नहीं आया इसलिये लोगों को बड़ी चिन्ता लग रही है। वैसे तो आप संस्कृत प्रिय हैं। संस्कृत के बारे में बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं इसलिये संस्कृत के बारे में जरूर सोचेंगे।

संस्कृत के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने ढाई करोड़ रुपये दिये संस्कृत विश्वविद्यालय को। अब ढाई करोड़ किस हिसाब से दिया, कितना दिया, यह तो आप जानेंगे लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर शोध के लिये सात पीठ बना रखी हैं आपने। सातों पीठों के जो अध्यक्ष हैं वह कब जाते हैं, कब आते हैं और कौन क्या करता है इसका कोई पता नहीं है। न तो उनके पास संसाधन हैं, न उनके पास स्टाफ है इसलिये संस्कृत शिक्षा के बारे में सभी चिंतित हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप डरना नहीं। लेकिन वैसे आप जैसी स्थिति अर्जुन की भी हो गयी थी। महाभारत में उन्होंने भी कहा गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा...

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री बीरूसिंह राठौड़।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ''क्लेब्यं मा स्म गम: पार्थ नैतत्वय्युपपयते, क्षुद्रं हृदयेदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप:' इन बातों को छोड़िये और आप भी परम तप के लिये लग जाइये और बातें इधर-उधर आती-जाती रहती हैं। मेरे यहां पर स्कूल खोलने के लिये....

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): 'ओम् नमो भगवते अंजनी मां ... (व्यवधान) मां भगवती को प्रणाम।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं भगवती नहीं हूं। मैं पुरूष हूं। इधर क्या मुंह कर रहे हो ?

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पुरुष और महिला में अंतर करो। मैं निवेदन यह करना चाह रहा था मेरे यहां पर इंटीरियर एरिया एस.टी. का एरिया है नायला और नौरंगपुरा एस.सी. है वहां पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खुली। आपकी कृपा पहले नहीं हुई थी। मैं समझता हूं अब हो जायेगी और सैकेण्डरी स्कूल के लिये भामोद है, लखेर है, लालवास और नेवर जो एस.टी. के एरिया हैं इसमें आप स्कूल खोलने का हमें बल देंगे तो लोगों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उनका काम होगा। मैं इस बात को जानता हूं। महाकवि कालीदास ने मेघदूत में यह कहा था कि 'याच्चामोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा मेघदूतम्' अद्यम आदमी से याचना नहीं करना...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आओ बीरूसिंहजी।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): करना तो भरे पूरे आदमी से बात करना। अद्यम आदमी से मांगना पुस्तक में निरर्थक होना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं..

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने बड़ी कृपा करी, बातें तो मैं बहुत लेकर आया था। एक निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा पर...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि गुर्जरों को कितना अच्छा ज्ञान आ गया कि संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। यह तो मानो विद्वता की बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह तो आपकी बातों से शक होता है आदमियों को नहीं तो गुर्जर तो ज्ञानी है ही।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब आप बात को समझो। प्राथमिक शिक्षा कालूलालजी गुर्जर की जो सौंप दो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो आपकी बुद्धि ही ऐसी है। भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है तो मैं ही क्या करूं इसका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कालूलालजी अगर भीलवाड़ा के गुर्जरों के साथ वह रहते न तो ऐसे नहीं होते। वह हमारे साथ रह रहे हैं इसीलिये हो गये हैं ऐसे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं भी आपके साथ रह रहा हूं ना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक आवश्यक बात और रह गयी..

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करें। समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मन से नहीं हो साथ उनके।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके और इनके बीच में राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हैं इसलिये आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मन से साथ नहीं हो तिवाड़ीजी के, यह मैं कह सकता हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक मिनट। एक निवेदन करना चाहता था प्राइवेट संस्थाओं के लिये शिक्षा मंत्रीजी से कि आप इस मामले में बड़े गम्भीर हैं। प्राइवेट संस्थाएं केवल अपना रोजगार नहीं करती हैं वह हमारे समाज का भी भला करती हैं।

यह सरकार का भी साथ देते हैं, अगर वह बंद कर देंगे तो। उन्हें आपको स्कूल खोलने पड़ेंगे। केवल मात्र 20 प्रतिशत आपको ग्रांट देते हैं और 20 प्रतिशत में भी जिन लड़कों की फीस आयेगी। वह फीस भी उसी में भर लेंगे फिर वह कैसे चलेंगे या तो उन्हें बिलकुल मना ही कर दें, नहीं देना है तो और यहां आपके कालेज एजुकेशन के लिए, प्राइवेट वालों के लिए 50 प्रतिशत वह देंगे और 50 प्रतिशत आप देंगे। इस बात पर गौर से ध्यान देकर के बात करें और उन लोगों की भी सारी, वह भी हमारे समाज के अंग हैं। आपने मुझे समय दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बीरूसिंह राठौड़।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ऊं नमः भगवते, आंजने मामे स्वाहा, मां भगवती को प्रणाम। मांग संख्या 24 पर चर्चा चल रही है। इसी पर मैं आज विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी, मेरे आदरणीय गुरूजी घनश्यामजी तिवाड़ी,

वासुदेवजी देवनानी और शिक्षा विभाग को इन ऊंचाई तक पहुंचाया है, इस लॉबी में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की योजना बनाकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में स्टेडी करके, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पिछले तीन साल से सुन रहा हूं। इस सदन में केवल दो नामों की ज्यादा चर्चा होती है, माननीय सोनिया गांधी और आर.एस.एस.।

श्री सभापति: आप तो मांग पर बात करें। फालतू में सोनिया गांधीजी का नाम लोगे और प्रोब्लम खड़ी करेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सुनना पड़ेगा इनको। तीन साल से यह सुना रहे हैं। आज तो इनको सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): वास्तव में इस संसार की दो वास्तविकताएं हैं, पहली वास्तविकता यह है कि 'ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय,' 'हीरे-मोती बहुत कमाये, कफन में जेब होती तो साथ ले जाते।' जब तक इन दोनों सिद्वांतों में तालमेल नहीं होगा। जब तक इनमें एकरूपता नहीं आयेगी, इनमें समन्वय नहीं होगा, इनमें सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। पूरे झगड़े की जड़ यही है। मेरे कई मित्रों ने मेरी जो संस्कारी मां है जिसको मैं आर.एस.एस. के नाम से पुकारता हूं, कई प्रकार के आरोप लगाये। अत: मैं आज अत्यंत दु:खी होकर, पीड़ा से आप सब लोगों से माफी मांगकर कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आईना में +++ तो हमने नहीं लिखा आपकी संस्था के लिए ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आप बैठे रहें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमने नहीं लिखा है आईना में +++ ...(व्यवधान) आपकी सरकार ने लिखा है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): हां, हां, आप मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान) आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार से बात करें आप ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): +++ लिखा है कि फलाना लिखा है वह तो आपको पता लग जायेगा ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आइना पुस्तक में सरकार ने +++ बताया है तो हमसे क्या बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) आप अपनी सरकार से बात करें ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभापति से बात कर रहा हूं ...(व्यवधान) मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैंने 27 साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। 1976 में मैंने गोल्ड मैडल लिया है और हिन्दुस्तान में जितने भी स्टेट हैं उनमें मेरी लगभग 50 किताबें चलती हैं। मैंने पवित्र कुरान का भी अध्ययन किया है। मैंने पवित्र बाइबल का भी अध्ययन किया है और मेरे जो पुराने कम्युनिस्ट मित्र हैं, मैंने एस.एफ.आई. का भी अध्ययन करा है, तो शांति से मेरे विचार सुनें। तथ्यों को स्वीकार करें और सत्य को आप लोग स्वीकार करें ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अभी तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया है ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस संसार में चार प्रकार की विचारधाराएं हैं ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इतने विद्वान होने के बाद गर्व किसी को ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): उसके अंदर से जो आपकी तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं, उनके विस्तार के कारण इस पूरे संसार में असंतुलन पैदा हो गया है। ऐसी कई विचाराधाराएं हैं जिन्होंने पूरे संसार को दारूल इस्लाम और दारूल हरव के अंदर बांट दिया है। इस बारे में आपको चिंतन करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको शोध करना पड़ेगा। ऐसी कौनसी वह दो विचारधाराएं हैं जिसके कारण से पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस्लाम की जिन्होंने स्थापना की उनको नमस्कार करता हूं पैगम्बर साहब को, उन्होंने कांसेप्ट बनाया और

उस कांसेप्ट के आधार यह कहा कि हमको दारूल इस्लाम की स्थापना करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पवित्र सिद्वांत जो दिया उसकी मान्यता आज की तारीख में बिलकुल समाप्त हो गयी है। सद्दाम हुसैन ने एक लाख अस्सी हजार मुसलमानों का कत्ले आम करा दिया। क्या वहां आर.एस.एस. की शाखाएं लगती हैं? मेरे आज तक बिलकुल भी समझ में नहीं आया। पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बांग्लादेश वहां पर रोज कितने मुसलमान कितने मुसलमानों को मार रहे हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। क्या वहां आर.एस.एस. की शाखाएं लगती हैं? इस बारे में आप सब लोगों को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आलोचना करने से हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, आर.एस.एस. आज दुनिया के 100 देशों में काम करता है। आर.एस.एस. के आज पूरे हिन्दुस्तान में 32 संगठन काम कर रहे हैं। हम जिस शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, मेरा आप सब को चैलेंज है कि आप दुनिया में किसी भी खुफिया एजेंसी से सर्वे करवा लें, आर.एस.एस. के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में जो 30 हजार स्कूलों का संचालन किया जा रहा है उसमें 32 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 1 लाख शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। उनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, मेरा आपको चैलेंज है और अन्य संस्थाएं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है तो आपको पूरे तथ्य समझ में आ जायें।

सभापति महोदय, एक नयी विचारधारा और भी है जिसको मैं चर्च के नाम से पुकारता हूं, जिसको मैं ईसाई धर्म के नाम से पुकारता हूं। यह भी चौथी विचारधारा है। आज आप नागालैंड में जा नहीं सकते हैं। आज आप मणिपुर में जा नहीं सकते हैं। आज आप केरल में जा नहीं सकते हैं। वहां पर वही होता है जो चर्च के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह कौनसी शिक्षा है। यह जो साम्येटिक रिलीजन की विचारधारा इस दुनिया में विकसित हो गयी है, यही इस मानव समाज के पतन का कारण बनेगी।

सभापति महोदय, मेरे जो सामने मित्र बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि 1917 में रशिया में साम्यवाद की स्थापना हो गयी। यह ऑन रिकार्ड है, 123 मस्जिद में से 120 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। वहां पर जितने कब्रिस्तान थे, उनको समाप्त कर दिया गया। जितने भी आपके मदरसे थे उनको समाप्त

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

कर दिया गया और पूरी दुनिया में 1917 से लेकर आज तक 10 करोड़ लोगों की आपने हत्या कर दी। माओवादी नक्सलवाद आज आपकी नाजायज संतान बन गये हैं। आप किस की बात करते हैं। क्या साम्यवाद के माध्यम से दुनिया में जो इतने लोगों की हत्याएं की गयी हैं, क्या उसमें आर.एस.एस. का हाथ है? इस बारे में भी आपको चिंतन करना पड़ेगा, जब तक आप इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप प्रोफेसर रहे हैं, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि अपन राजस्थान में शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा करें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैं संयम लोढ़ाजी से भी यह अपेक्षा कर रहा था कि राजस्थान के बारे में बोलें। इस मंच के माध्यम से इस ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, इतिहास गवाह है कि हर धर्म में आर.एस.एस. की तरह की विचारधारा के लोग होते हैं, चाहे किसी भी नाम से हों।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): इस विधान सभा का प्रयोग आप आर.एस.एस. की आलोचना करने में नहीं कर सकते हैं। जैसे आज मैं आरोप लगा दूं कि सोनिया गांधीजी विदेश की एजेंट हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं कह दूं कि +++, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं कहूं कि परम आदरणीय +++ तो अच्छा लगेगा? बिना किसी तथ्यों के आधार पर इस विधान सभा का प्रयोग इस आधार पर नहीं करना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आर.एस.एस. के बारे में ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): अगर आप लोग आर.एस.एस. की आलोचना करेंगे तो आपको भी आलोचना सुननी पड़ेगी। आप लोग आलोचना करेंगे तो आपको भी आलोचना को उत्तर देना पड़ेगा, अन्यथा आपको किसी भी राज्य की किसी भी संस्था की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय घनश्यामजी आप इस डिबेट को चलाये रखना चाहते हैं कि स्थगित कराना चाहते हैं?

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आप किसी भी तरह से आलोचना नहीं कर सकते हैं। आपको तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): या खतम करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब तक आप इस विषय को स्वीकार नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इन्होंने यह बात कही हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): यहां पर हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको भी पूरे विषय को समझना पड़ेगा। रसिया का नहीं है ...(व्यवधान) जो सत्य है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): सभापति महोदय, अन्य देशों में क्या किया है, यह आपको जानकारी दी है ...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आपको भी अधिकार नहीं है कि आर.एस.एस. मेरी संस्कारी मां है और जो मेरी मां को गाली देगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): हां, बैठिये। आपको भी यहां पर हत्यारा कहने का अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठे-बैठे बात नहीं करें ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): इस संसार में जब-जब रावण पैदा होगा तो राम को पैदा होना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजें आप।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): इस संसार में जब-जब कंस पैदा होगा, कृष्ण भगवान को पैदा होना पड़ेगा। इस संसार में जब-जब औरंगजेब पैदा होगा, शिवाजी को पैदा होना पड़ेगा। इस संसार में जब-जब अकबर पैदा होगा, महाराणा प्रताप को पैदा होना पड़ेगा और इस संसार में जब-जब अंग्रेज पैदा होगा, महात्मा गांधी को और सुभाष चंद्र को पैदा होना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): बिलकुल सही बात है। आप लोग सारे उसी के अनुयायी हैं, सारी आपकी विचारधारा उन्हीं की अनुयायी है इस बात को आप समझें ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय विचारधारा को मानने वाला हूं। आप कुछ भी कह दीजिए, आप उनके बारे में कहें जो कुछ हैं, मेरे ऊपर इस तरह का आरोप आप मत लगाना।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): हां, बहुत बढ़िया है। हम आपका स्वागत करते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह घनश्यामजी तिवाड़ी बैठे हैं और यह गुलाबजी बैठे हैं। यह इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाने की कोशिश मत करना। मेरे बारे में कुछ न कहें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैं खुद आपकी तरह मस्जिद में पांच बार नमाज पढ़ने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस के मुख्य सचेतक साहब, आप पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाने का किसी का कोई भाव नहीं है, आप बहुत अच्छी विचारधारा के हैं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): मैं बिलकुल तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): जो लोग बोल कर गए हैं और सुना कर गए हैं, सुनने का भी माद्दा सब को रखना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, आप बैठे-बैठे बात न करें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, आजादी के 59 वर्षों के बाद भी अब तक की जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने लगभग 45 हजार विद्यालयों की स्थापना की लेकिन पिछले 3 साल में माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने 39 हजार विद्यालयों की स्थापना की, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों में एक लाख शिक्षकों को हमने नियुक्तियां प्रदान की हैं। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसके पूरे परिवार का विकास होता है, उसकी उन्नति होती है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी दो लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

मिड डे मील योजना की चर्चा आपने काफी सुन ली, मेरा इसके बारे में माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को सुझाव है कि राजस्थान की जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों में जितने भी आपके स्कूल चलते हैं अगर इस योजना को वहां पर लागू कर दिया जाए तो माननीय वसुन्धरा राजेजी ने गरीब को गणेश मानकर जो अपना पूरा बजट बनाया है, अपनी पूरी योजनाएं बनाई हैं, उनकी अपेक्षाओं की भी पूर्ति होगी।

लगभग 56 कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालयों में एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक बंधुओं की लगभग 3748 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, इसके लिए भी मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों में 8135 करोड़ रुपए का निवेश स्टेट गवर्नमैंट के द्वारा कराया गया इसके लिए भी मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। राज्य में कार्यरत 1208 मदरसों के अंदर इस स्टेट गवर्नमैंट ने पिछले तीन सालों में लाखों रुपए लगाए हैं। हमारा जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा उसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रोविजन माननीय घनश्यामजी ने किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत पहले 20.44 था और पिछले तीन सालों में यह 43.09 हो गया है, इसके लिए भी मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी का आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि मैं महिला को कन्या के नाम से पुकारता हूं और महिला का मतलब होता है मां और मां का मतलब होता है- 'समर्पण की पराकाष्ठा। इस संसार में हमको सब चीजें दुबारा मिल जाएंगी लेकिन जिस मां ने हमको जन्म दिया इस संसार में एक बार ही मिलेगी, दो बार नहीं मिल सकती है। इस संसार में माता का कोई विकल्प नहीं है इसलिए माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, आपने इस रूप में इस राजस्थान में जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, जिनको मैं माताओं के नाम से पुकारता हूं, उनके लिए आपने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जब किसी परिवार में कोई महिला विधवा हो जाती है और हमारे राजपूत समाज में तो महिला की दुबारा शादी भी नहीं हो सकती है, ऐसी अनेक प्रकार की विधवाएं हैं, इसके लिए मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले 3 वर्षों में 3773 विधवाओं को नियुक्ति दी। आपने बिलकुल धर्म का काम किया है और मैं आपको बिलकुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले पन्द्रह-बीस सालों तक आप निश्चित रूप से विधायक बनेंगे और आपका प्रमोशन भी होगा, क्योंकि आपने बिलकुल धर्म का काम किया है। ...(व्यवधान)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

पहली बार लगभग एक करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने बनवाया और उन सब का चैक अप किया है, उनको अनेक प्रकार की दवाइयां प्रदान की गई हैं तो मैं उन सब बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं को कई प्रकार की पुस्तकें नि:शुल्क वितरित की गई हैं। सत्र 2004-05 में 12 करोड़ 60 लाख, सत्र 2005-06 में 12 करोड़ 39 लाख और इस वर्ष का सत्र आ रहा है हमारा सत्र 2006-07 में 13.50 करोड़ का प्रोविजन हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी ने किया है।

सबसे बढ़िया प्रयोग माननीय घनश्यामजी ने यह किया है कि एक आदमी को 24 घण्टे जिन्दा रहने के लिए 21600 बार सांस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम प्राण-वायु के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान में जितने भी स्कूल हैं उनमें हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी ने वृक्षारोपण बिलकुल अनिवार्य किया है। एक-एक विद्यालय को आपने सौ-सौ पेड़ उपलब्ध करवाए हैं और उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। मैं इसके लिए माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को दो सुझाव देना चाहूंगा कि इस संसार में दो ही ऐसे पेड़-पौधे हैं जो 24 घण्टे ऑक्सीजन देते हैं। एक तो तुलसी का पौधा जो दुनिया का सबसे बड़ा एण्टीबायोटिक है और विज्ञान यह कहता है कि तुलसी का पौधा आसपास के दो-तीन किलोमीटर के इलाके को शुद्ध करता है तो आप स्कूलों में निश्चित रूप से तुलसी के पौधे लगवाएं जिससे वातावरण भी शुद्ध होगा और हमारी तुलसी की पूजा भी होगी। इसी तरह पीपल का पेड़ भी 24 घण्टे ऑक्सीजन देता है। आपके जितने भी बड़े स्कूल हैं, या जहां पर खेल के मैदान हैं वहां पर पीपल के पेड़ लगाना कम्पलसरी करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा।

गार्गी पुरस्कार के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं जो 75 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर प्राप्त करती हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण योजना है लेकिन मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी से निवेदन करूंगा कि जो स्कूल हमारी पिछड़ी बस्तियों में बनी हुई हैं, कच्ची बस्तियों में बनी हुई हैं, वहां की बच्चियों के लिए भी आप अलग से योजना बनाएं और बाकी जो दूसरे स्थानों के स्कूल हैं उनके लिए आप अलग से योजना बनाएं। आपने वर्ष 2005-06 में 10804 बच्चियों को यह पुरस्कार दिया और इसके लिए आपने 108.04 लाख रुपए दिए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

शिक्षा विभाग में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, उनके परिवारों का पालन-पोषण कैसे हो, उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी न आए इसके लिए आपने लगभग 1430 मृतक आश्रित व्यक्तियों को नियुक्ति दी, जिनके या तो फादर की डेथ हो गई थी या जो सर्विस में थे उनके परिवार भी इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

माननीय घनश्यामजी, मेरा विधान सभा क्षेत्र 11 लाख की आबादी का है और राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। यहां की दो-तीन समस्याएं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 105 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 56 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 28 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 12 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 9 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। पिछले सत्र में आपने मेरे यहां पर सात स्कूलों को क्रमोन्नत किया था उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विज्ञान विषय अधिकांश स्कूलों में नहीं है, वह चालू करें। मेरा जो विधायक कोटा है उससे पिछले तीन साल में मैंने 40 लाख रुपए दिए हैं इससे स्कूलों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं चाहे वह फर्नीचर का मामला हो चाहे वह कमरों के निर्माण का मामला हो।

मैं पिछले 27 सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं। पिछले दस-पन्द्रह सालों से वहां हमारे कई शिक्षक, प्रोफेसर, लैक्चरर अस्थायी हैं, उनके प्रति भी आप चिंता करें, उनको स्थायी करें तो वह लोग भी आपको धन्यवाद देंगे।

एक प्रकरण विधान सभा में खूब आ रहा है, जितने भी आपके स्कूल हैं, उनकी जो खाली जमीन है उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, अगर उन सब की बाउण्ड्री वॉल बनवा दी जाए तो मैं समझता हूं कि स्कूल का भवन भी बच जाएगा और उसकी बाउण्ड्री वॉल भी बन जाएगी।

अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि चाहे किसी भी पार्टी में हो, आप न तो आर.एस.एस. की आलोचना करें, न आप कांग्रेस की आलोचना करें, 'सत्यमेव जयते', सत्य की विजय होती है। हम और आप सत्य के साथ चलें यह हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है। जब हम शिव पुराण की बात करते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि संसार में जो भी मानव जन्म लेता है वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर के

अंश को जो व्यक्ति समाप्त करने का प्रयास करेगा वह विचाराधारा, वह चिंतन स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, भारत माता की जय।

(समय : 18.33 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, आदरणीय सोनियाजी गांधी के ऊपर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, उनको आप देखकर एक्सपंज करवा दीजिए ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: देख लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था कर दी थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और माननीय सोनियाजी के बारे में जो भी गलत शब्द कहे गये हैं, उन्होंने स्वयं ही व्यवस्था कर दी थी कि उनको एक्सपंज कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या -24 जो शिक्षा के बारे में है उस पर अपने विचार रखना चाहूंगा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है ''माता शत्रु, पिता वैरी, येन: बालको पाठन्ति।'' जो मां–बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे शत्रु के समान हो जाते हैं। माता वैरी हो जाती है, पिता शत्रु के समान हो जाता है। राज का भी कर्तव्य है, राजा जो राज कर रहा है वो प्रजा का पिता की तरह है, जो भी राज में है वो पिता की तरह है और पिता का काम है कि उस प्रजा को, उन बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाये, नहीं तो वह राज दोषी माना जाता है।

मैं सरकार की और शिक्षा मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य में नये कीर्तिमान स्थापित किये। यूनेस्को पुरस्कार इस राजस्थान को मिला इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। यही नहीं राजस्थान पिछड़ी श्रेणी के राज्यों में था वो आगे की श्रेणी में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है।

हमारे यहां इन दिनों में इस सरकार के कार्यकाल में कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय खुला, जोधपुर में एम्स खुला, जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय

खुला, आयुर्वेद के बारे में विश्वविद्यालय जोधपुर में खुला। कितने प्रकार की यूनिवर्सिटियां हमारे यहां खोली गई हैं यह अपने आप में एक बहुत भारी कीर्तिमान है। आज के पहले कभी इस प्रकार के इंस्टीयूशंसन नहीं हुए, इतने कभी स्कूल और कालेज नहीं खोले गये।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज क्योंकि कई लोगों को बोलना है इसलिए मैं बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं कहते हुए दो-चार बातें कहना चाहता हूं। भारतवर्ष में 77 हजार पर एक कालेज है सारे देश में, और हमारे यहां इस सरकार की जागरुकता की वजह से, मुख्य मंत्रीजी की वजह से, शिक्षा मंत्रीजी की वजह से, सारे मंत्रिमण्डल की वजह से 63 हजार की पापुलेशन पर एक कालेज है। यह अपने आप में बड़ा भारी कीर्तिमान है। हमारे यहां 886 महाविद्यालय हैं, 117 राजकीय महाविद्यालय, 71 अनुदानित महाविद्यालय, 9 स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय, 689 निजी महाविद्यालय हैं। यही नहीं महिला महाविद्यालय 33 हैं जो कभी नहीं हुए। अनुदानित 29, गैर अनुदानित 262, गैर अनुदानित स्व-वित्त पोषित एक। माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना चाहता हूं जनजाति उप योजना में कभी इतने महाविद्यालय नहीं हुए। जनजाति के क्षेत्रों में 32 महाविद्यालय हुए, यह अपने आप में एक महान कीर्ति है। कीर्तिमान भी है और इनकी कीर्ति भी है। मैं इतना कहना चाहता हूं हमारे सिरोही के माननीय सदस्य आज यह कह रहे थे कालेज स्टूडेंट की जो बढ़ोतरी इन दिनों हुई है 'भूतो न भविष्यति', कभी सोच भी नहीं सकते। अनुसूचित जाति के लोग कालेज में हायर एजुकेशन में 51245, जो कुल स्टूडेंट्स की संख्या है उसमें 14.2 परसेंट है। अनुसूचित जनजाति के बच्चे 41471, 11.35 परसेंट और पिछड़ा वर्ग के 133459 कालेज में हैं, यानी 36.52 प्रतिशत। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वह कालेज एजुकेशन के बारे में है वह है 2.36, 8614 कालेज स्टूडेंट। सब मिलाकर 2.5 लाख कालेज स्टूडेंट आज विभिन्न कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इससे ज्यादा बड़ा कीर्तिमान क्या स्थापित हो सकता है? पहले सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में भी दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे आज कालेज विद्यार्थियों की यह संख्या आपने बढ़ायी है, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। आज बेरोजगार युवकों के लिए भी जब रास्ता निकला है, ग्रेजुएट हो गया, मारा-मारा फिर रहा है, कोई काम नहीं

है, चलो आपको 400 रुपये भत्ता देंगे। 400 रुपये भत्ता इस हिन्दुस्तान में कोई विधान सभा ऐसी नहीं है जिसने इस प्रकार का पास किया हो और मंत्रिमण्डल ने बजट रखा हो कि 400 रुपया भत्ता दिया जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुलायम सिंह नहीं है?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मुलायम सिंह नहीं है। है तो कम है। बेरोजगार ग्रेजुएट के लिए 400, महिला के लिए 500 और विकलांग के लिए 600, ऐसे 10 लाख लोगों को बिना किसी काम के पैसा दिया जाएगा, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है।

माननीय उपाध्यक्षजी, बच्चे माल-न्यूट्रिशन से परेशान हैं। छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, खाने को नहीं है, कुपोषित हैं उनको मिड डे मील दिया जा रहा है। मैं घूघरी में नहीं जाना चाहता, पर जिस तरह का भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है उससे बच्चे माल-न्यूट्रिशन के शिकार से बचकर आज अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं। धीरे-धीरे उनका क्लास में जो ड्राप आउट ज्यादा होता था, स्कूलों में नहीं आते थे, अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हमारे बच्चे सब पढ़-लिखकर होशियार हो गये तो किसी भी प्रकार की सहायता की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसके लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं।

'सर्व शिक्षा अभियान' में 150 करोड़ रुपया रखा है। 1500 सैकण्डरी स्कूल एक वर्ष में। मुझे तो याद नहीं राजस्थान बनने के बाद शायद 1977 में जरूर सैकण्डरी स्कूल खुले थे उसके बाद ठीक 30 साल बाद 1500 सैकण्डरी स्कूल एक साथ खोले जा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 30 साल में एक भी नहीं खुला?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कभी नहीं। एक वर्ष में कभी नहीं खुले।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कम से कम रिकार्ड को ठीक करके सदन में बोलें, अच्छा रहेगा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं रिकार्ड से कह रहा हूं और जो कहता हूं तथ्य से कहता हूं, गैर जिम्मेदाराना बात मैं नहीं करता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस सरकार ने तीन साल में कितने प्राइमरी स्कूल खोली हैं?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 16 हजार तो इस साल ही खोली हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कंफ्यूजन निकाल देना। 26 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम डिक्लेयर किया है, खुद ने चार हजार नहीं खोली हैं। बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यह आप कह देना।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): चपलोत साहब, आप अध्यक्ष रहे हुए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं आपने सही बात कह दी, लेकिन स्कूलें खोलने से उसका इंप्लीमेंट हो जाएगा? उसके बाद बता देना मास्टर लग जाए तो।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आ जाएंगे, मास्टर भी आएंगे। ...(व्यवधान) 600 हायर सैकण्डरी, 12300 शिक्षकों की इस साल भर्ती होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्रवण कुमारजी, आपका भाषण पूरा सदन सुनना चाहता है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सुनना चाहते हैं तो सुनाएंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, इस साल में 12300 स्कूल अध्यापक लगाये जाएंगे। यह अपने आपमें बड़ा भारी कीर्तिमान है। पहले भी 60 हजार के आसपास अध्यापक लगा चुके हैं। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें अध्यापक नहीं पहुंचा हो, शिक्षा की सुव्यवस्था नहीं हुई हो। इस प्रकार का अद्वितीय काम इस सरकार ने और यहां के शिक्षा मंत्रीजी ने करके दिखाया।

आई.टी.आई. खोलने का सवाल है, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। आई.टी.आई. आप जरूर खोलें और हर उप खण्ड स्तर पर, तहसील स्तर पर हो पर अब रोजगार इस प्रकार का ढूंढा जावे, उसकी ट्रेनिंग दिलाई जाए जिससे कि रोजगारयुक्त हो सकें, चाहे टैक्सटाइल में हो, चाहे चमड़े की ट्रेनिंग हो, कताई का हो, बुनाई का हो, इस प्रकार के किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग के सेंटर खोले जाएं। आई.टी.आई. की हमारे यहां भी काफी मांग हो रही है। हमारी तहसील रेलमगरा है, राजसमंद में वहां पर आई.टी.आई. नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जरूर आई.टी.आई. रेलमगरा में बनाएंगे। पिछड़ा इलाका है, किसी जमाने

(श्री शांतिलाल चपलोत)

में गंगानगर की तरह सरसब्ज इलाका था, आज वह सूख कर बिलकुल वैसा हो गया है इसलिए ऐसे में आई.टी.आई. वहां जरूर खोली जावे।

मैं आई.आई.टी. के लिए भी चाहूंगा। आई.आई.टी. आप हमारे मित्र हैं और आप उनको कह ही रहे हैं तो मैं तो चाहता ही हूं कि आई.आई.टी. आज उदयपुर में खोले जाने की महत्ती आवश्यकता है। साढ़े छह सौ, छह सौ एकड़ जमीन हमने आपको दे दी है। शिक्षा मंत्रीजी से भी मिले, मुख्य मंत्रीजी से भी मिले, नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का उदयपुर में डबोक में है, टू फोर लेन वहां से जा रही है, इंटरनेशनल 10 होटल्स हैं उसमें से 2 उदयपुर में हैं, 10 में से सारी दुनिया के 10 होटलों में 2 उदयपुर में हैं, जो इंटरनेशनल मानक में आते हैं, वातावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान है और मेरा तो आज भी दावा है, चाहे वह और कोई भी स्थान हो वह छह सौ एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा सकता, जो उदयपुर करा सकता है। उदयपुर के जन-प्रतिनिधियों ने, एम.एल.एज. ने सब ने कहा है कि हम अपने विधायक फंड को उसमें देने के लिए तैयार हैं, जमीन खरीदने के लिए तैयार हैं, हमने यू.आई.टी. को और उदयुपर की नगर परिषद् से भी कहा है, जन प्रतिनिधिनियों से भी कहा है, जनता से भी कहा है, जनता ने भी कहा है कि हम आई.आई.टी. उदयपुर में आएगी तो जितनी जमीन का पैसा है हम देंगे। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप जयपुर में खोलना चाहते हैं एक करोड़ रुपये बीघा की जमीन है, 12 सौ बीघा, साढ़े बारह सौ बीघा चाहिए, साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये केवल जमीन का जयपुर में चाहिए, अजमेर में चाहिए, जोधपुर में चाहिए, कोटा में भी इतनी जमीन एवेलेबल आज की तारीख में नहीं है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और हमारे पास, एक हमने सारे दस्तावेज आपको दिये हैं, केन्द्र सरकार की भी यही इच्छा है कि वह उदयपुर में ही हो, उसके मैं कारण बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तीनों ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): यह तो जहां सस्ती जमीन है वहां हो, साहब, गंगानगर में है सस्ती जमीन। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जोधपुर में आपको कितनी जमीन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसे क्या बात कर रहे हो ? जोधपुर में जमीन नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उसके बीच में उदयपुर पड़ता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): इसलिए कि राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार ने इसीलिए दिया है कि राजस्थान में बने और वह भी क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों इसके बीच में पास में पड़ जाएंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में भी विचार करें। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ही, एक बात और कहनी है। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों, अनुसूचित जनजाति के ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सारी सुविधाएं जोधपुर में देंगे, सारी जो मांगेंगे जोधपुर में देंगे, ये देंगे उससे हम डबल देंगे। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): XXX

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहस का विषय नहीं है। ...(व्यवधान) उन्होंने अपना एक बीच में अहम मुद्दा बताया है, आप उत्तेजित मत होइए बीच में। ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): XXX

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): XXX

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस का मुद्दा नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 24 पर विचार

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): XXX

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जाति भेदभाव को नहीं रखा है। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): XXX

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): तो एक करोड़ 15 लाख रुपये दिये। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, बीच में, कोई अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है, क्यों बहस कर रहे हो?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चपलोत साहब। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई है 9 हजार से 15 हजार कर दी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): XXX

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अब आप चुप करें थोड़ा। तीन जिलों में वैद्य विद्यालय 32 जिलों में अब वैद्य विद्यालय हो रहे हैं, संस्कृत विद्यालय दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये भाषण दे रहे हैं भाई।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आपने 15 हजार तक की फीस अनुसूचित जाति, जनजाति के तबकों के लिए कर दी। ...(व्यवधान) और जो लोग प्रेक्टिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो लोग मेडिकल कालेज में जाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग किसी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। वहां 50-60 हजार रुपये फीस लगती है। एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इतनी फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन बच्चों को जो 15 हजार की आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसमें कम से कम जो टेक्नीकल एजुकेशन लेने जा रहा है उसको 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्षजी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा के सम्बन्ध में मांग संख्या-24 पर चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोका-टाकी नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, तय यह हुआ था कि एक इधर से बोले, दो उधर से बोले और फिर एक बीच वाला बोले।

श्री उपाध्यक्ष: बोलेंगे, बाद में समय देंगे। समय दिया जाएगा, आप तसल्ली रखो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्षजी, तय यह हुआ था कि एक इधर से बोले, दो उधर से बोले और फिर एक बीच में से बोले। अब एक इधर से बोल गये, दो उधर से बोल गये, एक बीच वाले को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दो, अभी वो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, शिक्षा को सब ने औजार की तरह माना है। यह शाश्वत सत्य है कि शिक्षा के बिना न कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है, न समाज कर सकता है, न सरकार उन्नति कर सकती है। वर्डसवर्थ ने कहा है – 'A child is the father of the man' आज सही ज्ञान पाया बच्चा कल एक स्वच्छ समाज बनायेगा। इस सम्बन्ध में मैं पूर्व में जो चर्चा की है उस सम्बन्ध में दोहराना नहीं चाहता। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज जो माध्यमिक शिक्षा है उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। चाहे भारत सरकार के 'सर्व शिक्षा अभियान' में आपने भर्ती की, आपको मौका मिला, जितना करना था उतना नहीं कर पाये लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आज गांवों में शिक्षक की हालत ऐसी हो गई है कि सरकार का कोई कार्यक्रम हो, पंचायत समिति का कोई कार्यक्रम हो, जिलाधीश कोई कार्यक्रम करे, सब जगह उस शिक्षक की ड्यूटी लगती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्यों में पांच काम बताये हैं। आपके विभाग ने, आपके शिक्षा सचिवजी ने आदेश जारी करके राजस्थान के तमाम शिक्षा अधिकारियों को दिये हैं इसके बाद भी आज चाहे वार्ड सभा हो, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे कोई जल चेतना यात्रा हो, स्वास्थ्य चेतना यात्रा हो या बी. पी. एल. सर्वे हो, सब जगह जो कि गैर शैक्षणिक काम है उसमें उस शिक्षक को समय देना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इतने ज्यादा अध्यापकों की पहले से ही कमी है तो इस पर विचार करें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैंने पिछली बार भी मेरे विधान सभा के सम्बन्ध में निवेदन किया था, मैं फिर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्राथमिक शिक्षा जिसमें पंचायती राज भी शामिल है, 31.12.2003 को उसमें 290 पद रिक्त थे और आज पंचायत समिति दूदू में कुल स्वीकृत पद 1314 हैं और 472 पद रिक्त चल रहे हैं। यह कैसी विडम्बना है कि आप जैसे विद्वान शिक्षा मंत्री के होते हुए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है वह ऐसे कैसे चरमरा रही है? जयपुर जिले की पंचायत समिति, सांगानेर में जितने स्वीकृत पद हैं उनसे ज्यादा अध्यापक लग रहे हैं, जयपुर जिले की पंचायत समिति, झोटवाड़ा में जितने स्वीकृत पद हैं उनसे ज्यादा अध्यापक लग रहे हैं और पंचायत समिति, दूदू में 472 पद रिक्त चल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि

(श्री बाबूलाल नागर)

मई, 2006 से अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं और राजस्थान में कितने अध्यापक सेवानिवृत्त हो गये, आपने कितने नये विद्यालय खोल दिये उसके बाद भी आज तक आपने विद्यालय खोले, चाहे आपने सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती की लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि जिस दिन आपका राज आया उस दिन अध्यापकों के रिक्त पद कम थे और आज डबल में, उतने ही ज्यादा हमारे अध्यापकों के रिक्त पद हो गये। इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि 31.12.2003 को मात्र 44 स्कूल ऐसी थीं पंचायत समिति, दूदू में जहां एक अध्यापक था और शिक्षा मंत्रीजी, आज मेरी पंचायत समिति दूदू में 113 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक अध्यापक है। कहां 44 में एक अध्यापक था और कहां आज 113 में एक अध्यापक है। उस समय 4 मिडल स्कूल थे और आज 15 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक काम नहीं कर रहा है। मेरी समझ में यह नहीं बैठ रहा है। जयपुर जिले का पंचायत समिति, दूदू और सांगानेर विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए, यह दीया तले अंधेरा कैसे हो रहा है? कैसे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है शिक्षा मंत्रीजी? मैं यह विश्वास नहीं कर सकता। पता नहीं कैसी आपकी व्यवस्था है, कैसी आपके इन अधिकारियों की व्यवस्था है, कैसे इनका संचालन है कि जो हमारी दुर्दशा होती जा रही है।

मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, मैंने रोस्टर के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध किया था। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने इसी शिक्षा की डिमाण्ड पर जवाब दिया था, मैंने निवेदन किया था कि 5.7.1985 तक वेकेंसी आधारित रोस्टर था। सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 16-12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। इसके बाद में 20.11.1997 को जब राजस्थान में आपकी सरकार थी तब कार्मिक विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें वेकेंसी को छोड़कर के पद आधारित रोस्टर कर दिया और उसमें जो रोस्टर का मॉडल बनाया, रोस्टर का जो अंक बना है वह माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस तरह बना है कि राजस्थान में 100 में से अनुसूचित जाति को 16 स्थान मिलने चाहिए, 50 में से 8 मिलने चाहिए, 25 में से 4 मिलने चाहिए और 1997 के रोस्टर के अनुसार जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, 25 में 4 के स्थान पर तीन आरक्षित पद मिलते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में 100 में 12, 50 में 6 मिलने चाहिए लेकिन इस रोस्टर के अनुसार 50 में से

(श्री बाबूलाल नागर)

अनुसूचित जनजाति को 5 पद मिलते हैं। जब आपका रोस्टर ही सही नहीं है, रोस्टर ही संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है तो कैसे कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग में बैकलॉग नहीं है या बैकलॉग की पूरी पूर्ति कर रहे हैं? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं आंकलन करें। मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि बीकानेर में राजस्थान के उप निदेशकों की मीटिंग हुई उसमें दिसम्बर तक 69 लाख बच्चों का नामांकन हुआ और पिछले वर्ष दिसम्बर तक 73 लाख बच्चों का नामांकन हुआ। शिक्षा मंत्रीजी, आपने तो नई स्कूलें खोली हैं। क्या कारण हुआ कि एक साल में चार लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ? यह आपको आत्मचिंतन करने की बात है कि प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक और मिडल स्कूल आज गांवों में ऐसे हालात में पहुंच गये हैं कि ऐसी आपने स्कूल खोली, मेरे भी यहां बहुत खोली, मेरे यहां तो बिना कोई पक्षपात के खोली लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसी स्कूलों का क्या करें, आपके बच्चे स्कूल में नहीं जायें, बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जायें? अध्यापक वहां पढ़ाने के लिए नहीं है तो मैं समझता हूं, आपको इस सम्बन्ध में चिंतन करने की आवश्यकता है।

दूसरा, मैं आपको निवेदन करूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा मिशन की रिपोर्ट आपने देखी है। डाक्टर के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा मिशन की रिपोर्ट जारी हुई। उस रिपोर्ट में है, राजस्थान में आज शिक्षा में धन की कमी, गिरते मापदण्ड, शिक्षा की कमी, मानिटरिंग की कमी, शिक्षा में अव्यवस्था, इन सब के बारे में शिक्षा मिशन की रिपोर्ट में कहा गया है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि केन्द्र सरकार की ओर से ड्रॉप आउट और ट्रांजिशन रेट में राजस्थान को अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र बताया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रॉप आउट रेट का मतलब है शिक्षा मंत्रीजी, पहली से पांचवीं तक कितने बच्चों का नामांकन हुआ और कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी? केन्द्र सरकार के आंकड़ों में 57 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन हुआ लेकिन पहली से पांचवीं तक 57 प्रतिशत ने पढ़ाई छोड़ी। इसी तरह से ट्रांजिशन रेट में प्राइमरी से मिडल और मिडल से सैकण्डरी और सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी, इसमें मिडल में 88 प्रतिशत, सैकण्डरी में 81 प्रतिशत, यह जो हमारा राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

(श्री बाबूलाल नागर)

मैं एक और विषय पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूल में LTI यानी टीचर लर्निंग इन्स्ट्रमेंट, जिसके आप राजस्थान के पूरे जिला मुख्यालयों पर आजकल मेला लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, पहले इसमें प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपये मिलते थे। अभी यहां पर आपने प्रत्येक मिडल स्कूल को 30,000 रुपये किये, प्राथमिक स्कूल को 7,500 रुपये किये। मेरा निवेदन है कि जयपुर के पास में अभी भी यह मेला लग रहा है। इसके सम्बन्ध में जयपुर जिले के सभी अध्यापकों का यह कहना है कि इस मेले में जो स्कूलों में आपके एस.डी.एम.सी. के माध्यम से खर्च होता था, एस.डी.एम.सी. तय करती थी और वह 10 दुकानें देखकर सामान खरीदती थी, आपने मेले के द्वारा जो व्यवस्था की है, हो सकता है, आपकी जानकारी में नहीं हो, लेकिन मुझसे अध्यापकों ने चर्चा की है, मुझसे सम्पर्क किया है कि उस मेले में जो जिस रेट पर सामान मिल रहा है, बाजार में उससे काफी कम राशि में सामान मिलता है और उससे अच्छी किस्म का सामान मिलता है। उनका यह आरोप है कि इसमें मिलीभगत करके भ्रष्टाचार किया गया है। आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करायें। इस तरह के जो मेले लगाये हैं, जो बाध्य किया गया है उनको कि आप जो भी सामान है, वहां से खरीदें और चैक भी इन स्कूल वालों को उस मेले में ही दे रहे हैं तो आप उसको दिखवायें और दिखवाकर, मैं समझता हूं, आप इसको ठीक करवायें।

इसी तरह से मेरा एक निवेदन है, ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी, यह आपके मानेटरिंग की वजह से, मेरे क्षेत्र में मेरा प्रधान और ब्लाक शिक्षा अधिकारी विजिट करने गये। उन्होंने पंचायत समिति की मीटिंग की प्रोसीडिंग में यह कहा है कि 61 सम्भागीयों का बजट स्वीकृत था, उतना पैसा उनके खाने की, रहने की व्यवस्था का पैसा उन्होंने उठाया लेकिन वहां पर मौके पर आठ आदमी मिले। इसी तरह से जितने भी ब्रिज कोर्स हैं, इन सभी में एक ही हालात हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह से यह बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको आप दिखवाइये।

मेरा एक और निवेदन है, जिस तरह से हम शिक्षा में कितने ही स्कूल खोलें, कितने ही सुधारात्मक प्रयास करें लेकिन हमारे प्रदेश की, देश की जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, मैं चाहूंगा कि अपने पाठ्यक्रम में आप जनसंख्या को प्रभुता से रखें। इसी तरह से आप पर्यावरण को प्रभुता से रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसी तरह से गांव की हालत हो रही है, जिस तरह से अध्यापकों के प्रति भाव है, अध्यापकों का छात्रों के प्रति भाव है, वह जो नैतिक पतन हुआ है, नैतिक शिक्षा पर भी प्रायोरिटी रखें जिससे कि कम से कम स्कूल में वातावरण बढ़िया बन सके।

मैंने कालेज के लिए आपसे निवेदन किया था, आज भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में कालेज नहीं है। एक कोई निजी कालेज वहां चल रहा है। उसमें मुश्किल से 50 बच्चे पढ़ते हैं और उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है निजी कालेज वाले की। मुझे पता नहीं, किन मापदण्डों के आधार पर निजी कालेज की स्वीकृति दे दी गई। यह आपने नहीं दी है, यह तो स्वीकृति कांग्रेस सरकार के समय में दी गई है लेकिन किस तरीके से उसको दी? न भवन है, न व्यवस्था है तो मैं चाहूंगा कि जब इतना बड़ा एरिया है और वह भी डी.ई.डी.पी. में चयनित ब्लाक है, मरू विकास में चयनित ब्लाक है। हमेशा अकाल की चपेट में रहता है। पीने का पानी नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं। अगर वहां कालेज नहीं खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि गरीब का उद्धार नहीं हो सकता, गरीब को शिक्षा का आगे मौका नहीं मिल सकता।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नागर साहब, मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं, इसलिए आप समाप्त कीजिये। आपने करीब-करीब सब बातें कह दीं। श्री गोविन्द चौहान।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसी तरह से एक निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) राजस्थान विश्वविद्यालय में 1989 के बाद किसी तरह की कोई भर्ती नहीं की गई। 287 एडहोक को ले लिया। पिछली बार भी सदन में चर्चा हुई। एस.सी. एस.टी. का एक व्यक्ति भी उसमें नहीं है। आपने कहा कि अलग से हम एस.सी. एस.टी. के लिए बैकलाग के अनुसार भर्ती करेंगे, आज तक नहीं हो पाया। पूरे राजस्थान में एस.सी. के एस.टी. के मुश्किल से एक या दो प्रोफेसर हैं तो मेरा निवेदन है आपको, इसमें भी आप ध्यान दें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द चौहान।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): गोविन्दजी, मेरा नम्बर है। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो हमारा नम्बर होना चाहिए। बीच वालों में एक का तो नम्बर आ जाये। दो उधर से, दो इधर से कर दिये और हमारा नम्बर रह गया।

श्री उपाध्यक्ष: सबको समय दिया जायेगा।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसमें खूब चर्चा हुई। मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी वक्ता बोले, मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता और वैसे भी जो नये लोग हैं, उनको आप बीच में टोकाटोकी नहीं करें। मैं दो चीजों का ध्यान रखूंगा। एक तो पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और किसी की व्यक्तिगत आलोचना में हम विश्वास नहीं करते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुआ, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें बड़ी-बड़ी बातें कही कि इस देश के अन्दर सब को समानता का दर्जा मिलना चाहिए था सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, धरती का बंटवारा होना चाहिए था और अगले 10 साल तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि गरीब जाति के लिए आरक्षण दिया जाये और उसमें यह भी व्यवस्था दी थी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट भी उस समय थी कि जो ओ.बी.सी. के लोग हैं और जो जनरल कास्ट में भी, उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी लेकिन 59 साल की आजादी के बाद अगर हम उन बिन्दुओं पर चर्चा करें तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है, कांग्रेस के साथी कोई यहां खड़े होकर यह कहता है कि हमारे एस.सी. के अभी तक मात्र दो प्रोफेसर हैं। कुछ साथी हमारे खड़े होकर कहते हैं कि दलितों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। कुछ साथी खड़े होकर कह रहे हैं कि बैकलाग पूरा नहीं होता है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 59 सालों में सबसे ज्यादा इस देश में राज किसने किया और मात्र हम लोग आरोप और प्रत्यारोप करते रहे, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर हम लोग पूर्व में जायेंगे, इतिहास में जायेंगे तो अगर विश्व में सबसे ज्यादा कोई गुलाम देश रहा है तो उसका नाम हिन्दुस्तान है। सबसे ज्यादा कोई गरीब रहता है जिस देश में, उसका नाम भी हिन्दुस्तान पहले नम्बर पर आता है। यह किसकी जिम्मेदारी थी? 1967 तक कांग्रेस का किसी ने विरोध नहीं किया। चौधरी चरणसिंहजी विरोध में आये थे या फिर जो आर.एस.एस. थी जिसने विरोध किया था। 1977 में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सब मिलकर जनता पार्टी का राज बना। उससे पहले केन्द्र हो चाहे स्टेट हो, आज हमारे प्रतिपक्ष के जो साथी बैठे हैं, पूरे देश में राज इनका

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

था। मैं पूछना यह चाहता हूं कि आप लोगों ने यह कार्य क्यों नहीं किया? आज यह बात उठाते हैं हमारे यहां स्कूलें खुल गईं, हमारे कांग्रेस के क्षेत्र में जहां एम.एल.ए. है वहां अब स्टाफ नहीं लग रहा है, लेकिन साथियों, सबसे बड़े भागी आप हैं, सबसे बड़े दोषी शासक आप रहे हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि जब अंग्रेज आये देश में, उस समय देश में राज कौन कर रहा था, मुगल राज कर रहे थे? हमारे देश में उस टाइम जातिवाद, अंधकार, अंधविश्वास का भयंकर यहां अंधकार फैला हुआ था। उस वक्त के बाद में जब आजादी मिली, सबसे पहले कांग्रेस ने राज किया। जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, वह सभी तरह के लोग थे लेकिन इनके नेता चालाक थे, उन लोगों ने यह लेकर के राज चालू कर दिया। राज आपका रहा, फिर आप किस बात के आप दोषी हो, नहीं तो मैं सीधे-सीधे आपके ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, इस देश को जो पिछड़ने का काम किया है, आज भी हमारे देश में जो अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं इसके सीधे-सीधे जिम्मेदार आज आप हैं। मैं आज यह बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी बस्ती में जाता है, दलित बस्ती में, एक ही बात कहता है, यह झोंपड़ी वाले वोट हमारे हैं। जिस मोहल्ले में सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा जहां अंधविश्वास होता है वहां यह कहते हैं कि यह सारे के सारे वोट हमारे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन नेताओं से कि आपका वोटर तो गरीब रह गया और आप करोड़पति कैसे बन गये? आपका वोटर अनपढ़ कैसे रहा? इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा उपाध्यक्षजी, इस सदन का समय अधिकतर मैं देखता हूं कि छोटी-छोटी बातों पर दो-दो घंटे बहस चलती रहती है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे मंत्रीजी यहां थे, हम लोग बहुत इज्जत करते और हम सोचते थे कि सदन में बड़ी गम्भीर चर्चा होती होगी। यही पवित्र सदन है, इसमें बहुत गम्भीर चिंतन भी हुआ करता था, लेकिन आज मैं यहां देखता हूं कि छोटे-छोटे एक वाक्य को लेकर के बहुत वरिष्ठ साथी एक-एक घंटा लगा देते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जो है इसमें गम्भीर चिंतन होना चाहिए, इसमें गम्भीर मंत्रणा होनी चाहिए और मैं यहां सीधा कहना चाहूंगा हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कि अगर यह देश आज भी पिछड़ा हुआ है तो सीधे-सीधे जिम्मेदार आप लोग हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम मेघवाल: आज भी अगर शिक्षा के आंकड़े, गरीबी के

आंकड़े में जो पिछड़ा हुआ है, आज हमारी वसुंधरा राजेजी ने जो आज जनजाति के लिए योजना बनाई, आज हमारे घनश्यामजी ने जो...(व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतना अच्छा बोल रहे हैं, उधर बातें हो रही हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल: आज जो घनश्यामजी ने शिक्षा के लिए नीति बनाई, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आज आप लोग जो हैं, आप यह खुद कह रहे हैं, आज इनको दो सौ स्कूलें बीकानेर में अचानक खोलने की क्यों जरूरत पड़ी? आज चार हजार स्कूल नये खुले हैं, लेकिन आप इस राजीव गांधी पाठशाला में गरीब के बच्चे को पढ़ा कर क्या एसपी और कलक्टर बनाना चाहते हैं? एक आठवीं क्लास का बच्चा उनको पढ़ाने जा रहा है और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अशोकजी गहलोत ने बड़ी तगड़ी योजना बनाई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक जमाना था जब गांव में लोग अख़बार भी नहीं पढ़ते थे। आज भी लोग बहुत सारे कम पढ़ रहे हैं और जिस दिन लोग गांव में पढ़े-लिखे हो जायेंगे उस दिन सही लोकतंत्र आयेगा और उस दिन आपके जैसी पार्टी को, आपको वोट देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज यह आदिवासी क्यों है, आज अनुसूचित जाति का आदमी दुःखी क्यों है, इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार वह लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा राज किया है। इसलिए मैं आज आपको और बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, या तो शेरशाह सूरी के जमाने में सड़कें बनीं या अटलजी ने 'प्रधान सड़क मंत्री योजना' की एक पूरे देश में शुरूआत की। उसका आज परिणाम है कि राजस्थान में हमारी जो स्कूलें हैं गांव और ढाणी में, वहां सड़कें बन चुकी हैं। उसमें क्वालिटी भी है । तो धन्यवाद आप किस बात का ले रहे हैं । 'सर्व शिक्षा अभियान', यह भी अटल बिहारी वाजपेयीजी की देन है। इसलिए आज अटलजी का नाम आप इतिहास से दूर नहीं कर सकते। आज घनश्यामजी तिवाड़ी और वसुंधराजी राजे का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है कि इनके कार्यकाल में जो शिक्षा में प्रगति हुई, इन्होंने जो स्कूलें दीं और जो बजट दिया है, वह आप नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है क्योंकि केन्द्र में आपकी सरकार है, आज आपके सामने उत्तराखण्ड और पंजाब आपके हाथ से जा चुके हैं, एक जमाना था चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दक्षिण

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

हो, सब जगह आपकी सरकारें हुआ करती थी, आज आपके बिहार में क्या हालात हैं लालू के सहारे आप खड़े हैं। पूरे देश में आपकी पार्टी का जो पूरा शासन था, आज आपके हालात क्या हैं और राजस्थान में क्या हालात हो रहे हैं? इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप चाहे कितना ही जोर लगा लें, आप कितनी ही बड़ी-बड़ी बातें कर लें, मैं तो कहना चाहूंगा तिवाड़ी साहब को, इनकी आलोचना अच्छी है, जो-जो भी अच्छी बातें हैं इनसे ग्रहण करके हम लोगों को वह क्रियान्वित करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। मैं यह कहना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व साथी ने एक भाषण में कहा था कि घनश्यामजी तिवाड़ी झंडे का रंग देख कर स्कूल खोलने का काम करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कौन से झंडे को देख करके इस देश को पिछड़ा हुआ रखा है, इसके लिए आपके पीछे किसका हाथ है? आप कौन से देश के इशारे पर इस देश को पिछड़ा रखना चाहते हैं? आज भी जातिवादी का बोलबाला क्यों है? आप तो अच्छे आदमी थे, आज आप पाठ्यपुस्तकें निकाल कर दिखा रहे हैं कि इसमें जातिवाद का लिखा है, इसमें धर्म का लिखा है, हम तो कहना चाहेंगे कि बाबर यहां सौ आदमियों को लेकर आया था, ज्यादा कोई मुसलमान बाहर से नहीं आये थे। आज हम अगर किसी गरीब को इज्जत नहीं देंगे तो कोई मुगल बन जायेगा, कोई ईसाई बनेगा। इसलिए अभी भी सोचने की जरूरत है, जाति और धर्म पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर देश को हम लोग विश्व में बराबर की कहीं श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं तो दूसरे देश, वह अगर बिना जाति के आगे बढ़ सकते हैं तो भारत भी हमारा आगे बढ़ना चाहिए, यह हमारी सोच होनी चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो आज ढाणी-ढाणी में स्कूल दी हैं और मेरा साफ मानना है कि जब तक एजुकेशन नहीं आयेगी, इस देश में सही प्रजातंत्र नहीं आयेगा दोस्तों और गरीब को गणेश मानकर जिस झोंपड़ी में आज भी दीपक नहीं है उसमें दीपक आखिर तक जलना चाहिए, प्रत्येक आदमी प्रत्येक परिवार का पढ़ा-लिखा होना चाहिए। मैं वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदिवासी की बालिका को साइकिल का प्रोत्साहन देकर के उसमें एक प्रेरणा पैदा की है कि आप पढ़ने के लिए जाओ। मिड-डे-मील बिलकुल अच्छी व्यवस्था है, इसलिए कि बच्चा जो है उसको एक प्रोत्साहन मिले कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, वहां हमें इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम

लोग मात्र आलोचना करें, ऐसा काम नहीं करें, आप अगर जिस तरह से स्टेट गवर्नमैंट को सलाह देते हैं, आप अपनी सेंट्रल गवर्नमैंट को भी जानकारी दीजिये कि आज अटलजी का नाम पूरा, जिस तरह से शेरशाह सूरी का नाम चलता है, अटलजी का नाम कोई भी देश में भुला नहीं सकता दोस्तों। उसी प्रकार आप याद करो कि यहां पर आजादी के बाद में जो हमारे ओ.बी.सी. का, दलितों का जो पंचायत में आरक्षण होना चाहिए था, आपको किसने रोका था, आपने क्यों आरक्षण नहीं दिया। जब भैरोंसिंहजी की सरकार आई, भैरोंसिंहजी ने चिंता की इस बात की और एस.सी., एस.टी. के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मण्डल आयोग की रिपोर्ट....

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, यह पता है क्या कि राजीव गांधीजी ने 73वां अमेण्डमैंट करके यह व्यवस्था की थी। तब भैरोंसिंहजी ने दिया था, अपने आप नहीं दिया।

श्री गोविन्द राम मेघवाल: जुबेर खान साहब, बैठ जाइये। (व्यवधान) बैठ जाइये, बैठ जाइये। मैं वही कह रहा हूं कि आप में बीच में खड़े होने की आदत पड़ गई।

श्री राकेश मेघवाल: लागू किसने किया था, भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया, तब आप माननीय सदस्य, इस सदन में थे।

श्री बाबूलाल नागर: व्हिप जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामैंट में विरोध में वोट डाला था...(व्यवधान) आज बात करते हो आप पंचायतों की? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल: मैंने निवेदन किया है कि यदि आप विरोध करोगे तो हम भी आपके भाषण में विरोध करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज आप...(व्यवधान) नागर साहब, अगर आप विरोध करते हैं तो हम भी विरोध करना जानते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: घनश्यामजी जानते हैं कि किसने अमेण्डमैंट किया। घनश्यामजी को पता है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल: आप तो माननीय सदस्य, गुण गाओ। भारतीय जनता पार्टी के गुण गाओ कि जब हमारा राज बना तब आप जीतकर आते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामैंट में व्हिप जारी करके इस बिल के विरोध में वोट डाला है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: कांग्रेस ने वह किया है जो आज आप विधान सभा में बोल रहे हो। अम्बेडकर को संविधान बनाने का...(व्यवधान) उस आरक्षण की वजह से आज आप विधान सभा में हो। कांग्रेस ने यह किया है। आप इस बात को मत भूलो। (व्यवधान) हर सरकार अपना-अपना काम करती है, अटलजी ने किया, जवाहरलालजी नेहरू ने जो देश के निर्माण का काम किया है वह किसी ने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल: तभी आरक्षण दिया था भैरोंसिंहजी शेखावत ने। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल: उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने आपको बोलने का अधिकार दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: शिड्यूल्ड कास्ट को धोखा दिया।

श्री राकेश मेघवाल: बोलने का अधिकार तो संविधान ने दिया है, बोलने का अधिकार तो...(व्यवधान) यह भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिया। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल: 1993-95 में उस समय माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने शिड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण दिया, नहीं तो इनके जमाने में कोई वार्ड पंच और सरपंच बन जाता क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह देश जो गुलाम रहा है, उसका कारण ऐसे लोग शासन में थे। काले पन्नों में नाम लिखा जायेगा, यह हमारा भाषण भले ही रोक लें बीच में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम मेघवाल: मैं कहना चाहता हूं इनको यह जानकारी नहीं है कि आज अगर विश्व में आप जाकर देख लें कोई भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल: इनको जानकारी नहीं है सच्चाई सुनने के लिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैंने सुना है आई.ए.एस. आफिसर रहे हैं फिर सदन में इस तरह की बातें करते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता, उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया है तो आप तो आई.ए.एस. अफसर रहे हैं आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अम्बेडकर साहब को किसने बनाया? वह कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको संविधान निर्माता बनाया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ये किसी की जिंदगी खराब कर दी इन्होंने (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय गरीबों की बस्ती में जाए वहां भाषण देना ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): (व्यवधान) आपने पहले भी ... (व्यवधान) गुरु था, मैं इन कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं इन्होंने गरीबों का, दलितों का और (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसी की भी मदद करी नहीं सिर्फ धोखा दिया, कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) शायद जानकारी में नहीं थी लेकिन अब पता लगा कि काबुल में भी गधे होते हैं, यह उसी संकेत में समझ जाए अच्छा है (व्यवधान) अच्छी बहस चल रही थी, सुन लें, उसके बाद आपको जो कुछ कहना कहें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको सच्चाई, मेरी एक समझ में नहीं आ रही है मैं भी विचार दे रहा हूं उसके बाद (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): करेक्ट कर दूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैरोसिंहजी की देन है इसमें कोई शक नहीं है, हिन्दुस्तान में पहला राज्य राजस्थान था, सुनिये (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : राजस्थान में आरक्षण देने की माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोसिंहजी की देन है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में आप क्यों बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: जुबेर खानजी जो भी आपको बात कहनी है वह आपकी स्पीच में कहें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भैरोसिंहजी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया हिन्दुस्तान में पहला राज्य था जहां जनसंख्या के नियंत्रण पर यह किया कि पंचायत राज में वहीं लोग लड़ पाएंगे जिनके दो बच्चे से कम बच्चे हों, यह भैरोसिंहजी की देन है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आरक्षण, 73वें संविधान संशोधन के बाद राजीव गांधीजी की देन है, यह तिवाड़ीजी भी अच्छी तरह से जानते हैं (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): एक मिनट, संशोधन कर दूं, यह जो आरक्षण की जो व्यवस्था पंचायती राज और अरबन डवलपमैंट बाडीज में रखी है वह भैरोसिंहजी शेखावत की देन है 73 का एमेंड बाद में हुआ था, इसमें संशोधन करा लें यह तो रिकार्ड की बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह बात सही है कि राजस्थान विधान सभा में उनके नेतृत्व में बिल पास हुआ लेकिन 73वें एमेण्डमैंट में कहा था 33 प्रतिशत महिलाओं को और एस.सी., एस.टी. को आरक्षण देना है, उसी के अनुरूप दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, आपको कांग्रेस को (व्यवधान) चुनाव आता है जब राज बनता है जब जुबेर खानजी कांग्रेस का राज बनता है जब आप सदन में नहीं आते हो इसलिए कांग्रेस का गुणगान करना बंद कर दो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, कोई और सदस्य तो कोई बात कहे तो कोई बात नहीं, सरकार का मंत्री सदन में असत्य +++ बोले यह बिलकुल ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): संयमजी प्लीज आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कैसा असत्य +++ बोला है? क्या भैरोसिंहजी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया (व्यवधान) असत्य +++ तो आप बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रिकार्ड लाइए आप (व्यवधान) की वजह से 1989 के अंदर राज्य सभा में वह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी संयम लोढ़ा बोलेगा, मैं नहीं बोलने दूंगा यह मैं कह देता हूं (व्यवधान) कांग्रेस का कोई भी सदस्य बोले, यह तो आप समझे (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): संयमजी यह बताओ आपने कानून बनाया है लेकिन लागू किसे किया है? भैरासिंहजी ने किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का कोई भी सदस्य बोले, हम बोलने नहीं देंगे (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): (व्यवधान) भैरोसिंहजी शेखावत ने दिया था रिजर्वेशन (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सबसे पहले राजस्थान में लागू किया था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं और जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि अनुसूचित जाति को आरक्षण जो मिला है वह कांग्रेस ने दिया है मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा। यह डा. भीमराव अंबेडकर की देन है, यह संविधान की देन है यह किसी की बपौती नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं एस.सी. के बारे में यह जो भाषण है यह तो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): भीमराव अंबेडकर को संविधान विशेषज्ञ किसने बनाया था? क्या बी.जे.पी. वालों ने बनाया था? वह कांग्रेस थी, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेन्द्र प्रसादजी थे जिन्होंने (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): वह उनकी एबिलिटी थी, उनकी योग्यता थी, आपने कोई एहसान नहीं किया, उनकी योग्यता थी (व्यवधान) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में योग्यता थी (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): डा. भीमराव अंबेडकर में योग्यता थी आपने तो राज्य सभा से उनको हटा दिया था (व्यवधान) राज्य सभा में हटवा दिया था आपने भीमराव अंबेडर को। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कांग्रेस पार्टी ने दिया था उनको (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह आप गलतफहमी निकाल देना कि अब आपके भरोसे में विधान सभा में बैठे हैं (व्यवधान) आप गलत फंस गये हो आप (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गलत नहीं सही फंसे हैं, सही बात कह रहे हैं और सत्य सही होता है (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह आपका भाषण कच्ची बस्तियों में देना जहां अनपढ़ आदमी बैठा है (व्यवधान) आप गरीब बस्तियों में देना, यहां नहीं चलेगा भाषण, आपने उम्र भर नौकरी की है, राजनीति नहीं की है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): भैरोंसिंहजी ने दो बच्चों की व्यवस्था की (व्यवधान) जब से संविधान बना है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): XXX

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): XXX

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): XXX

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम थोड़ा सा गम्भीर चिंतन करने की कोशिश करते हैं, यह हमें लाइन से चुकाने के लिए बीच में डिस्टर्ब करते हैं यह इनकी चाल है और यह चाल है कि कोई मेघवाल एस.सी. का आदमी क्यों बोले, इनकी जैसे कोई बपौती है, और सदन जैसे कोई इन्होंने खरीद रखा है इसलिए हम चुप रहते हैं इसमें यह मत समझना हम बोलना नहीं जानते हैं, हम आपकी दिन-भर हरकतें देखते हैं कि आप क्या करते हो? कितनी आप में गम्भीरता है, इसलिए मैंने हाथ

जोड़कर पहले कहा है कि आप डिस्टर्ब मत करो आपका नम्बर आये जब मर्जी आये वह बोल लें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): XXX

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : जिन वोटों के भरोसे जीत कर के आते हो सी.डी. देवलजी, क्यों इतना चिढ़ रहे हो? मैं इतना हीं कह रहा हूं कि आज तक उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : अनुसूचित जाति को, कांग्रेस को वोट देने का वो आज तक भुगत रहा है दूसरी पार्टी के लोग यह समझते हैं 1977 का आंकड़ा उठा लो इंदिरा गांधी के पूरा देश खिलाफ हो गया था लेकिन अनुसूचित जाति का अधिकतर वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, जगजीवन रामजी ने पार्टी ने छोड़ दी थी उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति का वोट अधिकतर इनको मिला। आज भी आप विधान सभावाइज आंकड़ा मंगवा लें, अनुसूचित जाति का अधिकतर वोट इनको मिलता है। लेकिन जब कोई चीज देने का नम्बर आता है तो अनुसूचित जाति के आदमी को सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज मण्डल आयोग की रिपोर्ट किसके समय में लागू हुई? वर्षों से दबी हुई पड़ी रही, बीजेपी और जनता पार्टी का राज आया 1989 के अंदर जो है पार्लियामेंट में लागू होने का काम हुआ, इनको सच्ची बात सुनने में क्यों कड़वाहट हो रही है? और मैं अगर कही गलत बोल रहा हूं तो आपका नम्बर आये आप करेक्ट कर लेना, जैसे संयमजी बोल रहे थे हम सुन रहे थे न सारी बात (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज मैंने पहले भी यह बात उठाई है कि जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के साथी कहते हैं कि गंदी बस्ती, कमजोर बस्ती कौनसी है? जिसमें आप देखो सबसे ज्यादा गंदगी मिलेगी, जहां देखो वहां नाली का निर्माण भी नहीं है, सबसे गंदे मोहल्ले के लोग होंगे वो कहेंगे अब कांग्रेस वालों का मोहल्ला आ गया है। अब इनको सच्चाई सुनने में क्यों दिक्कत हो रही है? वो हम लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सदन में बैठे हैं जब

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

तक देश का यही हालात रहेगा हम विश्व में बड़े चौड़े होकर के नहीं चल सकते। यही तो मैंने आंकड़ें बताये हैं कि आज घनश्यामजी को (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दस हजार साल से आपको इस हालत में रखा है इन मनुवादियों ने, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिए आप, माननीय सदस्य...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कांग्रेस ने इन मनुवादियों की जकड़ से बाहर निकाला है आपको (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : आज घनश्यामजी को इतनी स्कूलें क्यों खोलनी पड़ी? अगर इनके राज में गरीबों के यहां ढाणियों में स्कूल खुल जाती तो हमें आवश्यकता ही नहीं होती, आज गली-गली में प्रधान मंत्री अटलजी को घोषणा करके वसुंधराजी और राजेन्द्रजी राठौड़ को पीएमजीएसवाई में सड़कें क्यों बनानी पड़ी? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): शिक्षा पर बोलो ना आप (व्यवधान) कौन बोलेगा शिक्षा पर (व्यवधान) शिक्षा पर बोलो ना आप (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : शहर के बीच के रास्ते (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा)मेरी बात तो बीच में ही उपाध्यक्ष महोदय डिस्टर्ब हो गई, कैसे समाप्त कर दूं मैं? मैं इसे कैसे समाप्त कर दूं मेरी बात को टोका गया (व्यवधान) मैं पांच मिनट में मेरी बात कह दूंगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने पूरा समय ले लिया है

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : मेरे साथी का मैंने टाइम लिया है, मैं कहना यह चाहता हूं इनके राज में शहर में पुल के ऊपर पुल बने, सड़क के ऊपर सड़क बनी, इन्होंने कभी गांव की चिंता नहीं की, अगर सड़कें बन गई होती तो आज अटलजी को पूरे देश में लोग जो है गरीब से गरीब आदमी बैठा भी गुणगान करता, आज हमारे राज्य में 12 किलोमीटर चार गांव एक दिन में जुड़ना, इनके दर्द क्यों हो रहा है? अब ये कह देंगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए आप।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : एक मिनट मैंने कह दिया हमारे साथी का समय लिया है (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर सही बात बता रहे हैं तो आपको कोई खतरा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप शिक्षा पर (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको कोई खतरा लग रहा है इनके बोलने से? एस.सी., एस.टी. के वोट टूट रहे हैं आपके? (व्यवधान) यह एस.सी., एसटी आपके विरूद्ध हो रही है इसलिए आप बार-बार खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : आज हमारे कम से कम (व्यवधान) हमारा काम पेयजल का हुआ है (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हकीकत बता रहे हैं सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : अगर इनके इतने साल के राज में, अगर ये लोग स्कीमें बना देते, तो मैं यह कहता हूं कि सांवरलालजी जाट की हमें स्वीकृति लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आज इनको सच्चाई सुनने में कहां दिक्कत आ रही है? मेरे तो यह समझ नहीं आ रहा है, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं बोल रहा, मैं तो यह कह रहा हूं कि गांव का आदमी जिस दिन शिक्षित हो जाएगा जो क्रांति हमारी सरकार ने लाई है जिस दिन एजुकेशन आ जाएगी, आपकी वही हालत होगी जो शहरों में हो रही है। आज पढ़ा लिखा आदमी इन पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, आज इनका वोट बैंक कहां बच गया है, जहां अज्ञानता है, जहां अशिक्षा है, इसलिए मेरा आग्रह है उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हो, तो यह ऊपर की बातों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा जैसे मेरे शरीर में अगर मेरे हाथ पर लकवा मार गया तो इसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा उसी प्रकार अगर समाज में कोई कमजोर अंग है चाहे वो दलित है चाहे ओबीसी है, चाहे सवर्ण जाति का कमजोर आदमी है यह संविधान में इसलिए व्यवस्था दी गई कि उसको बराबर का लाकर के बराबर का भाई खड़ा करें ताकि हमारे देश में कोई दूसरा आकर के अटैक नहीं कर सके और ये लोग चालीस साल तक षड्यंत्र करके और झूंठ बोल कर राज करते रहे, और जब हम यह कह रहे हैं कि

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

अगर आपके यही हालात रहे तो आप अभी 56 हो ना तो इससे हो सकता है 06 पर आ जाओ इसलिए आपकी आलोचना हम दिन भर सुनते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है आदमी को आंगन में भी निन्दा करने वाला व्यक्ति रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। आपने सब बात कह दी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस बार विधान सभा में न मैं बजट पर बोला हूं न मैं अभिभाषण पर बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप समय का ध्यान रखें माननीय सदस्य।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): मेरा समय भी इनको दे दिया जाए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ...(व्यवधान) मैं तीन चार खरी-खरी बातें इनको कहूंगा। मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं है लेकिन ये जो दिन भर...

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय भी इनको दे दीजिये ये अच्छा बोल रहे हैं इसलिए इनको मौका दीजिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ये दिन भर जो असत्य के आधार पर सदन को गुमराह करते हैं इनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में चिन्तन होना चाहिए और गंभीर मुद्दों पर चिन्ता होना चाहिए कि गांवों की समस्याएं क्या हैं। ये कभी किस मुद्दे को लेकर के, कभी किस मुद्दे को लेकर के छोटी-छोटी बातों में एक-एक घंटा डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके गोविन्दराम मेघवाल जिम्मेदार है? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मैं सचाई की तस्वीर लाना चाहता हूं कि जिस हमारे समाज को बरगलाकर, झूंठ बोलकर राज करते रहे। आज विधान सभा में हमें ताना दिया जा रहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट को किसी ने बोलने का अधिकार दिया है तो कांग्रेस ने दिया है इससे बड़ी हमारे लिए गाली नहीं हो सकती। ये गाली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आप तो चौहान लिखते थे अब मेघवाल कब से लिखने लग गये?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मैं इसलिए लिखने लग गया कि राजपूतों में ताना मारा गया कि चौहान कौन से राजपूत हो, इसलिए मेघवाल चालू किया कि मैं बिलकुल शिड्यूल्ड कास्ट हूं। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ये भी आपको परेशानी है । चौहान लिखा तो भी परेशानी है इसलिए मेघवाल लिखा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजपूत खराब हैं क्या जो आपने नाम बदल लिया?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): नहीं, मैंने नाम नहीं बदला। मैंने कहा कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो ।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): ये सदबुद्धि किसने दी आपको?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ये सदबुद्धि अपन जब लोकदल में साथ ही थे तब उस समय आपने ही दी थी मेरे को।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्षजी, ये लठदल के आदमी रहे हैं । पहली बार आये हैं इसलिए इनको मौका दो और थोड़ा सा।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ये मेरे फेवरेट हैं ये लोकदल में मेरे अध्यक्ष थे और बीकानेर का युवा लोकदल का मैं अध्यक्ष था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब समझ में आ गया गोविन्दजी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा संयमजी, मैं डिस्टर्ब नहीं करता आपको। ...(व्यवधान).

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गोविन्दजी, एक मिनट। आधा मिनट लूंगा आपका। आप जो बोल रहे हैं अब समझ में आ गया आप में बीज जनता दल का है इसलिए आपके ये विचार हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ये बात इन्होंने छेड़ दी तो इसका भी कह दूं एक जो रथ चल रहा था उसकी नेता सोनिया गांधी थीं और दूसरा जो रथ चल रहा था वो अटलबिहारीजी का चल रहा था तो हमने यह तय किया कि अगर जनता दल छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उसी आधार पर हम लोग आये। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी राष्ट्रीयता की कमी है इसलिए हमारा कोई संघ काम कर रहा है और राष्ट्रीयता की भावना, जो जापान छोटा-सा देश है अगर ऊपर से आवाज आती है कि एक दिन पूरे देश

को भूखा रहना है तो उनमें इतनी राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई है कि वो लोग एक दिन भूखे भी रहते हैं इसलिए हमारी जो पार्टी है इसमें राष्ट्रीयता की भावना है । आज ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ये एक नेता पैदा नहीं कर सके जो देश को चला सके । ये दूसरे के भरोसे अपने देश को चलाते हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि मैंने पहले भी कहा हमें छेड़ो मत, हमें अपनी बात कहने दो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रामेश्वर डूडी भी यह बात सुन रहा है जिसकी मेहरबानी से आप इस विधान सभा में आये हो, वो रामेश्वर डूडी भी यह बात सुन रहा है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मेरा आपसे यही आग्रह है कि हमें आज भी पूरे देश में गाली इस बात की पड़ रही है कि दलित और अनुसूचित जाति के इस कांग्रेस को जिन्दा रखने वाले आप लोग हो उसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं फिर भी मैं वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने अम्बेडकर पीठ बनाने का काम किया और एस.टी. की महिलाओं को साइकिल और स्कूटी देने का काम किया। अनुसूचित जाति के होस्टलों में वृद्धि करने का काम किया इसलिए मेरा आग्रह है कि कारवां जो है इन्होंने घनश्यामजी की जो अभी मैं किताब पढ़ रहा था उसमें बहुत अच्छा लिखा उन्होंने कहा है कि शिक्षा में हमने कोई पूर्ण नहीं कर लिया है यह हमारी शुरूआत है इसलिए हमारे साथी ने कहा था कि सामने वाले तो कत्ल कर लेते हैं तो चर्चा नहीं होती, आपने पूरे देश का कत्ल कर दिया। पूरे देश को आपने पूरे विश्व में पछाड़ कर रख-रख दिया। एजुकेशन में, आपने गरीबी में और सबसे अगर ज्यादा बढ़ोतरी की है तो वो भ्रष्टाचार में करवाई है विश्व में पांचवें नंबर पर खड़ा है। हवाला कांड, यूरिया कांड, चीनी कांड, तंदूर कांड जितने कांडों की गिनती आएगी वो कांग्रेस के राज में हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): और इसलिए जनता ने इनको नकारा है इसीलिए शहर के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग इनको वोट नहीं देते इसलिए मैं मेरा आग्रह करना चाहता हूं घनश्यामजी, भगवान आपको और सदबुद्धि दे कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोलें और हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जिस तरह से आपने स्कूलें देने का काम किया है गांव का आदमी जिस दिन पढ़-लिख लेगा तो ऐसे लोग राजनीति में उभर कर वापस नहीं आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, चौहान साहब। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): इसलिए मैं अब मेरी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): इनको बोलने दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मुझे तीन आदमियों का टाइम मिला हुआ है उपाध्यक्षजी।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दिया जाए तीन आदमियों ने समय दिया है इनको।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रामेश्वर डूडी की मेहरबानी से आप विधान सभा में आये हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): रामेश्वर डूडी जैसे हमने पैदा किये हैं राजनीति में। रामेश्वर डूडी जैसे पैदा किये हैं हमने। रामेश्वर डूडी तो उसका बाप मर गया था तब वो प्रधान बन गया था और गोविन्द चौहान पिछले बीस साल से राजनीति में है। माफ करना।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): रामेश्वर डूडी जैसे पैदा किये हैं मैं असेंबली में बोल रहा हूं कोई मैं कोने में नहीं बोल रहा हूं। आप दे देना, फैक्स दे देना मेरे यहां का विधान सभा का। +++ यह ध्यान रख लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, रामेश्वर डूडीजी एम.पी. रहे हैं ये शब्द आप एक्सपंज कराइये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ये जो धमकियां दे रहे हैं राजनीति में ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इन शब्दों को एक्सपंज कराइये।

श्री श्रवण कुमार: ये असंसदीय जो बोल रहे हैं इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या जो बोल रहे हैं आप?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये जो असंसदीय शब्द कहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, वो एक्सपंज कराइये आप।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप बार-बार इनको परेशान मत कीजिये। इनको बोलने दीजिये। आप जब बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): यह गलत टिप्पणी नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डूडी हमारे पास में बैठे हैं इनको तकलीफ क्यों हो रही है?...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): जिस तरह से कहते हैं राजनीति में ही हूं आगे हम रात-रात में पैदा होकर नहीं आये।

एक माननीय सदस्य: नहीं नाम का सवाल नहीं है डूडी का सवाल है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): हम बीस साल से हैं।

श्री श्रवण कुमार: ...(व्यवधान) इसको निकाला जाए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): डूडी आये होंगे तो अपनी गरज से आये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उसके दर्द था । एम.एल.ए. के समय आ गया, क्यों आया, किसने कहा? हमने नहीं मांगा वो चलाकर समर्थन देने के लिए आया था और जो वोट देगा तो क्यों नहीं लेंगे हम लोग।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कनक्लूड कीजिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश और राजस्थान की तस्वीर बदलनी है तो जो घनश्याम जी कर रहे हैं ...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत शब्द हैं उनको निकाला जाए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): जो घनश्यामजी कह रहे हैं हमें उनमें सहयोग करना चाहिए मेरा यही निवेदन है और जिस तरह से हमारी सड़कों का जाल, जो पेयजल स्कीम हम तो कहते हैं कि हमारे मंत्रिमण्डल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने राजस्थान की तस्वीर बदली। आज 11 हजार करोड़ का जो आपने बजट पेश किया है उसके लिए आपको धन्यवाद और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी अच्छे-अच्छे कार्य करती रहे और विपक्ष को भी सदबुद्धि दे कि वो सेन्टर को जाकर समझाये कि जो राजस्थान सरकार कर रही है उसी तर्ज पर केन्द्र भी कुछ कार्य करें इसके साथ ही जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम दो-दो मिनट बोलने वाले हैं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 24...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जाटव साहब, आपने तो समय नहीं दिया उनको?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ... शिक्षा एवं कला संस्कृति पर ... (व्यवधान) भाई सुरेशजी, प्लीज।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम दो-दो मिनट बोलने वाले लोग हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने समय तो नहीं दे दिया था ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां, दे दिया उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया तब फिर आप?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आज आपका बहुत कम टाइम लूंगा। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो हम बाहर चले जाएं?

श्री श्रवण कुमार: समय तो दे दिया था न उन्होंने अपना।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): इस पवित्र सदन में अब तक ऐसे अच्छे विषय के ऊपर जो डिबेट चल रही है यहां शोरगुल हुआ बहुत ज्यादा। आज हमारे सत्ता पक्ष के विधायक भाई मोहन लालजी गुप्ता से चालू हुआ वही टीका -टिप्पणी चालू हो गयी। अब मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं अब रात हो गयी, अब कुछ आपस में तालमेल का, संयमिता का, संयमजी लोढ़ा, आप सबसे निवेदन है कि ये जो विषय है, ये जो सब्जैक्ट है, ये सब्जैक्ट वो शिक्षा का है। शिक्षा क्यों जरूरी है शिक्षा की कहां आवश्यकता है, हमको शिक्षा कहां चाहिए, यह विषय आज की तारीख में है। माननीय उपाध्यक्षजी, मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बातों पर प्रकाश डाल दिया मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा।

(श्री जयराम जाटव)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में सब वक्ताओं ने जो कहा मैं सबसे पहले तो इस प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुंधराजी को जिन शब्दों में धन्यवाद देना चाहता हूं वह शब्द मेरे पास नहीं है । मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय घनश्यामजी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हू । आजादी के 59 साल के बाद डा. भीमराव अंबेडकरजी ने जिस संविधान की रचना की थी उस रचना में शिक्षा को पहला स्थान दिया था और उन्होंने एक सपना संजोया था कि हिन्दुस्तान के अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोग आजादी के बाद में शिक्षित हों, संगठित हो और संघर्ष करें । मैं आज इस बात का इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं अगर अनुसूचित जाति, गरीब दलित वर्ग को शिक्षा के माध्यम से कहीं उस बिन्दु पर, उस छोर पर जहां आजादी के 59 साल बाद में गांव में स्कूल नहीं था और उस डा. भीमराव अंबेडकरजी के हृदय को छू कर अगर किसी ने बात रखी है तो माननीय घनश्याम तिवाडीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है । मुझे याद आ गई जब कांग्रेस का राज था, मैं आलोचना नहीं करना चाहता किसी कांग्रेस के माननीय सदस्य की एक शब्द भी आलोचना नहीं करुंगा । मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके दिल में जो बात निकल कर आ रही है उसको यह मनन करें, झगड़ा ना करें । मुझे याद आ गई जब आज से तीन साल पहले कांग्रेस का राज था एक गांव का बच्चा रो रहा था । उसकी मां ने कहा कि बेटा स्कूल जा तुझे घूघरी मिलेगी । वह पांच दिन तक स्कूल गया छठे दिन वापस आ गया । उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा घूघरी खाने से पेट में दर्द हो गया । यह सत्य बात है और घूघरी की वजह से वह स्कूल बंद हो गया, स्कूल में जाना बंद हो गया । मैं मुख्य मंत्रीजी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीब का बच्चा जब कहता है मां, भूख लगी है क्या खाऊंगा, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिड डे मील के मार्फत बच्चों को स्कूल में जो भोजन दिया जाता है उससे वह दुबारा पढने के लिये जा रहा है । आज शुरूआत है, हमारे रामगढ़ से भाई जुबेरजी आते हैं, हमारा एक जिला है । मेवात क्षेत्र मेरे भी लगता है । अनुसूचित जाति, जनजाति गरीब की गांव में जो 80 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, प्रबुद्ध इसी जाति का है । आज जयपुर में सैकंडरी, सीनियर सैकंडरी स्कूल की कोई जरूरत नहीं है । जोधपुर में आवश्यकता नहीं हैं। आज सैकंडरी, सीनियर सैकंडरी के लिये कोई झगड़ा नहीं कर रहा है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर माननीय मंत्रीगणों के रिप्लाई एवं पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: समय निश्चित करो ना । क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 9 बजे तक के लिये बढाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक के लिये बढाया गया ।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, सहमति तो है पर बीच वालों को भी बुलवाओ नहीं फिर बढ़ाने से क्या फायदा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इसमें आप सब सहयोग करें, 2-2, 3-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जोधपुर के जितने माननीय सदस्य हैं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं जोधपुर, उदयपुर, अजमेर के हैं वह इस बात के लिये झगड़ रहे थे आई.आई.टी., आज राजस्थान के उस गांव में जहां प्राथमिक शालाएं नहीं थीं राजीव गांधी पाठशालाओं में 1200 रुपये में जो अध्यापक लगाये गये थे, किस तरीके की शिक्षा थी । आज चाहे मेवात हो, जनजाति क्षेत्र हो चाहे अनुसूचित जाति का गांव हो जहां शिक्षा का द्वार जो गरीब के घर में, किसान के घर में अगर दीपक जला है तो माननीय वसुंधराजी के राज में और घनश्याम तिवाड़ीजी की सोच में परिवर्तन से जला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं । जब कांग्रेस का राज था तब बी.ए., बी.एड. छात्र थे, जो बेरोजगार घर में बैठे थे कालेज में जाने के लिये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने इच्छा जाहिर नहीं की थी । उन्होंने कहा था नौकरी नहीं मिलेगी, खजाना खाली है और ऐसा हुआ तो लोगों ने बी.एड. करनी बंद कर दी । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी को जिन्होंने राजस्थान में टोटल शिक्षकों की जो भर्ती की जिसको पूरे हिन्दुस्तान में सराया लोक सेवा आयोग के द्वारा और उसमें लगभग 15

(श्री जयराम जाटव)

हजार अध्यापक अनुसूचित जाति के छात्र लगे । जिन लोगों ने आशाएं छोड दी थी, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां लोग अभी जाति पर लड़ रहे थे, हमारे अनुसूचित जाति के लोग न उद्योगपति हैं, न बहुत बड़े किसान हैं । एक परिवार में कोशिश करते हैं कि बच्चे को पढ़ाये और पढ़ाकर कोशिश करते हैं कि इसको नौकरी मिलेगी । कांग्रेस के राज में जब एक नौकरी नहीं मिली और यह बात सत्य है मैं भाई गोविंदजी की इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज में अनुसूचित जाति के लोगों ने नौकरी के लिये आशाएं छोड दी थीं । मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की इस सरकार को, कल्याणकारी सरकार को कि गांव के गरीब को रोजी-रोटी का द्वार मिला है तो वह इस सरकार ने दिया है। आज अच्छी डिबेट है, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं निकालीं शिक्षा के माध्यम से कि 75 प्रतिशत, हमारे जनजाति मंत्रीजी बैठे हैं कल कितना अच्छा भाषण था । इन्होंने कहा कि जो लडकियां 75 प्रतिशत से अधिक जनजाति क्षेत्र में उत्तीर्ण होंगी उसको स्कूटी दी जायेगी । मुख्य मंत्री को कल हमने देखा बहुत अच्छा लगा । उस जनजाति क्षेत्र की लडकियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूटी किसको कहते हैं और उसको स्कूटी दी गई । आज इस तरह की योजनाएं निकाल कर जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज था अनुसूचित जाति के साथ-साथ महिला वर्ग में क्रांति शिक्षा के नाते आई है तो वह वसुंधरा जी के नाते राजस्थान में आई है । वहां आठवीं पास करने के बाद नवीं कक्षा में पढाने के लिये अगर स्कूल 2 किलोमीटर से अधिक दूर है तो उसको 300 रुपये में फ्री साइकल मिलेगी । इस तरह की योजनाएं निकाल कर, कुछ लोग कह रहे थे राजस्थान की सरकार वाह-वाही लूट रही है । केन्द्र का पैसा है, योजनाओं के मद का पैसा है । मैं इस पवित्र सदन में एक बात कहना चाहता हूं हम राजस्थान प्रदेश के वासी कहां के हैं । केन्द्र में योजनाओं का पैसा, विभिन्न टैक्सों के माध्यम से जाता है वह कहां जाता है? हमारे हिस्से का पैसा है हमको किसी ने कोई वो नहीं दिया इसलिए हमको जो पैसा मिलेगा, पहले भी मिलता था लेकिन जो पैसा मिला उसका सदुपयोग हुआ । राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली में राजस्थान में जो तीन साल में पैसा मिला वह व्यय हुआ है । आज शिक्षा की जो बहस चल रही है इस बहस के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और पुरजोर शब्दों में इस बात के लिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना

(श्री जयराम जाटव)

चाहता हूं। मैं अभी यह किताब पढ़ रहा था उसमें हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया हमारे राजस्थान के सपूत ने 'सर्व शिक्षा अभियान' के माध्यम से, कई लोग कह रहे थे पाकिस्तान, बांग्ला देश के लोग भी फर्स्ट आये । राजस्थान का सपूत जिसको 12वें, 13वें स्थान पर विकास की दृष्टि से गिना जाता था, 'बीमारू' प्रदेश के नाम से जाना जाता था आज राजस्थान का शिक्षा मंत्री बाहर के देश में जाकर हिन्दुस्तान में पहले नंबर पर लाया । इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या होगी? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि योजनाओं के माध्यम से पहले पैसा मिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगा कि यह सब लोग जानते हैं और पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिए आज जो हमारी मुख्य मांग, शिक्षा के विषय में लंबी चौड़ी चर्चा हुई उसके लिए, चाहे वह किसी तरह की हो, हमारे बीच में मोबाइल बंद करने की बात हो...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, अब आ गई बात।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक-दो बात कहूंगा अपने क्षेत्र की। उपाध्यक्षजी, एक बात कहूंगा मात्र। लंबी चौड़ी बात कतई नहीं कहूंगा। जो बात कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। ग्रामीण अंचलों में पीने के लिए पानी नहीं था, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं था। आज मैं यह कह रहा हूं सारी सुविधाओं से अगर यहां राजस्थान में शिक्षा का द्वार खुला है तो इस राजस्थान में बी.जे.पी. के इस राज में खुला है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात न कहकर अपने क्षेत्र की छोटी सी मांग, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैंने देखा जब कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उधर था कि जो हमारे महत्वपूर्ण सुझाव यह माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य दे रहे हैं उनको शिक्षा मंत्रीजी अपने पेन से लिख रहे थे।

कई लोगों ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपका ऐसा स्वागत करेंगे, इस तरह का धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे, रंगोली बनाएंगे, वेलकम लिखेंगे, स्वागतम् लिखेंगे, हमको सैकण्डरी स्कूल दे देना, कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे, कांग्रेस के सदस्य इसलिए कह रहे थे कि पहले एक वर्ष में कभी 1500 माध्यमिक विद्यालय खुले राजस्थान में, पहली बार खुल रहे हैं। 600 उच्च माध्यमिक विद्यालय पहली बार खुल रहे हैं। यह दिमाग की उपज है। दिल में जो इच्छा शक्ति ठानी है, जो लक्ष्य तय किया था, पांच साल में जो

(श्री जयराम जाटव)

हमारा लक्ष्य, कारवां चला है माननीय गोविन्दजी कह रहे थे, अभी चालू हुआ है, आगे बढ़ेंगे।

आई.आई.टी. कालेज का जो झगड़ा था, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं अलवर जिले का हूं, जयपुर और दिल्ली के बीच में अलवर बसता है यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा, अलवर में खोल दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मेरी जो मांग थी वह राजकीय विद्यालय, खैरथल की मांग थी। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करके, मुख्य मंत्रीजी से, अपने क्षेत्र में, जो पिछड़ा क्षेत्र रहा है, कांग्रेस के राज में कई मंत्री वहां रहे, आज भी ग्रामीण अंचल में मैवात में स्कूल नहीं है। मुख्य मंत्रीजी गईं, एक बार लास्ट में धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उस मैवात अंचल में मैवात विकास बोर्ड के माध्यम से जो आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, वहां जमीनों की व्यवस्था करा रहे हैं, वहां आवासीय विद्यालय खुलेंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यह प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): वहां मुसलमानों की लड़कियां पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, इस सबके लिए पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लिए किसी ने कोई टोका टिप्पणी नहीं की सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जितेन्द्र सिंहजी।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 के ऊपर मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनिट से ज्यादा बोलते भी नहीं हैं, आप ज्यादा नहीं बोलते, जितेन्द्र सिंहजी ज्यादा नहीं बोलते।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): जो बात कहने वाली है वह तो (व्यवधान) वह ट्रेड यूनियन के भाषण दे रहे थे आप सुन रहे थे उनकी। (व्यवधान) जो बोलना था उसको बोलने नहीं देते, नहीं बोलना था उनको बुला रहे हो, आपका भी अजीब काम है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांइटेडली दो बात रखूंगा। आरोप-प्रत्यारोप, किसने क्या किया, कितना किया, कितनी स्कूल खोली, नहीं खोली उसके ऊपर बहुत सारी सदन में चर्चा हो चुकी है, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ही सक्षम, बहुत ही जिनके

तारीफों के पुल बंध रहे थे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं हमारे, लेकिन पक्षपात जरूर करते हैं यह। ऐसा पक्षपात करते हैं कि जहां कांग्रेस का विधायक है वहां एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोलते, वहां एक सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलते, एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलते।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा तो नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो अलवर जिला है वह हर-दम उपेक्षित रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स का रेवेन्यू अलवर से आता है। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के अंदर अलवर है। कनेक्टिविटी के रूप में अलवर जयपुर और दिल्ली के बीच में हैं। रेल से कनेक्टेड है, तीन-तीन नेशनल हाइवे से कनेक्टेड है लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट खुलता है, कोई भी इंजीनियरिंग कालेज खुलता है, कोई भी यूनिवर्सिटी खुलती है, कुछ भी होता है तो वह या तो खुलती है झालावाड़ के अंदर या होती है कोटा के अंदर या होती है जोधपुर के अंदर या अपने-अपने, मंत्री जो भी हैं वह अपने-अपने क्षेत्रों के अंदर लेकर जाते हैं। मैं तो सीधी, अलवर और अलवर का जो मत्स्य इलाका है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली, उस इलाके के हमारे साथी और भी विधायक हैं इन पाँच जिलों के, उनकी तरफ से मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि बहुत सालों से डिमांड चल रही थी अलवर में एक विश्वविद्यालय खोला जाए उसका नाम मत्स्य विश्वविद्यालय रखा जाए। विश्वविद्यालय खोलने के लिए माननीय मंत्री महोदय कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिये। चाहे ठीक है पक्षपात आप कर लेना, आपके भी बहुत सारे विधायक हैं,मंत्री भी है, अलवर से नहीं तो भरतपुर से तो हैं। एक क्राइट एरिया होता है, सिर्फ राजनीतिक क्राइटेरिया नहीं होता, एक क्राइटेरिया भी होता है। आप उसके अंदर देखते हैं कि कितनी वहां की जनसंख्या है, कितने कालेज है वहां। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं सिर्फ अलवर की बात कर रहा हूं भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली की बात नहीं कर रहा। केवल अलवर के अंदर 30 लाख की जनसंख्या है, 9 सरकारी कालेजेज हैं, 3 नर्सिंग कालेजेज हैं, 3 इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, 1 एस.टी.सी. कालेज, 1 होम्योपैथी कालेजेज है,3 नोन लॉ कालेजेज और 30 प्राइवेट कालेजेज हैं तो इससे अच्छा उपयोग,जगह कौनसी हो सकती है। अभी खैरथल से आने वाले सदस्य बात कर रहे थे मैवात की, मैवात विकास बोर्ड बना रखा है, पैसा अलोकेशन होता है, तो कभी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आपने सोचा मैवात की बच्चियों के लिए, मैवात क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए कभी कोई बात रखी, आपने सोचा ?

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन्डीपेंडेंस के बाद जब अलवर का विलय हुआ, मत्स्य का विलय हुआ, मत्स्य हो गया था, पूरा अलग बन गया था तो जब उसका विलय हुआ तो उस समय वादा करा गया कि अलवर के अंदर कोई इन्स्टीट्यूट, कोई इतना बड़ा कालेज, कोई यूनिवर्सिटी दी जाएगी लेकिन 60 साल के अंदर उसका भी ध्यान नहीं रखा गया।

इसके साथ-साथ एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान से एक डिमांड चल रही है आई.टी.आई. की। सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय आपने कभी सोचा कि आई.टी.आई. की जरूरत ही क्या है, एक क्राइटेरिया होता है। आई.टी.आई. सिर्फ कोई मंत्री का इनफेश्युल आदमी होता है उसके लिए आई.टी.आई. नहीं होती है। आई.आई.टी. खोलने के लिए बहुत इम्पोरटेंट है लोकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। उसके लिए पानी उपलब्ध है या नहीं उसके लिए होता है। सबसे इम्पोर्टैं जो बात है, सबसे जरूरी बात होती है वह है इण्डस्ट्री की, आई.टी.आई. और इण्डस्ट्री दोनों का एक तरह से चोली दामन का साथ होता है, एक तरह से जुड़ी हुई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर की कनेक्टिविटी अच्छी कनेक्टिविटी कोई हो ही नहीं सकती, राजस्थान का सिंघ द्वार है। एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है। 500 एकड जमीन का आपने क्राइटेरिया बना रखा है वह उपलब्ध है, अलवर के अंदर खुशखेडा, भिवाड़ी, नीमराना, शाहजहांपुर, बहरोड, इण्डस्ट्री एरिया है और इसके आस-पास सिर्फ अलवर में ही नहीं अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनूं, धौलपुर, सवाई माधोपुर को इसका फायदा होगा।

मैं आपसे इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इण्ड्स्ट्री इसलिए जरूरी होती है आई.टी.आई. के साथ कि आजकल बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज, बड़े-बड़े इण्डस्ट्रीज हाउसेज सीधा आई.टी.आई. के कैम्प्स में जाकर सलेक्शन कर लेते हैं उसकी बहुत जरूरत होती है। खासतौर से यह इण्ड्स्ट्री सपोर्ट दे सकती है आई.टी.आई. को। मुझे तो यह लगता है और मेरे साथी विधायकों

को यह लगता है कि अलवर से ज्यादा उपयोगी कोई ऐसा स्थान राजस्थान के अंदर नहीं है। आप जोधपुर की बात करें वहां आपने यूनिवर्सिटी खोल रखी है, बीकानेर की बात करें दुनियाभर के इंजीनियरिंग कालेज खोल रखे हैं लेकिन अलवर को आज तक कुछ भी नहीं दिया। और किसी भी क्षेत्र के अन्दर नहीं दिया। कोई भी रोड की बात करें तो अलवर के अन्दर नहीं होगी। आपने तो शायद इस तरह का एक माहौल बना रखा है। इस तरह का शायद, मुझे पता नहीं कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि अलवर के अन्दर, कोई रोड बनता है तो अलवर के अन्दर नहीं बनेगा। आप स्कूल अपग्रेड करते हैं तो अलवर में नहीं होगा। कोई भी योजना लेकर आती है सरकार तो अलवर का नाम तो सबसे पहले कट जाता है।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अलवर नहीं, मत्स्य प्रदेश में कुछ भी नहीं करेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मत्स्य की बात नहीं है। अलवर, मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं और मत्स्य आई.आई.टी. की बात कर रहा हूं। इसके अन्दर एक जिले को फायदा नहीं देने वाले हैं, आप आस-पास के 5 जिलों को फायदा देने वाले हैं, आसपास के राज्यों को फायदा देने वाले हैं। हरियाणा और यू.पी. का बार्डर हमारे साथ लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह सब बातें, आपकी राजनीतिक बातें और पक्षपात की बातें छोड़कर आप अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय और आई.आई.टी. की स्थापना करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीतमल खांट, शार्ट में ही।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शार्ट में ही बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति, इस पवित्र सदन में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं और सभी माननीय सदस्यों ने हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का अपने-अपने मुखारविन्द से भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मैं सारे आंकड़ों के बारे में, सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी है। मैं सबसे पहले विद्वान शिक्षा मंत्रीजी का और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को जो पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में बांसवाड़ा के अन्दर जो पहला तोहफा दिया, मैं उसके

(श्री जीतमल खांट)

लिये धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 1908 के अन्दर मानगढ़ की पहाड़ी पर सन्त गोविन्द गुरु के नाम से एक महान सन्त पैदा हुए। सन्त गोविन्द गुरु महाराज, आपको याद होगा, हमारे राजस्थान और पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात जहां पर सन्त गोविन्द गुरु के हजारों नहीं लाखों अनुयायी, उनके शिष्य हैं और 1908 के अन्दर उस मानगढ़ की पहाड़ी पर आजादी की मांग को लेकर डेढ हजार आदिवासियों को वहां पर इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला शंखनाद किया। वह जगह मानगढ़ की धरती और उस सन्त गुरु गोविन्द को सभी ने 1908 का मामला, आज दिन तक किसी ने याद नहीं किया लेकिन राजस्थान की सरकार, वसुन्धरा राजेजी और शिक्षा मंत्रीजी ने संयुक्त प्रयास से बांसवाड़ा कालेज का नाम सन्त गोविन्द गुरु के नाम पर राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा रखा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके जस्ट बाद में, 59 साल हो गये, कुशलगढ़ क्षेत्र हमारा शुरू से ही अपोजिशन का, जनता दल हो, जनता पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, आजादी से लगाकर अब तक कुशलगढ़ के अन्दर एक बार का इलेक्शन छोड़कर के, अब तक जनता दल या सोशलिस्ट पार्टी जीतती रही। कभी कालेज नहीं खोला लेकिन भैरोंसिंहजी के कार्यकाल में, जो आज महामहिम उप राष्ट्रपतिजी हैं, उनके कार्यकाल में वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोला और वर्तमान सरकार के प्रयासों से उस कालेज का नाम रखा मामा बालेश्वर दयाल, जिसके लिये इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

तीसरा महाविद्यालय जो कन्या महाविद्यालय, यह भी कहने से मैं नहीं भूलूंगा कि कन्या महाविद्यालय जो हमारे बांसवाड़ा जिले के सिरमौर, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में उस महाविद्यालय का नाम भी हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय का नाम देकर बांसवाड़ा का ही नहीं, राजस्थान में बांसवाड़ा के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मैं इन महापुरुषों का इसलिये जिक्र करना चाहूंगा कि आज माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारा देश धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक ढंग से, इस पूरे देश के अन्दर रहने वाले सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों का यह देश है।

(समय : 20.15 बजे)

(श्रीमती सुमित्रासिंह, अध्यक्ष पदासीन)

(श्री जीतमल खांट)

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सन्त गुरु गोविन्द और मामा बालेश्वर दयाल जैसे सन्त इस धरती पर अवतरित नहीं होते, इस दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके में पैदा नहीं होते, उनकी कर्म-भूमि नहीं बनती तो आज हम जो आदिवासी हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारे जो मूल्य और सिद्धान्तों को लेकर के, हमारी आदिवासी जो परम्परा, आदिवासी का जो अस्तित्व है, हम जीतमल खांट नहीं, कोई डेविड और कोई रोबिन होते। इसलिये उस इलाके के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मध्य प्रदेश व गुजरात का जो इलाका है, आज यह सारा का सारा इलाका ऐसे महान पुरुषों के सहयोग से उनकी कर्म-भूमि से वहां के आदिवासियों को ऐसी दिशा देने का काम किया जो हजारों साल बीतने के बाद में हमारे आदिवासी लोगों को इस तरह के संस्कार दिये जो संस्कार अनवरत रूप से चलते रहेंगे और हम सब को राष्ट्र की मुख्य धारा में बढ़ाने का काम ऐसे महापुरुषों के प्रयासों से हुआ है इसलिये मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात, आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन आज सवेरे-सवेरे अपोजिशन का एक अच्छा-खासा, जाना-माना नेता हमारे पास में आया, बैठकर चर्चा हो रही थी। वह कहने लगा कि कहने में तो इस बजट का विरोध मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री को वाकई धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं 20 साल से यह बजट पढ़ता रहा हूं लेकिन ऐसा बजट, वाकई में वह अपने-आप में यशस्वी हैं, वाकई हिम्मत वाली हैं और महिला होने के नाते भी पूरे राजस्थान में, दिल्ली की सरकार सहयोग करे, न करे, लेकिन अपने-आप में कोई ताकत रखती है, यह उनके शब्द थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान.. (व्यवधान) ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मिड-डे मील वगैरह की काफी सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन जो बांसवाड़ा जिले के अन्दर, शिक्षा ही जीवन है, हमारे कुछ साथियों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात कही है। मैं भी आपके माध्यम से कुछ जिले की बात को लेकर के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले के अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूल टोटल 68 हैं जिनमें प्रिंसिपल के 7 पद वेकेण्ट चल रहे हैं और यह लम्बे समय से चल रहे हैं। सैकण्डरी स्कूल

(श्री जीतमल खांट)

84, जहां पर 37 पोस्ट वेकेण्ट चल रही हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के अन्दर 640 प्रधानाध्यापक की पोस्टें हैं जिनमें से 122 पोस्टें वेकेण्ट चल रही हैं। ठीक उसी तरीके से तृतीय वेतन श्रृंखला के अन्दर कम से कम 2200 पद वेकेण्ट चल रहे हैं। तो यह तो आपकी विद्वता का एक प्रमाण है कि पिछली बार भी और इस बार भी उस ट्राइबल सब प्लान के इलाके के अन्दर जो गरीब के घर में जन्मा हुआ उस बालक को आपने एक बहुत बड़ी ताकत और सहारा देने का काम किया है। मैं इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन साथ में कुल मिलाकर बांसवाड़ा जिले के अन्दर जो किसी, हमारे प्रतिपक्ष के जो साथी हैं, वे भी पिछली बार राज में थे लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो साक्षरता का आन्दोलन चला उस समय राजस्थान का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के उपराष्ट्रपति भैरोंसिंहजी के कार्यकाल में पूरे राजस्थान में साक्षरता का आन्दोलन चला और उस आन्दोलन का परिणाम यह सामने आ रहा है कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर हायर एजुकेशन से लगाकर प्राइमरी एजुकेशन तक छात्र और छात्राओं का 5 लाख का आज की तारीख में, वे अध्ययनरत हैं जिसमें से ... (व्यवधान) एनरोलमैंट नहीं, पहली क्लास को छोड़कर, पहली क्लास को नहीं जोड़ रहा हूं। यह सिर्फ यू.पी.एस., निजी यू.पी.एस., सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी इन सारे आकड़ों को जोड़ते हैं तो 3 लाख का हमारा ग्राफ जाता है और पी.एस. को जोड़ते हैं तो 5 लाख तक पहुंचता है तो यह बांसवाड़ा जिले के लिए निश्चित रूप से यह कहना चाहिए और हम सब के लिए गर्व है कि किसी समय यह आकड़ा डेढ़ लाख से दो लाख पहुंचता था उसकी जगह पाँच लाख तक यह इतना एनरोलमैंट होना, बांसवाड़ा जिले के लिए और बांसवाड़ा जिला शिक्षा के क्षेत्र में एक कलंक था। गरीबी के नाम पर कलंक था। आज मैं यह कह सकता हूं कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर माननीय शिक्षा मंत्रीजी एक-एक परिवार से पाँच-पाँच, चार-चार और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने जो मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महा-अभियान अब चलाया जिसके माध्यम से जनता में काफी और जागरूकता आयी और उसी का परिणाम है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ हमें रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट के अन्दर मेरी बात समाप्त करूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, जिस तरीके से हमारे ट्राइबल सब प्लान की जितनी बालिकाएं हैं उनको निश्चित रूप से साइकल वितरण किया है, ठीक उसी प्रकार से आपने कम्प्यूटर की फीस भी माफ की है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप साइकल वितरण करें या नहीं करें लेकिन एक-एक परिवार से पांच-पांच, चार-चार बच्चे जो 9वीं क्लास से लगाकर 12वीं क्लास के बीच सारे अध्ययनरत हैं एक परिवार से, जब कम्प्यूटर की फीस का जहां सवाल आता है। सब के बीच में तकलीफ का और वह जुलाई का समय आता है जब जुलाई के अन्दर बोने का समय आता है और ऐसे माता-पिता को तीन-तीन बच्चों की कम्प्यूटर फीस जमा कराना यह हम सब के लिए तकलीफ का विषय है। आप इस पर विचार करेंगे।

मैं दूसरी एक बात कहना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं के अन्दर बांसवाड़ा जिले के अन्दर निजी शिक्षण संस्थाओं के अन्दर 53 हजार छात्र निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 53 हजार में से बड़ी मुश्किल से तीन या चार हजार बच्चे जनरल क्लास/आबालिग कॉस्ट के होंगे बाकी टोटल ही यह शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कॉस्ट के हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो शिक्षण संस्थाएं, ऐसी कौनसी शिक्षण संस्था है, आप उनकी तहक़ीक़ात करवायें और वहां के मिड डे मील का, ऐसे बच्चों को अगर इसका लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से आप प्रयास करें। जिसमें मैं एक संस्था का नाम बता दूं। एसोसिएशन फार सर्व सेवा अभियान, जो ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति के माध्यम से कम से कम इस विद्यालय में, इन संस्थाओं में पांच हजार शत-प्रतिशत ट्राइब्स के बच्चे हैं जो निजी शिक्षण संस्थाओं में यह अध्ययनरत हैं। आज छोटे बच्चों की हमेशा यह लालसा रहती है कि सरकारी स्कूलों में जब वे पहुंचते हैं तो हमें वहां पर यह सुविधा मिल रही है और निजी शिक्षण संस्थाओं से यह वंचित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर भी आप विचार करेंगे। साथ ही एक बात और कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। यह माननीय शिक्षा मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में कर रहे थे समाप्त।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जहां तक मिड डे मील का बनाना और उसके रख-रखाव, निश्चित रूप से इसमें शिक्षकों का

(श्री जीतमल खांट)

मामला थोड़ा गडबड़ होता जा रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि मिड डे मील बनाकर उसका उचित रख-रखाव और उसका भोजन कराने की व्यवस्था के लिए एक चपरासी की नियुक्ति आप अस्थाई रूप से, कांट्रेक्ट बेसिक पर किसी भी तरीके से लेकिन एक चपरासी की आप नियुक्ति करें वरना स्थिति क्योंकि किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं या मिडल स्कूल में चले जाएं एक भी जगह चपरासी नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों का जो शिक्षा का काम है वह प्रभावित हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्तिम एक बात और कह दूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो दो मिनट में बात समाप्त कर रहे थे।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मान्यवर, एक ही मिनट में। जो एस.डी.एम.सी. के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप राजस्थान का नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के सारे शिक्षाविदों का आप नेतृत्व करते हैं लेकिन एस.डी.एम.सी. के लोग जानते ही नहीं हैं। कहां एस.डी.एम.सी. है? कहां क्या चीज खरीद कर दे रहे हैं और दो अध्यापक बिलकुल उसके पीछे लगे हुए हैं। एक तो हमारे प्रधानाध्यापकजी और दूसरा है सचिव। कहां तो बजरी खरीदनी है, कहां रेत लानी है, कहां ईंट भाटा लाना है और यह सारी की सारी आप अपना सुझाव रखें भारत सरकार को और कहें और कहीं न कहीं हमारे उन नियमों के अन्दर संशोधन करें और कहें कि यह, आप इसका कोई न कोई बैठकर दूसरा कोई विकल्प ढूंढें वरना यह स्कूलों के अन्दर जो पढ़ाने का काम है उसकी बजाए यह सारा जितना भी भवन निर्माण में यह सारे अध्यापक कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कृपया जवाब दें। 8 बजकर 26 मिनट हो गये हैं। 8 बजकर 26 मिनट हो गये हैं। एक घंटा माननीय मंत्रीजी का जवाब में हो जाएगा। 9.30 बज जाएंगे। .(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने कम लोग बोलें हैं ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दिया जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): दो-दो मिनट दी जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने कम लोग बोले हैं इतनी महत्वपूर्ण मांग के ऊपर। कहीं तो चालीस-चालीस मिनट तक बुलवाया गया आसन से और कहीं दस मिनट में भी ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी है। हमारी पार्टी की ओर से हमें भी बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमें भी बोलने का मौका दें। ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। तीन-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): श्रवणकुमारजी आज तक नहीं बोलें। मंगलारामजी नहीं बोलें। नन्दलालजी पूनिया नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दो बार बोल चुके हो। नो-नो ।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। हमारी पार्टी की ओर से हमारा भी दस मिनट है। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतने टाइम तक बोले हैं। तीस-तीस मिनट तक बोले हैं। तीन-तीन मिनट हमें भी बुला दीजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसी क्या जल्दी है?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप रात को ग्यारह बजे तक चलाते हो। न्यायपालिका का समय तो ... (व्यवधान) ग्यारह बजे तक आप चूरू और सीकर जिले का ... (व्यवधान) झुंझुनूं, चूरू और सीकर के लिए तो आप ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। तीन-तीन मिनट में। कल भी हम मांग पर नहीं बोले थे। कल भी हमारा नम्बर नहीं आया था। आज तो तीन मिनट का समय दीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया गया है, आप बुलवाइये माननीय सदस्यों को। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): हम भी अपने क्षेत्र की बात कह दें उसके बाद जवाब हो जाए। आपकी परमिशन हो जाए तो ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हमें भी बोलने का समय दिया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चार माननीय सदस्य बोले हैं कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ चार ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपका आदेश शिरोधार्य है। आपका आदेश शिरोधार्य है। कल भी मांग पर हम नहीं बोले थे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): XXX

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): XXX

श्री सुरेश मीणा (करौली): XXX

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): XXX

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस पार्टी का सारा समय संयम लोढ़ा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ले लिया आज ... (व्यवधान) यह पहले बात तय हो गयी थी। यह तय हो गयी थी बात। सब का, दोनों का समय बांट दिया जाए। सत्ता पक्ष का समय भी बांट दिया जाए और प्रतिपक्ष का भी बांट दिया जाए। प्रतिपक्ष का समय सारा ले लिया संयम लोढ़ा ने। संयम लोढ़ा ने ले लिया, अब मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या कर सकती हूं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): XXX

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): XXX

श्री सुरेश मीणा (करौली): XXX

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): XXX

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): XXX

श्री हरीसिंह रावत (भीम): XXX

श्री अध्यक्ष: 8 बजकर 29 मिनट हो रही है। आसन की जिम्मेदारी है अनुशासन की ... (व्यवधान) हां, तो ... (व्यवधान) नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य रोज बोलती हैं और आपका नाम भी नहीं है और आप रोज बोलती हैं। आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा आज। अंकित नहीं किया जा रहा है आपका। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): XXX

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप तो उदारमना है, दो दो मिनट दे दें। आप नौ बजे करा दें अध्यक्ष महोदय। नौ बजे करा दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री अध्यक्ष: पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी माननीय सदस्य, दो मिनट नहीं, पाँच मिनट में भी नहीं मानता है। आप क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): XXX

श्री अध्यक्ष: आप रोज बोलती हैं, आप बैठें।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): XXX

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठ जायें। (व्यवधान) आप बैठ जायें। आप रोज बोलते हैं। आप बैठिये तो सही। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घड़ी की सुई के साथ पाँच मिनट का समय दे दें। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री अध्यक्ष: दो दिन तो मैंने आपको मौका दिया है। अब आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद): XXX

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : XXX

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, नवलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या, प्लीज बैठ जायें आप। (व्यवधान) प्रोटेक्शन आपको रोज देती हूं, अब बैठ जायें। रोज दे रही हूं आपको मौका, बैठ जायें। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष: बैठें आप चुपचाप। (व्यवधान) रोज बोल रही हैं दो दिन से और आप फिर खड़ी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष: अच्छा अधिकार, बड़े अधिकार आये। श्री श्रवण कुमार।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष: हां, आसन को अधिकार है मनमानी करने का ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर रही हूं न । ..(व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आसन का सम्मान करना माननीय सदस्या का कर्तव्य है। उन्होंने जो कुछ कहा लड़ाई के बारे में, उसे एक्सपंज करें अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पहली बार आई हैं। इन्हें न तो नियमों का ज्ञान है, न नियमों व परम्पराओं का ज्ञान है, न सदन की गरिमा का ख्याल है । पहली बार आई हैं इसलिए कह दिया होगा उन्होंने। अब आगे चलिये श्री श्रवण कुमार।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : XXX

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह राजस्थान विधान सभा है, ..(व्यवधान) यह राजस्थान विधान सभा है थोड़ा ख्याल रखिये कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को सिखायें आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आज मांग संख्या 24 पर निवेदन कर रहा हूं। सुबह से बहुत सारी बातें हो रही थीं मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं इस बात की लड़ाई में नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या किया। "चिंता शरीर शोषणम्, मातृ शरीरम् पोषणम्, विद्या शरीरम् आभूषणम्" चिंता से बड़ा शरीर का कोई शोषण करने वाला नहीं, मां से बड़ा कोई पोषण करने वाला नहीं और विद्या से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। मां सरस्वती, मां पर बात कहना चाहता हूं, सरस्वती मां के लिये कहा - 'मां तेरी उपमा चाँद से करूं, नहीं । कहा, मां चाँद में दाग है, तू पवित्र है । कहा मां, मेरी उपमा सूरज से करूं। बोला नहीं मां, सूरज गरम है तू ठंडी है । कहा मां तेरी उपमा समुद्र से करूं, नहीं मां, समुद्र का पानी खारा है तू मीठी है। इसलिए मां सरस्वती अपने आप में मां है, इसलिए किसी को इसके ऊपर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। मां सरस्वती पर कोई आक्षेप लगाता है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके बराबर भी यहां कई हैं। शिक्षा मंत्रीजी, आपसे विद्वान भी यहां कई बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह संत श्रवण कुमार बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संत श्रवण कुमार ।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह बात को श्रवण कुमार ही बोल सकते हैं।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अगर सरस्वती मां पर कोई आक्षेप लगाता है मैं समझता हूं वह पवित्र सदन का सदस्य नहीं है। सरस्वती के भण्डार की बात है 'ज्यों-ज्यों खर्चे, त्यों-त्यों बढ़ें बिन खर्चे घट जाये।' मैं बोलकर बताना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आज तो कमाल कर दिया । बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे पहले जब आप अंदर बैठे थे कोई मेवात से, कोई अलवर से, कोई भरतपुर से, कोई बाड़मेर से, कोई जैसलमेर से, कोई सिरोही से, कोई पाली से आने वाले लोग कह रहे हैं साहब कोई क्राइटेरिया है क्या आई.आई.टी. खोलने का, तब मुझे बड़ी वेदना और पीड़ा हो रही थी कि आज घनश्यामजी जैसे शिक्षाविज्ञ प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में मैं कहना चाहता हूं झुन्झुनूं जिला नम्बर वन है। सुनिये कैसे है, मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आपको लोहा मानना पड़ेगा झुन्झुनूं का।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आज राजस्थान के अंदर जो शहीदों की संख्या है, जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और उस करारी सर्दी में गोलियां चल रही थीं और सीने में गोलियां कौन खा रहा था, झुन्झुनूं का शहीद खा रहा था और 33 प्रतिशत शहीद कौन हुए, झुन्झुनूं जिले के लोग हुए और उन लोगों से आज ...

श्री मुरारीलाल मीणा : आई.आई.टी. वाला शहीद नहीं होता । (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): बैठो-बैठो, सुन तो लो पहले।

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दें। बीच में नहीं बोलें आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं इस बात की पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं उससे पहले तो चिल्लपों शुरू कर दी। क्या आई.आई.टी. के लिये मैं पकड़कर साइन करवा रहा हूं ? मैं मेरी भावना को अवगत कर रहा हूं। अगर 33 प्रतिशत शहीद होते हैं तो झुन्झुनूं जिले के होते हैं। शिक्षा में भी अग्रणी है । झुन्झुनूं जिले में अगर आपको बाड़मेर के अंदर सूई लगाती कोई महिला मिलेगी तो झुन्झुनूं जिले की नर्स मिलेगी। अगर किसी बच्चे का हाथ पकड़कर पट्टी पर पढ़ाती नजर आयेगी तो झुन्झुनूं जिले की महिला मिलेगी। अगर कोई कम्पाउंडर मिलेगा झुन्झुनूं जिले का मिलेगा। उसके बाद आप आइये गेम्स पर। अगर हिन्दुस्तान के किसी कोने में खेलने जायेगा तो झुन्झुनूं जिले का जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलो। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अगर उसके बाद प्रतिशत को तय करते हैं तो आज चित्तौड़ के अंदर सैनिक स्कूल खुली हुई है, अगर चित्तौड़ के अंदर दो प्रतिशत भी सैनिक हों तो इस बात को मैं एग्री करने को तैयार हूं। झुन्झुनूं जिले में न सैनिक स्कूल है, न आई.आई.टी. है, न मेडिकल कालेज है, न इंजीनियरिंग कालेज है। इससे बड़ी उपेक्षा और क्या चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्षजी भी झुन्झुनूं जिले के हैं और केन्द्र में मंत्री भी झुन्झुनूं जिले के हैं।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हम लोग पढ़ना नहीं जानते थे तब हमारी अध्यक्षजी पढ़कर आई थीं। इस बात का कोई आकलन नहीं कर रहा हूं मैं। मैं यह कहना चाहता हूं जिस जिले के अंदर प्राइवेट स्कूल बिड़लाजी की है उसमें

बिहार का लड़का पढ़ता है, मद्रास का लड़का पढ़ता है और उसके अंदर शिक्षा के लिये पचास हजार रुपये लगते हैं, जो गरीब व्यक्ति बियर नहीं कर सकता।

श्री कालीचरण सर्राफ : उसमें हिन्दुस्तान के लोग पढ़ेंगे, झुन्झुनूं जिले के नहीं पढ़ेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): झुन्झुनूं जिले में शिक्षा की बात करते हैं। (व्यवधान) जयपुर में बहुत हैं। बैठ जाओ, जयपुर तो शिक्षा में अग्रणी है।

श्री अध्यक्ष: इनकी भी बात सुनो आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यह सुनना नहीं चाहते, तकलीफ है। आई.आई.टी. पर साइन हो रहे हैं न झुन्झुनूं जिले के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं जो जिला हर चीज में अग्रणी है, उसको आज तक क्या मिला ? आपस की लड़ाई से हमारा जिला पीछे रह गया । आज झुन्झुनूं जिले के अंदर कुछ नहीं हुआ।

श्री कालीचरण सर्राफ : लीडर आफ अपोजिशन आपको मिल गया, सेंटर में मिनिस्टर आपका और क्या लेओगे ?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ठीक है, अख़बार में आ जायेगा। मैं कह दूंगा अख़बार वालों को। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं-नहीं, इसके लिये श्रवण कुमार जैसों के दिमाग में जब उपज जावे, जणा जोगी हो जावे तो आज ज्ञानी हो रह्या हो थे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हमारा ज्ञान प्रदर्शित करने के लिये कभी आप टाइम ही नहीं देते हो तो बोलेंगे कहां से ? मैं यह कहना चाहता हूं माननीय घनश्यामजी, आज प्राइवेट स्कूल के अंदर तो पूरी व्यवस्थाएं हैं। कुर्सी भी है, दरी भी है, टेबिल भी है, गरीब का बेटा जब स्कूल में पढ़ने के लिये जाता है, मैं स्कूलों में जब चैक करने जाता हूं तो गरीब का बेटा नीचे मिट्टी में खेलता है। दरी आपने कब खरीदी ? स्कूल के अंदर जाते हैं नवीं, दसवीं क्लास का बच्चा, नीचे बैठा है। इस बात के लिये जब तक दिमाग में सेंट्रलाइज नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करेगा ? वह बच्चा मिट्टी के अंदर लेट-लेटकर वापस आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट की बात करते हो और हिन्दुस्तान के अंदर आप इंटरनेट पर जाकर चाँद पर जाना चाहते हो और आज गरीब का बेटा मिट्टी में

(श्री श्रवणकुमार)

बैठा है। इससे बड़ी दु:ख की बात और क्या हो सकती है, आपने कभी सोचा है ? आपके दिमाग में कभी आई क्या यह बात ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब आई है। कहते ही आई है।

श्री अध्यक्ष: आपने इनको सोचने को बाध्य कर दिया है ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप यह कह रहे हो अध्यापकों की संख्या मैंने पूरी कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं आज गांवों के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानती हैं, लेकिन यह ऐसे आसन पर बैठी हैं कि बोलकर नहीं कह सकतीं। आज मैं कहना चाहता हूं गांवों की स्कूलों का रिजल्ट रहा है 13 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 19 प्रतिशत और आपने उन अध्यापकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है गांवों में सबसे ज्यादा मैं जाता हूं। महीने में 18-20 दिन मैं गांवों में रहता हूं और गांवों में लोग क्या कहते हैं, एम. एल. ए. साहब, हमारे स्कूल का रिजल्ट तो 13 प्रतिशत है और वह गर्व के साथ कहता है और वो गर्व के साथ कहता है कि क्या चाहते हो, एम.एल.ए. साहब को कहकर मैं यहीं रहूंगा, इस बात का हमारा खून जल जाता है। जो आदमी अपराध करता है और अपराधी कोई पार्टी का सदस्य नहीं होता, न किसी का दोस्त होता है अपराधी, केवल अपराध की एक संज्ञा अपराध होती है। ऐसे अध्यापकों को आप हटाइये, उनको पनिशमैंट नहीं मिलेगा तो यह 'राम तेरी गंगा मैली' पिक्चर देखी है क्या आपने? नहीं देखी है? 'राम तेरी गंगा मैली' पिक्चर में एक बूढा व्यक्ति चश्मा लगा कर लड़कियों को गलत रास्ता दिखाता है। उसने कहा, 'ए बाब, तुम जैसा आदमी इस तरह करने लग जायेगा तो लोग अंधों पर विश्वास करना बंद कर देंगे।' तो मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, अगर आपने जिस तरह शिक्षा में स्थिरता दे रखी है और शिक्षा को जिस तरह डुबोने का ठेका ले रखा है, अगर ऐसा ही किया तो लोग शिक्षा में जाना बंद कर देंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि कोई बोल कर नहीं कहता, हो सकता है आपकी चमचागीरी, मैं आपका खास व्यक्ति हूं, मैं आपका भला चाहता हूं और भला कौन चाहता है, जो आदमी सच्ची बात कहता है वो भला चाहता है। यह केवल चमचागीरी कर सकते हैं। मैं कहता हूं आपने मेरे सबसे ज्यादा स्कूल खोली, इस बात के लिए मैं नहीं करता। खा कर पानी को मना नहीं करेंगे, नमक हरामी नहीं करेंगे पर आपने इस समय जो दो साल में मास्टर को

(श्री श्रवणकुमार)

आपने छूट दी है, प्राइमरी स्कूलों को और मिडल स्कूलों को पंचायती राज में दे दिया। पंचायती राज में दे दिया, जब पंचायत समिति को हम चैक करने के लिए जाते हैं, अध्यापक को जाकर पूछते हैं कि कहां गया? दो बजे बोला, साहब, डाक देने के लिए गया है। डाक वाले सेण्टर में जाते हैं कि, कहां गया? बोले, साहब, वो तो हरियाणा में चला गया था दो बजे ही चला गया था। कि बच्चे कहां हैं? बोले, बच्चे, साहब डेढ़ बजे चले गये थे। अब मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, एक गरीब का बेटा स्कूल में पढ़ने जाता है, मां से कहता है, मां, बाकळी खा कर आ गया। यह भाई कह रहा था कि मेरा बेटा बाकळी से बोला कि पेट दुखने लग गया। आप हिन्दुस्तान के अन्दर और क्या चाहते हो? पैरासाइटिक बनाना चाहते हो? गरीब के बेटे को रोटी खिला कर उसको पैरासाइटिक बनाना चाहते हो? उसकी आत्मा को मारना चाहते हो? मैं आपके इस मिड डे मील से खिलाफ हूं। आप इस तरह देश की आत्मा को मार कर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो? देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मिड डे मील है? इसमें बच्चा खा कर के, क्या रोटी खाने के लिए देश को आजाद रखना चाहते हो? देश की शिक्षा से देश का जो भला करेगा, देश आगे बढ़ सकता है तो शिक्षा से बढ़ सकता है और शिक्षा कब जरूरी हो सकती है जब आपका प्रशासन सही होगा। आपके अध्यापक जो पहले बच्चों को पीट-पीट कर के पढ़ाते थे, आज मास्टर पीट नहीं सकता। स्कूल में टाइम पर आता नहीं, 12 बजे पानी देकर आ रहा है स्कूल में और 11 बजे आया, 12 बजे आया और दो बजे वापस चला गया। अगर कोई ज्यादा चैक करेंगे तो मास्टर कहेंगे, क्या कर लेगा मेरा, घनश्यामजी मेरा ट्रांसफर तो कर नहीं सकते? क्यों, बोले, हमारे यूनियन में बाउंडेड है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, थर्ड ग्रेड का मास्टर जिले में ही रहेगा। अब क्या करें? सचिवालय का बाबू क्या कहेगा? मेरे को कौन बाहर भेज सकता है? हमने भेजने की कोशिश की थी, अशोक गहलोत ने, बैठा दिया न खिलाफ में, अगर ज्यादा बदमाशी करोगे तो आपको भी बैठा देंगे।

इसलिए आत्मा की शक्ति है न, आप लोगों की इच्छा तो है पर इच्छा-शक्ति नहीं है आप लोगों की और मैं कहना चाहता हूं जिस व्यक्ति में इच्छा केवल होती है और इच्छा-शक्ति नहीं होती वो कभी देश की अग्रणी पंक्ति का नागरिक नहीं बन सकता।

आज मैं देखता हूं, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी डिपार्टमैंट का व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारे, सभी को मालूम है हम जो सदन में

(श्री श्रवणकुमार)

बैठे हैं, सब को मालूम है कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद, 1952 से लेकर 2006 तक प्रतिशत 17 परसेंट तक पहुंच चुकी है पर किसी बंदे की हिम्मत आज तक हुई क्या कि परसेंटेज बंद कर दी? मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी पंचायत समिति में उधर उसमें बैठते ही मैंने भ्रष्टाचार को बंद किया और एक चैलेंज करता हूं कि एक रुपया कोई आदमी सिद्ध कर दे मैं इस्तीफा दे सकता हूं। आपने की इच्छा-शक्ति, सोची क्या? केवल बातें करते हैं, बातें करने से कि वो तो कांग्रेस ने अन्याय किया इधर बैठ गये, आप अन्याय करोगे इधर बैठ जाओगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट लूंगा। मैं कहता हूं इस देश की आजादी का प्रारूप इस तरह नहीं बदल सकता जिस तरह आपने सोच रखा है। इन लोगों ने सोच रखा है, में कांग्रेस की कोई बड़ाई करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं इनका भांड नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी.जे.पी. हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, आप लोगों में किसी में इच्छा-शक्ति नहीं है केवल इच्छा तो है। लोग कहते हैं इच्छा तो है, इच्छा-शक्ति नहीं है। जब तक आपकी इच्छा-शक्ति जागृत नहीं होगी इस राजस्थान की 5 करोड़ 70 लाख जनता का भला नहीं हो सकता।

अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अभी स्कूलों में डी.पी.ई.पी. से मकान बनाते हैं। दो मास्टरनी, एक तो सीमेन्ट लाने के लिए जा रही है और एक बजरी लाने के लिए जा रही है और बच्चे कहां गये, बोले, बच्चे तो सुबह नौ बजे ही चले गये। आपने ठेकेदार बना दिया अध्यापकों को। अगर इस तरह देश की हालत खराब कर दी आपने, अध्यापक मकान बनाने लग गये, अध्यापक जनगणना में भेज दिया, मृत्यु का प्रमाण-पत्र अध्यापक बनाने लग गया फिर आप शिक्षा से क्या चाहते हो? मैं कहता हूं आप शिक्षा को सुधारना चाहते हो आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली हो, जो व्यक्ति समय पर नहीं आता है, उसका ट्रांसफर ही नहीं आपने कितनी चार्जशीट्स दीं? 16 सी.सी.ए. का नोटिस तक आप दे नहीं सकते, चार्जशीटेड आप कर नहीं सकते, किसी को सस्पैण्ड आप कर नहीं सकते। सस्पैण्ड कर दोगे तो दस साल बाद वापस आ जायेगा। इस तरह की आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं समझता हूं नगण्य हैं और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कहता हूं। स्कूल आप कितने भी खोलें, जब

तक जो सब्जैक्ट आपके खुले हुए हैं उन पर पूरा कमाण्ड नहीं होगा, जब तक अध्यापकों की पूरी संख्या नहीं होगी तब तक आप 1500 स्कूल चाहे मत खोलना, हम इस बात के लिए कोई शौकीन नहीं हैं कि हमारी स्कूल खुले।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया और –

जंगल में पक्षी अनेक होते हैं पर ठिकाना एक होता है,
जंगल में शिकारी अनेक होते हैं पर सब का निशाना एक होता है,
भाषाएं अलग-अलग होती हैं पर तराना एक होता है,
दिल में हो प्यार तो जमाना एक होता है।

श्री अध्यक्ष: वाह-वाह।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप रोज बोलते हैं। जो अभी तक इस सदन में नहीं बोले हैं ...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): कल नहीं बोले थे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके झुन्झुनूं जिले की बेटी हूं, थोड़ा-बहुत समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कल नहीं बोले थे, परसों बोले थे। परसों बोले थे। जो अभी तक बिलकुल नहीं बोले।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपकी इजाजत से ही बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): दो मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, तो एक इधर से बुलाऊंगी न। एक उधर से फिर इनको बुलाऊंगी। (व्यवधान) हां, हां तो एक इधर से बोल ले पहले।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): दो ही मिनट बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: राज कुमारीजी, नो, नो। (व्यवधान) जो बिलकुल नहीं बोले।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी हमारे सीकर से ही आये हैं इसीलिए मैं दो ही मिनेट बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अब नहीं, गलत बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें बुलाइये जो बोले नहीं आज तक भी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बिलकुल नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष: बुलाऊंगी, बुलाऊंगी उन्हें। (व्यवधान) आप नहीं बोले? बोल दीजिए। यह नहीं बोले। यह चौधरी भी नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया इसके लिए तो आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है। आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से आरोप लगाये वो आरोप बिलकुल निराधार आरोप हैं। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हिन्दुस्तान जिस समय विश्व गुरु था और विश्व गुरु था तो इसलिए नहीं था कि जैसे चर्चा हो रही है वैसी चर्चा हो। उन वेदों के ज्ञान के कारण विश्व गुरु था और आज उन वेदों के अंशों को अगर कहीं पढ़ाने की बात आती है तो यह कहते हैं, यह साम्प्रदायिकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की यह पवित्र धरती है, दुनिया को दिशा दी है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आपके जो यह बोल कर और चले जाते हैं आपके माननीय सदस्य ...(व्यवधान) बोल कर चले जाते हैं, मैं इनको मौका नहीं दूंगी। वो बोले और चले गये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सब यहीं हैं, कोई नहीं गया।

श्री अध्यक्ष: वो बोले और गये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): लेकिन आज नकारात्मक सोच के कारण आज देश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उसके अगर कोई दोषी हैं तो आज प्रतिपक्ष दोषी है। मान्यवर, आज अलगाववाद खड़ा हो गया, कौन दोषी है? आज की शिक्षा नीति दोषी है। आज की शिक्षा के कारण

अलगाववाद खड़ा हुआ है। उसको कौन स्वीकार करेगा? आज दो विचारधाराएं चलती हैं, सत्य और अहिंसा। यह परम्परा रही है। सत्य भी होता है, अहिंसा भी होती है, साथ-साथ चलती है। कोई आदमी इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप घबराइये नहीं।

एक माननीय सदस्य: सभी को धन्यवाद दो आप तो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है आपने इस हिन्दुस्तान की संस्कृति को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है, उसको आगे तक चलाए रखें। अब अगर इस प्रकार का शिक्षा में परिवर्तन हुआ तो मैं कहूंगा कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान पुन: इसी विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा।

मान्यवर, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आपने शिक्षा में योग-शिक्षा को महत्व दिया है। पहली से लगाकर के आठवीं तक आप योग की शिक्षा देंगे। आज योग के कारण हमारे ऋषि मुनिया ने साधना करके तपस्या करके और उस स्थान पर हिन्दुस्तान को ले आये। आज हमारे बच्चे योग को सीखेंगे और योग सीख करके कुछ कर पायेंगे और हमारा शरीर तो स्वच्छ रखेंगे ही रखेंगे लेकिन बुद्धि को भी स्वस्थ रख कर के और स्वस्थ विचारधारा से आगे चलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय का अभाव है, अगर पहले समय मिलता तो बहुत कुछ बोलते पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बहुत अध्यापकों की भर्ती की है और अध्यापक आपने हम को दिये भी हैं लेकिन आज भी उस दूर-दराज के एरिया में अध्यापकों की कमी है। जब आप भर्ती करें तो ऐसे वंचित क्षेत्रों को पहले प्राथमिकता दें जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि योग के माध्यम से आप शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करें। आज जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा ले रखा है वह इन्तजार कर रहे हैं कि हमें कभी मौका मिले तो हमभी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में कोटडा और झाड़ौल दो तहसील पड़ती हैं। दोनों जगह सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। वहां पर विज्ञान संकाय और

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

कामर्स संकाय नहीं है और नहीं होने के कारण यदि हम यह अपेक्षा करें कि वहां से डाक्टर तैयार हों, वहां से कोई कॉमर्स पढ़कर कॉमर्शियल सैक्टर में जाए, संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप बहुत कृपा करेंगे, आप बहुत ही विद्वान हैं, गम्भीरता से लेंगे इस बात को और आप वहां पर निश्चित रूप से झाड़ौल और कोटडा में विज्ञान और कॉमर्स संकाय खोलने की घोषणा करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आगे और कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में आपने स्कूलों की घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में डेढ़ हजार विद्यालय आप माध्यमिक क्रमोन्नत करेंगे और छह सौ विद्यालय उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत करेंगे। हमारा क्षेत्र ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां पर शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में बिरोठी झाड़ौल में पड़ता है, छह सात पंचायतों का एक क्लस्टर है। वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो वहां पर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का भी आश्वस्त करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं मामेर क्षेत्र जो कोटडा से पच्चीस तीस किलोमीटर दूर है वहां पर एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, मैं चाहूंगा कि इसको भी आप प्राथमिकता के आधार पर वहां पर हमें उच्च माध्यमिक विद्यालय देंगे तो वहां के क्षेत्र की जनता आपका अहसान मानेगी और मैं आपको वहां पर स्वागत के लिए बुलाऊंगा तो लोग आपकी बहुत आवभगत करेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नंदलाल पूनिया। मैंने नाम पुकार लिया नंदलाल पूनिया का।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग में माननीय मंत्रीगणों की रिप्लाई एवं इनके पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि मांग संख्या-24 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं या यह बोलें?

श्री अध्यक्ष: मैंने नंदलाल पूनिया का नाम पुकार लिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला व संस्कृति पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के युग में जितनी शिक्षा की महत्ता है और किसी चीज की नहीं। शिक्षा से विकास संभव है, चाहे आज अंतरिक्ष की बात ले लीजिए, चाहे परमाणु बम की बात ले लीजिए, यह सारा शिक्षा से संभव हुआ था।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा के सम्बन्ध में तो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा कोई कह ही नहीं सकता।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): ठीक है, मैं मेरी बात को रख देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी स्कूलों की चर्चा हो रही है, सरकार की बहुत प्रशंसा की गयी ...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं तो निवेदन कर रहा हूं निवेदन करने के लिए सीट नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद दो और क्या कहो आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): आज हमें इस बात पर विचार करना होगा कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते हैं जब कि सरकारी स्कूलों में अच्छे ट्रेन्ड टीचर हैं, अच्छा उनको वेतन मिलता है।

श्री अध्यक्ष: मध्यान्ह भोजन भी मिलता है।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): फिर भी वह लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, ऐसा क्यों है? इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपको सोचना पड़ेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आज...

श्री अध्यक्ष: पाइंट तो बहुत वेलिड है कि क्यों भेजते हैं, सही बात है यह तो।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): आज हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आज जो अध्यापन का कार्य है, जो आपके प्राइवेट स्कूलों में वहां एक उन पर पाबंदी कर रखी है आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको हटा देंगे और आपका आउट पुट नहीं आएगा तो आपको हम परमानैंट नहीं रखेंगे यहां। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज उनका सिर्फ अध्यापन का कार्य होना चाहिए लेकिन आज हो क्या रहा है उन अध्यापकों को कभी तो जनगणना में लगा देते हो आप, कभी बी.पी.एल. की सैंसस में लगा देते हो, कभी कुत्ते गिनने की गणना में लगा देते हो, कभी बिल्ली गिनने का काम पड़ता है तो उसमें लगा देते हो, कभी मिड डे मील में लगा देते हो। तो उनका जो काम है अध्यापन का काम, वह रुक जाता है और वह दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं और अपना जो काम था वह पूरा कर नहीं सकते। यह बहुत बड़ी सोचने समझने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सोचिये आप। मिड डे मील है और दूसरे कार्यक्रम हैं इनके लिए अलग से एजेंसी आप क्रियेट कर दीजिए और अध्यापक को सिर्फ अध्यापन के कार्य के लिए फ्री कर दीजिए ताकि वह उसका सही उपयोग कर सके।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी हाउस में हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि दो प्राइमरी स्कूलों के पीछे हमने मिडल स्कूल कर दिया, हो सकता है यह बात सारे राजस्थान में इनकी लागू हो लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं उनकी तरफ भी इनको ध्यान देना पड़ेगा।

मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे क्षेत्र में ठावली ढाणी, केरलीवास दो प्राइमरी स्कूलें हैं, उनके बीच की दूरी तीन चार किलोमीटर के तकरीबन है। इसी प्रकार लुटाणां मगनी व लुटाणा मगनीवास, यह दो स्कूलें हैं, इनकी दूरी भी करीब तीन से चार किलोमीटर है और धांगडा और धौलिया की करीब तीन किलोमीटर है। यह छह स्कूलें अलग-अलग अपने कैम्प्स में एक दूसरे से चिपते हुए हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था आप इन स्कूलों को क्रमोन्नत कर दीजिए आप सारा जो कार्यक्रम है आपका उस हिसाब से कि दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर की इनकी दूरी है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्कूलों को आप क्रमोन्नत कीजिए।

आपने बालिका शिक्षा में बहुत कुछ देने की घोषणा की है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह भी कहा था कि जितनी बालिका प्राथमिक शालाएं हैं वह उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर दी जाएंगी, हो सकता है आपने कर दी हों और कर भी दी हैं लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो तेरह बालिका उच्च प्राथमिक हैं वह आज से बहुत पहले, आज से करीब दस पन्द्रह साल पहले की शालाएं चल रही हैं। मैं चाहता हूं जैसे आपके नेशल है, डिंगली, जैतपुरा, चांदगोठी, हमीरवास, कालरी, रामपुर बैरी, भोजाण बधेला, नांगल छोटी, पहाड़सर, बनारसी देवी, इनको जो पन्द्रह साल पहले की उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल हैं उनको आप क्रमोन्नत करें तो बहुत अच्छी बात होगी।

मैं आपसे पुन: एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का शायद पन्द्रह सौ का टार्गेट रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल है राघा छोटी जो 1961 से उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उस शाला की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज उस गांव के बच्चे नवीं से, नवीं के बाद पांच-पांच, छह-छह किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। उन लोगों ने हारकर माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पेश की और उस रिट याचिका में यह डायरेक्शन राज्य सरकार को दी।

”After hearing the counsel for the petitioners we dispose of this writ petition with a direction to the authorities particularly the Director, Secondary Education, Govt. of Rajasthan, Bikaner and District Education officer, Churu to consider the matter keeping in view the interests of the students of the locality and take appropriate decision in public interest as early as possible.”

आज जिस स्कूल की तरफ 1961 के बाद किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मैं किरोड़ी लालजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन भी हैं, आप खोलना भी चाहते हैं तो सारी चीजें यह बात है। बूआ जाऊं जाऊं कह दी फूफो लेने आ गयो। हाई कोर्ट के आदेश हैं आपको मैं निवेदन...

श्री अध्यक्ष: प्लीज समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष: अब आप एक मिनट में कर दो निवेदन।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): डूंगरगढ़ पहले चूरू जिले में था और 1 अप्रैल, 2001 से अलग हुआ उस समय सभी विभागों में आप्शन मांगे थे कि बीकानेर में रहना चाहते हो कि चूरू में लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा कोई आप्शन नहीं मांगे। करीब दो सौ, ढाई सौ लोग चूरू जिले के थे उनमें से 34 आदमी हाई कोर्ट गये और उनमें भी ऐसा ही एक डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया था उसके बारे में मैं आपको कोट करना चाहता हूं ''Learned Counsel has filled certain more documents being annexure 5 to 10 along with the additional affi-davits. Issue notice of stay application also. Meanwhile vacancies of the posts of teacher Grade III, Physical Education in Churu district against which the petitioners were appointed may not be filled by transfer from other districts. However, this will not come in the way of the respondents if those posts are filled by adjusting or absorbing the petitioners." तो मेरा शिक्षा मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि आप चूरू जिले के जो आदमी हैं, जो बीकानेर में चले गये और यदि वह वापस आना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): एक थोड़ी सी और कहूंगा....

श्री अध्यक्ष: अब क्या थोड़ा सा रह गया ?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): 1998 में जिला परिषदों में एप्लीकेशन मांगी थी नियुक्ति के लिये। आज सब कुछ जगह दे दी गयी लेकिन 1998 वालों को कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज तक नियुक्ति नहीं दी गयी। वह 9 साल से जयपुर में कईयां तो घूमे है। कईयां के तो दाढ़ी आगी। जूती टूटगी, कपड़ा फाटगा कि उनको कुछ न्याय नहीं मिला। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके बारे में भी कुछ सोचिये और यदि संभव हो तो उनको आप जरूर नौकरी दें..

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): इसके अलावा एक संस्कृत का और है..

श्री अध्यक्ष: अब कृपया बैठ जाएं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): एक मिनट..

श्री अध्यक्ष: अब ऐसे कैसे ? आप तो पाँच मिनट की बात होते-होते आपने 8.53 पर शुरू किया अब 9.03 हो गये हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): हमारे क्षेत्र में एक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है..

श्री अध्यक्ष: अब आपके क्षेत्र में कुछ भी होगा। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): इसमें इतनी वेकेंसीज हैं लेकिन गांव वाले धरना देकर ताला लगाकर सात-सात दिन तक धरना दिया। मैंने मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन किया। उन्होंने यह कहा मैं तीन दिन में गांव वालों की मांग है उसके अनुसार प्रिंसीपल लगा दूंगा। इनसे बात करने के बाद मैंने गांव वालों से बात की। वह धरने से उठ गये लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन आश्वासन ही रह गया। इस प्रकार सरकार का दिया हुआ आश्वासन..

श्री अध्यक्ष: आश्वासन रिटन में थोड़ी दिया था...

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): इम्प्लीमैंट नहीं हो तो इससे बुरी क्या बात हो सकती है। इसके साथ ही मैं..

श्री अध्यक्ष: अब ठीक है। प्लीज...

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब कोई निवेदन नहीं...

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): संस्कृत प्रवेशिका..

श्री अध्यक्ष: नो-नो। अब अंकित नहीं हो। अब अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: अब कोई निवेदन नहीं। स्थान ग्रहण करो। अब स्थगन गहण करो आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): XXX

श्री अध्यक्ष: इधर से जो कोई नहीं बोले हैं अभी तक। आप प्लीज शुरू करें। प्रारम्भ करें।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्दलियों में से तो मेरे को एक को बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट का समय दूंगी। ओन्ली फाइव मिनिट्स।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं वैसे ही बहुत कम बोलता हूं लेकिन आदरणीय

(श्री जीवराम चौधरी)

घनश्यामजी ने जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में सन् 1952 की खुली हुई प्राइमरी स्कूल जो आज दिन तक आठवीं में क्रमोन्नत नहीं हुई थीं टोटल ऐसी 135 स्कूल मेरे विधान सभा क्षेत्र में थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से कि इसमें से 75 प्राइमरी स्कूलों को आठवीं में क्रमोन्नत करके इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है।

इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में ढाणियों में लोग रहते हैं। तीन साल में हमारी इस सरकार ने, माननीय घनश्यामजी ने 66 नयी प्राइमरी स्कूल खोलकर इसके अन्दर उन बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद अदा करता हूं।

मेरे क्षेत्र में छोटा सा सुझाव देता हूं कि मिड डे मील में जो इंटीरियर गांव है जहां फ्रूट अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें फ्रूट की जो व्यवस्था है सिटी से अगर फ्रूट ले जाते हैं और वहां देते हैं, दूसरे दिन देते हैं खराब हो जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इसके बदले बिस्किट वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था, सूखी चीज की ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए ताकि बच्चों को विटामिन वाले बिस्किट मिलें और फ्रूट वाले झंझट भी मिट जाए। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है, मैं इस अवसर पर चूंकि आपने दो मिनट का समय दिया है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं मेरी तरफ से, जैतारण की जनता की तरफ से, पास में बिलाड़ा, रायपुर की जनता की तरफ से कि उन्होंने महाविद्यालय खोला। इसके लिये बार-बार उनको धन्यवाद।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से दो-तीन बातें निवेदन करता हूं। एक तो पैराटीचर्स जो लगे हुए हैं काफी तो बी.एड. और बी एस.सी. किये थे अभी जो नियुक्ति आयी उसमें उनका चयन हो गया। बाकी जो बचे हुए हैं उनके एक तो कोई सर्विस रूल्स नहीं है। तो पहला काम आप यह करें कि कम से कम उनके सर्विस रूल्स तो बने जिससे उनको डर तो हो कि मेरे खिलाफ 16 की कार्यवाही हो सकती है, 17 की कार्यवाही हो सकती है। मैं नौकरी से हट सकता हूं कोई गलती करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा समय पर। क्योंकि उनको सरपंचों ने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

चयनित किया है। तो मेरा निवेदन एक तो यह है पैराटीचर्स के बारे में आप थोड़ा सा सोचें।

बाकी आपने स्कूलें खोलीं तीन सालों में जो बजट शिक्षा के क्षेत्र में रखा उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने शिक्षा के ऊपर, बच्चियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। मैं यह भी नहीं कहता कि अपन लोगों ने ध्यान दिया। इन्होंने भी पचास साल तक काम किया। पर चालीस साल तक इनका शासन रहा और इनको तीन साल में जो देखने को मिला, चाहे प्राइमरी से मिडल एवं मिडल से सैकण्डरी और सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी का जो बजट मिला है यह बजट ऐसा है तो इस अवसर पर मैं वसुन्धराजी को व घनश्यामजी को धन्यवाद देता हूं। पहले जो भी सरकारें बनती थीं वह सरकारें चेंज हुई वह नेगेटिव वोट लेकर चेंज हुई है। पहला मौका है कि इस बार पोजिटिव वोट लेकर सरकार वापस आएगी। यह क्यों आएगी? इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सब क्षेत्रों में जो काम किया है, वह वाकई में सराहने के काबिल है। मैं तो इस मौके पर एक और निवेदन मंत्रीजी से करता हूं। अपने जो सर्व शिक्षा का है, पैसा केन्द्र सरकार का हो, स्टेट का भी है परन्तु इसमें जो खर्च हो रहा है, चाहे निर्माण कार्य में हो रहा है, चाहे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके शिविर लगाकर उनको पढ़ाने में है। चाहे विकलांग बच्चों को ट्राइ-साइकिलें या उनको किताबें मुफ्त में देने के लिए तो इसके बारे में थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आज जिले में एक शिक्षा अधिकारी है और वह शिक्षा अधिकारी भी हमारे यहां पर तो गुर्दे का रोगी है, वह है ही नहीं वहां पर। न डी.ई.ओ. लगे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि- 'भगवान मिलता है भक्ति से और शासन चलता है सख्ती से।' जब तक सख्ती आप नहीं रखोगे और भय नहीं रखोगे तब तक शासन चल नहीं सकता। मेरा निवेदन है कि पहले आप किसी भी सूरत में जिला शिक्षा अधिकारी और बी.ई.ओ. लगाओ। और यह सर्व शिक्षा का सी.ई.ओ बैठती हैं उसके ऊपर भी अंकुश रखने के लिए बी.ई.ओ. को मॉनिटरिंग के लिए उसके अधिकृत करें वरना वह अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। न तो वह कोई कागज जन प्रतिनिधियों को भेजते हैं। सैंक्शन निकलती है, न वह कहां पर शिविर लगा है, शिविर आज लगा और आज लगने के बाद तीन महीने के लिए शिविर चल रहा है। पहले महीने में वे क्या करते हैं? किसी बच्चे की भर्ती करते नहीं, न वह शिक्षा विभाग को अवगत कराते हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

दूसरे महीने में थोड़े-बहुत बच्चे भर्ती कर लेते हैं और तीसरे महीने में पचास बच्चों की भर्ती करनी हो तो पचास कर लेते हैं और फिर 25 रुपये रोज की बच्चों को जो खाने की चीजें मिलती हैं वह जो लगे हुए टीचर हैं वह उठा लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उनके खाने की क्या व्यवस्था है। अब जैसे अखबारों में आता है कि बच्चों को जब रात को सुलाते हैं तो उनके बिस्तर किराये पर लेते हैं। उनकी क्या हालत है।

अध्यक्ष महोदय, आज पाली जिले में सर्व शिक्षा के बारे में आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। वहां पर इतना भ्रष्टाचार और इतनी अनियमितता हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। अगर आप कोई स्वतंत्र एजेंसी बिठाकर के या ए.सी.डी. में इस केस को भेज दें तो आपको पता लग जायेगा कि वाकई में सर्व शिक्षा में कितना भ्रष्टाचार है। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि हम सब सदस्य दो सौ बैठै हैं, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है। हम लोगों को पार्टी बाजी से ऊपर उठकर के शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब तक मैकाले की शिक्षा पद्धति और हिप्पोक्रेट की चिकित्सा पद्धति और लार्ड कर्जन की डिवाइडेड रूल्स की राजनीति जब तक इस देश पर हावी रहेगी तब तक शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, आज देश इक्कीसवीं सदी में जा रहा है परन्तु हालात क्या हैं वह अपने से छिपे हुए नहीं हैं। आज स्कूलों में गांवों के जो बच्चे हैं वहां जाकर के उनके बच्चों से पूछो, जो अभी श्रवणजी ने बताया मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आज ऐसे हालात हैं गांवों में कि एक बच्चा तो मास्टर के मिड डे मील का काम देख रहा है, एक बच्चा स्कूल की डाक ले जाकर के बी.ई.ओ. ऑफिस में ले जाकर के दे रहा है या सर्व शिक्षा में दे रहा है। डेढ़ सौ—डेढ़ सौ बच्चे हैं और एक-एक, दो-दो टीचर लगाये हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको मिड डे मील में लगाना भी है तो वह पैराटीचर जो कि आठवीं पास है, दसवीं पास है, उनको आप अधिकृत कर दो कि यह काम देखेगा। कम से कम जो बी.एड. और एस.टी.सी. किये हुए हैं वह तो सही ढंग से काम करें और बच्चों को पढ़ायें।

अध्यक्ष महोदय, आज देश इक्कीसवीं सदी में जा रहा है, लोग आई.आई.टी. की बातें कर रहे हैं। कम्प्यूटर युग की बातें करें और गांव के हालात बहुत खराब हैं। हकीकत में खराब हैं। आज मैं कह रहा हूं आपको कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सरकार अपनी है और अपन अच्छा करना चाहते हैं। उनकी सरकारें हैं और वह भी अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन धरातल क्या है। उसका आत्म विश्लेषण करके, आत्म चिंतन करके, धरातल पर जाकर के कि उन बच्चों के भाग्य का फैसला हमारे हाथ में है और जो राष्ट्र के निर्माण करने वाले टीचर हैं उनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। उनको यह समझाना पड़ेगा कि तुम शिक्षक हो न कि तुम व्यवसाय समझकर के शिक्षा दो। बहुत बड़ा फर्ज समझकर के, अपना कर्तव्य समझकर के शिक्षा जब तक नहीं दोगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं और बहुत सोचने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी बहुत रुचि है। मैं तो इनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जब तक उन टीचरों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाओगे, कि आपको यह शिक्षा अपना फर्ज समझकर के, कर्तव्य समझकर के देना है न कि व्यवसाय समझकर के शिक्षा देनी है। अगर व्यवसाय समझकर के शिक्षा दी तो मैं कहता हूं कि इस देश का वह नुकसान हो जायेगा जो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मुझे बुलवायें।

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, कल नहीं बोला था।

श्री अध्यक्ष: कल से मतलब नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): कल नहीं बोला था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्षजी, मंगलारामजी गोदारा भी नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): मेरे इलाके की मांग रखूंगा सिर्फ। दो मिनट के अंदर बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप में से आज कौन नहीं बोला? कोई नहीं है ऐसा।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मांग रखूंगा इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। भूमिका नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है, मैंने देखा है। वह बोल चुके हैं, वह बोल चुके हैं।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 ...(व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरी मांग रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: बोलें आप ...(व्यवधान) आप तो बोल चुके थे कल ही।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): कल नहीं बोला, कल नहीं बोला।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, संस्कृत एवं कला के ...(व्यवधान) माननीय अटलजी के सम्मान में मैं दो पंक्ति बोलना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भाग ले रहा हूं, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के लिये समर्पित भाव से जो घोषणाएं कीं उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, उस भर्ती के अंदर विधवाओं और परित्यक्ताओं को रिजर्वेशन दिया। पिछली सरकार के पांच वर्षों में एक भी नियुक्ति नहीं दी गयी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद करीब 60 हजार शिक्षकों को भर्ती दी जा रही है। इस बजट में मिड डे मील योजना जो प्राथमिक तक लागू की गयी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में राज्य सरकार के स्वयं के खर्चे पर उसको मिडल तक मिड डे मील देने की घोषणा की उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी बात चल रही थी स्कूल क्रमोन्नत होने की चाहे वह पांचवीं से आठवीं और आठवीं से दसवीं और दसवीं से बारहवीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार जीतकर आया हूं लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र जिसमें सौ ग्राम पंचायते हैं, चार तहसील हैं और सात लाख के करीब जनसंख्या है और 220 किलोमीटर के लंबे एरिये में फैला हुआ है। पिछले तीन

(श्री अशोक नागपाल)

वर्षों में जिसमें से पिछले तो आठवीं से दसवीं और दसवीं से बारहवीं हमारे विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुए। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा हरिसिंहपुरा गांव तहसील-सूरतगढ़ में उस गांव में मैं गया। 1967 में उस गांव में जो बुजुर्ग पढ़े थे पांचवीं तक और उसके बाद वह स्कूल क्रमोन्नत हुआ 2005 में जाकर के आठवीं तक। मुझे कुल पांचवीं से आठवीं तक 50 विद्यालय मिले, आठवीं से दसवीं 8 और दसवीं से बारहवीं 2, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर दसवीं तक का स्कूल अवश्य हो जिस तरह कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि एक-डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा पांचवीं तक के लिए पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े और 5-6 किलोमीटर की परिधि में आठवीं से दसवीं तक का स्कूल हो। उसी के अनुरूप पंचायत मुख्यालय दसवीं तक के अवश्य हों। मेरा यह सुझाव है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अगले सत्र में जो आने वाला नया बजट होगा इसमें इसको विशेष रूप से लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो शिक्षक भर्ती की गयी है उसमें विधवाओं और परित्यक्ताओं को जो नौकरी दी जा रही है उसमें एक क्लाज लगा हुआ है प्लस टू आज की समय की और ग्यारहवीं पुराने समय की, कुछ तलाकशुदा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूर्व में दसवीं की हुई है लेकिन वह अनुसूचित जाति से हैं। उनको उसमें सर्विस नहीं दी जा सकती है। चाहे उन्हें फोर्थ क्लास में ही नौकरी दी जाये इसके लिए भी विशेष रूप से योजना बनाकर के उन महिलाओं को जो इससे वंचित रही हैं उनको नौकरी अवश्य दी जाये यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन शिक्षा-कर्मी विद्यालय हैं जिनमें भवन बने हुए हैं, उनमें पूर्व में पांचवीं से आठवीं क्रमोन्नत कर दिये गये लेकिन वह शिक्षा-कर्मी होने के कारण लागू नहीं किये जा सके बछरारा, करड़ू और सांवतसर, मैं एक मिनट का समय लूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं कभी बोला भी नहीं हूं। पहले बोल चुका हूं पिछली बार।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मेरे क्षेत्र की जो प्रमुख

(श्री अशोक नागपाल)

मांग है वह आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि उस समय के तत्कालीन हमारे मुख्य मंत्री और अब के महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत ने अनूपगढ़ में 50 बीघा नि:शुल्क भूमि दी और उसमें राजकीय महाविद्यालय के लिए नींव भी रखी गयी जो आज तक वंचित पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह जो 50 बीघा भूमि नि:शुल्क आबंटित की हुई है उसमें राजकीय महाविद्यालय, चाहे राजकीय बालिका महाविद्यालय बनायें, उसके लिए भवन और जो भी आवश्यकता है वह हम हमारे शहर की तरफ से पूरी करवाकर देंगे, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगी कि 9 बजकर 20 मिनट हो गए हैं। आप अपने बोलने के लोभ का संवरण कर लें। कल मौका दूंगी आपको बोलने का। आखिर कब तक बैठेंगे? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कविता सुना लेने दो, दो लाइन में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) कल दूंगी आपको मौका। कल आपको मौका दूंगी। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। कल बोल लेना। (व्यवधान) नो, नो, नो। (व्यवधान) Mr. O.P. Mahendra, go there and tell him to sit. (व्यवधान) नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप भ्रष्टाचार खतम करने की बात करेंगे, मास्टरों की संख्या को आप पूरी करो तो हम ताली बजाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है, बैठ जाओ आप।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) कल दूंगी आपको समय कल। (व्यवधान) 9 बजकर 20 मिनट हो गए हैं, कब तक बैठेंगे आखिर? (व्यवधान) नहीं, अब कुछ नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):

आजादी के पचास साल बाद तुमने पहली बार किया है यह काम,
लाख को नौकरी दे किया यह कीर्तिमान, किया यह कीर्तिमान,
ऐसे घनश्याम तुझे सौ-सौ बार प्रणाम,
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किया तुमने हिन्दुस्तान में नाम।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):

जन-जन के होठों पर आज बस एक गान है,

नेता अटल है और वह भारत की शान है,

एक सोच है सभी की यह सब का बयान है,

आदर्श है वह शख्स तभी तो महान् है।

श्री अध्यक्ष: आप तो सभी कवि हो रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब तो विराज जाओ। अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): XXX

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): XXX

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, प्रारम्भ करें। यह तो सारे के सारे आपकी विद्वता से लोहा ले रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): XXX

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): XXX

मांग संख्या 24 का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में 315 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सारे कटौती प्रस्तावों को यहां प्रस्तुत हुआ मान लिया। मैं कोशिश करूंगा कि सात दिन में इनके जवाब दूं। मैं दो-तीन दिन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इन कटौती प्रस्तावों में स्कूल खोलने सम्बन्धी, क्रमोन्नत करने सम्बन्धी, बाउण्ड्री वॉल बनाने सम्बन्धी, भवन बनाने सम्बन्धी है। जो माननीय सदस्य बोल लिए हैं और जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, मैं उनके इन कटौती प्रस्तावों को उनकी डिजायर मानता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके कटौती प्रस्तावों के अनुसार सकारात्मक जवाब देने का प्रयत्न करूं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम को आगे बढ़ा सकें।

दूसरा, मैं निवेदन यह करूंगा कि मैं अपनी बात की शुरूआत, क्योंकि आजकल चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ है, जो भी आता है वह शेरो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शायरी से शुरू करता है। अब मैं शेरो शायरी से शुरूआत नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं शुरू करता हूं,

सर्वत्र शिक्षिता संतु, सर्वे ही जीविकान् विता,

सर्वे विकसिता संतु, राष्ट्र गौरव योजका

मेरी यह कामना है और शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य भी यह है कि सभी शिक्षित हो, सभी को रोजगार प्राप्त हो और सभी प्रगति करें और राष्ट्र का गौरव बढ़े, उससे हमारा भी गौरव बढ़े, यह हमारी सब की कामना के साथ शुरू करता हूं और इसलिए मैं पहली बार सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को या उनको नहीं लेकर नए अर्थ के साथ शुरू कर रहा हूं, 'विद्या अर्थकारि भवेत्', आज तक हमने सुना, 'सा विद्याया विमुक्ते, विद्या ज्ञानाना मुक्ति', इसके बजाय हम शुरू करना चाहते हैं, 'साविद्याया अर्थाया साधिका, विद्या अर्थकारि भवेत्', शिक्षा में उच्च आदर्श, आध्यात्मिक उन्नति एवं जीवन मूल्यों के समावेश के साथ ही उसका अर्थकारी होना भी बहुत आवश्यक है। अगर वह अर्थकारी विद्या नहीं है तो हमारा काम नहीं हो सकता और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के बारे में सोचा। मैं आज इसी के बारे में बोलना चाहता हूं। आज अगर तकनीकी शिक्षा का विस्तार नहीं है तो हम प्राथमिक शिक्षा, सैकण्डरी शिक्षा, सब शिक्षा देने के बाद भी अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा सकते या उसे कुछ दे नहीं पाते और रोजगार भी सरकार के क्षेत्र में इतना रोजगार नहीं है। यहां बहुत से प्रश्न उठे थे कि तीन लाख लोगों को रोजगार देना था, एक लाख लोगों को रोजगार देना था, मैं उन सब पर आऊंगा और बातें भी शिक्षा के सम्बन्ध में हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है और आज की चर्चा को मैं बहुत ही सकारात्मक रूप में ले रहा हूं। सैद्धान्तिक चर्चा भी यहां हाउस में हुई यह हाउस बना ही इसीलिए है, सैद्धान्तिक चर्चा होनी भी चाहिए, सैद्धान्तिक आलोचना भी होनी चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे से बहुत ऊपर हैं, हमें उन लोगों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसकी एक चर्चा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने की कि किताब में महात्मा गांधी के बारे में, यह प्रश्न तो बहुत पहले आ गया था, इसके बाद यह राज्य सभा में भी मामला उठा था और इसके बाद में हमने एक आदेश कर दिया था कि पुस्तक के नए संस्करण में

महात्मा गांधी के बारे में लिखी हुई बातों को हटा दिया गया, इसके साथ ही जो लेखक था उस पर भी कार्यवाही करने की बात की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन आदमी इस राष्ट्र में होगा जो महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र पुरुष के बारे में ऐसा सोच सकेगा। मेरा तो खुद का चिंतन है, मैं यह कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लोग शायद यह कहते होंगे कि महात्मा गांधी धर्म निरपेक्ष ताकतों के प्रतीक थे लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि हिन्दू समाज को बचाने का सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया तो महात्मा गांधी ने किया। आज के सौ साल पहले जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उस महात्मा गांधी के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है और जब तक मैं खुद शिक्षा मंत्री हूं, यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती कि हम इस तरह की बात सोच भी सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में विस्तार से बात करना चाहूंगा। (व्यवधान) मैं मेरी बात कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): महात्मा गांधी को हिन्दुओं के साथ ही क्यों जोड़ रहे हो? मानव जाति....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हिन्दू ही नहीं, मैं बता रहा हूं उनका तो यह है कि सब धर्मों के साथ थे लेकिन हिन्दू समाज के लोगों को भी उसमें लेना चाहिए, उनसे बड़ा हिन्दू समाज का दूसरा कोई नेता ही नहीं था जो सम्पूर्ण हिन्दू समाज को 'रघुपति राघव राजा राम' कहकर एक करने का काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यही नहीं, अभी जब शताब्दी पूरी हुई थी तो यूरोपियन देशों की एक कमेटी बनी जिस कमेटी ने यह किया था कि शताब्दी पुरुष कौन है पिछले सौ सालों का। उसमें जब सलेक्शन होने लगा, 150 लोग थे उसमें सब देशों के तो महात्मा गांधी का नाम एक नम्बर पर था, तीनों बार ही जब कमेटी में महात्मा गांधी का नाम आया तो उसकी घोषणा नहीं की गई। वह तो सम्पूर्ण विश्व के शताब्दी पुरुष थे, उनके बारे में क्या कहना?

मैं दूसरी बात कहूंगा, तकनीकी शिक्षा के बारे में कह रहा हूं कि यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार एक हजार की जनसंख्या राजस्थान में बहुत कम तकनीकी लोग हैं। यह बात सही है कि राजस्थान पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसको मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरा भी दोष है तो है। जो स्थिति है वह सामने है। जापान में प्रति एक हजार पर 10 आदमी तकनीकी शिक्षा में है, अमरीका में 55, ब्राजील में 30 और हमारे भारत में राष्ट्रीय औसत सिर्फ 3.5 है। इसलिए हमारे यहां तकनीकी शिक्षा कम है और राजस्थान में भी कमी है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में 15,688 लोग तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेकर हमारे पास पढ़ते थे, आज उनकी संख्या 50 हजार को पार कर गई है और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया था कि आई.टी.आई. के आपने इतने लाइसेंस जारी कर दिए लेकिन कितने चालू हुए तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर प्राइवेट सेक्टर में आई.टी.आई. के लिए लोगों को जमीन दी गई है वह ऐसे रिमोट एरिया में है जहां पर जमीनों की कोई बड़ी कीमत नहीं है, वह बहुत मुश्किल से उसमें है लेकिन फिर भी बारह महीने के अंदर वह काम पूरा करेंगे, बारह महीने में यदि वह प्रारम्भ नहीं करेंगे तो उनसे वह जमीन भी वापस ले लेंगे और जो लाइसेंस दिया है वह भी वापस ले सकते हैं। इसलिए उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2007-2008 के सत्र में वह आई.टी.आई. प्रारम्भ हो जाएं और वह आई.टी.आई. प्रारम्भ हो जाएंगी तो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वालों की संख्या 1 लाख पहुंच जाएगी और हमारा राजस्थान राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएगा। उसकी बात नहीं है। इसी प्रकार से हमने सरकार बनने के बाद 20 आई.टी.आई. खोले। पांच पोलीटेक्नीक कालेज खोले हैं। कुल 140 संस्थान थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 334 हो गई है, 521 पाइप लाइन में है। यह काम जब पूरा होगा तो निश्चित रूप से तरक्की कर पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि 113 पंचायत समितियां थीं जिनमें आई.टी.आई. नहीं थी, अब केवल 9 बची हैं, वे भी ऐसे इलाके हैं अधिकतर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आदिवासी क्षेत्र में हैं जहां पर कोई नहीं आया है। हमने दुबारा इसको विज्ञापित किया है और सुविधाएं देना चाहते हैं, फिर भी अगर नहीं आया तो कोशिश करेंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से आग्रह करेंगे, सरकारी क्षेत्र में आग्रह करके 9 स्थानों पर इसी साल में आई.टी.आई. पूरा करके राजस्थान के सारे ब्लाकों में आई.टी.आई. करेंगे। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य था ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 9 कौन से हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 9 ब्लाक हैं, मैं बता दूंगा, मेरे पास नाम हैं, 9 बाकी हैं। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं 12 जिले ऐसे थे जहां पोलीटेक्नीक कालेज नहीं थे। हमने उन 12 जिलों में पोलीटेक्नीक कालेज खोल दिये हैं। आज राजस्थान के सभी जिलों में पोलीटेक्नीक कालेज हो गये हैं, वह काम पूरा हो गया है।

इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कालेजों की हमारे यहां बहुत कमी है। सरकार ने एक नई नीति जारी की है इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग कालेज खोलने वालों के लिए हम नि:शुल्क भूमि का आबंटन करेंगे और सरकार कोशिश करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के सभी जिलों में हम इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने में सफलता प्राप्त करें ताकि यह भी एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस साल हम राजस्थान में चार नये इंजीनियरिंग कालेज सरकारी क्षेत्र में खोल रहे हैं। एक बीकानेर में, एक भरतपुर में, एक झालावाड़ में और एक अजमेर में इंजीनियरिंग महिला महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में हम खोल रहे हैं, चार नये इंजीनियरिंग कालेज की हमने शुरुआत की है। इस बार हमने यही नहीं कालेज खोल रहे हैं इनमें 644 अब तक हमने भर्ती कर दी है, 207 पदों के लिए और हमने अभ्यर्थना भेज दी है। इसी प्रकार इस वर्ष में 538 नियुक्तियां और 263 पदोन्नतियों की बात भी हमने की है। पिछले 5 वर्ष में कुल 66 करोड़ रुपये टेक्नीकल शिक्षा पर खर्च हुए थे अब तक हमने तीन वर्ष में 104 करोड़ का व्यय कर दिया है और प्रदेश के और भी बहुत से काम हैं जो हम इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। कुछ और घोषणाएं हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनको लिखित में मैं यहां पर सदन के पटल पर पेश कर दूंगा ताकि जो आगे काम करने वाले हैं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वह आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद भी दूं और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद दूं, यह कोई मेरी योग्यता नहीं है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि मुझे केब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यह एक विपक्ष से बनना था, एक कांग्रेस का बनना था, एक वामपंथियों में से बनना था, तीन अध्यक्ष बनने थे तो उनमें से अर्जुन सिंहजी ने मुझे चुन लिया और यूनिस्लाइजेशन ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया और हमारे सी.के. मैथ्यू साहब जो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेट्री थे उनको भी मैंने साथ लिया था। हमने सारे राज्यों से बात की, बात करने के बाद हमने कहा कि आज आजादी के 60 साल बाद हमारे गांव के लोग आकर खड़े होकर सामने कहते हैं हमारे सैकण्डरी स्कूल खोल दो, हमारे प्राइमरी स्कूल खोल दो और स्कूल खोलकर हमने कौनसा अहसान कर दिया, क्या पढ़ाया, हमने साइंस खोली नहीं, वाणिज्य हमने खोली नहीं, आर्टस के अंदर खोले, सारे काम हमने किये। इसलिए हमारी एक कमेटी बनी, उस कमेटी की सिफारिशें हुईं और मुझे कहते हुए प्रसन्न्ता है कि केब की यूनिस्लाइजेशन ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन की जिस कमेटी का मैं चेयरमैन था, जैसी रिपोर्ट जिस रूप में हमने दी उसी रूप में केब ने भी स्वीकार कर ली और भारत सरकार ने भी स्वीकार कर ली।

मैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद ही 'सर्व शिक्षा अभियान' जो डा. मुरली मनोहर जोशी ने शुरू किया था, आठवीं तक, उस 'सर्व शिक्षा अभियान' को अब दसवीं तक, बारहवीं तक करने का भारत सरकार ने मान लिया है और उसके माध्यम से हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसमें हमने साफ रिपोर्ट की कि यह अधिकार है हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे का यह अधिकार है, उस व्यक्ति का जो भारत में पैदा हुआ है फ्री कंपलसरी एजुकेशन बारहवीं तक प्राप्त करे, यह लेने का अधिकार उन बच्चों का है और देने का कर्तव्य भारत में राज करने वाले नेताओं का है। अगर आजादी के 60 साल बाद हम उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बारहवीं तक नहीं दे सकते तो हमारे कर्तव्य से हम च्युत होते हैं, यह उस रिपोर्ट में था। उसके आधार पर एजुकेशन पर एक परसेंट का सेस बढ़ाया गया और इस बार हमें दिया गया और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले इसका भी बड़ा हिस्सेदार राजस्थान बना। मुख्य मंत्रीजी ने 150 करोड़ रुपये सैकण्डरी एजुकेशन की सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए दिया वह हम वहां पर ले गये। वहां पर ले जाने के बाद वह योजना स्वीकार हो गई। अब सैकण्डरी स्कूल खोलने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, पहली

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बार अध्यक्ष महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो राजस्थान की हालत थी कि हमारे यहां 9 हजार पंचायतों में सिर्फ 4 हजार पंचायतों में सरकारी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी थी। 1400 हमने खोल दीं, पिछली साल नहीं खोलीं, दो बार में हमने 1400 स्कूल खोलीं। इस बार तय करके 2100 का सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी, 1500 और 600 खोलने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। हम कोशिश कर रहे हैं आंकड़ा और बढ़ जाए और मुझे पूरा इसका इल्म है कि 2100-2200 का जो आंकड़ा दिया है वह आंकड़ा 2800-3000 तक जाएगा और हम इसका निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे पास बजट है, प्रावधान है और उसमें अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान) श्रवण कुमारजी, एक बार बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना का और सदन की भावना का आदर करता हुआ और इस बात को मिटाता हुआ कि बहुत भेदभाव है, बहुत भेदभाव है ..(व्यवधान) कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके निर्देश की और मुख्य मंत्रीजी ने भी कल यह कहा था कि आपको 2100 तो दे दिये हैं, लेकिन लड़कियों का जरूर ध्यान कर लेना। तो राजस्थान में 371 लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल हैं उन 371 को हम सीनियर सैकण्डरी में बदल देंगे, वो किसी भी माननीय सदस्य की कांस्टीट्युएंसी में है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपर प्राइमरी हमने सब कर दी, मैंने देख ली, कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ स्कूलें जो प्राइमरी स्कूल लड़कियों की अपर प्राइमरी बनने से रह गई हैं उनको भी हमने आदेश जारी करने के निर्देश दे दिये हैं कि जितनी पिछले सत्र में प्राइमरी स्कूल लड़कियों की थीं एक्सक्लूसिव उन सब को अपर प्राइमरी में बदल दिया गया है और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि जितनी सैकण्डरी स्कूल लड़कियों की हैं 371, उन 371 को हम सीनियर सैकण्डरी में कन्वर्ट कर रहे हैं।

मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा, केवल यही नहीं कर रहे हैं हमने जो सीनियर सैकण्डरी खोलने की घोषणा की है उन सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में 400 स्कूलों में साइंस का सब्जेक्ट खोलेंगे ताकि जो टेक्नीकल शिक्षा का विस्तार हो रहा है उसमें साइंस में लोग पढ़ सकेंगे। अब वह जमाना नहीं है हम किसी को झुनझुना देकर, श्रवणजी, झुनझुना देकर भेज दें, स्कूल खोल दी, स्कूल खोल दी, जब तक साइंस नहीं आएगी तब तक यह नहीं होगा और अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी-सी बात कह रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने झुंझुनूं को मजाक ही बना लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): झुंझुनूं कैसे मजाक हो सकता है, झुंझुनूं तो हमारे सर माथे पर है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, यह मजाक है, देख लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मजाक मैं नहीं कर सकता, मेरा ससुराल है वहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह रहस्य खुला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपकी कांस्टीट्युएंसी चिड़ावा में ही है ..(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मुझे इस बात की खुशी है शिक्षा मंत्रीजी की ससुराल मेरे यहां है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं नजर जरा ठंडी रखना।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कुछ मजाक करने का मेरा अधिकार है आपसे। वैसे ही झुंझुनूं जिले से कैसे कर सकता हूं, शीशरामजी ओला साहब, रामनारायणजी चौधरी साहब और सब के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर मेरी मजाक करने की हिम्मत कहां है? श्रवणजी तो हमारे दोस्त की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन तीन तो ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इसी का परिणाम है, यहां पर एक बात की आलोचना की गई, आलोचना का स्वागत है, लेकिन माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा उसका जरा अध्ययन कर लें। मुझे कहा गया कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। मैं हां भर रहा हूं। आज राजस्थान में 351 से ज्यादा संख्या, मैं करेक्ट कर लूंगा और 30 हजार लड़के बी.एड. में हैं। जब मैं आया था तो सिर्फ 55 थी। अब 300 है और 30 हजार लड़के पढ़ रहे हैं और उसके पहले क्या था। हमने इनकी फीस तय की।

20 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा तो इसके साथ ही राइडर लगाया कि जब तक एफिडेविट से लड़का यह नहीं कहेगा कि 20 हजार से अधिक फीस ली है, चर्चा नहीं करे, उसके पहले राजस्थान के लोग जम्मू में जाते थे, एक लाख रुपये देकर जाते थे, यू.पी. में जाते थे, डिग्रियां लेकर आते थे।

अध्यक्ष महोदय, यह बी.एड. के कालेज उतनी संख्या में खोले, वह लोग जो बाजारीकरण करते थे, जो दलाली करते थे शिक्षा में, उनके पेट में बड़ी तकलीफ हुई। वह प्रचार करने लगे, इतने बी.एड. क्यों खोल दिये इसलिए खोल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिये कि राजस्थान के लोग यहां पढ़ रहे हैं, आज सीकर में, झुंझुनूं में, अलवर में, दौसा में सब जगह पढ़ रहे हैं और उन बी.एड. वाले हमारे लड़कों के कारण से आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो रिजल्ट निकला है, अभी आर.पी.एस.सी. का वह जो आने वाला है, उसमें अधिकांश राजस्थान के लोग हैं, ये आये हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यकता थी, आज 30-40 हजार अध्यापकों की प्रतिवर्ष राजस्थान को आवश्यकता है, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर है, चाहे वह सरकारी सैक्टर है और उनको करना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा तो बी.एड. की जरूरत थी, हमने खोली। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन में हमने कालेज खोला, क्यों खोला ? सरकार ने 116 और 12 अभी हमारी सरकार आने के बाद में यह सरकारी कालेज हैं, इन सरकारी कालेजों में कितनी भीड़भाड़ मारामारी थी, मेरिट में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के जहां आते नहीं थे, अब यह जब लेगिंग एरिया घोषित करके उनको सरकारी स्कूलें भी दी उनको दो पारी में चलाया, वहां खोले भी, अब नया-नया काम है, कभी इसमें गड़बड़ हो सकती है, किसी के पास बिल्डिंग नहीं होगी, किसी के पास फैकल्टी नहीं होगी, मैं जानता हूं लेकिन एक चला और चलने के बाद में जो कालेज एजुकेशन का जो विस्तार हुआ, आज राष्ट्रीय औसत है 8 प्रतिशत का और राजस्थान का औसत हो गया 11 प्रतिशत हायर एजुकेशन में। देश में औसतन 77 हजार की जनसंख्या में एक महाविद्यालय है, राजस्थान में 63 हजार हो गई है और 46 हमारे पास एन.ओ.सी. के लिए पैंडिंग है जो जुलाई में खोलेंगे और यह एवरेज 54 हजार का हो जाएगा। हम हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर होंगे कालेज एजुकेशन में और 2 लाख से बढ़कर संख्या 4 लाख हो गई। हर साल एक लाख कालेज स्टूडेंट्स की संख्या और यह कालेज स्टूडेंट्स की संख्या, अध्यक्ष महोदय, अगर केवल शिड्यूल्ड कास्ट के शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नहीं होती तो हालत आज यह है कि अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ी है, 7·3 परसेंट, अनुसूचित जनजाति की बढ़ी है 12·97 परसेंट और ओ.बी.सी. की बढ़ी है 16·79 परसेंट और लड़कियों ने तो रिकार्ड कायम कर दिया। जब सरकार बनी थी उस समय राजस्थान में कालेज में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 68 हजार थी जो आज बढ़ कर हो गई है 1 लाख 40 हजार, इतनी लड़कियां हैं और इसके अलावा हमने 18030 लड़कियों को रोडवेज की बसों में फ्री आने-जाने का पास जारी किया, 12वीं, 10वीं पास की लड़की है, वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन से हमने दिया और लड़कियों की संख्या बढ़ गई लेकिन इसमें खतरा भी पैदा हो गया, इसका एक आंकड़ा भी है। सवर्ण कास्ट, जो जनरल कास्ट है उसके लड़कों की बजाय लड़कियों की संख्या ज्यादा है कालेज एजुकेशन में। उनके लड़के कम पढ़ रहे हैं। (व्यवधान) उसका कारण तो कुछ भी है, मैंने मीटिंग में कहा था, कारण तो कुछ भी है लेकिन कुंवारे रहने का खतरा तो पैदा हो गया, यह तो खतरा उनको पैदा हो गया है तो यह सारा काम जो हुआ है, एक अभूतपूर्व काम है, इसमें हमारी शिक्षा में इसी प्रकार से रोजगार, हमने इसका अपग्रेडेशन करने के लिए, प्रत्यायन करने के लिए 80 प्रतिशत महाविद्यालयों का प्रत्यायन करा लिया है और यह पहली बार अपग्रेडेशन का काम हमने किया है, इंगलिश लैंग्वेज लेब की स्थापना की है, नालेज कोरिडोर की भी की है, भर्तियों के बारे में प्रश्न उठाया गया है, भर्तियां कर रहे हैं, 4 सौ, 456 की आपने बात की, वह की है, अब आर.पी.एस.सी. का नियम है, भर्ती करता है, हमने आर.पी.एस.सी. को अभ्यर्थना भेजने में लेट दो- तीन महीने की हो गई, मैं मानता हूं, वह स्वाभाविक रूप से यह जो सरकारी सारी प्रक्रियाएं हैं, फाइनैंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, आना स्वीकृति मिलना उसके तो लाख प्रयत्न करते रहने पर सभी इतना टाइम तो लग ही जाता है। उसके कारण से इसकी भर्तियों की कार्यवाही चालू हो गई है और आज मैं कह सकता हूं कि महाविद्यालयों में किसी भी स्तर पर कोई पदोन्नति बकाया नहीं है, सब डी.पी.सी. कम्पलीट करके हमने इस काम को पूरा कर दिया है, कोई बैकलॉग नहीं है और दूसरी बात और कहना चाहता हूं। इसमें हम जो बैकलॉग का प्रश्न भी उठा था, हमने इसमें बैकलॉग के सहित, मैं एक बात आप सब को, पूरे सदन को विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं, नागर साहब, आपको भी, सुरेशजी, आपको भी, मुरारी जी, आपको भी, आप यह निश्चित मान कर चलिए कि संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का, सरकार किसी भी स्थिति में उसको कम नहीं होने देगी और जो भर्तियां होंगी, उसमें बैकलॉग पूरा होगा और रोस्टर को भी ठीक करेंगे, बैकलॉग को भी ठीक करेंगे, यह भी करेंगे और आदिवासी इलाका जो हमारा है उसमें जो उनको जितना दिया गया है, उसको भी पूरा करेंगे। पिछली बार आदिवासी इलाके में एक गलती मेरे से हो गई। (व्यवधान) जिले में क्या गलती हुई मेरे से, मेरे से गलती यह हुई कि हमने आदिवासी इलाके की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लड़कियों को भी बाहर लगा दिया इसलिए लगा दिया कि जो आपकी जितनी संख्या थी उससे ज्यादा आ गई, तो अब यहां के आदमी अगर सीकर, झुंझुनूं में आपको पढ़ाने के लिए वहां लड़कियां जाती हैं तो आपकी लड़कियों को इधर आने दीजिए, विस्तार होने दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह वहीं रहेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह वहीं रहेंगी तो फिर पिछड़ जाओगे तो एक बार लगने दो फिर वापस भेज देंगे, आगे बढ़ो, इसमें समस्या क्या है ? तो बाकी मैंने उनकी भर्ती पिछली बार 18 सौ, कितनी बाकी रह गई थी, इस बार जो एरिया है, उसकी जितनी बकाया हैं, वह सारी की सारी भर्ती होगी और आज मैं यहां यह भी घोषणा कर रहा हूं इसी अप्रैल के महीने में जो आना वाला है जो उसमें 3 हजार विधवाओं का जो हमने इंटरव्यू लिया था, उनकी नौकरी भी इसी अप्रैल के महीने में उनको लगा दिया जाएगा। इस अप्रैल में उनका काम पूरा हो जाएगा।

महाविद्यालयों के संबंध में और कई घोषणाएं, अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटराइजेशन कर रहे हैं, एक अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की बहुत बड़ी समस्या है कालेज एजुकेशन में, एक और इसमें भी है, उसको फ्रीज कर दिया कि इतना रुपया आपको मिलेगा, पहले 10 परसेंट कम हो रहा था, हमने उसको फ्रीज कर दिया। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं, मैं भी अनुदानित शिक्षण संस्था में पढ़ा हूं, बद्रीदास दाउजी का स्कूल उसमें 50, 60 परसेंट अनुदान मिलता था, उनमें पढ़ कर आये हैं हम तो कोई इंगलिश स्कूलों में या उसमें पढ़कर आये नहीं हैं तो उन्हीं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में पढ़ कर आये हैं तो उनकी स्थिति खराब है तो सरकार इसमें विचार कर रही है, मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा है कि वह निश्चित रूप से कुछ हल इसका निकालेंगी, इसके एक्ट में संशोधन भी करेंगे और स्थिति जो खराब हो गई है, उसको ठीक करने का भी सरकार निश्चित रूप से प्रयत्न करेगी और उनको हम करेंगे। जो नये कालेज खुले थे उनकी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर ही दी थी इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा की मैंने कह दी, तकनीकी शिक्षा की कह दी, अब मैं प्राथमिक शिक्षा पर आना चाहता हूं। (व्यवधान) धन्यवाद है, अपन सब मिलकर काम कर रहे हैं, राजनीति मैं इसमें शिक्षा में कर ही नहीं रहा हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(व्यवधान) संयमजी ने इसको रोचक बनाया, मुझे प्रेरित किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं नहीं तो मैं सुस्त होकर बोलता।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विस्तार करने में यह कहा गया यूनेस्को अवार्ड, धन्यवाद देना चाहिए, इसमें कोई मेरी सरकार की ही नहीं है, हमारी, सॉरी, मेरी, हमारी, दोनों में आपको तकलीफ है। राज्य सरकार का ही केवल योगदान नहीं है, कांग्रेस ने यह परसों कहा है कि हम राजीव गांधी पाठशाला नहीं खोलते तो आप क्या करते ? कुछ हद तक मैं तो पहले ही मान चुका हूं, बार-बार कहने की जरूरत ही क्या है ? लेकिन यह राजस्थान का कार्यक्रम है, यह अवार्ड किसी प्रांत को नहीं मिलता है, यह प्रांत को नहीं मिलता है, राष्ट्रों को मिलता है, हमने एप्लाई भी नहीं किया। जिन प्रांतों की यहां पर तुलना हो रही था भारत सरकार ने उनको डेटा भेजे, बिहार के, यू.पी. के, सब के, मैं इस वाद- विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, हमने एप्लाई भी नहीं किया लेकिन वर्ल्ड जूरी जो बैठी उन्होंने तय किया कि पिछले सालों में राजस्थान ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सतत् शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वह उन राष्ट्रों को मिलने वाले काम से भी ज्यादा है, जो हमेशा आज तक केवल राष्ट्रों को मिलता था। चीन को मिला, अर्जेंटिना को मिला, मोरक्को को मिला और भारत को नहीं मिला क्योंकि भारत का एवरेज कम था लेकिन राजस्थान का एवरेज राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा था इसलिए राजस्थान को 20 हजार डालर का अवार्ड चीन में मिला, यूनेस्को के द्वारा मिला, प्रतिष्ठित अवार्ड है, भारत सरकार ने भी पत्र इसके लिए धन्यवाद दिया है तो मैं सारे सदन के माध्यम से सारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमने एप्लाई भी नहीं किया और जब वह मिला ...(व्यवधान) तो वह मुझे कह रहे थे कि विशिष्ट विचारधारा का, विशिष्ट विचारधारा का सवाल नहीं, विचारधारा को लेकर हम राजनीति में हैं, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, विचारधारा है, आपकी भी राजनीतिक विचारधारा है, मेरी भी राजनीतिक विचारधारा है तो हमने उस सारे पैसे का एक ट्रस्ट बनाया, सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्दर इस साल परम पूज्य गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष था उनका रुपया करके 11-11 हजार रुपये के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को प्रतिवर्ष श्री गुरुजी के नाम से पुरस्कार मिलेंगे और उसका परमानेंट ट्रस्ट हमने उसका बना दिया है, वह हमको इसका मिला है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कितने विद्यालय खोले गये, कितने क्रमोन्नत किये, हमारे साथ भेदभाव किया। भेदभाव नहीं किया, थोड़ा बहुत हो

गया होगा। अब मैं बता दूं, शुरू में ही मैंने कह दिया न कि अब पूरा कर देंगे। अब राजीव गांधी पाठशालाओं को जब क्रमोन्नत किया तो सब की हुई, जब सारी बालिकाओं को किया तो नहीं हुआ। सुनो तो सही। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि हमारे सीकर में राव राजा कल्याण सिंहजी थे। उनके लड़के हरदयाल सिंहजी इंग्लैण्ड से पढ़कर आ गये। आ गये तो उन्होंने एक इंटरव्यू कर लिया कि हमको एक अकाउंटेंट रखना है। एक आदमी मेरे जैसा आया, उसने कहा बी. कॉम. और कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठ गया तो कल्याण सिंहजी ने पूछा कि कितना पढ़ा है, तो कहा कि बी. कॉम। तो राव राजा साहब ने कहा कि इसको फेल करो, बोले क्यों, तो कहा कि यह टुकड़ों में है, पहले दसवीं की, फिर बारहवीं की, फिर बी. कॉम. किया और इसको तहजीब नहीं है, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। दूसरा आया, उसने कहा खमां-घणी हुकुम, पूछा कि कितने पढ़े हो? बोला- नॉन मैट्रिक वर्नाकुलर। पूछा कि गिनती आती है तो कहा कि आती है। फिर पूछा कि 10 और 10 कितने होते हैं तो जोड़कर के बोला कि 19, महाराज कुमार ने कहा कि महाराज, गलत है। बोले कि कितनी गलती है तो उन्होंने कहा कि एक की गलती है तो कहा कि इतने बड़े राज में एक की गलती तो चलती है। तो यह छोटी सी गलती तो चलेगी। इतना सा भेदभाव झंडा देखकर के कर दिया तो क्या हो गया। मैंने सब जगह पत्र लिखे हैं कि आपके ये विद्यालय खोले हैं, ये विद्यालय खोले हैं। थोड़ा बहुत तो झंडा देखकर हो जाता है। लेकिन इस बार जो लड़कियों की एक साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कराई है वह सभी कांस्टीट्यूएंसी में होगी इसलिए कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 54 हजार इसी साल, यह तुलना नहीं है, जब हम काम की आलोचना करते हैं उसमें हम काम की तुलना भी करें। जिस समय सरकार आई उस समय 50 हजार सरकारी विद्यालय थे यहां पर और इस बार का जो हमने सर्व शिक्षा अभियान का भेजा है और अब तक जो 40 हजार स्कूल खोले हैं उन सारे स्कूलों के जो हमने भेजा है अगर 50-50 पर भी स्वीकृत हुआ, 75-50 पर भी स्वीकृत हुआ, अगर 50-50 पर भी शुरू हुआ तो अध्यक्ष महोदय, ''आधा मैं देवी-देवता और आधा मैं खेतरपाल''। सरकार के आने के पहले 50 हजार थी और मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद तीन वर्ष में 50 हजार स्कूल खुल गई या क्रमोन्नत हो गई। यह क्या काम है? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं 3 वर्ष की और 5 वर्ष की, मैं तुलना कर रहा हूं 57 वर्ष की और 3 वर्ष की। इसमें तो थोड़ी बहुत बड़ाई करनी चाहिए, इसमें कोई थोड़ी बहुत कर दे तो मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई फूलता थोड़े ही हूं बड़ाई से। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह हमने काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कक्षा कक्ष कितने बने। हमने 9092 विद्यालय भवन बनाये हैं, 46019 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये हैं, 24357 शौचालय बनाये हैं, 18076 पेयजल का विस्तार किया, एक करोड़ बच्चों का मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल अभियान में मेडिकल कार्ड बनाकर के परीक्षण कराया और 18 हजार बच्चों को आंखों के चश्मे उपलब्ध कराये। ये काम कम नहीं है, पहली बार हुआ है। अब इसमें भारत सरकार का पैसा है, मना कौन कर रहा है, बिलकुल है, सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उस योगदान के साथ-साथ यह योगदान भी दीजिये कि जिस दिन हम आये थे, 220 करोड़ रुपया टोटल प्लान थी और आज 800 करोड़ रुपये की मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृति दे दी है। राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत हुआ तो 1600 करोड़ तक जाएगा और 75-25 का हुआ तो 2 हजार को क्रोस करेगा। सबसे बड़ी योजना राजस्थान की हो जाएगी।

अभी कई राज्यों की तुलना हो रही थी। मैं तो कहना नहीं चाहता हूं, मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, लगे हैं पैराटीचर। मेरे पास बिहार के उप मुख्य मंत्रीजी भी आकर के गये थे। उनके पैराटीचर्स की समस्या हो गई। मध्य प्रदेश वालों के भी कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। वो जितने टीचर्स का आप पढ़ रहे थे वो कोई भी रेगुलर वेजेज पर एक भी स्टेट में 'सर्व शिक्षा अभियान' में टीचर नहीं लगे। सिर्फ राजस्थान में लगे हैं। 54246 लग गये, 30 हजार की निकल गई, 3 हजार की मैंने घोषणा कर दी, 38 हजार की प्रक्रिया है पूरी, 94 हजार समझ लीजिये एक लाख नहीं। अगर जुलाई खुलने के पहले-पहले भर्ती हो जाती है और रेगुलर हो जाती है, बैकलॉग पूरा करके हो जाती है, महिलाओं की संख्या उसमें 40 प्रतिशत हो जाती है तो इससे बढ़िया और क्या राजस्थान विकास करेगा? मैंने एक पुस्तक भेजी है माननीय सदस्यों को, उसमें कोई गलती हो तो मुझे बता दें। 'यह तो अथ है' मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने काम पूरा कर लिया है, 'अथ' का मतलब यह तो प्रारम्भ है। इसलिए हमने उन शिक्षण संस्थाओं की लिस्ट दी है कि जो हमने नियमों में संशोधन करके छूट देकर के जो किया है उनमें भी 98 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। अकेले शिक्षा विभाग ने 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट रूप से रोजगार, पेमेंट का, भुगतान का और नौकरी पर लगा दिया है। मुख्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी ने एक लाख की घोषणा की थी सारे राज्य में मिलाकर, सरकारी नौकरी भी, प्राइवेट रोजगार की, दो लाख तो केवल इसने दिया और 8 हजार करोड़ हमारा इन्वेस्टमैंट हो गया है। यह कम नहीं है इसलिए इस काम की भी प्रशंसा की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राप-आउट के बारे में चर्चा हुई। ड्राप-आउट था राजस्थान में, आज भी है लेकिन जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 71 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत और जेंडर गैप 10 प्रतिशत कम हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा कम हुआ है 10 प्रतिशत कम हो रहा है। अब भर्ती की प्रक्रिया हमारी चल रही है। फिर बालिकाओं के बारे में एक और समस्या आई कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब लोगों की बच्चियां जो पिछड़ गईं, जो आ सकतीं उनके लिए क्या कर रहे हैं। उनके लिए कस्तूरबा गांधी, जो पहले 30 खोले थे, 150 की और स्वीकृति आ गई है और मैं आज आया हूं तब दस्तखत करके आया हूं, राजस्थान के 184 ब्लॉक में जुलाई के महीने से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय प्रारम्भ हो जाएंगे और उसमें सब में मिलाकर के 15 हजार बच्चियां पढेंगी। एक बच्ची पर 800 रुपये महीने का खर्च आयेगा। अध्यक्ष महोदय, एवरेज यह है कि आज जो नौकरी करने वाला भी आदमी है उसके अपने घर के बच्चे पर 600 रुपये महीने का सामान्य खर्चा है और 800 रुपये महीने का देकर के हम उस बच्ची को रख रहे हैं, उसको वहां रखेंगे, पढ़ायेंगे-लिखायेंगे, काम करेंगे, इतना काम किया है। तो प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में तो मैंने बता ही दिया...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय मंत्रीजी, इतना बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्टेट का भी शेयर है क्या या पूरा का पूरा भारत सरकार का है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, इसका भी है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था, मेवात में लड़कियों के आवासीय विद्यालय बनायेंगे, आप स्वीकृत तो करिये तभी तो बनेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सुनिये, मेवात के, आज ही मुख्य मंत्रीजी के आदेश से 6 विद्यालयों का मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, 6 विद्यालय मेवात के खोलने के आदेश जारी करके मैं सदन में आया हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, लैंग्वेज टीचर्स की वेकेंसी भी फिल-अप कर दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं आ रहा हूं। इस प्रकार से एक जो विषय है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये काम चल रहे हैं, ये काम 2020 तक चलाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यह काम केवल राज्यों के बलबूते पर नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने पत्र लिखने का आग्रह किया, उन्होंने टेलीफोन पर बात की है, और राज्यों के मुख्य मंत्री भी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी कह रहे हैं, स्वयं मानव संसाधन मंत्री कह रहे हैं, पूरा मानव संसाधन मंत्रालय कह रहा है कि यह जो 'सर्व शिक्षा अभियान' में पैसा मिल रहा है वह 75:25 से कम नहीं होना चाहिए। इसके दो कारण हमने बहुत बड़े दिये। एक तो जो सेस लगाया है वह एक तरह से टैक्स ही है उसमें राज्यों का हिस्सा होता है वह राज्यों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से जो बाहर का अनुदान आता है वो और बाकी भारत सरकार की योजना, 25 प्रतिशत से ज्यादा राज्य सरकारें सहन नहीं कर सकतीं। इसलिए हम चाहते हैं कि वह 75:25 का रेश्यो बना रहे इसके लिए आप लोग भी प्रयत्न करें, हम भी कर रहे हैं और 75:25 का रेश्यो रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दो साल के बाद में यहां खड़े होकर के आपको आवाज लगानी पड़ेगी कि प्राइमरी स्कूल लेने वाला है क्या, सैकण्डरी स्कूल लेने वाला है क्या, अपर प्राइमरी लेने वाला है क्या। मिलेगा ही नहीं। अगर रेश्यो कम हो गया, जो मांगने वाला था कि हमको दे दो, अब कहे ले लो, यह स्थिति पैदा होगी। यह प्राइमरी और अपर प्राइमरी में तो हमने की है। 2000 जो अल्टरनेटिव स्कूल थीं उनको भी प्राथमिक विद्यालय में बदलने का प्रस्ताव हमारा भेजा हुआ है और प्रस्ताव सिद्धांत रूप से भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अब वो योजना पर डिपेंड करता है कि कब होगी। अध्यक्ष महोदय, 600 अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में मैंने बता दिया। कुछ घोषणाएं हैं। सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें इस साल भी वितरित होंगी। पहली से 12वीं तक सभी को होंगी। एक माननीय मुख्य मंत्रीजी से हम आग्रह करेंगे कि जैसा अभी जनजाति क्षेत्र का खांट साहब ने मामला उठाया था, जनजाति क्षेत्र में कुछ संस्थाएं सेवा के भाव से काम कर रही हैं और हमारे पास पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, मुख्य मंत्रीजी दयालु हैं लड़कियों पर और आदिवासी क्षेत्र पर, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में जो सेवा के भाव से काम करने वाले विद्यालय हैं उनके बच्चों को भी पाठ्य-पुस्तकें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फ्री में मिल जाए, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करेंगे। इनकी कृपा होगी। मिड-डे-मील का तो बाद में करेंगे, पहले किताबों की तो करें। अंगुलि पकड़ते-पकड़ते पोंछा पकड़ो।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से 1,134 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमने तीन-तीन कम्प्यूटर, कम्प्यूटर लर्निंग प्रोग्राम के तहत दे दिये हैं और इस साल 500 में और उपलब्ध करा देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी प्रकार से 2,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब हमारे तीन-तीन कम्प्यूटर चले जायेंगे। 1000 विद्यालयों में सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं जिनमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय होंगे। बच्चियां वहां रात में रहेंगी तो बिजली के लिए सोलर पावर सिस्टम की आवश्यकता है, कम्प्यूटर के लिए है तो 1000 ग्रामीण विद्यालयों में यह लगायेंगे।

इसी प्रकार ब्रिज कोर्स के बारे में आया है। वह आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा संयम साहब, आपका पुराना आंकड़ा है। अब वह पूरे हो गये हैं। वह मैं आपको बताऊंगा अभी। 1.50 लाख बच्चों को देंगे। संभाग स्तर पर जो कच्ची बस्ती के बच्चों को परिवहन सुविधा, 15,447 बच्चों के लिए 1.85 करोड़ की लागत से परिवहन सुविधा मुफ्त करने का सरकार ने तय किया है। 10,800 विद्यालयों में जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए रैम्प का निर्माण करेंगे ताकि वह पढ़ने के लिए जा सकें। 18,700 बच्चों को पुन: नि:शुल्क अंग व उपकरण, चश्मा वगैरह देने का सिस्टम किया है और 8,920 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ए.सी. किट वितरित होगी तथा गुरु-मित्र कक्ष बनेंगे। पहली से आठवीं तक की बालिकाओं को, वे सभी वर्ग की हैं, जनरल, ओ.बी.सी., एस.सी. एस.टी., माइनोरिटी, जितनी भी हैं सब, उनको पहली से लेकर आठवीं तक सभी बालिकाओं को वर्गबुक नि:शुल्क उपलब्ध राज्य सरकार की ओर से कराई जायेगी। यह काम भी हम करेंगे।

इस बार भी 'मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल महाभियान' 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तहत अब तक विश्व आर्थिक मंच से सम्बन्धित 19 संस्थाओं से एम.ओ.यू. हुए हैं। इस वर्ष भी निजी एवं क्षेत्रीय सामूहिक संगठनों की भागीदारी से कम्प्यूटर शिक्षा का काम पूरा होगा। भारतीय फाउण्डेशन द्वारा 50 विद्यालयों में प्रबन्ध सहभागिता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हम करेंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक और घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कल मैंने बातचीत की थी और यह बहुत लम्बे समय से है, सब लोगों को आशा थी कि यह जो कम्प्यूटर शिक्षा है, इसके बारे में स्थिति यह है, यह है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया है कि एक जुलाई से पूरे राजस्थान में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा नि:शुल्क बच्चों को पढ़ाई जायेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको स्वीकार किया। आपने भी मांग की थी खांट साहब। आपकी बात को मुख्य मंत्रीजी ने सुन लिया था अन्दर बैठे-बैठे, वह काम उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से काम हैं जो किये हैं लेकिन मैं उसमें लम्बा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं बोल चुका। अध्यक्ष महोदय, अब दो-तीन बातें आपसे कहूंगा। पहली बात तो मैं कहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं एक बात कह कर खतम ही कर रहा हूं। दो-तीन बातें कही गई हैं। किताबों के बारे में जो गलती है, मैं उसको खुद देखूंगा। मैं यह सोचता हूं कि मेरी धारणा है कि भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के भेद को मैं मानता ही नहीं। मेरा कहना है कि 'अल्पसंख्यक' शब्द, यह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यह रिलीजन के कारण से नहीं हुआ, यह वर्ग के कारण से हुआ। 'गोरे' और 'काले', दक्षिणी अफ्रीका में हुए। एक ही सम्प्रदाय और एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन फीड अलग है, वर्ग अलग है। उनमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है। यहां हिन्दू और मुसलमान में क्या फर्क है। हमारे पूर्वज एक हैं। इस देश में आपको उतना ही अधिकार है, जितना माहिर साहब को प्राप्त है, उतना ही घनश्याम तिवाड़ी को है, कोई ज्यादा नहीं है। इसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है और यहां का जो इस्लाम है, इसकी खुशबू ही दूसरी है। यहां का जो इस्लाम है, वह जिस प्रकार से यहां साधु-संतों से और सूफी-संतों से फला-फूला है, आगे बढ़ा है, उसकी खुशबू हिन्दुस्तान की मिट्टी से मिलती-जुलती है इसलिए हम किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहते।

मुझे अच्छी तरह ध्यान है इतिहास के बारे में इसलिए हमने इतिहास लेखन योजना की घोषणा की। मदरसों को हमने दिया है, वेद विद्यालयों को हमने दिया है। वेद विद्यालयों से ज्यादा मदरसों को दिया है। हर मदरसे को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

50,000-50,000 रुपये कम्प्यूटर के लिए है, उनके आधुनिकीकरण के लिए पैसा दिया है। उनको मिड-डे-मील के लिए दिया है। उनको शिक्षा सहयोगी के लिए दिया है। उनको और भी देंगे। कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से हर जिले में वेद विद्यालय को दो लाख रुपये की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। वह भी हम कर रहे हैं, वह काम पूरा हुआ है।

मुख्य मंत्रीजी ने एक और स्वीकृति दी कल अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने आज कहा भी था। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि 1,345 की वेकेंसी शारीरिक शिक्षकों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में है, 145 की सैकण्डरी में है, कुल 1,500 शारीरिक शिक्षकों की भी इस साल में भर्ती की जायेगी। पी.टी.आई. की जो विभाग में थे, वह काम भी कर दिया है तो यह जो पी.टी.आई. का काम है, वह भी हमने कर दिया है।

यह जो इतिहास लेखन का काम हुआ है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। कल कटारा साहब ने भाषण दिया था। आज अभी खांट साहब कह रहे थे। संत गोविन्द गुरूजी, मामा बालेश्वर दयालजी, पूंजा भीलजी, सब जानते हैं जब हम गाना गाते हैं तो बोलते हैं "महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंहजी ने बहुत बड़ा काम किया है" सब जानते हैं लेकिन गोकुला जाट को कभी याद ही नहीं करते। उसका भी तो इतिहास में स्थान है। डूंगजी, जवाहरजी की बात करते हैं, लोट्या जाट की कोई बात नहीं करता। महाराणा प्रताप की बात करते हैं, पूंजा भील की कोई बात नहीं करता तो हम जब यह इतिहास लिख रहे हैं तो आम आदमी का इतिहास लिख रहे हैं, जिसके कारण से यह राजस्थान बना हुआ है। केवल राजा-महाराजाओं के इतिहास लिख देने से राजस्थान का इतिहास पूरा नहीं होता। बहुत लोगों को लिखना पड़ेगा इतिहास को। यह किसी जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, किसी के खिलाफ नहीं है। जब हमने यह चयन करने की बात की कि राजस्थान में किस-किस ने क्या-क्या काम किया, आजादी के आन्दोलन में किसने काम किया, कौन लड़ा, किस-किस ने संघर्ष किया? वह कहानियां आएंगी तो आपके पिताजी की भी आएगी माननीय अध्यक्ष महोदय, करणीरामजी की भी आएगी तो वह कहानियां आनी चाहिए, वह दबकर पड़ी हुई है तो इसके लिए हमने कहा कि "दबे मत रहो पड़े भूमि में, और उठो तो बदल दो जमाना" वह जमाना बदलने के लिए अपने पुरखों से जुड़ना जरूरी है इसलिए हमने इस काम को किया है। यह किसी के खिलाफ नहीं है। क्योंकि मास्टरजी अकेले नहीं करेंगे। गांव-गांव में इसकी पूरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यापक योजना है। हमने **"ग्राम प्रथम"** चुनने का तय किया है। ग्राम प्रथम में कौन सबसे पहले गांव में शहीद हुआ, कौन स्वतंत्रता सेनानी हुआ, किसने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया, कौन सेना में गया, कौन इंजीनियर बना, कौनसी महिला सबसे पहले पढ़कर आई। ये 15-20 बिन्दु बनाये हैं। एक गांव में ग्राम प्रथम लगकर जब 40,000 गांवों में उन ग्राम प्रथम की लिस्ट लगेगी तो उनके बच्चों को भी याद आएगा कि हमारे पूर्वज थे और लोगों की प्रेरणा के स्त्रोत भी बनेंगे। यह केवल हमारे यहां भारत में नहीं चलता। यह चीन जो साम्यवादी देश है, उसने एक्स-चैनल के साथ, स्टीवाले के साथ अभी-अभी कांट्रेक्ट किया है, परसों अख़बार में आया था। जो पहले उनके राजा थे चीन में, उन राजाओं का इतिहास लिखने का काम चीन ने शुरू किया है। हम राजाओं का नहीं लिख रहे हैं। अभी अमेरिका और जर्मनी ने यूनिफिकेशन के बाद में इतिहास लेखन की योजना बनाई है। अमेरिका में save our history के नाम से एक प्रोग्राम सरकार ने चालू किया है। हम भी राजस्थान में हमारे पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए हमारे गांव की विधा को, गांव के साधु को, बावड़ी को, गांव के मंदिर को, गांव के पुरखों को और ग्राम प्रथम में अगर चयन करके एक संकलन करते हैं तो यह स्वाभिमान की बात है। किसी जाति-बिरादरी की बात नहीं है। तो गांव प्रथम गिनेंगे तो हमारे जिले के कायमखानी भी जो जाटों के साथ, राजपूतों के साथ शहीद हुए हैं, उनका इतिहास भी लिखा जायेगा। जिनको वीर चक्र मिला है, उनका भी नाम लिखा जायेगा। किसी का भेदभाव नहीं है। यह सारे राजस्थान भर के साथ इतिहास लेखन की योजना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत वह हमको सहायता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया था कि 23 जिलों में जो शिविर लगने थे, वह नहीं लगे। महिला शिक्षण शिविर 5,000 थे, 5,991 लगे हैं। वह दो महीने पहले के आंकड़े आपके पास हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक पंचायत समिति में जो शिविर लगाने थे, वह भी 5,474, 237x2, यानी 100 प्रतिशत सभी में लग गये हैं।

इसी प्रकार से शिक्षा गारंटी केन्द्रों को जो क्रमोन्नत किये हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो कुछ रह गये हैं, आपकी यह बात सही है, आपने कहा है कि हमने घोषणा की थी कि 700 विद्यालय बनायेंगे, वे वास्तव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में रह गये हैं। वे नहीं बने हैं और इसका कारण है। शहरी क्षेत्र में हमको भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए 700 के 700 विद्यालय शहरी क्षेत्र में बच गये हैं, नहीं बना पाये हैं। आपने आंकड़ा ठीक कहा था। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूंगा कि इस साल में वह हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां बहुत से प्रश्न उठाये, शिक्षा से अलग भी उठाये। उनका थोड़ा सा, हल्का सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। वैसे बीरूसिंहजी ने और जालमसिंहजी रावलोत ने कर दिया। हमें कहा गया कि गुरु गोलवलकर की जन्म शताब्दी मनाई गई। हां, हमने मनाई। हमने गुरु गोलवलकर के नाम से 'गुरु गोलवलकर योजना' भी प्रारम्भ की। गुरु गोलवलकर के नाम से हमने वह भी किया। हमने ही नहीं किया अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, जहां श्री गुरूजी का देहांत हुआ था तो स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रिकार्ड तोड़ा, उन्होंने कहा कि संसद में केवल एम.पी. और एम.एल.ए. को मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे संसद में हैं स्वर्गीय महात्मा गांधीजी को, जयप्रकाश नारायणजी को, उसके साथ परम पूजनीय श्री गुरूजी को भी संसद में नियमों को तोड़कर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तब उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। उन्होंने भी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वह राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व था। हम भी मानते हैं, किसी से हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, डाक्टर हेडगेवारजी के बारे में कहा गया, डाक्टर हेडगेवारजी पहले क्रांतिकारियों में थे, फिर नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के सह मंत्री थे और उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, यह बात ठीक है। हम जब इतिहास लिखते हैं कुछ संगठनों का, तो लिखते हैं कि भाई ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की, उसके बाद में क्रांतिकारी आये, विप्लवी आये, कांग्रेस के आज के स्वरूप का विकास हुआ। इतिहास लिखा जाता है, कांग्रेस का लिखा जायेगा, बी.जे.पी. का लिखा जायेगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी लिखा जायेगा। इतनी बड़ी शाखाओं के साथ, इतनी बड़ी संस्थाओं के साथ एक विचारधारा का जिसका प्रभाव हो, जरूर लिखेंगे और हम उससे सहमत हैं, हम यहां ना नहीं करते और हम यह भी कहते हैं कि जो कुछ थोड़ा-बहुत हमने सीखा है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में ही सीखा है। यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है और गलती

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई है जो हमारी है इसलिए मैं इसको इश्यू नहीं बनाना चाहता, अगर हिंदुत्व का इश्यू नहीं हो, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसमें लिखा है, मैं कह रहा हूं, दो बातों में मेरा विश्वास ही नहीं है, एक तो उन्होंने कहा कि यह वर्णाश्रम हम पढ़ा रहे हैं, मेरा कोई वर्णाश्रम में विश्वास नहीं है। वर्ण जन्मजात है ही नहीं। वर्ण के बारे में साफ लिखा हुआ है जन्मना जाते शुद्र कर्मणा द्विज उच्चते, चातुर्वर्णम् मयासृष्टम् गुणकर्म स्वभावजम्। चातुर्वर्ण की जो सृष्टि है...

श्री शांतिलाल चपलोत: गुण कर्म और विभाग से है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हां, गुण कर्म और विभाग से है, जन्म से है नहीं और वर्ण खतम है और जाति यथार्थ है अध्यक्ष महोदय, मानना पड़ेगा, आज हिन्दुस्तान में जो भेदभाव हुआ है वह जाति के कारण से ही तो हुआ है। मैंने शिड्यूल्ड कॉस्ट के घर में जन्म ले लिया आज के पच्चीस वर्ष पहले, एक लाख रुपये, मैं करोड़पति भी होता तो मुझे पास में बैठा लेते क्या? यह भेदभाव जाति के आधार पर ही तो हुआ, तो जो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ उस जाति के आधार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन जातियों को चाहे शिड्यूल्ड कॉस्ट की हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब की हो, उनको महत्व देना ही पड़ेगा और वह हमको समाप्त करना पड़ेगा और हम समाप्त करने में उसके लगे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, फिर कहा कि हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूं यहां, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, हिंदुत्व वेद भी है, हिंदुत्व आयुर्वेद भी है, हिंदुत्व ज्योतिष भी है, हिंदुत्व कर्मकांड भी है, हिंदुत्व हिंदुस्तान की अठारह-बीस भाषाएं भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, मुसलमान भी है, उर्दू भी उसी का अंग है। हिंदू का मतलब, जब यहां का मुसलमान हज करने जाता है तो उसको हिंदू-मुसलमान कहते हैं न, वह हिंदुत्व की परिभाषा है, वह राष्ट्रवाचक शब्द है, वह धर्मवाचक शब्द नहीं है। सर्वतो सनातन धर्म है, किसी का जैन धर्म है, कोई भैंरूजी को, कोई बालाजी को, यहां तो तैंतीस हजार देवी-देवता हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तैंतीस करोड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, तैंतीस करोड़ देवी-देवता हैं और दो हमारे में और मिल जाय, मोहम्मद साहब और ईसा मसीह, तो तैंतीस करोड़ दो हैं। तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसमें क्या फर्क है, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए सरकार किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं रखती है, सरकार किसी प्रकार की नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, काम करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया है और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की राजनीति शिक्षा में नहीं है। 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में हमको काम करना पड़ेगा। मैं आज सभी माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं कुछ और बातें कहना चाहता था लेकिन एक कार्यक्रम में भोजन में जाने के लिए सब पर्चियां भेज रहे हैं, भोजन में जाना है, मेरे तो नवरात्रा है..(व्यवधान) कुछ स्कूलें खुलने का, यूनिवर्सिटी खोलने के कई प्रावधान आये हैं, मैं तो घोषणा नहीं कर सकता, उन सारी बातों को माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करेंगे। पैराटीचर्स के बारे में मामला उठाया है, मुख्य मंत्रीजी खुद उस विषय को देख रही हैं, उसका समाधान करेंगी, और बहुत से काम हैं, जो प्रश्न उठे हैं, मैं अंत में आप सब से यही कहना चाहता हूं कि इस बार...

मोहम्मद माहिर आजाद: लेंग्वेज। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी के जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं उनको भरने की बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उनकी वेकेंसी निकाल रहे हैं। संस्कृत के 1070 पद थोड़े ही दिनों में और सेकण्ड ग्रेड के इन सभी सब्जेक्ट्स जो आपने बताये, इनके पद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रैल के पहले सप्ताह में उनकी वेकेंसी निकाली जायेगी। 2500 सेकण्ड ग्रेड के हैं और 1070 संस्कृत के थर्ड ग्रेड के और तीन हजार विधवाओं की नियुक्ति अप्रैल के महीने में हो जायेगी, कमेटी हो गई, उसका काम करीब-करीब पूरा हो गया, अप्रैल और मई के बीच के अंदर निश्चित रूप से होगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह कर रहा था कि इन सब कामों के साथ आप कहेंगे कि मैंने...

श्री मुरारीलाल मीणा: पैराटीचर्स का।

श्री जीतमल खांट: राजीव गांधी पाठशालाओं में जो पढ़ा रहे हैं उनका...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हां, वह मुख्य मंत्रीजी करेंगी। वह मुख्य मंत्रीजी बात कर रही हैं, मेरे मुंह से होगा तो कोई छोटी-मोटी बात निकलेगी।

श्री शांतिलाल चपलोत: कुछ शिक्षाकर्मी बाकी रह गये हैं उस पर आप विचार करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: शिक्षाकर्मियों के बारे में इस सरकार ने... (व्यवधान) बेनीवाल साहब, बोल रहा हूं। शिक्षाकर्मियों के बारे में इस सरकार ने जितना काम किया है, आप सब लोगों को परिचित है, जोगेश्वरजी गर्ग ने सारी बातें बताई हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनकी समस्या का भी समाधान करेंगे, एक-दो कानूनी पहलू हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं। शिक्षाकर्मियों का भी करेंगे, पैराटीचर्स के बारे में मुख्य मंत्रीजी स्वयं देख रही हैं, मैं कहना चाहूंगा, मेरे मुंह से छोटी बात निकलेगी, मुख्य मंत्रीजी करेंगी तो बड़ी बात हो जायेगी। इसलिए आप उन पर छोड़ दीजिये उसको, वह काम करेंगे। मैं अंत में, अध्यक्ष महोदय...

श्री जुबेर खान: मंत्रीजी, पंजाबी और उर्दू के बारे में भी कहिये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पंजाबी और उर्दू और सिंधी, तीनों भाषाओं की भी वेकेंसी निकाल रहे हैं, तय कर दिया है, स्वीकृति मिल गई है हमको।

श्री नन्दलाल पूनिया: 98 वाला क्या हुआ, सर, उन अध्यापकों का।

श्री अध्यक्ष: 98 के चयनित के बारे में भी करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: 98 वालों को दस वर्ष हो गये। दस वर्ष हो गये। 98 वालों को और पैराटीचर्स को, सब को हमने एज में छूट देकर उसमें बैठाने की व्यवस्था की थी, उसमें बैठ गये और पैराटीचर्स पहले पिछली बार तेरह हजार आ गये थे, इस बार भी आ गये हैं, 98 वाले भी बहुत आ जायेंगे, और फिर भी रह जायेंगे तो अगली साल, पहले साल भर्ती हुई, दूसरे साल भर्ती और तीसरे साल भी भर्ती होगी और उनको फिर आप लोग कहेंगे तो परीक्षा में बैठने की छूट दे देंगे और फिर भी नहीं कर पायेंगे तो दो या तीन बस, फिर मेरा वश नहीं रहेगा, वह रह जायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब माननीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने प्रस्ताव दिये हैं, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, जिन्होंने इसमें विचार रखे हैं, जिन्होंने आलोचना की है, जिन्होंने बड़ाई की है, जिन्होंने समालोचना की है, उन सब को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह डिमांड बहुत बड़ी है...

श्री संयम लोढ़ा: तिवाड़ीजी, इस अकादमी पुरस्कार का तो कह दो वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हां, वह डेढ़ सौ, अध्यक्ष महोदय, यह मुझे भी बात जची नहीं कि यह जो अकादमी का पुरस्कार है उसमें यह प्रतिबंध लगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया है कि डेढ़ सौ, दो सौ पेज होने चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि वह दो सौ पेज है, वह नहीं हों। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: मंत्री महोदय, सर्वशिक्षा प्रोजेक्ट में जो हैं उनको भी परमानेंट कर दीजिये जब सभी कुछ कर रहे हैं तो। उनकी लाइफ पूरी निकल गई है प्रोजेक्ट के अंदर ही, पहले लोक जुम्बिश में थे, फिर सर्वशिक्षा में आ गये हैं, उनको भी कन्फर्म करने पर कुछ विचार कर लें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: मंत्रीजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन को खाली दो बातों पर आश्वस्त कर दें, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके बहुत विद्वतापूर्ण भाषण, आपके एचीवमैंट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नम्बर एक, राजस्थान सरकार नॉन प्लान की कितनी पोस्ट पर भर्ती करेगी, नम्बर एक। नम्बर दो, आपने सदन को हर बार आश्वस्त किया, फिर आश्वस्त करने की स्थिति में हैं क्या कि यह जुलाई महीने में नाइंटी फोर थाउजेंड टीचर लग जायेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी प्रश्न उठाया था माननीय सदस्य ने और मैंने उसमें कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ बातें स्टेट के इंटरेस्ट की है, वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता चाहूं, तो राज को राज रहने दीजिये। वैसे हमने 1905 सेकण्ड ग्रेड के, आठ सौ अध्यापक वह और बाकी जो अभी यह सारे जो एक हजार व्याख्याता जिनमें 990 लग गये हैं, बाकी हिन्दी के ऊपर स्टे है, 'सर्व शिक्षा अभियान' में नहीं हैं, राज्य के पूर्णतया बजट पर हैं और यह बाकी भी राज्य के बजट पर हैं, और वैसे भी राज्य के बजट पर नहीं है तो भारत सरकार का और हमारा बजट कोई अलग-अलग थोड़े ही है। हम तो भेदभाव करते नहीं हैं, वह भी हमारा और यह भी हमारा। तो हम सारे काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कोई सवाल नहीं किसी का। कृपया कन्क्लूड करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: चलो छोड़ो। हां, अध्यक्ष महोदय, पचास अरब रुपये की डिमांड है, पास करा दीजिये, लोगों को भोजन करने जाना है। पचास अरब की।

श्री राजेन्द्र राठौड़: कला और संस्कृति पर भी मंत्रीजी बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, डिमांड पास करवाइये। (व्यवधान) समय पर आवे तो आधा घंटा पहले खत्म हो जावे यह ध्यान रखें हम लोग। हर मंत्री दोबारा रिपीट करता है हर उस बात को। आप पास करवायें अब। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पास करवायें अब।

श्री गजेन्द्रसिंह खींवसर: मैं दस मिनट से ग्यारह मिनट नहीं लूंगा।

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति पर आज किसी ने कुछ नहीं बोला है। कला और संस्कृति पर किसी ने कुछ बोला ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: हमारी घोषणाएं सुन लें। नहीं, घोषणाएं करेंगे, सिर्फ घोषणाएं सुन लें अध्यक्ष महोदय। इसमें भी शानदार कीर्तिमान स्थापित किये हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सरकार ने...

डा. सी. पी. जोशी: पास करा दो, अब क्या है, वैसे ही पास कराओ। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: माननीय अध्यक्षजी, मैं माफी चाहता हूं सदन से लेकिन दो ऐसी मांग है जो मेरे ख्याल में पूरा सदन भी चाहेगा, मेरी मांग थी, कटौती प्रस्ताव भी दिया हुआ था मेरा, कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी केशवानंदजी के नाम से रखा जाय और बीकानेर यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा गंगासिंहजी के नाम से रखा जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं...

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हो मिस्टर प्रताप सिंहजी, what are you doing?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति): यदि हम भारत के अन्य प्रदेशों से कंपेयर करें तो कई तरह से बहुत हार्डशिप्स है और कई तरह से बहुत हैडिंकेप है, न तो हमारे हिमालय जैसा पर्वत है, न बर्फ है, न गंगा जैसी पेरेन्निअल नदियां हैं, पानी बहुत गहरा है और गर्मी, आंधी है और यह हमारी जो परिस्थितियां हैं काफी दूसरे प्रदेशों से जब कंपेयर करते हैं तो काफी खराब है लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज राजस्थान के अंदर मैक्सिमम ट्यूरिस्ट आते हैं और इसका जो कारण है, एक कहा जाता है कि एशिया का जो कला और संस्कृति का जो एपिकसेंटर इण्डिया माना जाता है और इण्डिया का ऐपीकसेंटर राजस्थान माना जाता है तो ये सब समस्याओं के बावजूद जो राजस्थान में इतने ज्यादा ट्यूरिस्ट आ रहा है इसका करण है

हमारा इतिहास, हमारे कलर्स, चाहे वह चुन्दरी हो, चाहे वह पचरंगा हो, चाहे वह लहरिया हो, हमारे गीत, हमारे नृत्य जैसे कालबेलिया हो, चाहे घूमर हो और हमारी जो भाषा, हमारी जो सिम्प्लीसिटी जो है इसकी वजह से यहाँ पर रिकार्ड ट्यूरिस्ट आता है और मैं आपका यह कहना चाहूंगा कि एक हमारे बढ़ेरों की मारवाड़ में कहावत है कि सदियां चली जाती हैं, जनरेशन चली जाती है पर जो चीज इतिहास का जो प्रमाण है वह है गीतड़ा और भीतड़ा तो राजस्थान के अंदर हमारी जो कला व संस्कृति है वह बहुत रिच है...

श्री अध्यक्ष: प्रतापसिंहजी क्या किया जाए आपका?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यहां तो अध्यक्ष महोदय की मान लिया करो, मुख्य मंत्रीजी की तो सब जगह मानते ही हैं आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और पर्यटन जो है वह हमारी सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है और पर्यटन की जो इफेक्ट्स है जो इकॉनोमिक इफेक्ट्स है, मल्टी-प्लायबल इफेक्ट है, जो इम्प्लोयमैंट देती है वह बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल में कोई इण्डस्ट्री ऐसी नहीं है। हमें पूरे विश्व से कंपीट करना है और इस कॉम्पीटिशन के लिए हमें हमारी जो इमारतें हैं, हमारी जो आर्ट और कल्चर है उसको हमें वर्ल्ड स्टेण्डर्ड तक लाने की जरूरत है। जयपुर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं लेकिन सबको 'रामेश्वरम्' जाना है, उठ-उठ के जाने लग गये, इसको शॉर्टआउट कराओ आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): (व्यवधान) कंट्रोल किया जाये, अब घड़ी के हिसाब से तो कंट्रोल कराओ (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया आप बिराजो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया है (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको जयपुर के बारे में क्या कार्य हो रहा है, देखिए हवामहल में क्या हो रहा है, आमेर में क्या हो रहा है, शायद आप भी ट्यूरिस्ट बनकर के जाओगे वहां पर। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): शेखावाटी से ज्ञान शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष: आप अच्छा बोल रहे हो इसका मतलब आप बार-बार खड़े होंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): तो जयपुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपने गोल्डन ट्राइन्गल में जैसे यहां राजस्थान में एंट्री होती है जयपुर के जरिए होती है और राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतने युद्ध स्तर पर और इतने विशाल तरीके से कार्य हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्री खुद इसमें विशेष रुचि ले रही हैं, खुद पधारती हैं, खुद कार्य देखती हैं, आमेर महल के अंदर एक 'आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण' की स्थापना हुई। एक युनेनिमस और ओटोनेमस और रजिस्टर्ड सोसायटी बनी अप्रैल, 2006 में इसका कार्य शुरू हुआ है और ये कार्य अब मार्च, 2009 में कंपलीट हो जाएगा और इसकी लागत होगी 395 लाख, इसके अंदर जितनी भी ओवरहैड वायरिंग हैं, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है एक तो बहुत वर्ल्ड क्लास लाइट एंड साउंड सिस्टम और ऑडियो गाइड जब आप आमेर महल में जाएंगे तो आप हैड-फोंस लगाकर के हर कमरे में जाएंगे तो आपको उसके बारे में बताएगा, आपको गाइड की जरूरत नहीं होगी, यह जो लेटेस्ट ऑडियो-सिस्टम है और एक साउंड लाइट एंड इफेक्ट जो है जैसे रेड फोर्ट में है, वह भी आपके 2008 के अंदर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट कार्डस है जिनका इण्ट्रोडेक्शन हो रहा है जैसे आप मेट्रो में जाते हैं कि वो जब आप मशीन में लगाते हैं तो गेट खुलता है एक जने के लिए, अभी जो आमेर के थ्रू जो रेवेन्यू हो रही है वह साल 365 लाख हो रही है और स्मार्ट कार्ड और ये जो अपग्रेडेशन होगा इससे अनुमान हम लगाते हैं एक वर्ष के अंदर यही जो इन्कम है 365 लाख से यह 1200 लाख एक साल के अंदर बढ़ेगी। हम वैल्यू एडीशन कर रहे हैं, इस इमारत के अंदर और यह कभी भी राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है, शीश महल की ऐसी जर्जर हालात हो गई थी उसको भी बहुत तरीके से उसका रिपयेर हो रहा है। 130 पुराने जो नक्शे हैं, उनको बनाकर के एक ऑरिजनल तरीके से महलों का काम हो रहे हैं, जो पुराने जो पत्थर मिलते थे, जिन खानों से पत्थर मिलते थे, वो खानें बंद हो गई हैं, एक हरा रंग का पत्थर मिलता था जिससे कार्य हुआ था तो उसके पास वाली खानों से वैसा ही पत्थर बिलकुल मैचिंग उसका ऑरिजनल रेस्टोरेशन के लिए उसको लाया जा रहा है, यह एक बहुत कठिन कार्य है। एक आपके सुर्खी भट्ठा भी स्थापित किया गया है और आपके जो पहले जो पेंट होता था वह

एक फूल होता था टेसू फूल, उसको लेकर के उसके साथ वो गुड भी मिलाते थे और चूना भी मिलाते थे, गुगल भी मिलाते थे और उसे पेंटिंग हुई जाती थी तो एक्चुअली ऑरिजनली ये उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं लगाये जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो रेस्टोरेशन है वह बिलकुल वर्ल्ड क्लास का है और ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को इंस्पेक्ट किया है यूनेस्को ने, वर्ल्ड मॉन्युमैंट फंड ने, प्रिंस चार्ल्स ने और इंटेक ने और यूनेस्को ने अपनी जो विज्डन बुक में लिखा है:-

"Fabulous site, and a challenging project of conservation being taken with exemplary care. UNESCO will be supporting your efforts in every possible way."

अर्थात बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत मुश्किल का कार्य है और कार्य नीयत प्रोजेक्शन से किया जा रहा है और यूनेस्को इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट देगी। यह जो कार्य मैंने आपको बताया है यह आपके 2008 के अंदर कंपलीट हो जाएगा। इसके अलावा जो ऐतिहासिक जलेब चौक है वहां पर भी मीना बाजार स्थापित किया जाएगा, वहां पर स्टॉल स्थापित किया जाएगा और वहां पर हैण्डीक्राफ्टस और आर्टिजंस को भी लाया जाएगा..

श्री अमराराम (धोद): आपने हमको तो बोलने नहीं दिया, हम आभारी हैं आपने व्यवस्था दी लेकिन अब तो हमारा पीछा छुडवाओ अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति): वहां पर ग्लोबल आर्टस बनाया जा रहा है...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): बोलने दीजिए आप इनको, अच्छी बात कह रहे हैं सदन को ज्ञान करा रहे हैं आप करो भाषण पूरा अपना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कन्क्लूड करिए आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति): हवा महल के अंदर 660 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है मार्च, 2008 में यह कार्य भी पूरा हो जाएगा, वहां पर नीचे दो इमारतें थीं देवस्थान की और आयुर्वेद डिपार्टमैंट की, उनको भी मर्ज कर दिया गया है। वहां पर लाईब्रेरी बनेगी, टॉयलेट्स बनेंगे, स्टडी होगी और एक जो पुराने जो सिक्के हैं, उसका

(श्री गजेन्द्र सिंह)

म्यूजियम भी बनाया जाएगा और वहां पर एक जो मूर्ति की चोरी हुई थी, घीया ने जो चोरी की थी, वह मूर्ति भी वहां पर स्थापित की जाएगी ट्यूरिस्ट के लिए। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है इसके अंदर 550 लाख रुपए खर्च होंगे और 31 मार्च, 2008 तक यह कार्य भी पूरा हो जाएगा। लाईटिंग सिस्टम, लाईब्रेरी सिक्योरिटी सिस्टम और जो भी वहां पर रिपयर्स है, रिफ्रेशमेंट्स, टिकट बूथ और सिक्योरिटी, फर्निशिंग का कार्य हो रहा है, एक मॉडल म्यूजियम बनेगा। यह राजस्थान का और राजस्थान के विभिन्न विभागों की जो भी कला की चीज है चाहे ड्रेस हो, चाहे हैण्डीक्राफ्टस हो, चाहे आरमरी हो, ये जो संग्रहालय है इसको बिलकुल टॉप क्लास एक मॉडल संग्रहालय जो राजस्थान के सब विभागों का करेक्टर रिफ्लेक्ट करे, यह कार्य भी जो है 31 मार्च, 2008 तक कंपलीट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर 200 ऐतिहासिक दरवाजे हैं और जर्जर हालत में हैं और इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 31 मार्च, 2008 तक चार करोड़ रुपए खर्च करके साठ दरवाजे तैयार हो जाएंगे और शेष दरवाजे 2009 में होंगे। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा जैसे भरतपुर है भरतपुर में 9 गेट, धौलपुर के अंदर 6 दरवाजे, अलवर के अंदर 13, जोधपुर के अंदर 7, जालौर के अंदर 7 जैसलमेर में 8, सोजत में 5, अजमेर में 11, सीकर में 6, बीकानेर में 11, रतनगढ़ में 9, उदयपुर में 10, डूंगरपुर में 7, झालावाड़ में 3, झालरापाटन में 3, बूंदी में 8, बारां में 4, जयपुर में 3 इसके अलावा पोकरण, ब्यावर, नागौर, मेड़ता और कोटा के भी अन्य दरवाजों की मरम्मत होगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैं एक आपसे जानना चाहता हूं कि कुम्भलगढ़ फोर्ट और बाली में एक जो किला है उसमें जेल लगा रखी है, मैं चाहूंगा कि वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह मेरा एक सुझाव है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): ...(व्यवधान) इसकी तो पूरी जानकारी लेकर उसके अनुसार करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नैनवां में पाँच हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान में टूरिस्टों का जो आकर्षण झुंझुनूं जिले में है वो किसी भी जिले से कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वहां की हवेलियां स्थापत्य कला का नमूना है। राजस्थानी स्थापत्य कला का नमूना है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ... अभी जो घोषणा हुई उसमें उसका कहीं नाम ही नहीं है। कला संस्कृति में टूरिज्म ही तो आता है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): अध्यक्ष महोदय, जवाहर कला केन्द्र के अन्दर ..

श्री अध्यक्ष: आपने प्रतिपक्ष के नेता की बात नहीं सुनी?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): नहीं सुनी।

श्री अध्यक्ष: सुनिये आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): फरमायें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): कला और संस्कृति में झुंझुनूं जिला बहुत रिच है । वहां ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आर्ट गैलेरी है साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वहां आर्ट गैलेरी नहीं है सोने की दुकानें हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, वहां की हवेलियों की स्थापत्य कला ...।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): महणसर के अन्दर सोने की दुकान मशहूर है जहां टूरिस्ट आते हैं फ्रांस और यूरोप से।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल सब जगह से दुनिया के तमाम कोनों से।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हां, सब जगह से आते हैं और महणसर के अन्दर एक कमरा है जिसकी आर्क इतनी बड़ी है कि वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उतना उसके अन्दर मेसनरी वर्क है वो इतना सुन्दर है कि उसको देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट के अन्दर मंडावा, नवलगढ़, महणसर, मुकुंदगढ़ ...

श्री अध्यक्ष: मांग पास नहीं होगी जब तक नाम आएगा। मांग पास करानी है तो दो नाम।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ... अलसीसर, मलसीसर जितने भी जागीरदार थे जिनके किले थे उन सब में टूरिज्म का काम हो रहा है। मुकुन्दगढ़, नवलगढ़ उसका आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): राजसमंद में भी 'रूठी रानी का महल' है साहब ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपने कर दिया न । आपने कर दिया वो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): अपने हवेलियां हैं । हवेलियां हैं जैसलमेर की हवेली देखने जाते हैं लोग वैसे मंडावा में, बिसाऊ में और रामगढ़ में...

श्री अध्यक्षः नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में और झुंझुनूं में है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पुराने जमाने की जो हवेलियां हैं उन पर जो दस्तकारी है कारीगरी है आपको वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो प्रस्ताव दिया और जो भी आपने सजेशन दिया उसकी मैं पूरी जानकारी लूंगा।

श्री अध्यक्षः और उनको भी इंक्लूड करूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): आपके शेखावाटी क्षेत्र में सर्वे ऑलरेडी चल रहा है । अभी सर्वे चल रहा है और शेखावाटी तो आपके टूरिज्म में बहुत एडवांस्ड है ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आपने यह मीटिंग अटेंड नहीं की।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): शेखावाटी में झुंझुनू ही तो है। सीकर और झुंझुनूं दो ही है जिसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्षः झुंझुनूं, सीकर, चूरू तीनों हैं शेखावाटी में।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आज हमें तकलीफ है कि आप इतने जागरूक अध्यक्ष हैं कि अपने झुंझुनूं की हर चीज ध्यान रखते हैं और इस सरकार को बताया ही नहीं आपने। मतलब इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत झुंझुनूं में है और सरकार को पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः वो इंगित कर दिया न प्रतिपक्ष के नेता ने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं ऐसा नहीं है नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अध्यक्षजी ने पर्यटन मंत्री ऊषा पूनियाजी को बताया था गजेन्द्रसिंहजी के पास वो कागज नहीं आया।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): ...(व्यवधान) मेरे को पूरी जानकारी है ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) ऐतिहासिक झील और 'रूठी रानी के महल' बहुत ऐतिहासिक हैं कृपया वहां पर्यटन कार्यालय नहीं है जिला मुख्यालय पर पर्यटन कार्यालय खोला जाए, ताकि संरक्षण हो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): अध्यक्ष महोदय, अंत में आखिरी चीज यह कहना चाहूंगा कि एक जो नयी योजना बनायी गयी थी जिसके अन्दर 7700 इमारतें आईडेंटीफाई की गई थीं थ्रू पटवारीज और थ्रू कलक्टर्स उनके ऊपर भी 35 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और पुरानी जो बावड़ी हैं, कुएं हैं, ब्रिटिश शासन के पुराने रेल्वे स्टेशन हैं और युद्ध स्थल हैं, पुराने डाक बंगले हैं उनका भी अभी सर्वे हो चुका है उनका भी कार्य होगा। आखिरी में मैं यहीं कहना चाहता हूं कि जब अपन कला एवं संस्कृति को इतना बूस्ट दे रहे हैं तो यह हर वर्ष अपने जो राजस्थान डे सेलीब्रेशंस हो रहे हैं अब आ रहा है उसमें हम तो जाते ही हैं पर हम देखते हैं प्रतिपक्ष के कोई भी नेता लोग पधारते नहीं हैं इतनी अच्छा कार्यक्रम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है इसके अन्दर आप जरूर पधारें।

श्री अध्यक्ष : इनको कला, संस्कृति का ज्ञान नहीं है तो।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जाते हैं तो रामनिवास बाग़ में डंडे चलते हैं क्या करें वहां जाकर?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): मैं आपको ले चलूंगा मेरे साथ में।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि उदयपुर में एक सज्जनगढ़ करके स्थान है उसके बारे में भी ....

श्री युनुस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान दिवस की माननीय मंत्री महोदय ने चर्चा की अब की बार एस.एम.एस. स्टेडियम में 24 तारीख को राजस्थान के सभी पारंपरिक खेलों की और ग्रामीण खेलों की शुरूआत और राजस्थान दिवस की शुरूआत एस.एम.एस. स्टेडियम से होगी। सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं और सब के लिए पूरे राजस्थान की जनता के लिए खुला आमंत्रण है और 24 तारीख को सायंकाल इसकी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उदघाटन करके शुरूआत होगी जिसमें पहली बार राजस्थान के परम्परागत ग्रामीण खेलों को शामिल किया गया है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... 26, 27 का भी बता दो प्रोग्राम आगे का भी। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कला व संस्कृति): सदन के सभी माननीय सदस्यों को इन्वीटेशंस भेजे गये हैं और हमारे राजस्थान की जो रिच कला व संस्कृति है उसका डिसप्ले देखने के लिए अवश्य पधारें। धन्यवाद।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मांग का प्रस्ताव तो रखा ही नहीं कि पास की जाए।

श्री अध्यक्ष: रख दिया था। पहले कह दिया था मंत्रीजी ने।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,26,39,15,000/- (पचास अरब छब्बीस करोड़ उन्तालीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.37 बजे, शुक्रवार; दिनांक 23 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्व ग्राम योग्य मजरे एवं ढाणियां

214. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में 250 या उससे अधिक आबादी के कितने मजरे व ढाणियां हैं जिन्हें आज तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मजरों व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार उक्त मजरों/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में 250 या उससे अधिक आबादी के 43 मजरे/ढाणियां हैं जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं, किया गया है। इनका ब्यौरा संलग्न सूची परिशिष्ट ''क'' में अंकित है।

(2) किसी मजरे/ढाणी को राजस्व ग्राम बनाने हेतु सामान्य क्षेत्र में उसकी आबादी 250 तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 होना आवश्यक है, राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद मूल राजस्व ग्राम की आबादी भी उक्त क्षेत्रों में क्रमश: 250 एवं 200 से कम नहीं रहे। प्रस्तावित राजस्व ग्राम की दूरी मूल ग्राम की आबादी से कम से कम एक कि.मी. होनी चाहिये। इस जनसंख्या का आधार वर्ष 2001 की जनगणना है।

निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले मजरे/ढाणियों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट ''क''

जिला चित्तौड़गढ़ के 250 या उससे अधिक आबादी वाले मजरे/ढाणी की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	जनंसख्या 2001 के अनुसार	प्रस्तावित मजरे/ढाणी का नाम	जनसंख्या 2001 के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	छोटी सादड़ी	जलोदिया	2094	शिवपुरा	320
2.	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	16602	धावड़ा	262
3.	छोटी सादड़ी	भेरवी	1172	सोमपुर कमोलिया	515

1	2	3	4	5	6
4.	छोटी सादड़ी	भेरवी	1172	रामाखेड़ा	313
5.	छोटी सादड़ी	बिलिया	654	झालाकाखेड़ा	265
6.	छोटी सादड़ी	सेमरथली	1940	जीवनपुरा	261
7.	चित्तौड़गढ़	नगरी	2989	सांवरिया नगर (गुजरखेड़ा)	575
8.	चित्तौड़गढ़	नगरी	2989	श्रीरामनगर (धोरड़िया)	614
9.	भदेसर	हटटीपुरा	814	धामनीखेड़ा	250
10.	राशमी	गुरजनिया	1589	मात्रीकुण्डिया	300
11.	राशमी	देवीपुरा	671	देवीपुरा बी	400
12.	राशमी	बस्सी	557	भेरूखेड़ा	260
13.	राशमी	लसाड़िया कला	1707	शंभुपुरा	600
14.	राशमी	पहुना	5229	नन्दपुरा	300
15.	राशमी	पहुना	5229	गणेशपुरा	350
16.	अरनोद	साखथलीखुर्द	1976	डोर	380
17.	अरनोद	जीरावता	1335	लालाखेड़ी	335
18.	अरनोद	लुहारखाली	1609	पांतरिया	355
19.	अरनोद	अम्बीरामा	1940	अधारियाबडला	260
20.	अरनोद	अम्बीरामा	1940	ठीकरिया	340
21.	अरनोद	मोठीया	1341	छायणी	368
22.	अरनोद	मानपुराकलां	859	परनाला	305
23.	अरनोद	कोटडी	2965	भेरूखाखरा	268
24.	अरनोद	सेवना	3768	दूधियातालाब	475
25.	अरनोद	बडवास कलां	2062	खजूरीखेडा	335
26.	अरनोद	मोवाई	1794	मोयाखेडा	265
27.	अरनोद	निनोर	2314	धडमंगरा	270
28.	अरनोद	निनोर	2314	अम्बेडी	335
29.	निम्बाहेड़ा	अजोता	704	हीराजी का खेड़ा	302

1	2	3	4	5	6
30.	निम्बाहेड़ा	कनेरा	5787	पटीयार	250
31.	निम्बाहेड़ा	टाटरमाला	1106	ईन्द्रा नगर	350
32.	डूंगला	तलावदा	1160	महुड़ीखेड़ा	255
33.	बडीसादड़ी	खरदेवला	1931	कापडियो का खेड़ा	313
34.	बडीसादड़ी	खरदेवला	1931	गोपालजी का खेड़ा	297
35.	बड़ीसादड़ी	खरदेवला	1931	सोनगरों का खेड़ा	300
36.	रावतभाटा	भेसरोडगढ़	5075	गोपालपुरा	275
37.	रावतभाटा	भेसरोडगढ़	5075	मन्दारचोक	350
38.	बेगूं	राजगढ़	1908	राजपुरा	252
39.	बेगूं	रावड़दा	1633	गोपालपुरा	265
40.	बेगूं	धारला	969	उमर	295
41.	गंगरार	जवासिया	1944	माताजी का खेड़ा	369
42.	गंगरार	धोली	738	रूपाखेड़ा	265
43.	गंगरार	सालरिया	1048	रड़ा की बालद	260

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा मुद्रण कार्य में निजी मुद्रणालयों को प्राथमिकता

216. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी संस्थाओं का सभी तरह छपाई का कार्य सहकारी प्रेस में ही कराना आवश्यक है? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक सहकारी संस्थाएं उक्त आदेश को न मानकर निजी प्रेस से छपाई का कार्य करा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) वर्ष 2005 व 2006 में जयपुर स्थित शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का छपाई का कार्य कराया गया इसमें से किनती राशि का कार्य सहकारी प्रेस से और कितनी राशि का निजी प्रेस से करवाया गया? पृथक—पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सहकारी प्रेस के स्थान पर निजी प्रेस से छपाई कार्य कराने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि सहकारी संस्थाओं का सभी प्रकार का कार्य सहकारी प्रेस से ही कराने बाबत् परिपत्र समय-समय पर रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा जारी किये गये, जिसकी प्रतियां परिशिष्ट ए से डी पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि अनेक सहकारी संस्थाएं निजी प्रेस से छपाई का कार्य करवा रही हैं, क्योंकि सहकारी मुद्रणालय की नियमित मुद्रण क्षमता लगभग 4.00 करोड़ रुपये वार्षिक है। राजकीय विभागों के भी अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य आदेश प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सम्पादित किया जाना होता है। उक्त स्थिति में सहकारी संस्थाओं का कार्य मुद्रणालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पूर्ण नहीं कर पाने पर सहकारी संस्थाओं के समक्ष अन्य मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य करवाने का विकल्प ही शेष रहता है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) वर्ष 2005-06 में 10 शीर्ष संस्थाओं ने 16,74,719.00 रूपये राशि का छपाई कार्य करवाया, जिसमें से 13,72,876.00 रुपये राशि का छपाई कार्य सहकारी प्रेस से करवाया है तथा 3,01,843.00 रुपये राशि का कार्य निजी प्रेस से करवाया है।

(4) बिन्दु संख्या 2 में वर्णित औचित्यपूर्ण कारणों से निजी प्रेस से छपाई कार्य कराने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं माने जाने से उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

महिलाबाग चिकित्सालय, जोधपुर शहर में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

217. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर शहर के महिलाबाग चिकित्सालय को रेफरल चिकित्सालय बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) रेफरल चिकित्सालय में कम से कम कितने चिकित्सक व नर्सिंगकर्मी होने चाहिये?

(3) रेफरल चिकित्सालय बनाने में पूर्व महिलाबाग चिकित्सालय में कितने चिकित्सक व नर्सिंगकर्मी थे और आज कितने चिकित्सक व नर्सिंगकर्मी हैं?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी महिलाबाग जोधपुर को 50 शैय्याओंयुक्त चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई हैं।

(2) स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय में 11 चिकित्सकों के एवं 16 नर्सिंग कर्मियों के पद होने चाहिये।

(3) राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी महिलाबाग जोधपुर को 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने से पूर्व 9 चिकित्सकों के एवं 6 नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत थे। वर्तमान में 13 चिकित्सकों के एवं 16 नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत हैं।

(4) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ का एक रिक्त पद है जिसे विभागीय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदोन्नती समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी का भी एक रिक्त पद है जिसे शीघ्र भरने का प्रयास किया जावेगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय का पद सीधी भर्ती का है जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सीकर में विश्वविद्यालय की स्थापना

218. श्री अमराराम (धोद) (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सीकर में लम्बी अवधि से की जा रही मांग के मद्देनजर विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

जालौर जिले में एनीकट, बांध एवं तालाबों के निर्माण में अनियमितताएं

219. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में विगत 03 वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के एनीकटों, तालाबों व बांधों का निर्माण करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन एनीकटों, तालाबों व बांधों का निर्माण करवाया गया है उनमें आज भी पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिन एनीकटों, तालाबों व बांधों का निर्माण करवाया गया वे पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर में नये एनीकट, तालाब व बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा पिछले 3 वर्षों में 11 बांध, तालाब एवं 30 एनीकटों के निर्माण कार्य करवाये गये जिनकी लागत

(सिंचाई मंत्री)

क्रमशः 460.01 लाख रु. एवं 101.86 लाख रु. है। विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पानी उपयोग में ले लिया गया है।

(3) विगत तीन वर्षों में निर्माण करवाये गये बांध/तालाबों में से वर्ष 2006 की वर्षा ऋतु में 3 बांध क्रमशः राजीकावास बांध, वोमल क्रास बांध व झाव क्रास बांध अत्यधिक वर्षा एवं बांधों की भराव क्षमता से अधिक पानी की आवक के कारण टूट गये हैं।

(4) जी हां। उपयुक्त स्थान, जहां पानी रोका जा सकता है।

प्रपत्र "अ"

विगत तीन वर्षों में निर्माण किये गये कार्यों की सूची

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (स्वीकृत राशि)	तहसील	पंचायत समिति	ग्राम	व्यय की गई राशि (लाखों में)	पानी की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	लघु सिंचाई परियोजना							
1	कानीवाडा बांध	101.82	जालोर	जालोर	कानीवाडा	81.94	शून्य	पेटा काश्त होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं है।
2	वणधर बांध	162.80	जालोर	रानीवाडा	वणधर	94.14	शून्य	504 हैक्टर में सिंचाई पूर्ण होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं है।
3	धुमडामाता बांध	39.25	जालोर	आहोर	धुमडामाता	42.49	शून्य	पेटा काश्त होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं है।
4	भेटाला बांध	34.28	जालोर	जालोर	भेटाला	31.58	शून्य	
5	कोलर बांध	43.36	जालोर	सायला	कोलर	39.26	शून्य	
6	मेडा उपरला बांध	39.87	जालोर	जालोर	मेडा उपरला बांध	29.46	शून्य	
7	उच्चमत बांध	19.85	जालोर	जसवन्तपुरा	उच्चमत	19.42	शून्य	
8	कवराडा बांध	26.67	जालोर	रानीवाडा	कवराडा	22.16	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	सान्तरू बांध	20.32	जालोर	रानीवाडा	सान्तरू	19.78	शून्य	पेटा काश्त होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं है।
10	राजपुरा I बांध	32.55	जालोर	जसवन्तपुरा	राजपुरा	24.03	शून्य	
11	राजीकावास बांध	63.60	जालोर	जसवन्तपुरा	राजीकावास	55.75	शून्य	पेटा काश्ता के कारण पानी उपलब्ध नहीं है। ओवरफ्लो क्षतिग्रस्त
	योग:'	**584.37**				**460.01**	शून्य	
	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कार्य योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य						शून्य	
3	नासरा एनीकट	8.00	आहोर	आहोर	नासरा	5.66	शून्य	,,
4	नोरवा एनीकट	6.60	आहोर	आहोर	मालगए	4.55	शून्य	,,
5	साकरणा बेसफ्लो	7.01	आहोर	जालोर	साकरणा	3.79	शून्य	,,
6	सवणा बेसफ्लो	3.87	जालोर	जालोर	सवणा	2.52	शून्य	,,
7	चांदणा बेसफ्लो	8.42	जालोर	जालोर	चांदणा	4.94	शून्य	,,
8	सरदारगढ बेसफ्लो	9.35	जालोर	जालोर	सरदारगढ	5.28	शून्य	,,
9	महेशपुरा बेसफ्लो	9.93	जालोर	जालोर	महेशपुरा	6.29	शून्य	,,
10	जालोर बी बेसफ्लो	7.62	जालोर	जालोर	जालोर बी	4.23	शून्य	,,
11	देलदरी बेसफ्लो	5.03	जालोर	जालोर	देलदरी	3.41	शून्य	,,
12	उच्चमत एनीकट (पालकियों का झरणा)	6.60	रानीवाडा	तसवन्तपुरा	उच्चमत	2.16	शून्य	,,
13	उच्चमत एनीकट (खोवा झरणा)	5.00	रानीवाडा	तसवन्तपुरा	उच्चमत	1.79	शून्य	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	जाविया एनीकट (खाकरवाला डेला)	7.93	रानीवाडा	तसवन्तपुरा	जाविया (खाकरवाला डेला)	1.43	शून्य	,,
15	जाविया (खोल का नाका)	7.93	रानीवाडा	तसवन्तपुरा	जाविया	3.33	शून्य	,,
16	पोसालिया एनीकट	7.09	भीनमाल	भीनमाल	नवापुरा	4.70	शून्य	,,
17	नयावाडा एनीकट	8.42	भीनमाल	भीनमाल	नयावाडा	4.92	शून्य	,,
18	सीमयावाला एनीकट	7.56	भीनमाल	भीनमाल	कोटकाश्ता	4.18	शून्य	,,
19	पुरोहितो की ढाणी एनीकट	7.38	भीनमाल	भीनमाल	मेडा ब्राह्मणान	4.75	शून्य	,,
20	सुरावा बेसफ्लो	8.00	साचोर	साचोर	सुरावा	2.68	शून्य	,,
21	अरणाय बेसफ्लो	6.00	सांचोर	सांचोर	अरणाय	1.12	शून्य	,,
22	लखनाडी बेसफ्लो	6.00	साचोर	सांचोर	गुन्दड	1.01	शून्य	,,
23	पांचला बेसफ्लो	5.00	साचोर	साचोर	पांचला	1.77	शून्य	,,
24	रूपा की ढाणी लूनीयासर	6.00	साचोर	सांचोर		0.82	शून्य	,,
25	मेवानाल एनीकट	2.50	आहोर	आहोर	भाद्राजून	1.50	शून्य	,,
26	कटकेश्वर एनीकट	3.85	जालोर	जालोर	बारलावास	2.17	शून्य	,,
27	मयलावास एनीकट	7.40	जालोर	जालोर	मयलावास	4.39	शून्य	,,
28	धारा एनीकट	11.46	रानीवाडा	जसवन्तपुरा	पूणे	7.05	शून्य	,,
29	पाड का नाला एनीकट	3.91	भीनमाल	भीनमाल	कोटकाश्ता	1.22	शून्य	,,
30	गुडानाल के पास मेडा एनीकट	4.90	भीनमाल	भीनमाल	मेडा ब्राह्मणान	1.21	शून्य	,,
					योग:-	**101.86**	शून्य	

नदबई (भरतपुर) हेतु बाइपास निर्माण

220. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कस्बा नदबई (भरतपुर) के मुख्य बाजार में स्थित रेलवे फाटक के बन्द रहने के कारण विगत काफी समय से क्षेत्र की जनता को आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बाईपास निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। उक्त स्थान पर बाईपास का निर्माण राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्माण करता है।

आमेर के लम्बित खातेदारी प्रकरण

221. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गैर खातेदारों को खातेदारी प्रदान करने के कितने आवेदन पत्र गत तीन वर्षों में प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने प्रकरणों में गैर खातेदारों को खातेदारी प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गैर खातेदारों को खातेदारी प्रदान करने के कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गत तीन वर्षों में गैर खातेदारों को खातेदारी प्रदान करने के कुल 237 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 184 प्रकरणों में गैर खातेदारों को खातेदारी प्रदान की गई, 52 प्रकरण निरस्त किये गये एवं एक प्रकरण शेष है। सूची परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गैर खातेदार श्री मोहन लाल जाट को ग्राम बसेडी में खातेदारी प्रदान करने का एक प्रकरण वर्ष 2006 से लम्बित है।

(3) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 में खातेदारी प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन

222. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)- क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं और ये कब गठित किए गए?

(2) क्या सरकार प्रत्येक जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन का विचार रखती है?

(3) सिरोही जिले में कुल कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं इनमें से कितनी कार्यशील हैं एवं कितनी निष्क्रिय? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन के सम्बन्ध में सरकार को कब-कब आवेदन प्राप्त हुए एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) सिरोही जिले से कितना दूध अन्य जिलों अथवा राज्यों में जा रहा है? इस बाबत वर्ष 2006 में आन्दोलन कब-कब हुए व क्यों? वर्ष 2006 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 17 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं, जिनकी गठन संबंधी सूचना परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) सिरोही जिले में कुल 46 पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिसमें से 27 कार्यशील, 7 निष्क्रिय एवं 12 अवसायनाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-'ख' पर उपलब्ध है।

(4) सिरोही जिला दुग्ध संघ के गठन के संबंध में अक्टूबर, 2006 व जनवरी, 2007 में दो आवेदन प्राप्त हुए, आवेदकों की स्पष्ट पहचान व पूर्ण विवरण के अभाव में इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(5) सिरोही जिले से लगभग 81,717 लीटर दूध प्रतिदिन जिले से बाहर जाता है। वर्ष 2006 में 31.01.06 से 09.2.06 तक रेवदर क्षेत्र के कतिपय दुग्ध उत्पादकों ने आन्दोलन किया, जो बनासकांठा जिला दुग्ध सहकारी उत्पादक संघ, पालनपुर (गुजरात) द्वारा दुग्ध संकलन बन्द करने से आन्दोलित थे।

परिशिष्ट ''क''

जिला दुग्ध संघों की मय पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक गठन संबंधी सूचना

क्रम संख्या	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	पंजीकरण दिनांक	संघ का नाम
1.	579/एफ	29.08.1972	उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बीकानेर
2.	1875/आर	27.05.1972	कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. कोटा
3.	1650/ए	02.09.1972	अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अलवर
4.	1203/क्यू	12.7.1972	पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर
5.	2902/के	22.03.1975	जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर
6.	2404/बी	14.02.1972	अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर
7.	843/ई	18.08.1972	भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा
8.	2107/डी	09.2.1972	भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भरतपुर
9.	1560/वाई	26.08.1972	उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर
10.	1252/यू	30.06.1978	सवाई माधोपुर एवं टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सवाई माधोपुर
11.	813/आई	17.11.1980	चुरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सरदारशहर
12.	1180/टी	02.02.1980	पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पाली

क्रम संख्या	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	पंजीकरण दिनांक	संघ का नाम
13.	35/केएच	30.01.1984	श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़
14.	398/वी	14.09.1983	सीकर-झून्झूनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सीकर
15.	597/ डब्ल्यू	27.03.1986	जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रानीवाड़ा
16.	647/बी	17.03.1986	बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बांसवाड़ा
17.	5-के-ओ	25.01.2007	झालावाड़-बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. झालावाड़

परिशिष्ट "ख"

सिरोही जिले में कार्यशील/निष्क्रिय/अवसायनाधीन दुग्ध समितियों का विवरण।

क्रम संख्या	दुग्ध समिति का नाम	कार्यशील/निष्क्रिय/अवसायनाधीन
1.	आवाड़ा	निष्क्रिय
2.	कोटड़ा	निष्क्रिय
3.	बांट	कार्यशील
4.	जैतावाड़ा	कार्यशील
5.	सारड़ा	कार्यशील
6.	मोरवाड़ा	कार्यशील
7.	पीथापुरा (मण्डार)	कार्यशील
8.	बासाड़ा	कार्यशील
9.	मगरीवाड़ा	निष्क्रिय
10.	खाण	निष्क्रिय
11.	जीरावल	कार्यशील
12.	दातराई	कार्यशील

क्रम संख्या	दुग्ध समिति का नाम	कार्यशील/निष्क्रिय/अवसायनाधीन
13.	अमरापुरा (हरनी)	कार्यशील
14.	अनापुर	निष्क्रिय
15.	केसुआ	कार्यशील
16.	बडबज	कार्यशील
17.	निम्बतलाई	निष्क्रिय
18.	अनावरा	अवसायनाधीन
19.	करोड़ी	अवसायनाधीन
20.	धवली	अवसायनाधीन
21.	जावल	अवसायनाधीन
22.	बड़ेची	अवसायनाधीन
23.	जोलपुर	निष्क्रिय
24.	भटाना	अवसायनाधीन
25.	बुटेड़ी	अवसायनाधीन
26.	मीठन	अवसायनाधीन
27.	जागठा	अवसायनाधीन
28.	रूखाड़ा	कार्यशील
29.	सुथारों का गुड़ा	कार्यशील
30.	चुली	कार्यशील
31.	राड़बर	कार्यशील
32.	छिवावांव	कार्यशील
33.	उथगण	कार्यशील
34.	जोयला	कार्यशील
35.	नया जोगापुरा	कार्यशील
36.	गंजपुरा	कार्यशील
37.	अरठवाड़ा	कार्यशील
38.	झाडोलीवीर	कार्यशील
39.	तलेटा	कार्यशील
40.	बड़ा लखमावा	कार्यशील
41.	छोटा लखमावा	कार्यशील
42.	मनादर (महिला)	कार्यशील
43.	केराल	कार्यशील
44.	ईसरा	अवसायनाधीन
45.	बालवा	अवसायनाधीन
46.	कृष्णगंज	अवसायनाधीन

मेड़ता के चिकित्सालयों में रिक्त पद

223. श्री रामचन्द्र जारोडा (मेड़ता, नागौर) **:** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सामुदायिक चिकित्सालय मेडता को 100 बैड का स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थान में चिकित्सकों के 7 पद रिक्त हैं।

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर, हड्डी रोग एवं निश्चेतन) के रिक्त पदों को चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर, हड्डी रोग एवं निश्चेनत) उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेडता में वर्तमान में 50 शैय्यायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2006 में मात्र 42.10 प्रतिशत उपयोग रहा है इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़तासिटी को 50 से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सिकराय के विद्यालयों में रिक्त पद

224. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शिक्षक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) कितने विद्यालयों में भवनों की चारदीवारी है? क्या सरकार चार दीवारी रहित विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र सिकराय में 218 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 113 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जा सकेगा।

(3) 74 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, 81 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 11 माध्यमिक विद्यालयों, एवं 6 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी है।

जी हां। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनान्तर्गत विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण करवाये जाते हैं।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के एनीकटों/तालाबों की मरम्मत

225. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने तालाब व एनीकट कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तालाबों व एनीकटों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से नये तालाब व एनीकट बनाये गये व किन-किन तालाबों, एनीकटों की मरम्मत करवाई गई? व्यय की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कहां-कहां नये तालाब व एनीकट बनाये जाने प्रस्तावित हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में केवल 8 एनीकट स्थित हैं। एनीकटों का स्थान संलग्न प्रपत्र-'अ' में वर्णित है। उक्त क्षेत्र में जल संसाधन विभाग का कोई तालाब (सिंचाई बांध) नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त एनीकटों की मरम्मत की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) 1 जनवरी, 2004 से अब तक इस क्षेत्र में 8 एनीकटों का निर्माण कराया गया जिस पर 86.98 लाख रुपये का व्यय किया गया। कोई नये तालाब/बांध का निर्माण नहीं कराया गया है। इस दौरान किसी भी तालाब/एनीकट की मरम्मत का कोई कार्य नहीं कराया गया है। विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में 8 एनीकटों के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। तालाब का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विवरण प्रपत्र-'ब' पर संलग्न है।

प्रपत्र 'अ'

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 जनवरी, 2004 से अब तक निर्माण कराये गये एनीकटों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	तहसील	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	31.01.07 तक व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खण्डल	खण्डल	साभर	फुलेरा	खण्डेल नाले पर श्मशान के पास एनीकट का निर्माण कार्य	12.97	पूर्ण	11.04
2.	कीरो की ढ़ाणी	कालख	साभर	फुलेरा	कीरो की ढ़ाणी के पास एनीकट का निर्माण कार्य	6.97	पूर्ण	5.50
3.	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा नागरा	साभर	फुलेरा	मेडा नदी पर एनीकट का निर्माण कार्य	11.20	पूर्ण	10.13
4.	जैतपुरा	जयसिंहपुरा	साभर	फुलेरा	जैतपुरा खरड मे एनीकट का निर्माण कार्य	8.99	पूर्ण	7.71
5.	खटावड़ी कलां	खटावड़ी कलां सिनोदिया	साभर	फुलेरा	चौसाला वले पर अपूर्ण एनीकट को पूर्ण करने का कार्य	17.76	अपूर्ण	3.63
6.	मुण्डोली	मुण्डोली	साभर	फुलेरा	जयपुर नावा रोड के उत्तर की ओर एनीकट निर्माण कार्य	19.10	पूर्ण	13.76
7.	लालपुरा	लालपुरा श्यामा की ढाणी	साभर	फुलेरा	मेडासर नदी पर एनीकट निर्माण कार्य (लालासर)	20.94	पूर्ण	19.45
8.	ढाणी बोराज	ढाणी बोराज	साभर	फुलेरा	ढ़ाणी बोराज की एनीकट का निर्माण कार्य	16.80	पूर्ण	15.74
					कुल योग :-	**114.60**		**86.98**

प्रपत्र 'ब '

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में प्रस्तावित एनिकटों का विवरण

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5	6	7
1	जयपुर	फुलेरा	सांभर	मठ (डूंगरी कलां) की तरफ पहाड़ी की पूर्व दिशा में एनीकट निर्माण	मठ (डूंगरी कलां)	जोरपुरा सनोदिया
2	जयपुर	फुलेरा	सांभर	पहाड़ी के उत्तर दिशा में क्रेशर मशीन बडी के पेडों के पास एनीकट निर्माण	डूंगर	डूंगरी
3	जयपुर	फुलेरा	सांभर	खारडा विन्जारिया व घडली ढाणी के बीच एनीकट	डूंगर	डूंगर
4	जयपुर	फुलेरा	सांभर	चालला नाले पर अपूर्ण एनीकट पूर्ण करना	खतावडी कलां	खतावड़ी कलां/ सनोदिया
5	जयपुर	फुलेरा	सांभर	फुलेरा से आने वाले नाले पर भरपुरा से शीशन वाली कुई व नरेल रोड तक एनीकट निर्माण	भदरापुरा	ठेठियावास
6	जयपुर	फुलेरा	सांभर	एनीकट निर्माण जयपुर नावां रोड से उत्तर की ओर	मुण्डोती	मुण्डोती
7	जयपुर	फुलेरा	सांभर	नदी पर एनीकट निर्माण	अगरपुरा	अगरपुरा-ढेहरा
8	जयपुर	फुलेरा	सांभर	नदी पर एनीकट निर्माण	लालपुरा	लालपुरा-श्यामा की ढ़ाणी

गंगरार की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

226. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार की बड़ी सड़कों यथा कारोई से कपासन, गंगापुर से चित्तौड़गढ़, राशमी से चन्देरिया, रूद से गंगरार, साडास से गंगरार, बस्सी से भीलवाड़ा तक का पुन: निर्माण कराने व चौड़ाई 5 मीटर तक बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार कारोई से कपासन तक की एम.डी.आर. सड़क को स्टेट हाइवे सड़क का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सड़कों का पुनर्निर्माण (नवीनीकरण) सड़कों का वर्गीकरण एवं नवीनीकरण साइकिल नीति के अनुसार निर्धारित अवधि में राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इन सड़कों का 5 मीटर में चौड़ाईकरण मापदण्डानुसार आवश्यक नहीं है। 5 मीटर चौड़ाईकरण करने हेतु यातायात गणना घटक कम से कम 5000 पी.सी.यू. होना चाहिए जबकि इन सभी सड़कों का यातायात गणना घटक 5000 पी.सी.यू. से काफी कम है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क उदयपुर-कपासन-चित्तौड़गढ़ सड़क के किमी 87 से बाइफरकेट होकर डिण्डोली-राशमी होकर भीलवाड़ा जिले में कारोई कस्बे को जोड़ती है। भीलवाड़ा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है। अतः वर्तमान में कारोई (जिला भीलवाड़ा) से कपासन (जिला चित्तौड़गढ़) को एम.डी.आर. से स्टेट हाईवे बनाने का औचित्य नहीं है।

खातेदार द्वारा पंजीकृत भूमि पर आवासीय कॉलोनी हेतु नियम

227. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोई व्यक्ति अपनी खातेदारी की जमीन भूखण्डों के रूप में कॉलोनी काट कर भूमि रूपान्तरण करवाये बिना अन्य को हस्तान्तरित कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों में? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंजीयन के पश्चात् पंजीयन शुदा भूमि को रूपान्तरित किया जा सकेगा? यदि नहीं, तो इसकी अन्य क्या शर्तें होंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौमूं की निर्माणाधीन सड़कें

228. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनवरी, 2003 के बाद कौन-कौनसी सड़कें बनाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम सुल्तानपुरा, शिम्भुपुरा व दम्माकाबास गांवों को मिसिंग लिंक सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या तिगरिया से जगतपुरा, नांगलबरडा से रींगस तथा डेहरा से मानपुरा माचेडी गांवों को जो कि दो तहसीलों को जोड़ने का काम करती है, को बनाने के प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड ने तैयार किये हैं? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनवरी 03 से अब तक 7 सड़कें 21.90 किमी. लम्बाई में 231.61 लाख रुपये व्यय कर निर्माण करवाई गई हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रश्नांकित निर्माण कार्यों की दिनांक 21.02.07 को स्वीकृति जारी की गई है। निविदा प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2008 तक निर्माण कार्य पूर्ण होना सम्भावित है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट- ''अ''

जनवरी 2003 से अब तक बनाई गई सड़कों की सूची

जिले का नाम	कृ.उ.म. स.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	वास्तविक लम्बई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	निर्मित वर्ष	विशेष विवरण
जयपुर	चौमूं	चौमूं	1. मिसिंग लिंक सीतारामपुरा रोड से मलीकपुर	22.98	3.00	3.00	22.90	2004.05	कार्य पूर्ण है।
			2. मिसिंग लिंक नांगल भरडा से अमरपुरा	44.94	4.60	4.60	44.78	2005.06	कार्य पूर्ण है
			3. मिसिंग लिंक नांगल भरडा से बरवाड़ा वाया वीर हनुमान का मन्दिर	75.56	4.00	4.00	72.27	2005.06	कार्य पूर्ण है।
			4. मिसिंग लिंक बिशनपुरा से चारणवास	5.80	1.00	1.00	5.06	2004-05	कार्य पूर्ण है।
			5. डोडसर से सिंगोद खुर्द	37.97	4.80	4.80	38.03	2005-06	कार्य पूर्ण है।
			6. मिसिंग लिंक मण्डाभिण्डा से हस्तेडा	26.75	2.00	2.00	23.40	2006	कार्य पूर्ण है।
			7. मिसिंग लिंक आस्ती मोड से बधाल	26.75	2.50	2.50	24.62	2006	कार्य पूर्ण है।
			योग	**240.75**	**21.90**	**21.90**	**231.06**		

परिशिष्ट- ''ब''

वर्ष 2006-07 में स्वीकृत सड़कों की सूची

जिले का नाम	कृ.उ.म.स.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति एवं दिनांक (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	विशेश विवरण
जयपुर	चौमूं	चौमूं	1. सम्पर्क सड़क सामोद बाग से सुल्तानपुरा (राजीव गांधी पाठशाला तक)	34.05/21.02.07	1.90	निविदा 17.3.07 को प्राप्त की जानी है
			2. सम्पर्क सड़क कानपुरा से शिम्भुपुरा	56.10/21.02.07	3.50	निविदा 17.3.07 को प्राप्त की जानी है
			3. सम्पर्क सड़क विमलपुरा से दम्बा का बास	28.50/21.2.07	2.25	निविदा 17.3.07 को प्राप्त की जानी है
			योग	**118.65**	**7.65**	

भारतीय चिकित्सा परिषद दल द्वारा बीकानेर के चिकित्सालयों का निरीक्षण

229. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मेडीकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा अस्पतालों के निरीक्षण हेतु समय-समय पर दौरा किया जाता है यदि हां तो क्या दौरे की राज्य सरकार को पूर्व सूचना होती है तथा क्या सरकार के प्रतिनिधि भी दौरे के दौरान साथ रहते है ।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर 2006 के मध्य मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की टीम द्वारा बीकानेर के अस्पतालों का दौरा किया गया? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन अस्पतालों का ?

(3) क्या यह सही है कि दौरे के दौरान उक्त दल द्वारा पी.बी.एम. अस्पताल की विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जाहिर किया गया ? यदि हां, तो दौरे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि उक्त दौरे के बाद पी.बी.एम. अस्पताल में क्या-क्या सुधार किए गए ?

उत्तर

(1) जी हां । बहुधा दौरे की पूर्व सूचना संबंधित मेडीकल कालेजों के प्रधानाचार्यों को मेडीकल काउिन्सल इण्डिया द्वारा दी जाती है । दौरे के समय सरकार के प्रतिनिधि के रुप में संबंधित मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों के प्रशासन से संबंधित अधिकारी भी साथ रहते है ।

(2) जी हां । मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की टीम द्वारा दिनांक 13/14-10-2006 को मेडीकल कालेजों बीकानेर एवं संबंद्ध अस्पतालों यथा पी.बी.एम. अस्पताल, जनाना अस्पताल, टीबी अस्पताल नेत्र अस्पताल, तथा शिशु अस्पताल का दौरा किया गया ।

(3) मेडीकल काउन्सिल आफ इण्डिया के निरीक्षण दल की रिपोर्ट परिशिष्ट अ के रुप में सदन के पटल पर रख दी गयी है । इस रिपोर्ट में कुछ कमियां दर्शाई गयी हैं। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रधानाचार्य मेडिकल कालेजों बीकानेर ने रिपोर्ट में इंगित कमियों के बारे में किये गये सुधारों का विवरण मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया को दिनांक 20.2.2007 को प्रेषित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कर दिया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट- ब के रुप में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

लोक जुम्बिश परियोजनान्तर्गत नियुक्त मुक्तकों का शिक्षाकर्मी विद्यालयों में समायोजन

230. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 मार्च, 1998 को कार्यालय समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना कोटा द्वारा अध्यापन कार्य हेतु कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो जारी विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञप्ति में मुक्तकों को कार्मिक माना है ? यदि हां, तो फिर इनको हटाते समय सैनिक वेलफेयर सोसायटी एवं नवाचार क्यों बताया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को निदेशक लोक जुम्बिश परिषद द्वारा पत्र क्रमांक लो.जु.प/जय/2002/42064 दिनांक 30 अप्रैल, 2003 में मुक्तकों को शिक्षाकर्मी के समान माना गया है ? यदि हां तो इन मुक्तकों को शिक्षाकर्मी विद्यालयों में समायोजित क्यों नही किया गया जबकि लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित किये गये ओपन मिडिल स्कूलों को शिक्षाकर्मी स्कूलों में समायोजित किया गया है ?

(4) क्या सरकार मुक्तकों को शिक्षाकर्मी मानकर शिक्षाकर्मी विद्यालयों में लगाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 20 मार्च 1998 को कार्यालय समन्वयक लोक जुम्बिश परियोजना कोटा द्वारा अध्यापन कार्य हेतु कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी । विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) विज्ञप्ति में मुक्तकों के लिये कार्मिक शब्द का उल्लेख है परन्तु लोक जुम्बिश परिषद (कार्मिक एवं सेवा) रेगुलेशन 1993 में मुक्तक पद का उल्लेख नहीं होने से उन्हें लोक जुम्बिश कार्मिकों की श्रेणी मेंबही माना गया है। लोग जुम्बिश परिषद द्वारा मुक्तांगन योजना नवाचार के रुप में ही शुरु की गई

(शिक्षा मंत्री)

थी तथा शैक्षिक सत्र 1998-99 में मुक्तक लोक जुम्बिश परिषद द्वारा लगाये गये थे। पश्चातवर्ती वर्षों में आवश्यकता अनुरुप मुक्तक सैनिक वैलफेयर सोसायटी के माध्यम से लगाये गये थे। मुक्त को फिक्स मानदेय रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान देय था ।

(3) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) बिन्दु संख्या-3 के अनुसार।

परिशिष्ट ''क''

विज्ञप्ति

लोक जुम्बिश परियोजना, राजस्थान राज्य में लोक सहभागिता के माध्यम से 5-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं के लिये गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के विकास खण्ड किशनगंज में खण्डेला संकुल (25-30 गांवों का समूह क्षेत्र) के 15-17 गांवों में दिन भर के खुले विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है। कार्मिकों का पदस्थापन किसी निश्चित गांव के लिए किया जावेगा।

1. पदों की अनुमानित संख्या-50

2. योग्यताऐं- (क) पुरूष अभ्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण व महिलाओं हेतु 10वीं उत्तीर्ण।

(ख) पुरूषा-शाहबाद/किशनगंज तहसील के मूल निवासी ही पात्र होंगे।

3. वेतन एवं शर्तें (1) अभ्यार्थियों का समेकित वेतन 2000/- फिक्सड प्रतिमाह देय होगा।

(2) सभी चयनित अभ्यार्थियों को उसी गांव में रहकर काम करना होगा।

4. चयन परीक्षा- अभ्यार्थियों की एक लिखित परीक्षा हिन्दी भाषा व गणित में किशनगंज विकास खण्ड कार्यालय पर आयोजित की जावेगी। उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर खण्डेला संकुल मुख्यालय पर साक्षात्कार के बाद प्रारम्भिक चयन किया जावेगा।

नोट:- साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. अन्तिम तिथि- सभी अभ्यार्थी निम्न प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 20/4/1998 तक परियोजना अधिकारी, लोक जुम्बिश परियोजना, किशनगंज (बारां) के नाम से भिजवायें।

1. अभ्यार्थी का नाम, 2. पिता/पति का नाम, 3. जन्म तिथि, 4. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के हों तो उसका उल्लेख करें, 5. शैक्षणिक योग्यताऐं मय विषय, श्रेणी तथा प्रतिशत प्राप्तांक, 6. अनुभव यदि कोई हो, 7. डाक का पूरा पता- हस्ताक्षर आवेदक, दिनांक सहित।

नोटः- निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करनी हैं-

1. जन्म तिथि, 2. शैक्षणिक योग्यताऐं (10वीं तथा 12वीं परीक्षा की अंक तालिका, 3. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो।

(आनन्द कुमार जैन)
क्षेत्रीय समन्वयक
लोक जुम्बिश परियोजना,
कोटा।

बूंदी जिले में सिंचाई शुल्क वसूली हेतु जारी नोटिस

231. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी में सरकार द्वारा सिंचाई पटवारियों के पद कब समाप्त किये गए और पद समाप्ति के पश्चात से लघु मध्यम एवं बडी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई शुल्क वसूलने का दायित्व किन को सौंपा गया है।

(2) पद समाप्ति के पश्चात प्रतिवर्ष कितनी भूमि पर सिंचाई हुईऔर उसको कितना सिंचाई शुल्क बना ? क्या यह भी सही है कि इसकी मांग पत्र दिये जाने का प्रावधान है। यदि हां, तो क्या पद समाप्त होने के पश्चात इस प्रकार के डिमाण्ड नोट किसानों को जारी किये गये ? यदि हां, तो किन को, कब-कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पटवारियों के पद रिक्ति के पश्चात राजस्व पटवारियों द्वारा अब किसानों से मय ब्याज व पैनल्टी के सिंचाई शुल्क वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये हैं यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग में पटवारी के पद राज्य सरकार के आदेश दिनांक

(सिंचाई मंत्री)

26.09.2001 से समाप्त किये गये। इस आदेश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना का शुल्क वसूलने का दायित्व राजस्व विभाग के पटवारियों को सौंपा गया। चम्बल वृहद सिंचाई परियोजना में सिंचाई शुल्क का निर्धारण व वसूली का कार्य उक्त आदेश के पूर्व से ही जल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जा रहा है।

(2) पद समाप्ति के पश्चात प्रतिवर्ष हुई सिंचाई एवं सिंचाई शुल्क का विवरण प्रपत्र- 'अ' संलग्न है।

जी हां । वस्तुस्थिति की जानकारी की जा रही है।

(3) जी हां। राशि बकाया के कारण।

प्रपत्र- ''अ''

पद समाप्ति के पश्चात बूंदी जिले में प्रतिवर्ष हुई सिंचाई एवं सिंचाई शुल्क का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	सिंचित क्षेत्र है. में	शुल्क राशि रुपये में
1.	2002-03	3069.74	1780592
2.	2003-04	101041.00	369059
3.	2004-05	148217.45	3095528
4.	2005-06	144205.31	8135426

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शहीद आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरण

390. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1999 के पश्चात् विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक कितने पात्र आश्रितों को नौकरी दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनेक पात्र आश्रितों के आवेदन नौकरी हेतु लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व क्यों? उक्त का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पात्र आश्रितों को आवेदन उपरान्त सरकारी नौकरी प्रदान करने की कोई समयावधि निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004 से अब तक 53 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई हैं सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। 18 प्रकरण नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(3) पात्र आश्रितों को आवेदन उपरांत सरकारी नौकरी प्रदान करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

परिशिष्ट ''क''

वर्ष 2004 से नियुक्ति प्राप्त पात्र आश्रितों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नियुक्ति प्राप्त आश्रितों की संख्या
1.	सीकर	13
2.	अलवर	9
3.	नागौर	3
4.	करौली	1
5.	गंगानगर	1

क्र. सं.	जिले का नाम	नियुक्ति प्राप्त आश्रितों की संख्या
6.	भरतपुर	3
7.	बाड़मेर	1
8.	झुन्झुनूं	7
9.	चिड़ावा	1
10.	पाली	1
11.	जोधपुर	3
12.	टोंक	3
13.	जयपुर	3
14.	चुरू	3
15.	भीलवाड़ा	1
योग		**53**

परिशिष्ट "ख"

राज्य सरकार के पास नियुक्ति हेतु विचाराधीन प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	शहीद आश्रित का नाम	जिला	विभाग जहां प्रकरण लम्बित हैं।
1.	श्रीमती भंवरी देवी पत्नि शहीद जयपाल सिंह	सीकर	जिला कलक्टर, सीकर
2.	श्रीमती नीता जैम्स पत्नि शहीद मेजर जेम्स थॉमस	बीकानेर	आयुक्त, मा. शिक्षा, बीकानेर
3.	श्रीमती अल्पना कमलेश पत्नि शहीद मेजर कमलेश प्रसाद	अजमेर	शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज., जयपुर
4.	श्रीमती संतोष देवी पत्नि धर्मवीर	अलवर	कार्मिक विभाग, जयपुर
5.	श्री दुर्गाराम पुत्र शहीद है. का. रूग्गाराम	नागौर	जिला कलक्टर, नागौर
6.	मुनेश कुमार पुत्र शहीद भूर सिंह	सवाई माधोपुर	जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर
7.	श्रीमती सुनीता पत्नि शहीद उम्मेद सिंह	भरतपुर	जिला कलक्टर, भरतपुर
8.	श्रीमती रामा देवी पत्नि शहीद कंवरसिंह	भरतपुर	जिला कलक्टर, भरतपुर

क्र. सं.	शहीद आश्रित का नाम	जिला	विभाग जहां प्रकरण लम्बित हैं।
9.	श्रीमती जगवीरी पत्नि शहीद लाखन सिंह	भरतपुर	जिला कलक्टर, भरतपुर
10.	श्रीमती श्यामवती पत्नि शहीद अनुपकुमार	भरतपुर	जिला कलक्टर, भरतपुर
11.	श्रीमती सुमन देवी पत्नि शहीद सत्यवीर सिंह	भरतपुर	सहायक निदेशक, प्रा. शि. बीकानेर
12.	श्रीमती रतन कौर पत्नि शहीद नैनसुख	चिड़ावा	रा. लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा बैटल कैजुअल्टी की श्रेणी में नहीं मानने के कारण प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन
13.	श्रीमती सुमन देवी पत्नी राजू सिंह	चिड़ावा	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं
14.	श्रीमती सरिता पत्नी शहीद मेजर हर्ष	चिड़ावा	जिल कलक्टर, झुन्झुनूं
15.	श्रीमती संगीता देवी पत्नी दामोदर प्रशाद शर्मा	चुरू	संभागीय आयुक्त, बीकानेर
16.	श्रीमती सीता देवी पत्नी शहीद सुभाष चंद	चुरू	जिला कलक्टर, चुरू
17.	कु. कविता पुत्र शहीद हव. महेन्द्र सिंह	चुरू	जिला कलक्टर, चुरू
18.	श्री सुनील कुमपा पुत्र शहीद शिशुपाल	झुन्झुनूं	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं

निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग,

राज. जयपुर

विशेष आर्थिक जोन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति

391. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में स्पेशल इकॉनोमिक जोन बनाकर मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के साथ शेयर हॉल्डिंग एग्रीमेंट किया

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गया था? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत अब तक कितनी जमीन सरकारी एवं भू-अवाप्त करके दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्पेशल इकॉनोमिक जोन के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इकॉनोमिक जोन के अन्तर्गत उद्योग विभाग ने महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा एवं अन्य उद्योगों के लिए भी भूमि आबंटित की है? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी और किस दर पर? उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि आबंटन करना अभी शेष है?

(4) उक्त इकॉनोमिक जोन में जिन-जिन कम्पनियों अथवा संस्था अथवा व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराई गई, वह किन-किन उद्देश्यों के लिए थी और उनके द्वारा उस पर अब तक कितनी राशि का विनियोजन किया जा चुका है और कितनी का करना शेष है?

उत्तर

(1) जी हां। शेयर होल्डिंग एग्रीमेन्ट मैसर्स महेन्द्रा जैस्को डवलपर्स लि. महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लि. एवं रीको के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड भूमि रीको को आबंटित की गयी थी जिसे रीको द्वारा महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. को हस्तान्तरित की गयी है। शेष 2000 एकड़ भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगरीय विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में 49 हैक्टेयर भूमि पर सूचना प्रोधौगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु दिनांक 7.4.2006 को औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है। बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु दिनांक 7.4.2006 को सैद्धान्तिक स्वीकृति भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है।

(3) इस स्पेशल इकोनोमिक जोन से अभी तक किसी को भी भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(4) अभी तक किसी भी कम्पनी अथवा संस्था को भूमि आबंटित नहीं की गई है।

शिक्षित बेरोजगारों के लम्बित ऋण प्रकरण

392. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध करने हेतु कौन-कौनसी योजनाएं चला रखी हैं एवं उनके मानदण्ड क्या हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन योजनाओं में अभ्यर्थी को आवेदन करने से ऋण प्राप्त करने तक की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं में कितनी समय सीमा?

(3) ऋण स्वीकृति के पश्चात् अभ्यर्थियों को बैंक में भुगतान किन-किन कारणों से प्राप्त नहीं होता है? विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में गत तीन वर्षों में इस प्रकार के कितने प्रकरण स्वीकृत हुए एवं कितनों को भुगतान मिल गया और कितनों को ऋण स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान किन कारणों से नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वर्ष 1993 से भारत सरकार द्वारा संचालित 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' का क्रियान्वयन उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

1. आयु	सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिये सामान्य रूप से 18 से 35 वर्ष जिसमें अनु. जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिये 10 वर्ष की छूट है।
2. शैक्षणिक योग्यता	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। उन व्यक्तियों को वरियता दी जायेगी, जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता/अनुमोदित किसी ट्रेड में कम से कम 6 महीने की अवधि के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
3. पारिवारिक आय	लाभ प्राप्तकर्ता की आय पति/पत्नी सहित तथा लाभ प्राप्तकर्ता के माता-पिता की आय अलग से 40,000/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. निवासी	आवेदक रोजगार स्थापित करने के क्षेत्र का कम से कम 3

(उद्योग मंत्री)

वर्ष से स्थायी निवासी होना चाहिये। विवाहित महिला के मामले में महिला के सास-श्वसुर की निवास अवधि स्थायी निवासी होने का आधार माना जाता है।

5. चूककर्ता — आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का बाकीदार नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अन्य सरकारी योजना में पहले से राज सहायता प्रदान नहीं होनी चाहिये।

योजना के प्रारम्भिक आदेश दिनांक 24-9-1993 की प्रति परिशिष्ट 'क' तथा योजनान्तर्गत मापदण्ड संबंधी संशोधन की प्रति परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से अर्जित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तिय वर्ष टाइम मैट्रिक्स निर्धारित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:-

तिमाही	**जिला उद्योग केन्दों द्वारा बैंकों को प्रायोजित आवेदन पत्र**	**बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत**	**बैंकों द्वारा ऋण वितरण**
प्रथम	50%	25%	10%
द्वितीय	100%	50%	25%
तृतीय	125%	90%	75%
चतुर्थ	-	100	100

(3) प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत के पश्चात् भी अभ्यार्थियों को बैंक द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके मुख्यतया निम्न कारण होते हैं:-

1. बैंक की औपचारिकताएं पूर्ण करने में असमर्थ।
2. बैंक की प्राथमिक जांच के दौरान किसी अन्य बैंक/वितीय संस्था का डिफाल्टर होना।
3. चयनित व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करना।

(उद्योग मंत्री)

4. राजकीय या प्राइवेट क्षेत्र में नियमित रोजगार मिल जाना।

5. बैंक के अनुसार व्यवसाय का आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होना।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में बैंकों द्वारा गत 3 वर्षों में निम्नानुसार ऋण स्वीकृत कर ऋण भुगतान किया गया:-

वर्ष	ऋण स्वीकृत की संख्या	ऋण वितरण की संख्या	ऋणा वितरण नहीं हुआ की संख्या
2003-04	102	89	13
2004-05	92	83	09
2005-06	94	86	08
2006-07 (दि. 8-3-2007 तक)	108	68	वित्तीय वर्ष 2006-07 में अभी बैंकों से ऋण स्वीकृतियां प्राप्त होना शेष हैं। स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षण उपरान्त ऋण वितरण होना सम्भव हो सकेगा।

ऋण स्वीकृति के पश्चात् अभ्यार्थियों को ऋण का भुगतान प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण हैं बैंक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करना, नौकरी लग जाना अथवा बाहर चले जाना तथा अभ्याथी द्वारा ऋण लेने से मना कर देना आदि हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू जिले में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता

393. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में भूमिगत जल प्रबंधन संस्थान द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया गया है? तहसीलवा र विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में भूमिगत जल परीक्षण उपरान्त कितने क्षेत्र का जल पीने योग्य पाया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) जिला चूरू में पेयजल किन स्रोतों से कहां-कहां उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डार्क जोन में आने वाले क्षेत्रों में सतही पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूमिगत जल प्रबन्धन संस्थान नामक कोई संस्थान राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत नहीं है। भारत सरकार की भू-जल मूल्यांकन समिति के निर्देशानुसार भू-जल विभाग द्वारा जिला चूरू में उपलब्ध भू-जल भण्डारों के मूल्यांकन (31.03.2004) के आधार पर वर्गीकरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**ब्लॉक/पंचायत समिति**	**श्रेणी/स्थिति**
1	रतनगढ़	सुरक्षित
2	चूरू	सुरक्षित
3	सरदारशहर	सुरक्षित
4	सुजानगढ़	विषम (क्रिटीकल)
5	राजगढ़	अतिदोहित (ओवर ड्रॉफ्टेड)
6	तारानगर	भू-जल खारा होने के कारण वर्गीकृत नहीं किया गया।

(2) राजस्थान प्रान्त के अधिकतर क्षेत्रों में सीमित मात्रा में भू-जल उपलब्ध होने तथा भू-जल मानक गुणवत्ता अनुरूप न होने के कारण विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता मानदण्डों में छूट प्रदान की गई है। तदनुसार चूरू जिले की 6 तहसीलों के 134 गांवों में जल पीने योग्य पाया गया है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**तहसील**	**ग्राम**
1	रतनगढ़	29
2	चूरू	08
3	सरदारशहर	28
4	सुजानगढ़	30
5	राजगढ़	22
6	तारानगर	17
	कुल	**137**

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) इंदिरा गांधी नहर को स्त्रोत लेकर चूरू जिले हेतु वर्तमान में निम्नानुसार पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है-

(अ) राजगढ़ तहसील के आपणी योजना से जुड़ने से शेष बचे एवं आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों (175 गांव) हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जून, 2006 में हो चुकी है। तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इस योजना से राजगढ़ शहर को भी लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(ब) सुजानगढ़ तहसील के 162 गांव, रतनगढ़ तहसील के 94 गांवों को तथा 5 शहर क्रमश: रतनगढ़, राजलदेसर, सुजानगढ़, बीदासर एवं छापर हेतु योजना (रतनगढ़-सुजानगढ़) बनाई गई है जो सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है, ताकि वित्त प्रबन्धन एवं तदनुसार स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जा सके।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण उपखण्ड, सरदारशहर का डीजल घोटाला प्रकरण

394. श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरदारशहर के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रामीण उपखण्ड में 32.87 लाख रुपये का घोटाला हुआ है? यदि हां, तो इसमें कितने अधिकारियों व कर्मचारियां को आरोप पत्र दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस घोटाले पर लम्बे समय तक कार्यवाही न करने का क्या कारण रहा? सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किस प्रकार की जावेगी व उनसे पुनर्भरण किस प्रकार से किया जावेगा?

(3) क्या इस प्रकरण में जनहित याचिका दायर हुई है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई व न्यायालय में चालान पेश हुआ है? यदि हां, तो इसमें कितने अभियुक्तों का चालान पेश किया गया व कितने अभियुक्त पुलिस द्वारा पकड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

(4) इस डीजल घोटाले में परिवहन करने वाली फर्म द्वारा कितने रुपये का सरकार को नुकसान पहुंचाया गया व इस फर्म का पंजीयन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? रकम की वसूली कैसे की जावेगी?

(5) इस घोटाले में कितनी लॉग बुकें जमा हुई तथा कितनी नहीं? सरकार कब तक उक्त लॉग बुकें जमा करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण उपखण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सरदार शहर में डीजल उपभोग बाबत शिकायतों के संदर्भ में वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर 5 अधिशासी अभियन्ता, 7 सहायक अभियन्ता एवं 3 कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध बनाए गए आरोप पत्र स्वीकृति के सन्दर्भ में जांच प्रक्रिया में है।

(2) तथाकथित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में आरोप पत्र बनाना तथा पुलिस थाने में 16.6.2006 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना शामिल है। सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही बाबत नियमों में पर्याप्त प्रावधान है।

(3) जी हां। पुलिस थाना, सरदार शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.6.2006 को दर्ज हुई। पुलिस थाना, सरदारशहर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रकरण में अब तक एक गिरफ्तारी हुई एवं 12.2.2007 को चालान पेश हुआ। प्रकरण वर्तमान में पुलिस विभाग में अनुसंधान में है।

(4) प्रकरण में विशेष जांच दल से जांच करवाकर जांच प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर फिल्ड अधिकारियों से उत्तर ले लिया गया है जो जांच प्रक्रिया में है। जांच प्रक्रिया में तथ्य पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

(5) ढाणी तेतरवाल से सम्बन्धित लाग बुक पुलिस विभाग के पास अनुसंधान में है। शेष लाग बुक प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सुजानगढ़ तहसील में जलदाय योजनाओं के स्वीकृत कार्य

395. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में खण्ड कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार सुजानगढ़ में जल संसाधन का खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सुजानगढ़ तहसील में दिसम्बर, 1998 से नवम्बर, 2003 तक तथा जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2006 तक जलदाय योजना के कितने कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत किस-किस गांव के लिए स्वीकृत किये गये? इन स्वीकृत कार्यो पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान था तथा कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई योजनावार, नामवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन स्वीकृत कार्यो में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने अभी तक अपूर्ण हैं? इनको कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन खण्ड कार्यालय की स्वीकृति मूल कार्यो के लिये 140.00 लाख रुपये एवं रख-रखाव कार्यो के लिये 56.00 लाख रुपये होने पर खण्ड कार्यालय की स्वीकृति जारी की जाने का प्रावधान है। सुजानगढ़ में जल संसाधन विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में उपरोक्त सीमानुसार कार्यभार नहीं है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट–'अ' पर उपलब्ध है।

(3) विवरण निम्नानुसार है:-

कुल स्वीकृत योजनाएं – 243

पूर्ण की गई योजनएं - 175

प्रगतिरत योजनाएं – 68

प्रगतिरत योजनाओं को पूर्ण करने की सम्भावित अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट– 'अ' में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

चयनित वरिष्ठता सूची में डिप्लोमाधारी सहायक अभियन्ता

396. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए उप सचिव-प्रथम के पत्रांक प.16/पी.एच.ई.डी./71 दिनांक 2 अप्रैल, 2000 द्वारा वरीयता सूची जारी की गई है? यदि हां, तो कितने सहायक अभियंता राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से व कितने डी.पी.सी. के माध्यम से लिए गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वरीयता सूची बनाने में अभियांत्रिकी सेवा नियम, 1968 के नियमों का पालन किया गया? यदि हां, तो जारी सूची में डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियंताओं का चयन किस अनुपात में कितनों का किया गया व यदि नियम 1968 का पालन नहीं किया गया तो क्यों? नियमों की प्रति सहित चयनित सहायक अभियंताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए दिनांक 2 अप्रैल, 2000 को कोई वरीयता सूची जारी नहीं की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

फतेहपुर में कार्यरत ट्यूबवैल्स

397. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिन-जिन गांवों में पेयजल हेतु एक ही नलकूप है वहां दूसरा नलकूप चालू करने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जलाशय बनाने के मानदण्ड क्या है? सांसद/विधायक क्षेत्र विकास कोष से किसी गांव में उच्च जलाशय बनाने हेतु क्या मानदण्ड हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के शहर फतेहपुर में कितने ओपन वैल एवं कितने ट्यूबवैल चालू हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिन ओपन वैल की बोरिंग व नाल खराब हो चुकी है उनके स्थान पर नया ट्यूबवैल उसी के पास खोदने का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे कितने ट्यूबवैल विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में खोदे गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध नलकूप से कम पेयजल उत्पादन होने से ग्राम में मांग

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्त्रोत संवर्द्धन का कार्य किया जाता है। पेयजल स्त्रोत की संख्या पेयजल मांग, स्त्रोत की जल आवक क्षमता आदि पर निर्भर करती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जलाशय निर्माण बाबत मानदण्ड निम्नानुसार है:-

(अ) वर्ष 2001 की आबादी 4000 या इससे अधिक होने पर पाइप्ड योजना के तहत,

(ब) ''स्वजलधारा कार्यक्रम'' के तहत समुदाय/प्रयोक्ता की रूचि के आधार पर सामुदायिक भागीदारी के तहत,

(स) सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी गांव में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भी वर्ष 2001 की आबादी 4000 या इससे अधिक होने पर पाइप्ड योजना के तहत तथा

(द) स्थानीय सांसद/विधायक की अभिशंसा पर उनके चाहे अनुसार सार्वजनिक स्थान पर पेयजल से संबंधित ऐसे कार्य जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नोर्म्स में नहीं आते, उन कार्यों का क्रियान्वयन पंचायत राज संस्थान से कराया जा सकेगा जो संस्था जिला कलक्टर की दृष्टि में ऐसे कार्य कराने में सक्षम है। परन्तु ऐसे कार्यों के रख-रखाव संबंधित पंचायत/पंचायत समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो।

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के शहर फतेहपुर में वर्तमान में 17 खुले कुओं एवं 33 नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची संलग्न परिशिष्ट–'क' पर उपलब्ध है।

(4) जिन ओपन वैल की बोरिंग एवं/अथवा नाल (कुएं की स्टेनिंग) खराब हो चुकी है, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि समीप में बोरिंग/नाल की मरम्मत सम्भव नहीं है, ड्रिलिंग हेतु स्थान की उपलब्धि एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर नजदीक में नलकूप बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि विद्युत व्यय व पाइप का खर्च न्यूनतम रहे।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में परित्यक्त खुले कुंओं के स्थान पर स्वीकृत 10 नलकूपों में से 9 नलकूप निर्मित कर चालू कर दिये गये हैं व 1 नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विवरण संलग्न परिशिष्ट–'ख' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-''क''

फतेहपुर के शहर फतेहपुर में चालू ओपन वैल एवं ट्यूबवैल की सूची

क्र. सं.	चालू खुले कुंओं का विवरण	क्र. सं.	चालू नलकूपों का विवरण
1	खाकी कुआ	1	ट्यूब वैल नम्बर-1
2	मोचियों का कुआ	2	ट्यूब वैल नम्बर-2
3	आर ए सी कुआ	3	ट्यूब वैल नम्बर-3
4	चण्डी का कुआ	4	ट्यूब वैल नम्बर-4
5	खटीकों का कुआ	5	ट्यूब वैल नम्बर-5
6	हरनाथ का कुआ	6	ट्यूब वैल नम्बर-6
7	चौधरियों का कुआ	7	ट्यूब वैल नम्ब्र-7
8	कायथों का कुआ	8	ट्यूब वैल नम्बर-8
9	केजडी वाल कुआ	9	ट्यूब वैल नम्बर-9
10	तेलियों का कुआ	10	ट्यूब वैल नम्बर-10
11	चमारों का कुआ	11	ट्यूब वैल नम्बर-11
12	गुरू का कुआ	12	ट्यूब वैल नम्बर-12
13	पीर का रोजा	13	ट्यूब वैल नम्बर-13
14	सासीयों का कुआ	14	ट्यूब वैल नम्बर-14
15	अलडियों का कुआ	15	ट्यूब वैल नम्बर-15
16	मुरीदों का कुआ	16	ट्यूब वैल बाई पास चूरू
17	गोडमल का कुआ	17	ट्यूब वैल छतरियों का
		18	ट्यूब वैल कॉलेज वाला
		19	ट्यूब वैल एफसीआई गोदाम के पास
		20	ट्यूब वैल भरतियों अस्पताल के पास
		21	ट्यूब वैल सतीवाला
		22	ट्यूब वैल शिवालय
		23	ट्यूब वैल तेलियों का
		24	ट्यूब वैल चूंगी वाला

क्र. सं.	चालू खुले कुंओं का विवरण	क्र. सं.	चालू नलकूपों का विवरण
		25	ट्यूब वैल सरदारपुरा
		26	ट्यूब वैल महिचो का नं. 1
		27	ट्यूब वैल महिचों का नं. 2
		28	ट्यूब वैल धोली सती
		29	ट्यूब वैल लक्ष्मीनाथनगर
		30	ट्यूब वैल स्टेशनवाला
		31	ट्यूब वैल बेसवा पुलिया
		32	ट्यूब वैल बेसवा रोड
		33	ट्यूब वैल चूरू बाईपास होटल के सामने

परिशिष्ट ''ख''

फतेहपुर में खराब हो चुके ओपन वैल की बोरिंग व नाल के स्थान पर स्वीकृत नये नलकूप एवं वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्त्रोत का स्थान	विशेष विवरण
1	रामगढ़ शेखावाटी	खटीकों के कुंए के पास सार्वजनिक चौक	
2	कारंगा छोटी	सार्वज्निक चौक	
3	अठवास	हरिजनों के कुंए के पास	
4	भिंचरी	मस्जिद वाला कुंआ	
5	गुदड़वास	सार्वजनिक चौक वाला कुंआ	
6	रोहलसाहबसर	हरीजन कुंआ	
7	नेठवा	हरीजन कुंआ	
8	तिहाय	राजपूतों का कुंआ	कार्य प्रगति पर 1 अप्रैल, 2007 तक चालू करना प्रस्तावित है।
9	उदनसर	सार्वजनिक चौक वाला कुंआ	
10	गारिण्डा	सार्वजनिक चौक वाला कुंआ	

उदयपुर सम्भाग की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

398. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कस्बा सलूम्बर, खैरवाड़ा, ऋषभदेव, धरियावाद, भीण्डर वाया मावली में पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

वर्तमान में खैरवाड़ा कस्बे हेतु संशोधित पुनर्गठित पेजयल योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। योजना के जांच में सही पाये जाने के उपरान्त स्वीकृति बाबत निर्णय सम्भव होगा।

दोषी नायब तहसीलदार को अनियवार्य सेवानिवृति

399. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी सेवा में नियम विरुद्व भ्रष्टाचार, लापरवाही के आरोप में बार-बार कृत्य करने पर आवश्यक सेवानिवृत्ति करने के लिए आदेश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो परिपत्र, आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान तहसीलदार सेवा के नायब तहसीलदार धर्मदास गौरी के विरुद्व सेवाकाल में 16 व 17 सी.सी.ए. की चार्जशीट व प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब? चार्जशीटवार व नोटिसवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्व अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 19-4-2006 की प्रति मय संलग्नकों के संलग्न है।

(2) जी हां। श्री धर्मदास गौरी, नायब तहसीलदार को निम्नांकित दण्डों से दण्डित किया गया है-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	नोटिस नियम/चार्जशीट दिनांक	दण्ड	दण्डादेश दिनांक
1.	सीसीए-17/27-2-1989	दो वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	5-5-1989
2	सीसीए-17/22-5-1989	दो वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	22-5-1990
3	सीसीए-17/26-6-1990	एक वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	12-1-1991
4	सीसीए-16/17-7-1989	दो वा.वे.वृ. संचयी प्रभाव से रोकी	15-2-1995
5	सीसीए-16/6-10-1994	एक वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	22-1-1998
6	सीसीए-17/17-4-1997	एक वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	14-7-1999
7	सीसीए-17/31-5-1999	एक वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	27-4-2000
8	सीसीए-17/18-9-2001	परिनिन्दा	7-1-2002
9	सीसीए-16/18-12-1999	दो वा.वे.वृ. असंचयी प्रभाव से रोकी	17-9-2003
10	सीसीए-16/10-9-2004	जांच अधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित है।	

उक्त अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है।

(3) अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण भाग-2 में उल्लेखित किया गया है। आवश्यक सेवानिवृत्ति हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

उप तहसील मासलपुर (करौली) का क्रमोन्नयन

400. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली के डांग क्षेत्र मासलपुर को उप तहसील से तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

आसींद तहसील मुख्यालय पर उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

401. श्री हंगामी लाल मेवाडा (आसीन्द) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला भीलवाड़ा की तहसील आसींद पर उपखण्ड

(श्री हंगामी लाल मेवाड़ा)

मुख्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल नये उपखण्ड कार्यालय सृजित किये जाने के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है। जब भी विचार किया जावेगा तब इस प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

आई.टी.सी. होटल्स जयपुर का लीज हस्तान्तरण प्रकरण

402. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आई.टी.सी. होटल्स को लीज राइट्स हस्तान्तरण के संबंध में तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त, जयपुर श्री राजेन्द्र भाणावत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त विक्रय के संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर ने अटल परिवार को अनुमति दी है? यदि हां, तो जिला कलक्टर की अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि सम्पदा विभाग की है? यदि हां, तो जयपुर कलक्टर द्वारा किस आधार पर इसे बेचने की अनुमति प्रदान की गई?

उत्तर

(1) आईटीसी होटल्स को लीज राइट्स हस्तान्तरण के संबंध में तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त, जपयुर श्री राजेन्द्र भाणावत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही विचारधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि पर्यवेक्षकों हेतु निर्धारित कार्य

403. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) कृषि पर्यवेक्षकों हेतु क्या जाब निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि पर्यवेक्षक का पद समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि पर्यवेक्षकों हेतु निर्धारित जाब का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

कृषि पर्यवेक्षकों हेतु जाब (कार्य एवं दायित्व)

कृषि विस्तार के कार्य व योजनाऐं कृषि में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि, उद्देश्यों हेतु संचालित की जाती हैं। नवीनतम अनुसंधान को समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कृषकों तक पहुंचाने में कृषि पर्यवेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कृषि पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत संपर्क एवं बैठक पर आधारित कृषि विस्तार पद्धति व सिद्धान्तों को पूरी तरह समझकर तकनीकी ज्ञान कृषकों तक पहुंचाऐं। प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र को 8 किसान मण्डल क्षेत्रों अथवा खण्डों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण कर समय-समय पर प्रशिक्षण में प्राप्त सामयिक उन्नत कृषि विधियों के तकनीकी ज्ञान को प्रत्येक कृषक तक उपलब्ध कराना, इनका आधारभूत दायित्व होगा।

कृषि विस्तार के इस महत्वपूर्ण कार्य को कुशलता से सम्पादित करने के लिए इनके प्रमुख कार्य व दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

1. प्रशिक्षण : जिला/उपजिला स्तर के मासिक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। अपने क्षेत्र की कृषि तकनीकी समस्या से उच्च अधिकारियों/कृषि वैज्ञानिकों को अवगत करायेंगे एवं प्राप्त समाधान कृषकों तक पहुंचाऐंगे।
2. कृषक मण्डल/खण्ड भ्रमण : निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र को 8 मण्डलों/खण्डों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप भ्रमण एवं आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जाकर कृषि तकनीकी का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करायेंगे। कृषि पर्यवेक्षक चयनित किए

गए कृषकों द्वारा बोयी जाने वाली विभिन्न फसलों के आधारभूत आंकड़े व उसके पास उपलब्ध कृषि संसाधनों की सूचना संकलित करेंगे। चयनित कृषकों के यहां प्रत्येक सीजन में दो प्रमुख फसलों (एक अनाज वाली एवं एक दलहनी या तिलहनी) की अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु जो कृषि तकनीकी कृषकों द्वारा नहीं अपनायी जा रही है उन्हें अपनाने के लिए प्रेरणा देकर उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करवायेंगे। फसलवार इन कृषकों की तकनीकी अन्तर चिन्हीकरण रिपोर्ट तैयार (Identification of Technical Gap) की जायेगी।

कृषि पर्यवेक्षक, तकनीकी प्रयोग इकाई के रूप में विकसित किए गए प्रक्षेत्रों पर इच्छुक किसान मण्डल के सदस्यों एवं नजदीक के किसानों का अपने भ्रमण के दिन प्रयोग स्थल पर उपस्थित रहकर कृषि तकनीकी की भी जानकारी देगा। इन प्रक्षेत्रों की प्रगति की चर्चा मण्डल की आयोजित बैठक में भी की जावेगी।

3. किसान सेवा केन्द्र : प्रत्येक गुरूवार को किसान सेवा केन्द्र प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संचालित करेंगे। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसान सेवा केन्द्र का संचालन, कृषि चिकित्सालय की भांति करेंगे। कृषकों से प्राप्त समस्त प्रकार की समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे। वो समस्याऐं, जिनका निराकरण कृषि पर्यवेक्षक स्तर पर सम्भव नहीं हो, उनका निराकरण उच्चाधिकारियों/कृषि वैज्ञानिकों से समाधान प्राप्त कर कृषकों को उपलब्ध करायेंगे।

4. कृषक पाठशाला : मण्डल भ्रमण से पूर्व प्रतिदिन दो घंटे किसान सेवा केन्द्र पर आमंत्रित 30-40 कृषकों को सामयिक व महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण हेतु कृषक पाठशाला संचालित करेंगे।

इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित किसान मण्डल बैठकें, कृषक पाठशाला, भ्रमण तथा किसान सेवा केन्द्रों का संचालन करेंगे एवं शेष दिवसों में कलस्टर बैठक एवं मुख्यालय पर रहकर अन्य राजकीय कार्यों का संचालन करेंगे।

5. कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक, विभिन्न कृषि विस्तार कार्यालय व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे:-

अपने क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम एवं ग्राम पंचायत की कृषि उत्पादन योजना तैयार करेंगे और उसके अनुरूप निर्धारित कृषि आदानों की आपूर्ति

सुनिश्चित कर प्रमुख फसलों के उत्पादन/उत्पादकता के लक्ष्यों को विभिन्न निवेश एवं बिना निवेश के प्रभावी बिन्दुओं का अनुसरण करवाकर लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। रबी/खरीफ फसलों की बुवाई के समय पिछली रबी/खरीफ की उत्पादकता की समीक्षा की जायगी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आगामी बोयी जाने वाली फसलों की बुवाई के विषय में विचार-विमर्श कर रूप-रेखा बनाई जायेगी।

प्रत्येक खरीफ ऋतु में 10 अप्रैल से पहले तथा रबी ऋतु में 10 अगस्त तक बीज, उर्वरक, जिप्सम, पौध संरक्षण रसायनों, कृषि औजारों और पौध संरक्षण उपकरणों की मांग तैयार कर संबंधित सहकारी समिति एवं सहायक कृषि अधिकारों को निर्धारित तिथि तक अवगत करायेंगे। जहां सहकारी समिति कार्यरत नहीं हो वहां एक रिटेल आउटलेट निजी क्षेत्र में खुलवायेंगे ताकि समय पर आदान उपलब्ध हो सकें। सरसों, चने की अग्रिम बुवाई वाले क्षेत्रों में कृषि आदानों की मांग 25 जुलाई तक प्रेषित की जावें।

सिंचाई के समुचित उपयोग के साधन जो क्षेत्र में उपयोगी हो यथा स्प्रिंकलर, पाइप लाइन, ड्रिप, डिग्गी आदि की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे एवं आने वाली कठिनाइयों से उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगे। जल वितरण समिति की बैठकों में भाग लेकर वांछित फसल चक्र अनुसार जल वितरण हेतु तकनीकी सुझाव देंगे। बिजली एवं डीजल की कमी की जानकारी कर समाधान हेतु सहायक कृषि अधिकारी को सूचित करेंगे।

अपने क्षेत्र के किसानों के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था और अल्प एवं मध्यकालीन ऋण हेतु आवेदन पत्र तैयार करने में सहायता करेंगे। जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति काम नहीं कर रही हो वहां किसानों को आदान जुटाने में व्यवहारिक बैंकों से ऋण सुलभ कराने के विशेष प्रयास करेंगे।

मण्डल क्षेत्र में अधिकतम एवं न्यूनतम उपज प्राप्त करने वाले कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाओं पर समीक्षात्मक चर्चा की जाये एवं निर्धारित प्रारूपानुसार, विवरण संधारित किया जावे।

अपने क्षेत्र के आधारभूत आंकड़े संकलित करेंगे जिसें श्रेणीवार कृषकों की संख्या, कृषि से संबंधित क्षेत्र के आधारभूत आंकड़े अंकित करेंगे एवं अपने क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर क्षेत्र की सीमा, सड़कें, कृषि आदान वितरण केन्द्र, बैंक एवं अन्य संस्थाओं के मुख्यालय चिन्हित करेंगे।

किसान मण्डल क्षेत्र के कृषकों की पूर्ण सूची रखेंगे व उनमें आवश्यकतानुसार संशोधित कराने के प्रस्ताव सहायक निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

मिट्टी व पानी के निर्धारित संख्या के नमूने प्रतिवर्ष जांच हेतु एकत्रित कर खरीफ के लिए 15 अप्रैल तथा रबी के लिए 31 अगस्त तक उप जिला कृषि कार्यालय को पठायेंगे एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अनुरूप संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करवाने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करा, उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु तकनीकों का प्रसार व ऊसर भूमियों के सुधार हेतु जिप्सम के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

नियमित रूप से विभाग द्वारा निर्धारित डायरी, पंजिका एवं दस्तावेजों का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, फसल, मौसम, कीट-व्याधि प्रकोप की सूचना, प्रदर्शन पंजिका, कृषि संबंधी समस्याओं, फसल ऋतुवार प्रभावी बिन्दु पंजिका एवं प्रगति पंजिका का संधारण करेंगे।

बीज उपचार तम्बाकू इल्ली, सफेद लट, दीमक, कातरा, सरसों में चेपा, चने में सूण्डी, टिड्डी व अन्य कीट-व्याधि महामारियों के नियन्त्रण के लये अभियान आयोजित करेंगे। क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों में कीट व्याधि प्रकोप की पहचान, विश्लेषण एवं उपयुक्त उपायों की जानकारी तथा मौके पर जाकर स्वयं के समक्ष उपचार करवायेंगे।

अपने क्षेत्र के किसानों के यहां लक्ष्यानुसार विभिन्न प्रकार के कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट आदि तैयार करवायेंगे। पौध भण्डारण की नवीन विधियों को अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित करेंगे। प्रत्येक किसान मण्डल क्षेत्र में निर्धारित संख्या में कृषकों के कृषि प्रक्षेत्रों पर सघन शुष्क खेती की पद्धति का अनुसरण करायेंगे।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करवायेंगे एवं निर्देशानुसार इस योजना में राजस्व तथा विभागीय फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न करवायेंगे।

ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, नवयुवक मण्डल, महिला संगठन, कृषक समूह आदि संस्थाओं की बैठक में भाग लेंगे। ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक में व राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों तथा कृषि समस्याओं का समाधान संकलन कर अग्रेषित करेंगे।

निर्धारित रात्रि गोष्ठियां आयोजित करेंगे तथा रात्रि गोष्ठी के दौरान

दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। प्रसार कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधार हेतु कृषकों एवं स्वयं के सुझाव दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को सहायक निदेशक कृषि के माध्यम से अग्रेषित करेंगे।

अपने क्षेत्र हेतु आबंटित सभी तरह के मिनिकिट व प्रदर्शनों का अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला व सामान्य वर्ग के कृषकों के खेतों पर नियमानुसार आयोजन करेंगे।

खरीफ में 20 सितम्बर व रबी में 15 मार्च तक प्रदर्शन क्षेत्रों पर उन्नत कृषि विधियों के प्रचार प्रसार हेतु क्षेत्र दिवसों के आयोजन की तिथि से सहायक कृषि अधिकारी को अवगत कराते हुए आयोजन करायेंगे।

विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथा मिनिकिट् प्रदर्शन, फसल प्रदर्शन/समन्वित कीट प्रबन्धन संबंधित एफ.एफ.एस., जैव उर्वरक, भूमि सुधार एवं पोषक तत्व आदि आबंटित कार्य पूर्ण करेंगे।

उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये सुझावों व मार्गदर्शी बिन्दुओं की क्रियान्विति का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 404

(स्थगित)

लूणी में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र

405. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप सवास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में आगामी वित्तीय वर्ष में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलबध है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में इस वर्ष 130 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई है।

(3) वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राज्य में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार करते समय विधान सभा क्षेत्र लूणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया।)

खेतड़ी के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

406. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रत्येक राजस्व गांव में सब-सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार टीबा बसई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालय ढाणी-बाढ़ा में भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5000 एवं जनजाति तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है इसलिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति खेतड़ी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाणों की ढाणी का भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

सीकर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

407. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसर देव बाबर)

(1) जिला सीकर में किन-किन राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, एसएमपीडब्लू, वरिष्ठ लिपिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं बीएचएस के पद पदोन्नति के पद हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

अता. प्रश्न संख्या-408

(स्थगित)

स्वास्थ्य जन चेतना यात्रा पर व्यय राशि

409. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में कुछ समय पूर्व ''स्वास्थ्य जन चेतना यात्रा'' कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों व ब्लाकों में आयोजित की गई थी? यदि हां, तो उक्त यात्रा पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रा की व्यवस्था हेतु राज्य की ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों को भी राशि प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त यात्रा कार्यक्रम का आम जनता को क्या लाभ मिला?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2006 से 30.12.2006 तक राज्य के सभी जिलों के ब्लॉकों में स्वास्थ्य जन चेतना यात्रा कार्यक्रम की क्रियान्विती की गई थी।

उक्त यात्रा पर कुल रुपये 891.89 लाख व्यय किये गये जिसमें से जिले स्तर पर किये गये व्यय रु. 732.34 लाख का जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) अभियान की विभिन्न गतिविधियों के तहत ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों को सीधे राशि आबंटित नहीं की गई थी। यह राशि निदेशक आई.ई.सी. के द्वारा जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मदों पर व्यय हेतु दी गई थी। जिसमें मदान्तरण करने के लिए जिला कलक्टर को पूर्णतया अधिकृत किया गया था।

(3) स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य भर में ग्राम स्तर तक विभिन्न विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, ग्रामीण एवं पंचायती राज, शिक्षा आदि के सम्मिलित सहयोग से 1 दिसम्बर, 2006 से 30 दिसम्बर, 2006 तक स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की गांव-गांव तक पहुंच व जानकारी उपलब्ध कराना था ताकि अधिक से अधिक लोगों द्वारा विभागीय सेवाओं का उपयोग कर तथा अभिनव योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाया जा सके।

यात्रा के दौरान जन समुदाय को सरल भाषा में दृश्य श्रृव्य माध्यमों से स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या स्थिरीकरण, संचारी रोग, मौसमी बीमारियों, टीकाकरण, छोटा परिवार, कन्या भ्रूण हत्या, विवाह की उचित आयु, जननी सुरक्षा योजना, स्तनपान आदि विषयों पर जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य चेतना यात्रा की विजुअल मानिटरिंग के दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधि विधायक/सरपंच/वार्डपंच/युवक/युवतियां, स्कूली बच्चों आदि से योजनाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी से मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी ली गई।

स्वास्थ्य चेतना यात्रा की निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं:-

स्वास्थ्य चेतना यात्रा के अन्तर्गत 9205 केम्प आयोजित किये गये।

केम्पों में कुल 3105610 मरीज देखे गये, जिसमें एलोपैथिक पद्धति से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1902598 तथा आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक व यूनानी पद्धति से 1203013 मरीज देखे गये।

285282 मरीजों की पैथोलोजी लेब जांचे की गई। 13561 मरीजों को उचित इलाज हेतु रेफर किया गया।

बाल स्वास्थ्य हेतु 150197 शिशु रोग के मरीज देखे गये।

0 से 1 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के अन्तर्गत 55205 बी.सी.जी. 127213 डी.पी.टी. व ओपीवी I, II & III 38971 मिजल्स के टीके लगाये गय। 0 से 1 वर्ष तक 96692 बच्चों को विटामिन **''ए''** का घोल पिलाया गया।

आयु वर्ग 1-5 वर्ष तक 243303 बच्चों को विटामिन **''ए''** का घोल पिलाया गया।

प्रपत्र 'अ'

स्वास्थ्य चेतना यात्रा 2006 हेतु जिले स्तर पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**व्यय की गई राशि (रु. लाख में)**
1	धौलपुर	14.56
2	झुन्झुनूं	24.60
3	बून्दी	14.96
4	बीकानेर	11.99
5	बारां	19.31
6	बांसवाड़ा	26.79
7	करौली	19.45
8	कोटा	17.18
9	सिरोही	13.71
10	चित्तौड़गढ़	32.27
11	हनुमानगढ़	17.89
12	भीलवाड़ा	18.23
13	भरतपुर	28.98
14	पाली	26.10
15	श्रीगंगानगर	24.00
16	राजसमन्द	21.98

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**व्यय की गई राशि (रु. लाख में)**
17	चूरू	19.38
18	सीकर	25.72
19	सवाई माधोपुर	16.39
20	उदयपुर	38.92
21	डूंगरपुर	18.75
22	दौसा	17.55
23	जयपुर	39.36
24	जोधपुर	28.70
25	जालौर	18.65
26	जैसलमेर	16.83
27	नागौर	33.66
28	टोंक	18.58
29	अजमेर	25.38
30	अलवर	36.84
31	झालावाड़	16.32
32	बाडमेर	29.31
कुल योग :-		**732.34**

खारची के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रैबीज इन्जेक्शनों की आपूर्ति

410. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप के काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन व रैबीज के इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खारची में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कब-कब कितने इन्जेक्शन उपलब्ध करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त इन्जेक्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(3) विधान सभा क्षेत्र खारची में पिछले तीन वर्षों में रैबीज व सांप काटने के कितने प्रकरण किस-किस स्थान पर सामने आये तथा उन्हें उक्त इन्जेक्शन कहां से उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रैबीज के इन्जेक्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से बी.पी.एल. कार्डधारियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप काटने के इन्जेक्शन उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराये जाते है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से उपलब्धता के आधार पर बी.पी.एल. कार्डधारियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र खारची के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिन पर मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी गठित है उन पर रैबीज एवं सांप काटने के इन्जेक्शन बी.पी.एल कार्डधारियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गठित मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी बी.पी.एल. कार्डधारियों को इन्जेक्शन क्रय कर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र खारची के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थान पर गत 3 वर्षों में सर्पदंश एवं श्वानदंश के चिन्हित केसेज की संख्या एवं उनको जिन चिकित्सा संस्थान से इन्जेक्शन उपलब्ध करवाये गये का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

खारची के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में श्वानदंश के चिन्हित केसेज की संख्या एवं उनको जिला चिकित्सा संस्थान से इंजेक्शन उपलब्ध करवाये गये का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र का नाम	श्वानदंश						इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा संस्थान का नाम
		2004		2005		2006		
		रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	
1	बागोल	41	4	54	06	53	6	सामु. स्वा. केन्द्र सादड़ी
2	धामली	33	5	33	4	33	7	बांगड अस्पताल/पाली/सोजत
3	धनला	0	0	75	7	81	13	बांगड अस्पताल/पाली/सोजत
4	जोजावर	0	0	13	0	15	0	बांगड अस्पताल/ पाली/सोजत
5	खारची	94	0	114	5	110	2	बांगड अस्पताल/पाली/सोजत
6	खिवाडा	27	5	22	7	32	3	बांगड अस्पताल/सोजत

खारची के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में सर्पदंश के चिन्हित केसेज की संख्या एवं उनको जिन चिकित्सा संस्थान से इंजेक्शन उपलब्ध करवाये गये का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र का नाम	सर्पदंश						इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा संस्थान का नाम
		2004		2005		2006		
		रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	रोगियों की सं.	बी.पी.एल. कार्डधारी	
1	बागोल	1	0	0	0	1	0	सामु. स्वा. केन्द्र सादडी
2	धामली	0	0	0	0	0	0	बांगड अस्पताल/पाली/ सोजत
3	धनला	2	0	0	0	0	0	बांगड अस्पताल/पाली/ सोजत
4	जोजावर	1	0	2	0	2	0	बांगड अस्पताल/पाली/ सोजत
5	खारची	1	0	12	1	13	1	बांगड अस्पताल/पाली/ सोजत
6	खिवाडा	5	0	7	0	9	1	बांगड अस्पताल/पाली/ सोजत

खारची के बी.पी.एल. कार्डधारी रोगियों को चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई गयी है।

प्रतापगढ़ के भवन रहित चिकित्सा केन्द्र

411. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो भवन रहित हैं? वर्तमान में यह भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्र किस-किस भवन में चलाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखते हुये यह भी बतायें कि क्षेत्र में भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वयं का भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? चालू वित्तीय सत्र में क्षेत्र में भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है?

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के अन्तर्गत आने वाले ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अनुरूप नहीं हैं एवं भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा वर्तमान में उक्त केन्द्रों को किस भवन में चलाया जा रहा है का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में उप स्वास्थ्य केन्द्र कानगढ़ पंचायत समिति अरनोद एवं कैरवास पंचायत समिति प्रतापगढ़ के भवन निर्माण हेतु प्रति केन्द्र 4.60 लाख रुपये की दर से चरणबद्ध रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख रुपये प्रति केन्द्र की दर से राशि उपलबध कराई गई है।

परिशिष्ट 'अ'

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के अन्तर्गत आने वाले ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनका भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अनुरूप नहीं है एवं भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा वर्तमान में किस भवन में चलाये जा रहे हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

तहसील का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	वर्तमान में किस भवन में संचालित हैं	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	वर्तमान में किस भवन में संचालित हैं
अरनोद	अचनेरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में	जीरावता	किराये के मकान में
			बोरदिया	किराये के मकान में
			रायपुर	किराये के मकान में
			नोगांवा	किराये के मकान में
			खरखडा	किराये के मकान में
			फतेहगढ़	किराये के मकान में
			बडायला	किराये के मकान में
			अचलावदा	किराये के मकान में
			कनाड	किराये के मकान में
			बैडमा	किराये के मकान में
			बोरी	किराये के मकान में
			लीलीया	किराये के मकान में
			नांदीखेडा	किराये के मकान में
			कानगढ़	किराये के मकान में
प्रतापगढ़	सिद्धपुरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में	पटेलिया	किराये के मकान में
	रामपुरिया	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में	सेलारपुरा	किराये के मकान में
	बरडिया	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में	मदुरातलाब	किराये के मकान में
	देवगढ़	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में	खोरिया	किराये के मकान में
			कोतवाल	किराये के मकान में
			कल्याणपुरा	किराये के मकान में
			पानमोडी	किराये के मकान में
			कैरवास	किराये के मकान में

सादुलपुर-बहल सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण

412. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सादुलपुर-बहल सड़क अन्तरराज्यीय सड़क है तथा यह राजस्थान सीमा से कितनी दूरी पर है?

(2) वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई कितनी है?

(3) क्या सरकार अन्तरराज्यीय मार्ग होने के कारण इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है?

(4) क्या उक्त सड़क बीकानेर-जोधपुर-दिल्ली मार्ग का सब से छोटा मार्ग है? यदि हां, तो इसे कब तक चौड़ा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इस सड़क की राजस्थान राज्य में लम्बाई 17.20 कि.मी. है।

(2) वर्तमान में इस सड़क की डमरीकृत चौड़ाई 3.75 मीटर है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। वर्तमान में उक्त सड़क पर पी.सी.यू. 4096 होने के कारण निर्धारित नार्मस् अनुसार सड़क को चौड़ा करना प्रस्तावित नहीं है।

सम्पर्क सड़क जरवाना-रायथल (बूंदी) का मुआवजा प्रकरण

413. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क जरवाना-रायथल (बून्दी) के लिये अवाप्त भूमि में से कुछ भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान कतिपय कारणों से नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो किस-किस खसरा कृषक को, किस-किस नम्बर की, कितनी-कितनी भूमि का किस-किस कारण से? कृषकवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शेष रहे किसानों की मुआवजा राशि अदा की जाने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या तथा यह कार्यवाही कब तक पूर्ण की जाकर मुआवजा राशि अदा कर दी जाएगी?

(3) क्या सरकार सड़क निर्माण के काम आने वाली भूमि के मामलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही कृषि भूमि की मुआवजा राशि के

(श्री रामनारायण मीणा)

भुगतान के लिये नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जखाना से रायथल (बून्दी) के लिये अवाप्त भूमि में से कुछ मुआवजा राशि का भुगतान कतिपय कारणों से नहीं किया जा सका। जिसका विवरण कृषकवार मय अवाप्ति भूमि व खसरा नम्बर प्रपत्र 'अ' पर अंकित है।

(2) जी हां। शेष किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2006-07 में कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। नियमों में क्योंकि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही कृषि भूमि के मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है।

प्रपत्र-अ

कृषकों की सूची जिनको मुआवजे का भुगतान कतिपय कारणों से नहीं हुआ

क्र. सं.	कृषक का नाम	निवास स्थान	खसरा संख्या	अवाप्त भूमि	भुगतान नहीं होने का कारण
1	रामचन्द्र पुत्र मन्ना मीणा	सा. कांजरी सिलोर	245	0.08 का 1/4 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जायेगा।
2	ओंकार पुत्र मन्ना मीणा	सा. कांजरी सिलोर	245	0.08 का 1/4 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
3	फुन्दिया पुत्र मन्ना मीणा	सा. कांजरी सिलोर	245	0.08 का 1/4 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जावेगा।

क्र. सं.	कृषक का नाम	निवास स्थान	खसरा संख्या	अवाप्त भूमि	भुगतान नहीं होने का कारण
4	गेन्दिया पुत्र मन्ना मीणा	सा. कांजरी सिलोर	245	0.8 का 1/4 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
5	कालू पुत्र गेन्दिया दरोगा	मण्डित्या	82	0.10 का 1/3 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
6	हीरा पुत्र गेन्दिया दरोगा	मण्डित्या	82	0.10 का 1/3 भाग	हितधारी की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसान द्वारा परवर्तित रिकोर्ड प्रस्तुत करने पर तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
7	धन्ना पुत्र गेन्दिया दरोगा	मण्डित्या	82	0.10 का 1/3 भाग	हितधारी अन्थड़ा गांव में रहता है तथा नोटिस तामील हो चुका है। उपस्थित होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

बीकानेर जिले के अनुपयोगी राजकीय भवन

414. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में ऐसे अनेक सरकारी भवन हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों तथा यह भवन कहां-कहां स्थित हैं? इन भवनों का निर्माण किन उद्देश्यों से किस एजेन्सी द्वारा, कितनी लागत से, कब व किसकी देख-रेख में पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि दीर्घकाल से खाली रहने के कारण ये भवन असामाजिक तत्वों का ठिकाना/कचरा पात्र बन गए हैं या इनके दरवाजे, खिड़कियां आदि चोरी हो गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इन भवनों को पुनः राजकीय कार्यों के उपयोग में लेने-बेचने/किराए पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला बीकानेर में मुख्यालय पर ऐसे 18 राजकीय आवासीय भवन हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है।

उक्त आवासों में से आठ आवास वर्ष 1998 से, एक आवास वर्ष 1999 से, एक आवास वर्ष 2000 से, चार आवास वर्ष 2002 से, तीन आवास वर्ष 2004 से, एवं एक आवास वर्ष 2005 से रिक्त हैं।

उक्त आवासों में से नौ आवास अमरसिंहपुरा, तीन आवास सिविल लाईन, दो गजनेर सड़क एवं चार कोट गेट क्षेत्र में स्थित हैं।

उक्त भवनों का निर्माण राजकीय आवासों के उद्देश्य से किया गया था। पन्द्रह आवास रियासत काल वर्ष 1948 से पूर्व एवं तीन आवास सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा (वर्ष 1958 में दो एवं 1976 में एक) निर्मित है।

उक्त आवासों की तत्कालीन लागत रुपये 4.35 लाख थी।

(2) उक्त आवास उपयोग योग्य नहीं होने के कारण रिक्त हैं। इसीलिए अमरसिंहपुरा स्थित आवासीय भवनों से दरवाजे, खिड़कियां आदि उतरवाकर विभाग के स्टोर में जमा कर लिये गये हैं।

(3) मरम्मत करके उपयोग में लेना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

निम्बाहेडा-दाहोद सड़क मार्ग का निर्माण प्रकरण

415. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से दाहोद गुजरात सीमा-वाया बांसवाड़ा नेशनल हाइवे मार्ग नम्बर 113 के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी

(श्री नवनीत नीनामा)

है? यदि हां, तो इनका कार्य कब शुरू होगा? मय लागत के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नेशनल हाइवे सड़क विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गांव मूड़ासेल में नाड़ा तोड नाम की घाटी हाइवे सड़क योजना द्वारा कटिंग कर एक्सीडेन्ट के खतरों को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। निम्बाहेड़ा से दाहोद गुजरात सीमा वाया बांसवाड़ा नेशनल हाइवे मार्ग नम्बर 113 जिसकी कुल लम्बाई 225 कि.मी. है यह सड़क पूर्व में ही निर्मित है। इस सड़क को फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया था तत्पश्चात इस सड़क पर वर्ष 2005-06 में 59.50 कि.मी. में सामयिक नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत राशि रुपये 483.83 लाख के कराये गये। वर्ष 2006-07 में कि.मी. 2/0 से 20/0 तथा 200/0 से 219/0 में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के तकमीने केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे। इनमें से कि.मी. 200/0 से 213/0 की स्वीकृत राशि रुपये 794.60 लाख की प्राप्त हो गई है जिसकी निविदायें दिनांक 07-4-2007 को प्राप्त करने हेतु निविदा सूचना जारी की जा चुकी है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास एवं सुधार कार्य केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति से किये जाते हैं। यह कार्य भी केन्द्र सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

रैस्ट हाउस तिजारा (अलवर) का जीर्णोद्धार

416. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर स्थित रैस्ट हाऊस जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

सराड़ा के स्वीकृत निर्माण कार्य

417. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में चालू वित्तीय वर्ष में किस-किस मद से क्या-क्या कार्य कराया गया? इन पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में चालू वित्तीय वर्ष में करवाये गये कार्यों का मदवार व कार्यवार, स्वीकृत राशि व व्यय राशि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

सराडा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	फरवरी 2007 तक कुल व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
1	सेमारी कुराडिया	71.95	59.67
2	सम्पर्क सड़क नीमडी	112.16	94.15
3	सम्पर्क सड़क ढेलाई	112.27	1309
4	सम्पर्क सड़क केजड से मायर	82.10	28.01
5	सम्पर्क सड़क ओरा	65.54	13.86
6	सम्पर्क सड़क पादरडा	46.95	20.03
7	सम्पर्क सड़क खरड	138.68	123.75
8	सम्पर्क सड़क कानपुर	40.16	33.01
9	सम्पर्क सड़क वली	54.33	8.10
10	सम्पर्क सड़क करणपुरिया	58.98	31.64
11	सम्पर्क सड़क अम्बाला	88.88	55.11
12	सम्पर्क सड़क बरोठी	122.92	37.69

1	2	3	4
13	सम्पर्क सड़क वेलवडी	49.41	32.93
14	सम्पर्क सड़क ढाली मेलाणा	61.20	28.67
15	सम्पर्क सड़क पाडला से कोटडी	177.54	66.59
16	सम्पर्क सड़क कुण्डाल	45.65	19.69
17	सम्पर्क सड़क सैयत भागल	42.07	15.06
18	सम्पर्क सड़क लुहारिया	34.56	12.20
19	सम्पर्क सड़क सेन्थल	81.12	41.61
20	सम्पर्क सड़क अम्बाला	91.41	54.46
21	सम्पर्क सड़क बेजपुर	44.23	16.80
22	सम्पर्क सड़क मुण्डाला	90.64	18.86
23	सम्पर्क सड़क चन्दाजी का गुडा	55.91	7.50
	योग:-	**1768.66**	**832.48**
2. डब्ल्यू बी.एम. बी.टी. फेज द्वितीय			
1	ईटाली, बडावली, सल्लाडा, डींगरी	52.00	17.41
2	सल्लाडा से बस्सी	11.00	4.03
	योग:-	**63.00**	**21.44**
3. डब्ल्यू बी.एम. बी.टी. फेज तृतीय			
1	केजड़ से नीमच	78.00	0.07
2	ढाणी से ढाणी सेपुर	36.00	27.10
3	ए/आर चन्दोडा	24.00	15.06
4	चावण्ड से बण्डोली	43.00	7.26
5	ए/आर ढाणी सीपुर से मूलेश्वर महादेव	11.00	7.67
	योग:-	**192.00**	**57.17**

1	2	3	4
4. 3054-टी.एफ.सी.			
1	कातनवाड़ा से चावण्ड	6.50	0
2	सुरखन खेडा रेल्वे स्टेशन से नावडा	9.75	0
3	सम्पर्क सड़क शक्तावतों का गुडा	26.00	0.03
4	सम्पर्क सड़क खरबड़	19.50	0
5	पाल सराडा से ठाकरडा	12.00	0.04
6	सलूम्बर चावण्ड	20.00	0.20
7	जयसमन्द बस्सी करोडिया	13.00	0
8	सम्पर्क सड़क घोडासर	9.75	0
9	पलोद्ड़ा, देवपुरा, जावर माइन्स	18.00	0
10	सम्पर्क सड़क गातोड	6.00	0
11	सम्पर्क सड़क अदवास	31.50	0.20
12	सम्पर्क सड़क नठारा	13.50	0
13	सम्पर्क सड़क भोराई	7.00	0
14	सम्पर्क सड़क बाणा कला	6.50	0
15	सम्पर्क सड़क सरसिया	9.75	0
16	सम्पर्क सड़क प्रताप स्मारक	4.25	0
17	ए/आर चनावदा	22.75	22.75
	योग:-	**235.75**	**23.22**
5. 3054-टी.एफ.सी. सी.सी. रोड			
1	सी.सी. कार्य टोकर विलेज	26.00	0
	योग:-	**26.00**	**0**
6. 2245- बाढ़ सहायता			
1	सलूम्बर कल्याणपुर	3.00	1.68
2	ऋषभदेव, सराड़ा, जयसमन्द, जगत रोड	3.00	1.67

1	2	3	4
3	पलोदड़ा कल्याणपुर रोड	4.00	2.95
4	सलूम्बर चावण्ड रोड	2.00	0.07
5	ओडा जावर माइन्स	20.00	0.14
6	चावण्ड, थाना, डींगरी	1.50	0
7	ए/आर खरबर	4.00	3.99
8	पाण्डेर कुई से ढाकरडा	2.50	0
9	टोकर-शक्तावतों का गुडा	1.50	1.41
10	जावद से माल	3.00	0
11	पलोदड़ा, जावर माइन्स	1.50	0
12	ईटाली, बडावली, सल्लाड़ा, डींकरी	10.00	7.65
13	मरम्मत कार्य ए/आर चणावदा	4.00	4.00
	योग:-	**60.00**	**23.56**
7. 3054-विशेष मरम्मत (बाढ़ सहायता)			
1	ऋषभदेव, सराड़ा, जयसमन्द, जगत रोड	3.50	1.26
2	ओडा जावर माइन्स	5.00	0
3	टोकर-शक्तावतों का गुडा	0.50	0
4	पलोदड़ा, जावर माइन्स	0.50	0
	योग:-	**9.50**	**1.26**
8. 8443-डिपोजिट (बाढ़ सहायता)			
1	सलूम्बर कल्याणपुर	3.40	0.29
2	ऋषभदेव, सराड़ा, जयसमन्द, जगत रोड	6.50	4.69
3	पलोदड़ा कल्याणपुर रोड	4.10	0.33
4	सलूम्बर चावण्ड रोड	4.20	0.31
5	ओडा जावर माइन्स	0.15	0.15
6	चावण्ड, थाना, डींकरी	3.10	1.69
	योग:-	**24.35**	**8.72**

1	2	3	4
9. 8443-डिपोजिट तृतीय (एन.आर.ई.जी.एस.)			
1	ग्रेवल सड़क बरोठी से गुप्तेश्वर महादेव वाया पोला मगरा	21.21	1.37
2	ग्रेवल सड़क बरोठी से माताजी	13.07	2.09
3	ग्रेवल सड़क मऊडी घाटी से धावड़ी घाटी	23.68	1.04
4	उप्रावि मायर से रा.ग्रा.पा. जोयरा तक सड़क	16.28	0.25
	योग:-	**76.24**	**4.75**
भवन कार्य			
1. 4210-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य			
1	पी.एस.सी. सब सेन्टर सुरखनखेडा	4.60	0
2	रा.आयु. औषधालय टोकर का निर्माण	3.00	1.17
3	रा.आयु. औषधालय पिलादर का निर्माण	3.00	1.96
	योग:-	**10.60**	**3.13**
2. 8443–डिपोजिट (एन.आर.एच.एम)			
1	डाक्टर नर्सिंग एवं वार्डबॉय क्वाटर झाडोल	43.80	0
2	डाक्टर नर्सिंग एवं वार्डबॉय क्वाटर सेमारी	48.50	0
	योग:-	**92.30**	**0**
3. 8443–डिपोजिट (टी.ए.डी.)			
1	निर्माण कार्य कन्या छात्रावास 50 बेडेड (एस.टी.) भौराई पाल का कार्य	33.37	22.80
	योग:-	**33.37**	**22.80**

सड़क निर्माण हेतु रिफायनरी से प्राप्त डामर का उपयोग

418. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सड़क कार्यों के ठेकेदारों द्वारा डामर एवं इम्मलसन निर्धारित मात्रा से कम प्रयोग कर घटिया सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार डामर उपयोग की मात्रा रिफायनरी से प्राप्त मात्रा से अधिक पाये जाने पर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा उपयोग एवं रिफायनरी से प्राप्त विभिन्न तरह के डामर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, विभाग के अधीन सड़कों के कार्यों पर ठेकेदारों द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ही डामर एवं इम्मलसन का प्रयोग कर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

(2) गत तीन वर्षों में रिफायनरी से प्राप्त विभिन्न तरह के डामर एवं उपयोग की मात्रा का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

<u>परिशिष्ट-'अ'</u>

गत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06, 2006-07) में सरकार द्वारा उपयोग एवं रिफाइनरी से प्राप्त विभिन्न तरह के डामर का विवरण

क्र. सं.	जोन का नाम	रिफाइनरी से प्राप्त डामर का विवरण		डामर उपयोग की मात्रा (टन में)	
		इम्म्लशन (मात्रा टन में)	80/100, 60/100 सी.आर.एम.बी. डामर (मात्रा टन में)	इम्म्लशन	80/100, 60/100 सी.आर.एम. बी. डामर
1	प्रथम-जयपुर	6396.46	21286.44	6140.54	20488.60
2	द्वितीय-जयपुर	3278.41	23875.36	3173.00	22908.00
3	अजमेर	9702.90	43827.48	9650.54	41328.77
4	बीकानेर	7386.52	32072.96	7046.96	31322.39
5	जोधपुर	13706.07	56608.12	11594.86	53472.52
6	कोटा	7095.98	30226.80	6392.33	28425.66
7	उदयपुर	8767.07	38303.33	8612.64	34663.31
	कुल योग:-	**56333.41**	**246200.49**	**52610.87**	**232609.25**

जयपुर जिले के विद्यालयों हेतु आबंटित भूमि

419. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा आपरेशन गुरूकुल की शुरूआत किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कब व किन जिलों में की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा कितने सरकारी स्कूलों को भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण को कब प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कितने भूमिहीन स्कूलों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित कर लाभान्वित किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) स्कूलों को भूमि विलम्ब से उपलब्ध कराने के क्या कारण रहे तथा शेष भूमिहीन स्कूलों को कब तक भूमि का आबंटन कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आपरेशन गुरूकुल की शुरूआत निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जयपुर जिले में की गई है:-

1. जिन विद्यालयों के नाम भूमि का आबंटन होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है उनको सूचीबद्ध किया जाना तथा विद्यालय भूमि पूर्णतया अतिक्रमण रहित है, यह सुनिश्चित करना।
2. विद्यालयों को आबंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अमल या नक्शे में तरमीम करवाना।
3. जिन विद्यालयों को भूमि आबंटित नहीं हुई है, उनको भूमि का आबंटन करवाना।
4. आबादी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवाने की कार्यवाही करवाना।
5. जो विद्यालय निजी खातेदारी भूमि में स्थित है, उनके लिए संबंधित काश्तकार को प्रेरित कर विद्यालय के लिए राज्य सरकार के पक्ष में भूमि समर्पित करवाई जाकर भूमि आबंटन किया जाना सुनिश्चित करवाना।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अब

(शिक्षा मंत्री)

तक 494 विद्यालयों को भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव परिशिष्ट '1' पर अंकित तिथि अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 15 भूमिहीन स्कूलों को भूमि आबंटित कर लाभान्वित किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-2

(4) स्कूलों को भूमि आबंटन हेतु आस-पास भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि आबंटित नहीं की जा सकी तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संजयनगर कच्ची बस्ती में वांछित क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा राजकीय संस्कृत विद्यालय, मोहनपुरा को प्रस्तावित भूमि गैर मुमकिन तलाई होने के कारण आबंटन नहीं की गई। इसके अलावा शेष प्रकरणों में भूमि आबंटन की कार्यवाही विचाराधीन है। भूमि उपलब्ध होते ही आबंटन की कार्यवाही शीघ्र कर दी जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील मुख्यालय बायतु (बाड़मेर) पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

420. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बायतु तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बायतु तहसील मुख्यालय के समीप 7 सीनियर विद्यालय, 8 माध्यमिक विद्यालय एवं 54 उच्च प्राथमिक विद्यालय पोशक विद्यालयों के रुप में विद्यमान हैं?

(3) क्या सरकार बायतु में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं । बजट के सीमित संसाधनों के कारण बाड़मेर के बायतु तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय क्षेत्र में वर्तमान में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है ।

बाड़मेर के बायतु तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने हेतु बजट की उपलब्धता होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

तहसील संगरिया/सादुल शहर में अध्यापकों के रिक्त पद

421 श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) संगरिया तहसील एवं सादुल शहर तहसील में पिछले तीन वर्षो में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है इन नव क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों के पद भर दिये गये यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने को विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संगरिया एवं सादुल शहर तहसील में पिछले तीन वर्षो में 42 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' सलंग्न है ।

(2) जी नहीं । विभाग के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जा सकेगा ।

परिशिष्ट ''क''

सादुल शहर एवं संगरिया में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण

क्र. स.	तहसील	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालय का स्थान
1	सादुल शहर	राउप्रावि	लालगढ़ जाटान (बालिका)
2	सादुल शहर	राउप्रावि	खैरुवाला (बालिका)
3	सादुल शहर	राउप्रावि	बनेवाली (बालिका)
4	सादुल शहर	राउप्रावि	अमरगढ़ (बालिका)
5	सादुल शहर	राउप्रावि	मोरजण्ड खारी (बालिका)

क्र. स.	तहसील	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालय का स्थान
6	सादुल शहर	राउप्रावि	सरदारपुरा जीवन
7	सादुल शहर	राउप्रावि	करड़ वाला (बालिका)
8	सादुल शहर	राउप्रावि	पतली (बालिका)
9	सादुल शहर	राउप्रावि	सादुल श्हर (बालिका)
10	सादुल शहर	राउप्रावि	41 पी.टी.पी.
11	सादुल शहर	राउप्रावि	12 एस.पी.एस.
12	सादुल शहर	राउप्रावि	12 एच.एच
13	सादुल शहर	राउप्रावि	1 बी.बी
14	सादुल शहर	राउप्रावि	जी.बी. वाला (बालिका)
15	सादुल शहर	राउप्रावि	डूंगर सिंह पुरा
16	सादुल शहर	राउप्रावि	प्रतापपुरा
17	सादुल शहर	राउप्रावि	मन्नीवाला
18	संगरिया	राउप्रावि	नकेरा
19	संगरिया	राउप्रावि	3 आर.टी.बी.
20	संगरिया	राउप्रावि	एस.एल.जी.
21	संगरिया	राउप्रावि	बोलावाली
22	संगरिया	राउप्रावि	संतपुरा
23	संगरिया	राउप्रावि	मोरजण्ड सिखान
24	संगरिया	राउप्रावि	मानकसर
25	संगरिया	राउप्रावि	शाहचीनी
26	संगरिया	राउप्रावि	9 एन.के.आर.
27	संगरिया	राउप्रावि	किशनपुरा उतरादा
28	संगरिया	राउप्रावि	रासुवाला
29	संगरिया	रामावि	भाखरांवाली
30	संगरिया	रामावि	इन्द्रगढ़
31	सादुल शहर	रामावि	गणेशावाली
32	सादुल शहर	रामावि	नूरपुर ढ़ाणी
33	सादुल शहर	रामावि	सुन्दरपुरा
34	संगरिया	राउमावि	संतपुरा

क्र. स.	तहसील	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालय का स्थान
35	सादुल शहर	राउमावि	चक महाराज का
36	सादुल शहर	राउमावि	सरदारपुरा जीवन
37	सादुल शहर	राउमावि	डूंगरसिंहपुरा (बालिका)
38	सादुल शहर	राउमावि	पन्नीवाली जाटान
39	संगरिया	राउप्रासस्कृतवि	चक 2 आर.टी.पी.
40	सादुल शहर	राउप्रासस्कृतवि	8 एल.एल.जी. लालगढ़
41	सादुल शहर	राउप्रासस्कृतवि	21 एम.एल. कुलडियों की ढाणी
42	सादुल शहर	राउप्रासस्कृतवि	सादुल शहर (न.पा.)

सेवानिवृत्त अध्यापिका का पेंशन प्रकरण

422. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती उर्मिला शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापिका को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर शहर पश्चिम जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक व.उ.जि.शि.अ/ज.श.प./नि.स./ज./153 दिनांक 18 फरवरी, 2005 के द्वारा उनसे प्रथम नियुक्ति पत्र, स्थानान्तरण आदेश, योग्यता प्रमाण-पत्र, वेतन स्थिरीकरण आदेश एवं अवकाश स्वीकृत आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 19 मार्च 2005 द्वारा उप जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि श्रीमती शर्मा की नियुक्ति दिनांक 8 जुलाई, 1958 को अध्यापिका के पद पर पिलानी राजस्थान में हुई थी ? यदि हां, तो इनका प्रथम नियुक्ति पत्र एवं सेवा अभिलेख की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरुप एक समिति का पुन: गठन किया गया ? यदि हां, तो समिति का गठन कब हुआ

(श्री मुरारीलाल मीण)

व इसमें कौन कौन सदस्य थे तथा उक्त समिति द्वारा जांच कब पूर्ण की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रीमती उर्मिला शर्मा की प्रोवीजनल पेन्शन जारी कर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो प्रोवीजनल पेन्शन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बताने का श्रम करें कि इनके पूर्ण पेन्शन के आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती उर्मिला शर्मा का डुप्लीकेट सेवा रिकार्ड तैयार करने हेतु वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर पश्चिम ने अपने पत्र दिनांक 18.2.2005 के द्वारा प्रथम नियुक्ति पत्र, स्थाइकरण आदेश, योग्यता प्रमाण पत्र, वेतन स्थिरीकरण आदेश तथा अवकाश स्वीकृति आदेश आदि रिकार्ड चाहा गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अपितु 8.7.1957 को राबाउप्रावि, चिड़ावा (झुन्झुनूं) में हुई।

(4) श्रीमती उर्मिला शर्मा का डुप्लीकेट सेवा रिकार्ड तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जयपुर द्वारा दिनांक 11.2.2005 को निम्न समिति का गठन किया गया।

1. श्री भूपसिंह यादव, वउजिशिअ, जयपुर पश्चिम।

2. श्री गोविन्द गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार।

3. श्री महेशचन्द शर्मा, प्र.अ. राआप्रावि चांदपोल जयपुर।

उक्त समिति द्वारा कोई जांच नहीं की गई अपितु यह समिति डुप्लीकेट सेवा रिकार्ड तैयार करने का कार्य कर रही है।

(5) श्रीमती उर्मिला शर्मा की प्रोविजनल पेन्शन जारी हो चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-क संलग्न है। कार्मिक द्वारा वांछित सहयोग नहीं करने के कारण डुप्लीकेट सेवा रिकार्ड तैयार नहीं किया जा सका है।

परिशिष्ट – 'क'

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर

उपदान (ग्रेच्यूटी) भुगतान आदेश

मांग संख्या – 15 पेंशन

2071 – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ

01 – सिविल   जी.पी.ओ.सं.

104 – उपदान   216010

(001) राज्य कर्मचारियों को उपदान

रुपये 8191/- आठ हजार एक सौ इक्यानवें मात्र से कम

क्रमांक:/पी.आर 3 /पी.एफ: 729 के 106/02-03   दिनांक ....

प्रेषित :

पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी.........................

मार्फत कोषाधिकारी ....

महोदय,

कृपया श्री/श्रीमती/कु. उर्मिला शर्मा उपदान गृहिता/ अवयस्क के संरक्षक को शिक्षा विभाग के प. संख्या .... दिनांक .... में स्वीकृत उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से नीचे अनु. संख्या 2 में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार वसूलियों को घटाकर एवं शर्तों की पूर्ति के पश्चात् नियमानुसार कोषालय/उपकोषालय जयपुर से रुपये 8190/- (आठ हजार एक सौ नब्बे मात्र) का भुगतान कराने की व्यवस्था करें।

2. निम्नांकित वसूलियां प्राधिकृत उपदान की राशि में से की जाकर उन्हें प्रत्येक के सामने अंकित शीर्षों में जमा की जानी चाहिए।

वसूली का विवरण	**राशि**	**लेखा शीर्ष जिसमें जमा करनी है**
1. भवन अग्रिम	....	7610
2. वाहन अग्रिम	....	7610
3. ब्याज/वाहन-भवन	....	0049
4. विभागीय वसूली	....	
5. पुन: नियुक्ति	....	
6. अन्य	....	

3. इस प्राधिकार पत्र को विवरण अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में उस समय तक रखा जाना चाहिए जब तक कि इसका भुगतान न हो जाये। यह इसके जारी होने की तारीख से केवल 12 माह तक प्रभावशील रहेगी। यदि इस अवधि में कोई भुगतान नहीं होता है तो इसे अमान्य समझा जाना चाहिये, तथा इस कार्यालय को लौटा दिया जाना चाहिए।

4. उपदान राशि से निम्न प्रकार राशि रोकी गई है:-

कुल स्वीकृत राशि ....

रोकी गई राशि ....

अधिकृत की गई राशि ....

5. कृपया इस आदेश की प्राप्ति सूचना भिजवायें।

भवदीय

संयुक्त निदेशक/सहा. निदेशक

पी.आर. 11834C 18-11-2003............................/पी.एफ; .... के .... दिनांक ....
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमती उर्मिला शर्मा A97 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा मोड़ जयपुर कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी जयपुर के समक्ष भुगतान प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।
2. जि. शि. अ. प्रा. जयपुर .... (कार्यालय)
3. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।

सहायक निदेशक

संयुक्त निदेशक/सहा. निदेशक

राजस्थान, जयपुर

<table>
<tr><td colspan="2">कोषागार कार्यालय उपयोग हेतु
बैंक/कोषागार
कृपया रुपये .... शब्दों में ....
.... का भुगतान करें।
जांच की इन्द्राज किया
(अ)
(ब) निम्न मदों में जमा की
लेखाकार दिनांक.................. कोषाधिकारी</td></tr>
<tr><td>प्राप्तकर्ता की रसीद
रू. .... का भुगतान दिनांक .... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर</td><td>बैंक/नॉन बैंक कोषागार के लिए
दिनांक .... को रुपये .... का भुगतान किया।

बैंक की मुद्रा प्रबन्धक/कोषाधिकारी</td></tr>
</table>

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:पी.आर.उपी.एफ.729/नि.पें.वि./06/02-2003 दिनांक :...........

प्रेषित

पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर

कोषाधिकारी .... मूल पेंशन रु. .... 249/- ....प्र.मा.

उप कोषाधिकारी ....रूपान्तरित पेंशन रु. .... X .....प्र.मा.

(मार्फत कोषाधिकारी...........) घटी हुई पेंशन रु. ..... 249/-... प्र.मा.

महोदय,

श्री/श्रीमती/कु: उर्मिला शर्मा .... भूतपूर्व : ......अध्या. .... कार्यालय : .... शिक्षा .... के पक्ष में पी.पी.ओ. संख्या 59389 आर एफ पी पी ओ संख्या ..../ (आर.एस.एफ.) पेंशन रु. .... 249/- .... प्र. मा. एवं मंहगाई राहत नियमानुसार की दोनों पड़त, पहिचान संबंधित दस्तावेज एवं वर्णात्मक नामावली संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। पेंशनर को पेंशन दिनांक .... 1-1-1975............. से प्रारंभ होगी।

पेंशन प्राप्तकर्ता की पहचान के संबंध में आपकी संतुष्टि के पश्चात् पेंशनर की पड़त वितरण अधिकारी पेंशन के हस्ताक्षर के पश्चात् उसे उपलब्ध करवा देवें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद भिजवावें।

भवदीय

संलग्न 1. पी.पी.ओ.नं. .... 59389 (आर)

एफ.पी.पी.ओ. नं. .... (आर.एस.एफ.)

2. पहिचान संबंधी दस्तावेज फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

लेखाधिकारी

3. वर्णनात्मक नामावली।

प्रेषित : पी.आर. .... /पी.एफ. .... /नि.पें.वि. .... दिनांक .... प्रतिलिपि प्रेषित है:- 11831 – C/18-11-2003

श्रीमती उर्मिला शर्मा, A97 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा मोड़, जयपुर .... (पेंशनर का नाम मय पता) को भेजकर लेख है कि वे इस अधिकृति का भुगतान प्राप्त करने हेतु पी.पी.ओ./कोषाधिकारी जयपुर से सम्पर्क करे।

जिला शिक्षा अधि. प्रा. जयपुर (विभाग/कार्यालय का नाम)।

लेखाधिकारी
सहायक निदेशालय

प्रश्न संख्या-423

(स्थगित)

नव चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया

424. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह फरवरी, 2007 में कितने शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा ली गई? संवर्गवार एवं जिलेवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी? वरीयता सूची का निर्धारण किस प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा? निर्धारित प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी? यदि हां, तो किस प्रक्रियान्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीसिंह रावत)

(4) क्या यह सही है कि एस.टी.सी. एवं बी.एड. अभ्यर्थियों की वरीयता अलग-अलग निर्धारित की जायेगी? यदि हां, तो किस तरह से? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 29028 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती हेतु फरवरी, 2007 में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। सवंर्गवार एवं जिलेवार पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' 'ख' संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थियों की सूची मय आवेदन-पत्र विभाग को प्राप्त होने पर उनके वरीयता क्रम से वर्गवार उस समय रिक्त पदों के अनुरूप आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाकर नियुक्ति हेतु निर्देशित किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में विभाग द्वारा निर्धारित है।

(3) उक्त नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों में महिलाओं के लिए उनके वर्ग में 30 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

(4) आयोग द्वारा नियमानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु विज्ञापित पदों की वरीयता सूची नियमानुसार जारी की जायेगी। बी.एस.टी.सी. डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र है।

परिशिष्ट-क

प्राथमिक विद्यालयों के लिए नवीन 10268 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों का जिलेवार एवं वर्गवार आबंटन

SN	District	GB POST	BACKLOG	ACTUAL POST	Gen			OBC			SC						ST						TOTAL	EX. SERVICEMAN	HANDICAPPED
											NON TSP AREA			TSP AREA			TON TSP AREA			TSP AREA					
					TOTAL	Gen	Female	TOTAL	Gen	Female	TOTAL	Gen	Female	TOTAL	Gen	Female	TOTAL	Gen	Female	TOTAL	Gen	Female			
1	Ajmer	76	0	76	40	28	12	15	11	4	12	9	3				9	7	2				76		
2	Alwar	231	0	231	120	84	36	48	34	14	36	26	10				27	19	8				231		
3	Barmer	1437	0	1437	735	515	220	301	211	90	229	161	68				172	121	51				1437		
4	Bharatpur	76	0	76	40	28	12	15	11	4	12	9	3				9	7	2				76		
5	Bhilwara	376	0	376	193	136	57	78	55	23	60	42	18				45	32	13				376		
6	Bikaner	119	0	119	62	44	18	24	17	7	19	14	5				14	10	4				119		
7	Bundi	141	0	141	74	52	22	29	21	8	22	16	6				16	12	4				141		
8	Churu	17	0	17	10	7	3	3	3	0	2	2	0				2	2	0				17		
9	Dausa	287	0	287	148	104	44	60	42	18	45	32	13				34	24	10				287		
10	Dholpur	296		296	152	107	45	62	44	18	47	33	14				35	25	10				296		
11	Hanuman-garh	87	0	87	46	33	13	18	13	5	13	10	3				10	7	3				87		
12	Jaipur	322	0	322	166	117	49	67	47	20	51	36	15				38	27	11				322		
13	Jaisalmer	272	0	272	140	98	42	57	40	17	43	31	12				32	23	9				272		
14	Jalore	500	0	500	255	179	76	105	74	31	80	56	24				60	42	18				500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	Jhalwar	200	0	200	102	72	30	42	30	12	32	23	9				24	17	7				200		
16	Jhunjhunu	15	0	15	9	7	2	3	3	0	2	2	0				1	1	0				15		
17	Jodhpur	856	0	856	439	308	131	179	126	53	136	96	40				102	72	30				856		
18	Karoli	331	0	331	171	120	51	69	49	20	52	37	15				39	28	11				331		
19	Kota	76	0	76	40	28	12	15	11	4	12	9	3				9	7	2				76		
20	Nagour	627		627	321	225	96	131	92	39	100	70	30				75	53	22				627		
21	Pali	151	0	151	78	55	23	31	22	9	24	17	7				18	13	5				151		
22	Rajsamand	401	0	401	205	144	61	84	59	25	64	45	19				48	34	14				401		
23	Swaimad-hopur	194	0	194	100	70	30	40	28	12	31	22	9				23	17	6				194		
24	Sikar	221	0	221	114	80	34	46	33	13	35	25	10				26	19	7				221		
25	Ganganagar	147	0	147	77	54	23	30	21	9	23	17	6				17	12	5				147		
26	Tonk	67	0	67	35	25	10	14	10	4	10	7	3				8	6	2				67		
27	Banswara	761	0	761	381	267	114	0	0	0	0	0	0	38	27	11	0	0	0	342	240	102	761		
28	Baran	94	0	94	50	35	15	9	7	2	7	5	2	0	0	0	5	4	1	23	17	6	94		
29	Chittorgarh	301	0	301	157	110	47	50	35	15	38	27	11	2	2	0	28	20	8	26	19	7	301		
30	Dungarpur	532	0	532	267	187	80	0	0	0	0	0	0	26	19	7	0	0	0	239	168	71	532		
31	Sirohi	114	0	114	62	44	18	20	14	6	15	11	4	0	0	0	11	8	3	6	5	1	114		
32	Udaipur	943	0	943	483	339	144	85	60	25	68	48	20	25	18	7	51	36	15	231	162	69	943		
	TOTAO	10268	0	10268	5272	3702	1570	1730	1223	507	1320	938	382	91	66	25	988	705	283	867	611	256	10268	1283	308

S N	tırtsi D	TS OP GB	GOI CAB	TS OP UTCA	Gen			OBC			SC						ST						LATOT	NA MED VRES. XE	FRAD DNAH
											NON TSP AREA			TSP AREA			TON TSP AREA			TSP AREA					
					ne G	ne G	ne G	CBO	CBO	CBO	AERA PST NON	AERA PST NON	AERA PST NON	AERA PST	AERA PST	AERA PST	AERA PST NOT	AERA PST NOT	AERA PST NOT	AERA PST NOT	AERA PST	AERA PST			
1	Ajmer	363	0	363	181	131	50	76	54	22	61	41	20				45	31	14				363		
2	Alwar	666	0	666	333	240	93	139	98	41	110	75	35				84	56	28				666		
3	Barmer	1173	0	1173	571	420	151	246	173	73	202	131	71				154	98	56				1173		
4	Bharatpur	324	0	324	162	117	45	68	48	20	53	36	17				41	27	14				324		
5	Bhilwara	831	0	831	414	299	115	174	122	52	138	93	45				105	70	35				831		
6	Bikaner	768	0	768	384	276	108	161	113	48	127	86	41				96	65	31				768		
7	Bundi	422	0	422	211	152	59	88	62	26	70	47	23				53	35	18				422		
8	Churu	464	0	464	233	167	66	97	68	29	77	52	25				57	39	18				464		
9	Dausa	336	0	366	166	122	44	70	49	21	56	38	18				44	28	16				336		
10	Dholpur	361	0	361	179	131	48	75	53	22	60	40	20				47	31	16				361		
11	Hanuman-garh	357	0	357	180	129	51	74	52	22	59	40	19				44	30	14				357		
12	Jaipur	989	0	989	492	355	137	207	145	62	165	111	54				125	83	42				989		
13	Jaisalmer	441	0	441	219	159	60	92	65	27	74	49	25				56	37	19				441		
14	Jalore	537	0	537	265	194	71	112	79	33	91	60	31				69	45	24				537		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	Jhalwar	503	0	503	250	181	69	105	74	31	84	56	28				64	42	22				503		
16	Jhunjhunu	556	0	556	280	201	79	116	82	34	91	62	29				69	47	22				556		
17	Jodhpur	927	0	927	455	332	123	194	136	58	157	104	53				121	78	43				927		
18	Karoli	424	0	424	210	153	57	89	63	26	71	47	24				54	35	19				424		
19	Kota	379	0	379	191	137	54	79	56	23	62	42	20				47	32	15				379		
20	Nagour	791	0	791	390	284	106	166	117	49	134	89	45				101	66	35				791		
21	Pali	435	0	435	217	157	60	91	64	27	72	49	23				55	37	18				435		
22	Rajsamand	531	0	531	262	192	70	111	78	33	89	59	30				69	45	24				531		
23	Swaimad-hopur	342	0	342	171	124	47	71	50	21	57	38	19				43	29	14				342		
24	Sikar	563	0	563	279	202	77	118	83	35	94	63	31				72	47	25				563		
25	Ganganagar	353	0	353	177	127	50	74	52	22	58	40	18				44	30	14				353		
26	Tonk	554	0	554	278	199	79	116	82	34	91	62	29				69	47	22				554		
27	Banswara	848	30	878	407	298	109	0	0	0	0	0	0	51	30	21	0	0	0	420	288	132	878		
28	Baran	360	175	435	129	94	35	26	19	7	23	14	9	0	0	0	17	11	6	240	168	72	435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	Chittorgarh	621	175	796	307	224	83	103	73	30	85	56	29	6	5	1	65	42	23	230	164	69	796		
30	Dungarpur	793	3	796	383	279	104	0	0	0	0	0	0	46	28	18	0	0	0	367	252	115	796		
31	Sirohi	444	66	510	223	161	62	80	56	24	64	43	21	2	2	0	49	33	16	92	65	24	510		
32	Udaipur	514	441	955	245	186	59	46	33	13	47	26	21	13	10	3	38	20	18	566	397	169	955		
	TOTAO	**17870**	**890**	**18760**	**8844**	**6423**	**2421**	**3264**	**2299**	**965**	**2622**	**1749**	**873**	**118**	**75**	**43**	**1997**	**1316**	**681**	**1915**	**1331**	**584**	**18760**	**2233**	**536**

भीलवाड़ा जिले के क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत में व्याप्त अनियमितताएं

425. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बाढ़ के तहत भीलवाड़ा तहसील क्षेत्र व माण्डल तहसील क्षेत्र में क्षतिग्रस्त तालाबों पर मरम्म्त कार्य कराया गया? यदि हां, तो क्या इनमें अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा अलग-अलग अधिकारियों से जांच करवाई गई? यदि हां, तो इस जांच में किस-किस तालाब में अनियमितताएं पाई गई तथा इनमें कौन-कौन दोषी पाये गये?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति सुवाणा के कुम्हारिया खेडा तालाब के वर्ष 2004 में क्षतिग्रस्त नहीं होने पर भी स्वीकृति जारी कर फर्जी भुगतान किया गया? इसी तरह आटूण तालाब के एक ही कार्य का अलग-अलग माप पुस्तिका में इन्द्राज किया गया जिसके बारे में सहायक अभियंता ने एतराज उठाया? यदि हां, तो क्यों व दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। एक कार्य पर दो या अधिक माप पुस्तिकाएं काम में ली जा सकती हैं। इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं है तथा सहायक अभियंता द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया।

पंचपहाड़ी (कोटपूतली) बांध के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

426. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पंचपहाड़ी बांध का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो कब तथा किस योजना के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध पर लघु सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो सरकार अब कब तक उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कोटपूतली में पंचपहाड़ी बांध का आंशिक कार्य वर्ष 1987-88 में अकाल राहत मद के अन्तर्गत करवाया गया था।

(2) जी हां। बांध का निर्माण कार्य 6 प्रतिशत पूर्ण हुआ था।

(3) जी नहीं। उक्त योजना तकनीकी जांच प्रक्रिया में है, योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पाये जाने पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना सम्भव होगा।

ग्राम नौंवी (सुमेरपुर) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

427. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राज्य में नए पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम नौंवी की आवश्यकता व महत्ता को ध्यान में रखते हुए वहां कब तक पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

वर्तमान में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

जयपुर डेयरी में नियम विरूद्ध अनुकम्पात्मक नियुक्ति

428. श्री प्रकाश चौधरी (बड़ीसादड़ी) क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जयपुर डेयरी में वर्ष 2006-07 में कितने मृताश्रित व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई?

(2) क्या यह सही है कि इन अनुकम्पा नियुक्तियों में तीसरी संतान संबंधी नियमों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी में वर्ष 2006-07 में 3 मृताश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई।

(2) जी हां।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति रायपुर का वाहन चालक प्रकरण

429. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने सिरोही जिले की स्वरूपगंज समिति से दिनांक 23 मई, 1991 से एक पुराना वाहन खरीदा और उसके बाद श्री रघुवीर सिंह चारण नामक व्यक्ति को ड्राइवर के पद पर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह वाहन दिनांक 28 मई, 1997 से खराब हो जाने के कारण बंद है और सहकारी समिति द्वारा उसके इस वाहन को नीलाम करने की अनुमति उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली से मांगी थी, जो नहीं दी गई? यदि हां, तो गत साढ़े नौ वर्ष से इस नाकारा वाहन के नीलामी से जो रकम सहकारी समिति रायपुर को प्राप्त होती, उसके नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या इस हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार वसूली की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि संस्था का ड्राइवर दिनांक 28 मई, 1997 से दिनांक 3 जुलाई, 1999 तक बिना वाहन के कार्यरत रहा और दिनांक 30 जुलाई, 1999 को बिना किसी अनुमति के स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गया जो दिनांक 21 जून, 2005 तक कार्य पर नहीं आया?

(4) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति रायपुर की आम सभा ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा वाहन चालक का पद समाप्त करते हुए ड्राइवर की सेवायें समाप्त कर दीं और अगली आम सभा में इसकी पुष्टि कर दी गई? यदि हां, तो दोनों प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार, सहकारी, समितियां जयपुर द्वारा स्टॉफ स्ट्रेंथ आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 के द्वारा रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के आदेश को निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा

(श्री सी.डी. देवल)

दिनांक 4 अगस्त, 1995 को संस्था के इस ड्राइवर को निलम्बित कर दिया गया और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया? यदि हां, तो निलम्बन आदेश व जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1996 को पूर्व जांच अधिकारी को बदल कर श्री संजय अमरावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया? यदि हां, तो जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश की प्रति और जांच अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां पाली ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति रायपुर में कार्यरत मैनेजर रविन्द्रसिंह भाटी को हटाकर दिनांक 22 जून, 2005 को श्री संजय अमरावत को मैनेजर का कार्यभार दिला दिया? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह भी सही है कि श्री संजय अमरावत ने बिना किसी आदेश के रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 के प्रस्ताव संख्या 6 को अपखण्डित किये तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 की अवहेलना कर बिना पद व सेवा से पृथक किये गये ड्राइवर श्री रघुवीर सिंह को पुन: ड्यूटी पर ले लिया जो आज तक बिना वाहन के कार्यरत है? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मई 1991 में नया वाहन खरीदा था। यह सही है कि श्री रघुवीर सिंह चारण को ड्राइवर के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि दिनांक 28.05.1997 के पश्चात् वाहन काम में नहीं आया है। इस वाहन की नीलामी लम्बे समय से लम्बित रहने के प्रकरण के जांच के आदेश सहकारी विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2007 को दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तदनुसार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि सदंर्भित ड्राईवर 28.05.1997 से 30.04.1999 तक समिति में उपस्थित रहा तथा 01.05.1999 से 01.07.2005 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहा।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी हां। क्रय-विक्रय सहकारी समिति रायपुर की आम सभा दिनांक 20.10.2000 को प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा वाहन चालक का पद समाप्त करते हुए ड्राईवर की सेवायें समाप्त करने का निर्णय हुआ तथा अगली आम सभा दिनांक 13.12.2001 को इसकी पुष्टि प्रस्ताव संख्या-1 से होना अंकित है, किन्तु इसमें गत आम सभा की दिनांक 20.12.2000 अंकित की गई है। दोनों प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट दो व तीन पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। 21.12.2000 का ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है।

(6) जी हां। निलम्बन आदेश व जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश की प्रति परिशिष्ट चार पर संलग्न है।

(7) जी नहीं। सही यह है कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली द्वारा दिनांक 28.09.1996 को पूर्व जांच अधिकारी को बदलकर श्री संजय अमरावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जांच अधिकारी नियुक्ति आदेश एवं जांच अधिकारी दी गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट पांच व छः पर संलग्न है।

(8) जी नहीं। संदर्भित आदेश दिनांक 22.06.2005 को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा जारी किये गये थे, जिसकी प्रति परिशिष्ट सात पर संलग्न है।

(9) जी नहीं। किन्तु यह सही है कि समिति प्रशासक के निर्देशानुसार ड्राइवर श्री रघुवीर सिंह को दिनांक 01.07.2005 को पुनः ड्यूटी पर लिये जाने के आदेश जारी हुये तथा ड्राईवर अभी कार्यरत है। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम-2001 की धारा 55 के अन्तर्गत रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. की कराई गई जांच में कतिपय अधिकारीगण को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिसमें श्री संजय अमरावत का नाम भी शामिल है।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में आरक्षित वर्ग की रिक्तियां

430. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत है? यदि हां, तो क्या उक्त विश्वविद्यालय

(श्रीमती वन्दना मीणा)

में स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान कार्यरत पदों की संख्या आरक्षित पदों की कुल संख्या, आरक्षित पद पर कार्यरत की संख्या संवर्गवार, पदवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आरक्षित पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर राज्य सरकार द्वारा पारित मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 द्वारा स्थापित है। विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

(2) विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या, आरक्षित पदों की कुल संख्या एवं आरक्षित पदों पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या का संवर्गवार शैक्षणिक पदों का विवरण परिशिष्ट –1 पर एवं गैर शैक्षणिक पदों का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरते समय नियमानुसार आरक्षित पदों को भी भरा जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-431

(स्थगित)

फुलेरा के औषधालयों में रिक्त पद

432. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किस-किस श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में किस-किस प्रकार के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कुल 25 विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत व संचालित है इनकी सूची परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गयी है। यह सभी औषधालय 'बी' श्रेणी के हैं।

(2) इन औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के 25 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 26 पद तथा परिचालक के 24 पद स्वीकृत हैं। नर्स/कम्पाउण्डर व परिचालक के रिक्त पद नवीन नियुक्ति उपरान्त भरे जा सकेंगे। स्वीकृत पदों व रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य में 30 नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। आवश्यक होने पर इस क्षेत्र में औषधालय खोला जा सकेगा।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची मय स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण – स्थिति दिनांक 1-3-07

क्र. सं.	नाम औषधालय	स्वीकृत पद		
		आयु. चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचालक
1	2	3	4	5
1	किशनगढ़ रेनवाल	1	1	1
2	जोबनेर	1	3	1
3	ईटावा जूनश्या	1	पद स्वीकृत नहीं	1
4	करणसर	1	1	1
5	कालख	1	1	1
6	डूंगरी खुर्द	1	1	पद स्वीकृत नहीं
7	बधाल	1	2	1
8	बाधावास	1	1	1
9	बासडी खुर्द	1	1	1

10	भोजपुर कलां	1	1	1
11	भादवा	1	1	1
12	भैसावा	1	1	1
13	मण्डा भीमसिंह	1	2	1
14	रामजीपुराकला	1	1	1
15	लालासर	1	1	1
16	लूणियावास	1	1	1
17	सिनोदिया	1	1	1
18	खण्डेल	1	पद स्वीकृत नहीं	1
19	त्योदा	1	1	1
20	पचकोडिया	1	1	1
21	सुरमलिकपुर	1	1	1
22	खीरवा	1	1	1
23	भोजपुर खुर्द	1	पद स्वीकृत नहीं	1
24	हरसोली	1	1	1
25	जोरपुरा सुन्दरियावास	1	1	1

नोट:-

1. उक्त सभी औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर चिकित्सक पदस्थापित है।
2. औषधालय बासडी खुर्द, मण्डाभीमसिंह व त्योदा में नर्स/कम्पाउण्डर का पद रिक्त है।
3. औषधालय मण्डाभीमसिंह, लालासर, हरसोली व जोबनेर में परिचालक का पद रिक्त है।

जयपुर में अन्त:रोगी होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना

433. श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य में 50 शैय्याओं का हौम्योपैथिक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जयपुर में इस प्रकार के चिकित्सालय की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विभागान्तर्गत राज्य में 50 शैय्याओं का होम्योपैथिक चिकित्सालय वर्तमान में संचालित नहीं है। जयपुर शहर में 50 शैय्याओं का नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयुर्वेद चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों का दर्जा

434. श्री मदनमोहन सिंघल (कांमा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के समान कार्य होते हुए भी समान वेतन श्रृंखला नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में आयुर्वेद चिकित्सकों के करीब 700 वरिष्ठ/कनिष्ठ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हुये थे? यदि हां, तो उन पर आयुर्वेद चिकित्सकों को पदोन्नति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(3) क्या आयुर्वेद विभाग चिकित्सा पुनर्भरण की औषिध सूची मेडीकल की तरह नेगेटिव सूची (अर्थात् जो पुनर्भरण योग्य नहीं) बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के समान वेतनमान देने का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) राज्यादेश दिनांक 4.11.96 द्वारा 740 वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक के पद सृजित किये गये थे, किनतु इन पदों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.5.98 द्वारा समाप्त कर दिये जाने से इन पदों पर पदोन्नति नहीं दी गई है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) जी हां। राज्यादेश क्रमांक प. 25 (9) आयु./2000 दिनांक 24.2.07 द्वारा नई पुनर्भरण योग्य सूची तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त निर्णय लिया जावेगा।

(4) विभागीय आयुर्वेद चिकित्सकों के पद विशेषज्ञता के आधार पर सृजित नहीं हैं। कार्यरत चिकित्सकों में से कुछ चिकित्सक निम्न विषयों के स्नातकोत्तर उपाधिकारी है।

1. कार्य चिकित्सा	2. बाल रोग
3. प्रसूति व स्त्री रोग	4. शरीर रचना
5. स्वस्थ वृत	6. द्रव्यगुण
7. शरीर क्रिया	8. शल्य शालाक्य
9. रोग व विकृति विज्ञान	10. रस शास्त्र व भैष्य कल्पना

परन्तु आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के चिकित्सालय में विषय-विशेषज्ञता उपलब्ध है। एकल चिकित्सक व्यवस्था होने से औषधालयों में विषय विशेषज्ञता सम्भव नहीं है।

कृषि विपणन बोर्ड के संस्थापन व्यय में कमी हेतु कार्य-योजना

435. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कब करवाये गये व चुनाव बाद निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को क्या-क्या अधिकार प्रदान किए गये?

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के संस्थापन खर्चे का बोझ मण्डियों को वहन करना पड़ता है? यदि हां, तो प्रदेश की विभिन्न मंडियों से बोर्ड को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है? वर्ष 2006-07 में प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि उपज मण्डियों पर कृषि विपणन बोर्ड का खर्च कम करने की सरकार की क्या कार्य-योजना है?

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव 15 मई, 2006 को करवाये गये। मण्डी समितियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य राजस्थान कृषि उपज

(कृषि विपणन मंत्री)

मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 9 के अनुसार एवं कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 33 के अनुसार है। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड के संस्थापन खर्चों का भार मण्डी विकास निधी पर है। प्रदेश की मण्डी समितियों से उनकी श्रेणी के अनुसार राजस्थान कृषि विपणी अधिनियम 1961 के नियम 18ए के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड अंशदान विपणन बोर्ड को प्राप्त होता है। जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	मण्डी की श्रेणी	बोर्ड अंशदान की दर
1.	विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समिति	30 प्रतिशत
2.	'अ' श्रेणी की मण्डी समिति	20 प्रतिशत
3.	'ब' श्रेणी की मण्डी समिति	10 प्रतिशत

वर्ष 2006-07 में माह फरवरी 2007 तक 3040.39 लाख रुपये बोर्ड अंशदान के प्राप्त हुए।

(3) कृषि विपणन बोर्ड को प्राप्त होने वाला अंशदान विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप है जिसे कम करने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 9

1. मण्डी समिति की शक्तियां और कर्तव्य – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मण्डी समिति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा-

(i) मण्डी क्षेत्र में, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों का उप-विधियों को कार्यान्वित करना;

(ii) उसमें कृषि उपज के विपणन के लिए ऐसी सुविधाएं उपबंधित करना जिनका निदेशक या राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे;

(iii) ऐसे अन्य कार्य करना जो, मण्डी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के सम्बन्ध में या मण्डी क्षेत्र में किसी भी स्थान में कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के लिए और उपर्युक्त मामलों से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, और उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर

सकेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबंधित किये जायें; और

(iv) ऐसी अन्य बातें करना जो इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उद्देश्यों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और मण्डी समिति के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित हो सकते हों।

(2) पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डी समिति-

(i) मण्डी क्षेत्र के भीतर प्रधान यार्ड और उप-मण्डी यार्डो का अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगी;

(ii) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी यार्ड के भीतर और प्रधान मण्डी यार्ड के बाहर और उप-मण्डी यार्डों के भीतर और उप-मण्डी यार्डों के बाहर कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपबंध कर सकेगी;

(iii) मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और अन्य व्यक्तियों को काम करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगी या जारी करने से इन्कार कर सकेगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द कर सकेगी, मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडागारपालों और अन्य व्यक्तियों के आचरण का पर्यवेक्षण कर सकेगी और अनुज्ञप्ति की शर्तों को प्रवर्तित कर सकेगी;

(iv) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या मण्डी समितियों की उप-विधियों के अधीन अधिकथित उपबन्ध और प्रक्रिया के अनुसार कृषि उपज के नीलाम का विनियमन और पर्यवेक्षण कर सकेगी;

(v) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या मण्डी समितियों की उप-विधियों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कृषि उपज नीलाम का संचालन और पर्यवेक्षण कर सकेगी;

(vi) विक्रय, तौल, परिदान, संदाय के करार की रचना निष्पादन और प्रवर्तन या रद्दकरण और कृषि उपज मण्डी से संबंधित अन्य मामलों का विहित रीति से विनियमन कर सकेगी;

(vii) विक्रेता और क्रेता के बीच कृषि उपज के विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार के संव्यवहार से उदभूत होने वाले समस्त विवादों और उनसे आनुषंगिक सभी विषयों के निपटारे के लिए उपबन्ध कर सकेगी;

(viii) कृषि उपज में अपमिश्रण रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठा सकेगी;

(ix) कृषि उपज के श्रेणीकरण और मानकीकरण के लिए उपबन्ध कर सकेगी;

(x) मण्डी यार्ड में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल की तुलाई और परिवहन के लिए तुलाईकारों और हम्मालों को चक्रानुक्रम से नियोजित करने के लिए इन्तजाम कर सकेगी;

(xi) अपने क्षेत्र में विस्तारी क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के संबंध में जानकारी का संग्रहण, रख-रखाव और प्रसार को कार्यान्वित करने के लिए कृषि विपणन इकाई की स्थापना में लोक भागीदारी स्थापित और प्रोन्नत कर सकेगी;

(xii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-नियत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे क्रय और विक्रय रोकने के लिए अध्युपाय कर सकेगी;

(xiii) ऐसी रेटें, प्रभार, फीस और अन्य धनराशियां उदगृहीत, वसूल और प्राप्त कर सकेगी जिनके लिए मण्डी समिति हकदार है;

(xiv) इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारी और सेवक नियोजित कर सकेगी,;

(xv) मण्डी समिति में निहित प्रधान मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्डों में व्यक्तियों और यानों, यातायात के प्रवेश का विनियमन कर सकेगी;

(xvi) इस अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिए व्यक्तियों को अभियोजित कर सकेगी और ऐसे अपराधों का शमन कर सकेगी,

(xvii) अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन के प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भी जंगम या स्थावर सम्पति का आबंटन/व्ययन कर सकेगी;

(xviii) कोई भी वाद, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् संस्थित कर सकेगी

या उसका प्रतिवाद कर सकेगी और ऐसे वाद, कार्यवाही आवेदन या माध्यमस्थम् में समझौता कर सकेगी;

(xix) मण्डी समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों के छुट्टी भत्ते, पेंशन या भविष्य निधि के पेटे वेतन, भत्तों, उपदानों, अंशदान का विहित रीति से संदाय कर सकेगी;

(xx) मण्डी समिति निधि का प्रशासन और उसके लेखाओं का संधारण विहित रीति से कर सकेगी;

(xxi) प्रत्येक प्रधान मण्डी यार्ड और उपमण्डी यार्ड में मानक बाटों और मापकों का एक ऐसा सेट रख सकेगी जिससे तौल और मापों की जांच की जा सके;

(xxii) मण्डी क्षेत्र में उपयोग में आने वाले पैमानों, बाटों और मापकों तथा मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों, दलालों, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भांडारपालों और अन्य व्यक्तियों द्वारा संधारित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का भी ऐसी रीति से निरीक्षण और सत्यापन कर सकेगी जो विहित की जाये;

(xxiii) विनियमन, संव्यवहार पद्धति, मण्डी क्षेत्र में उपबंधित सुविधाओं इत्यादि के फायदों के बारे में, पोस्टरों, पुस्तिकाओं, विज्ञापन पट्टों, सिनेमा स्लाइडों, फिल्म प्रदर्शनी, समूह बैठकों इत्यादि, जैसे साधनों के माध्यम से या अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे गये किन्हीं या अन्य साधनों के माध्यम से प्रचार कर सकेगी;

(xxiv) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, जो मण्डी यार्ड या मण्डी क्षेत्र में किये गये हैं, संदाय विक्रेता को उसी दिन किया जाना और व्यतिक्रम में प्रश्नगत कृषि उपज साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति की अन्य सम्पति का अभिग्रहण और उसके पुन: विक्रय की व्यवस्था और हानि की दशा में, हानियों के प्रभारों, यदि कोई हो, की वसूली के प्रभारों सहित उसकी मूल क्रेता से वसूली करना और कृषि उपज की कीमत का विक्रेता को संदाय करना सुनिश्चित कर सकेगी;

(xxv) तुलाईकारों और हम्मालों के संबंध में प्रभारों की वसूली, और उनका तुलाईकारों और हम्मालों को वितरण कर सकेगी यदि क्रेता या यथास्थिति, विक्रेता द्वारा उनका संदाय नहीं किया जाता है;

(xxvi) मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले उत्पादकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के फायदों के लिए कृषि उपज के मण्डी में संचलन को सुकर बनाने

के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, मण्डी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का जिम्मा ले सकेगी;

(xxvii) कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के संबंध में जानकारी संगृहित और संधारित कर सकेगी और ऐसी जानकारी का प्रसार कर सकेगी, जैसा निदेशक द्वारा निदिष्ट किया जाये; और

(xxviii) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दष्टि से-

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारी उनकी क्षमता से अधिक कृषि उपज का क्रय नहीं करें और उपज के व्ययन में विक्रेताओं को जोखिम से बचाने के लिए यथोचित अध्युपाय कर सकेगी, और

(ख) क्रेताओं की क्षमता के अनुसार आवश्यक नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति प्राप्त करने के पश्चात ही अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी।

(3) निदेशक की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति अपने विवेक से कृषि उपज के परिवहन और भण्डारण को सुकर बनाने के लिए या मण्डी यार्ड के विकास के प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में सड़कों या गोदामों के निर्माण के लिए बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या किसी भी अन्य विभाग या लोक उपक्रम या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी को अनुदान या अग्रिम निधियां प्रदान करने का जिम्मा ले सकेगी।

(4) ऊपर उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डी समिति निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगी :-

(क) अपने अधिकारियों द्वारा समस्त प्राप्तियों और संदायों पर समुचित नियंत्रण रखना,

(ख) मण्डी समिति निधि से प्रभार्य समस्त संकर्मों का समुचित निष्पादन; और

(ग) इस अधिनियम की और तदधीन जारी किये गये नियमों और अधिसूचनाओं की ओर अपनी उप-विधियों की प्रति अपने कार्यालय में नि:शुल्क निरीक्षण के लिए रखना।

परिशिष्ट ब

राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 का नियम 33

अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां–अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष-

(1) मंडी समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन करेगा,

(2) वित्तीय कार्यकारिणी प्रशासन के ऊपर निगरानी रखेगा,

(3) अत्यावश्यक मामलों में जिसमें मण्डी समिति की स्वीकृति की अपेक्षा हो किसी कार्य को रुकवाने का या करवाने का निर्देशन दे सकेंगा।

(4) सरकार या निदेशक से समस्त पत्राचार के लिये उत्तरदायी होगा,

(5) वह सैक्रेटरी की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी होगा।

अन्य प्रकार के अवकाश के लिये सैक्रेटरी अध्यक्ष के माध्यम से निदेशक को आवेदन करेगा जो सरकारी कर्मचारी पर लागू अवकाश नियमों के अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही करेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्नोत्तर की सूची

सीकर जिले में वर्तमान में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र संचालित है जिसमें निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

क्र.सं.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय	कार्यरत वर्ष
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीकर	1 फिटर 2 टर्नर 3 इलैक्ट्रीशियन 4 वायरमैन 5 ड्राफ्टसमैन सिविल 6वैल्डर (गैस एवं इलैक्ट्रीक)	1965
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर	1 मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 वैल्डर (गैस एवं इलैक्ट्रीक) 3 ड्रेसमैकिंग	1996
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खुड	1 फिटर 2 इलैक्ट्रोनिक्स 3 इलैक्ट्रोक्सि 4 वैल्डर (गैस एवं इलैक्ट्रीक)	2006
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र			
क्र.सं.	**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम**	**व्यवसाय**	**कार्यरत वर्ष**
1	हजरत उमर बिन खताब औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर	1 इलैक्ट्रीशियन 2 मैकेनिक डीजल 3 फिटर	2005
2	अरावली औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नीम का थाना, जिला-सीकर	1 इलैक्ट्रोनिक्स मैकेनिक 2 फिटर	2005

हस्ताक्षर
निदेशक (प्रशिक्षण)

<u>परिशिष्ट-2</u>

तारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

परिशिष्ट अ

जिले का नाम : जयपुर

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में क्षतिग्रस्त/किनारे टूटे हुए सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई	क्षतिग्रस्त सड़क		क्षतिग्रस्त भाग	क्षतिग्रस्त किनारे	कब से
			कहां से	कहां तक			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सम्पर्क सड़क कारोली (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 1/600	1.600	0/170	0/190	0.020	-	6 माह
2	सम्पर्क सड़क भूरी भड़ाज (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 4/500	4.5	2/250	3/700	0.200	-	5 वर्ष
3	सम्पर्क सड़क मोलाहेड़ा (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 1/0	1.00	0/0	0/100	-	0.100	6 माह
4	सम्पर्क सड़क बालावास (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 2/0	2.00	0/0	0/100	0.100	-	5 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
5	चिमनपुरा से बनेठी (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 5/0	5.00	2/500	2/550	0.050	-	2 माह
			4/900	5/000	0.100	-	
6	नांगल पण्डितपुरा से राजनौता (नांगडीवास) (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 4/0	4.00	3/000	3/050	0.050	-	6 माह
			3/500	3/570	0.070	-	
7	पावटा-नारेड़ा सड़क (ओ.डी.आर-16) 0/0 से 25/0	25.00					
			0/55	0/65	-	0.010	2 माह
			1/100	1/110	-	0.010	2 माह
			5/200	5/400	0.200	-	5 वर्ष
			6/100	6/300	0.200	-	5 वर्ष
			7/400	7/700	0.300	-	5 वर्ष
			20/520	20/600	0.080	-	5 वर्ष
			24/090	24/200	0.110	-	5 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
8	गोरधनपुरा (एन.एच.-8) से चौलाई वाया कांसली (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 8/0	8.00					
			3/350	3/400	0.050	-	5 वर्ष
			4/850	5/00	0.150	-	5 वर्ष
9	प्रागपुरा-पाछुडाला सड़क (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 15/0	15.00	1/150	1/200	0.050	-	6 वर्ष
			5/050	5/150	0.100	-	6 वर्ष
			5/360	5/370	-	0.010	2 माह
			7/100	7/200	0.100	-	6 वर्ष
			8/080	8/090	-	0.010	2 माह
10	सम्पर्क सड़क भैसलाना (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 4/0	4.00	3/500	3/700	0.200	-	5 वर्ष
11	चोटिया से हरियाणा बॉर्डर वाया बनेठी (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 14/800	14.800	14/0	14/800	0.800	-	5 वर्ष
12	नारेड़ा से हरियाणा बॉर्डर सड़क (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 12/0	12.00	0/700	1/120	0.420	-	5 वर्ष
13	एन.एच.-8 राजनोता कराना (ग्रामीण सड़क) 0/0 से 10/0	10.00	1/180	1/190	-	0.010	3 माह
			2/570	**2/585**	-	**0.015**	**2 माह**

परिशिष्ट 'ब'

सार्व. निर्माण विभाग द्वारा नवीनीकरण की गयी सड़कों की सूची जिस पर सोलडर बांधे गये

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	विवरण
1	2	3	4
अ	**नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य**		
	वर्ष 2002-03 (आर.यू.पी.-I)		
1.	सीकर कोटपूतली बानसूर सड़क एम.डी.आर.-25 कि.मी. 114/500 से 115/500, 117/0 से 117/500 व 123/0 से 124/500	2.90	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
2.	सम्पर्क सड़क सुधरपुरा ढाडा कि.मी. 3/0 से 6/0	3.00	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
3.	सम्पर्क नांगल पण्डितपुरा से राजनोता कि.मी. 0/0 से 3/0	3.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
4.	एन.एच.-8 से हरियाणा बोर्डर कि.मी. 0/0 से 5/0	5.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी

परिशिष्ट 'ब'

सार्व. निर्माण विभाग द्वारा नवीनीकरण की गयी सड़कों की सूची जिस पर सोल्डर बांधे गये

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	विवरण
1	2	3	4
अ	**नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य**		
	2004-05 (आर.एम.यू.पी-I)		
1	एन.एच. 8 से पूतली सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0	1.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
2	एन.एच.-8 से कांसली वाया सुन्दरपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	5.000	मूरम की पटरी
3	एन.एच.-8 से कल्याणपुरा खुर्द सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0	0.900	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
4	द्वारिकापुरा से दांतिल सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	3.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
5	दांतिल से तालवा सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	2.900	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
	2005-06 (आर.एम.यू.पी.-II		
6	नारंडा से हरियाणा बॉर्डर कि.मी. 0/0 से 11/400	11.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
7	सम्पर्क सड़क राकरणपुरा कि.मी. 0/0 से 0/930	0.930	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
8	कोटपूतली से चिमनपुरा वाया गोपालपुरा कि.मी. 0/0 से 8/600	8.600	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
	2006-07 (मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना)		
9	कोटपूतली-बानसूर सड़क का सुधार कार्य (सी.सी. सड़क) 0/247 से 2/00	1.753	ग्रेवल की पटरी बनाई गई

परिशिष्ट 'ब'

राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की रखरखाव की सूची में से नवीनीकरण की गयी सड़कों की सूची जिस पर सोल्डर बांधे गये

क्र.सं.	**सड़क का नाम**	**लम्बाई (कि.मी.)**	**विवरण**
अ	**नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य**		
	2002-03 (आर.यू.पी.I)		
1.	एच.एच.-8 से राजनौता कराना कि.मी. 5/00 से 10/00	5.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
2.	प्रागपुरा से पाछुडाला कि.मी. 10/00 से 15/00	5.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
3.	चौटिया से हरियाणा बॉर्डर कि.मी. 0/00 से 14/00	14.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
4.	सम्पर्क सड़क भैंसलाना कि.मी. 0/00 से 4/00	4.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
5.	सम्पर्क सड़क पावटा से भोनावास कि.मी. 0/00 से 4/00	3.500	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
6.	सम्पर्क सड़क विराटनगर से पावटा कि.मी. 17/0 से 21/0	4.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
	2003-04 (आर.यू.पी.II)		
7.	एन.एच.-8 से राजनौता कराना कि.मी. 0/00 से 5/00	5.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
8.	सम्पर्क सड़क प्रागपुरा से पांछुडाला कि.मी. 0/00 से 10/00	9.430	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
9.	सम्पर्क सड़क चौकी गोवर्धनपुरा से चौलाई वाया कांसली कि.मी. 0/00 से 8/00	8.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
10.	सम्पर्क सड़क पावटा से नारेड़ा कि.मी. 0/00 से 25/00	23.700	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
11.	सम्पर्क सड़क सुंदरपुरा ढाढा सड़क कि.मी. 0/00 से 3/00	3.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
12.	विराटनगर से पावटा कि.मी. 21/00 से 24/00	3.000	मिट्टी की पटरी बनाई गयी
13.	कोटपूतली-बानसूर सड़क कि.मी. 2/00 से 6/400	4.400	मिट्टी की पटरी बनाई गयी

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न संख्या- 215 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र ब्यावर में रिक्त भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	रिक्त भूखण्डों की संख्या एवं माप
1	औद्योगिक क्षेत्र ब्यावर द्वितीय चरण	एक भूखण्ड 4000 वर्ग मीटर
2	औद्योगिक क्षेत्र ब्यावर तृतीय चरण	तीन भूखण्ड 2000 वर्ग मीटर
		तीन भूखण्ड 1500 वर्ग मीटर

परिशिष्ट-4

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुये माने गये

जोधपुर नगर निगम का कार्य क्षेत्र व आय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

माननीया जी,

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर नगर निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ाने एवं इसकी आय बढ़ाने हेतु प्रयास की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

अपने संसाधन सीमिति होने से नगर निगम आज भी शहरवासियों की सेवा करने में असमर्थ है। वहीं जोधपुर में निवास कर रहे विभिन्न कालोनियों के निवासी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम का यही जवाब होता है कि उनका क्षेत्र निगम की सीमा में नहीं है अत: निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन कालोनियों के निवासियों को मूलभूत सुविधा जैसे : सीवर लाइन, रोड लाइट, सड़कें व राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में यहां के रहवासियों को रसोई गैस भी उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके अलावा पानी-बिजली की समस्या है वह अलग ही है।

जोधपुर में 28 फरवरी, 1962 को नगर परिषद की स्थापना के समय नगर परिषद की सीमा में 16 राजस्व ग्राम थे। 45 वर्षों के बाद भी वही सीमा है। जब कि जोधपुर के सन 1977 के मास्टर प्लान में नगरीय सीमा में 33 राजस्व ग्राम प्रस्तावित थे और सन 2003 के मास्टर प्लान में 71 राजस्व ग्राम प्रस्तावित थे। नगर निगम ने भी 31.01.1995 को अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर निगम की सीमा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा जिसे जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने 22.10.1997 के पत्र द्वारा निगम की सीमा 50 राजस्व ग्राम तक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। परन्तु उस पर भी आज तक कार्यवाही लम्बित है।

मेरा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि इन प्रस्तावों पर तुरन्त कार्यवाही कर नगर निगम की सीमा बढ़ाई जाय जिससे कि शहर की विभिन्न कालोनियों में रह रहे निवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके और नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
(सूरसागर, जोधपुर)

तहसील फागी में बिजली की 132 के.वी. ग्रेड स्थापित करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील फागी जिला जयपुर में कई वर्षों से बिजली की गम्भीर समस्या से ग्रस्त है। यहां पर 40-50 कि.मी. लम्बी बिजली की लाइन झूल रही है जिसके कारण जब तेज हवाए चलती हैं, तो बिजली के तार आपस में भिड़ जातें है। जिसके कारण तारों में फाल्ट हो जाता है। फाल्ट होने पर करीब 2-3 दिनों तक बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है। बिजली की लम्बी लाइन होने के कारण एक जगह भी फाल्ट हो जाने पर सम्पूर्ण तहसील की बिजली बंद करनी पड़ती है। पूरा पावर सप्लाई नहीं होने के कारण ग्रामीण किसानों की मोटरें प्राय: जल जाती हैं। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता, किसानों व व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है, कि तहसील फागी में बिजली के गम्भीर समस्त को देखतें हुए बिजली की 132 के.वी. ग्रेड अतिशीघ्र स्थापित करवाने की कृपा करें, ताकि ग्रामीण जनता, किसानों व व्यापारियों की बिजली की समस्या का समाधान हो सके।

लक्ष्मीनारायण बैरवा

(फागी)

आपणी योजना में बड़े गांवों को घर-घर पानी कनेक्शन देकर लाभान्वित करने हेतु

महोदय,

जल प्रदाय योजनाओं के प्रबन्धन में आपणी योजना प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। इस योजनान्तर्गत जिला चूरू तथा जिला हनुमानगढ़ के 335 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना से पानी की फिजूलखर्ची व बरबादी पर काफी नियंत्रण हुआ है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं तथा ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है।

आपणी योजनान्तर्गत निर्धारित नियमों व माप-दण्डों के आधार पर प्रारम्भ से ही कुछ कस्बों तथा बड़े गांवों को घर-घर पानी कनेक्शन देकर

लाभान्वित किया गया था। अब आवश्यकता यह है कि जिन गांवों की जनसंख्या एक निश्चित निर्धारित माप-दण्ड से अधिक हो गई है, को भी घर-घर कनेक्शन देकर लाभान्वित किया जावे। ऐसा न करने से अनेक बार अनेक गांवों में अवैधानिक तरीके से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी कनेक्शन लेकर व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के गैर-कानूनी कनेक्शन से पानी की भी फिजूलखर्ची होती है।

जिन गांवों में घर-घर पानी का कनेक्शन नहीं है, वहां आमतौर पर घर की महिलाओं द्वारा घर से कुछ दूर स्थित पीएसपी अथवा अन्य संसाधनों से पानी भरकर लाना पड़ता है। वर्तमान में अधिकतर शिक्षित नवविवाहित गृहणियों को इस तरह पानी लाने में संकोच व परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आपणी योजनान्तर्गत जुड़े हुए तहसील तारानगर के बड़े गांवों जैसे कि बुचावास, कोहिणा, राजपुरा, सात्युं, पुनसीसर, भालेरी, धीरवास, कालवास बाय तथा ढाणी कुम्हारान में घर-घर पानी का कनेक्शन देकर ग्रामवासियों को लाभान्वित किया जावे।

डा. चन्द्रशेखर बैद
(तारानगर)

सूरतगढ़ तहसील के गांव संगोता एवं 5 एसडी में आई सेम से निजात दिलवाने हेतु

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ को ग्राम पंचायत पदमपुरा के गांव संगोता एवं 5 एसडी पिछले काफी समय से सेम समस्या से ग्रस्त है इस संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा समय-समय पर लिखित में या मौखिक रूप से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया गया सिंचाई विभाग द्वारा इस संबंध में एक पत्र भी मुझे लिखा कि उपरोक्त कार्य सन 2006-07 में पूर्ण कर दिया जायेगा लेकिन आज रोज तक उपरोक्त कार्य पूरा होना तो दूर की बात इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी पिछले दिनों हुई बरसात से इन गांवों में सरकारी सम्पत्ति जैसे विद्यालय, औषधालय अन्य सरकारी क्वाटर्स के साथ-साथ निजी सम्पति को भारी नुकसान हुआ है और गांव वालों ने इस पर धरना भी दिया जो मेरे लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने वापिस लिया।

अध्यक्ष महोदय सेम समस्या से काश्तकारों व गांव वालों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है भूमि जो कृषि योग्य नहीं रही है अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो इससे कृषि भूमि आवासीय मकान सरकारी सम्पत्ति को सेम निगलती रही है जहां सेम का प्रकोप बढ़ रहा है वहीं इन्दिरा गांधी नहर अनूपगढ़ शाखा को भी खतरा हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु शीघ्र बजट जो कि करीब 30 लाख रुपया होगा आबंटित कर समस्या का निराकरण कर पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करें।

अशोक नागपाल

(सूरतगढ़)

10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के सैशनल मार्क्स देने की व्यवस्था को समाप्त करने बाबत

महोदय,

मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विगत लगभग 8 वर्षों से अधिक समय से 10वीं एवं 12वीं को बोर्ड परीक्षाओं में सैशनल मार्क्स (को जो प्रथा विद्यार्थियों के हित में जारी है जिसके तहत 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड को विद्यार्थियों को 10 नम्बर विद्यालय से ही बोर्ड को भेजे जाते हैं जिसका अध्यापकों द्वारा सरेआम ट्यूशनखोरों के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है इन 10 नम्बरों में से अधिक से अधिक नम्बर सैशनल मार्क्स बोर्ड में भेजने के बदले अध्यापक, विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिये अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है। जिससे विवश होकर विद्यार्थियों को ट्यूशन जाने पर विवश होना पड़ता है कुछ प्रमुख विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि के अध्यापकों ने सरेआम ट्यूशन खोरो मचा रखी है जिसका खामियाजा निर्धन विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है। इन 10 नम्बरों का खेल ट्यूशन खोरों अध्यापकों के लिये ट्यूशन उद्योग के रूप में खूब फल फूल रहा है।

कभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माने जाने वाला राजस्थान राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नये कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है जिससे हम सब भलि भांति परिचित हैं किन्तु दूसरी ओर सैशनल मार्क्स जैसी प्रथा जिसे

विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखकर लागू किया गया था जो आज शिक्षा विभाग के नाम कलंक तथा ट्यूशन खोर अध्यापकों के नोट कमाने का जरिया साबित हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि 10वीं एवं बारहवीं बोर्ड के विद्यार्थियों को 10 नम्बर विद्यालय में भेजने की प्रथा को समाप्त किया जावे इससे गरीब छात्रों को काफी फायदा होगा।

सादर प्रेषित है।

स्नेहलता

(डग)

निवाई नगरपालिका द्वारा प्लाट आबंटित कराने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका निवाई द्वारा वर्ष 1996-97 में भूखंड आबंटन हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी। इस बाबत निवाई के निवासियों ने भूखंड आबंटन कराने हेतु आवेदन भी किया गया था। साथ ही नियमानुसार निर्धारित राशि भी जमा करा दी गई थी। परन्तु दस वर्ष गुजर जाने के बाद भी भूखंड आबंटन नहीं किये। जिससे गरीब एवं अनु. जाति एवं मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को काफी परेशानी हो रही है। जिससे आवासीय समस्याऐं भी उत्पन्न हो रही हैं। नगरपालिका द्वारा आज तक भी प्रभावी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि उनको राशि जमा कराये दस वर्ष हो चुके हैं। नगरपालिका प्रशासन से संपर्क करने पर आबंटियों को संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है।

अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 67 आबंटियों को तुरन्त कार्यवाही कराकर भूखंड आबंटन कराकर अनु. जाति/गरीब एवं पिछड़े वर्गों के आबंटियों को राहत प्रदान करावें।

हीरा लाल

(निवाई)

बृजेन्द्र मिनरल्स के खिलाफ रायल्टी चोरी की डिमाण्ड समाप्त करने विषयक

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि खान विभाग के निदेशक श्री जी.

एल. व्यास द्वारा नियम विरूद्ध मैसर्स बृजेन्द्र मिनलर्स के खिलाफ कायम की गई रायल्टी चोरी की डिमाण्ड को खतम कर नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही कार्यवाही की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि अतिरिक्त निदेशक खान विभाग के दिशा-निर्देश पर दिनांक 8.4.2005 को खनिज अभियन्ता (सतर्कता) द्वारा मैसर्स बृजेन्द्र मिनरल, ग्राम कानोता तह-दौसा जिला-दौसा में आकस्मिक निरीक्षक में उत्पादनता निरीक्षण में अन्तर वजन 140237 टन को रायल्टी रुपये 2804740/- को मांग विभाग द्वारा मैसर्स बृजेन्द्र मिनलर्स के खिलाफ कायम की गई बार-बार अवसर देने के बावजूद भी डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराई गई तथा विभाग द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा उपरोक्त फर्म का निरस्त करने की कार्यवाही को खान निदेशक उपरोक्त पट्टाधारी फर्म से मिलकर पुन: एक समिति द्वारा जांच करने हेतु अधिकारियों की कमेटी काम उन उनके पत्र क्रमांक निदे/सतर्क ता/जय/पा-21/2005/दिनांक 15.3.2007 द्वारा किये गये हैं जो सरकार नियम विरूद्ध है तथा फर्म को लाभ देने की नियम से जारी किये है तथा इस समिति का अध्यक्ष श्री एस.के. स्वामी, अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) को बनाया गया है जो दिनांक 31 मार्च, 2007 को सेवानिवृत हो रहा है तथा श्री स्वामी के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत जांच चल रही है। तथा इसी फर्म को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाने की गरज से बिना खनिज अभियन्ता, जयपुर को टिप्पणी प्राप्त किये श्री स्वामी द्वारा उपरोक्त फर्म को माईनिंग स्कीम को अनुमोदित किया था। शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जांच) विभाग ने श्री बृजेन्द्र मिनलर्स के पक्ष में की गई नियम विरूद्ध कार्यवाही को गंभीर दुराचरण, घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता माना है। इसी श्री स्वामी को उपरोक्त फर्म मैसर्स बृजेन्द्र मिनरर्स के विरूद्ध अवैध खनन/निर्गमन के संबंध में प्राप्त संलग्न शिकायतों की जांच एवं अधिशुल्क निर्धारण के संबंध में विस्तृत जांच हेतु अधिकारियों को कमेटी का अध्यक्ष सरासर नियम विरूद्ध तथा सरकार को 28 लाख रुपये की रायल्टी से मुक्त कराने की खान निदेशक श्री व्यास की साजिश रचकर उपरोक्त फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है।

अत: मैं माननीय खान मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

राम किशोर मीणा

(सिकराय)

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमिपर बसी कालोनियों का नियमन करने के संदर्भ में

महोदय,

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में 15-20 कालोनियां कृषि भूमि पर बसे 30-35 वर्ष हो चुके हैं तथा जिन गृह निर्माण समितियों ने इन कालोनियों को बसाने का कार्य किया था उन सोसाईटियों का भी अता-पता नहीं है अत: इन कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों को आये दिन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है इन कालोनियों के नगरपालिका के सीमित संसाधन होने के कारण विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इन कालोनियों में पीने के पानी सड़क बिजली आदि का अभाव है।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि नगरपालिका चौमूं की कृषि भूमि पर स्थित इन्दिरा कालोनी, कृष्णा कालोनी मगध विहार आदित्य नगर, राधाबाग, श्रीराम नगर जोगी कालोनी श्याम बिहार, नरवानिया कालोनी श्री कृष्णा कालोनी अशोक बिहार आदि कालोनियों का सर्वे करवाकर इनका नियमन करवाने के लिए सरकार का निर्देशित करने का श्रम करें ताकि लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

सम्पूर्ण बानमवास विधान सभा क्षेत्र को पेयजल संकट के संबंध में

महोदय,

जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास व बौंली के करीब 300 ग्रामों की वर्तमान में पेयजल संकट से त्रस्त हैं, क्योंकि बामनवास तहसील के करीब 50-60 गांव जो पेयजल का काम तालाब के पानी से चलाते थे इस वर्ष तालाब नहीं भरने से पूरा वर्ष पानी की समस्या से जूझ रहे हैं जिन गांवों में हैंड पम्प, कुओं से पेयजल आपूर्ति होती थी जल स्तर गिर जाने से कुएं एवं हैंडपम्प भी सूख गये हैं और हैंडपम्प सूखने के कगार पर हैं। केवल मात्र पानी की समस्या गांवों में से जनता को बाहर पलायन करने पर मजबूर कर रही है मवेशियों को जिन्दा रखना तो दूर की बात जन जीवन को पानी मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात में दोनों तहसील के करीब 250-300 ग्रामों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु विशेष कार्य योजना की अति आवश्यकता

है। मार्च निकलने के बाद यह स्थिति बहुत ज्यादा भयावह बनने वाली है पानी संकट जन जीवन के लिए मृत्युदायी भी बन सकती है।

ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए सरकार को विशेष कार्य योजना की अति आवश्यकता है। क्या सरकार इस समस्या के प्रति संवेदनशील रहकर तत्काल कोई योजना बना रही है। और कस्बा बौंली के लिए जो चरणक्याटय से पेयजल योजना को कब तक स्वीकृत कर कस्बा बौंली को पानी की सप्लाई होगी और कस्बा बामनवास में पेयजल हेतु देहरी योजना से कब तक पानी की सप्लाई शुरू हो जायेगी। कृपया पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

हीरालाल मीणा
(बामनवास)

कोटपूतली को जिला बनाने के संबंध में विशेष उल्लेख

मान्यवर,

कोटपूतली को जिला बनाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। कोटपूतली एवं आस-पास की तहसीलों बानसूर, बहरोड़, नीम का थाना, शाहपुरा व विराटनगर के लोगों को अपने कार्य जिला मुख्यालय पर 135 से 140 कि.मी. तक की दूरी तय कर जिला प्रशासन से करवाने पड़ते हैं जो अत्यन्त कष्टकारक तथा धन को अपव्यय करने वाला है।

भौगोलिक दृष्टि से भी कोटपूतली जिला बनाने योग्य है जिसके लिए कोटपूतली एवं आस-पास की तहसीलों की जनता द्वारा समय-समय पर जिला निर्माण की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाकर राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। वर्तमान में भी गत 200 दिनों से लगातार क्षेत्र की जनता द्वारा कोटपूतली के आजाद चौक पर कोटपूतली को जिला बनाये जाने के लिए धरना दिया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विधान सभा में बजट पेश करने के दो दिवस पूर्व मेरे साथ कोटपूतली का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें सर्वदलीय जिला निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष वैद्य बालाबक्श शास्त्री, पूर्व विधायक डा. आर.एस. गौड, पूर्व विधायक रामचन्द्र रावत, पूर्व विधायक रामकरण सिंह गुर्जर तथा भाजपा नेता श्री योगेन्द्र सिंह तंवर सम्मिलित थे, ने माननीय मुख्यमंत्री महोदया से विधान सभा परिसर में मिलकर कोटपूतली को जिला

बनाये जाने की मांग की थी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने परिसीमन आयोग का हवाला देते हुए वर्तमान में नये जिला गठित किये जाने में असमर्थता जाहिर की थी लेकिन इसके बावजूद भी प्रतापगढ़ को जिला घोषित कर कोटपूतली की अनदेखी की है तथा कोटपूतली व कोटपूतली के साथ लगती हुई सभी तहसीलों के निवासियों को निराश किया है।

प्रशासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के जिला मुख्यालयों की दूरी अत्यावश्यक रूप से कम होनी चाहिये। 50 से 60 कि.मी. के मध्य जिला मुख्यालय की दूरी होने से आम आदमी का जिला कलक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से सीधा सम्पर्क हो सकता है जिससे आम आदमी को प्रशासनिक जरूरतों का लाभ प्राप्त हो सकेगा, और शासन के विकेन्द्रीकरण की सोच पर भी अमल हो सकेगा। कोटपूतली के अंतिम गांव से जयपुर जिले की दूरी 140 कि.मी., बहरोड़ तहसील के अंतिम गांव से अलवर जिले की दूरी 135 कि.मी. तथा नीम का थाना तहसील के अंतिम गांव से सीकर जिले की दूरी 137 कि.मी. है।

कोटपूतली में वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, जिला पुस्तकालय, जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा अन्य विभागों के कार्यालय संचालित हैं।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया तथा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कोटपूतली को जिला बनाने की मांग करता हूं।

सुभाष चन्द्र शर्मा
(कोटपूतली)

गंगनहर का निर्माण कार्य बुर्जी सं. 31 से 205 को पक्की करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गंगनहर पर निर्माण विभिन्न वितरिकाओं पर प्रगति पर है एवं फीडर की बुर्जी 205 से 240 का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है परन्तु आर.डी. 31 से 205 के मध्य निर्माण होना है जिसके लिये नहर निर्माण में विद्यमान कठिनाईयां जैसे नहर के साथ-साथ

अत्यधिक ट्यूबवैलों का होना है जिस डाइवर्सन का निर्माण संभव प्रतीत नहीं हो रहा एवं इसी कारण विभाग इस कार्य को शुरू करने में कतरा रहा है इसके समाधान के लिये नहर निर्माण बिना डाइवर्सन नहर का संचालन इस प्रकार करें कि नहर दो हालते लगातार चलाकर दो हफते बन्द करवाकर निर्माण किया जा सकता है तथा ठेके भी छोटी-छोटी रीच बनाकर किये जावे ताकि ज्यादा ठेकेदार काम कर सकेंगे एवं एक साथ काफी स्थानों पर कार्य किया जा सकेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को तुरन्त दिशा-निर्देश दिये जावें।

फीडर कैनाल को टेल से निकलने वाली करणीजी वितरिका 0 से 50 तक पूर्व में बीकानेर कैनाल (पंजाब) के साथ ही चूने की लाईनिंग से बनी है जो जर्जर हो चुकी है परन्तु इस भाग को पक्का नहीं किया जा रहा है इसको तुरन्त ए.आई.बी.पी. के तहत पक्का करवाया जाना जरूरी है अन्यथा करणीजी आर.डी. 50 से आगे को सारी पक्की नहर बनाने का लाभ क्षेत्र के कृषकों को नहीं मिलेगा।

लाल चन्द मेघवाल
(रायसिंहनगर)

परबतसर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर नया पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने के संबंध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जो कि पूर्व में नागौर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड रह चुका है, जिसमें परबतसर मकराना व नावा विधान सभा क्षेत्र आते थे अब नावा मकराना को अलग बना दिया गया है, एवं उक्त दोनों उपखण्ड मुख्यालयों पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित है। जब कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है जिसके अन्तर्गत परबतसर थाना, पीलवा थाना व गच्छीपुरा थाना तथा बिदियाद पुलिस चौकी एवं बडू पुलिस चौकी लगती है। परबतसर शहर में अंग्रेजों के जमाने का कारागृह है। परबतसर शहर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट तथा ए.डी.जे. (फास्टट्रेक) कोर्ट भी स्थित है। परबतसर बस स्टेण्ड पर रोजना लगभग सौ से अधिक रोडवेज बसों का व अन्य निजी बसों का आवागमन होता है जिसमें भारत के कोन-कोने से तरह-तरह यात्री आते रहते हैं। परबतसर शहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुष्कर व अजमेर

से बहुत नजदीक, एवं पुष्कर की तलेटियों में 7 कि.मी. में बसे होने के कारण तथा परबतसर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 से जुडे होने के कारण इस विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से तरह-तरह के लोगों का व सैंकड़ों वाहनों, ट्रकों का प्रतिदिन आवागमन रहता है। जिससे इस क्षेत्र में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

राज्य सरकार द्वारा इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पूर्व निर्मित सब जेल के स्थान पर जिला मुख्यालय के बाद वर्तमान में 2 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से उप कारागृह के लिये विशाल भवन का निर्माण परबतसर में ही करवाया है।

राजस्थान के गठन के साथ ही परबतसर में उपखण्ड मुख्यालय स्थापित किया गया। मकराना में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां प्रदूषण एवं गन्दगी की भरमार है। पूर्व में मकराना पुलिस थाना व तहसील मुख्यालय तथा मकराना का मुंसिफ कोर्ट परबतसर में ही होने के कारण अपर जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय भी मकराना में ही स्थापित किया गया था। मकराना शहर में गन्दगी कचरा की समस्या इतनी बड़ी है कि प्रशासन भी हालात पर काबू नहीं पा सका है। इस समस्या के निदान के लिये माननीय उच्च न्यायालय में भी पर्यावरण संस्था व स्थानीय नागरिकों द्वारा मुकदमा किया गया है, तथा आज भी मकराना के नागरिकों द्वारा गन्दगी नहीं फैलने देने हेतु प्रदर्शन व क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। वर्तमान में किशनगढ़ से कुचामन तक मेगा हाइवे पर कोई भी पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय स्थापित नहीं है। चूंकि परबतसर नागौर जिले का सबसे पुराना उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है जिसके नाते भी परबतसर में पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय आवश्यक है। वर्तमान मकराना शहर जो परबतसर के बाद में तहसील और उपखण्ड घोषित किया गया है, तथा कुचामन जो न तो उपखण्ड मुख्यालय है न ही तहसील मुख्यालय है फिर भी इन दोनों स्थानों पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय स्थापित है।

अतः इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर नया पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करवाकर अनुगृहित करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

1. दूदू में सरकारी कॉलेज खोलने व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के कार्यों व सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. पंचायत समिति दूदू में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विद्यालयों में मिड-डे मील वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. प्राथमिक शिक्षा मे किये जा रहे स्थानान्तरणों में पंचायत राज एक्ट की अवहेलना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. सैकण्डरी शिक्षा में सैकण्ड ग्रेड व विषय अध्यापकों की भर्ती करने तथा पंचायत समिति दूदू में अयोग्य व अक्षम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की वजह से शिक्षा में हो रही दुर्दशा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

6. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राज. प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने, सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने तथा राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (दीगोद) :

8. अध्यापकों की योग्यता जानने व उनका नियमित रुप से मूल्यांकन कर परीक्षा लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

9. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की उपस्थिति की योजना बन्द तरीके से जांच करके दोषी अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. माध्यमिक शिक्षा को पंचायत समितियों के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की शहरों में पुनर्नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

12. कठपुतली बनाने वालों को सरकार द्वारा आवास हेतु भूमि आबंटित किए जाने एवं कालबेलियों को आवास उपलब्ध करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निजी शिक्षण संस्थानों की भांति अंग्रेजी माध्यम चालू किये जाने एवं अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षकों को स्थाई करने, शिक्षकों को स्थाई करने, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने एवं राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माध्यमिक विद्यालय नौरंगपुरा व नीमला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भामोद, बोबाड़ी, लखेर, भावणी एवं लालवास को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने एवं शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. प्राथमिक विद्यालय बुढा हरवाड़ा शंकरपुरा, जुगलपुरा एवं बादशाहपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

19. विद्यालयों में मिड-डे मील के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

20. शेरगढ़ में उपाध्याय स्तर के संस्कृत विद्यालय को शास्त्री स्तर में क्रमोन्नत करने, बालेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं राज. मा. विद्यालय यामू, सोलकिमातला, सोमेतर, राइसर, बालेसर, दुर्गावता, बस्तवा को राज. उ. मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये प्राथमिक पाठशाला खोलने, जर्जर व क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत, विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

22. राज्य में अनुदानित विद्यालयों के गिरते स्तर को देखते हुये अनुदान बन्द करने व स्कूलों के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

23. शिक्षा को प्रमुखता देते हुए स्कूलों में शिक्षकों को अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

24. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राज. मा. विद्यालय, गुढा नाथावत, राज. मा. विद्यालय रानीपुरा, राज. मा. वि. तन्थूर विद्यालयों को राज. सी. मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के राज. उ. प्राथ. विद्यालय चतरगंज, रामचन्द्रजी का खेड़ा, चैंतां, डाबेटा, नेगठ, मांगली कलां, अभरत्या आदि अन्य वियालयों को माध्यमिक वियालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में एक भी राज. सी. मा. विद्यालय में 'विज्ञान' विषय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

27. सभी स्तर के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये शिक्षकों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोड़ाभीम) :

28. टोडाभीम में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

29. बाड़मेर जिले में राज. सी. मा. वि., मा. वि., उ. प्रा. वि. व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में राज. उ. प्रा. वि. उडासर, भीमथल, बोर, पीपराली, खारी, भुकने का शोभाला जैतमाल, बाण्ड, मालपुरा, कोशल, निम्बलकोट, खंरटीया, सणया, नोसर, बोड़वा, पुनियों की बस्ती, रामसरका कुआं, बेरीवाला तला, नोख, बुठ जैतमाल, लख, बांटा, रतनपुरा, भाखरपुरा, लूणवा जागीर, सांजटा, टाके, बेरी, कमण्ठाई, मंगले की बेरी, सरणू, चिमन जी, जालीखेड़ा, नेहनों की ढ़ाणी, धोलानाड़ा, राणासर खुर्द को मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

31. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में ग्राम घासौली, नांगल सालिया, पाटन अहीर, खानपुर, मेवान में उच्च मा. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. कस्बा खैरथल में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

33. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के मा. वि. जसवन्तगढ़, उ.प्रा.वि. पुनावली, रामव मादड़ा, रावछ कडेच, झेड़, देवला, पालछा, झालरा, भुतवड़ कुर्रा, हायला व पंचायत मुख्यालय के सभी विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में माध्यमिक विद्यालय चित्रावास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

35. पंचायत समिति कोटड़ा में प्रा. वि. सांभरमाल, उ.प्रा.वि. झालरा तथा अन्य विद्यालय बन्द होने एवं अध्यापकों की अनुपस्थिति से बच्चों के भविष्य के साथ घोर खिलवाड़ होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

36. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के स्कूलों के रिक्त पदों को भरने तथा ढ़ाणी मजरों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के नारायण खेड़ा, खेमाणा, बागड़, खाखामाला, अरमीना, सुरूवास, नान्दणा, मीरां को माध्यमिक विद्यालय में तथा आशाहोली, नारी, झाड़ौल, कोट नाथडीमास, सरगांव को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. गंगापुर (भीलवाड़ा) मे महिला महाविद्यालय तथा रायपुर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था एवं हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

40. राज्य में शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिये विद्यालयों के खेल मैदानों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. राज्य में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य के विद्यालयों में अपेक्षित शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राज्य में प्रतिभाओं की कला को निखारने एवं आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

44. 1996 में विधवा एवं परित्यक्ता कोटे में नियुक्त शिक्षिकाओं की, जिन्होंने मान्यता रद्द कोटा खुला विश्वविद्यालय से बी.एड., डिग्री प्राप्त की तथा जिन्होंने दूसरी बार अन्य मान्यता विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर ली हो, तो उनको अध्ययन अवकाश व वेतन वृद्धि देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. राज्य में चल रहे कुछ निजी विद्यालय जो केवल धनोपार्जन में लीन रहते हुए संस्कृति को प्रदूषित करने का कृत्य करते हैं, उन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

46. राज. बा.मा. वि. चण्डावल नगर का नाम भवन निर्माता संत वासुदेव महाराज रा. कन्या मा. वि. करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. आई.आई.टी. जोधपुर अथवा पाली में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. रायपुर तहसील में आई.आई.टी. एवं डिग्री कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय नानगा, बिरारिया खुर्द, हाजीवास, मुरडावा, मोहराकलां, करमावास मालिवान, कन्या वि. बर कन्या वि. देवली कलां व कन्या वि. कुशालपुरा को माध्यमिक विद्यालय में एवं गिरी सेन्दड़ा, रामपुराकलां मा. विद्यालयों को उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

50. राज्य में कला व संस्कृति को संरक्षित एवं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में स्कूल, कॉलेजों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

53. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

54. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जिला मुख्यालय की राजकीय महिला महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की तहसील व पंचायत समिति बायतु मुख्यालय पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतु में विज्ञान व वाणिज्य वर्ग के संकाय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की तहसील व पंचायत समिति बायतु मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की तहसील व पंचायत समिति बायतु मुख्यालय पर राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

58. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के माध्यमिक विद्यालय अमरथून में अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान के अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के संस्कृत कॉलेज गनौड़ा में व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के राज. मा. विद्यालय दुदका में विज्ञान, गणित, विशेष हिन्दी के 03 पद III ग्रेड के व एक पद शारीरिक शिक्षक की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के राजकीय मा. विद्यालय डूंगरिया में व्याख्याताओं की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय देलवाग में प्रधानाध्यापक सहित 05 अध्यापकों के रिक्त स्थान पर रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

63. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी पं. स. क्षेत्र में आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी तहसीलों में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने व अन्य स्टॉफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बाहेड़ा, कनेरा व राज. बा. उ. मा. वि. निम्बाहेड़ा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, (नवीन) निम्बाहेड़ा में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा को स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान करने तथा छोटी-सादड़ी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

68. हिण्डोली मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

69. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय महिला कॉलेज में प्राइज़ के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. उदयपुर संभाग के अंग्रेजी, गणित द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के क्रमोन्नति के नियम जयपुर संभाग में अलग लागू करने से अध्यापकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कूंठता मण्डीयाना, मचीद, नेगड़िया, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों तथा कोसीवाड़ा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

73. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उ.प्रा.वि. ढ़िकोड़ा, पलां, भाडेर तथा भादवी गुढा, को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

74. अलवर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

75. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के कस्बे बजीरपुर में कन्या माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

76. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

77. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्कूलों में अध्यापक लगाने, शाला क्रमोन्नत करने, महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

78. राज्य में शिक्षा के गिरते हुए स्तर एवं विद्यालय खोलने में भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

79. प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के बजट में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में इतिहास पुर्नलेखन का कार्य शिक्षकों से कराने से शिक्षक वर्ग में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में रिक्त अध्यापकों तथा उर्दू अध्यापकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राज. विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

83. भरतपुर जिले की नगर तहसील के राज. मा. विद्यालय, बेरू, मुण्डिया को सीनियर में तथा राज. उ. प्रा. वि. जालूकी, सैमला कलां व भरपुरा को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

84. मकराना क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय एवं राज. प्रा. शाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

85. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा कस्बे में आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सकरावास, जीतावास, सादड़ी बड़ारड़ा, खटामला में मा. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

87. राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

88. माध्यमिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा की तरह सार्वजनिकीकरण तथा सरकारी की उच्च शिक्षा नीति में बदलाव पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

89. मुण्डावर तहसील में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बालिका उ. मा. विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. बा.उ.मा. विद्यालय मुण्डावर में साईन्स (बॉयलोजी) विषय खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. राज. उ. मा. विद्यालय जाट बहरोड़ में साईन्स विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राज. उ. मा. विद्यालय बीजवाड़ चौहान में कृषि विषय को यथावत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

94. केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां में कॉलेज स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में रिक्त पदों के लिये विशेष भर्ती अभियान चलाने व निश्चित अवधि तक स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. कोटा विश्वविद्यालय संचालित होने के बाद से ही शिक्षा विभाग द्वारा स्टाफ भर्ती की व्यवस्था नहीं करने व कर्मचारी ठेके पर भर्ती होने के कारण रिक्तियां भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

97. राजगढ़ (चूरू) में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नेसल एवं डिगली को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राजगढ़ (चूरू) तहसील के प्राथमिक शाला धोलिया, धागड़ा, केरलीवास डाबली ढ़ाणी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बेबड (राजगढ़) में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

100. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में किराये के भवनों में चल रहे विद्यालयों के नवीन भवन बनाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नये प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उच्च प्रा. विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़ -सीकर) :

105. संस्कृत कॉलेज सालासर-सीकर-श्रीमाधोपुर-चिराणा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

106. डी.पी.ई.पी. के द्वारा बनाये गये भवनों के नक्शे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. तहसील लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. लक्ष्मणगढ़ तहसील में संस्कृत स्कूल, नेछा व लक्ष्मणगढ़ को राजकीय विद्यालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

110. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्रामीण क्षेत्र के सभी उ.मा. विद्यालयों में कृषि विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. नसीराबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद में भूगोल विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. मेजर कमलेश राज. उ. मा. विद्यालय, नसीराबाद में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के जिलावड़ा व बिठुर तथा लामाना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

115. डेगाना तहसील मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जिला नागौर में दीर्घावधि से रिक्त शारीरिक शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राज. उ. मा. वि. थांवला, रा.मा.वि. मेवड़ा, रा.मा.वि. बिखरनियां कलां, रा.उ.मा.वि. खूडीकलां, रा.मा.वि. बुटाटी, जालसू खुर्द, जालसू कलां, कोड, चक ढ़ाणी आदि अनेक पाठशालाओं में लम्बे समय से चले आ रहे अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

118. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सभी बाकी बचे वैकल्पिक और राजीव गांधी पाठशालाओं को रा.प्रा. विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. राज. मा. वि. डोडियाना, आलनियावास, बिखरनियो कलां, कितलसर एवं निम्बड़ी चांदावता को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

120. राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. राजगढ़ (चूरू) में पोलीटेक्निक कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

122. स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार, विज्ञान व वाणिज्य विषय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

123. सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पाली में सम्पूर्ण जिले में अनुसन्धान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और मोनीटरिंग पर होने वाले खर्चों में भारी अनियमिततएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

124. सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पाली में सम्पूर्ण जिले में स्कूल ना जा सकने वाले बच्चों के लिये होने वाले खर्चों में भारी अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. जैतारण विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. रा.उ.मा. विद्यालय निमाज तहसील जैतारण में विज्ञान विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पाली के सम्पूर्ण जिले में अध्यापक प्रशिक्षण, सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण, विकलांग बच्चों के लिये व्यवस्था में किये गये खर्चों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

128. विधान सभा क्षेत्र लूणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों-दुन्दाड़ा, धवा, डोली, झंवर, लूणावास कलां, बालिका लूणी में वाणिज्य व विज्ञान (गणित व जीव) वर्ग खुलवाये जाने तथा तहसील मुख्यालय लूणी में एस.टी.सी./बी.एड. कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र लूणी में रियासत काल में निर्मित जीर्ण-शीर्ण व जर्जर रा.उ.मा. विद्यालय लूणी के भवन की मरम्मत करने, रा. बालिका उ.मा. विद्यालय लूणी व रा. बालिका मा. विद्यालय धुन्धाड़ा के भवनों का आवश्यकतानुसार विस्तार, रा.मा. विद्यालय सतलाना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा केन्द्र खोलने, ग्राम नंदावन व लूणी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने, विधान सभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय लूणी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र लूणी के कस्बों-डोली, झंवर, नंदवान, शिकारपुरा, रोहियाखुर्द, वाली, सर, सरेचां, पीपरली, खाराबेरा पुरोहितान, बड़लिया, फींच, जानादेसर, खाटावास, खुडाना, रामपुरिया, भाटियान, रामासनी, ओलवी, चांदेलाव, बोयत, बाला इत्यादि में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा रा.उ.मा.वि. धवा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र पुन: खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र लूणी के रा.मा. विद्यालयों बिसलपुर, मोगड़ाकलां, सतलाना, खाराबेरा पुरोहितायान, फींच, काकेलाव, पीथावास, जानादेसर, फिटकासनी, बोयत, बालीका धुन्धाड़ा, शुभदण्ड, खुडाली, को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने, राज. उ. प्रा. विद्यालयों सर, लूणावास, खारा, भाण्डूकलां, रोहिचा खुर्द, चाली, भाचरना, नंदवान, रामासनी, चांदेलाव, बीनावास, सिनली, उत्तेसर, बालिका मोगड़ा कलां, बालिका मोडी जोशियान, खेजड़ली कलां, सजाड़ा, लोलावास, बीरामी, जसपाली तथा भाण्डूखुर्द, बड़लिया, कालीजाल, सेनाई को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

132. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विद्यालयों में रिक्त प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

133. राज्य में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के उ.प्रा. विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने, प्रत्येक 5 कि.मी. की परिधि में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना एवं प्रत्येक ढ़ाणी व मजरे में प्रा. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के प्रत्येक स्तर के सरकारी विद्यालय के चार दिवारी के निर्माण, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय व प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत व भवन निर्माण की राशि आबंटन पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) (नागौर) :

136. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राज. उ. मा. वि. बालिका में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में रा.उ.प्रा.वि. बतानी, खेड़ूली, गवारड़ी बिटन को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में रा.मा.वि. इन्द्रावड़, लाम्बोलाई, मोकाला व गगराना को उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में रा.उ.मा. वि. जारोड़ा व पाड़कलां में विधान संकाय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में रा.प्रा., उच्च प्रा., मा., उच्च मा. विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

141. विधान सभा क्षेत्र कपासन के विद्यालयों में हाथ से रंगाई छपाई कार्य को विशेष प्रोत्साहन व दर्जा प्रदान करने एवं अधिक ऋण व उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र कपासन में विद्यालय क्रमोन्नत कराने विद्यालयों में पद सृजित कराने व रिक्त पदों पर पदस्थापन करने, रा.उ.मा. वि.

(श्री बद्रीलाल जाट)

आकोला में प्रयोगशाला सहायकों के पद सृजित कराने तथा उ.मा. विद्यालयों में नये विषय संकाय चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कालेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

144. सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. भीनमाल व जालोर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. जालोर जिले के विद्यालयों में शिक्षक मित्र लिये जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

147. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) कडोदिया, धरोनिया, सलोतिया व औसाव के गांवों के सैकण्डरी स्कूल को सी.हा.सै. स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) खरपालका, चसलाय, सांभरिया, बोलिया, बुजुर्ग, सेमलिया, दूबलिया, स्वांस, गोविन्दपुरा के गांवों के मिडिल स्कूल सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के ग्राम अलताफ नगर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के सी.हा.सै. स्कूल पिड़ावा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

151. सीमावर्ती जिला जैसलमेर-बाड़मेर में अध्यापकों का केडर अलग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

152. गिताउ तथा रेलमगरा में प्राप्त पुरातत्व के अवशेष व सिंधुकालीन

(श्री शांतिलाल चपलोत)

सभ्यता से भी पुरानी कृतियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. नऊवा चतुरसाधना धाम एवं ऋगभाषित मावली को संस्कृति एवं कला से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र मावली के सभी हायर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान, गणित, कृषि, वाणिज्य एवं कला संकाय के विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र मावली के सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी विद्यालयों की जर्जर अवस्था विद्यालयों के भवनों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

156. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के नाडोल रा.उ.मा. वि. में जीव विज्ञान का विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतेन्द्र सिंह (अलवर) :

157. अलवर मत्स्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. अलवर मत्स्य क्षेत्र में आई.आई.टी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. कला एवं संस्कृति से रुबरु करवाये जाने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला अलवर उत्सव का नाम परिवर्तन कर मत्स्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

160. विधान सभा क्षेत्र सीकर में नवीन यूनिवर्सिटी खोलने एवं तकनीकी शिक्षा के लिये महिला पोलोटेक्निकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) :

161. उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर पब्लिक स्कूल के तर्ज पर जनजाति विद्यार्थियों के लिये स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

163. नोहर में श्री बालिका उ. प्रा. विद्यालय के अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापिकाओं का शिक्षण कार्य का बकाया वेतन वर्ष जनवरी 2000 से जुलाई 2001 तक का दिलवाने, पी.एफ. का बकाया भुगतान दिलवाने एवं बिना सरकार की अनुमति के विद्यालय को बन्द करने पर खुलवाने या हटाई गई अध्यापिकाओं को अनुदानित पदों पर कार्यरत हैं को सरकारी पदों पर समायोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

164. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी में विज्ञान/वाणिज्य एवं गणित संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

165. अजमेर शहर के महिला राजकीय महाविद्यालय का स्वयं का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. अजमेर स्थित तोपदड़ा शिक्षा परिसर को पं. दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल के रुप में विकसित करने हेतु चर्चा के लिये।

167. अजमेर पूर्व विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा के खेल मैदानों के रख-रखाव एवं नये स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दर विलास में वाणिज्य संकाय, गुलाबबाड़ी व आदर्श नगर में विज्ञान व वाणिज्य संकाय, उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन बालुपुरा, मायुपुरा, राजाकोठी व गुलाब बाड़ी में वाणिज्य व विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

169. जिला अलवर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव को उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

170. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उच्च माध्यमिक विद्यालय विनायका में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

172. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवासी, शक्करगढ़, पारोली, रोपां, खजूरी, पीपलून्द एवं टीकड़ में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय रोपां को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

175. पंचायत समिति कोटड़ा के दूरदराज विद्यालयों में पोषाहार नहीं पहुंचने व विद्यालय बन्द रहने से शिक्षा स्तर में निरन्तर हो रही गिरावट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

176. कस्बा रावतसर एवं टिब्बी में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

177. अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

178. अन्य जनजाति क्षेत्र, माडा योजना आदि के जनजाति बच्चों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति में अपनाई जा रही अनावश्यक देरी एवं अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. जिला प्रा. शि. कार्यक्रम, डी.पी.ई.पी. के माध्यम से चलाये जा रहे कार्यक्रमों तथा निर्माण कार्यों में पारदर्शिता अपनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

180. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता राशि को बढ़ाने, राजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों में रिक्त पद भरने के लिये शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. छात्रवृत्तियों की स्वीकृति में किये जाने वाले अनावश्यक विलम्ब की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. अराजकीय विद्यालयों को दी जा रही सहायता में बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

183. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के शिक्षाकर्मी स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने व मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी व सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

184. नाथद्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं अन्य विषयों के लम्बे समय से रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

185. राजस्थान साहित्य अकादमी की अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विभाग द्वारा आमेर किले व आमेर क्षेत्र का मूल स्वरूप नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. सिरोही जिले में तत्कालीन जिला शिक्षाधिकारी कमला यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच प्रमाणित होने के बावजूद कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में वर्ष 2004, 2005, 2006 में सिरोही विधान सभा क्षेत्र की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनर्गल बातें व पढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

190. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की सभी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. राजकीय माध्यमिक विद्यालय दादीया (रामपुरा) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनिहारवास, पंचायत समिति खण्डेला को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. ग्राम जाजोद राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. राजकीय माध्यमिक विद्यालय आमावास पंचायत समिति श्रीमाधोपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

195. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा में भूगोल, अंग्रेजी व विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

196. ग्रामीण क्षेत्र के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की संकायें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) :

197. जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) का कार्य क्षेत्र परबतसर, मकराना, नावां, कुचामन एवं डीडवाना का हैडक्वार्टर कुचामन सिटी डाइट में उपलब्ध भवन में कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में वंचित पंचायत हैडक्वार्टर की सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार) :

199. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. योजना में चार-दीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

200. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में माध्यमिक विद्यालय डिडापच, भेडौला, सारसोप एवं छाण, गोठडा को सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक भवन निर्माण एवं चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम डेकवा, जौला, मुई बलरिया, हापुर महापुरा एवं चितारा मेईकलां, मण्डावर, अनिपाला, रोड़ावद पाली एवं बिचपुरी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

204. राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेजों में एवं स्नातकोत्तर कोर्सेज के विषयों व लॉ-कॉलेज में वर्तमान सीटों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र हवामहल की बालक एवं बालिकाओं के सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर में विज्ञान, गणित, वाणिज्य एवं भूगोल विषय के संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. ब्रह्मपुरी, जयपुर में स्थित बालक एवं बालिका विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

208. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की शिक्षाकर्मी विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

209. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण करवाने एवं पुराने भवनों की मरम्मत करवाने तथा चारदीवारियों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण की स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

212. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क जयपुर के सरकारी स्कूलों में शौचालय, मूत्रालय, फर्नीचर, पानी-बिजली की कमी पूर्ति करने तथा जीर्ण-शीर्ण पुराने भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में सरकारी स्कूलों में स्थित खेल के मैदानों के लिये दीवारों का निर्माण कर अतिक्रमण रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थित कच्ची बस्तियों में स्कूल भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) :

215. ग्राम कोकपुरा ग्राम पंचायत अड़कसर उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो कमरे, प्रधानाध्यापक कक्ष, यूरिनल, कीचन सैड इत्यादि निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. नावां शहर में महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. राजकीय सोनी देवी सोमानी बालिका माध्यमिक विद्यालय, कुचामनसिटी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

218. सर्व शिक्षा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु गांव की रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था/जनप्रतिनिधियों/भामाशाह की समितियों के गठन पर एवं पंचायत समिति की तरह इनसे भी मूल्यांकन बुक का संधारण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

219. सर्व शिक्षा के तहत किये जा रहे निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र खारची में माध्यमिक विद्यालय आऊवा व पांचोटिया को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र खारची में उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटसोकियान, सांसरी पंचायत समिति देसूरी, भिभालिया, जोजावर बालिका, गुडारामसिंह व ईसाली, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तथा खिवाड़ा बालिका विद्यालय पंचायत समिति रानी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र खारची में जोजावर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

223. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

225. राज्य के आई.टी.आई. एवं अन्य तकनीकी शिक्षा के संस्थानों सहित राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों एवं संकायों में वर्तमान सीटों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. जयपुर में महिला महाविद्यालय खोलने एवं आई.टी.आई. की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर पर्यटन स्थल विकसित करने एवं पापड़ के हनुमान मन्दिर के आसपास के क्षेत्र को धार्मिक स्थल (पर्यटन क्षेत्र) के रुप में विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की सभी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

229. शिक्षकों को शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाने से विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में बाधा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

230. प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने एवं विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. राजस्थान में खुलने वाले आई.टी.आई. को जयपुर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. जयपुर में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

235. खानपुर जिला झालावाड़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में प्रिन्सिपल का रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

236. बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर के अन्तर्गत डूंगर महाविद्यालय एवं महारानी सुदर्शन महाविद्यालय, बीकानेर को संघटक महाविद्यालय न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के कार्यों को धीरे-धीरे छीन कर जयपुर स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. बीकानेर विश्वविद्यालय बीकाने के प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरु नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

239. राज्य के विभिन्न विशिष्ट विद्यालयों में सरकारी खर्चे पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवर्ष लगभग 1200 विद्यार्थियों

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को निजी एवं पब्लिक स्कूलों में गत तीन वर्षो से भर्ती नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

240. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

241. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

242. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अगवरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओडवाड़ा, चूण्डा, रोडला, आईपुरा, भागली पुरोहितान को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम बाला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जर्जर कमरों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा-बालोतान में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अग, सांकरणा व नौसरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामा, कुआड़ा, भवरानी, रायथल, वागोवरा, बोटियावास आहोर, सुगालिया, सिंघलाना वारणी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

247. खानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा सत्र के दौरान विद्यालय भवन को वैवाहिक कार्यक्रम में देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

248. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बागौर तहसील नादौती जिला करौली में कार्यरत प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में अनियमितताएं बरतने एवं

(श्री नरेन्द्र नागर)

अधिकतर समय विद्यालय से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की पंचायत समिति बस्सी में कार्यरत अध्यापकों को सही समय पर वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

250. उच्च माध्यमिक विद्यालय डण्डाली पंचायत समिति सिणधरी (बाड़मेर) के अतिवृष्टि में ध्वस्त भवन का पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी (बाड़मेर) के नये भवन का जन सहयोग से निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. सिवाना (बाड़मेर) में राजकीय महाविद्यालय सह शिक्षा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. जीर्ण-शीर्ण छात्रावास सिवाना एवं रमणिया की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. सिणधरी (बाड़मेर) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नव सृजन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

255. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के स्कूलों में पर्याप्त भवन, पानी तथा शौचालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

257. विभाग द्वारा प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के अनुदान राशि कम करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

258. राज्य में संस्कृत विद्यालयों को सिर्फ 2 करोड़ रुपये आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. स्कूलों में मिड-डे मील पकाने के लिये रसोईघर की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

260. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों से रिक्त पड़े व्याख्याता, प्राध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, सामान्य अध्यापकों के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापक, अध्यापिकाओं व अन्य स्टाफ के पदों से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बेड़ा एवं चामुण्डेरी में विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भन्दर, भाटुन्द, बीजापुर व नाणा में वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि महाविद्यालय पोलोटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लम्बित पेंशन बीमा-जीपीएफ, साधारण दुर्घटना दावा, मेडिकल, यात्रा भत्ते व अन्य सेवा सम्बन्धी क्लेम प्रकरणों के निस्तारण एवं इन विद्यालयों में पानी-बिजली-शौचालय-मूत्रालय की कमी तथा अधूरे निर्माण कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

265. मिड-डे मील में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. ग्रामीण विद्यालयों में बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. स्टेट ऑपन स्कूल में सुचारु व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

268. राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. सर्व शिक्षा अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन व लक्ष्यों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

270. प्रत्येक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में विज्ञान एवं कृषि प्रधान जिलों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

में कृषि विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती स्नेहलता (डग) (झालावाड़) :

271. अनुकम्पा पर दी गयी नौकरियों में महिला शिक्षकों को बी.एड. करने के उपरान्त भी ग्रेड इन्क्रीमेंट न देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

272. पैरा टीचर्स एवं शिक्षा सहयोगियों को स्थायी तृतीय श्रेणी अध्यापक नहीं बनाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

273. शिक्षा के पाठ्यक्रमों को साम्प्रदायिककरण करने से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. राज्य में शिक्षकों की कमी से शैक्षिक कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र धोद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूड, मूण्डवाड़ा में साइन्स बॉइलोजी संकाय, फागलवा में कला संकाय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धोद में साइन्स बाइलोजी संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरदुगा में कृषि संकाय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

276. विधान सभा क्षेत्र फागी में रिक्त अध्यापकों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमू) :

277. राजकीय महाविद्यालय, चौमूं में ड्राईंग व पेंटिंग, भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

278. राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सामोद व बांसा में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. राजकीय शास्त्री महाविद्यालय कालाडेरा को आचार्य स्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल शर्मा)

280. राजकीय सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा की भूमि पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोका-कोला कम्पनी द्वारा नलकूप खुदवाने एवं भूमि खेती के लिये देने की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. आर. एल. सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा में स्नातकोत्तर कला संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

282. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (संस्कृत) विराटनगर (जयपुर) को महाविद्यालय का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र बैराठ में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

284. राज्य प्राथमिक शिक्षा स्तर पर खेल विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

285. राज्य में सैनिक विद्यालयों के स्तर के समान जिला हैडक्वाटर्स पर विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

286. राज्य के विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

287. शिव एवं फतेहगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

288. प्रत्येक एक किलोमीटर की दूरी पर विद्यार्थी होने पर प्राथमिक स्कूल की अनिवार्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

289. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल खोलने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु चर्चा के लिये।

290. विद्यालयों की निरीक्षण व्यवस्था प्रभावी बनाने तथा शिक्षा अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

291. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुन्नापुरा, दरियापुर, रतनपुरा, वरखेड़ा, ऊमरारा, भागीरथपुरा, खनपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारीलाल)

292. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के पुरानी छावनी, विश्नोदा, मौरोली, तगावली, चौराखेड़ा, कुम्हेरी, कोलुआ, लुहारी, भेसेना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

293. धौलपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव, विरोधा, माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर, काकोली में पर्याप्त कक्षा-कक्ष नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

295. धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में एम.ए. राजनीतिशास्त्र एवं हिन्दी विषय, एम.एस.सी. में गणित व रसायन विज्ञान तथा बी.ए. में संस्कृत एवं लोक प्रशासन विषय नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

296. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बा कालू, नापासर, लूणकरणसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

297. विभिन्न विद्यालयों में रिक्त अध्यापक पदों को भरने, शैक्षणिक व्यवस्थार्थ अथवा डेपूटेशन के नाम पर की गई व्यवस्था को समाप्त करने, सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने, कक्षा के कमरों की कमी पूर्ति करने, पोषाहार व्यवस्था में सुधार लाने, पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अर्जुनसर, गुसाईसर, रामसर, शेरपुरा, दन्तोर, मूंडसर, सींथल, कालू (बालिका) को उच्च माध्यमिक में, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय धीटेटा, सेझां, फुलोजी, भीखमेरा, कुजरी, सहजरासर, रावांसर, कागासर, खिमेरा, साबनिया, सेसारदेसर, महादेववाली, हापासर, 2 केएलडी, सुरनाणा, तख्तपुरा, हटियासर (भार्डरा), सोढवाली, बडेरन, शुभलाई, बखूसर, ढाणी छिपलाई, बामनवाली, धीटेंटा स्टेशन, कुम्भाणाबास (लूणकरणसर), राणीसर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

299. विधान सभा क्षेत्र लूणरकणसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंगल महाजन, शेरेरा, शेखसर में कृषि/वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नापासर, लूणकरणसर में कृषि, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाजूवाला, नापासर, कालू में कृषि संकाय खोलने पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

300. तहसील बस्सी में बालिका महाविद्यालय नहीं खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

301. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की चल रही कमी को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय बस्सी में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

303. राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय बस्सी में कक्षा 1 से 8 तक को अलग भूमि व भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

304. गोनेर एस.टी.सी. मुख्यालय को जयपुर शहर में करने से स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस पर झण्डारोहण नहीं करने से स्थानीय जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

305. फुलेरा क्षेत्र में भूमि/भवन रहित राजकीय विद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

306. फुलेरा क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरने तथा चतुर्थ श्रेणी व प्रयोगशाला सहायक के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल व फुलेरा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में नये संकाय/विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा सांभर में स्थित राजकीय सीनियर सैकण्डरी

(श्री नवरतन राजोरिया)

कन्या विद्यालयों में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

310. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

311. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि संकाय में अध्ययन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

312. किशनगढ़ (अजमेर) मॉडल कॉलेज में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनगढ़ (अजमेर) में अतिरिक्त नये विषयों में अध्ययन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. किशनगढ़ राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ड्राईंग एवं पेंटिंग विषय में अध्ययन चालू कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।